



प्रातः स्मरणीय, पूजनीय एवं स्नेहमयी  
माँ स्वर्गीय श्रीमती रामकली शर्मा की  
पुण्य स्मृति में सादर समर्पित

# समष्टि आर्थिक सिद्धान्त (MACRO ECONOMIC THEORY)



(डॉ. ए. सी. शर्मा के पाठ्यक्रमानुसार)

96195

लेखक

डॉ. एस. सी. शर्मा

रीडर एवं अध्यक्ष अर्थशास्त्र  
स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन विभाग,  
नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
भोगाँव (मैनपुरी)  
आगरा विश्वविद्यालय

द्वितीय संस्करण

1994

---

---

**रत्न प्रकाशन मन्दिर**

पुस्तक प्रकाशक एवं विंक्रेता

1/185-A, प्रोफेसर्स कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा-282 002

---

---

● लेखक एवं प्रकाशक

मूल्य .35 00 रुपए मात्र



प्रकाशक : रतन प्रकाशन मन्दिर

1/185-A, प्रोफेसर कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा-282 002

शाखाएँ :

|         |   |                                   |
|---------|---|-----------------------------------|
| आगरा    | : | अस्पताल मार्ग                     |
| दिल्ली  | . | 21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज       |
| पनपुर   | . | तिलक हॉल लेन, मेस्टन रोड          |
| लखनऊ    | . | इन्दिरा मार्केट, अमीनाबाद         |
| गोरखपुर | . | 18, प्रतिभा कॉम्प्लेक्स, भवशीपुर  |
| मेरठ    | : | वेस्टर्न कचहरी रोड                |
| वाराणसी | : | K-62/106, जवाहर मार्केट, सप्तसागर |
| जयपुर   | : | बिचून मार्केट, किशन पोल बाजार     |

## प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

वर्तमान समय में अर्धशास्त्र के अध्ययन को व्यष्टि तथा समष्टि अर्धशास्त्र के रूप में पढ़ा जाता है। मर्मष्टि आधिक्य विद्वान् की प्रस्तुत पुस्तक अर्धशास्त्र की ११ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमानुसार तैयार की गई है। वैसा ना मर्मष्टि अर्धशास्त्र पर अनुका पुस्तक उपलब्ध हैं और उन पर टीका टिप्पणी करना उपयोग्य नहीं है। लेखक का वर्तमान पुस्तक लिखन में यह प्रयास रहा है कि यह पुस्तक स्नातक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये उपयोगी उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के मानदण्डों पर सही उतरगी।

प्रस्तुत पुस्तक का 20 अध्यायों में विभक्त किया गया है। मर्मष्टि अर्धशास्त्र में सम्बन्धित जटिल समस्याओं का सरल में सरल भाषा शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिसे स्नातक विद्यार्थीगण मर्मष्टि अर्धशास्त्र के महत्त्व पहलकों का आभासी से समझ लें। प्रत्येक अध्याय के अंत में सम्बन्धित अध्याय की सामग्री के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Questions) का समावेश किया गया है। वर्तमान प्रतिपादिता के युग में विद्यार्थियों को अपने अध्ययन तथा डिग्री प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्ति हेतु परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होती हैं। इन परीक्षाओं की सफलता के बाद उन्हें साक्षात्कार चयन बोर्ड के समक्ष जाना होता है। एक विद्यार्थी की दृष्टि से यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनकी सफलता के लिए अर्धशास्त्र जैसे तकनीकी एवं व्यावहारिक विषय के लिए कृषी साबित होंगे ऐसा विश्वास लेखक को है। विद्यार्थियों की सफलता से सम्बन्धित एक अन्य सामग्री प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट 1 में परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें के रूप में दी गई है। इसमें उन्हें परीक्षा भवन में प्रश्नों के चुनने से लेकर आदर्शात्मक उत्तर देने तक की प्रक्रिया को समझाया गया है।

लेखक यह तो दावा नहीं करता कि यह पुस्तक अपने में सभी दृष्टि में पूर्ण होगी परन्तु उसका प्रयास पुस्तक को उत्तम से उत्तम तथा आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। विद्वान् अध्यापक बन्धु एवं अन्य सज्जनवृद्ध इस पुस्तक को उपयोगी समझेंगे इस विश्वास के साथ लेखक का यह प्रयास उनके विश्लेषण हेतु प्रस्तुत है। यह लेखक के रूप में लेखक की मुद्रा बैकिंग तथा मुद्रा बैकिंग एवं राजस्व स्नातक कक्षाओं के लिए, आर्थिक विचारों का इतिहास एवं मुद्रा की रूपरेखा तथा एवमात्र लेखक के रूप में समष्टि अर्धशास्त्र स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रवर्धित हो चुकी है जिनको अर्धशास्त्र के ज्ञानसु विचारों द्वारा सराहा गया है यही लेखक के लिए उनका सन्नेह प्रस्वार है।

पुस्तक लेखन के प्रेरणास्रोत में अनेक बन्धु शुभचिन्तक एवं परिवारीजन रहे हैं। उनकी स्नेहपूर्ण शुभ कामनाएँ सदा मेरे मार्ग के अवरोधकों को पार करने में मेरे लिए बड़ा सहारा रही हैं। पूजनीय माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहा तथा जो रोग शीघ्र पर होते हुए भी मेरी तथा मेरे कार्य की प्रगति के लिए चिन्तित रहती थी। मैं अपनी धर्म पत्नी श्रीमती गायत्री शर्मा का उल्लेख अवश्य करूँगा जिन्होंने मुझे लेखन कार्यावधि में पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रखा। मेरी बच्ची चिन्ती जो अभी अबोध है वह भी मेरे कार्यों में जाने-अनजाने अपना सहयोग देती रही है। मैं अपने श्वसुर श्री ब्रज बिलाम शर्मा वैद्य तथा माम श्रीमती कमला शर्मा का भी वृत्तज हूँ जिन्होंने प्रीष्ठावकाश में पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु मुझे बाछनीय सुविधाएँ तो प्रदान की ही साथ ही अपना स्नेह एवं शुभकामनाएँ भी दी हैं। मैं अपने मित्र एवं शुभचिन्तक श्री विनोद कुमार वर्मा धानपुर का उल्लेख करना चाहूँगा जो मेरे कार्य की

प्रगति के लिए सदैव अपनी शुभकामनाएँ देते रहे हैं । अन्त में, मैं अपने प्रकाशक श्री प्रेम चन्द जैन का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने वर्तमान पुस्तक के लेखन हेतु मुझे निमन्त्रण दिया । उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं एवं बढ़ते हुए दायित्वों के बाद भी पुस्तक को यथामय प्रकाशित करके पाठकगणों के समक्ष रखकर महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान दिया है ।

पुस्तक से सम्बन्धित रचनात्मक सज्ञाओं की प्रतीक्षा लेखक के लिए मार्गदर्शक होगी ।

नटराज होटल बिल्डिंग,  
मैनपुरी-205001  
उत्तर प्रदेश ।

— एस. सी. शर्मा

# विषय-सूची (CONTENTS)

## समष्टि अर्थशास्त्र (MACRO ECONOMICS)

- समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics) 1-11  
व्यष्टि अर्थशास्त्र, परिभाषाएँ, विषय क्षेत्र, लाभ एवं महत्व, सीमाएँ, समष्टि अथवा व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ, लाभ एवं महत्व, सीमाएँ एवं दाय, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता, समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न ।
- राष्ट्रीय आय (National Income) A 12-27  
राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ एवं उनकी आलोचनाएँ, राष्ट्रीय आय की अन्य धारणाएँ—कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, वैयक्तिक आय, उपभोग्य आय, वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय का माप-उत्पादन प्रणाली, आय प्रणाली, व्यय प्रणाली, राष्ट्रीय आय की गणना की अन्य प्रणालियाँ, सामाजिक लेखांकन का प्रस्तुतीकरण, मिश्रित प्रणाली, राष्ट्रीय आय के माप के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ, अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय की माप सम्बन्धी कठिनाइयाँ, राष्ट्रीय आय विश्लेषण का महत्व, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का वास्तविक सूचकांक नहीं है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कसौटी, भारत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समिति, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सम्बन्धी कठिनाइयाँ, परीक्षा-प्रश्न ।
- बेरोजगारी तथा पूर्ण रोजगार (Unemployment and Full Employment) B 28-40  
बेरोजगारी का अर्थ, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार—सरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण—अबन्ध नीति सिद्धान्त, न्यून माँग सिद्धान्त, व्यापार चक्रीय सिद्धान्त—अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा, वीन्स की धारणा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा, समुक्त राष्ट्र सच, पूर्ण रोजगार के मुख्य तत्व, अर्द्ध-विकसित देश तथा पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की नीति, मौद्रिक नीति, राजस्वोपेय नीति, अन्य उपाय एवं नीतियाँ, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न ।
- रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of Employment) 41-51  
मिखा, जे. बी. मे. का बाजार नियम, मान्यताएँ, मुख्य तत्व, आलोचनाएँ, प्रो. से. के. यम की क्रियाशीलता, पीगू का भजदरी यटौती सम्बन्धी रोजगार सिद्धान्त,

आलोचनाएँ, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एक दृष्टि में, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की आलोचनाएँ प्रतिष्ठित तथा प्रो. कीन्स की विचारधाराओं में अन्तर, परीक्षा-प्रश्न।

1. **कीन्स का रोजगार सिद्धान्त (Keynesian Theory of Employment)** 52-68  
 कीन्स विश्लेषण की मान्यताएँ, प्रभावपूर्ण माँग, प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व – कुल माँग फलन, कुल पूर्ति फलन, कुल माँग फलन तथा कुल पूर्ति फलन का सापेक्षिक महत्त्व, कीन्स का रोजगार सिद्धान्त, रोजगार का निर्धारण, बचत एवं विनियोग दृष्टिकोण, सिद्धान्त की आलोचनाएँ, कीन्स के सिद्धान्त का महत्त्व – सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्त्व, कीन्स का सिद्धान्त तथा अल्प-विकसित देश, कीन्सवादी चरों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध, कीन्सवादी रोजगार मॉडल में स्वतन्त्र तथा निर्भर चर, कीन्स के रोजगार सिद्धान्त की प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त से श्रेष्ठता, परीक्षा-प्रश्न।
2. **उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति (Consumption Function or Propensity to Consume)** 69-81  
 कीन्सवादी उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, मान्यताएँ, सिद्धान्त का अभिप्राय, चिरकालिक स्थिरता, उपभोग क्रिया का अर्थ, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग क्रिया या फलन, औसत तथा सीमात उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग क्रिया को आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, वस्तुनिष्ठ तत्व, ध्यस्तनिष्ठ तत्व, साधारण उपभोग फलन के परिष्कार, प्रो. ड्यूसेन बेरी परिष्कृत, परीक्षा-प्रश्न।
3. **विनियोग क्रिया (The Investment Function)** 82-91  
 विनियोग का अर्थ, नियोजित तथा अनियोजित निवेश, निवेश का महत्त्व, कुल तथा शुद्ध निवेश, निवेश के प्रकार, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, निवेश को निर्धारित करने वाले तत्व, परीक्षा-प्रश्न।
4. **पूँजी की सीमान्त क्षमता (Marginal Efficiency of Capital)** 92-99  
 परिभाषा, पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन तत्व, पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक तत्व, आशासाएँ तथा पूँजी की सीमान्त क्षमता, पूँजी की सीमान्त क्षमता विचार की आलोचना, परीक्षा-प्रश्न।
5. **तरलता पसदगी तथा ब्याज की दर (Liquidity Preference and the Rate of Interest)** 100-110  
 तरलता पसदगी का अर्थ, ब्याज का तरलता पसदगी सिद्धान्त, ब्याज एक मौद्रिक तत्व है, तरलता पसदगी वक्र, तरलता वक्र, तरलता जाल, मुद्रा की माँग-सौदा उद्देश्य, मर्तकता उद्देश्य, सद्दा उद्देश्य, मुद्रा की पूर्ति, सिद्धान्त की आलोचनाएँ, प्रतिष्ठित तथा तरलता पसदगी सिद्धान्तों की तुलना, ब्याज की दर का निर्धारण, परीक्षा-प्रश्न।
6. **गुणक (Multiplier)** 111-123  
 गुणक – एक कालिक गुणक, अर्वाधि गुणक, गुणक में सामयिक परिवर्तन, गुणक के प्रभाव में क्षति, गुणक की आलोचना, गुणक सिद्धान्त का महत्त्व, एक अर्द्ध-विकसित देश तथा गुणक, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न।
7. **त्वरक (Accelerator)** 124-132  
 त्वरक का अर्थ, त्वरक तथा गुणक में अन्तर, त्वरक की क्रियाशीलता, त्वरक

सिद्धान्त की सीमाएँ त्वरक सिद्धान्त का महत्व त्वरक सिद्धान्त की आलोचनाएँ गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया परस्पर क्रिया का महत्व, परीक्षा-प्रश्न ।

12. मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य (Definition and Functions of Money) 133-146  
 मुद्रा क्या है ? मुद्रा की परिभाषा—वर्णनात्मक परिभाषाएँ वैधानिक परिभाषाएँ सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ परिभाषा से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण, परिभाषाओं की कतिपय सीमाएँ-मुद्रा के कार्य मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण I तथा II, परीक्षा-प्रश्न ।
13. मुद्रा का चक्राकार प्रवाह एवं महत्व (Circular Flow and Importance of Money) 147-161  
 मुद्रा का चक्राकार प्रवाह सन्तुलन की समस्या सरकार तथा गति का आकार । मुद्रा का महत्व—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व मुद्रा के दोष मुद्रा का नियन्त्रण परीक्षा-प्रश्न ।
14. मुद्रा की पूर्ति तथा माँग (The Supply of and the Demand for Money) 162-173  
 मुद्रा की माँग—कीन्स तथा प्रीडमैन की व्याख्या मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की प्रभावी पूर्ति मुद्रा का चलन वेग मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले कारण मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप शक्तिशाली मुद्रा परीक्षा प्रश्न ।
15. मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) 174-197  
 मुद्रा परिमाण सिद्धान्त—लेन-देन दृष्टिकोण फिशर की व्याख्या मुद्रा का चलन-वेग फिशर के सिद्धान्त की मान्यताएँ फिशर के सिद्धान्त की आलोचनाएँ सिद्धान्त की ऐतिहासिक पुष्टि, कैम्ब्रिज अधशास्त्रिया का दृष्टिकोण—प्रो माशल, प्रो पीगू, प्रो राबर्टसन तथा प्रो कीन्स के समीकरण नवद शोध समीकरण की आलोचनाएँ फिशर की व्याख्या तथा कैम्ब्रिज व्याख्या की तुलना दोनों समीकरणों में समानता असमानताएँ, दोनों समीकरणों में कौन सा श्रेष्ठ है परीक्षा प्रश्न ।
16. स्फीति तथा अवस्फीति (Inflation and Deflation) 198-236  
 स्फीति की परिभाषा पूर्ण तथा आंशिक स्फीति स्फीति की विशेषता स्फीति के प्रकार माँग प्रेरित बनाम लागत वृद्धि स्फीति स्फीति अंतराल मन्दी स्फीति स्फीति का कारण स्फीति के प्रभाव स्फीति को रोकने का उपाय अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था में स्फीति स्फीति तथा आर्थिक विकास अवस्फीति की परिभाषा अवस्फीति का प्रभाव अवस्फीति को रोकने के उपाय स्फीति तथा अवस्फीति के बीच चुनाव परीक्षा-प्रश्न ।
17. व्यापारिक बैंक तथा साख निर्माण (Commercial Banks and Credit Creation) 237-256  
 बैंकों का महत्व बैंक तथा आर्थिक विकास अर्द्ध-विकसित देशों में बैंकों का महत्व बैंकों का वर्गीकरण—व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक कृषि बैंक, बचत बैंक, केन्द्रीय बैंक अन्तरराष्ट्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, बैंक द्वारा साख-मुद्रा का निर्माण, साख निर्माण शक्ति की सीमाएँ साख सृजन सिद्धान्त की आलोचना, परीक्षा प्रश्न ।



18 कन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य (Central Bank and its Functions) 257-279

गतिहासिक पृष्ठभूमि कन्द्रीय बैंक की परिभाषा कन्द्रीय बैंक के कार्य नाटनिगमन का एकाधिकार सरकारी बैंकर गजन्त एवं सैलाहकार बैंक का बैंक राष्ट्र की अन्तर्गर्तीय मुद्रा का सुरक्षक मद्रम्य बैंक का समाशाधन गृह अंतिम ऋण दाता भारत का नियन्त्रण भारत नियन्त्रण भारत नियन्त्रण की आवश्यकता परिभाषात्मक विधीयाँ- बैंक दर नीति की सीमाएँ राल बाजार की क्रियाएँ न्यूनतम बैंध आर्गधन अनपात तरल कापानुपात - भारत नियन्त्रण की गुणात्मक विधीयाँ - भारत मुद्रा गशातिग प्रत्यक्ष कायवाही नैतिक अनुयथ चयनात्मक भारत नियन्त्रण उद्देश्य विज्ञापन एवं प्रचार अद्व विरमित अर्थव्यवस्था में कन्द्रीय बैंक परीक्षा-प्रश्न ।

19 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) 280-296

रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य संगठन तथा प्रबन्धन रिजर्व बैंक के विभाग रिजर्व बैंक के कार्य रिजर्व बैंक भारत नियन्त्रण में असफल क्या रहा रिजर्व बैंक तथा अनुमूर्चित बैंक रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त रिजर्व बैंक की सफलताएँ रिजर्व बैंक की असफलताएँ परीक्षा-प्रश्न ।

20 व्यापार चक्र (Trade Cycle) 297-309

व्यापार चक्र की परिभाषा व्यापार चक्र के रूप व्यापार चक्र की अवस्थाएँ समृद्धि अवस्था मन्नी अवस्था मदी अवस्था चतना अवस्था व्यापार चक्र नियन्त्रण सम्बन्धी नीति निष्पत्त परीक्षा-प्रश्न ।

"There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital You are only half educated if your understand the one while being ignorant of the other " —Samuelson

अध्याय 1

## समष्टि अर्थशास्त्र

(MACRO ECONOMICS)

वर्तमान समय में अर्थशास्त्रीय अध्ययन को प्रमुख रूप से व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में बाँटा जाता है। वर्ष 1933 में इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग ओमनो विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर रेनर फ्रिच (Prof Raenar Frisch) ने किया था। वर्तमान समय में आर्थिक विश्लेषण के यह शब्द अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का आशय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की छोटी अथवा लघु इकाइयों में होता है। दूसरी ओर समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र का आशय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इसके बड़े-बड़े समूहों जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार कुल उपभाग, कुल विनियोग कुल बचत, सामान्य कीमत स्तर आदि से होता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय, व्यापार चक्र राजस्व बैकिंग आदि बहुत से ऐसे विषय हैं जो समष्टि अथवा व्यापक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत आते हैं।

### व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र

(Micro Economies)

व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं जैसे एक फर्म एक उद्योग, एक व्यक्ति एक परिवार आदि। इनके अन्तर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति की स्थिति क्या है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति अपनी आय किस प्रकार अर्जित और व्यय करता है, एक फर्म किस प्रकार से सामर्थ्य की स्थिति को प्राप्त करती है एक उद्योग की उद्योग में रोजगार, उत्पादन तथा विप्रेषण आदि की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत या लघु इकाइयों के संगठन, स्वरूप एक उनके व्यवहार से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करते हैं। इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय संतुलन स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम कीमत विश्लेषण में एक उत्पादन या साधन की कीमत का अध्ययन करते हैं न कि सामान्य कीमत स्तर का। इसी प्रकार भूमि विश्लेषण में हम एक व्यक्ति- एक फर्म एक परिवार तथा एक उद्योग की माँग का अध्ययन करते हैं सामूहिक अथवा समुदाय विशेष की माँग का अध्ययन नहीं करते। आय विश्लेषण में हम एक व्यक्ति एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग की आय का अध्ययन करते हैं सम्पूर्ण या समुदाय की कुल आय का अध्ययन नहीं करते।

सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में हम पूर्ण रोजगार की मान्यता मानते हुए इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता या एक उत्पादक गार्ह्य की स्थिति को कैसे प्राप्त करता है। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है इसमें भी समूहों का अध्ययन किया जाता है परन्तु यह समूह उन समूहों में भिन्न होते हैं जिनका सम्बन्ध ममष्टि अर्थशास्त्र से होता है।

### व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ (Definitions of Micro Economics)

प्रो० वे० ई० बोल्डिंग के अनुसार—

सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशेष फर्मों विशेष परिवारों व्यक्तिगत कीमती मजदूरी आय, व्यक्तिगत उद्योग तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है।<sup>1</sup>

प्रो० हैण्डरसन तथा क्वॉंट के शब्दों में—

व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तथा ठीक से परिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है।<sup>2</sup>

प्रो० एफ० एस० बोरोमैन के अनुसार—

व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु से सम्बन्धित बाजार की माय प्रणाली तथा व्यक्तिगत श्रेता तथा विप्रेता के व्यवहार की व्याख्या की जाती है।<sup>3</sup>

### व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र (Scope of Micro Economics)

यह हम पहले ही बना चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं।

उपभाग के अन्तर्गत व्यक्तिगत व्यवहार से सम्बन्धित नियम घटती हुई सीमांत उपयोगिता — नियम तथा सम-सीमांत उपयोगिता नियम (Law of Diminishing Marginal Utility and Law of Equi-marginal Utility) व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की नियम-वस्तु हैं। मोट तौर पर हम कह सकते हैं कि सीमांत विश्लेषण से सम्बन्धित जो भी आर्थिक नियम हैं वह सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन के विषय-क्षेत्र में आते हैं। एक

1 "Micro Economics is the study of particular firms Particular house hold individual prices, wages, income, individual industries and particular commodities" —K E Boulding

2 "Micro Economics is the study of economic actions of individuals and well defined group of individuals." —Handerson and Quandt

3 "Micro Economics seeks to explain the working of markets for individual commodity and the behaviour of individual buyer and seller." —F. S. Boroman

व्यक्ति के पास जैसे-जैसे किमी वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं उनमें प्राप्त उपयोगिता या मनुष्टि का स्तर उन्नततर गिरता जाता है इसी प्रकार एक उपभोक्ता अपने सीमित माधनों से अधिकतम मनुष्टि का स्तर कैसे प्राप्त करेगा आदि का अध्ययन प्रथम घटती हुई सीमान्त उपयोगिता नियम तथा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के उदाहरण हैं तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री है। एक उपभोक्ता की भाँति एक उत्पादक भी अपने सीमित माधनों से अधिकतम लाभ तभी प्राप्त करेगा जबकि प्रत्येक माधन से प्राप्त सीमांत उत्पादनमा तथा उम माधन पर किया गया व्यय दोनों बराबर नहीं हो जाते जैसा कि प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में एक फर्म तथा एक उद्योग की उत्पादन तथा मूल्य सम्बन्धी नीति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आता है। विनियम के क्षेत्र में एक वस्तु की कीमत निर्धारण तथा एक बाजार विशेष से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन तथा वितरण के क्षेत्र में उत्पादित के प्रत्येक माधन का पारिधमिक आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययन कहलायेगा।

### व्यष्टि अर्थशास्त्र का लाभ एवं महत्व (Advantages & Importance of Micro Economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक रूप धारण के समय से ही प्रारम्भ हो चुका है। इसका उपयोग विभिन्न आर्थिक नियमों के निर्माण तथा सिद्धान्तों के विवेचन हेतु किया गया है। ममष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आजकाल बहुत बढ़ गया है फिर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व विन्दुल गमाप्त नहीं हुआ है। इसका महत्व निम्न बातों से पता चलता है -

(1) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने हेतु—मूहम अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। जैसे हम देश के सामान्य कीमत स्तर (General Price Level) को समझने के लिए व्यक्तिगत कीमतों का भी अध्ययन करना होगा। ठीक इसी प्रकार से देश की कुल राष्ट्रीय आय को समझने के लिए व्यक्तिगत आय का अध्ययन जरूरी है।

(2) वस्तु के मूल्य निर्धारण में सहायक—व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है एक उत्पादित के माधन का पुरस्कार कैसे निश्चित होना है आदि। एक वस्तु के मूल्य निर्धारण तथा एक माधन की कीमत निर्धारण के अध्ययन में हम माँग और पूर्ति की शक्तियों का अध्ययन करते हैं अर्थात् कीमत निर्धारण माँग और पूर्ति के मनुष्टि द्वारा होता है। त्रिम बिन्दु पर माँग और पूर्ति साम्य की स्थिति में होगी वही पर माधन या वस्तु की कीमत निश्चिन होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक उत्पादक एक माधन को जो कीमत देता है वह उम माधन की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निश्चित होती है। इसी प्रकार एक वस्तु की कीमत सीमान्त आमद तथा सीमान्त लागत (MR तथा MC) के बराबर होने के बिन्दु पर निश्चिन होगी।

(3) आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक—व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। जब सरकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है तो इसके प्रभाव को माधनों के वितरण, व्यक्तिगत कीमतों, आयों तथा मजदूरियों पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि सरकार की नीतियाँ समाज के निम्न वर्ग के विरुद्ध हों, तो तुरन्त उनमें सुधार करते उनको पुनर्निर्मित किया जाता है। देश का वित्त मंत्री जब करारोपण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि बंटों का बोझ समाज के नीचे या कम आय वाले वर्ग पर कम से कम रहे।

(4) व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायक—  
 व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति एक एक एक परिवार तथा एक उद्योग आदि का आर्थिक व्यवहार कैसा होगा। जैसे एक उत्पादक का यही प्रयत्न रहेगा कि वह न्यूनतम लागत मयों पर उत्पादन के विभिन्न माध्यमों को आदर्श अनुपात में समाकर अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। उसी प्रकार एक उपभोक्ता को अपने मौज्जा माध्यमों में अधिकतम मनुष्यता तभी मिलेगी जबकि विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली अन्तिम इकाइया में उसे मौज्जा उपयोगिता बराबर मिले। यदि उपभोक्ता को व्यवहार इस प्रकार का न होगा तो वह अधिकतम मनुष्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें व्यक्तिगत उपभोग बचत आय, विनियोग आदि की जानकारी देकर उनके आर्थिक व्यवहार में निर्णय लेने में सहायता करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कर्मों तथा उद्योगों की राय प्रणाली, उनकी समस्याओं तथा इनमें निपटने हेतु समाधानों का अध्ययन भी करता है।

(5) आर्थिक कल्याण में सहायक - आर्थिक कल्याण की जानकारी प्राप्त करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। सबसे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण के मापन हेतु व्यष्टि आर्थिक विवरण का महत्त्व दिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन जैसे बचत उपभोग आय विनियोग आदि के माय-माय मावज्जा व व्यय तथा मावज्जा आय का समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी मिलती है। यदि मावज्जा व्यय ने होने वाले लाभ मावज्जा आय में होने वाले बाँटों की तुलना में अधिक है तो निश्चित रूप में यह समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक होगा यदि स्थिति इसके विपरीत होगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ने की अपेक्षा निश्चित रूप में कम होगा।

### व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitations of Micro Economics)

जहाँ एक आर्थिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है वहाँ उसकी कुछ कमियाँ या सीमाएँ भी हैं जैसे—

(1) व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता—  
 व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। वही यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण की रचना व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा होती है परन्तु इनमें हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र नहीं मिलता। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने ही हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सही प्रकार में समझा सकत हैं। इसलिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए अपर्याप्त मानित होता है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों तक सीमित रहता है जो गुरुचित्त होता है।

(2) व्यष्टि अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होते—

प्रायः यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण को बनाने वाली व्यक्तिगत इकाइयाँ ही हैं इसलिए जो निष्कर्ष एक व्यक्तिगत इकाई के लिए उचित हैं वह सम्पूर्ण के लिए सच ही उचित समझने चाहिये। यह तथ्य धारक है कि जो बात व्यक्तिगत दृष्टिकोण में सही हो वह सम्पूर्ण के लिए भी सही ही हो जैसे बचत करने उसका विनियोग न करना एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा कहा जाएगा परन्तु यदि सभी बचतकर्त्ताओं का व्यवहार ऐसा होगा तो इससे बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आ जायेंगी क्योंकि हममें कुन समर्थ भाग में कमी मिलेगी परिणामस्वरूप कुन उत्पादन, कुन रोजगार तथा कुन आय का स्तर गिरेगा।

(factors) की व्याख्या की तथा अर्थव्यवस्था का मदी म उवाग्न हतु ठोम मुनाव दिग । कीन्म ने यह मिद्ध किया कि राष्ट्रीय आर्थिक समस्याआ क समानान समष्टि आर्थिक विश्लेषण म खाजने चाहिए । कीन्म क अतिरिक्त प्रो० वानरम प्रो० णीगू विकमीन प्रा० किशर तथा अन्य बहुत स विद्वाना न समष्टि अर्थशास्त्र क विवाम म महत्वपूण यागदान दिया ।

### समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ (Definitions of Macro Economics)

समष्टि अर्थशास्त्र म हम सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था या उमम मम्बन्धित औमता तथा समूहा का अध्ययन करत है । कुल माँग कुन पूति कुन उत्पादन कुन राष्ट्रीय आय कुन वचत कुन विनियोग सामान्य कीमत स्तर कुन राजगार आदि का अध्ययन करत है । समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएँ निम्नवत हैं —

प्रो० के० ई० बोल्डिंग के अनुसार —

समष्टि परक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राआ का अध्ययन नही करता वरन् इन मात्राआ क समूहा का अध्ययन करता है व्यक्तिगत आय का नही वरन राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत कीमता का नही वरन सामान्य कीमत स्तर का व्यक्तिगत उत्पादन का नही वरन राष्ट्रीय उत्पादन का ।<sup>1</sup>

प्रो० गार्डनर ऐक्ले के शब्दों मे -

समष्टि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध एक अर्थव्यवस्था म उत्पादन का समस्त मात्रा जैग चरा माधना का किम सीमा तक प्रयाग किया जा रहा है राष्ट्रीय आय क आकार तथा सामान्य कीमत-स्तर स है ।<sup>2</sup>

प्रो० शेपीरो के अनुसार -

समष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का काय प्रणाला स सम्बन्धित हाता है ।<sup>3</sup>

### समष्टि अर्थशास्त्र के लाभ एव महत्व (Advantages & Importance of Macro Economics)

वतमान समय म समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है । आज दुनिया क मनी दश अपना प्रगति और विकास म लग हुए है । आर्थिक विश्लेषण क बहुत स महत्वपूण विषया जैम पूण राजगार सामान्य कीमत-स्तर राष्ट्रीय आय कुन उत्पादन कुन

1. 'Macro Economics deals not with individual quantities as such but with the aggregates of these quantities not with individual incomes but with national income not with individual prices but with price level not with individual output but with the national output' — K E Boulding
2. 'Macro Economics concerns with such variables as the aggregate volume of the output of an economy with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level' — Gardner Ackley
3. 'Macro Economics deals with functioning of the economy as a whole' — Shepiro

बचत कुल विनिमय विदेशी विनिमय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मौलिक तथा राजकाषीय नीति भुगतान स तुषन राजस्व औद्योगिक नीति व्यापार चक्र आर्थिक नियोजन धाकित आदि का अध्ययन समष्टि आर्थिक विश्लेषण की विषय-वस्तु हैं। किसी देश के विकास के लिए इन विषयों के अध्ययन एवं उनके माग में आने वाली पठितनाइय का अध्ययन एवं मुशाव आदि के लिए समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता होत है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एक साधो को निम्न तथ्यों के आधार पर आवा जा सकता है—

(1) सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका— वर्तमान युग में सावजनिक कर््यों में विस्तार हुआ है और सरकार की जनता के कल्याण की विभिन्न योजनाएँ चालू करनी पडती है। सरकार समष्टिगत तत्त्वा का सहायता से विभिन्न आर्थिक योजनाओं का निर्माण करती है जो अग चलकर देश के रोजगार आय उत्पत्ति का मात्रा विनियोग उपभोग वचत के स्तर को निर्धारित करत ह। अव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर सरकार समष्टिगत नीतिया बनाती है।

(2) देश के आर्थिक विकास की जानकारी में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व—किसा भी देश के आर्थिक विकास की जानकारी के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन अथवा व्यापक चरों को निर्धारित करने वाले तथ्यों का अध्ययन करना पडत है। राष्ट्रीय विकास को निमित्त करने वाले तथ्यों का अध्ययन करके ही देश की विकासात्मक स्थिति का अध्ययन सम्भव हो सकता है। विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण आधार है। देश मत्कीतिक अथवा अवस्कीतिक जानकारी हेतु हमें सामान्य शीमत-स्तर का प्रयोग करना पडता है जो हमें समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन स प्राप्त होता है।

(3) समष्टिगत मात्राओं का प्रथक से अध्ययन करना अनिवार्य होता है—समष्टि गत मात्राओं का अपनी एक पृथक विशेषता होती है जिसके कारण इनका पृथक स अध्ययन अनिवार्य होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आवश्यक परिवर्तन हाते रहत है तथा उसका अस्तित्व बना रहता है जैसा कि अव्यवस्था में पुराने उद्योगों का स्थान नय उद्योग लेने रहते हैं तथा अव्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है।

(4) दृष्टि अर्थशास्त्र की व्याख्या के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है—विनी साधन की मजदूरी निर्धारित करने हेतु एग सम्पूर्ण अव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी व्यवस्था का अध्ययन करणा होगा। उदाहरणार्थ जब सामान्य कीमत स्तर सूचकांक बढ रहा हो तो हमें एक साधन विशेष की मजदूरी वढानी होगी। इसका आशय यह है कि किसी कम या साधन विशेष की मजदूरी पर दश व सामान्य कीमत स्तर का प्रभाव पडता है। अर्थात् व्यापक अर्थशास्त्र क अध्ययन क लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र व अध्ययन की आवश्यकता होती है।

( ) आर्थिक समस्याओं का समाधान समष्टिपरक अर्थशास्त्र व अध्ययन स अर्थशास्त्री को आर्थिक समस्यार्थ। से समाधान स काफी सहायता मिलता है।

(6) सामान्य रोजगार की प्राप्ति में सहायक—वर्तमान कल्याणदारा राज्या व सम्मुख बेरोजगारी की भ्रंषण समस्या है और सभी इसके समाधान के लिए प्रयत्नारत है। पूर्ण रोजगार अथवा अधिनतम रोजगार की प्राप्ति वर्तमान समष्टि आर्थिक विनियोग व माध्यम से हो सकती है। इस प्रकार सामान्य रोजगार की प्राप्ति की निशा में समष्टिपरक अर्थशास्त्र सहायक हो सकता है।

(7) विकास सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में सहायक— समष्टिपरक अर्थशास्त्र ने राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाओं जैसे विषयों के अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाया है। इनके द्वारा हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण ने अर्द्ध-विकसित देशों की विकास सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन और इनके निराकरण को सम्भव बनाया है।

### आर्थिक समष्टिभाव की सीमाएँ एवं दोष

#### (Limitations and Disadvantages of Macro Economics)

आर्थिक समष्टिभाव के लाभ के अलावा इसके कुछ प्रमुख दोष एवं सीमाएँ निम्न प्रकार हैं —

(1) व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के लिए अपर्याप्त समष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल समूह। अंशतो अथवा कुल का अध्ययन किया जाता है और इगम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है। जब कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थव्यवस्था में जरूरी होता है जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अन्तर्गत नहीं होता। इस प्रकार समष्टिगत अर्थशास्त्र अधूरा है।

(2) भ्रामक स्थिति का परिचायक— समष्टिगत अर्थशास्त्र का आधार मानकर जा नीतियाँ बनाई जाती हैं वह कभी-कभी भ्रामक परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरणार्थ यदि देश का कीमत स्तर सामान्य है तो इससे यह अनुमान लगाना गलत होगा कि सभी वस्तुओं की कीमतों में सामान्य स्थिति हो कुछ की कीमतें बढ़ रही होंगी तो कुछ की गिर रही होंगी।

(3) समष्टिगत मात्राओं की प्रगति में असुविधा— जब व्यक्तिगत मात्राओं का योग द्वारा समष्टिगत मात्राओं को प्राप्त किया जाता है तो वह उपयुक्त नहीं हो सकता। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में व्यक्त करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन होता है। यदि अनुमन्धातवर्ती का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो तो भी निष्कर्ष नहीं होंगे। इस प्रकार समष्टिगत मात्राओं का गही अनुमान लगाने में अनेक कठिनाइयों का अनुभव होता है।

### व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर

#### (Distinction between Micro and Macro Economics)

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर निम्न प्रकार में देखा जा सकता है —

(1) व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी-छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग आदि। जब कि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग अर्थात् राष्ट्रीय योगों का अध्ययन करता है जैसे कुल राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन कुल बचत, कुल उपभोग तथा कुल रोजगार आदि।

(2) व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के मूल अथवा एक भाग में सम्बन्धित होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है।

(3) व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को तोड़ने की प्रिया (Disaggregation) को आधार माना जाता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की प्रिया (aggregation) होता है।

(4) व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धान्त का विश्लेषण करना होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय तथा रोजगार होता है।



(5) व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, आय तथा उत्पादन के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील मानता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इन्हें स्थिर मानता है।

(6) व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण के लिए दी हुई परिस्थितियाँ की मान्यता पर आधारित है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य मन्तुलन के आधार पर कुल कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करता है।

(7) व्यष्टि तथा समष्टि का अन्तर आर्थिक विरोधाभास (Paradoxes) के कारण भी जरूरी हो जाता है। कुछ निष्कर्ष जब एक व्यक्तिगत इकाई पर लागू किए जायें तो उचित प्रतीत होते हैं। परन्तु जब उन्हें समस्त अर्थव्यवस्था पर लागू किया जाये तो अनुचित होता है। जैसे यदि एक जमाकर्ता बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल ले तो वह अनुचित नहीं कहलायेगा। परन्तु सभी जमा बर्ताओं का व्यवहार ऐसा होगा तो बैंक फेल हो जायेंगे। यह आर्थिक विरोधाभास का उदाहरण है।

(8) समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्तर को जगल का उदाहरण देकर प्रो० बोल्डिंग (Prof Boulding) ने समझाया है। समष्टि अर्थशास्त्र यदि एक जगल का अध्ययन है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पेड़ का अध्ययन मात्र है।

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसका कारण यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी समूहों का अध्ययन किया जाता है परन्तु यह समूह उन समूहों से अलग होते हैं जिनका सम्बन्ध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग की वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन तथा रोजगार सम्बन्धी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग बहुत सी फर्मों का समूह होता है जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार माँग और पूर्ति की परस्पर क्रियाओं द्वारा एक वस्तु की कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। किसी वस्तु की बाजार माँग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की माँग का योग होती है।

हमें यहाँ यह बात ध्यान रखना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में जिन समूहों का अध्ययन होता है वे भिन्न प्रकृति के होते हैं। उदाहरणार्थ समष्टि अर्थशास्त्र उन समूहों की व्याख्या करता है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। हमें अर्थशास्त्र के बड़े समूहों एवं उनमें उप समूहों की व्याख्या की जाती है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के समूहों से भिन्न होते हैं।

प्रोफेसर गाडनर एकले के विचार इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं वे कहते हैं, 'समष्टिपरक अर्थशास्त्र में भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से छोटे समूहों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इनकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के उप-विभाग बन जाते हैं। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र भी समूहों का प्रयोग करता है परन्तु पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के सन्दर्भ में नहीं।

व्यष्टि तथा समष्टि के बीच स्पष्ट विभाजन रखा सोचना उपयुक्त नहीं है। व्यष्टि चर (Micro Variables) समष्टि का रूप ले सकते हैं और समष्टि चर (Macro Variables) व्यष्टि की परिधि में पहुँच सकता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों में भावधानीपूर्वक अन्तर करना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के एक भाग से तथा समष्टि अर्थशास्त्र में योगों का सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है। इन दोनों में अन्तर उनकी विषय सामग्री का नहीं बरन् इन दोनों हेतु प्रयोग की जाने वाली रीति का होता है।

## व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है

(Micro and Macro Economics are Complimentary to each Other)

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र व उपर्युक्त अन्तर व आधार पर हम इन दोनों का एक दूसरे का प्रतिपादन नहीं समझना चाहिए वरन् यह तो एक दूसरे व पूरक है क्योंकि एक को समझने व लिए दूसरे की आवश्यकता होता है। यह बात निम्न तथ्या से साबित होती है —

(1) व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता—

(1) बाजार में एक वस्तु का कीमत व वस्तु उभर वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर नहीं करता वरन् इसका मूल्य सम्बन्धित वस्तुओं का मांग और पूर्ति द्वारा भी प्रभावित होता है।

(2) उत्पत्ति व एक साधन का कामत या पुनर्स्कार का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। परन्तु यह पुनर्स्कार अर्थ में जो का सा जान यात्री मजदूरियाँ पर निर्भर करेगा।

(3) एक फर्म का उत्पादन नाति क्या है इसका लिए फर्म व उत्पादक का अपना वस्तु के लिए समाज का कुल मांग तथा देश में व्याप्त आय एवं राजस्व व स्तर का भी देखना होगा।

(II) समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता—

(1) समाज में एक उद्योग का रूप प्राण करता है तथा सब उद्योग सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

(2) समाज व्यक्तियों का समूह होता है इस प्रकार समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं।

(3) राष्ट्रीय आय का गणना का आधार व्यक्तिगत आय भा होता है अर्थात् तब तक राष्ट्रीय आय का गणना नहीं हो सकती जब तक व्यक्तिगत आय या उत्पादक व उत्पादन को जाँच न लिया जाए।

(4) समाज में आर्थिक क्रियाओं का स्तर उपभाग का मात्रा कुल उत्पादन कुल बचत कुल विनियोग कुल राजस्व आदि का मात्रा अनिश्चित फर्मों व निषया व कारण दिखाने देता है।

निष्कर्ष—व्यष्टि तथा समष्टि दोनों ही एक दूसरे व लिए जरूरी हैं। प्रा० सैम्यु-एलसन ने दोनों का महत्त्व व वतावट हुए कहा है कि 'दाम्भिक व व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही आवश्यक हैं। यदि आप एक का समझते हैं तथा दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप कब तक अर्थ शिक्षित हैं।

"There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital You are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other —Samuelson

### परीक्षा-प्रश्न

1 व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर बताइए। इन दोनों का मध्य क्या सम्बन्ध है ?

(Distinguish between Micro and Macro Economics What is the relationship between the two ?)

- 2 समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसके महत्व प्रकृति तथा सीमाओं को बताए।

(Define Macro Economics Discuss its importance nature and limitations)

- 3 सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र के बीच अन्तर स्पष्ट काजिए तथा आर्थिक विश्लेषण में समष्टि दृष्टिकोण की आवश्यकता बताइए।

(Distinguish between Micro and Macro Economics and explain the need of macro approach in economic analysis)

4 वास्तव में सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही आवश्यक हैं। यदि आप एक का समझते हैं तथा दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध-शिक्षित हैं। संयुक्त रूप से इस कथन को व्याख्या कीजिए।

(There is really no opposition between Micro and Macro Economics Both are absolutely vital You are only half educated if you understand the one while being ignorant of the other Discuss this statement)

—Samuelson

[संकेत—यह कथन अर्थशास्त्री प्रो० संयुक्त का है। दोनों की परिभाषा तथा सीमाएँ दीजिए। फिर दोनों के बीच विरोधाभास की चर्चा काजिए। अतः वे बताइए कि फिर भी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।]

5 टिप्पणी लिखिए—

व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र

(Write notes on Micro and Macro Economics)

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है और कौन-सा गलत है —

- (i) माइक्रो अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है।
- (ii) मैक्रो अर्थशास्त्र का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था तथा उससे सम्बन्धित योगों से होता है।
- (iii) समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया (aggregation) है जब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग तोड़ने की क्रिया (Disaggregation) है।
- (iv) समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियाँ व निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- (v) माइक्रो अर्थशास्त्र व अन्तर्गत द्रव्य तथा वित्त का अध्ययन होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) सही है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) गलत है।

National income is the net output of commodities and services flowing during the year from country's productive system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods ' — Simon Kuznets

## अध्याय 2

### राष्ट्रीय आय

(NATIONAL INCOME)

राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अवशास्त्राव अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय आय से हमारा ज्ञान किसे राष्ट्र की एक वष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का कुछ राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि शब्दों में व्यक्त करने का चयन बढ़ गया है। राष्ट्रीय आय का कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार से दी गई हैं—

राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ (Definitions of National Income)—

प्रा० माशन का परिभाषा

प्रा० माशन के शब्दों में — 'एक देश में प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूँजी द्वारा कार्य करने पर प्रत्येक वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन होता है। यही शुद्ध वार्षिक आय अथवा देश का आगत अथवा राष्ट्रीय आभाष है।'<sup>1</sup>

प्रा० माशन की परिभाषा में ज्ञात होता है कि देश की उत्पादक क्रियाओं द्वारा प्राप्त शुद्ध उत्पादन का जोड़ किया जाए तो हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति का पता चल जाएगा। कुल उत्पादन में ग मशीनों का घिसावट का घटाकर निरक्षण में प्राप्त शुद्ध आय का राष्ट्रीय उत्पत्ति में जोड़ देना चाहिए।

आलोचना— प्रा० माशन की परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टि से अच्छी लगने व ठाम मान्य पवती है परन्तु इसमें प्रमुख दोष निम्नवत् हैं —

(1) देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनकी कीमती का जोड़ पाना एक कठिन कार्य है।

(2) कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिनका सम्बन्ध मात्रा बाजार में प्रिकन व लिए नहीं आता। एक उत्पादक या निमाता वस्तु का कुछ मात्रा का अपन उपयोग व लिए अपन पास रखेता है जिसका मौद्रिक मूल्य ज्ञान करना कठिन होता है।

1 The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial including services of all kinds. Thus is true net annual income or revenue of the country or the national dividend

—Marshall

(3) मार्शल के विचारानुसार यदि देश के कुल उत्पादन की गणना की जाएगी तो कुछ वस्तुओं को दो बार गिनने की सम्भावना बनी रहेगी।

प्र० पीगू की परिभाषा—प्र० पीगू के अनुसार

राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का जिनमें नि सन्देह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है वह भाग है जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है।<sup>1</sup>

प्र० पीगू के उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ शामिल की जानी चाहिए जिनको हम मुद्रा रूपी पैमाने में नाप सकते हैं। प्र० पीगू की परिभाषा को प्र० मार्शल की परिभाषा के ऊपर एक मुद्धार माना जाता है। इसे अधिक व्यवहारिक सरल और निश्चित माना जाता है।

आलोचना— प्र० पीगू की परिभाषा भी दोष मुक्त नहीं है निम्न तथ्या के आधार पर इसकी आलोचनाएँ की जाती है।

(1) प्र० पीगू की परिभाषा बहुत अधिक संकुचित है। पीगू ने राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया है जिनका वर्ष में न केवल उत्पादन हो बरन जिनको मुद्रा में मापा भी जा सकता है। वस्तुओं का एक ऐसा समूह भी होता है जिसका विनिमय नहीं होता जबकि इन वस्तुओं का सामाजिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में न जोड़ना वहाँ तक उचित है।

(2) प्र० पीगू की परिभाषा के अनुसार अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता जिनका आदान प्रदान वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत होता है। इनकी परिभाषा अर्द्ध-विकसित देशों के लिए नहीं बरन विकसित देशों के लिए सही हो सकती है।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को अपने उपभोग के लिये रख लेने पर उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जायगा। इसी प्रकार अवैतनिक कर्मचारियों की सेवाओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जायगा। यह सारी बातें असंगतिपूर्ण हैं।

प्र० फिशर की परिभाषा—प्र० फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभाश या आय में केवल अन्तिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक पर्यावरण से हुई हो या मानवीय पर्यावरण से को शामिल किया जाता है। इस प्रकार एक वियाना अथवा एक जावर बोट जा मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, मेरी इस वर्ष की आय का अंश न हाकर रूँजी में वृद्धि मात्र है। केवल इन वर्ष में इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए की गई सेवाएँ ही इस वर्ष की आय हैं।<sup>2</sup>

1 'National dividend is that part of objective income of the community including of course income derived from abroad which can be measured in money.  
—Pigou

2 "National dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers whether from their material or from their human environment Thus a piano or an overcoat made for me this year is not a part this year's national income but an addition to capital only the services rendered me during this year by these things are income."  
—Irving Fisher

प्रो० पिशर न राष्ट्रीय आय में केवल उन्ही सेवाओं को शामिल किया है जो उप-भोक्ता का एक अवधि विशेष में प्राप्त होती है। उनके अनुसार बहुत सी वस्तुएँ अधिक टिकाऊ होती हैं जिनका उपयोग लगातार चलता रहता है। जब हम एक वर्ष विशेष को राष्ट्रीय आय का ले तो हम उमर उमर वर्ष विशेष में अमुक वस्तु का उपयोग मूल्य को ही लेना चाहिए। प्रा० पिशर की परिभाषा आर्थिक कयाण की दृष्टि में उपयोगी ता है परन्तु यह भी दोष मुक्त नहीं है।

आलोचना—प्रो० पिशर की परिभाषा की आलोचनाएँ निम्नलिखित बातों के आधार पर की जाती हैं

(1) यह जानना अत्यन्त कठिन है कि अमुक वर्ष में अमुक वस्तु का कितना उपयोग हुआ है।

(2) किसी वर्ष को राष्ट्रीय आय को जानने के लिये पिछले वर्षों में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं का उन भागों की कीमतें मान ली जाती होंगी जिनका उमर वर्ष में उपयोग हुआ है।

(3) टिकाऊ वस्तुओं का हस्तांतरण इस प्रकार हो सकता है कि अन्तिम स्वामी ने वस्तु के प्रारम्भिक स्वामी का कोई सम्बन्ध ही न रहे तथा यह पता ही न चल सके कि वस्तु का निर्माण कब हुआ था।

राष्ट्रीय आय की बीन्स धारणा—प्रो० बीन्स प्रा० मार्श, पीगू तथा पिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में महत्त्व नहीं है। उन्होंने कहा कि इन विद्वानों ने राष्ट्रीय आय में उन तत्वों की व्याख्या नहीं की थी जो अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत कर मा। प्रो० बीन्स ने बताया कि राष्ट्रीय आय की धारणा कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच की धारणा है। प्रा० बीन्स कहते हैं राष्ट्रीय आय को जानने के लिए मर्मा मूल्य हानि (Depreciation) तथा अप्रचलन का राष्ट्रीय आय में से नहीं घटा देना चाहिए बल्कि इसमें से केवल प्रयोगकर्ता लागत (users cost) को ही घटाना चाहिए। प्रयोगकर्ता लागत = माल-मरणा के लिए प्रयोग किए जाने पर मूल्य हानि—मूल्य में कमी जब इसे प्रयोग में न लाया जाए—अनुसंधान व्यय। इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कि हम मशीन का उद्योग में लगाने हैं तो उसकी कीमत 1500 रुपये है परन्तु जब उसको काम में लाया जाए तो उसकी कीमत 1000 रुपये रह जाती है अर्थात् मशीन को प्रयोग में लाने पर उसकी कीमत में 500 रुपये मूल्य का हानि हो गया। यदि हम मशीन को प्रयोग में नहीं लाया जाता तो हमारे मूल्य में थोड़ी सी गिरावट आती क्योंकि हमारे मशीन में थोड़ी जग आदि खर्च जाती और इसकी सफाई आदि में यदि 50 रुपये का व्यय होता तो हम अनुसंधान व्यय (Maintenance cost or expenditure) कहा जाएगा। इस प्रकार प्रयोगकर्ता लागत 500 रुपये—मशीन के प्रयोग न करने की स्थिति में 200 रुपये मूल्य में कमी हो जाती है + 50 रुपये का अनुसंधान व्यय हो तो प्रयोगकर्ता लागत 500—250 = 250 रुपये होगी। प्रो० बीन्स कहते हैं कि प्रयोगकर्ता लागत को घटाकर अर्थव्यवस्था में किसी अवधि विशेष को राष्ट्रीय आय निकालना चाहिए। प्रो० बीन्स के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय का जानने का निम्न सूत्र है—

$$\text{शुद्ध राष्ट्रीय आय} = A - U - V$$

A = कुल राष्ट्रीय आय

U = प्रयोगकर्ता लागत

V = पूरक लागत

V—पूरक लागत से आशय उस लागत से हाता है जा अनिश्चित हाती है। इस प्रकार के व्यय अनियन्त्रित तथा अनीच्छित होते है। जैसे अप्रचलन व्यय मशीना का पुराना पड जाना आदि

राष्ट्रीय आय की कुछ अन्य परिभाषाएँ— प्रो० बीन्स के बाद राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा परिभाषाएँ दी गई है जिन्हें हम राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषाएँ भी कह सकते है।

प्रो० सैम्युलसन के शब्दों में— राष्ट्रीय आय अथवा उत्पाद वह अंतिम सरया है जिसे आप विविध वस्तुआ सेवा सन्तार तथा मशीना जिहे कोई समाज उपलब्ध भूमि धम तथा पूंजीगत साधनों से उत्पादित करता है का मौद्रिक माप देने पर प्राप्त किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (Indian National Income Committee) के अनुसार— राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय में वस्तुओं तथा सेवाओं का माप है। इसमें देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है चाहे उसका सम्बंध जूती तथा जहाजों के निर्माण से हो अथवा चिकित्सालय या न्यायालय सम्बंधी सवायें प्रदान करने से हो।

प्रो० सराइमन कुजनेटस के शब्दों में— राष्ट्रीय आय वस्तुआ तथा सेवाओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के पास पहुँचती है अथवा देश के पूजागत वस्तुओं का स्टॉक में विशुद्ध रूप से वृद्धि करती है।

राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय की व्याख्या प्रमुख रूप से तीन प्रकार से हो सकती है—

- (1) प्राप्तियों की कुल मात्रा की दृष्टि से
- (2) व्यय की कुल मात्राओं की दृष्टि से
- (3) उत्पादित मात्रा के कुल मूल्य की दृष्टि से।

### राष्ट्रीय आय की अन्य धारणाएँ (Other Concepts of National Income)

राष्ट्रीय आय की कुछ प्रमुख धारणाएँ निम्न प्रकार से हैं—

(1) कुल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product—GNP) एक वर्ष की अवधि में जो भी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पादित की जाती है उन सभी के बाजार मूल्य को कुल राष्ट्रीय आय कहा जायगा। इस धारणा की दो प्रमुख बातें हैं—प्रथम तो यह कि एक वर्ष भर में उत्पादित वस्तुआ को मुद्रा के मूल्य में जोड़ा जाता है दूसरे यह कि कुल उत्पादन में केवल अंतिम परवुओं तथा सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। ऐसी गणना करते समय माध्यमिक वस्तुआ जैसे रई कच्चा चोहा आदि को शामिल नहीं करना चाहिये।

कुल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वस्तुआ तथा सेवाओं के उत्पादन में जो मशीन अथवा अचल पूंजी की घिसावट या मूल्य ह्रास हो इसे शामिल नहीं करना चाहिये। कुल राष्ट्रीय आय की यह धारणा राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयोग में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह विचार एक अवधि विशेष में उत्पादन तथा रोजगार सम्बन्धी दशाओं का एक विश्वस्तनीय सूचकांक है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह सरल धारणा है क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास को घटाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(2) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP) - कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं का जैम मशीन तथा यन्त्र आदि की धिमापट पर हानि का वान ध्यय का घटान पर जो कुछ बचता है उम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहत है। इम बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय (National Income at Market Prices) भी कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय की धारणा का विशेषता यह है कि यह चानू उपभाग एउ चानू प्रनिम्यापित निवेश क ऊपर कुल उत्पादन म वृद्धि का स्पष्ट करती है और आर्थिक विराग र निण पूंजी की उत्पादकता म हानि यात्री विशुद्ध वृद्धि का बतती है। इम गुण र कारण इमरा विवाग र अथशास्य (Economics of Growth) र निण विशेष महत्व है।

इम पद्धति की प्रमुग कठिनाई यह है कि एक समय विशेष म मूल्य ह्लाम का अनुमान वास्तविकता म काफी दूर हाता है। इमरा कारण यह है कि मूल्य ह्लाम की जानन मे निण माजगज्जा क कुल मूल्य म उमक जीवन अवधि र उर्षो म भाग दना हाता है। माजगज्जा र जीवन वान र वना वगाना स्वय कठिन है। इमक अतिरिक्त एउ वप विशेष म माजगज्जा की कीमत म वृद्धि हा जान पर यह समस्या और गम्भीर हा जाती है कि पुरानी कीमत पर या नई कीमत पर मूल्य ह्लाम निकाना जाय। यदि एक मशीन अपन अनुमानित जीवनवान क वान म ही अप्रचलित हा जाय ता मूल्य ह्लाम की समस्या और भी कठिनाई पैदा रर दर्ती है।

(3) साधन लागत पर राष्ट्रीय आय (National Income at Factor Cost) - एउ म कुल वस्तुओं तथा गवाआ रर उत्पादन उत्पादि र साधना क सामूहिक प्रयाग का परिणाम हाता है। इम प्रकार कुल उत्पादि का जो मोद्रिक मूल्य हाता है उम ही उत्पादि र विभिन्न साधना र शीत्र शीत्र दिया जाता है। उत्पादि र साधना न जितनी आय अर्जित की है जैस भूगर्भा न वगान ध्रमिक न मजदूरी पूंजीपति न व्याज साहगी न वाभ आदि प्राप्त किया है इम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाणगा। उत्पादि क विभिन्न साधना र। यह आय उनरा अपन साधन वगान पर प्राप्त हुई है।

साधन लागत पर राष्ट्रीय आय जानन क निण हम शुद्ध राष्ट्रीय आय म म अप्रत्यक्ष कर घटा दना चाहिए तथा मरगार द्वारा दा जान वानी आर्थिक महायता जाड दना चाहिए। इम एक सूत्र द्वारा भा व्यक्त कर मरत है।

साधन लागत पर राष्ट्रीय = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन - अप्रत्यक्ष कर + मरगार द्वारा दी जान वानी आर्थिक महायता

National Income at Factor Cost = Net National Product - Indirect Taxes + Subsidies

(4) वैयक्तिक आय (Personal Income) - यह वह कुल आय है जिम नागान न विभिन्न साधना म प्राप्त किया है। इमर अन्तगत मजदूरी तथा बतन वगान व्याज तथा वाभाश मय मजगार प्राप्त नागान की आय जैम रिगान डाक्टर दुरानदार आदि की आय रर शामिल किया जाता है। एउ रर का ममयापधि म उत्पादन क साधना द्वारा जा आय अर्जित क जाती है यह पूगी री पूरी उन्न नही मिलती इमरा कारण यह है कि इम म कई प्रकार की कर्तौतियाँ क जाती ह। उदाहरणार्थ एउ मयुक्त पूंजी कम्पनी क अग धारिया द्वारा जाय ता कुछ भाग कर र रूप म मरगार का द दिया जाता है। इगी प्रकार धर्मिता तथा अन्य बतन भागी क मधारिया का उन्न प्रदान की जाव वा री सामाजिक सुरक्षा मवाआ र उदन म नाममात्र का कर्तौतियाँ की जाती है। टीक इमी प्रकार उत्पादि क साधना का जिना उत्पादन काय किण हुए कुछ रकम प्राप्त हा जाती है जैम बुद्धाय रर पेंशन मजगारी भत्ता आदि। इम हस्तांतरण आय भी कहत है।



जब हमें राष्ट्रीय आय को ब्यक्तिक आय द्वारा मालूम करना हो तो हमें आय के उस भाग को जो बचाया तो गया है परन्तु उसकी वारतविक प्राप्त उत्पत्ति के साधन को नहीं हुई है घटा देना चाहिए, और वह रकम जो बिना बचाए प्राप्त हुई हो उसे जोड़ देना चाहिए।

**5 उपभोग्य आय (Disposable Income)**— एक व्यक्ति की अपनी समस्त आय पर पूरा अधिकार नहीं होता और न ही वह इसको पूरी तरह से इच्छानुसार व्यय, बचत या अन्य प्रकार से उपयोग कर सकता है। उसे अपनी आय में से आय कर सम्पत्ति कर् तथा बीमा सम्बन्धी कुछ शैतियाँ देना होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति के पास उपभोग्य आय वह मात्रा होती है जो व्यक्ति विशेष को आय में से सरकार को दिए जाने वाले करों या अन्य देनदारियों को देने के बाद बचती है। यह जरूरी नहीं है कि समस्त उपभोग्य आय को पूरी तरह उपभोग पर व्यय ही कर दिया जाए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति या परिवार अपनी उपभोग्य आय में से बचा लेता है। उपभोग्य आय को निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है

$$\text{उपभोग्य आय} = \text{उपभोग} + \text{बचत}$$

$$\text{Disposable Income} = \text{Consumption} + \text{Saving}$$

इस विचारधारा की विशेषता यह है कि एक व्यक्ति या परिवार की उपभोग्य आय क्या होगी। यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता कि सरकारी वित्तीय नीति कैसी है। यदि सरकार न अधिक कर लगा रखे है तो उपभोग्य आय कम रहेगी।

**6 वास्तविक आय (Real Income)** राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। परन्तु मुद्रा की क्रयशक्ति में कीमत-स्तर में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। यदि कीमत-स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और कीमत-स्तर गिरने का आणव्य मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने से लगाया जाना है। यदि हमें किसी विशेष समय-वधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय का पता लगाना है तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना चाहिए।

$$\text{वास्तविक आय स्थिर मुद्रा के रूप में} = \frac{\text{नकद आय वर्तमान मुद्रा में}}{\text{वर्तमान समय में सूचकांक}}$$

$$\text{Real Income in Terms of Constant Prices} = \frac{\text{Nominal income in Current money}}{\text{Price Index for Current Period}}$$

**राष्ट्रीय आय का माप (Measurement of National Income)**—राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में तीन प्रमुख विचारधाराओं का स्थान है। प्रथम कुल आय या प्राप्त, दूसरे कुल व्यय तथा तीसरे कुल उत्पादन का मूल्य, यह तीनों ही धारणाएँ इस तथ्य पर आधारित हैं कि एक समय में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आय होता है। इसी विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। जैसे (1) उत्पादन प्रणाली, (Product Method) (2) आय प्रणाली (Income Method) तथा (3) व्यय प्रणाली (Expenditure Method) इनको प्रत्येक रूप से निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है

(1) उत्पादन प्रणाली (Product Method) - इस विचारधारा को वस्तु सेवा प्रणाली (Commodity Service Method) भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादन के कुल मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है जैसे बित्री-स्वयं उपभोग; स्टॉक में वृद्धि।

सभी क्षेत्रों के कुल उत्पादित मूल्य को ज्ञात करने के बाद उसमें में अन्य उद्योगों या क्षेत्रों में खरीदे गए पदार्थों के मूल्य तथा उत्पादन पूंजी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है और इस प्रकार शुद्ध उत्पादन मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हुए विस्तृत उत्पादन के मूल्यों को जोड़कर तथा विदेशी व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय को जमा करने कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय आय के माप की यह विधि उन देशों में प्रयुक्त होती है, जहाँ राष्ट्रीय उत्पादन की गणना होती है तथा उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध होते हैं।

(2) आय प्रणाली (Income Method)— इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पत्ति के विभिन्न माधनों को प्राप्त होने वाली आय का जोड़कर राष्ट्रीय आय का निष्पत्ता जाता है। इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय निम्नलिखित समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए

(i) इनके अन्तर्गत हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ना चाहिए जैसे वृद्धायम्या में पेंशन तथा निर्धन लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि।

(ii) जिन सेवाओं के बदले में मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता उन सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना के समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) उत्पादक द्वारा जो सेवाएँ प्रदान की जा रही हों और यदि वे लागत का अर्थ है तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) मयुक्त पूंजी सम्पत्ती या अन्य फर्मों द्वारा जो धनराशि रिजर्व निधि में डाल दी जाती है उसे शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस धनराशि का वापस के रूप में वितरण नहीं होता है।

इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न माधनों के राष्ट्रीय आय में स उनके भाग या हिस्से का आसानी से पता चल जाता है और माधन विशेष की वार्षिक आर्थिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है।

(3) व्यय प्रणाली (Expenditure Method)— इस प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए व्यय को जोड़ा जाता है। एक देश में जितना उत्पादन हुआ है उसे बाजार मूल्यों पर खरीदने के लिए व्यय किया जाता है। जितनी भी आय होती है वह पूरी व्यय नहीं की जाती है, इसका एक भाग बचकर रख लिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जानने के लिए एक वर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय + कुल बचत को ज्ञात किया जाता है।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इन देशों में जहाँ व्यक्तिगत उपभोग या व्यय तथा बचत सम्बन्धी विवरणनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करना आसान नहीं है। इसलिए अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय को जानने के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। विकसित देशों में भी इससे इस अवगुण के कारण उसका उपयोग सीमित ही है।

### राष्ट्रीय आय की गणना की अन्य प्रणालियाँ (Other Methods of Measuring National Income)

4. सामाजिक लेखांकन प्रणाली (Method of Social Accounting)— पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए सामाजिक लेखांकन प्रणाली का विनाम



सामाजिक लेखांकन के अनुसार अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है। जैसे—उत्पादन क्षेत्र (Productive Sector), मध्यम या व्यापारी क्षेत्र (Intermediate or Business Sector), तथा अन्तिम माँग या अन्तिम उपभोक्ता क्षेत्र (Last Demand or Consumer Sector)। समुक्त राष्ट्र सभ के अनुसार अर्थव्यवस्था को पाँच भागों में बाँटा जाता है (i) उत्पादन मन्थान (ii) वित्तीय मध्यम्य (iii) बीमा व सामाजिक सुरक्षा मन्थान (iv) अन्तिम उपभोक्ता (v) बाह्य जगत (विदेशी लेन-देन)। वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (Indian National Income Committee) ने अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटा है (i) व्यावसायिक मन्थान (ii) परिवार तथा निजी अनाम मन्थान (iii) सरकार तथा गवर्नमेन्ट मन्थान।

कृत्रिम लेखांकन एक क्षेत्र विशेष के लिए 12 लेखों तैयार किए जाते हैं। सामाजिक लेखों के लिए एक लेन-देन आधारा (Transaction Matrix) का प्रयोग होता है जिसमें पंक्तियों के अन्तर्गत अर्थ क्षेत्रों की देनदारियाँ तथा लेनदारियाँ दिखाई जाती हैं। यह याद रखना चाहिए कि सामाजिक लेखों में मन्थान बनाए रखने के लिए एक पक्ष के कृत्रिम जोड़ उभरे समकक्ष कौन्सम पक्ष के कृत्रिम जोड़ के बराबर होना चाहिए।

### सामाजिक लेखांकन का प्रारूप

| देनदारियाँ<br>लेनदारियाँ | आर्थिक गतिविधि |      |        | योग  |
|--------------------------|----------------|------|--------|------|
|                          | व्यावसायिक     | निजी | सरकारी |      |
| 1. उत्पादन लेखा          |                |      | ...    |      |
| 2. उपभोग लेखा            |                |      |        |      |
| 3. निजी लेखा             |                | .    |        |      |
| 4. बाह्य लेखा            |                |      |        | ...  |
| योग                      | ..             | ..   |        | .... |

सामाजिक लेखांकन का महत्त्व (Importance of Social Accounting) — सामाजिक लेखांकन प्रणाली का महत्त्व निम्न तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है —

- (1) यह प्रणाली अर्थव्यवस्था की संरचना रखने वाले तत्वों की विस्तृत जानकारी देती है। जैसे उत्पादन उपभोग बचत विनियोग विदेशी व्यापार आदि।
- (2) यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या करते हैं तथा उनमें तुलनात्मक अध्ययन को भी बताते हैं। हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनमें सापेक्षिक योगदान का सूचकांक दिया जा सकता है।
- (3) हमें देश देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी के माध्यम-माध्य विदेशी अर्थ व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- (4) यह सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में परिणाम-मूल्य उनके आर्थिक प्रभावों की जानकारी भी प्रस्तुत करता है।

5 मिश्रित प्रणाली (Mixed Method)— राष्ट्रीय आय के माप के लिए कोई भी अकेली विधि पर्याप्त नहीं है। सभी के अपने गुण-दोष हैं। जब हम दा या हमें अधिक प्रणालियों का उपयोग राष्ट्रीय आय की गणना हेतु करते हैं तो हम प्रणाली को मिश्रित प्रणाली बना सकते हैं। एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में हम प्रणाली का प्रयोग अधिकांश किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विभाग न होने के कारण हमें विभिन्न-भिन्न मापों के उपयोग नहीं होते। भारतीय अर्थ विशेषज्ञ डा० पी० के० आर० पी०

राय (Dr V K R V Rao) न राष्ट्रीय आय की गणना हुई मरव इस प्रणाली का प्रयोग किया और भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों का मिश्रित प्रणाली अपनाय भी मनाह दी । यह प्रणाली विकसित देश म भी लागूप्रिय हा रहहा हे क्यकि वचन एक प्रणाली का ही राष्ट्रीय आय जानने के लिए उपयुक्त नही माना जा सकता ।

### राष्ट्रीय आय के माप के सम्बन्ध मे कठिनाइयाँ (Difficulties in the Measurement of National Income)

प्रो० साइमन कुजनेटस (Prof Simon Kuznets)~ न राष्ट्रीय आय का अनुमान लगात समय आने वाली सांख्यिक अवधारणाओं का सम्बन्धित कठिनाइया का और हमारा ध्यान आकर्षित किया है जैन -

(1) राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने सम्बन्धी कठिनाई - राष्ट्रीय आय का परिभाषित करते समय क्या हम एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत अर्जित की जान वाली आय का ही शामिल कर अपना विवेचना म उम राष्ट्र के उम, द्वारा पूजा पर अर्जित व्याज या राभाण को भी राष्ट्रीय आय म शामिल कर ।

(2) राष्ट्रीय आय मापने हेतु प्रणाली का प्रयोग - राष्ट्रीय आय का मापन क न्य किस प्रणाली का उपयोग किया जाय । कोई भी एक प्रणाली वास्तविक राष्ट्रीय आय का अनुमान लगान के लिए पूण नही कही जा सकती । अर्द्ध विकसित देश म विकसित देश की अपेक्षा यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती है ।

(3) राष्ट्रीय आय की आर्थिक क्रिया - राष्ट्रीय आय का माप न सम्बन्ध म एक अय कठिनाई यह आती है कि आर्थिक क्रिया किस स्थिति पर राष्ट्रीय आय मनाया जाए । अर्थात् उपभोग उत्पादन या वितरण मे से किस क्रिया को आधार माना जाय ।

(4) वस्तुओं तथा सेवाओं की चुनाव सम्बन्धी समस्या - राष्ट्रीय आय की गणना म एक अन्य समस्या वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव की समस्या आती है । वस्तु विनिमय द्वारा होन वाले साधन के भोग म यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती ह ।

(5) दोहरी गणना सम्बन्धी समस्या - राष्ट्रीय आय का गणना म एक अन्य समस्या दोहरी गणना (Double Counting) सम्बन्धी सामन आता है । इसका समाधान हेतु हम प्राथमिक तथा माध्यमिक वस्तुओं के स्थान पर अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ लनी चाहिये ।

(6) हस्तांतरण भुगतान सम्बन्धी कठिनाई - राष्ट्रीय आय के माप क सम्बन्ध म एक अन्य कठिनाई हस्तांतरण भुगतान सम्बन्धी सामने आती है । यह भुगतान आय के पुन-वितरण के कारण होता है ।

(7) विदेशी फर्मों की आय की समस्या - इस सम्बन्ध म कठिनाई यह आता ह कि विदेशी फर्मों की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय माना जाए अथवा नही ।

(8) सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन - एक अन्य समस्या यह आता ह कि सरकार द्वारा प्रदान क जाने वाली सेवाओं का मूल्य क्या और कैसे आँका जाए ।

### अर्द्ध-विकसित देशों मे राष्ट्रीय आय की माप सम्बन्धी कठिनाइयाँ (Difficulties of Measuring National Income in Under developed Countries)

एक अर्द्ध विकसित देश म राष्ट्रीय आय का मापन क सम्बन्ध म वचन भी कठिनाइयाँ आती है । यह कठिनाइयाँ सांख्यिकीय एवं सांख्यिकीय (Statistical and Conceptual) होती है ।

(1) अमौद्रिक क्षेत्र का होना—अर्द्ध-विकसित देशों में अमौद्रिक क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में काफी कठिनाई आती है। एवं उत्पादक या निर्यात अपने उत्पादन का अच्छा भाग अपने उपभोग के लिये रख लेता है और उसे बाजार में बेचने को नहीं लाता। इसका एक छोटा-सा भाग यह वस्तु-विनिमय के लिए छोड़ दिया जाता है। यह कठिनाई अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में आती है।

(2) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव—अर्द्ध-विकसित देशों में अधिकांश उत्पादकों के अशिक्षित एवं गणितकीय व्यवस्था का समुचित उपयोग न होने से पर्याप्त एवं विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले के समक्ष यह समस्या आती है कि जो कुछ भी आँकड़े उभर मिल रहे हैं उनमें सत्यता का अंश कितना है।

(3) विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट वर्गीकरण का अभाव—अर्द्ध-विकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट वर्गीकरण के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई आती है। कभी-कभी यह आत नही हा पाता कि कौन-सा क्षेत्र औद्योगिक और कौन-सा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है।

(4) आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन—अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के कारण बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं। इनके देशों में प्रायः राग अध-विश्वासी एवं परम्परावादी होते हैं। वे अपनी आय तथा परिवार में सम्बन्धित किर्तियों की प्रशंसा को सूचना देने में संकोचते हैं।

राष्ट्रीय आय विश्लेषण का महत्त्व (Importance of National Income Analysis)—वर्तमान समय में किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी तथा देश विशेष की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में काफी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय आय में सम्बन्धित आँकड़े आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों द्वारा अंशित जा सकता है।

(1) आर्थिक प्रगति का सूचक—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी गणितकीय से हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का ज्ञान हो से अनुमान लगा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति (Trend) वृद्धि को बताती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है, यदि राष्ट्रीय आय स्थिर है तो यह अर्थव्यवस्था की स्थिरता का, यदि राष्ट्रीय आय में गिरावट के चिह्न हैं तो इसके अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत मिलते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का आँकड़ा आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं।

(2) आर्थिक नीति निर्माण एवं नियोजन में सहायक—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों से सरकार को आर्थिक नीतियों का निर्धारण तथा निर्माण में काफी सहायता मिलती है। सरकार को अपनी वर नीति मौद्रिक नीति प्रमुख नीति, तथा अन्य प्रकार की नीतियों के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन के लिए अर्थव्यवस्था तथा दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है।

(3) अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर समुचित प्रकाश डालते हैं। इन आँकड़ों द्वारा आसानी से हम पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है।

(4) जीवन स्तर की जानकारी—राष्ट्रीय आय का हम प्रतिव्यक्ति आय द्वारा भा व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिव्यक्ति आय की गति जागा के जीवन स्तर का व्यक्त करती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि को बताती है जिससे हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दशवासिया का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

(5) समाज में आय के वितरण की जानकारी—राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े से हम समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय के वितरण की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय आय के वितरण में व्यक्त असमानताओं की जानकारी भी हम आसानी से मिल जाती है।

(6) उपभोग बचत तथा विनियोग की जानकारी—राष्ट्रीय आय व अनुमानों के आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यय उपभोक्ता व्यय तथा निवेश में किस प्रकार बँटा है। दश में उपभोग बचत तथा निवेश का स्थिति क्या है। दश में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण माँग स्वयं उपभोग तथा विनियोग द्वारा प्रभावित होता है।

(7) करदात क्षमता का अनुमान—राष्ट्रीय आय द्वारा दशवासिया का करदात क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं जिससे सरकार को अपनी वसुधा सम्बन्धी नीति व निर्धारण में सहायता मिलती है।

(8) सशोधन सरकारी नीतियों के निर्माण में सहायक—राष्ट्रीय आय के विकास द्वारा सशोधन सरकार को अपने विभिन्न घटक जैसे वेद शासित क्षेत्रों तथा राज्या को प्रदत्त अनुदान तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता व बँटवारे में काफी सहायता मिलती है।

(9) सांख्यिक तथा निजी क्षेत्रों की जानकारी—राष्ट्रीय आय व आँकड़ों द्वारा हम भारत जसी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सांख्यिक तथा निजी क्षेत्र (Public and Private Sectors) व सांख्यिक योगदान का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(10) अर्थ विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण—राष्ट्रीय आय के अनुमानों का आधार पर अर्थ विकसित देशों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान की जानकारी आसानी से पता चल जाती है।

### राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण (National Income and Economic Welfare)

कल्याण शब्द का आशय मनुष्य तथा समाज का प्राप्त हान वाला भौतिक सुख-सुविधाओं से होता है। कल्याण का सम्बन्ध मनुष्य के रहन-सहन में भा व्यक्त किया जा सकता है। उच्च आर्थिक कल्याण उच्च रहन-सहन व स्तर का प्रतीक है तथा निम्न आर्थिक कल्याण निम्न रहन-सहन के स्तर को बताता है। यदि हम समाज में रहन वाल सभी व्यक्तियों व कल्याण को जोड़ दें तो हमें कुल सामाजिक कल्याण की जानकारी हा जाएगी। प्रो. पीगू ने कल्याण को दो भागों में बाँटा है (i) आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) (ii) अर्थ-व्यतिरिक्त कल्याण (Non economic Welfare)। यह बात हम प्रकार से एक-दूसरे से सम्बन्धित है कि इसे पृथक करना बर्तन है। प्रो. पीगू ने आर्थिक कल्याण का परिभाषित करते हुए कहा कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिस प्रत्यक्ष अर्थ-व्यय पर ही कल्याण के मुद्दे के रूप में तर्क लाया जाता है।

राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण का घना सम्बन्ध (Positive Correlation) की कल्पना अधिकांश विद्वानों में की है। प्रो. पीगू का भी ऐसा मत है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। उनका अनुमान है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जागी है। आय वितरण के पहलू से गणना रहने पर हमें पता चला है।

आर्थिक बन्धन म वृद्धि होती है अर्थात् उनक रहन-सहन क स्तर म भी वृद्धि हा जाती है। इस आधार पर हम कह सकने हैं कि राष्ट्रीय आय का इस आर्थिक बन्धन का सूचकांक कह सकत हैं।

राष्ट्रीय आय आर्थिक बन्धन का वास्तविक सूचकांक नहीं है (National Income is not a Real Index of Economic Welfare)

क्या हम राष्ट्रीय आय का आर्थिक बन्धन का वास्तविक सूचकांक कह सकत हैं ? यह प्रश्न हम तभी नहीं रूप म समझ म आ सकगा जब कि हम निम्न तथ्या पर भी ध्यान दें।

(1) राष्ट्रीय आय का वितरण—राष्ट्रीय आय म वृद्धि से आर्थिक बन्धन बढ़ा है या कम हुआ है। इसके लिए हम देखना होगा कि राष्ट्रीय आय क वितरण की स्थिति क्या है। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि म धनी तारा का इतना हिस्सा अधिप पहुँचना है और निधना का कम ता कुल बन्धन नहा बढ़गा।

(2) राष्ट्रीय आय की वृद्धि का स्वरूप—हम राष्ट्रीय आय का वृद्धि क स्वरूप का अध्ययन करना होगा। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि स्थिरा तथा बच्चा या धर्मिका से अधिक घण्ट काम करकर तथा उमक बढ़न म उह उचित पारधर्मिक न दकर का गद है ता एसी स्थिति म राष्ट्रीय आय की यह वृद्धि समान व आर्थिक बन्धन म वृद्धि का सूचक नहा होगा।

(3) जनसंख्या वृद्धि की दर—यदि जनसंख्या वृद्धि का दर राष्ट्रीय आय म वृद्धि दर से अधिक तेज है ता इससे प्रति व्यक्ति आय गिरगा और तारा का आर्थिक बन्धन गिरगा।

(4) कीमत स्तर म परिवर्तन की स्थिति—हम राष्ट्रीय आय का प्रचलित मादिक कामता म आँख म। कीमत स्तर म वृद्धि या कामा राष्ट्रीय आय म वृद्धि या कामा का सूचक हानी है। कामत स्तर म यह परिवर्तन बिना बस्तुआ तथा मवाआ क वास्तविक उत्पादन म परिवर्तन क हा मतता है। प्रायः राष्ट्रीय आय का वृद्धि का अर्थ हम आर्थिक बन्धन म वृद्धि म तारा बँटत है जा भ्रुण्ण है। वास्तविकता यह है कि कामत स्तर म वृद्धि बिना उत्पादन म वृद्धि क हान पर आर्थिक बन्धन बढ़न क स्थान पर गिर जाता है क्योंकि तारा क रहन-सहन क स्तर म गिरावट आती है।

(5) राष्ट्रीय आय वृद्धि की संरचना—राष्ट्रीय आय म वृद्धि क माप यदि प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि हा ता हम इस आर्थिक बन्धन का वृद्धि का सूचकांक नहीं समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय आय की संरचना का अध्ययन हम भ्रुण्ण करक हा यह पत कर सकत हैं। यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि उपभाग बस्तुआ क उत्पादन म न हाकर पूजोगत बस्तुआ क उत्पादन म वृद्धि क फलस्वरूप हूँ है ता यह आर्थिक बन्धन म वृद्धि का परिचायक नहीं कहनाएगा। इस प्रकार यदि कुछ बस्तुआ (war goods) क उत्पादन म वृद्धि क कारण राष्ट्रीय आय बढ़ा है ता म यह आर्थिक बन्धन म वृद्धि का सूचक नहीं होगा।

(6) लोगो की अभिरुचियो तथा मानवीय मूल्यो मे हास यदि राष्ट्रीय आय म वृद्धि क साथ-साथ तारा का अभिरुचिया तथा मानवीय मूल्यो म गिरावट आर है ता इससे आर्थिक बन्धन बढ़न क स्थान पर गिरगा। अत्यधिक आय म वृद्धि क कारण तारा का रचि मादक बस्तुआ क सबन वण्णवृत्ति तथा जुए आदि का तरफ मुका है ता एसा स्थिति म समाज क आर्थिक बन्धन म तारा जागी वृद्धि अरु आर्थिक बन्धन गिरगा।



## आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कसौटी

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि फिर आर्थिक कल्याण में वृद्धि का क्या कसौटी है ? राष्ट्रीय आय में वृद्धि का आर्थिक कल्याण का सूचक तभी माना जा सकता है जब कि (i) राष्ट्रीय आय वितरण निम्न व्यक्ति व अनुसूच हो (ii) आर्थिक कल्याण में वृद्धि की साम्यविक कसौटी उपभोग स्तर में वृद्धि अथवा लोगों के वास्तविक रहन-सहन में वृद्धि में उपाया जाना चाहिए। आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण निम्नो व अनुसूच होकर उनका रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाना होना चाहिए। राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण का निम्नता क पक्ष में करने के लिए हम धनियों पर अधिक कर निम्नो को प्रयत्न या परोक्ष आर्थिक सहायता आदि के द्वारा किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के पुनर्वितरण की एक शर्त यह है कि राष्ट्रीय आय का आकार किसी भी प्रकार से कम न हो अथवा इससे कुछ आर्थिक कल्याण मिलेगा।

**भारत में राष्ट्रीय आय (National Income in India)** भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान स्वतंत्रता से बहुत पहले लगाया गया था। वष 1866 में उद्धारवादी भारतीय नेता श्री दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 70 रुपये मात्र आँकी गई थी। वष 1900 में लाड बज्रन के समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 30 रुपये मात्र थी। इससे बाद अन्व विद्वानों ने राष्ट्रीय आय आवदन के प्रयास किए परंतु विश्वसनीय आँकड़ा के अभाव में यह अनुमान वास्तविकता से काफी दूर रहे। राष्ट्रीय आय के अनुमानों में सबसे अधिक विश्वसनीय अनुमान प्रो० डा० वी० के० आर० वी० राव (Dr V K R V Rao) ने लगाया। वष 1925-26 में उह ने भारत की आय 76 रुपये वार्षिक आँकी थी। जो बदकर 1942-43 में 114 रुपये हो गई।

**राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee)**— स्वतंत्रता के पश्चात् वष 194) में प्रो० पी० सी० महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई। भारतीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ ए० वी० के० आर० वी० राव तथा पी० गाडगिन इस समिति के सदस्य थे। इस समिति का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ा तथा अन्य सम्बन्धी तथ्या पर सामग्री एकत्रित करना था। वष 1951 में इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जिसमें वष 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए गए थे। वष 1954 में समिति ने अपना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वष 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान तथा वष 1950-51 के राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान तथा उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इस समिति ने उत्पादन सगणना प्रणाली (Production Census Method) द्वारा सन्नित्त उपयोग वृद्धि वनस्पति पशुधन से प्राप्त आय का अनुमान लगाया गया। व्यापार याता यात घरेलू संघाया तथा दस्तकारी में प्राप्त आय का अनुमान आय सगणना प्रणाली (Income Census Method) द्वारा लगाया गया तथा शेष धन का आय का अनुमान लगाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लिया गया।

वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान व आय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा लगाया जाता है। इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय पर प्रतिवर्ष एक श्वेतपत्र (White Paper) प्रकाशित किया जाता है। इस संगठन द्वारा प्रदत्त आँकड़ा राष्ट्रीय आय के विश्वसनीय आँकड़ा होता है।

**भारत में राष्ट्रीय आय की लगाना सम्बन्धी कठिनाइयाँ**—भारत में राष्ट्रीय आय का मापन संभवतः म प्रतीकान्ती व विनाएयो की जथा गणना में राष्ट्रीय आय समिति ने की

धी। इसका अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जाचनन में दो कठिनाइयाँ प्रमुख रूप में आती हैं।

### (1) धारणात्मक (Conceptual) तथा 2 सांख्यिकीय (Statistical)

1 धारणात्मक कठिनाइयाँ—भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का वेतन-दान मुद्रा के माध्यम से होता है। जब कि वस्तु स्विकृति यह है कि बाजार का एक क्षेत्र असंगठित होता है और उभय वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती है। इसका अतिरिक्त यहाँ के लोग न आंशिकतः ज्ञान एवं अज्ञानता के कारण उत्पादक अपनी उत्पत्ति का लेखा जोखा नहीं रख पाते तथा स्वयं उपभोग हेतु रखी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन की गणना करते समय गणित नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं यहाँ के लोग एक वर्ष में बड़े व्यवसायों अथवा कार्यों में लग जाते हैं और जो धन इनमें अर्जित करते हैं उसका गरीब-गरीब हिस्सा नहीं रख पाते इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय का पता लगाने में कठिनाई होती है।

(2) सांख्यिकीय कठिनाइयाँ—भारत में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जाँचने में विश्वसनीयता एवं सत्यता का अभाव पाया जाता है। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है अन्य महायंत्र कार्यों तथा व्यवसायों में लागत तथा आय सम्बन्धी अंकितों का विश्वसनीयता प्रायः सिरिप्त रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय आँकड़ों का विश्वसनीय जाँचकारी के अभाव में राष्ट्रीय आय के अनुमानों में अत्यन्त अशुद्धता ही रह जाती है।

### परीक्षा-प्रश्न

1 राष्ट्रीय आय में आय क्या समझते हैं। इस संबंध में प्रा० माणन पीगू तथा फिशर के विचारों का ज्ञापन।

(What do you understand by National Income? Discuss the views of Prof. Marshall, Pigou and Fisher in this connection.)

2 राष्ट्रीय लेखांकन में आय क्या समझते हैं? इसका विभिन्न अंगों की व्याख्या का ज्ञापन।

(What do you understand by National Income Accounting? Explain its various components.)

3 राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और इस मापन की विधियाँ बताइए।

(Define National Income and explain various methods for measuring National Income.)

4 राष्ट्रीय आय का परिभाषित कीजिए। इसका मापन में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(Define National Income. What are the difficulties faced while measuring National Income?)

5 राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के सम्बन्ध का व्याख्या कीजिए। क्या यह कहना ग़लत है कि कुल राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है?

(Explain the relationship between National Income and Economic Welfare. Is it correct to say that increase in the size of aggregate National Dividend must cause an increase in Economic Welfare?)

6 राष्ट्रीय राजाज में आयतत तात्पर कया है ? आर्थिक कल्याण न इनर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण कीजिय ।

(What do you mean by National Income ? Explain its relation ship with Economic Welfare )

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

1 कुन राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद म अन्तर बर पर हाता है—

- (i) अन्त्यक्ष बन्
- (ii) अन्त्य रर
- (iii) मूल्यह्रास वा घिसावट (Depreciation)
- (iv) टिकाऊ वस्तुआ पर उपभाक्ता व्यय
- (v) उपभोग्य आय ।

उत्तर —(iii) सही है ।

2 वैयक्तिक आय (Personal Income [PI]) बराबर होनी ह

- (i) राष्ट्रीय आय— रर
- (ii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद —घिसावट
- (iii) राष्ट्रीय आय—हस्तांतरण भुगतान
- (iv) राष्ट्रीय आय—सामाजिक सुरक्षा के अशदान—निगम आयकर —अवितरित निगम लाभ—हस्तांतरण आय
- (v) व्यय योग्य आय —प्रत्यक्ष

उत्तर (iv) सही है ।

3 शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNP) बराबर हाती ह ।

- (i) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—घिसावट व्यय
- (ii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद —आयात
- (iii) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—हस्तांतरण आय
- (iv) कुन राष्ट्रीय उत्पाद—प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर
- (v) कुन राष्ट्रीय उत्पाद + निर्यात

उत्तर—(i) सही है ।

Full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to further increase in effective demand " —Dudley Dillard

### अध्याय 3

## बेरोजगारी तथा पूर्ण रोजगार

(Unemployment and Full Employment)

बेरोजगारी वतमान सभी प्रकार की अवस्थाओं में बिना किसी रूप में दगल का मित्रनी है। बेरोजगारी एक अभिशाप है और मानव जाति के लिए एक बुरा है। बेरोजगारी एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कष्ट है इसका कुप्रभाव सब बेरोजगार व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता बल्कि सम्पूर्ण समाज का इससे दुष्परिणाम भुगन्न रहते है।

**बेरोजगारी का अर्थ**—बेरोजगारी का अर्थ उम व्यक्ति से लगाया जाता है जबकि व्यक्ति काय करने में सक्षम हो कार्य करने का इच्छुक हो परन्तु रोजगार अवसर का अपूर्णताओं तथा बर्बाद कारण उम रोजगार नहीं मिल पाता। एक अवश्यासीय दृष्टि-कोण से बेरोजगारी की परिभाषा उम प्रकार दी जा सकती है। एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपनी कार्यकुशलता पर योग्यता के अनुसार मजदूरी की प्रस्तावित दर पर कार्य करने में तैयार है परन्तु उम कार्य नहीं मिल पाता है। (An unemployed person is that person who is seeking work at the prevailing wage rate according to his efficiency and qualifications but he is unable to seek any job )

उम बचन का आशय यह है कि समाज में कुछ लोग हर समय एक पाए जावेग जा कार्य करने योग्य है तथा कार्य करना ही नहीं चाहते। उम लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते है क्योंकि उम व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक ही नहीं होते। अवश्यास्य में उमने ऐच्छित बेरोजगारी (Voluntary unemployment) कहते है और उम प्रकार की बेरोजगारी का अध्ययन एक अवश्यासी नहीं करता। उमके विपरीत कुछ उम भी व्यक्ति हात है जा कार्य करने के योग्य है, कार्य करना भी चाहते है परन्तु उम कार्य नहीं मिलता उमो बेरोजगारी, क. द. अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment) कहते है। एक अवश्यासी का सम्बन्ध अनैच्छिक बेरोजगारी का अध्ययन करने उमो समाधान हेतु मुझाव देना है। उम बेरोजगारी के मुख्य उमो कारण तथा उममें सम्बन्धित कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे।

### ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी

(Voluntary and Involuntary Unemployment)

बेरोजगारी के दो प्रमुख रूप है (i) ऐच्छिक बेरोजगारी (ii) अनैच्छिक बेरोजगारी

### (I) ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)

ऐच्छिक बेरोजगारी यह स्थिति होती है जब व्यक्ति काय करत की याच्यता रहता है, उसे प्रचलित मजदूरी पर कार्य मिल भी सकता है परन्तु वह अपनी इच्छा से काय करना नहीं चाहता। ऐसे लोग समाज में हर समय पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन नहीं करता। ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं—

(1) व्यक्ति आत्मो अथवा पारिवारिक कारणों के कारण मजदूरी मिलने पर भी कार्य नहीं करना चाहता।

(2) प्रचलित मजदूरी की दरें व्यक्ति की योग्यता के अनुसूच भी न हों तो भी व्यक्ति रोजगार में लगना नहीं चाहता।

(3) अत्यधिक सम्पन्नता एवं धनवान होने के कारण व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहते हो।

(4) आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में जैसे चोर उर्बत या ममाज विरोधी तत्वों में भी ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है।

### (II) अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment)

अनैच्छिक बेरोजगारी का आशय उन स्थिति में होता है जबकि व्यक्ति कार्य करने के योग्य कार्य करने का इच्छुक हो फिर भी उसे उम्मे प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य उपलब्ध न होता हो। हम अनैच्छिक बेरोजगारी को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

जब काय करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने का इच्छुक भी हो परन्तु उसे रोजगार के अवसरों की कमी के कारण रोजगार उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहलाएगी। एक अर्थशास्त्री का सम्बन्ध अनैच्छिक बेरोजगारी का अध्ययन करके उसके समाधान हेतु सुझाव देना होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है जैसे प्रभावपूर्ण माँग में कमी का होना, तकनीकी परिवर्तन, श्रम बाजार की अपूर्णताओं, मौसमी कारणों तथा कृषिय उच्चावचनो आदि द्वारा।

### अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार (Types of Involuntary Unemployment)—

अनैच्छिक बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है जो ऊपर बताए जा चुके हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर अनैच्छिक बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार हैं—

(i) संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)—संरचनात्मक बेरोजगारी का आशय अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण बेरोजगारी के होने में लगाया जाता है। ऐसी बेरोजगारी मुख्य रूप से अर्द्ध-विकसित देशों में पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी श्रमपूर्ति का उनकी माँग से अधिक होने से होती है। देश में भूमि तथा पूंजीगत साधन सीमित हैं और जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण लम्बे समय तक व्यक्ति को बेरोजगार रहना पड़ सकता है। श्रमिकों की माँग से पूर्ण नहीं अधिक हो जाती है। प्रो० बेनहम ने संरचनात्मक बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है— संरचनात्मक बेरोजगारी, नमिर्मातृ तथा स्पर्धात्मक बेरोजगारी की अपेक्षा अधिक दीर्घकालिक होती है और इसे अर्थव्यवस्था के स्थायी एवं पर्याप्त आर्थिक विकास से ही दूर करना सम्भव होता है .....।" इसका आशय यह है कि स्थायी आर्थिक विकास के द्वारा ही इस प्रकार की बेरोजगारी से निपटा जा सकता है। आर्थिक विकास से रोजगार के आधक अवसर उपलब्ध होंगे—अधिक आय बढ़ेगी—अधिक माँग—अधिक लाभ बढ़ेगा—अधिक पूंजी विनियोजन होगा—आर्थिक विकास में निरन्तरता बनी रहेगी।

(ii) घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—घर्षणात्मक बेरोजगारी में आशय अल्पकालिक रूप में उत्पन्न होने वाली अस्थायी बेरोजगारी में होता है। ऐसी बेरोजगारी कुछ समय बाद स्वतः ही समाप्त होने लगती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है जैसे रोजगार के अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में व्याप्त गतिहीनता, बच्चे मान की उम्र, मशीनों को टूट-पूट करवाती निवृत्तता, श्रमिकों में अंतरांगी भावना आदि। इस प्रकार की बेरोजगारी भी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। प्रत्येक देश में उक्त कारणों से कुछ न कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं। प्रो० डी० टिनाई ने अपने ग्रन्थ में घर्षणात्मक बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा है कि “घर्षणात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोगों को थोड़े समय के लिए काम नहीं मिल पाता है।”

घर्षणात्मक बेरोजगारी का स्तर आर्थिक विकास के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है। आर्थिक विकास में नई-नई विधियों को उत्पादन में अपनाने से उत्पादन के माध्यमों और उनकी मात्रा के स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ नए उद्योगों का विकास होने लगता है तथा पुराने उद्योगों का महत्त्व कम होने लगता है। इस आर्थिक परिवर्तन के कारण कुछ लोग पुराने व्यवसायों को छोड़कर नए व्यवसायों में रोजगार की तलाश करने लगते हैं। इस प्रकार घर्षणात्मक बेरोजगारी दिव्दि होती है।

(iii) तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)—तकनीकी बेरोजगारी का स्वरूप भी अस्थायी होता है। ऐसी बेरोजगारी नवीन तकनीकों के प्रयोग के कारण मशीनों का आधुनिकीकरण स्विकीकरण तथा वैज्ञानिक विधियों आदि के द्वारा होती है। जब उत्पादन के क्षेत्र में नए नए घटाने तथा लाभ की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से नई उत्पादन विधियों एवं नए-प्रकृत आदि की नीति अपनाई जाती है तो उमरे कारण उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है।

(iv) मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—एक अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर कार्य नहीं रहता। इनमें कार्य करने वाला के लिए एक वर्ष में कुछ महीने बेरोजगार रहना पड़ता है। चर्चिता उद्योग कृषि क्षेत्र, वर्ष के कार्यान्वयन, चायन मितों आदि में लोगों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं होता।

(v) अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) छिपी बेरोजगारी का अर्थ व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता या कार्यक्षमता के विरुद्ध कम उत्पादन प्रियात्रा में कार्य करना होता है। छिपी बेरोजगारी की स्थिति का आशय किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अधिक दबाव का आवश्यकता में अधिक बढ़ना होता है। श्रीमती जान गविन्सन के शब्दों में “छिपी या अदृश्य बेरोजगारी यह स्थिति है जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करके उत्पादन के लिए, अल्पतः योग्यता के विरुद्ध, कम उत्पादन व्यवस्थाओं में धकेल दिए जाते हैं।”<sup>1</sup> विकासवादी विचारक प्रो० रेगनर नामों का कहना है कि अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति अर्द्ध-व्यवस्थित देशों में अधिक दिव्दि होती है। यह कहते हैं कि ऐसे देशों में पाय यह देखने को मिलता है कि जहाँ 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती

1. “Disguised unemployment is a situation in which the wage workers take to less productive jobs because they lose their regular jobs owing to cyclical ebb in economic activity.”

—Smt Joan Robinson

है वहाँ 7 व्यक्ति लगे होते हैं। यदि इस 7वें व्यक्ति को रोजगार न दिया गया तो हमसे उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देलने में 7वा व्यक्ति रोजगार में अवश्य ही लगा मातूम होता है परन्तु बावजूब में वह बेरोजगार होता है। एक उदाहरण द्वारा छिपी बेरोजगारी को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। माना कि एक व्यक्ति विद्यार्थी प्रशिक्षण की डिप्लोमा पास है परन्तु रोजगार अवसरों की कमी के कारण उसे अपनी योग्यता से नीचे पढ़ पढ़ कार्य करना पड़े जैसे एक इन्जीनियर को एक मैकेनिक या रोडभूतन के पद पर कार्य करना पड़े तो इसे छिपी बेरोजगारी कहेंगे।

(vi) चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—चक्रीय बेरोजगारी से आशय व्यापार चक्रों अथवा कभी तेजी और कभी मंदी के होने से उत्पन्न होती है। जब कभी वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग उनके उत्पादन से कम हो जाती है तो कुछ माल बिना बिके रह जाता है कीमतें गिरने लगती हैं, उत्पादन के मध्य निराशावादिता दखने को मिलती है, उत्पादन गिरने लगता है और पूँजी निवेश गिरने लगता है। यह स्थिति मंदी काल की स्थिति कहलाती है। मंदी में एक ओर उत्पादन कम होने लगता है क्योंकि उत्पादन कार्य प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण गिर जाता है दूसरी ओर उत्पादन कार्य में लगे हुए श्रमिकों की छुटनी होने लगती है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। चक्रीय बेरोजगारी पूँजीवादी तथा विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में दिखाई देती है। तेजी तथा मंदी (Boom and Depression) के कारण लोगों के आय के स्तर, मुद्रा की मात्रा विनियोग उपभोग तथा कीमत-स्तर में परिवर्तनों के कारण ऐसी बेरोजगारी की स्थिति देलने को मिलती है।

(vii) अस्थायी बेरोजगारी (Casual Unemployment)—जैसा कि हम जानते हैं कि श्रमिकों की माँग व्युत्पन्न (Derived Demand) होती है अर्थात् उनकी माँग प्रत्यक्ष न होकर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। उत्पादन उतना ही किया जाता है जितना कि वस्तुओं की माँग होती है। श्रम की माँग उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति अस्थायी होती है। ऐसी बेरोजगारी निवृत्त उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों में देखने को मिलती है जिनकी वस्तुओं की माँग में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं परन्तु यह उच्चवचन अस्थायी होते हैं।

बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कोई एक कारण विशेष उत्तरदायी नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर हमने कई कारण बताए हैं। विभिन्न देशों में बेरोजगारी का स्वरूप अलग-अलग दिखता है इसलिए बेरोजगारी के लिए न तो एक प्रकार के कारण ही उत्तरदायी हैं और न ही उनके समाधान के लिए एक प्रकार के सुझाव दिए जा सकते हैं। मोटे तौर पर बेरोजगारी के कारणों के सम्बन्ध में निम्न विचारधाराओं का उल्लेख जरूरी है—

(1) बेरोजगारी का अव्यक्त नीति सिद्धान्त (Laissez Faire Theory of Unemployment)—इस सिद्धान्त के समर्थक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। उनका ऐसा विश्वास था कि जब अर्थव्यवस्था के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है तो बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। इस विचारधारा के समर्थक प्रा० एडम स्मिथ, जे० ओ० से, रिचार्ड्स, जे० एच० मिल तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन विद्वानों का कहना था कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप की नीति के कारण बेरोजगारी होती है। यह विद्वान

पूण राजभार नर मा-यत। पर इशुभाग करने व थीर उनके इम शिशुवाम नर आधर  
 फामोगी अर जारगी जे० वर० नर के राजार नियम म था कि "पूति अपनी मरिग स्वय  
 पैदा करती ह। पहल तर यह विद्वान बेररजगरी के गामान्य स्थिति मानते ही नही  
 थे। यदि कभी बेररजगरी हा जाए तो मजदूरी बढ़ती तीरत अपनाकर डमे दूर बिपा जा  
 मरता है। एमा प्रतिष्ठित विद्वाना वर कहता था।

(2) बेररजगरी न्यून मरिग सिद्धान्त (Demand Deficiency Theory of Unemployment) — इम सिद्धान्त व वाम्त्विक जनक तो प्रो० रास्टं माथम हीं थे जिन्हन मभी प्रतिष्ठित अर शाम्प्रिया वर न्यून उपभाग वर अति उत्पादन सिद्धान्त दकर चौका दिया था। प्रो० जे० एम० कीन्स वर इम सिद्धान्त वर वाम्त्विक प्रवर्तक माना जाना है। परन्तु कीन्स ने स्वय इमन विषय अपने वर माथम वर ऋणी माना है। प्रो० जे० एम० कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी मे बताया कि प्रभावपूर्ण मरिग म कमी के कारण बेररजगरी दिगई देती है। जब ममाज अपनी सम्पूर्ण आय वर व्यय कर देता है अर्थात् आय = व्यय या उत्पादन — उपभोग होता है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। प्रो० कीन्स वर कहता है कि आय — व्यय प्रवाह (Income—expenditure flow) उम समय टूटना है जबकि व्यक्ति अपनी मरिग आय वर कुछ भाग बचा कर रख लेता है। बचा वर आशय व्यय म कमी अथवा कुन मरिग म गिरावट मे लगाना जाता है उत्पादन भी गिरता है लोगा वर आय कम हानी है वस्तुजा की मरिग म कमी आती है तथा बेररजगरी की स्थिति देखने वर मिलती है। यह सिद्धान्त विकसित देशा म अधतर मदी ने समय क्रिया-जीन होने दगा जा मवता है।

(3) बेररजगरी वर व्यापार चक्रीय सिद्धान्त (Cyclical Theory of Unemployment)—इम प्रकार की बेररजगरी व्यापार चक्रा ने उदय व कारण होती है। पूंजी-वादी अर्थव्यवस्था म व्यापार चक्रा वर उदय होना एक आवश्यक घटना मानी जाती है। इममे कभी तेजी वरन वीर कभी मदी वरन वर स्थिति देखने वर मिलती है जिनमे आय, रोजगार उत्पादन उपभोग तथा विनिमय वर स्तर प्रभावित होता रहता है। व्यापार चक्रा के उदय हाने वर कारण बेररजगरी के बारे म अर्थशास्त्रियों मे मत भिन्नता है परन्तु मभी विद्वान यह स्वीकार करत है कि एर निश्चित ममयावधि के बाद बेररजगरी की घटना विद्यमान हो जाती है वीर प्राय मदी काल मे अधिक बेररजगरी देखने वर मिलती है।

### अल्प विकसित देशो मे बेररजगरी

#### (Unemployment in Under-developed Countries)

बेररजगरी विकसित तथा अर्द्ध या अल्प विकसित दोनों ही प्रकार के देशो म पाई जाती है। इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप म अन्तर होता है इमलिए इनमे बेररजगरी वर स्वरूप भी अलग-अलग देखने वर मिलता है। विकसित देशा म बेररजगरी अस्थायी तथा अर्द्ध-विकसित देशो मे इमतरा स्वरूप म्थामी होता है। विकसित देशो मे कर्षीय वरगजगार उन्नत आर्थिक विकास वर परिणाम होती है जबकि अल्पविकसित देशो म अनैच्छित तथा लिपा हुई बेररजगरी (Involuntary and Disguised Unemployment) आजाग तथा दिगई देती है। इन देशो मे बेररजगरी के कुछ प्रमुख कारण अशक्ति ह—



(1) जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना—अर्द्ध विकसित देशों में अधिक बराजगारा का एक प्रमुख कारण तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत वार्षिक रहती है। विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध विकसित देशों में जनसंख्या की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। बढ़ा हुई जनसंख्या अधिक भूमि की पूर्ति बनाती है। नवीन रोजगार अवसरों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि का दर तेज होती है और बेरोजगारी की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आज अर्द्ध विकसित देशों में भूमि की उपलब्धता अधिक होने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने से भूमिहीनता का हास हो रहा है।

(2) कृषि प्रधान अवस्था—अधिकांश अल्प विकसित देश कृषि प्रधान हैं। कृषि प्रधान देशों में प्रति व्यक्ति कम आय कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य न मिलना प्रति व्यक्ति में पर्याप्त अधिकांश अनार्यिक जोतों का होना कृषि पर अधिक दबाव आदि की स्थिति पाई जाती है। कृषि प्रधान अवस्थाओं में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ देवना की मिलती हैं प्रथम तो जनसंख्या का दबाव कृषि पर अधिक होता है और उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। दूसरे कृषि व्यवसाय अनिश्चित एवं मौसमी है। आज भी अधिकांश कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के लोगों में निधनता का प्रमुख कारण अज्ञानता तथा रोगों की कृषि पर निर्भरता है अपनी निधनता के कारण कृषि पर निर्भर उद्योगों जैसे पशु या मुर्गी पालन मछली पालन कुटार उद्योगों का अभाव का कारण जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता रहती है।

(3) धीमा औद्योगिक विकास—अर्द्ध विकसित देशों में औद्योगिक विकास का गति धीमी होती है इसका प्रमुख कारण वैज्ञानिक तथा तकनीक का पिछड़ापन पूँजी का अपर्याप्त उपलब्धता तथा माहौल प्रवृत्ति का अभाव होता है। ऐसे देशों में यदि औद्योगिक विकास अधिक तेजी से हो और विविध उद्योग जैसे बड़े उद्योग के साथ छोटे तथा कुटार उद्योगों का पर्याप्त विकास हो तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा बेरोजगारी का प्रभाव कम हो जाता है।

(4) आर्थिक पिछड़ापन—अर्द्ध विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन या धीमे विकास के कारण बेरोजगारी की अधिकता बनी रहती है सामान्यतया ऐसे देशों में विकास की औसत दर 3 प्रतिशत के आस पास या इससे भी कम होती है। आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण न होना कृषि पर निर्भरता औद्योगिक पिछड़ापन परम्परावादी एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है। आर्थिक पिछड़ापन का मीमा सम्बन्ध आर्थिक विकास दर से होता है तथा ऐसे देशों में बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आती है।

(5) निरक्षरता एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—अर्द्ध विकसित देशों में निरक्षरता एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का कारण बेरोजगारी अधिक दिसाई देती है। शिक्षा प्रणाली व्यवसाय प्रधान नहीं होती है। पढ़ लिख लोगो की कमी के कारण भी रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं होने पाते। इसके लिए हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके इस रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए। लोगों में व्याप्त निरक्षरता को दूर करना होगा जिससे उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए और वह परिस्थितियाँ का अनुरूप अपने को ढाल सकें।

**पूर्ण रोजगार (Full Employment)**—एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूण रोजगार से आशय देश के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना हो सकता है परंतु सभी व्यक्तियों को रोजगार दिवाना सम्भव नहीं होता। अव्यवस्था वाले विकसित हो या अर्द्ध विकसित उसमें अच्छे घटनात्मक एवं संरचनात्मक बराजगारा विमान किसी रूप में पाई जाती है। पूण रोजगार की धारणा में निम्नलिखित तत्त्वों को ध्यान में

कहा है कि 3 से 5 प्रतिशत लोग हमेशा ही ऐच्छिक, घर्षणात्मक एवं मरचनात्मक बेरोजगारी के अन्तर्गत रहते हैं इसलिए यदि देश की जनसंख्या का 95 प्रतिशत भी रोजगार में लगा हो तो उसे पूर्ण रोजगार की मंजा देना चाहिए। नर विलियम बेबरिज तथा वीन्स जैसे विद्वानों ने पूर्ण रोजगार का आशय इसी मद्दम में लिया है। इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं होता।

**पूर्ण रोजगार की परिभाषा**—पूर्ण रोजगार के मद्दम में विभिन्न धारणाओं के अध्ययन के बाद ही हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को आगामी न समझ सकते हैं।

(i) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार को एक सामान्य घटना मानते हैं। इनके अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति वह स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी पाई नहीं जाती। थोड़ी बहुत मात्रा में ऐच्छिक मरचनात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जा सकती है। (Full Employment is Characterised by Absence of Involuntary Unemployment) इन विद्वानों ने पूर्ण रोजगार का अर्थ उस स्थिति में लिया है जिसमें कार्य करने के इच्छुक लोगों को प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य उपलब्ध हो जाता है। प्रो० ए० पी० लनर ने इसी मद्दम में पूर्ण रोजगार को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें बिना किसी कठिनाई के प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य चाहने वाले को रोजगार मिल जाता है।<sup>1</sup>

(ii) जे० एम० वीन्स की धारणा—जे० एम० वीन्स प्रतिष्ठित विद्वानों की इस विचारधारा में विन्तुल महमत नहीं है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था एक सामान्य घटना है। वे यह तो मानते हैं कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने पूर्ण रोजगार की अवस्था में मरचनात्मक घर्षणात्मक तथा ऐच्छिक बेरोजगारी के होने की जो बात की है वह ग़रीब होती है। वे प्रतिष्ठित विद्वानों के इस विचार में भी महमत नहीं है कि मजदूरी की दर में बढ़ती में बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी। वीन्स ने कहा कि साम्बन्धिक स्थिति अपूर्ण रोजगार के पाग जानने की जाती है तथा बेरोजगारी को मजदूरी बढ़ती के स्थान पर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके कम किया जा सकता है।

प्रो० वीन्स ने पूर्ण रोजगार की स्थिति का सामान्य घटना न मानते हुए इसे प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार किया है। वीन्स के शब्दों में "पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसके बाद प्रभावपूर्ण माँग में प्रत्येक वृद्धि उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं करती तथा प्रभावपूर्ण माँग में कोई भी वृद्धि कीमतों में वृद्धि लायेगी और व्यवहारिक दृष्टि में कोई रोजगार नहीं बड़ेगा।"<sup>2</sup>

(iii) आधुनिक अर्थशास्त्रियों की धारणा—प्रो० ए० पी० लनर ने पूर्ण रोजगार को परिभाषित करते हुए कहा है कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें प्रचलित

1 Full employment is a situation in which all those who want to work at the existing rate of wage get work without any undue difficulty "

—A. P. Lerner.

2 ' Full employment is a situation which involves an appropriate amount of effective demand, a unique level of employment beyond which no further increase in output and employment are possible and any increase in effective demand will lead to a more rise in prices and practically no increase in employment. ' J. M. Keynes

मजदूरी की दर पर बिना किसी विशेष बठिनाई के इच्छुक व्यक्तिदा को काम मिल जाता है प्रो० लनर के बिना किसी बठिनाई वाक्यांश का अर्थ कुल व्यय में वृद्धि करने (मुद्रा प्रमाण बिना) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने से है।

१० डिनाड के शब्दों में पूण रोजगार वह बिन्दु होता है जिसके पश्चात् प्रभाव पूण माग में वृद्धि होने पर उत्पत्ति बेसोच सिद्ध होती है।<sup>2</sup>

सयुक्त राष्ट्र सघ (United Nations Organisations) की एक रिपोर्ट में पूण रोजगार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पूण रोजगार का स्थिति वह अवस्था माननी जानी चाहिए जिसमें प्रभावपूण माग में वृद्धि होने पर रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

प्रो० ई० नौरस के शब्दों में आदर्श रूप से पूण रोजगार की अवस्था वह होगी जो अधिकतम उत्पादन तथा लोगों की वास्तविक शक्ति को प्रोत्साहित करेगी।<sup>3</sup>

सर विनियम वेबरिज ने पूण रोजगार को परिभाषित करते हुए कहा है कि पूण रोजगार वह अवस्था है जहाँ बेरोजगारों से अधिक रिक्त स्थान पाये जाते हैं जिससे एक कार्य को तीन तथा दूसरे को प्राप्त करने के मध्य समय बितम्ब बहुत ही कम होगा।<sup>4</sup>

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन के अनुसार जब एक देश में 3 से 4 प्रतिशत तक बेरोजगारी पाई जाती है तो उस देश में पूण रोजगार की प्राप्ति कर ली गई है। अर्द्ध० एल० ओ० द्वारा पूण रोजगार की अन्य शर्तें यह हैं कि इसमें किसी प्रकार श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए तथा श्रामक बिना किसी बितम्ब के रोजगार प्राप्त करने योग्य होना चाहिए।<sup>4</sup>

पूण रोजगार के मुख्य तत्व—पूण रोजगार की धारणा का समर्थन के लिए हम इससे सम्बन्धित मुख्य तत्वों को देखना होगा।

(1) पूण रोजगार की स्थिति वह होती है जिसमें बेरोजगारी की न्यूनतम मात्रा 3 से 5 प्रतिशत तक बनी रहती है। इसका आशय यह है कि यदि किसी समय किसी देश

1 Full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to further increase in effective demand

—Dudley Dillard

2 Full employment may be considered as the situation in which employment cannot be increased by an increase in effective demand

—Dudley Dillard

3 Ideally full employment would be such as promote continuous maximisation of production and real purchasing power for the people

—Nourse

4 Full employment is a situation where there are more vacant jobs than unemployed men so that normal lag between losing one job and finding another will be very short

—William Beveridge

5 that when only 3 percent to 4 percent unemployment exists in a country the country can be said to have reached full employment Other conditions of full employment mentioned by I L O are that there should be no exploitation of labour and that the workers should be able to find alternate employment early

—I L O Report on Full Employment

म 90 म 98 प्रतिष्ठा तर रायगोर जनगव्या वा गोजगार मित्ता हुआ हा ता उगे पूर्ण गजगार की स्थिति मानता चाहिए ।

(2) पूण गजगार वह स्थिति हाती है जिमम प्रवर्तित मजदूरी की दर पर कार्य राहत वान की राजगार के अन्तर उपलब्ध हा ।

(3) पूण गजगार की अवस्था मे अभिप्राय उन अवस्था म हाता है जबकि वराजगार व्यक्तिया की तुलना म रिक्त स्थान आधार मात्रा म उपलब्ध हा जिमम कि वराजगार ध्यान वान गजगार प्राप्त करन म अधिक् कठिनाई न हा ।

(4) पूण राजगार स्तर प्राप्त हा जान व बाद अथव्यवस्था म कुन व्यय या प्रभावपूर्ण माँग म वृद्धि हान पर उत्पादन तथा गजगार म वृद्धि नहीं हागी ।

**अर्द्ध-विकसित देश तथा पूर्ण रोजगार**—पूण राजगार की विभिन्न धारणाओं विकसित अवस्था म सम्बन्धित है । जहाँ वराजगारी का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण माँग म ध्याप्त कमी हाती है । अर्द्ध-विकसित अथव्यवस्था वान देश म पूण राजगार की स्थिति कभी नहीं पाए जाती ब्याकि एम देश म वराजगारी पूँजी के अभाव तथा तकनीकी प्रगति क अभाव क कारण होती है न कि प्रभावपूर्ण माँग म कमी क कारण । अर्द्ध विकसित देश म अदृश्य वराजगारी संरचनात्मक वराजगारी घणनात्मक वराजगारी आदि पाए जाती है । एमम अदृश्य वराजगारी की प्रमुखता रहती है । फिर भी एम देश म सरकार द्वारा क्य णकारा राज्य का स्थापना हेतु डा मक्य विषय जान है उनम पूण गजगार का उद्देश्य मानकर वराजगारी दूर करन क प्रयास किए जान है ।

**पूर्ण रोजगार की नीति (Policy for Full Employment)**—वराजगारी मानव जानि व तिरा समम वरक अ नशाप है । वराजगारा क दुःप्रभाव म उपलब्ध श्रम शक्ति क हान ता है हा माथ हा माथ एमम गार्ह्य आय तथा गार्ह्य उत्पादन म कमी म रहन-सहन क स्तर म गिरावट ट्रेण तथा हीन भावना तथा रग सघन आदि कुरीनियाँ पनवता । एम कारण पूण गजगार की नीति हीं कमी हा गयती है जिम अपनाकर समाज वराजगारी क दुःप्रभाव म बच मवता है । पूण गजगार हेतु राष्ट्रीय नीति का हाना वान आवश्यक है । परन्तु पूण गजगार की स्थिति का प्राप्त करन आसान कार्य नहीं है । पूण गजगार हेतु निमित्त मौद्रिक तथा राजस्वारीय नीतिया का मिश्रण हाता है । जैसा कि एम जानत है, विकसित तथा अर्द्ध विकसित अवस्थावस्था म मौद्रिक तथा राजस्वारीय नीतिया क उद्देश्य म विभिन्नता पाई जाती है इसलिए पूण गजगार प्राप्ति हेतु इन देश क प्रयाना म भी अन्तर-रूपन का मिश्रण है । विकसित देश म आर्थिक स्थिरता का वनाए रखकर पूण गजगार प्राप्त करन का प्रयास किया जाता है तथा महत्वपूर्ण माँग म वृद्धि क द्वारा वराजगारी का दूर किया जाता है । अर्द्ध-विकसित देश म आर्थिक विकास की गति का तीव्र करन का प्रमुख समस्या हाती है और एम देश म पूँजी के अभाव तकनीकी अज्ञानता का दूर करन तथा उपलब्ध प्राकृतिक साधनता का समुचित विदाहन करन वराजगारा का दूर करन क प्रयास किए जान है । पूण गजगार प्राप्ति हेतु निम्नान्वित नीतिया एम उपाय अपनाए जा सकत —

### (i) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

मौद्रिक नीति क अन्तगत व सभी उपाय वान है जिमका सरकार जनता द्वारा किए जान ता क कुन व्यय का विनियमित करन क लिए करती है । मौद्रिक नीति विभिन्न उद्देश्य ता पूर्ण क लिए अपनाई जा मरती है इनम पूण गजगार की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य है । मौद्रिक नीति क अन्तगत मुद्रा तथा माँग नीति का नियन्त्रित करन पूँजी विनियानन प्रभावपूर्ण माँग तथा गजगार के स्तर का प्रभावित किया जाता है । पूँजीवादों एवं विक-



वित्त करती है वास्तविक मजदूरी को नहीं। देखा जाए तो वास्तविक मजदूरी ही महत्वपूर्ण होती है। परन्तु मजदूरी नीति का सम्बन्ध मौद्रिक मजदूरी से ही होना है। मजदूरी नीति ऐसी हो कि जिससे श्रमिक तथा उत्पादक दोनों ही वर्गों के हितों की सुरक्षा हो सके। इसका आशय यह है कि मजदूरी की दरें इतनी अधिक न हों जिनसे कि लागते इतनी बढ़ जायें कि उसका लाभ श्रमिकों को न मिल सके और मजदूरी इतनी कम भी न हो जिनसे कि श्रमिकों के लिए जीवन यापन ही दुर्लभ हो जाए। मजदूरी दर व लाभ के अनुपात में उचित सन्तुलन रहना चाहिए।

मजदूरी नीति इस प्रकार से भी निदिष्ट हो कि उद्योगों व्यापारों तथा अन्य क्षेत्रों में मजदूरी दर विशिष्ट रूप से प्रभावित की जाए न कि मजदूरी के सामान्य स्तर को। इसके साथ ही मजदूरी नीति ऐसी हो जिनसे मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं की कीमता में स्थिरता बनी रहे। स्थिर कीमता के साथ बढ़ती हुई मजदूरी नीति अपनाता अधिक श्रेयस्वर होता है।

प्रो० ए० पी० लनर का कहना है कि मजदूरी नीति मापक आकर्षण सूचकांक (Index of Relative Attractiveness) पर आधारित होनी चाहिए। मजदूरी नीति ऐसी हो ताकि उत्पादकता में वृद्धि के साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जा सके। उन स्थानों में मजदूरी में तजी से वृद्धि होना चाहिए जहाँ पर मापक आकर्षण सूचकांक राष्ट्रीय औसत सूचकांक से नीचा हो तथा उन स्थानों में मजदूरी दर कम हो जहाँ मापक आकर्षण सूचकांक राष्ट्रीय औसत सूचकांक से ऊँचा हो।

2. कीमत नीति (Price Policy)—पूरा राजस्व की प्राप्ति हेतु कीमत समर्थन नीति भी अपनाई जा सकती है। मदी के समय कीमतें जब गिरती हैं तो सरकार का न्यूनतम कीमतें घापित करना चाहिए परन्तु यदि कीमत स्तर इस निर्धारित कीमत स्तर से नीचे जान की प्रवृत्ति दिखलाए तो स्वयं सरकार को अनिश्चित स्टॉक की खरीद करना चाहिए। जब तेजी काल में कीमत-स्तर अनावश्यक रूप से बढ़ रहा हो तो उसका बाजार में विपरीत हेतु लाकर वस्तुओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार मदी तथा तजी काल दोनों ही स्थितियों में समर्थन कीमत नीति (Price Support Policy) अपनाकर राजस्व में वृद्धि करना सम्भव होता है।

3. भ्रम बाजार की अपूर्णताओं को दूर करने की नीति (Policy for Removing Imperfections of Labour Markets)—इस नीति का आशय यह है कि विभिन्न व्यवसायों एवं क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करना चाहिए। इस के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं—

(i) जिन क्षेत्रों या व्यवसायों में श्रमिकों की माँग अधिक हो उनमें उनकी पूर्ति हेतु निरन्तर सरकार को सजग रहना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

(ii) रोजगार कार्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिनसे कि बेरोजगार व्यक्ति वहाँ पहुँचकर अपना पंजीकरण करा सके तथा राजस्व सृजन करने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यालयों में रिक्त स्थानों की सूचना दे सके।

4. उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption)—बेरोजगारी दूर करने के लिए माँग का निरन्तर बन रहना भी आवश्यक होता है जो बिना उपभोग वृद्धि के सम्भव नहीं होता। इसके लिए विशेषतः पर मन्दीकाल में सरकार को मार्गजनिक व्यय बढ़ाने चाहिए जिनसे लोगों को आय बढ़े तथा उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करेगी। परिणामस्वरूप रोजगार का स्तर भी ऊँचा उठेगा।

**5 विनियोगो मे वृद्धि (Increase in Investment)**—आ० काम न विनियोगा म वृद्धि द्वारा अल्पकाल मे रोजगार क स्तर का ऊँचा उठान का दान कहा था। उहूँ न माँशीकाल म मावजनिक तथा निजा विनियोग दान का ही वददान का मुभाव लिया था। उनका कहना था कि विनियोग वददान म रागा का अय बढगा तथा राजगार मिलगा। वह कहते ह कि विनियोग दा घाता पर निभर कगता है (i) व्याज का दर (ii) पूजा की मीमात उत्पादकता। व्याज की नाचा दर द्वारा लागो का अधिक पूजा की माँग वददान तथा विनियोगा क लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नीचा व्याज का दर लाग करना सस्ती मुद्रा नीति भा कहलत है।

विनियोगा म वृद्धि क लिए आवश्यक है पूजा का सामात उत्पादकता अथात् पूजा निवेश स होने बाल लाभ स होता है। जब निजा माहमी पूजा निवेश कगता है तो वह पूजा की सामात उत्पादकता तथा व्याज की दर का तुलना करता है। सरकार म पूजा की मीमात उत्पादकता या कुशलता म काफी गिरावट आ जाता है और व्याज की दर म भी यह नीची गिर जाता है तो निजा साहसिया क लिए पूजा निवेश अलाभकर हाता है। इसलिए कीस न मदा बाल म मावजनिक निवेश म वृद्ध क लिए सरकार का विभन निर्माण कार्यों का प्रारम्भ करन की बनाव दी था। इसम लागो का राजगार प्राप्त हागा अय बढगा उपभाग म वृद्धि स प्रभादपूण भाग बढगा जिमसे निवेश लाभप्रद बन रहग।

**6 विदेशी व्यापार मे वृद्धि (Increase in Foreign Trade)**—पूण राजगार हदु विदेशा व्यापार म वृद्धि क लिए प्रयास करना चाहिये। विदेशी व्यापार म वृद्धि होन स निर्यातक उद्योगा म लग श्रमिका का माँग बढगा। अर्द्ध विकसित दशा म विदेशा पूजा की आवश्यकता भा अधिक हाती है जिसम एस दश विदेशा स तकनाक तथा आवश्यक वस्तुआ का आयात कर सक। विदेशा व्यापार म वृद्धि म एक आर ता ँग के लिए पयाप्त विदेशी मुद्रा अजित करना सम्भव होगा दूसरी आर निर्यात उद्योगा का प्रोत्साहन मिलगा और श्रमिका की माँग बढगा उनका पर्याप्त राजगार मिलेगा अय बढगा उपभाग प्रवृत्ति म वृद्धि हागा और उत्पातका को भी पर्याप्त प्रोत्साहन उत्पादन का जारी रखन क लिए बना रहगा।

**निष्कष (Conclusion)**—पूण रोजगार की नीति एक लक्ष्य क रूप म एक श का स्वाकार करना चाहिए। पूण राजगार क लक्ष्य का प्राप्त करन के लिए सरकारी हस्तक्षप की नाति की आवश्यकता होती है क्यार्कि सरकार क द्वारा हा विभिन्न प्रकार का नीतिया जैसे मौद्रिक राजकोषीय तथा अय नातिया क मध्य ममावय तथा उचित तन मन स्था पित किया जा सकता है। पूजावाता तथा विकसन अवस्था की आता समाजवाता या नियन्त्रित अथ व्यवस्था बान दशा म पूण राजगार का प्राप्त करना थोडा सरन हाता है। इसका कारण यह है कि नियन्त्रित अथ व्यवस्था म विभिन्न नातिया का आवश्यकता नुमार उहूँ अपनाया जा सकता है तथा उतम सामग्र्य स्थापित करके उहूँ जोर अच्छे रूप से नियन्त्रित किया जा सकता है।

परीक्षा प्रश्न

1 बराजगारा स आप क्या समझत ह ? बराजगारा क विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए।

(What do you understand by unemployment Explain different types of unemployment)

2 अप विकसित दशा म बराजगारा क क्या कारण ? एम एम म बराजगारा दूर करन क लिए आप क्या मुभाव दग ?

(What are the causes of unemployment in under-developed countries ? What measures would you suggest to remove unemployment in such countries ?)

3 पूर्ण रोजगार में आप क्या समझते हैं ? पूर्ण रोजगार नीति की व्याख्या कीजिए।

(What do you mean by full employment ? Discuss full employment policy)

4 निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी लिखिए।

- (i) घषणात्मक बेरोजगारी
- (ii) संरचनात्मक बेरोजगारी
- (iii) अदृश्य बेरोजगारी
- (iv) चक्रीय बेरोजगारी
- (v) मौसमी बेरोजगारी
- (vi) एच्छित तथा अनेच्छित बेरोजगारी।

Write notes on any two of the following

- (i) Frictional unemployment
- (ii) Structural unemployment
- (iii) Disguised unemployment
- (iv) Cyclical unemployment
- (v) Seasonal unemployment
- (vi) Voluntary and Involuntary unemployment

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन-सा सही है और कौन सा गलत है।

- (i) पूर्ण रोजगार का स्थिति का बनाए रखना जबवा बेरोजगारी का समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाया ज़रूरी है।
- (ii) घषणात्मक बेरोजगारी एक अस्थायी प्रकार का बेरोजगारी होती है।
- (iii) छिपी हुई बेरोजगारी एक अस्थायी बेरोजगारी होता है।
- (iv) संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण अव्यवस्था की संरचना का दोषपूर्ण होना है।
- (v) चक्रावृत्त बेरोजगारी विकसित देशों में होती है जो समय-समय पर स्थित व्यापार चक्रों के कारण होती हैं और मंदी के कारण होती हैं।
- (vi) अदृश्य बेरोजगारी विकसित अव्यवस्थाओं में पाई जाती है।
- (vii) पूर्ण रोजगार का अर्थ यह है कि प्रचलित मजदूरी का दर पर काम चाहने वालों का साथ मिलना है।
- (viii) पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जहाँ अदृश्य बेरोजगारी अनुपस्थित रहती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) गलत है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) सही है। (vi) गलत है। (vii) सही है। (viii) गलत है।



## अध्याय 4

## रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त

## (CLASSICAL THEORY OF EMPLOYMENT)

## भूमिका

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त का वास्तविक रोजगार का सिद्धान्त भी कहा जाता है। यह सिद्धान्त का समर्थन प्रो. एडम स्मिथ प्रा. रिचार्ड्स, जे. व. स तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों ने किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि अव्यवस्था में सर्वप्रथम रोजगार की स्थिति बनी रहता है और यदि कभी बेरोजगारी हो तो अव्यवस्था में स्वयं ऐसे कारण उपस्थित हो जायेंगे जिनसे बेरोजगारी समाप्त होकर पूरा रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पूरा रोजगार को सामान्य स्थिति प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे और बेरोजगारी को असामान्य स्थिति। उनकी इस धारणा का मुख्य आधार प्रा. जे. बी. से (Prof J B Say) का बाजार नियम या जिनके अनुसार 'पूरा अपना माँग स्वयं जुदा कर लेता है।' (Supply creates its own demand) प्रा. जे. एम. सिन्ड का कहना था कि 'वास्तविक उत्पादन चाहे कितना ही क्यों न हो यह वास्तविक माँग से किसी भी हालत में अधिक नहीं हो सकता। इसी आधार पर इन विद्वानों का दावा था कि अनच्छिक तथा सामान्य बेरोजगारी की स्थिति पाई नहीं जाएगी।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा प्रा. जे. बी. से का पूरा विश्वास था कि जब अव्यवस्था स्वतंत्र रूप में कार्य करती है तो बेरोजगारी तथा अच्छिक उत्पादन की स्थिति हा ही नहीं सकता। प्रतिष्ठित विद्वानों का कहना था कि पूरा रोजगार की स्थिति वाला समाज में अच्छिक तथा मध्यमक (Voluntary and Frictional Unemployment) हा ही नहीं सकता। अच्छिक बेरोजगारी से आशय उस स्थिति से होता है जब प्रचलित मजदूरी दर पर श्रमिक कार्य करने का तयार न हो। ऐसी स्थिति कि जब धामिरा का कार्य उपलब्ध हो और वह कार्य नहीं करना चाहें तो इस बेरोजगारी का मना नहीं दी जा सकता। मध्यमक बेरोजगारी से आशय उस स्थिति में है जब कि श्रमिकों का रोजगार सम्बन्ध था वाता वा पूरी जानकारी न हो या बाजार मध्यम अपूर्णता तथा अपना अज्ञानता के कारण श्रमिक बेरोजगार रहे।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि अनच्छिक तथा सामान्य बेरोजगारी का स्थिति नहीं पाई जा सकती। उनका कहना था कि अनच्छिक बेरोजगारी सम्बन्ध नहीं है अर्थात् अनच्छिक बेरोजगारी का न हान पर हा पूरा रोजगार का स्थिति पाई जाएगी। अनच्छिक बेरोजगारी का न पाया जाता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धान्त का मुख्य विशेषता है। उनका विश्वास था कि जब काम करने वाले व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहते तो ऐसा उन समय होता है जब कि अव्यवस्था के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा या गड़बड़ हो जाए जैसे—(1) मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रम संधि द्वारा श्रमिकों

(7) मुद्रा वस्तु विनिमय की अमूर्त धारणा का अर्थ यह है कि अतिरिक्त आरंभ नहीं है।

से क नियम की आलोचनाएं (Criticism of Say's Law)

प्रांज वा मर वाजार नियम का आलोचनाएं अनेक अर्थशास्त्रियों ने की है। प्रा० ज० वा० मर वाजार नियम का सबसे बड़ा आघात वर्ष 1929-30 का मंदान पहुँचाया। मन्त्रालय में पहले ही प्रा० मर वाजार नियम का आलोचना हान गयी। प्रा० हागन ने मर नियम का सबसे पहला आलोचना का पर तु उत्तर प्रहार की मर नियम का विरुद्ध अतिरिक्त तर्क नही था। मर 1936 में प्रकाशित आर्थिक ध्यान (The General Theory) में प्रा० मर वाजार नियम का बड़ी आलोचना प्रांज जम के मर वा। एमके अलावा अमराकन अर्थशास्त्रियों वी० वरान अग्रजा अर्थशास्त्रियों प्रा० राबर्टसन ने भी मर नियम का आलोचना का। एनर नियम का मरम बढ आलोचना प्रांज जम कीमि ह। प्रा० फी० एम स्वार्ज का एम मरम धर्म कहता है कि 'कीम की मरम बढा मरमता एमरा अमरिक्त अर्थशास्त्रियों का ज वा मर वाजार नियम मरुत्पारा स्थाना था। प्रां मर वाजार नियम का प्रमुख आलोचना एं निम्न प्रकार मरुत्पारा जा सकता है।

(1) नियम अवास्तविक है— आलोचना का कहना है कि प्रां मर वाजार नियम मर अवास्तविक मायना पर आधारित है कि जितना मात्र उत्पादन होता है वह मांग का मारा विक्रित होता है। अर्थात् समस्त आय का मांग 'पेभार' कर दिया जाता है या फिर उस निवेश कर लिया जाता है। आय स्वतः एवाम् उत्पादन पर व्यय कर ला जाता है जिसे मरमा माधन का पूष राजगार मित जाता है। आय का यह प्रवाह (Flow) तथा कार रहता है। मां मर कहता है पुन मांग मरुमी आ रहता है क्योंकि समस्त आय का समस्त उत्पादन का प्रय करन पर व्यय नही किया जाता।

(2) मुद्रा बचत विनिमय का माध्यम ही नहीं है प्रा० मर मुद्रा का विनिमय माध्यम काय का है प्रमुख माना है। प्रा० कीम का कहना है कि मुद्रा का एक अर्थ काय मूल्य संचय ना है अर्थात् भावा जावश्यकताओं का पूर्ति अथवा विभिन्न उद्देश्यों का पूर्ति हेतु मुद्रा का संचित करन रखा जा सकता है। एमके आय व्यय प्रवाह टूट जाता है और अति उत्पादन तथा बराजगारा का स्थिति दखा जा सकता है।

(3) बचत एवं विनियोग की समानता—प्रा० मर का कहना था कि 'आज र दर र माध्यम मरुत्पाना मरुत्पानता स्थापित का जा सकता है। प्रा० काय कहता कि बचत तथा निवेश 'आज की दर र अर्थ का लाभ का आग मर अतिरिक्त भावत हान है। प्रा० काय का कहना है कि आय का स्वतः मरुत्पानता उरुत्पानता एर विनियोग मरुत्पानता स्थापित किया जा सकता है।

(4) सरकारी हस्तक्षेप—प्रा० मर का नियम स्वसंचालित एवं मरुत्पानित मायना पर आधारित है। प्रा० कीम ने कहा कि अर्थ व्यवस्था मरुत्पानता स्थापित करन के लिए अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र रूप मरुत्पानता स्थान पर ररुत्पारा एमके एर का नाति अपनाना चाहिए।

1 | Keynes greatest achievement was the liberation of Anglo American Economists from tyrannical dogmatic Say's law

(5) मजदूरी में कटौती करना आवश्यक नहीं है—प्रो० पगून ने 7 नियम का समर्थन करते हुए कहा कि तब तक मजदूरी में कमी करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। प्रो० कांस न इस विचार की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरी लागत का अंश ही नहीं बल्कि एक प्रकार से साधन की आय है। मजदूरी में कटौती का आशय प्रभावपूर्ण माँग में कमी लाएगी उत्पादन कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी।

(6) दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण—प्रो० से का नियम दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण पर आधारित है अर्थात् दीर्घकाल में माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। प्रो० वीन्स का कहना है कि वास्तविक स्थिति तो अल्पकालीन साम्य की होती है जिसके बारे में प्रतिष्ठित विद्वान कुछ नहीं कहते।

(7) पूर्ण तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता—प्रो० से का नियम वृद्धि तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो वृद्धिपूण है। इस सम्बन्ध में आलोचना का कहना है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है।

(8) मुद्रा आय, उत्पादन तथा रोजगार को भी प्रभावित करती है—प्रो० से के नियम के अनुसार मुद्रा एक आवरण मात्र है जिसमें वस्तुएँ तथा सेवाएँ हमारे पास लिपट कर आती हैं। जबकि प्रो० वीन्स का कहना है कि मुद्रा आय उत्पादन रोजगार तथा अन्य घटकों के निर्धारण में एक स्वतंत्र भूमिका निभाती है।

प्रो० से के बाजार नियम की उपर्युक्त आलोचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रो० से का नियम वास्तविक एवं व्यवहारिक है। प्रो० हेबर्लर ने से के नियम का खण्डन करते हुए कहा है कि—आधुनिक आर्थिक सिद्धान्त में से के नियम के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। तब परम्परावादी अर्थशास्त्रियों ने भी अपने मुद्रा तथा व्यापार चक्र सम्बन्धी सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कार्यों में इसको पूरी तरह नकार दिया है।<sup>1</sup>

### प्रो० से के नियम की क्रियाशीलता (Applicability of Say's Law)

प्रो० जे० बी० से के बाजार नियम के समर्थक इस नियम की त्रिपाशीलता को वास्तविकता मानते हैं और कहते हैं कि यह नियम सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होता है। से के जिन मान्यताओं की व्याख्या की है यदि वह नहीं हों तो नियम भी लागू होगा।

(1) वस्तु विनिमय व्यवस्था में से का नियम (Say's Law in Barter System)—से के नियम के समर्थक कहते हैं कि यह नियम वस्तु-विनिमय प्रणाली में लागू होता है। इसकी मान्यता यह है कि मुद्रा का व्यर्थ प्रवाह संभव नहीं रहता है। एक विप्रेता द्वारा धन के लिए अपनी वस्तुएँ बेची जाती हैं जैसे ही इन वस्तुओं से प्राप्त धन उस मिलता है वह अन्य वस्तुओं पर व्यय कर देता है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय सरल बनाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय अनुपात समान रहते हैं।

1 There is no place and no need for say's law in modern Economic Theory and that it has been completely abandoned by neo classical in their actual theoretical and practical work on money and the business cycles'

आधुनिक आशाश्रयी इस कथन में सहमत नहीं है। उनसे अनुमान वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय अनुपात सर्वद्वय बराबर हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इनकी माँग और पूर्ति में असम्यक्ता ही गिनति उत्पन्न हो सकती है और नियम लागू नहीं होगा।

(2) मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से वा नियम (Says Law in Monetary Economy)— परम्परावादी तथा नव परम्परावादी सिद्धान्तों ने कहा कि प्रो० में वा नियम मौद्रिक व्यवस्था में भी लागू होता है। वे इस सम्बन्ध में दो तर्क देते हैं।

(i) मुद्रा विनिमय का एक माध्यम मात्र है। मुद्रा वस्तुओं का एक समूह का विनिमय बरतने के बाद दूसरी वस्तुओं के समूह का विनिमय सम्भव कराने लगती है। (ii) उत्पादन बढ़ने के साथ आय में वृद्धि होती है तथा उतना ही व्यय बढ़ जाता है। जो धन बचा लिया जाता है उसका विनिर्योग हो जाता है तथा धन संचय नहीं किया जाता। आय वृद्धि जितनी मात्रा में बढ़ती है उतनी ही मात्रा में व्यय भी किया जाता है। इससे ही माँग तथा पूर्ति में सर्वद्वय सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

प्रो० पीगू का मजदूरी कटौती सम्बन्धी रोजगार सिद्धान्त (Prof Pigou's Wage-cut Theory of Employment) परम्परावादी अर्थशास्त्री प्रो० पीगू (Prof A C Pigou) की यह धारणा थी कि यदि श्रमिक अपनी सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी देने को तैयार रहें तो श्रम बाजार में कमी बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। वे कहते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण श्रमिका द्वारा उंची मौद्रिक मजदूरी की माँग, सरकारी हस्तक्षेप तथा श्रम सभा (Labour Unions) का प्रभाव पाया जाना है। अव्यवस्था यदि स्वतन्त्रतापूर्वक बाय बर ता प्रत्येक दशा में मजदूरी का निर्धारण श्रमिका की माँग और पूर्ति के आधार पर तय होगा और मजदूरी की दर मजदूरी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) के बराबर हो जायगी। प्रो० पीगू कहते हैं कि "स्थिर दशाओं में श्रमिकों का मध्यम वर्ग जायदादा पूर्ण प्रतिप्रोत्तितता पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने और उस बनाए रखने की एक निश्चित गारन्टी है।"

यदि किसी समय श्रमिकों की पूर्ति उनकी माँग से अधिक हो जाय तो श्रम-बाजार में मजदूरी की दर गिरने लगेगी और यह प्रसन्न तब तक चलता रहेगा जब तक कि श्रम की माँग और पूर्ति में समानता स्थापित नहीं हो जाती। श्रमिका की माँग उनकी पूर्ति से बढ़ने पर मजदूरी की दरें तब तक गिरनी रहेंगी जब तक कि माँग और पूर्ति दोनों बराबर नहीं हो जाती। इस प्रकार मजदूरी की लोचता ही अव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को ला सकती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि किसी समय बेरोजगारी पैदा जाए और वह काफी समय बनी रहे तो यह समझना चाहिए कि मजदूरी में लोचनीयता व्याप्त है। ऐसी दशा में मजदूरी की दर में कमी करने रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी बँधे हुए होगी इसके सम्बन्ध में प्रो० पीगू का स्पष्ट मत है कि इसमें अर्थात् मजदूरी में कटौती उत्पादन लागत को गिरायेगी—बँधने कम होंगी—वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी—उत्पादन अधिक होगा—रोजगार का स्तर उँचा उठेगा। मजदूरी कटौती में त्राणत घटने का एक प्रभाव यह होगा कि उत्पादकों के लाभ बढ़ेंगे। अधिर पूँजी विनिर्योग होयगा—उत्पादन तथा रोजगार दोनों बढ़ेंगे। प्रो० पीगू कहते हैं कि 'श्रम बाजार में बेरोजगारी के दबाव के कारण मजदूरी कटौती का प्रसन्न तब तक जारी रहेगा जब तक उन सभी व्यक्तियों जो रोजगार के हच्छुव हैं, रोजगार नहीं मिल जाता।'

### पीगू के सिद्धान्त की आलोचनायें (Criticism of Pigou's Theory)

(1) मजदूरी कटौती का भ्रुटिपूर्ण विचार—प्रो० पीगू का सिद्धान्त बँधे तो देयमें में प्रसन्न तब नहीं प्रतीत हो सकता है परन्तु यह उतना नहीं नही है जितना कि यह दिखता है।

प्रो० पीगू तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मजमें यही भूत यह थी कि विद्वान्ता न मजदूरी कटौती को एक पदम या उद्योग की अपेक्षा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक औपधि मान लिया। यदि यह मान भी लिया जाए कि एक उद्योग ने मजदूरी कटौती करने रोजगार बढ़ेगा तो भी उम उद्योग में लग व्यक्तियों की कुल माँग उम उद्योग के उत्पादन की माँग से बही अधिर मात्रा में कम होगी। यदि सभी उद्योगों में रोजगार बढ़ाने हेतु मजदूरी कटौती की जायगी तो इनमें लोगों की आय (श्रमशक्ति) कम होगी जिससे प्रभावपूर्ण माँग इतनी गिर जायेगी कि रोजगार के स्थान पर बेरोजगारी ही बढ़ेगी।

(2) आय पक्ष की अवहेलना—प्रो० पीगू के सिद्धान्त की दूसरी बन्धी यह थी कि उन्होंने मजदूरी कटौती के केवल लागत पक्ष के बारे में सोचा तथा आय पक्ष की अवहेलना की। यदि मजदूरी एक उत्पादक के लिए लागत है तो एक साधन की आय का स्रोत भी है जो माँग को प्रभावित करती है। रोजगार तो कुल माँग पर निर्भर करता है जो आय द्वारा निर्धारित होता है। मजदूरी कटौती से श्रमशक्ति (आय) के कम होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी।

(3) व्यावहारिकता की कमी—प्रो० पीगू के सिद्धान्त पर एक अन्य आरोप उसने व्यावहारिक पक्ष का कमजोर होना है। प्रो० कीन्स कहते हैं कि पीगू का मजदूरी कटौती का विचार सैद्धान्तिक दृष्टि से तो उचित लग सकता है परन्तु उमका व्यावहारिक पक्ष अत्यधिक कमजोर है।

(4) उपभोग प्रवृत्ति की अवहेलना—प्रो० कीन्स ने पीगू के विचार की आलोचना करते हुए कहा कि पीगू यह नहीं समझ पाय थे कि मजदूरी कटौती से उपभोग तथा विनियोग दोनों ही प्रभावित होते हैं। उन्होंने उपभोग प्रवृत्ति पर मजदूरी कटौती के पड़ने वाले प्रभावों की अवहेलना करते हुए अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया। मजदूरी कटौती रोजगार के स्तर को नहीं बढ़ाने में मफल होगी जब कि इससे उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) बढ़े।

### रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एक दृष्टि से (Classical Theory of Employment at a Glance)

रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त से हमारा तात्पर्य उम रोजगार सिद्धान्त से है जिनका समर्थन प्रो० एडम स्मिथ रिकार्डों जे० बी० से जे० एम० मिच माशल तथा पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। प्रो० जे० बी० से तथा प्रो० पीगू के रोजगार सम्बन्धी विचार चाहे उन्होंने पृथक रूप से रखे हों परन्तु इन दोनों के विचार प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त के दो प्रमुख स्तम्भ हैं। संक्षेप में तथा एक दृष्टि में हम प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धान्त को निम्न प्रकार रख सकते हैं —

(1) अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजित होने की क्षमता होती है। जो कुछ भी उत्पादित होता है वह सभी बिक जाता है।  $\Sigma O = \Sigma C$  कुल उत्पादन = कुल उपभोग।

(2) अति उत्पादन की स्थिति नहीं पाई जाती। प्रत्येक अनिश्चित उत्पादन अति श्रमशक्ति को जन्म देता है अर्थात् आय = व्यय ( $\Sigma I = \Sigma E$ )।

(3) अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है।

(4) वचत एवं विनियोग में समानता ब्याज की दर के माध्यम से होती है।

$$(\Sigma S = \Sigma I)$$

(5) जब धर्मिक अथवा सीमान्त उत्पादनता से अधिक मजदूरी की माँग करते हैं तभी बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है।

(6) उस प्रकार मजदूरी बराबरगरी नहीं पाई जाती है।

(7) अर्थव्यवस्था में पूरा रोजगार एक सामान्य स्थिति है और बेरोजगारी असामान्य स्थिति।

(8) पूर्ण प्रतिपायिता की स्थिति में मजदूरी में कमी के कारण पूरा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

### प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticism of the Classical Theory of Employment)

प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की बड़ी आलोचना प्रो० वीन्स ने की। प्रारम्भ में प्रो० वीन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में हमारे सामने आए परन्तु बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की विशेष रूप में रोजगार सिद्धान्त की आलोचना की। उनका स्पष्ट मत था कि रोजगार के बारे में प्रो० जे० वी० में तथा प्रो० पी० वी० में मत इस आधार पर असामान्य है कि अर्थव्यवस्था में पूरा रोजगार की स्थिति पाई जाती है और बेरोजगारी नहीं होती। प्रो० वीन्स ने 1929-30 की मन्दी को देखा था और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बेरोजगारी एक असामान्य स्थिति नहीं है। यदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का पूरा रोजगार का विचार नहीं होता तो मन्दी के समय बेरोजगारी नहीं पाई जाती। वीन्स ने प्रो० जे० वी० में रोजगार नियम का खण्डन किया तथा प्रो० पी० वी० द्वारा मजदूरी बढ़ाने द्वारा बेरोजगारी दूर करने के प्रस्ताव को अनुचित और असामान्य दर्शाया।

प्रो० वीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ पर आलोचना की।

(1) पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य घटना नहीं है—प्रो० वीन्स का कहना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य घटना नहीं है। पूँजीवादी प्रणाली तथा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार नाना एक सामान्य घटना होती है।

(2) अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित नहीं होती—प्रो० वीन्स का कहना था कि अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित नहीं होती। वीन्स ने बताया कि समाज में घन व जनसंख्या की व्याप्त असमानताओं व कारण एक ओर तो धनी वर्ग की आवश्यकताएँ पहन में ही सन्तुष्ट हो चुका होती हैं और उमरे द्वारा उपभोग की मात्रा में वृद्धि नहीं होती दूसरी ओर निम्न व्यक्तियों में व्याप्त गरीबी के कारण उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाता है तथा कुल उपभोग में कमी आती है। कुल उपभोग कुल उत्पादन की अपेक्षा कम रहता है और समर्थ माँग में गिरावट आती है। इस असन्तुलन व अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप द्वारा ठीक किया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था में समायोजित होने की शक्ति नहीं पाई जाती।

(3) मजदूरी में बढ़ोतरी द्वारा रोजगार बढ़ाना एक असमर्थ धारणा है—प्रो० वीन्स ने कहा कि प्रो० पी० वी० का मजदूरी बढ़ोतरी द्वारा रोजगार के स्तर को बढ़ाना एक श्रुतिपूर्ण धारणा कमजोर है। प्रो० वीन्स कहते हैं कि मजदूरी में बढ़ोतरी द्वारा नहीं बरन् प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। मजदूरी की बढ़ोतरी रोजगार के स्तर को बढ़ाने के स्थान पर गिरती है। इसके अलावा धर्मसंधों व प्रभाव के कारण मजदूरी में बढ़ोतरी करना सम्भव नहीं होता।

(4) दीर्घकालीन मान्यता—प्रो० वीन्स का कहना है कि प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धान्त दीर्घकालीन मान्यता पर आधारित है जब कि हम जिन समाज में रहते हैं, वहाँ अल्पकालीन स्थिति होती है।

(5) बचत एवं विनियोग की समानता—प्रो० कींस का विचार है कि प्रतिष्ठित विद्वानों की यह धारणा है कि बचत एवं विनियोग समान रहते हैं अर्थात् लोग अपनी समस्त आय का उपभोग कर लेते हैं। यदि कुछ बचत होती है तो उसे विनियोजित कर दिया जाता है। उनका कहना है कि बचत एवं विनियोगों में समानता व्याज की दर की अपेक्षा आय के स्तर पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं बून आय हमेंना व्यय ही कर दी जाए इस बात का भी सफ़टन प्रो० कींस ने किया और बताया कि आय का एक भाग बचा लिया जाता है और यदि इस भाग को विनियोग न किया जाए तो बेरोजगारी पैदा जाएगी।

(6) अवास्तविक मान्यताएँ—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धान्त पूरा रोजगार पूरा प्रतियोगिता अवन्ध नीति (Laissez faire) तथा कीमल-प्रक्रिया जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यह मान्यताएँ वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती इंग्लिश प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धान्त अव्यावहारिक है। वर्तमान समय में बिना सरकारी हस्तक्षेप के किसी भी दश में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना हुआ में महन बनाने जैसी बात होगी। प्रो० कींस ने कहा कि परम्परावादी अर्थशास्त्र में जिन विशिष्ट सिद्धांतों की व्याख्या की गई है वे उस वर्तमान वास्तविक समाज के अनुसार नहीं हैं जिसमें हम रहते हैं। यह सिद्धान्त एक अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है।

### प्रतिष्ठित तथा प्रो० कींस की विचारधाराओं में अन्तर (Difference between Classical and Keynesian Views)

इन दोनों विचारधाराओं में निम्न अन्तर पाए जाते हैं 96195

(1) प्रो० कींस की विचारधारा अल्पकालीन सन्तुलन की व्याख्या पर आधारित है जबकि प्रतिष्ठित विद्वान् दीर्घकालीन सन्तुलन पर जोर देते हैं।

(2) प्रतिष्ठित विद्वान् पूँजी निर्माण के लिए बचतों को आवश्यक मानते हैं जबकि कींस कहते हैं कि बचतों प्रभावपूर्ण माँग को गिराती है जिससे रोजगार का स्तर गिरता है।

(3) प्रतिष्ठित विद्वान् अथव्यवस्था में पूरा रोजगार की स्थिति को सामान्य बात मानते हैं जबकि कींस का कहना है कि पूँजीवादी अथव्यवस्था में बेरोजगारी एक सामान्य घटना होती है।

(4) प्रतिष्ठित विद्वान् प्रचलित मजदूरी की दर में कटौती करके पूरा रोजगार के स्तर को प्राप्त करने का सुझाव देते हैं जबकि कींस का कहना है कि मजदूरी कटौती नीति उचित एवं व्यावहारिक नहीं है।

(5) प्रतिष्ठित विद्वान् सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पर अधिक जोर देते हैं जबकि कींस व्यापक आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं।

(6) प्रतिष्ठित विद्वान् की अधिवाश मान्यताएँ अवास्तविक हैं जबकि कींस गतिशील मान्यताओं को अपने सिद्धान्तों में स्पष्टीकरण में प्रयोग करते हैं।

(7) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा विशिष्ट सिद्धान्त पर आधारित है जबकि कींस का सिद्धान्त एक सामान्य सिद्धान्त है।

(8) प्रतिष्ठित विद्वान् सन्तुलित बजट (Balanced Budget) बनाने पर जोर देते हैं, जबकि कींस घाटे के बजट (Deficit Budget) आर्थिक सकट दियोपकर मदीकास में निपटने के लिए जरूरी मानते हैं।

(9) प्रतिष्ठित सिद्धान्त की यह मान्यता है कि पूरा रोजगार की स्थिति पाई जाने पर मुद्रा की पूर्ति करने में कीमत स्तर बढ़ता है। कीमत बढ़ना है कि पूर्ण रोजगार विन्दु से पहले मुद्रा की पूर्ति नहीं हो सकती तब कीमत-स्तर में समानुपातिक दर में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ता है। पूरा रोजगार के बाद मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि कीमत-स्तर को समानुपातिक रूप से बढ़ाएगी क्योंकि तब उत्पादन बढ़ने की सभी सम्भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी।

(10) प्रतिष्ठित सिद्धान्त व्याज का त्याग का पुरस्कार मानते हैं जबकि कीन्स ने बताया कि व्याज की दर स्तर-ता समदर्शी तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा तय होती है।

(11) प्रतिष्ठित सिद्धान्त स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में सम्भव है कि कीमत बढ़ते हैं कि सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

### परीक्षा-प्रश्न

प्र० ० जे० बी० से के बाजार नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(Examine critically Prof J B Say's Law of Markets)

अथवा

पूर्ति अपनी माँग स्वयं पैदा कर लेती है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(Supply creates its own demand Discuss critically this statement)

[संकेत—पहले प्र० जे० बी० से के नियम की नाविक व्याख्या कीजिए बाद में उनके इस सिद्धान्त की आलोचना कीजिए।]

2 रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(Discuss critically the Classical Theory of Employment)

3 प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। किन आधारों पर कीन्स द्वारा इसका सफाई किया गया।

(Explain the Classical Theory of Employment On what grounds has it been challenged by Keynes)

4 क्या भुजुगरी म कटौती द्वारा रोजगार को बढ़ाना सम्भव है? अपने उत्तर की पुष्टि कारण देकर कीजिए।

(Is it possible to increase employment through wage cut? Give reasons for your answer)

5 किस आधार पर कीन्स ने प्रतिष्ठित व्यवस्था को अपने सिद्धांत पर प्रहार किया? उनकी व्याख्या प्रतिष्ठित व्याख्या से किस प्रकार भिन्न है?

(On what basis did Keynes attack the classical system and its conclusions? Where does his system differ from that of classical system?)



(अ) **सैद्धांतिक महत्व (Theoretical Importance)**—प्रो० बीन्स का सिद्धांत वा सैद्धांतिक महत्व निम्न तर्कों द्वारा स्पष्ट होता है

1 प्रो० बीन्स का विचारण व्यापक आर्थिक सिद्धांत व निरूपक महत्वपूर्ण है।

2 प्रो० बीन्स ने अनुसार आय तथा रोजगार का समन्वय अर्थ रोजगार स्तर पर स्थापित हो जाता है।

3 प्रो० बीन्स का सिद्धांत वा सामाजिक सिद्धांत है जो विविध स्थितियों में लागू होता है।

4 प्रो० बीन्स का सिद्धांत का नीति तथा उपपादन सिद्धांत के साथ समन्वित करने में सफल हुए हैं।

5 प्रो० बीन्स का दृष्टिकोण प्रावैशिक है अर्थात् कि उनसे सिद्धान्त में प्रावैशिक तत्वों का समावेश किया गया है जिससे आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करने में सहायता मिली है।

6 प्रो० बीन्स ने विनियोगों को रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि बचत एवं विनियोगों में असंतुलन से अर्थ व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। उपभोग व्यय तथा आय के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए विनियोगों का सहारा लिया जाना चाहिए।

(ब) **व्यावहारिक महत्व (Practical Importance)**— प्रो० बीन्स का सिद्धांत व्यावहारिक पक्षों में निरूपित है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है—

1 प्रो० बीन्स का कहना था कि पूरा रोजगार के निर्धारक तत्व प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि सरकारी हस्तक्षेप की नीति के द्वारा हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने अर्थ व्यवस्था में असंतुलन स्थापित होने पर सरकारी हस्तक्षेप की नीति को महत्वपूर्ण माना है।

2 आर्थिक विकास के लिए सदैव सन्तुलित बजट का सहारा नहीं लिया जा सकता सरकार को विकास की गति तेज करने तथा मंदी से अर्थ व्यवस्था को निवारण के लिए घाटे के बजट बनाना चाहिए।

3 प्रो० बीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) को महत्व की ओर हमारा ध्यान दिनाया।

4 प्रो० बीन्स ने राजवाणीय नीतिक महत्व का ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया साथ ही मौद्रिक नीति की कमियों की ओर भी बताया।

5 प्रो० बीन्स का कहना था कि मजदूरी की दरें घटाने से रोजगार में वृद्धि करना उचित नहीं है।

6 प्रो० बीन्स ने एक उचित मजदूरी नीति तथा कीमत नीति अपनाते वा व्यावहारिक पहलू हमारे समक्ष प्रस्तुत किया।

7 प्रो० बीन्स ने कुल राष्ट्रीय आय कुल उपभोग कुल विनियोग कुल बचत आदि विचारों को लेकर अर्थ व्यवस्था में सामाजिक उत्तरादन नीति (Social Accounting Policy) का तैयार करने की प्रेरणा दी।

कीन्स सिद्धान्त तथा अल्पविकसित देश (Under-developed Countries and Keynes Theory)

अल्प विकसित देशों के लिए वी.के. कीन्स का रोजगार सिद्धान्त निम्न कारणों में लागू नहीं होता—

1 अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वल्प अलग होता है—प्रो० कीन्स का सिद्धान्त विकसित तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए तो नहीं है परन्तु अल्प विकसित देशों के लिए यह नहीं है क्योंकि ऐसे देशों में बेरोजगारी की समस्या आर्थिक उच्चावचन का कारण नहीं आती। ऐसे देशों में बेरोजगारी परम्परागत एवं तत्कालीन पाई जाने वाली होती है। इन देशों में अदृश्य बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या अधिक होती है साथ ही मधुन परिवार प्रणाली और सामाजिक रीतियों के कारण भी बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें जमावा श्रम की अधिकता तथा अन्य कारणों की म्यूनता बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसलिए प्रो० कीन्स का सिद्धान्त अल्प-विकसित देशों में बेरोजगारी दूर करने के लिए लागू नहीं है।

2 अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक विरासत की उच्च दर को प्राप्त करना होता है— प्रो० कीन्स ने कथन विकसित देशों में व्याप्त होने वाली आर्थिक जस्थिरता की समस्या का अध्ययन किया है। अल्प विकसित देशों के मामले में प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की होती है जिसके लिए पूंजी निर्माण तथा पूंजी विनियोजन अति आवश्यक है। पूंजी निर्माण वचन को प्रोत्साहित करने सम्भव होता है। कीन्स वचन करने को अच्छा नहीं मानते थे।

3 कीन्स सिद्धान्त की मान्यताएँ अल्पविकसित देशों के लिए सही नहीं हैं—प्रो० कीन्स की मान्यताएँ दो शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं (1) अल्पकालीन विनियोजन सम्बन्धित (ii) गुणवत्ता सम्बन्धित। कीन्स कहते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन तकनीक श्रमपूर्ति श्रम की वाय-बुझता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्प विकसित देशों के विकास के लिए इन्हीं तत्वों का परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता सम्बन्धी मान्यताएँ, जैसे—अनिच्छित बेरोजगारी वस्तुश्रम तथा सेवाओं की लाचपूषण पूर्ति, वच्चें माल की लोचपूषण पूर्ति, उपभोग पदार्थों को निर्मित करने वाले उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता या होना आदि अल्प-विकसित देशों में नहीं पाई जाती इसलिए इन्स का सिद्धान्त भी अल्प विकसित देशों में नहीं लागू पाया जाता। ऐसे देशों में अल्प-रोजगार, अदृश्य बेरोजगारी तथा अर्थ-व्यवस्था की अकुशलता से गतिशील होना आदि बातें गुणवत्ता की त्रियाशीलता में बाधा पहुँचाती हैं।

4 घाटे की वित्त व्यवस्था और सस्ती मुद्रा नीति का लाभकारी न होना—अल्प विकसित देशों में सस्ती मुद्रा नीति और घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाकर विनियोजकों को बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करना लाभप्रद नहीं है। इनमें स्थितिक स्थितियों को जन्म मिलता है। अल्प-विकसित देशों में वचन को बढ़ाकर पूंजी निर्माण द्वारा घन जुटाकर विकास को बढ़ाना सम्भव होता है। प्रो० कीन्स वचन को बढ़ाने के विरोध में थे।

5 अल्प-विकसित देशों का विकास योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा सम्भव है— प्रो० कीन्स की विचारधारा अल्प-विकसित देशों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। वर्तमान समय में अल्प-विकसित देश योजनाबद्ध तरीके से अर्थानु-नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपने विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे देशों में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाकर तथा विनियोजकों को बढ़ाकर ही विकास करना सम्भव नहीं है। ऐसे देशों में जनसंख्या की अधिकता के कारण उपभोग पर अकुशल लगाकर तथा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी विनियोजन का महाराज किया जा रहा है।

कीन्सवादी चरों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध (Inter-relation between Keynesian Variables)

प्र० कीन्स के रोजगार मॉडल में रोजगार की मात्रा कुल प्रभावपूर्ण माँग की मात्रा पर निर्भर करती है जो स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है—(1) उपभोग (Consumption) तथा (2) विनियोग (Investment) उपभोग की मात्रा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है जबकि विनियोग की मात्रा ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमांत कुशलता या क्षमता (MEC) पर निर्भर करती है। इस प्रकार कीन्स के सम्पूर्ण रोजगार मॉडल के तीन मुख्य आधार हैं (i) उपभोग क्रिया (Consumption Function) (ii) पूँजी की सीमान्त कुशलता अथवा क्षमता (Marginal Efficiency of Capital) तथा (iii) ब्याज की दर (Rate of Interest)। यह तीन चर कीन्सवादी प्रणाली के स्वतन्त्र चर कहे जा सकते हैं अर्थात् यह अन्य चरों से प्रभावित नहीं होते। परन्तु यह एक दृष्टि से अन्तर-निर्भर चर (Interdependent Variables) कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी एक में परिवर्तन दूसरे चरों को प्रभावित कर सकता है। कीन्स ने इनके बारे में कहा है कि यह निर्धारक (उपभोग प्रवृत्ति पूँजी की सीमांत कुशलता तथा ब्याज की दर) अपने आप में स्वयं जटिल हैं और इनमें से प्रत्येक में अन्य चरों द्वारा आशाकृत परिवर्तनों के कारण प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। परन्तु इन्हें इसलिए स्वतन्त्र चर कहा जाता है कि इनके मूल्य अन्य चरों के मूल्यों द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते।<sup>1</sup>

प्र० कीन्स ने इन स्वतन्त्र चरों की व्याख्या करते हुए कहा है कि ब्याज की दर मुद्रा की माँग तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की पूर्ति बैंक तथा सरकार द्वारा प्रभावित होती है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की माँग तरलता पसंदगी के कारण होती है और यह तीन उद्देश्यों द्वारा प्रभावित होती है जैसे—(i) लेन देन उद्देश्य (ii) सुरक्षा उद्देश्य तथा (iii) सट्टा उद्देश्य। इनमें से प्रत्येक दो उद्देश्य आय की मात्रा में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होते हैं और ब्याज की दर का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि तीसरा उद्देश्य सट्टा उद्देश्य ब्याज की दर द्वारा अधिक प्रभावित होता है इसी बात को प्र० कीन्स ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया है।

$$M = f(r, y)$$

M = मुद्रा की पूर्ति f = फलन r = ब्याज की दर y = आय स्तर। इस समीकरण में जो मुद्रा पूर्ति या फलन r तथा y से दिखाया गया है उसे हम तरलता क्रिया (Liquidity Function) की संज्ञा दे सकते हैं। मुद्रा की माँग में परिवर्तन का सीधा सम्बन्ध आय की मात्रा में परिवर्तन से होता है और ब्याज की दर से इसका विपरीत सम्बन्ध होता है।

उपभोग की मात्रा में वृद्धि का मुख्य निर्धारक तत्व वास्तविक आय का स्तर है। आय की मात्रा या स्तर में वृद्धि होने से उपभोग की मात्रा बढ़ती है परन्तु आय में होने वाला वृद्धि व अनुपात दर से उपभोग में कम दर से वृद्धि होती है अर्थात् इकाई से कम उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोग प्रवृत्ति भी ब्याज की दर से प्रभावित हो सकती है। ब्याज की दर में वृद्धि होने से लोग अधिक मुद्रा बचावेंगे और उपभोग पर व्यय कम

1 These determinants (propensity to consume marginal efficiency of capital and rate of interest) are indeed themselves complex and each incapable of being effected by prospective changes in all other variables. But they remain independent in the sense that their values cannot be inferred from one another" — J. M. Keynes

करेंगे परन्तु उपभोग प्रवृत्ति का ब्याज की दर में सम्बन्ध अप्रत्यक्ष है और अधिक प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता। यदि हम औसत उपभोग को (C) आय स्तर को y में तथा ब्याज की दर को r से व्यक्त करें तो हमें उपभोग प्रिया (Consumption Function) का समीकरण प्राप्त हो जायेगा जिसे हम निम्न प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं—

$$C = f(y, r)$$

विनियोगों का स्तर ब्याज की दर तथा पूँजी की सीमान्त कुशलता या क्षमता द्वारा निर्धारित होता है। यदि I को विनियोग की मात्रा r का ब्याज की दर तथा c को उपभोग की मात्रा द्वारा व्यक्त करें तो हम विनियोग प्रिया (Investment Function) का समीकरण प्राप्त हूँगा जो निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$I = f(r, c)$$

आय के एक स्तर पर ब्याज की दर मुद्रा की माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है और ब्याज की दर विनियोग के स्तर को निर्धारित करती है। यदि विनियोग का स्तर उस बिन्दु पर स्थिर रहता है जहाँ ब्याज की दर और पूँजी की सीमान्त कुशलता के बराबर रहता है, तो ऐसी अवस्था को साम्यावस्था में कहा जायेगा। अन्यथा विभिन्न चरणों में जब तक परिवर्तन होते रहेंगे जब तक वे एक-दूसरे के बराबर न हो जाएँ।

कीन्सवादी रोजगार मॉडल में स्वतन्त्र तथा निर्भर चर<sup>1</sup> (Dependent and Independent Variables in Keynesian Model of Employment)

आर्थिक चरणों को दो भागों में बाँटा जाता है—(i) स्वतन्त्र चर (Independent Variables) तथा (ii) निर्भर चर (Dependent Variables) स्वतन्त्र चर वे चर होते हैं जो अन्य चरणों द्वारा प्रभावित नहीं होते जबकि निर्भर चर वे चर होते हैं जिनका मूल्य अन्य स्वतन्त्र आर्थिक चरणों के मूल्या द्वारा प्रभावित होता है। कीन्सवादी मॉडल में स्वतन्त्र और निर्भर चरणों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की गई है

**स्वतन्त्र चर (Independent Variables)**

- (1) उपभोग प्रिया (Consumption Function)
- (2) पूँजी की सीमान्त कुशलता अनुसूची (Schedule of MEC)
- (3) तरलता वरीयता अनुसूची (Liquidity Preference Schedule)
- (4) मुद्रा की मात्रा (Quantity of Money)
- (5) मजदूरी इकाई (Wage Unit)

**निर्भर चर (Dependent Variables)**

- (1) ब्याज की दर (Rate of Interest)

(2) राष्ट्रीय आय उत्पादन तथा रोजगार (National Income, Output and Employment)

- (3) उपभोग (Consumption)
- (4) विनियोग तथा बचत (Investment and Saving)

स्वतन्त्र चरणों में प्रथम तीन चर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रियाओं द्वारा शामिल होते हैं जबकि चौथे तथा पाँचवें चरणों के मुद्रा अधिकारी द्वारा नियन्त्रित होते हैं। चरणों के

1. इन चरणों की विस्तृत व्याख्या अलग में विभिन्न अध्यायों में की गई है।

स्वतन्त्र तथा निर्भर चरों में वर्गीकरण द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्धारण इस प्रकार इन तत्वों द्वारा होता है—(i) तीन मनोवैज्ञानिक प्रियाओं (उपभोग पूर्णता की सीमान्त कुशलता तथा तरलता वरीयता) (ii) मजदूरी इकाई तथा (iii) मुद्रा की पूर्ति। मजदूरी इकाई (Wage Unit) का मूल्य सेवायोजकों तथा मजदूरों के बीच मोलभाव की शक्ति पर निर्भर करता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत तथा विनियोग के वास्तविक निर्धारण में सहायता मिलती है क्योंकि यह कीमतों में परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। व्याज की दर पूर्णता की सीमान्त कुशलता विनियोगों के स्तर को प्रभावित करती है जो राष्ट्रीय आय का एक अंग है। इसी प्रकार उपभोग प्रिया उपभोग की मात्रा को प्रभावित करती है जो राष्ट्रीय आय का एक अन्य अंग है। इस प्रकार मुक्त उपभोग + मुक्त विनियोग किसी समय कुल आय द्वारा उत्पादन अथवा रोजगार की मात्रा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार उपभोग या विनियोगों द्वारा सृजित आय का प्रभाव यहीं पर समाप्त नहीं होता बरन् आगे चलकर यह विभिन्न स्वतन्त्र चरों को प्रभावित करता है। स्वतन्त्र चर स्वयं भी निर्भर चरों (Dependent Variables) द्वारा प्रभावित तो होते हैं परन्तु उनके द्वारा निर्धारित नहीं होते। यद्यपि स्थिति यह है कि राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत ही जटिल होती है।

कीन्स के रोजगार सिद्धान्त की प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त से श्रेष्ठता (Superiority of Keynesian Theory of Employment over Classical Theory of Employment)

प्रतिष्ठित तथा कीन्स के रोजगार सिद्धान्तों के अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही सिद्धान्तों की अपनी-अपनी कमियाँ हैं। परन्तु दोनों सिद्धान्तों में कौन सा श्रेष्ठ है? यदि हम प्रश्न का उत्तर ढोजें तो हमें यह आसानी से पता चल जायगा कि प्रतिष्ठित अवशास्त्रियों के रोजगार सिद्धान्त की अपेक्षा कीन्स का रोजगार सिद्धान्त निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता निम्नलिखित तत्वों से साबित हो जाती है—

(1) कीन्सवादी दृष्टिकोण वास्तविकता के निकट है—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति को एक सामान्य स्थिति मानते हैं। जबकि कीन्स का कहना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था प्रायः पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर मन्तुलन में होती है अर्थात् अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी हमेशा पाई जाती है। ऐसा करने कीन्स ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह वास्तविकता के अधीन निकट है।

(2) पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखने के सम्बन्ध में—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए मजदूरी बढ़ती नीति अपनावो चाहिए जबकि कीन्स का कहना है कि कुल प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

(3) बजट प्रारूप के बारे में—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना था कि सन्तुलित बजट बनाना चाहिए, इसी विपरीत कीन्स मन्दीकाल में विनियोगों में वृद्धि हेतु घाटे के बजट बनाने का सुझाव देते हैं।

(4) दृष्टिकोण में अन्तर—कीन्स ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि यह पूर्ण रोजगार, पूर्ण से अधिक रोजगार तथा अल्प रोजगार सभी प्रकार की स्थितियों का व्याख्या करता है जब कि प्रतिष्ठित सिद्धान्तों ने पूर्ण रोजगार की स्थिति माना है और उनका दृष्टिकोण सन्तुलित एवं विशिष्ट है।

(९) सरकार की भूमिका—प्रतिष्ठित विद्वान् स्वतन्त्र एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली अवस्था में पूर्ण रोजगार की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि बेरोजगारी होने पर यदि अव्यवस्था अवाधित रूप में अर्थात् बिना हस्तक्षेप के बाय बर्नी रहे तो दीर्घकाल में बेरोजगारी स्वतः ही दूर हो जायेगी। इसके विपरीत कीन्स का कहना है कि बिना सरकार हस्तक्षेप के पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना उचित कार्य है।

### परीक्षा-प्रश्न

- 1 प्रभावपूर्ण माँग से आप क्या समझते हैं? यह रोजगार के स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है?

(What do you understand by effective demand? How does it determine the level of employment?)

- 2 प्रभावपूर्ण माँग क्या है? प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व कौन से हैं?

(What is effective demand? What are the determinants of effective demand?)

- 3 कीन्स के रोजगार सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त से किस प्रकार श्रेष्ठ है?

(Discuss critically the Keynesian Theory of Employment How far is it an improvement over classical theory?)

- 4 कीन्स के रोजगार सिद्धान्त का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक महत्त्व बताइए। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में यह कहाँ तक लागू हो सकता है?

(Discuss the theoretical and practical importance of Keynesian Theory of Employment to what extent is it applicable in a country like India?)

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्न कथना में स वाक्य-समूह सही है और वाक्य-समूह गलत है—

- (i) कीन्स का रोजगार सिद्धान्त सरकारी हस्तक्षेप का पक्षधर है।
- (ii) कीन्स के रोजगार सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है।
- (iii) कीन्स रोजगार सिद्धान्त के अनुसार अव्यवस्था प्रायः पूर्ण रोजगार में कम स्तर मनुष्यत्व में रहती है।
- (iv) कुल माँग फलन तथा कुल पूर्ति फलन का कटाव बिन्दु ही प्रभावपूर्ण माँग को बताता है।
- (v) कीन्स का रोजगार सिद्धान्त एक दीर्घकालीन व्याख्या है।
- (vi) पूँजी विनियोजन व्याज की दर पर नहीं बरन् पूँजी की सीमांत बुझता पर निर्भर करता है।

### वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) गलत है। (iii) गलत है। (iv) गलत है। (v) गलत है। (vi) गलत है।

Keynes most notable contribution was his consumption function

—Hansen

The psychology of the community is such that when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased but not by so much an income

—J M Keynes

$$MP_c = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \quad A P_c = \frac{C}{Y}$$

अध्याय 6

## उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति

(CONSUMPTION FUNCTION OR PROPENSITY TO CONSUME)

प्रो. कीन्स । उपभोग विद्या का एक मनावैज्ञानिक नक़ किया बताया है । इसलिए प्रा० का म ब उपभोग विद्या का सम्बन्धित नियम को उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम (Psychological Law of Consumption) कहा जाता है । उपभोग विद्या मकीन्सवादी आय का उत्पादन तथा राजस्व की व्याख्या म प्रमुख स्थान है । कीन्स न अपना पुस्तक *The General Theory* म उपभोग विद्या की व्याख्या करत हुए कहा है कि समुदाय की मनोवैज्ञानिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि जब कुल वास्तविक आय का मात्रा म वृद्धि होती है तो वह उपभोग बढ़ता है परन्तु आय म वृद्धि के अनुपात कम वृद्धि उपभोग म होती है ।<sup>1</sup> म न आय म वृद्धि व उपभोग पर पड़न वाल प्रभाव का उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग विद्या की सज्ञा की है ।

कीन्सवादी उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Keynesian Psychological Law of Consumption)

प्रो० कीन्स न उपभोग विद्या की व्याख्या का उपभोग व मनावैज्ञानिक सिद्धान्त म स्पष्ट किया है । प्रो० कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग सिद्धान्त तीन प्रमुख तर्कों पर आधारित है —(1) कुल आय म मुाउ व माध उपभोग का मात्रा म वृद्धि होती है परन्तु आय म वृद्धि की दर स कम दर पर वृद्धि होती है योकि जैम-जैम व्यक्ति की आय बढ़ती जाता है वेम-वेम उसकी आवश्यकताओं की शरुति होती जाता है आर इसलिए आय म वृद्धि न अनुपात म

1 The fundamental psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much the increase in their income.

—J M Keynes

*The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) pp 96*

कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होती है। (2) जब आय में वृद्धि होती है तो यह अतिरिक्त आय उपभोग और बचत में मध्य बँट जाती है। (3) आय में वृद्धि के बढ़ने में उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होती है।

### सिद्धान्त की मान्यताएँ

(1) लोगो की उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता अथवा लोगो की व्यय करने की आदतें पहले जैसे ही रहती हैं। आय में परिवर्तन होने पर आय चर्रा जैसे—आय का वितरण वस्तु की कीमता तथा जनसंख्या की वृद्धि आदि लगभग अपरिवर्तित रहते हैं।

(2) अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति पाई जाती है और अत्यधिक स्फीति या युद्ध जैसे असामान्य स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं।

(3) स्वतन्त्र पूँजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। उन अर्थव्यवस्थाओं में यह नियम लागू नहीं होगा जहाँ सरकार द्वारा लोगो की उपभोग प्रवृत्ति पर अकुशल रखा है।

कीन्स के सिद्धान्त का अभिप्राय (Implications of Keynes Psychological Law)—अधिकतर अर्थशास्त्री प्रा० कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का बीज की प्रमुख दम स्वीकार करते हैं। उपभोग प्रिया का आर्थिक विश्लेषण के धर्म में एक महान अस्त्र के रूप में जाना जाता है। कीन्स के उपभोग सिद्धान्त की प्रमुख धारा का निम्नलिखित रूप से दर्शा जा सकता है—

विनियोग का महत्व—कीन्स ने आय तथा राजस्व के स्तर या ऊँचा उठाव के लिए विनियोग में वृद्धि के महत्त्व का स्वीकार किया है। उपभोग सिद्धान्त यह बताता है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि का दर आय में वृद्धि या दर में कम होता है और आय तथा उपभोग में अन्तर का पाटन के लिए विनियोग का महत्त्व बना चाहिए। यह सिद्धान्त ज्ञाता है कि आय में प्रत्येक वृद्धि के साथ उपभोग तथा आय का अन्तर बढ़ता जाता है और आय से उच्च स्तर का बनाय रखने के लिए अधिक से अधिक विनियोग बढ़ाने की आवश्यकता होती है यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट आती है जिसमें अर्थव्यवस्था भी नीचे का आर जाती है। इस प्रकार विनियोग का महत्त्व अधिक होता है।

सामान्य अति-उत्पादन—यह सिद्धान्त बताता है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन तथा बराजगारी की स्थिति आ सकती है। आय में वृद्धि के साथ उपभोग में इकाई में कम वृद्धि होती है और आय से उपभोग का स्तर पिछड़ जाता है जो अन्ततः अति उत्पादन और बराजगारी में परिणत हो जाता है।

प्रो० से के नियम का खण्डन—कीन्स ने अपने उपभोग सिद्धांत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रा० जे० बी० से के का नियम कि 'पूँति अपनी माँग स्वयं पैदा करती है' की बड़ी आलोचना की और बताया कि भीमात उपभोग प्रवृत्ति इकाई में कम होती है इसलिए जितना मान उत्पादन किया जाता है उतना गवनी माँग नहीं होने पाती और पूँति अपनी माँग पैदा करने में समर्थ नहीं होता इसलिए अति उत्पादन (Over production) की स्थिति पाई जा सकती है।

सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता—सम्पूर्ण आय का व्यय नहीं किया जाता इसलिए कोई भी स्वयं चालित व्यवस्था नहीं होती जिससे कि आय तथा व्यय में बराबरी रहे इसलिए सरकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। सरकार अपनी हस्तक्षेप की नीति द्वारा इस बात का ध्यान रखती है कि कुल प्रभावपूर्ण माँग पूँति में कम न होने पाए।



अति बचत—प्रो० कोन्म कहते हैं कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में उम्मीद मात्रा में वृद्धि नहीं आती है इसलिए बचत का स्तर अधिक बढ़ता जाता है। धनी देशों में निधन देशों की अपेक्षा अधिक बचत बढ़ने का खतरा अधिक रहता है और इसके परिणाम अत्यंत भयंकर होते हैं।

पूँजी की सीमान्त कुशलता का गिरना—लोगों की उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ लगभग अरिखणित रहने की होती है, जिससे पूँजी की सीमान्त कुशलता (लाभ की दर गिरने की सम्भावना) में गिरावट की स्थिति दिखाई देती है। पूँजी की सीमान्त कुशलता में गिरावट को रोकने के लिए आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि करना जरूरी होता है। अतः विनियोग के माँग दर्शन के लिए उपभोग या प्रभावपूर्ण माँग का बढ़ना जरूरी है।

आय में वृद्धि—कीन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक मिथ्यान्त बनाना है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकार्ड में कम होती है और लोगों के पास क्रयशक्ति को बढ़ाने के लिए उनकी आय में वृद्धि करना जरूरी होता है जिसको हम थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं।

न्यून रोजगार साम्य—कीन्स ने बताया है कि यह जल्गी नहीं है कि पूर्ण रोजगार बिन्दु पर कुल माँग निया कृत्र पूति निया के बराबर हो। पूर्ण रोजगार बिन्दु पर साम्य की स्थिति तभी होगी जबकि विनिवेश की माँग बराबर हो जाएगी उस अन्तर्गम में जिस पर कुल आय पूर्ण रोजगार पर तथा कुल उपभोग व्यय (उम्मीद आय पर) दोनों बराबर हो जायेंगे। कीन्स का विश्वास था कि विनियोग माँग आय की राशि और उपभोग माँग (पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर) के बीच अन्तर को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगी इसलिए कुल माँग निया तथा कृत्रपूति निया मर्दब ही न्यून रोजगार साम्य (पूर्ण रोजगार साम्य से नाचे स्तर पर) एवं डूंगरे को काटेंगे।

96195

चिरकालिक स्थिरता (Secular Stagnation)

प्रो० कीन्स की ऐसी मान्यता है कि आय में वृद्धि में उपभोग में वृद्धि उपायान्वित होती है कि विनियोग माँग कमजोर होती चली जाती है और अत्यव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर बढ़ने की वृद्धि बचनों की निष्कामी के लिए या विनियोग बढ़ाने की सम्भावनाएँ समाप्त हो जाएँगी। (पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए जो जरूरी होता है)। इस अवस्था को चिरकालिक स्थिरता की स्थिति कहते हैं और ऐसी स्थिति को रोकना चाहिए जिसके लिए उपयोग में स्थिरता नहीं आने देना चाहिए।

व्यापार चक्र—कीन्स ने उपभोग के मनोवैज्ञानिक मिथ्यान्त में यह बताने का प्रयास किया है कि व्यापार चक्रों की स्थिति में परिवर्तन कैसा होता है। कीन्स के विचारों में पहले व्यापार चक्र के विभिन्न मिथ्यान्तों का प्रतिपादन किया गया था परन्तु कीन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिनने बताया कि उपभोग निया के स्थिर रहने पर व्यापार चक्र में विभिन्न अवस्थाएँ कैसे आती हैं। जब व्यापार चक्र मनुद्धि के उच्च स्तर पर होता है उस समय आय बढ़ने में, वृद्धि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति इकार्ड में कम होती है जिसके कारण मनुद्धि में निरन्तर व्यापार की दिशा गिरावट की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार जब व्यापार चक्र निम्नतम बिन्दु पर पहुँचता है, तो लोगों की आय बहुत गिर जाती है, परन्तु लोग अपने उपभोग के स्तर को आय में गिरावट के अनुसार कम नहीं करते, तो व्यापार चक्र के ऊपर उठने का प्रथम प्रारम्भ हो जाता है।

## उपभोग प्रवृत्ति वा अर्थ (Meaning of Propensity to Consume)

आय तथा व्यय व मरुवन्ध वा वतान वागी क्रिया ही उपभाग प्रवृत्ति कहलती है। उपभाग प्रवृत्ति इस बात की आर सकत करती है कि आय म परिश्रुतन व गार्थ-मार्थ उपभोग मे परिश्रुतन किम प्रकार हाता है। उपभाग व्यय आय वा फरत हाता है अर्थात्  $C = f(y)$ । उपभाग फरत की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

प्रो० एफ० एस० डब्लु के अनुसार— उपभाग फरत इस बात वा दर्शाता है कि आय के प्रत्येक मरुभाविता स्तर पर उपभाक्ता वस्तुवा तथा सेवावा पर वितनी व्यय करना चाहग।<sup>1</sup>

प्रो० मरुडगल एव डर्नबर्ग द्वारा— वह सूचा जा उपभाग वा उपभाक्ता आय म मरुभाविता करता है उय उपभाग प्रवृत्ति वा उपभाग क्रिया कहल है।<sup>2</sup>

प्रो० कुरीहारा के शब्दों मे— उह पूष सूचा जा आय व विभिन्न तरा पर उपभाग की विभिन्न राशिवा म मरुभाविता हाता है। शान्त न हा हा उपभाग प्रवृत्ति अथवा उपभाग फरत कहा है।<sup>3</sup>

## उपभोग क्रिया (Consumption Function)

उपभाग क्रिया वा शान्ति न सामान उपभाग डवृत्ति कहा है। उपभाग क्रिया वा शान्ति उपभाग प्रवृत्ति वा आय तथा उपभाग व फारम र्व मरुवन्ध द्वारा दिशाया जाता है जिमका हम इस प्रकार व्यक्त कर सकत है  $C = f(Y)$ । शान्त आय र तरा पर उपभाग व विभिन्न स्तर हाता है। विभिन्न आय र स्तर पर उपभाक्ता व्यय दर्शान व त्रिए जा अनुसूचा बनाड जाता है उस उपभाग प्रवृत्ति अनुसूचा कहल है। हम एक तमा परल जषव्यवस्था वा जषव्यव करग। जगम विभिन्न व रवाग। शी ममान जाय विभिन्न फमा द्वारा उत्पादित ररुजा तथा सेवावा की गरोदन म व्यय पर दा जाती है। आय (Y) वा स्तर चाह जा कुछ भी हा उपभाग पर (C) व्यय पर दिया जाता है अथवा  $C = Y$ । इस स्थिति वा हम अश्रावित ग्राफिचर द्वारा प्रस्था कर सकत है—

अश्रावित ग्राफिचर म दिशाया गया है कि यदि आय 100 रुपय हाती है ता उपभाग भी 100 रुपय रहता है और यदि आय बरवर 200 रुपय हा जाती है ता उपभाग भी बरवर 200 रुपय हा जाता है। एसी स्थिति म हमग ममन्त आय वा उपभाग व बराबर मान त्रिया है।

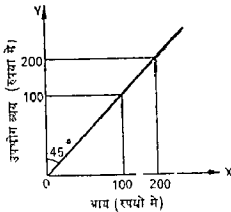
1 Consumption function shows what expenditure consumers will wish to make on consumers goods and services at each possible level of income ' —F S Brooman

2 The schedule that relates consumption to disposable income is called the propensity to consume or the consumption function —Mc Dougall and Dernburg

3 The whole schedule relating to various amounts of consumption and various levels of income is what Keynes calls the propensity to consume or simply the consumption function

—Kurishara

हम वास्तविक स्थिति पर विचार करें तो पता चलता है कि मनुष्य अपनी समस्त आय को उपभाग पर व्यय न करके कुछ एक अंश को बचक करता है और शेष का बचा



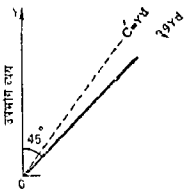
ताता है अर्थात्  $S = Y - C$ । व्यय द्वारा आय के वृत्तीय प्रवाह को बनाए रखने के माय पर जो पभाव पडता है वह महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक भाग व्यय कर लेता है तो वह दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है और आगे चारकर आय का वृत्तीय प्रवाह में योगदान देता है यदि वह व्यय को आय का वृत्तीय प्रवाह से हटा लेता है तो यह एक प्रवार में इसमें क्षरण (Erosion) पैदा कर देता है।

### दीघकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग त्रिया या फलन (The Long run and Short run Consumption Function)

उपभोग त्रिया को हम दीघकालीन तथा अल्पकालीन उपभोग त्रियाओं में बाँट सकते हैं। दीघकालीन उपभोग त्रिया का सम्बन्ध दीघकालीन आय से होता है। दीघकालीन उपभोग फलन का एक सरल रेखाचित्र द्वारा दिखाया जाता है जो मूल बिन्दु से गुजरती है जैसा कि निम्नान्वित रेखाचित्र में दिखाया गया है।

$Y_d$  - स्थायित या उपभोग्य आय  
 $C$  उपभाग

स्पष्टीकरण—प्रस्तुत रेखाचित्र में  $OC$  एक सीधी रेखा जाकि मूल बिन्दु  $O$  से प्रारम्भ होती है जो बताती है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है परन्तु यह वृद्धि

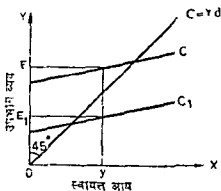


आय अनुपात की दृष्टि में एक-सी रहती है। O बिन्दु से एक आय रेखा  $OC'$  खींची गई है जो यह बताती है कि यदि उपभोक्ता अपनी मांगी आय खर्च कर देगा तो स्थिति क्या होगी?  $OC$  रेखा  $OC'$  रेखा की अपेक्षा नीचे की ओर धीरे-धीरे आती है जिससे आशय यह है कि उपभोग का अनुपात आय की अपेक्षा हमेशा इकाई से कम रहता है। आय को उपभोग्य आय द्वारा दिखाया गया है।

### अल्पकालीन उपभोग प्रक्रिया या फलन (The Short-run Consumption Function)

व्यवहार में वस्तु की मांग की परिस्थितियाँ काफी स्थाई होती हैं। यदि मांग अल्पकालीन है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वस्तु की कीमत पर पड़ता है। इसलिए हम अल्पकालीन विश्लेषण में अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करेंगे कि मांग का परिणाम क्या वस्तु की कीमत के साथ क्या सम्बन्ध है। उपभाग व्यय निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है—

- (1) मांग परिस्थितियों में निर्दिष्ट माध्यमों के अग्रिमवर्तित रहते हुए आय का स्तर
- (2) व सभी माध्यम जो यह निर्धारित करते हैं कि आय का कितना उपभोग होता है चाहे आय का विशेष स्तर कुछ भी हो।



### (अल्पकालीन उपभोग फलन का एक स्थान परिवर्तन)

अल्पकाल में उपभोग में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से आय में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम होते हैं। अतः उपभोग को आय स्तर से सम्बन्धित करना और अन्य कारकों को "प्राचल" (Parameters) मानना उचित होगा।

**स्पष्टीकरण**—प्रस्तुत रेखाचित्र में  $C$  तथा  $C_1$  के बीच की स्थिति उपभोग और आय के बीच सम्बन्ध को बताती है। चित्र में  $C$  तथा  $C_1$  तक वक्र की गति उम्र बर्षों को सूचित करती है जो किमी प्राचल में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में हुई है। अतः आय स्तर  $OY$  पर उपभोग  $OE$  में गिरकर  $OE_1$  हो जाता है। नुतिघ्रा की दृष्टि में हम यह मान लेते हैं कि आय में वृद्धि होने के साथ उपभोग में भी वृद्धि हो जाती है।

### औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (Average and Marginal Propensity to Consume)

आय तथा उपभोग के सम्बन्ध को नापने के लिए हम औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्तियों को उपयोग करते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति एक समयावधि में कुल आय के घटने में कुल उपभोग की स्थिति को बतानी है जबकि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति आय की

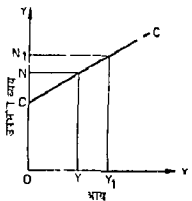
वृद्धि में हुए परिवर्तन के मन्दभ्रम उपभोग में वृद्धि के परिवर्तन की व्याख्या करती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति आय के मन्दभ्रम में उपभोग की दर को तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति आय के परिवर्तन के अनुपात में उपभोग में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करती है।

$$APC = \frac{C}{Y} \text{ तथा } MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

APC = औसत उपभोग प्रवृत्ति MPC = सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति  
 C = उपभोग Y = आय  $\Delta C$  = उपभोग में होने वाली वृद्धि में परिवर्तन  
 $\Delta Y$  = आय में होने वाली वृद्धि में परिवर्तन

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आय तथा उपभोग का सामान्य सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है परन्तु यह वृद्धि इकाई से कम होती है। इसी बात को एक रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है—

प्रस्तुत रेखाचित्र में दिखाया गया है कि जब आय OY है तो उपभोक्ता ON उपभोग करता है यदि आय बढ़कर OY<sub>1</sub> हो जाती है तो उपभोग व्यय बढ़कर ON<sub>1</sub> हो जाता है। उपभोक्ता OC उपभोग व्यय करेगा चाहे उसकी आय शून्य ही क्यों न हो। इसका आशय यह है कि भूखी भरण से अच्छा उपभोक्ता यह समझेगा कि वह अपनी भूतपूर्व बचतों को व्यय करे अथवा अपनी सम्पत्ति को बेचेगा। आय हाया न हो परन्तु एक निम्न स्तर अर्थात् जीवित रहने के लिए जितना व्यय जरूरी है उपभोक्ता करेगा ही। CC<sub>1</sub> रेखा बताती है कि आय में बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में उपभोग प्रिया विभिन्न रूप ग्रहण कर लेती है और रेखा चित्र का आकार भी उसी प्रकार परिवर्तित होता जाता है।



आय तथा उपभोग को सामान्य रूप से वास्तविक आय तथा वास्तविक उपभोग द्वारा दिखाया जाता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने का प्रभाव उपभोग के स्तर पर देखने के लिए हमें वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के समर्थन में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि उपभोक्ता की आय तथा कीमतें दुगनी हो जाएँ तो उपभोग भी मात्रा भी दुगनी हो सकती है एवं व्यय 75 प्रतिशत ही बढ़े तो हम इन दोनों स्थितियों को उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा नहीं दिखा सकते। इस प्रकार कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के उपभोग व्यय में भी परिवर्तन हो जाते हैं और इन परिवर्तनों को वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा पृथक रूप से देखना चाहिए। बीचवर्णित्रीय भाषा में उपभोग फलन को हम अग्रलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

$C + C(Yd) C =$  कुल वास्तविक उपभोग

$yd =$  कुल वास्तविक स्थायक आय

यदि उपभाग फलन रर्रीय (Linear) है तो हम इन प्रकार रूप सवते हैं —

$C = Co + bYd$

$Co$  - शून्य स्थायक आय पर उपभाग की मात्रा

$b$  - सीमात उपभोग प्रवृत्ति

सीमात तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में सम्बन्ध (Relation between MPC and APC)

आय में वृद्धि के साथ APC तथा MPC दोनों ही गिरते हैं परन्तु MPC के गिरने की दर APC से अधिक होती है। निधन तथा विवामशील देशों में MPC APC से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि धनी देशों में लोगों की विभिन्न आवश्यकताएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी होती हैं इसलिए जैसे-जैसे आय बढ़ती है उपयोग व्यय बढ़ने की अपेक्षा वचत अधिक होने लगती है। निधन देशों में लोगों की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए आय वृद्धि का अधिकांश अनुपात उपभाग पर व्यय कर दिया जाता है।

उपभोग क्रिया को आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व (Factors Other than Income Affecting Consumption Function)

हम उपभोग राशि (Consumption Amount) तथा उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) में मध्य अन्तर का स्पष्ट रूप में समझना चाहते हैं। उपभोग राशि स्थिर नहीं होती क्योंकि यह आय पर निर्भर करती है जो समय परिवर्तनशील होती है। इसके विपरीत अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर होती है क्योंकि यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर जो कि मनुष्य का एक स्थायक हा जाता है निर्भर करती है। केवल युद्ध अति रशीत या अन्य आर्थिक सबटा के समय उपभोग प्रवृत्ति हा जाती है। हाताकि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहने की प्रवृत्ति दिखताती है परन्तु यह पूर्णतया बेवचन नहीं होती। उपभोग प्रवृत्ति में अल्पकाल में सम्भार की राजस्वार्थीय नीतियों, ब्याज की दर तथा पूँजी मूल्य (Capital Values) के कारण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। Prof. Keynes ने कहा है कि स्थायक आय में ग किए जाने का व्यय की राशि पर उद्भुतिष्ठ तत्व (Objective Factors) तथा व्यक्तिनिष्ठ तत्व (Subjective Factors) दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इनकी अलग-अलग चर्चा हम इन प्रकार करेंगे।

उद्भुतिष्ठ तत्व (Objective Factors)— यह तत्व निर्मातमित प्रकार में हा सकते हैं—

(i) समुदाय में धन तथा आय का वितरण (The Distribution of Wealth and Income in the Community)— उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण में आय तथा सम्पत्ति का वितरण का प्रमुख रूप में प्रभाव पड़ता है। धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निधन व्यक्तियों में APC तथा MPC दोनों ही उँची होती हैं अर्थात् अपनी आय के अधिक भाग को उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक हाती हैं इसका कारण यह है कि निधन व्यक्तियों की परत में ही बहुत सी आवश्यकताएँ समन्तुष्ट बनी रहती हैं। इसका विपरीत धनी व्यक्ति उच्च जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हाते हैं और उनकी अधिकांश आवश्यकताएँ समन्तुष्ट रहती हैं इसलिए अतिरिक्त का अधिकांश भाग वे बचा लेते हैं। इस प्रकार धन और आय के अधिक समान रूप में वितरण करने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि की जा सकती है।

(ii) उपलब्ध परिसम्पत्तियों का आकार तथा स्वरूप (The Size and Nature of Assets Held)— एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की परिसम्पत्तियाँ हो सकती हैं प्रथम नगद

पतल  
परिसम्पत्ति (Liquid Assets) तथा अन्य द का नपन परिसम्पत्ति (Illiquid Assets) नकद परि-  
सम्पत्तियाँ ऐसी परिसम्पत्तियों हैं होता है जिन्हें उद्देश्य उपभोक्ता विरी भी समय  
आसानी से कर सकता है जब कि अन्यकद परिसम्पत्तियों का अंशक जैसे—मकान भूमि या  
अन्य पूँजीगत वस्तुएँ जादि से होता है। अन्यकद परिसम्पत्तियों के वहन पर उपभोग में  
वृद्धि हो सकती है क्योंकि इनके धारक यह समझते हैं कि सवटवान में इन्हे बेचकर या  
बदल कर नकदी प्राप्त की जा सकती है।

(iii) कीमतों का स्तर (The Level of Prices)—मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अ-  
स्फीति (Inflation and Deflation) का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर आवश्यक रूप से पड़ता  
है। मुद्रा स्फीतिदान में आय में अप्रत्याशित वृद्धि होती है दग कारण व्यक्ति स्तन्त्रता-  
पूर्वक उपभोग व्यय करता है। साथ ही कीमतें बढ़ने से ऋण पत्रों आदि के मूल्य गिरने  
लगते हैं। जिन व्यक्तियों के पास यह चीजें होती हैं वे समझते हैं कि इनकी लागतें  
गिर रही हैं और वे बहुत घुरी स्थिति में पहुँच गए हैं इसलिए इनके धारक इन ऋण  
पत्रों के वास्तविक मूल्य बनाए रखने के लिए कम व्यय करते हैं। स्फीतिकाल में मजदूरी  
की अपेक्षा उच्च आय वर्ग को अधिक लाभ होते हैं। इसलिए स्फीति में उपभोग  
गिरता अर्थात् नीचे की ओर चला जाता है जब कि अवस्फीति काल में यह उपरी हट  
जाता है। ऐसा उच्च आय स्तरों पर विशेष रूप से होता है हमें यह ध्यान रखना चाहिए  
कि स्फीति में अधिकांश लोग उच्च आय समूह में आ जाते हैं। अतः वास्तविक रूप से बढ्द मान  
कराधान से अधिक धनराशि सरकार द्वारा अधिकांश धनराशि वगूल करली जाती है।

(iv) प्रत्याशाएँ (Expectations)—व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की कीमत में भारी  
परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग नियम पर पड़ता है। यदि उपभोक्ताओं को यह पता चल जाए  
कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी अथवा वस्तुओं की कीमतें में कमी आ जायेंगी  
तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएँ खरीदेंगे इनके इस व्यवहार से उपभोग  
नियम में वृद्धि हो जायेगी ऐसा प्रायः मुद्रा छिड़ जाने या फिर स्फीतिक स्थितियों के कारण  
लगातार कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों को यह  
आशा हो कि भविष्य में वस्तुएँ अधिक मात्रा में मिलेंगी या वस्तु की कीमतें गिर जायेंगी  
तो वह थोड़े समय के लिए वस्तुओं की खरीद पर रोक लगा देंगे जिससे उपभोग नियम में  
गिरावट आ जायेगी।

(v) सरकार की नीति (Government Policy)—सरकार की राजसोपेय नीतियाँ  
जैसे करारोपण व्यय तथा बचत नीतियाँ उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव डालती हैं। ऋणों में  
थोड़ी छूट देने से लोगों के पास स्वायत्त आय की मात्रा बढ़ जाती है और लोग उपभोग  
पर व्यय बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत अधिक कर लगाने से स्वायत्त आय में गिरावट आती  
है जिसके परिणामस्वरूप उपभोग गिर जाते हैं। यदि सरकार बहुत अधिक प्रगतिशील कर  
प्रणाली अपनाती है तो इससे आय में वितरण की असमानताएँ कम हो जाती हैं तथा  
उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा खरीद खरीद योजना (Hire Purchasing  
Scheme) तथा बैंक ऋण नियामता ढाग लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरी  
ओर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्रों बचत प्रमाण पत्रों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ पर  
दरों में छूट आदि का बचता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में घरेलू  
बचतें पूँजी निर्माण का प्रमुख स्रोत कही जाती हैं।

(vi) व्यय पर निजी क्षेत्र के प्रभाव (Influence of Private Sector on Spending)—समय अपूर्ण प्रतिभोगिता की स्थिति बाजार में पाई जाती है। विज्ञान और प्रचार  
के माध्यम से निजी पक्ष अपना महंगा वस्तुएँ उपभोक्ताओं को बेचने में समर्थ हो जाते हैं,

$C + C(Yd) = C =$  कुल वास्तविक उपभोग

$Yd =$  कुल वास्तविक स्थायित आय

यदि उपभोग फलन रैखीय (Linear) है तो इसका प्रसारण स्वरूप निम्न है —

$$C = C_0 + bYd$$

$C_0$  - शून्य स्थायित आय पर उपभोग की मात्रा

$b$  - सीमांत उपभोग प्रवृत्ति

सीमांत तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में सम्बन्ध (Relation between MPC and APC)

आय में वृद्धि के साथ APC तथा MPC राना ही रहती है परन्तु MPC के गिरने की दर APC में अधिक होती है। निधन तथा संचयनशील राना में MPC APC में अधिक होती है। इसका कारण यह है कि धनी वर्ग में आगामी की विभिन्न आवश्यकताएँ पहले ही तृप्त हो चुकी होती हैं इसलिए जैसे जैसे आय बढ़ता है उपभोग व्यय बढ़ने की अपेक्षा बचत अधिक हो सकती है। निधन राना में आगामी की बढ़ती माँग आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए आय वृद्धि का अधिकांश अनुपात उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है।

उपभोग प्रिया की आय के अलावा प्रभावित करने वाले अन्य तत्व (Factors Other than Income Affecting Consumption Function)

हम उपभोग राशि (Consumption Amount) तथा उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) में मध्य अन्तर का स्पष्ट राना में समझना चाहते हैं। उपभोग राशि स्थिर नहीं होती क्योंकि यह आय पर निर्भर करती है जो समय परिवर्तनशील होती है। इसके विपरीत अल्पसंख्यक में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहती है क्योंकि यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है जो अल्पसंख्यक में स्थिर रहती है। कबल युद्ध आदि स्थिति या अन्य आवश्यकताओं के समय उपभोग प्रवृत्ति हो सकती है। हालाँकि अल्पसंख्यक में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहती है परन्तु यह पूर्णतया बचत नहीं होती। उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन में परिवर्तन की राजकीय नीतियाँ, व्याज की दर तथा पूँजी मूल्य (Capital Values) का कारण परिवर्तन दिये जा सकते हैं। Prof. Keynes ने कहा है कि स्वस्थ आय में भी निम्नलिखित बातें व्यय की राशि पर असुनिष्ठ तत्व (Objective Factors) तथा व्यक्तिगत तत्व (Subjective Factors) दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। इनकी अवगमना के लिए हम इस प्रकार प्रारम्भ करेंगे।

असुनिष्ठ तत्व (Objective Factors)—यह तत्व निम्नलिखित प्रकार में हो सकते हैं—

(i) समुदाय में धन तथा आय का वितरण (The Distribution of Wealth and Income in the Community) उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारण में आय तथा सम्पत्ति का वितरण का प्रमुख रूप में प्रभाव डालता है। अर्थात् व्यक्तिगत की आय तथा व्यक्तिगत की सम्पत्ति का वितरण ही अपेक्षा होती है जहाँ अपनी आय का अधिक भाग का उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है इसका कारण यह है कि निधन व्ययों की पूर्ति में ही बहुत सी आवश्यकताएँ अमनुष्य बनती रहती हैं। इस विपरीत धनी व्यक्ति उच्च जीवन स्तर व्यतीत कर रहे होंगे और उनकी अधिकांश आवश्यकताएँ मनुष्य रहती हैं इसलिए अतिरिक्त का अधिकांश भाग बचाव में है। इस प्रकार धन और आय का अधिक समान रूप में वितरण करने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि का जा सकता है।

(ii) उपलब्ध परिसम्पत्तियों का आकार तथा स्वरूप (The Size and Nature of Assets Held)—एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की परिसम्पत्तियाँ हो सकती हैं प्रथम नगद



परिसम्पत्ति (Liquid Assets) तथा अनवद परिसम्पत्ति (Illiquid Assets) तक परि-  
सम्पत्तियाँ ऐसी परिसम्पत्तियाँ हैं जो ता है जिसका उपयोग उपभोक्ता किसी भी समय  
आसानी से कर सकता है जब कि अनवद परिसम्पत्तियों का अर्थ है—मान भूमि या  
अन्य पूंजीगत वस्तुएँ आदि से होता है। अनवद परिसम्पत्तियों के वृद्धि पर उपभोग में  
वृद्धि हो जाती है क्योंकि इनके धारक यह समझते हैं कि संकटकाल में इन्हें बेचना या  
वदल कर तबकी प्राप्ति की जा सकती है।

(iii) कीमतों का स्तर (The Level of Prices)—मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अ-  
स्फीति (Inflation and Deflation) का प्रभाव उपभोग प्रवृत्ति पर आवश्यक रूप से पड़ता  
है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव में अप्रत्याशित वृद्धि होती है इस कारण व्यक्ति सतन्त्रता-  
पूर्वक उपभोग व्यय करता है। साथ ही कीमते बढ़ने से ऋण पत्रों आदि के मूल्य गिरने  
लगते हैं। जिन व्यक्तियों के पास यह चीजें होती हैं वे समझते हैं कि इनकी लागने  
गिर रही है और वे बहुत बुरी स्थिति में पहुँच गए हैं इसलिए इनके धारक इन ऋण  
पत्रों के वास्तविक मूल्य बनाए रखने के लिए कम व्यय करते हैं। स्फीतिकाल में मजदूरी  
की अपेक्षा उच्च आय वर्ग को अधिक लाभ होते हैं। इसलिए स्फीति में उपभोग  
गिरता अर्थात् नीचे की ओर चला जाता है जब कि अवस्फीति काल में यह उपरी हूट  
जाता है। ऐसा उच्च आय स्तरों पर विशेष रूप से होता है हमें यह ध्यान रखना चाहिए  
कि स्फीति में अधिवाण लोग उच्च आय समूह में आ जाते हैं। अतः वास्तविक रूप से वृद्धिमान  
व्यय का अधिक धनराशि सरकार द्वारा अधिवाण धनराशि वसूल करली जाती है।

(iv) प्रत्याशाएँ (Expectations)—व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं की कीमत में भारी  
परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग प्रिया पर पड़ता है। यदि उपभोक्ताओं को यह पता चल जाए  
कि भविष्य में वस्तुओं की कीमते बढ़ जायेंगी अथवा वस्तुओं की कीमतें कम आ जायेंगी  
तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएँ खरीदने इन्हें इस व्यवहार से उपभोग  
नियम में वृद्धि हो जायगी ऐसा प्रायः मुझ छिड़ जाने या फिर स्फीतिक स्थितियों के कारण  
लगातार कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों को यह  
आशा हो कि भविष्य में वस्तुएँ अधिक मात्रा में मिलेंगी या वस्तु की कीमतें गिर जायेंगी  
तो वह थोड़े समय के लिए वस्तुओं की खरीद पर रोक लगा देंगे जिससे उपभोग प्रिया में  
गिरावट आ जायगी।

(v) सरकार की नीति (Government Policy)—सरकार की राजकोषीय नीतियाँ  
जैसे बजट नीति तथा वृत्त नीतियाँ उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव डालती हैं। ऋणों में  
थोड़ी छूट देने से लोगों के पास स्वायत्त आय की मात्रा बढ़ जाती है और लोग उपभोग  
पर व्यय बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत अधिक कर लगाने से स्वायत्त आय में गिरावट आती  
है जिससे परिणामस्वरूप उपभोग गिर जाते हैं। यदि सरकार बहुत अधिक प्रगतिशील कर  
प्रणाली अपनाती है तो इससे आय में वितरण की असमानताएँ कम हो जाती हैं तथा  
उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा विदेशी खरीद योजना (Hire Purchasing  
Scheme) तथा बैंक ऋण नियामकों द्वारा लोगों को उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरी  
ओर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्रों वृत्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर  
दरों में छूट आदि का वृत्त पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी देशों में परेनू  
बचने पूर्ण निर्माण का प्रमुख स्रोत बनी जाती है।

(vi) व्यय पर निजी क्षेत्र के प्रभाव (Influence of Private Sector on Spending)—समय अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बाजार में फैल जाती है। निश्चय और प्रचार  
के माध्यम से निजी फर्म अपनी महंगी वस्तुएँ उपभोक्ताओं की बेचने में समर्थ हो जाती हैं।

जिमसे उपभोग का स्तर उँचा हो जाता है। उदाहरणार्थ स्मूटर रशीन टेलीविजन, कारें एयर कण्डीशनर आदि। ऋण सम्बन्धी नीतियां में समय समय पर छूट दिए जाने से भी लोग खुलकर व्यय करते हैं और उपभोग का स्तर उँचा उठता है।

(vii) अप्रत्याशित लाभ अथवा हानि (Unexpected Gains or Loss)—कभी-कभी आय में अप्रत्याशित वृद्धि या गिरावट के कारण उपभोग प्रिया प्रभावित हो जाती है। आय या लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर उपभोक्ता सामान्य उपयोग से अधिक उपभोग करने लगता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को कभी अप्रत्याशित हानि उमकी आय में हो जाए तो उसके उपभोग का स्तर सामान्य उपभोग से कम हो जाता है।

**व्यक्तिनिष्ठ तथ्य (Subjective Factors)**

प्रो० वीन्स कहते हैं कि लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति या उपभोग प्रवृत्ति पर व्यक्तिनिष्ठ तथ्यों का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति स्वभाव से दूरदर्शी होता है दूरदर्शिता का अर्थ किसी व्यक्ति में अधिक तो किसी में कम होता है। दूरदर्शिता उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी जान वाली धनराशि (जैसे—बुढ़ापे, बीमारी दुर्घटना बच्चों की शिक्षा तथा वेगजगारों आदि) जैसे—बचत व लिए सम्पत्ति को एकत्रित करना, भावी आवश्यकताओं या दुर्घटनाओं के लिए धनराशि की बचत पूँजी विनियोजन से होने वाले लाभ की कामना जितनी अधिक होगी उपभोग प्रवृत्ति में उतनी ही गिरावट आएगी।

प्रो० वीन्स ने व्यक्तिनिष्ठ तथ्यों के पीछे निम्नलिखित आठ उद्देश्य बताए हैं—

- (1) भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए रक्षित कोष को रखना।
- (2) भविष्य की आय तथा आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्ध की दृष्टि से कुछ धनराशि बचाना जैसे—बुढ़ावस्था पारिवारिक शिक्षा अथवा आश्रिता के भरण-पोषण के लिये आदि।
- (3) व्याज के रूप में धनराशि प्राप्त करने के लिए लोग वर्तमान उपभोग की अपेक्षा भावी उपभोग को महत्व देते हैं।
- (4) भविष्य में अच्छे जीवन स्तर को व्यतीत करने की लालसा से बचत करना।
- (5) स्वतन्त्रता की अनुभूति का आनन्द लेने के लिए और काम करने की शक्ति की दृष्टि बिना किसी स्पष्ट विचार या स्पष्ट विशिष्ट कार्य की इच्छाओं से।
- (6) मृत्यु उद्देश्य या व्यापारिक परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए।
- (7) सम्पत्ति अर्जित करने की इच्छा।
- (8) विशुद्ध बचसूची या कृपणता की सतुष्टि के लिए।

प्रो० वीन्स ने उपर्युक्त उद्देश्यों की सुरक्षा, दूरदर्शिता अनुमान या आकलन, प्रगतिशीलता, स्वतन्त्रता, ग्राहकता, कृपणता आदि की सजा दी है। उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रो० वीन्स ने केन्द्रीय तथा स्वायत्त संस्थाओं या फर्मों द्वारा बचत करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं—

1. बाजार से ऋण या पूँजी प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयं पूँजीगत विनियोगों की दृष्टि से।

2. तरलता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिमसे कि तरल साधनों की सुरक्षा की जा सके और आपात स्थिति, कठिनाइयों तथा मन्दी से निपटा जा सके।

3 प्रगति के उद्देश्य की दृष्टि से।

4 आर्थिक चतुराई व उद्देश्य की दृष्टि से जिसमें कि ऋण शोधन तथा भावी सम्पत्ति की तागत को समाप्त करने के लिए व्यवस्था ही सके।

इन सभी उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता सस्थाओं तथा संगठनों को आर्थिक समुदाय की आदता शिक्षा रीति रिवाजों धर्म और वर्तमान नैतिक स्तर वर्तमान की आशाओं तथा भूतकारीन अनुभवों पूंजीगत अस्त्रों के पैमाने तथा तकनीक सम्पत्ति के प्रचलित वितरण व्यवस्था तथा लागत द्वारा जीवन-स्तर व्यतात करने आदि बातों पर निर्भर करेगा।

अल्पकाल में व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तत्वा में अधिक परिवर्तन नहीं होते इस लिए हम उपभोग वक्र की आकृति को अपरिवर्तित मानकर चलते हैं।

**साधारण उपभोग फलन के परिष्कार (Refinements of the Simple Consumption Function)**

प्रो० कीन्स ने उपभोग फलन की धारणा निम्नलिखित ध्रुव धारणाओं पर आधारित है—

(1) उपभोग विद्यमान आय का फलन होता है  $C = f(Y_t)$ ।

(2) उपभोग फलन आय के सम्बंध में परिवर्ती होता है यदि आय में कमी होगी तो व्यक्ति उसी हिसाब से उपभोग में कमी कर देगा जिस प्रकार आय बढ़ने पर उन्होंने उपभोग के स्तर को बढ़ा दिया था।

(3) उपभोक्ता द्वारा व्यय करने की विधि स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। वे आय उपभोक्तियों व व्यय पर निर्भर नहीं करने।

**प्रो० ड्यूसेनबेरी परिष्कल्पना (Prof Duesenberry Hypothesis)**

सन् 1957 में प्रकाशित प्रो० ड्यूसेनबेरी ने अपनी पुस्तक = *Income Saving and the Theory of Consumer Behaviour* में प्रो० कीन्स का संश्लेषण किया और दो मुख्य बातों को बताया जो उपभोग फलन के सम्बंध में पाई जाती हैं इन्हें ड्यूसेनबेरी परिष्कल्पना (Duesenberry Hypothesis) कहा जाता है। प्रथम उनका कहना यह है कि एक व्यक्ति का उपभोग व्यय उसकी वर्तमान आय के द्वारा ही तय नहीं होता। परंतु भूतकाल में व्यतीत जीवन स्तर के द्वारा भी तय होता है। वे कहते हैं कि जब किसी परिवार की आय उस नये स्तर तक पहुँचती है जिसे स्थायी माना जाता है तो परिवार अन्ततः अपने उपभोग का समायोजन एक उच्च आय स्तर पर करेगा। इस बात को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यदि एक परिवार की दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति 7 है और स्वायत्त आय 7000 रुपये है तो वह 4900 रुपये उपभोग करेगा। यदि उसकी आय बढ़कर 9000 रुपये हो जाती है तो उपभोग बढ़कर 6300 रुपये हो जाएगा परंतु यदि किसी कारणवश उस परिवार की आय फिर 7000 रुपये रह जाती है तो परिवार अपने भूतकालीन उपभोग धरारशि 6300 रुपये को घटाकर 4900 रुपये नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उसी जीवन स्तर को बनाए रखेगा जिसका वह पहले आदी हो चुका होगा।

प्रो० ड्यूसेनबेरी के तर्क अर्थ यह है कि प्रो० कीन्स का यह धारणा सही नहीं है कि उपभोग विद्यमान आय का फलन ही नहीं है। वरन् यह पहले प्राप्त आय के उच्चतम स्तर का भी फलन है। वे कहते हैं कि अधिकतम आय वाले वर्ग का उपभोग वह स्तर स्थापित

करता है निम्न वर्गों को जाता है। अधिकतम उपभोग जितना अधिक होगा उपभोग को घटाने की स्तर पर जाता उतना ही रहित होगा।

दूसरे में उपभोग के नतीजे की इस प्रकार धारणा पर भी आधुनिक विचार है कि उपभोक्ता द्वारा व्यय करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। उनका कहना है कि किसी परिवार का पारिवारिक व्यय या उपभोग उस परिवार की वृद्धि स्वतंत्र गति का ही चयन नहीं है बल्कि उच्च आय के समूह के अन्य उपभोक्ताओं की गति का भी प्रभाव होता है। निम्न आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया उच्च आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया द्वारा प्रभावित होती है। यदि निम्न आय वर्ग का उच्च आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया का उपभोग प्रारम्भ कर देता है तो उच्च आय वर्ग के लोग की उपभोग प्रिया का उपभोग प्रारम्भ कर देता है इस प्रकार उपभोग प्रिया का विस्तार होता जाता है।

### परीक्षा-प्रश्न

1. उपभोग प्रिया या फलन का बताइए। औसत तथा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति में आप क्या समझते हैं और इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?  
(Explain consumption function. What do you mean by Average and Marginal Propensities to consume? What is the relationship between them?)
2. कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम तथा उसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए।  
(Discuss Keynes's Psychological Law of Consumption and its limitations)
3. कीन्स का सबसे उल्लेखनीय योगदान उसकी उपभोग प्रिया की व्याख्या है। (हैन्सन) इस कथन के आधार पर उपभोग प्रिया का समष्टि आर्थिक विस्तारण में महत्त्व बताइए।  
(Keynes's most notable contribution was his consumption function. (Hansen) In the light of this statement bring the importance of consumption function in macro economic analysis)
4. उपभोग फलन में आप क्या समझते हैं? उपभोग फलन का निर्धारित करने वाले व्यक्तिगत तथा दम्बुनिष्ठ तत्वों का समझाइए।  
(What do you understand by consumption function? Explain subjective and objective factors which determine the consumption function)
5. उपभोग प्रवृत्ति में आप क्या समझते हैं? सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति में भेद कीजिए।  
(What do you understand by the consumption function? Distinguish between the Marginal propensity to consume and Average Propensity to consume)

6 टिप्पणी लिखिए—

- (i) कुल माँग श्रिया तथा कुन पूर्ति श्रिया  
 (ii) कीन्स रोजगार मॉडल के निम्न तथा स्वतन्त्र चर ।

Write notes on —

- (i) Aggregate Demand Function and Aggregate Supply Function  
 (ii) Dependent and Independent Variables of Keynesian Model of Employment

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्न प्रश्न सही या गलत बताइए ।

- (i) उपभोग फलन उपभोग तथा आय के सम्बन्ध को बताता है ।  
 (ii) कीन्स का उल्लेखनीय योगदान उमकी उपभोग श्रिया है ।  
 (iii) औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) एक समयावधि में कुल आय के मन्दभ में कुल उपभोग की स्थिति को बताती है ।  
 (iv) सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) आय की वृद्धि में होने वाले परिवर्तन के मन्दभ में उपभोग में होने वाली वृद्धि के परिवर्तनों की व्याख्या करती है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है (ii) सही है (iii) सही है (iv) सही है ।

"Investment is the net addition to the existing stock of real capital assets" — Dudley Dillard

अध्याय 7

## विनियोग क्रिया

(THE INVESTMENT FUNCTION)

### विनियोग का अर्थ (Meaning of Investment)

निवेश का अर्थ इसके सामान्य अर्थ से अलग होना है। साधारण बोलचाल की भाषा में निवेश का अर्थ स्टॉक तथा अग्रे अर्थो ऋण-पत्रों सरकारी प्रतिभूतियों तथा बाण्डों आदि के प्रय करने से होता है। परन्तु प्रो० बीन्स ने विनियोग का अर्थ कुछ व्यापक दृष्टि-कोण में किया है। निवेश व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टियों में हो सकता है। निवेश दो प्रकार का होता है। (i) वित्तीय निवेश (Financial Investment) (ii) वास्तविक निवेश (Real Investment)। जब कोई व्यक्ति या फर्म कुछ स्टॉक तथा अन्य ऋण-पत्र या सरकारी प्रतिभूतियाँ या बाण्ड खरीदती है तो हम इसे वित्तीय निवेश करते हैं। इसमें एक व्यक्ति या फर्म इन अर्थो ऋण-पत्र या बाण्डों को बेचती है तो दूसरा धारिता या फर्म इन्हें खरीदती है। यह तो एक प्रकार में एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति ग्वामि व वा हस्तांतरण होता है इसमें एक के द्वारा विनियोग या निवेश और दूसरे के द्वारा अविनियोग (Disinvestment) किया जाता है। इसमें राष्ट्र की वास्तविक पूँजी के स्तर में वृद्धि नहीं होती।

### निवेश का अर्थ (Meaning of Investment)

प्रो० बीन्स ने वास्तविक विनियोग का अर्थ नये पूँजीगत पदार्थों के उत्पादन करने तथा खरीदने के लिए किया है अर्थात् नई फर्मों के अथ, कोण्डन, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने से लिया है। इसका आशय वर्तमान स्तर में वास्तविक पूँजी पदार्थों में वृद्धि से लिया जाता है। वास्तविक विनियोग (Real Investment) की शर्त यह है कि इस नये विनियोग नये पूँजीगत पदार्थों (Capital Assets) में वृद्धि के साथ ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हो तथा अधिक कच्चे माल का उपयोग विभिन्न फर्मों द्वारा किया जाए। प्रो० बीन्स की विचारधारा में मिलनी हुई विचारधारा प्रो० टडने रिवाड ने विनियोगों के अर्थ के रूप में स्वीकार की है। वे कहते हैं कि "पूँजी पदार्थों के वास्तविक उपलब्ध स्तर में शुद्ध वृद्धि को विनियोग कहते हैं।"<sup>1</sup>

प्रो० पीटरसन के शब्दों में—“निवेश एवं नये उत्पादन द्वारा टिकाऊ यन्त्रों पर होने वाले व्यय तथा निर्माण कार्यों में होने वाले परिवर्तनों के ध्यय शामिल होते हैं।”<sup>2</sup>

1. "Investment is the net addition to the existing stock of real capital assets." — Dudley Dillard

2. "Investment expenditure includes expenditure for 'producers' durable equipments new construction and the change in inventories"

—Peterson

## नियोजित तथा अनियोजित निवेश (Intended and Unintended Investment)

विनियोग का अर्थ हमें उपलब्ध स्टॉक में केवल वृद्धि म ही नहीं लगाना चाहिए वरन् निमित्त वस्तुआ तथा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादिक अन्य वस्तुओं की वृद्धि से भी लेना चाहिए। इस प्रकार विनियोगों का अर्थ पूंजीगत पदार्थों तथा नई माला (inventories) में वृद्धि दोनों से हो लगाना चाहिए। इन प्रकार inventories में वृद्धि नियोजित तथा अनियोजित दोनों ही तरह में हो सकती है। जानबूझकर (Intentional) उत्पादन क्षमता में वृद्धि दो कारणों से हो सकती है जैसे विप्री में वृद्धि तथा मजिप्य में वीमतों के बढ़ने की आशा के द्वारा। बिना सोचे विनियोग या अनियोजित विनियोग उस समय होता है जब बाजार की भावी अनिश्चितताओं तथा स्थितियों के कारण बिना विने वस्तुआ का मचप हो जाता है। यदि एक व्यापारी जिसके पास 5 लाख रुपए का स्टॉक है और वह उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर लेता है तो इसका आशय यह है कि उसने अपना वास्तविक विनियोग बढ़ाकर दुगुना कर लिया है और उसने वस्तुआ की नई माँग अधिक धमिकों को रोजगार तथा अन्य उत्पादक साधना में लगाकर पैदा कर ली है। कैंन ने नियोजित तथा अनियोजित विनियोग को कोई खास महत्व नहीं दिया है।

## निवेश का महत्व (Importance of Investment)

प्रो० वीन्स ने रोजगार सिद्धान्त तथा प्रभावपूर्ण माँग के सिद्धान्त में अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति को स्थिर माना है। इसलिए आय उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण में विनियोगों का महत्व बहुत अधिक है। आय की मात्रा तथा उपभोग की मात्रा के बीच अन्तर को पाटने के लिये विनियोगों का होना जरूरी है। विनियोग उपभोग की अपेक्षा अधिक नीतिगत चर है और आय की मात्रा को निर्धारित करने में विनियोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम पहले ही यह देस चुने है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग ब्यय बढ़ता है परन्तु यह वृद्धि की दर आय की दर से कम होती है अर्थात् उपभोग इकाई से कम बढ़ता है। यदि हमें बड़ी हुई आय की दर को बनाए रखना है तो उसने लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक निवेश आय और उपभोग के बराबर उसी आय में से कर देना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि दिन-दिनियोगों को बढ़ाये, आय में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। इस प्रकार प्रो० वीन्स ने विनियोगों को आय उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने मन्दीकाल में निजी विनियोगों की अपेक्षा सार्वजनिक विनियोगों को बढ़ाने का सुझाव दिया है।

## कुल तथा शुद्ध निवेश (Gross and Net Investment)

अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में जो कुछ वास्तविक निवेश होता है उसे कुल निवेश की संज्ञा दी जाती है परन्तु कुल निवेश का आगत कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि से नहीं लेना चाहिए। परन्तु इसका एक भाग ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है और शेष भाग पिछावट के अर्थ, साज-सज्जा के रख रखाव अथवा प्रतिस्थापन माँग का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके विपरीत शुद्ध निवेश कुल निवेश का वह भाग होता है जो अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि का सूचक होता है।

कुल निवेश तथा शुद्ध निवेश का अन्तर स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए गायक हो सकता है। स्थिर अर्थव्यवस्था में शुद्ध निवेश की समस्या नहीं होती क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए मजिन नहीं रखा जाता परन्तु स्थिर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल पूंजी स्टॉक को स्थिर बनाए रखने की समस्या बनी रहती है क्योंकि यन्त्र तथा साज-सज्जा को टूट-पूट तथा पिछावट के कारण पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में कमी

आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष कुछ न कुछ कुछ वास्तविक निवेश आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में कुछ निवेश शून्य होता है।

**निवेश के प्रकार (Types of Investment)**

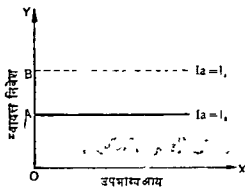
विनियोगों की एक विशेषता यह है कि इनके विभिन्न रूप होते हैं। विनियोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों स्वायत्त मन्त्रालयों विभिन्न फर्मों व्यक्तियों निजी मन्त्रालयों आदि द्वारा हो सकते हैं। विनियोग ध्वज प्लाट तथा मशीनों भवन निर्माण सांख्यिक सेवाओं जैसे मठकों, पुलों, रेलवे, जहाज तथा वायुयानों के निर्माण आदि के लिए हो सकता है। सामान्यतः विनियोग दो प्रकार के होते हैं—(1) स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) तथा (2) प्रेरित निवेश (Induced Investment)।

(1) स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment)—स्वायत्त निवेश वह होता है जिसका सम्बन्ध आय तथा उत्पादन के स्तर में नहीं होता और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य में नहीं किया जाता दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वायत्त निवेश समर्थ मांग (Effective Demand) में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। स्वायत्त निवेश उत्पादन तकनीक प्रविष्टि, जनसंख्या के आकार, आविष्कार तथा सरकारी नीतियाँ या सुरक्षा आदि पर किया गया व्यय कहलाता है। यह आय और लाभ निर्पन्न होता है अर्थात् आय तथा लाभ में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता। मठक, अस्पताल अनुसन्धान तथा विकास पर किया गया व्यय स्वायत्त निवेश के उदाहरण हैं। आय में परिवर्तन होते हुए भी स्वायत्त निवेश स्थिर रह सकता है और आय स्थिर रहते हुए स्वायत्त निवेश परिवर्तित हो सकता है।

स्वायत्त निवेश—  $(IA) = I_1$

$IA =$  स्वायत्त निवेश

$I_1 =$  स्थिर निवेश



उपर्युक्त रेखाचित्र में स्वायत्त निवेश तथा उपभोग्य आय को दर्शाया गया है। चूंकि स्वायत्त निवेश आय में परिवर्तनों के कारण नहीं होते हैं इसलिए इसे  $X$  अक्ष के समानान्तर खींचा गया है।  $Ia = I_1$  तथा  $Ia = I_2$  वक्रों में ज्ञात होता है कि उपभोग्य आय चाहे जो कुछ भी हो स्वायत्त निवेश में परिवर्तन नहीं होते। यह स्थिति  $OA$  तथा  $OB$  किमी भी वक्र द्वारा दिखाई जा सकती है।

(2) प्रेरित निवेश (Induced Investment)—अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश की मात्रा आय तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होती है। निजी क्षेत्र में माहुरी या अन्य कोई फर्म उनी समय पूंजीगत का नया अथवा उत्पादन उस समय करेगी जब उसे अपनी वस्तुओं की मांग में मांग बनी रहने की आशा हो। उपभोग्य वस्तुओं की मांग की

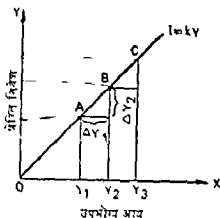


स्वित्त भविष्य में क्या होगा यह उपभोक्ताओं को उपभोग्य आय द्वारा तय होगी और उपभोग्य आय स्वयं आय में स्तर तथा व्यतिगत बरों की माया द्वारा तय होने हैं और औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) पर निर्भर होती है। APC के स्थिर रहने हुए आय में वृद्धि होने पर कुल समग्र मांग में भी स्तर दर पर वृद्धि होती है। इस प्रकार आय में वृद्धि होने पर समग्र मांग गिर जाती है। इन प्रकार प्रेरित निवेश आय सापेक्ष (Income elastic) होता है। अन्यकाल में पूर्ण उत्पादन अनुपात स्थिर रहने के कारण जोय तथा प्रेरित निवेश के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध होता है। प्रेरित निवेश आय में परिवर्तनो द्वारा प्रभावित होता है क्योंकि नुरा समग्र मांग में वृद्धि आय में वृद्धि का परिणाम होती है।

प्रेरित निवेश की आय सापेक्षता धनात्मक होती है। प्रेरित निवेश की आय सापेक्षता शून्य तथा ऋण के मध्य होती तथा यह सामान्य उपभोग प्रवृत्ति तथा पूर्ण उत्पादन अनुपात द्वारा निर्धारित होती अर्थात् प्रेरित निवेश का आय में परिवर्तन के सम्बन्ध में न तो वर्तमान आय सापेक्ष होगा तथा न ही पूर्णतया आय निरपेक्ष। उपभोग्य आय में परि-

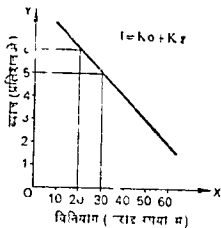
वर्तना द्वारा प्रेरित निवेश में उत्पन्न परिवर्तन धनात्मक होगा अर्थात्  $\frac{dIP}{dY} = dIP = \text{प्रेरित}$

निवेश  $dY$  उपभोग्य आय में परिवर्तन। इसी बात को विभक्तित रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है



$$I = K_0 + K_1 r \text{ तथा } K_1 > 0$$

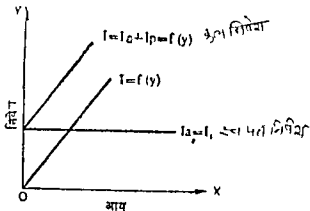
प्रस्तुत रखाचित्र में स्पष्ट है कि जब व्याज की दर 6% से गिरकर 5% रह जाती है तो निवेश राशि भी 20 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपये हो जाती है। जैम-जैसे व्याज की दर गिरती जाएगी वैसे वैसे प्रेरित निवेश बढ़ता जाएगा।



प्रेरित निवेश आनु-स्तर आय में परिवर्तन की दर, औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति, वृत्त इत्यादि आन्तरिक कारणों से प्रभावित होता है जो कि उत्पादन निवेश आविष्कारों, नवीन प्रविद्याओं, जनसंख्या वृद्धि, बुद्ध अन्तर्गत व्यापार श्रेय आन्दोलन, विज्ञान योजनाओं, ऋतुओं आदि में परिवर्तन द्वारा प्रभावित होता है। स्वायत्त निवेश का विचार नियोजित तथा बुद्ध अव्यवस्थाओं में लागू होता है जहाँ निवेश लाभ व विचार से प्रभावित नहीं होता वरन् अन्य कारणों द्वारा लागू होता है।

एक अव्यवस्था में कुल निवेश बराबर प्रेरित + स्वायत्त निवेश। वास्तविक कुल निवेश का कुछ भाग निजा क्षेत्र में व्यक्ति निवेश तथा कुछ भाग गावजनिव क्षेत्र में सरकारी निवेश के रूप में होता है। अव्यवस्था में कुल निवेश का गणना करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों तथा सरकार द्वारा विदेशों में किए गए निवेश का गणना करना अनिवार्य होता है। एक प्रकार वि.शिया द्वारा किए निवेश का कुल निवेश में से घटा देना चाहिए।

कुल निवेश अर्थात् प्रारम्भ + स्वायत्त निवेश का हम निम्नांकित रखाचित्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं



रुत वाचित्र म  $OY$  अक्ष पर कुल निवेश (प्रति + स्वायत्त निवेश) तथा  $OX$  अक्ष पर उपभोग्य आय दिखाई गई है।  $I = I_p - f(y)$  वक्र प्रति निवेश तथा  $I_1 = I_2$  वक्र स्वायत्त निवेश को व्यक्त करते हैं।  $I_1 + I_2$  वक्र कुल निवेश मांग को व्यक्त करता है। कुल निवेश  $I_1 + I_2$  यह व्यक्त करता है कि कुल निवेश कुल उपभोग्य आय से इस प्रकार सधना मक रूप से सम्बन्धित होता है कि कुल उपभोग्य आय में वृद्धि या कमी होने पर कुल निवेश में वृद्धि या कमी होती है इसका अर्थ यह है कि उपभोग्य आय में परिवर्तन

तथा कुल निवेश में परिवर्तन का अनुपात धनात्मक होता है अर्थात्  $\frac{dI}{dY} > 0$

निवेश को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors Determining the Investment)

जब व्यवस्था में निवेश प्रति कुल निवेश प्रमुख रूप से दो तत्व निर्धारित करते हैं—(1) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता या कुशलता (Marginal Efficiency of Capital) (2) ब्याज की दर (Rate of Interest)। जब कभी एक फर्म विनियोग करने का विचार करती है तो या तो इसमें उसे वित्तीय सहायता कहाँ से उधार लेना होगा या फिर उस अपने मापनों से उधार करना होगा। पहली स्थिति में उसे ब्याज देना होगा जबकि दूसरी स्थिति में उसे धनराशि पर भिन्न वाला ब्याज की राशि का त्याग करना होगा। विनियोग लाभ को प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं। एक साहसी विनियोग करते समय पूँजी की सीमान्त क्षमता तथा ब्याज की दर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है जब तक ब्याज की दर में पूँजी की सीमान्त क्षमता अधिक रहेगी तब तक विनियोग होते रहेगे अर्थात् साहसी को लाभ मिलेगा।

ब्याज प्रति अवधारण में निवेश इसी दाना शक्तियाँ द्वारा निर्धारित होता है परन्तु इन दोनों शक्तियों का निवेश का मात्रा पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों में से पूँजी की सीमान्त क्षमता कुल निवेश को ब्याज की दर की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ब्याज की दर में ज़रा-जल्दी परिवर्तन नही होने। निवेशों को प्रेरणा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा अधिक मिलती है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) स्थिर रहते हुए ब्याज की दर में थोड़ी सी गिरावट से कुल निवेश बढ़ने हैं क्योंकि बका तथा ऋण पदान बनाना संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसके विपरीत ब्याज की दर में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि अर्थात् विनियोगों की लागत महंगी हो जाती है और लाभ - माजिन कम हो जाता है और माहसियों के लिए विनियोगों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं रहता।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि निवेश ब्याज सापेक्ष होता है जबकि प्रो० कासने अपना पुस्तक (General Theory) में यह बताया है कि निवेश इतना ब्याज सापेक्ष नहीं होता जसाकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों समझते थे। प्रो० कोसने ने कहा कि निवेश ब्याज की अपेक्षा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में अल्प मात्रा में अस्थिरता तथा चिरव्यवस्थित गतिहीनता का प्रवृत्ति पाई जाती है।

प्रो० कोसने का कहना है कि मन्थनान्त में निवेश हेतु ब्याज की सापेक्षता बहुत कम होती है तथा धनात्मक ब्याज की दर पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि तथा निवेश के बीच पूर्ण जोड़गार वस्तु पर मूल्य स्थापित नहीं हो सकता। कोसने का विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर (प्रतामक) 2% से नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इस मूल्य

दर पर लागू द्वारा असीमित मात्रा में मुद्रा की माँग व वारण नकदा अधिमान वक्र (Liquidity Preference Curve) पूणतया व्याज से पक्ष हो जाता है। व्याज की इस दर पर निवेशकर्ता अपने सम्पत्ति का सर्वोत्तम प्रतिभूतिया या वाण्डा में न करके नकदी के रूप में रखना अधिक पसंद करेगा। व्याज की इस न्यूनतम दर पर पूण राजगार वचत (Full Employment Saving) पूण राजगार निवेश (Full Employment Investment) का तुलना में अधिक होगा और इस दरों का जब तक अतिरिक्त निवेश अथवा अतिरिक्त उपभाग द्वारा नहीं पाटा जाएगा तब तक अर्थव्यवस्था में पूण राजगार का प्राप्त करना कठिन होगा।

जहाँ तक उपभाग में वृद्धि का सवाल है यह आय का मात्रा तथा आय का जपभाग प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि निधना के पीछे आय का पुनर्वितरण करके उपभाग में कुछ वृद्धि की जा सकती है परंतु पजीवाण अर्थव्यवस्था में इसका कुछ समाप्ति है। पूण राजगार प्राप्त करने के लिए कोसम का विचार है कि व्यय बचाए जाए अर्थात् नाक वयाणाय योजनाओं का चालू किया जाए।

दूसरा प्रमुख शक्ति जो निवेश का प्रभावित करता है वह पूँजी का सीमान्त क्षमता (MEC) कहलाती है। पूँजी का सीमान्त क्षमता पूँजी परिमर्पित का वर्तमान लागत (पति मूल्य) तथा माहंगियों के पूँजी परिमर्पित में वृद्धि से होने वाले लाभ का आशाओं पर निर्भर करता है। एक माहंगे का लाभ सम्पत्ति आशाएँ (Expectations) अल्प कालिन तथा दीर्घकालिन दोनों प्रकार का हो सकती है। अल्पकालिन आशाएँ साहमी तथा व्यापारियों का वर्तमान पूँजी से निवेश में वृद्धि से होने वाला आय होता है। अल्प कालिन आशाएँ - अल्पकालिन आशाओं की तुलना में अधिक स्थिर होता है इसका प्रमुख कारण यह है कि दीर्घकालिन आशाएँ अर्थिक अनिश्चितता होता है। अल्पकालिन आशाएँ मुख्यतः लाभ माँग बताने तथा व्याज की दर आदि आंतरिक कारणों द्वारा प्रभावित होता है। दीर्घकालिन आशाएँ युद्ध, जनसंख्या वृद्धि, अनुसंधान एवं आविष्कार नवीन प्रक्रिया, विज्ञान व्यय, अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियाँ, श्रद्धा तथा विवादायक कार्यों आदि अनेक बाह्य कारणों द्वारा प्रभावित होता है।

साहमी उम्र समय तक निवेश करेगा जब तक कि यह आशा करे कि उच्च निवेश लाभप्रद होगा। यह स्थिति का ज्ञान करने के लिए निम्नलिखित समीकरण दिया जा सकता है।

$$\frac{dR}{dI} > \frac{dC}{dI}$$

अथवा 
$$\frac{dR}{dI} - \frac{dC}{dI} > 0$$

$dR$  = आय में परिवर्तन  $dI$  = विनियोग में परिवर्तन

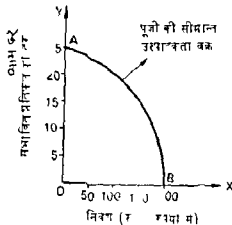
$dC$  = वृत्त लागत में परिवर्तन।

उपरोक्त समीकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब फर्म के निवेश में परिवर्तन ( $dI$ ) होने के लिए आय में परिवर्तन ( $dR$ ) फर्म के निवेश में परिवर्तन हेतु उमकी वृत्त लागत में परिवर्तन ( $dC$ ) का तुलना में अधिक होता है तो विनियोग हात में अर्थव्यवस्था नहीं।

फर्म का दृष्टि में अतिरिक्त पूँजीगत परिमर्पित का लागत मजान का कामत होता है तथा फर्म इसका ज्ञान नहीं करती ग प्राप्त होने वाली आय में करगी। इनके साथ ही

फर्म उस व्यय को भा शामिल करती जा उस मशीन तथा अन्य उत्पादन मज्जा का खरीदन व लिए बिल य सखाआ तथा बना से प्राप्त ऋणा पर ब्याज के रूप म करना पड़ता है । एक फर्म निवेश करत समय ता विशेष बटटा दर को जात करत वा प्रयान करेगा जिस पर ऋण प्राप्त करन म मशीन तथा अन्य उत्पादन मज्जा की बतमान लागत उम मज्जा द्वारा विभजत वर्षों म प्राप्त हान वानो कुल आय व समान हागा । यत् बटटा दर बतमान ब्याज की दर से अधिक हू ता फर्म निवेश याजता का वायान्वित करके निवेश करया अन्यथा नही ।

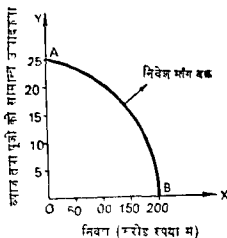
किमा का हुद समयावधि म एक फर्म के सामन कई ऐस अवसर उपस्थित हात है जिसस फर्म को भिन्न आय दर प्राप्त हाती है । अधक लाभ का दर को अप ता कम लाभ व अवसर अधिक होत ह । जैसे जब निवेश क माया म वृद्धि होता है बस वसे लाभ की दर भी कम हाती जाता है । इम स्थिति का निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है ।



प्रस्तुत रेखाचित्र म AB वक्र पूजा सामान्त उत्पादकता वक्र है । इम वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु आसणित लाभ दर तथा इम लाभ दर पर किए जान वान अधिकतम निवेश की माया का सूचित करता है । पूजा की सामान्त उत्पादकता का ऋणामक दाता यह ध्यक्त करता ह कि निवेश का माया तथा लाभ की दर के मध्य इम प्रकार का परस्पर सम्बन्ध है कि निवेश की माया म वृद्धि हान पर लाभ का दर कम हा जात है । एसा प्राय दो कारण म हा सकता है (1) किमा र्भ उद्योग म निवेश म वृद्धि हा जान म लाभ की दर म कमा हा जातो है । (2) निवेश म वृद्धि हान म पूजा का सामान्त उत्पादकता (MEC) गिरता है । मने इराइया की पूर्ति म वृद्धि होने स उनका लागत म वृद्धि हा जाता है क्वाकि उत्पादन माजना तथा बच्चे माल का माँग म वृद्धि स इनकी सामने बढ जाती है ।

हम जब पूजा का सामान्त उत्पादकता पात हात हुए भा ब्याज का दर पात हान म उस अधिकतम निवेश माया का जात किया जा सकता है जिस व्ययमाय वग वाय रूप म परिणत करया क्वाकि निवेश उन माया तक हागा जहाँ MEC - Marginal Rate of Interest इम भी अप्राकित रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है जो उपयुक्त रेखाचित्र का भीति है ।

प्रस्तुत रखाचित्र में AB निवेश वक्र है। इस वक्र पर गिन प्रत्येक बिंदु निवेश की उस अधिकतम मात्रा का घटक करने है जिसमें माहूमी भिन्न भिन्न ब्याज दरों पर प्रियाचित करण।



### परीक्षा प्रश्न

- 1 स्वायत्त निवेश का क्या अर्थ है? इस निवेश के अंतर्गत किम प्रकार के निवेश आते हैं? इस निवेश का आर्थिक महत्व क्या है?

(What is meant by autonomous investment? What kind of investment fall under this category? What is the economic significance of this kind of investment?)

- 2 प्रारत निवेश में आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन तत्वों का बतलाया जा प्ररित निवेश का निर्धारण करते हैं।

(What is meant by induced investment? Discuss those factors which govern the induced investment in a capitalist economy.)

- 3 विनियोग क्रिया में आप क्या समझते हैं? उन तत्वों का व्याख्या कीजिए जो विनियोग का प्रभावित करते हैं।

(What do you understand by investment function? Discuss those factors which determine the investment.)

- 4 टिप्पणी लिखिए—

(अ) कुल तथा शुद्ध निवेश (ब) स्वायत्त तथा प्ररित निवेश (ग) नियोजित तथा अनियोजित निवेश (द) निवेश का निर्धारण करने वाले कारण।

Write notes on —

(a) Gross and Net Investment (b) Autonomous and Induced Investment (c) Intended and unintended Investment (d) Factors Determining the Investment

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)**

निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही है और कौन गलत है ।

- (i) पूजा पदार्थों के वास्तविक उपलब्ध स्टाक में शुद्ध वृद्धि को वित्तियोग कहते हैं ।
- (ii) स्वायत्त निवेश समर्थ माँग में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होता है ।
- (iii) प्ररित निवेश की मात्रा आय तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती है ।
- (iv) कास व अनुसार निवेश ब्याज की अपा पूजा का मामात उत्पादकता द्वारा अधिक प्रभावित हाता है ।
- (v) पूजा की क्षीमान्त उत्पादकता में अल्पकालीन तथा चिरकालीन गतिहीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है ।

**वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर**

- (i) सही है । (ii) गलत है । (iii) सही है । (iv) सही है । (v) सही है ।

Marginal efficiency of capital is the ratio between the prospective yield of additional capital goods and their supply price " Kurthara

अध्याय 8

## पूँजी की सीमान्त क्षमता

(MARGINAL EFFICIENCY OF CAPITAL)

पूँजी का सीमान्त क्षमता अथवा उत्पादकता कीमत्वादा अर्थशास्त्र में जाय उत्पादन तथा राजस्व का स्तर का प्रमुख निर्धारक तत्व है। एक उत्पादकता या फल के लिए पूँजी की सीमान्त उत्पादकता का विशेष महत्त्व है। एक उत्पादक या फल पूँजी विनियोजन करने में पहले पूँजी में प्राप्त प्रतिफल अर्थात् पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा पूँजी पूर्ति की लागत अर्थात् व्यय की तुलना करना है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता माहमी की मनावैज्ञानिक विचारधारा द्वारा तय होता है जिसके बारे में माहमी कवन अनुमान ही लगाता है। पूँजी की सीमान्त क्षमता या उत्पादकता उस सम्भावित लाभ की दर होती है जिसका सम्बन्ध वर्तमान में लाभ की दर में नही होता और जिसमें अन्वयान्त में अधिक उच्चावचन दखन का मिनत है।

**परिभाषा**— विभिन्न विद्वानों द्वारा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की परिभाषाएँ इस प्रकार की गई हैं—

प्रो० के० कुरीहारा के अनुसार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता अतिरिक्त पूँजीगत पदार्थों की अनुमानित तथा उनकी पूर्ति कीमत के मध्य अनुपात का बताती है।<sup>1</sup>

प्रो० डिलाई के अनुसार किन्हीं विषय पूँजी परिसम्पत्ति की अतिरिक्त इकाई लागत पर आय की जा अधिकतम दर प्राप्त होती है उस पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कहा जाता है।<sup>2</sup>

1 Marginal efficiency of capital is the ratio between the prospective yield of additional capital goods and their supply price

—Kurthara

2 The marginal efficiency of a particular type of capital asset is the highest rate of return over cost expected from an additional unit of that type of asset

—Dudley Dillard



प्र० स्टोनिगर तथा हेग के शब्दों में किसी विशेष प्रकार के पूँजीगत पदार्थ की सीमान्त उत्पादकता इस बात को व्यक्त करती है कि एक माहसल एक अनिश्चित पूँजी परिसम्पत्ति लगाकर इससे उस पर व्यय किए गए धन की तुलना में बिलनी आय प्राप्ति की आशा रखता है।<sup>1</sup>

पूँजी की सीमान्त क्षमता एक पूँजी पदार्थ की उस बट्टा दर को कहते हैं जिस पर एक पदार्थ की भावी प्राप्ति (Prospective Yield) का बट्टा इतना होता है कि उस पदार्थ की पूर्ति कीमत में बराबर हो जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि प्रत्याशित वार्षिक प्राप्ति (Qs) के मूल्य का अनुमान तथा उसकी लागत का पता चल जाए तो इन दोनों के अनुपात अथवा दर को पूँजी की सीमान्त क्षमता कहा जाएगा। प्र० कीस ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूँजी की सीमान्त क्षमता की परिभाषा इस प्रकार दी है। कीस के शब्दों में पूँजी की सीमान्त क्षमता बट्टा की उस दर के बराबर होती है जो पूँजी परिसम्पत्तियों के जीवन काल में प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक प्रतिपत्तियों की मात्रा के बतमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर दे।<sup>2</sup>

प्र० कीस की परिभाषा को एक समीकरण द्वारा भी दिखाया जा सकता है—

पूर्ति कीमत = बट्टा की गई भावी प्राप्ति

Supply Price = Discounted Prospective Yields

$$\text{अथवा Cr or Sp} = \frac{Q_1}{1+r} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \frac{Q_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Q_n}{(1+r)^n}$$

Cr अथवा Sp = पूँजी परिसम्पत्ति की पूर्ति कीमत अथवा पुनः स्थापन लागत  
(Cost of replacement)

$Q_1, Q_2, Q_3, Q_n$  - प्रत्याशित वार्षिक प्राप्ति (Prospective yields in various years)

$r$  = वह बट्टा दर है जो वार्षिक प्राप्ति के बतमान मूल्य को पूँजी परिसम्पत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर बना देता है।

व्यवहार में एक पूँजी पदार्थ के जीवन काल में तथा उससे प्राप्त होने वाली सम्भावित प्राप्ति का अनुमान लगाना कठिन होता है। परन्तु इस प्रकार के अनुमान लगाने के अलावा कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है जो एक पूँजी पदार्थ के जीवनकाल और उत्पन्न प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगा सके। इतना ही नहीं उपयुक्त समीकरण में  $Q_s$  के मूल्य का अनुमान हम गतिशील समाज में नहीं लगा सकते जिनमें हम रहते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता पूँजी पूर्ति की कीमत तथा पूँजी पदार्थ से प्राप्त भावी प्राप्ति (Prospective Yields of Assets) द्वारा निर्धारित होती है जबकि व्याज की दर

1 The marginal efficiency of a particular type of asset shows that an entrepreneur expects to earn from one more asset of that kind compared with what he has to pay to buy it — *Sturker and Hague*

2 Marginal efficiency of capital as being equal to the rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the return expected from the capital asset during its life just equal to its supply price — *J M Keynes*

नषदी अधिमान अनुसूची तथा चलन में मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। निवेशों की मात्रा में परिवर्तन पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं परन्तु व्याज की दर को प्रभावित नहीं करते। पूँजी की सीमान्त क्षमता तथा व्याज की दर दोनों को बराबर नान में निवेशों की मात्रा में परिवर्तन जरूरी होते हैं।

एक समयावधि में विभिन्न निवेशों पर पूँजी की सीमान्त क्षमता भी अलग-अलग होती है। इसमें जिसकी सीमान्त क्षमता सबसे अधिक होगी यदि अतिरिक्त विनियोग उस पर किया जाय तो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि में वही विनियोग सबसे अधिक लाभप्रद समझा जाएगा। इसलिए यदि हमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में विनियोगों में वृद्धि करना है तो हमें ऐसी पूँजी परिस्थितियों की मात्रा को बढ़ाना होगा जो अधिकतम क्षमता प्रदान कर सकें। प्रो० बीन्स ने पूँजी की सीमान्त क्षमता को पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में जलग माना है। उनमें अनुसार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता पूँजी की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग में दान प्राप्त में होने वाली वृद्धि होती है। इसके विपरीत पूँजी की सीमान्त क्षमता बढ़ती में वह दर होती है जो पूँजी परिस्थिति में प्राप्त होने वाली कुल सीमान्त आय को इसकी पुन स्थापना लागत (Replacement Cost) के बराबर कर देती है। सीमान्त क्षमता का सम्बन्ध वर्तमान वार्षिक लाभ से नहीं बरन् प्रत्याशित भावी प्राप्तियों (Expected Prospective Yields) की विनियोग प्रेरणा में रूप में देवना चाहिए।

विनियोग माँग अनुसूची—विनियोग माँग अनुसूची एक समयावधि में विभिन्न विनियोग स्तरों पर पूँजी पदार्थ की विभिन्न सीमान्त क्षमताओं को बताती है। इस अनुसूची के आधार पर जिस वक्र का निर्माण किया जाता है उसे विनियोग माँग वक्र कहते हैं। यह वक्र बायें हाथ से दाहिने हाथ नीचे की ओर गिरता हुआ होता है जो बताता है कि जैसे-जैसे विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे पूँजी की सीमान्त क्षमता में कमी होती जाती है। प्रो० बीन्स कहते हैं कि एक प्रकार की पूँजी परिस्थिति (मशीन) में किसी समय विनियोग की मात्रा में वृद्धि के साथ पूँजी की सीमान्त क्षमता में गिरावट आती है ऐसा सम्भवत दो कारणों में होता है—(1) जैसे ही उम सम्पत्ति की प्रति बढ़ेगी उसमें भावी प्राप्ति गिरेगी, (2) ऐसी सम्पत्ति की उत्पत्ति की मुविद्याओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने में इनकी प्रति कीमत भी बढ़ेगी।

### विनियोग माँग अनुसूची (Investment Demand Schedule)

| विनियोग करोड़ रुपयों में | पूँजी की सीमान्त क्षमता का वार्षिक प्रतिशत |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 100                      | 15                                         |
| 200                      | 12                                         |
| 300                      | 10                                         |
| 400                      | 8                                          |
| 500                      | 5                                          |

विनियोग माँग सूची रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह व्याज की दर में परिवर्तन होने में विनियोग की मात्रा या राशि परिवर्तन को व्यक्त करती है। हालांकि प्रो० बीन्स ने व्याज की दर को विनियोग की मात्रा में स्वतन्त्र माना है जबकि पूँजी की सीमान्त क्षमता विनियोग की मात्रा का फल होती है अर्थात्  $MEC = f(I)$ । जितनी पूँजी की सीमान्त क्षमता में लोच जितनी अधिक होगी, व्याज की गिरती हुई दर पर उतना ही विनियोग की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार जितनी पूँजी की सीमान्त क्षमता में लोच कम होगी उतनी ही कम विनियोगों में वृद्धि एक

गिरती हुई ब्याज की दर पर होंगी। विनियोग माँग अनुसूची की स्थिति जीर उगता स्वरूप विभिन्न जटिल कारणों पर निर्भर करेगी जो कि प्रत्येक साहसी के अर्नेअपने अलग अनुमानों तथा पुनरीक्षण द्वारा मासित होंगे। एक उद्योग निवेश या एक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की विनियोग माँग सूची का निर्माण करना कठिन होता है। MEC की माँग अनुसूची कम लोचपूर्ण होती है न कि अधिक लोचपूर्ण। ब्याज की दर में परिवर्तन नये विनियोगों को अधिक प्रभावित नहीं कर पाते बरन् विनाश या वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति में सम्मन्वित तत्व विनियोगों की माया को ब्याज की दर की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों तत्व प्रभावित करते रहते हैं—

(I) पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन तत्व

1. उपभोग प्रवृत्ति—अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर जाने को प्रवृत्ति होती है इसलिए इसका पूँजी की सीमान्त क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ने से आगिय रूप से पूँजीगत वस्तुओं की माँग बढ़ती है।

2. माँग, लागत तथा कीमतों का स्वभाव—यदि लागतों के बढ़ने को प्रवृत्ति बनी रहती है तो एव उत्पादक को विनियोगों से प्राप्त होने वाली प्रतिफल की दर में गिरावट आएगी और पूँजी की सीमान्त क्षमता गिरेगी। भविष्य में कीमतों तथा माँग के गिरने की प्रवृत्ति से भी पूँजी की सीमान्त क्षमता में गिरावट आती है। इसके विपरीत लागतों में गिरावट, कीमतों तथा माँग में वृद्धि की आशा होने पर पूँजी की सीमान्त क्षमता बढ़ेगी।

3. आय में परिवर्तन—पूँजी की सीमान्त क्षमता आय में अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती है। आय में परिवर्तन लाभ तथा हानि में अत्रत्याखिन परिवर्तन, बरों में छूट आदि द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। आय में वृद्धि से पूँजी की सीमान्त क्षमता बढ़ेगी और आय में गिरावट होने से MEC गिरेगी।

4. नकद सम्पत्तियों में परिवर्तन—यदि एक साहसी के पास नकद सम्पत्तियाँ अधिक हैं तो विनियोगों से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए जब कभी भी उसे अच्छे अवसर दिखाई देंगे तो वह इनका लाभ उठाएगा और MEC बढ़ेगी इसके विपरीत यदि उसने पास नकद सम्पत्तियाँ (Liquid Assets) नहीं हैं तो वह लाभपूर्ण पूँजी विनियोजनों के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकेगा।

5. वर्तमान प्रतिफल की दर—पूँजीपति पूँजी विनियोजन इस आशा से करते हैं कि उनके विनियोजन से प्राप्त प्रतिफल की दर अच्छी रहेगी और वर्तमान में तागु प्रतिफल की दर से कम नहीं होगी जिस पर कि विनियोग हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान प्रतिफल की दर पूँजी विनियोजन के लिए जरूरी होती है।

6. प्रत्याशाएँ—पूँजी की सीमान्त क्षमता एव साहसी या उत्पादन की प्रत्याशाओं पर भी निर्भर करती है और यह प्रत्याशाएँ आशावादी और निराशाजनक (Pessimistic and Optimistic) दोनों ही प्रकार की होती हैं। आशावादिता की स्थिति में पूँजी, विनियोजन से प्राप्त प्रतिफल को आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाया जाता है जिससे MEC बढ़ती है जबकि निराशावादिता की स्थिति में जरूरत से कम प्रतिफल प्राप्त होने को धारणा रहती है इसलिए MEC गिरती है।

(II) पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक तत्व

MEC को प्रभावित करने वाले प्रमुख दीर्घकालिक तत्व अघातित बताए जा सकते हैं—

1. जनसंख्या का स्वरूप—जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे-वैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए विभिन्न मारुजर्जर सेवाआ, भवनो, उपभोक्ता वस्तु उद्योगो आदि की माँग बढ़ती है और इनके लिए पूँजी विनियोजन बढ़ता है इसलिए MEC भी बढ़ती है क्योंकि इन सबका मित्रा-जुना प्रभाव सभी क्षेत्रो में माँग में वृद्धि के रूप में होता है।

2 उत्पादन विधियो की अपनाना—उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक विधियो विशेष रूप में पूँजी लगाने वाले क्षेत्रो या ऐसे क्षेत्रो में जहाँ लागत गिराने के प्रयाग बने रहे, विनियोग बढ़त है और MEC बढ़ती है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रो में मीमेष्ट, लोहा गैस कपडा ओटोमोबाइल (कार स्मूटर माटरमाइकिला) आदि के उद्योगो के क्षेत्रो में तकनीकी प्रगति न इन क्षेत्रों में पूँजी विनियोजन का उदान में महायता दी है।

3 पूँजी साधनों की पूर्ति—पूँजी साधनों की पूर्ति बनी रहन पर ही उत्पादन तकनीक बाजार के विस्तार जनमाया वृद्धि आदि की माँग को पूरा किया जा सकता है। यदि वर्तमान मशीनो तथा विभिन्न उत्पादन के प्लांटो की क्षमता में ही उपयुक्त, बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके तो पूँजी निवेश नहीं बढ़ेगा अन्यथा निवेश बढ़ेगा और MEC भी बढ़ेगा।

आशांसाएँ तथा पूँजी की सीमान्त क्षमता (Expectations and Marginal Efficiency of Capital)

पूँजी की सीमान्त क्षमता के दो प्रमुख निर्धारक तत्व हाते हैं—(1) पूर्ति कीमत अथवा लागत (2) भावी प्राप्तियाँ या प्रनिफल (Prospective Yield or Return)। अपवान में पूर्ति कीमत या लागत स्थिर रहती है इसलिए MEC पर भावी प्राप्ति या प्रतिफल का प्रभाव अधिक होना है। भावी प्राप्तियाँ अनिश्चित होती हैं। भावी प्राप्तियाँ विनियोजका की आशमाओं पर निर्भर करती हैं। एक विनियोजक या पूँजी विनियोजन करने समय वर्तमान प्राप्ति अथवा जाय की अपक्षा भावी प्राप्तियो अथवा जाय को अधिक महत्त्व देता है।

एक माहमी के लिए भावी प्राप्तियाँ का मध्यम अपने पूँजी पदार्थ के उत्पाद को बेचने में प्राप्त होने की आशा होती है। यह आशमाएँ मुख्यत दो प्रकार की होती हैं—(1) अल्पकालीन आशमाएँ, (2) दीर्घकालीन आशमाएँ। अल्पकालीन आशमाओं का मध्यम एक माहमी को अपने कारगराने के प्लांट की उत्पादन क्षमता के अथवा उमकी रित्री से होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्लांट की क्षमता को स्थिर मान लिया गया है। जबकि दीर्घकालीन आशमाओं का मध्यम नए निवेशों में प्राप्त प्लांट की क्षमताओं में परिवर्तन अथवा नए प्लांट को स्थापित करने में विश्वी अथवा उत्पादन से होता है। इन दोनों आशमाओं को हम पुनर्-पुनः रूप में निम्न प्रकार में रख सकते हैं—

1 अल्पकालीन आशांसाएँ (Short-term Expectations)—दीर्घकालीन आशमाओं की अपक्षा अल्पकालीन आशमाएँ अधिक स्थिर होती हैं क्योंकि यह वर्तमान तत्वों पर आधारित होती हैं। वर्तमान में बँते हुए समय को घटनाएँ आने वाले समय के लिए एक अच्छा और सुरक्षित मार्ग दर्शक हो सकती हैं। इन आशमाओं से तात्पर्य वर्तमान दृष्टियों के उत्पादन एवं विश्वी से होता है जिनसे यारे में कुछ निश्चित अनुमान लगाए जाते हैं। अल्पकालीन आशमाओं में मनु होने का गुण अधिक पाया जाता है क्योंकि बहुत सी स्थितियाँ जो वर्तमान उत्पादन को प्रभावित करती हैं, लगभग स्थिर रहती हैं। अल्पकालीन आशमाओं को गिठने अनुभवों के आधार पर नियन्त्रित किया जा सकता है। चूँकि अल्पकालीन आशमाएँ अधिक स्थिर होती हैं इसलिए यह विनियोग में उच्चारचनों को व्यक्त करने में अममयं होती हैं।

२ दीर्घकालीन आशाएँ (Long term Expectations)—दीर्घकालीन आशाएँ भावी प्राप्तियो से सम्बन्धित होने के कारण, अल्पकालीन आशाओं की अपेक्षा पूर्णतया अनिश्चित होती है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग तथा कुल रोजगार होने वाले उच्चावचनो को व्यक्त करने में यह अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि आने वाले चार वर्षों की आर्थिक क्रियाओं की तिथिलता या प्रवृत्ति पिछले चार-पाँच वर्षों की आर्थिक क्रियाओं की भांति होगी जहाँ हम अप-कालीन आशाओं के तार में अधिक निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि दीर्घकाल में सभी तत्व परिवर्तनशील हो जाते हैं उदाहरणार्थ दीर्घकाल में एक बोरखाने के स्वरूप उसके उत्पाद की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा सभी में परिवर्तन हो सकते हैं। एक फस या उत्पादन की इकाई में स्थापित मर्जन तथा बोरखाने के सम्भावित जीवनकाल, उसे कार्यशील रखने की लागत, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन उपभोक्ताओं की रुचियो, प्रभावपूर्ण माँग में परिवर्तन, मजदूरी स्तर निर्यात की स्थिति प्रतियोगिता की स्थिति, सवटकालीन परिस्थितियो तथा भावी राजनैतिक तथा अन्य आर्थिक शक्तिया आदि ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं होता। दीर्घकाल में अनिश्चितताओं के कारण विनियोगकर्ता उन्ही तत्वों को देखते हैं जिनके बारे में वे अधिक आशावान और विश्वस्त होते हैं। इसलिए दीर्घकालीन आशाएँ विनियोजकों के विश्वास द्वारा शासित होती हैं। भविष्य में विश्वास उतना अधिक निश्चित होगा विनियोग उतना ही अधिक और लाभपूर्ण समझा जायेगा। इसलिए विनियोग में उच्चावचन, दीर्घकाल में साहसी के विश्वास पर निर्भर करत है। विनियोग में अधिकता के बाद निराशावादिता तथा मदी की स्थिति आती है जिसमें टिकाऊ पदार्थों में विनियोग गिरते हैं।

पूँजी की सीमान्त क्षमता के विचार की आलोचना (Criticism of the Concept of Marginal Efficiency of Capital)

प्रो० कीन्स के पूँजी की सीमान्त क्षमता का विचार आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। प्रो० सालनियर तथा हैनलिट इस विचारधारा में प्रमुक्त आलोचक हैं—

(1) प्रो० सालनियर (Prof Saulnier) ने अपनी पुस्तक Contemporary Monetary Theory (1947) में कीन्स के इस विचार की आलोचना करने हुए कहा है कि MEC को विशेषात्मक अध्ययन का तब तक एक अस्त्र नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम वितरण के सिद्धान्त का पूरा स्वरूप और विभिन्न उत्पादक साधनों का अंशदान न मालूम हो।<sup>1</sup> वे आगे कहते हैं कि कीन्स ने पूर्ण प्रतियोगिता का बल्पना भी है और उन तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया है जो कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए जरूरी होते हैं। बाजार की दारसविक स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता की होती है। कीन्स के विनियोग प्रिया के विशेषण को MEC तथा ब्याज की दर से सम्बद्ध किया है क्योंकि उन्होंने मजदूरी को श्रम की सीमान्त उत्पादकता के बराबर माना है। यदि मजदूरी से सम्बन्धित इस मान्यता को हम छोड़ दें तो मजदूरी दर भी विनियोग प्रिया के सिद्धान्त का एक आवश्यक अंग बन जाती है।

(2) प्रो० सालनियर कहते हैं कि प्रो० कीन्स ने MEC के विचार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में देखा है। उचित यह होता कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए MEC का विचार अलग-अलग होता है। इस तत्व का हमारी जैसा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की व्यवस्था में विशेष महत्व है।<sup>2</sup>

1 R J Saulnier "Contemporary, Monetary Theory" (1947) pp 340-41.

2 Ibid

(3) प्रो० गाननियर कहते हैं कि कीम विष्णुपण इग बत वा उरलेख करता है कि वृत्त विनियोग माँग अनुसूची का निर्धारण रिग प्रवार होता है । यह इग बात को नही यताता कि पूँजी की उत्पादकता परिवर्तन कौने होते हैं । पूँजी के अलावा अन्य माधनों के स्थिर रहने पर पूँजी की सीमान्त क्षमता (MEC) में कौने परिवर्तन होगा । न ही इगमे इग बात पर ध्यान दिया गया है कि पूँजी तथा अन्य माधनों के परिवर्तनशील होने पर MEC में रिग प्रवार परिवर्तन होगा ।

प्रो० मालनियर कहते हैं कि कीम विष्णुपण उन वचनों तथा अवचतों (Economics and Diseconomics) की व्याख्या नही करता जो कि विनियोग माँग अनुसूची की आरुति प्रभावित करती है । प्रो० गाननियर ना कहना है कि कीम विष्णुपण न ही पूण है और न ही उन तत्वों की गतोपजनन व्याख्या करता है जो पूँजी की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं ।

(4) प्रो० हैज़लिट (Prof Hazlitt) कहते हैं कि कीम ने MEC शब्द विभिन्न अर्थों में किया है कि दूसरे सही अर्थ ना ज्ञान यदि असम्भव नहो तो रटिन अवश्य है । प्रो० कीम ने MEC शब्द का कोई निश्चित अर्थ नही बताया है । कीम के समय MEC शब्द के साथ सीमान्त उत्पादकता आय उपयोगिता आदि शब्दों के उपयोग का भी चलन था । परन्तु कीम ने इन सब शब्दों में सबसे अधिक अस्पष्ट शब्द पूँजी की सीमान्त क्षमता (MEC) का उपयोग ही किया । यदि वे दूसरे स्थान पर अन्य किमी शब्द का उपयोग अपने विष्णुपण में करने तो यह काफी आलोचनाआ में वच गवते थे ।

प्रो० कीम ने व्याज की दर के महत्व को अस्वीकार करत हुए कहा था कि पूँजी की सीमान्त क्षमता का महत्व हमारे जैम प्रार्वगिर गमाज में है जवकि व्याज की दर की धारणा स्थिर समाज के लिए महत्वपूर्ण है । कीम ने इन प्रकार में मोचने का कोई औचित्य नही है । इग मान्यता के मानन का जय यह होगा कि साहमी वेचन भावी प्रत्याशाओं (Expectations) द्वारा ही प्रभावित होते हैं जवकि शृण पूति करने वाला वगं ऐसी प्रत्याशाओं द्वारा प्रभावित नही होना । कीम ने इससे लिए कुछ नही कहा है ।

### परीक्षा प्रश्न

1. पूँजी की सीमान्त क्षमता का क्या अर्थ है ? रोजगार के सिद्धान्त में इग विचार की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

(What is meant by marginal efficiency of capital? Examine the role of this concept in the theory of Employment)

2. उन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तत्वों की व्याख्या कीजिए जो विनियोग की सीमान्त क्षमता अथवा पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करते हैं ।

(Explain the short-run and long-run factors which affect the marginal efficiency of investment or the marginal efficiency of capital)

3. विनियोग माँग अनुसूची से आप क्या समझते हैं ? पूँजी की सीमान्त क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए ।

(What do you understand by Investment Demand Schedule? Discuss the factors that influence the marginal efficiency of capital)

में इस तरह का 1/2 (1/2 गुणक) बढ़ अनुपात है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और निरियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप महत्त्व को बताता है जिसमें आय में वृद्धि होती है।

रोजगारण रीय भावा में निरियोग  $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I} k = \text{गुणक}$

$\Delta Y$  राष्ट्रीय में वृद्धि  $\Delta I = \text{निरियोग में वृद्धि}$ ।

उसी बात को रोजगारण रीय भावा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में निरियोग 10 करोड़ रुपय में किए जाएं और उसमें राष्ट्रीय आय 50 करोड़ रुपय की

वृद्धि हो तो गुणक  $50/10 = 5$  होगा। गुणक का मूल्य 5 गुना होगा अर्थात्  $k = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$

or  $k = \frac{50}{10} = 5$ । गुणक का मूल्य सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमान्त

उपभोग प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume or MPS) का आधार पर गुणक को प्राप्त कर सकते हैं।

प्रो० वीन्स के बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने गुणक को अपने अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। इनमें प्रो० फ्रिट्ज मॅकलूप, गार्डनर एक्ले रिचार्ड गूडविन तथा जी० एच० एम० शैलर (Prof Fritz Machlup, Gardner Ackley Richard Goodwin and Prof G. L. S. Shale) आदि विद्वानों ने अपने अर्थशास्त्रियों द्वारा गुणक विज्ञान में महत्त्वपूर्ण अनेक विचारधाराएँ महत्त्वपूर्ण का अध्ययन किया।

प्रो० वाहन की धारणा - प्रो० वाहन ने रोजगार गुणक का विचार दिया अर्थात् उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि निरियोग में वृद्धि होने से रोजगार में कितनी गुना वृद्धि होती है। प्रो० वाहन ने रोजगार गुणक का विचार प्रो० वीन्स के आय गुणक का विचार प्राप्त किया अर्थात् प्रारम्भिक निरियोग में आय में कितनी गुना वृद्धि होती है। प्रो० वीन्स ने General Theory में निरियोग गुणक को  $k$  का नाम दिया है और इसको परिभाषित करते हुए कहा है "गुणक हमको बताता है कि जब कुल निरियोग की मात्रा में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय में वृद्धि होती है जो कुल निरियोग में हुई वृद्धि का  $k$  गुना होती है।" प्रो० वाहन ने रोजगार गुणक को  $k'$  द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि निरियोग में  $\Delta I$  का मात्रा में वृद्धि होती है और उससे परिणामस्वरूप निरियोग उपयोग में प्रारम्भिक रोजगार की मात्रा में  $\Delta N_1$  की वृद्धि होती है तो कुल रोजगार की मात्रा में होने वाली वृद्धि  $\Delta N$  प्रारम्भिक रोजगार की मात्रा में हुई वृद्धि  $\Delta N_1$  का  $k$  गुना होगी अर्थात्  $\Delta N = k' \Delta N_1$ ।

$K$  तथा  $K'$  के मध्य परस्पर समानता होना जरूरी नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि निरियोग में कुल पूंजी बंधों के बाल इस प्रकार के होंगे कि रोजगार वृद्धि तथा माँग वृद्धि के मध्य निरियोगों के समान अनुपात होगा। निरियोग गुणक, जो निरियोग में हुए आरम्भिक परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप आय में हुए कुल परिवर्तन का

1. Let us call  $k$  the investment multiplier. It tells us that when there is increment of aggregate investment, income will increase by an amount which is  $k$  times of the increment of investment."

"General Theory" p. 115.

--- Keynes

अनुपात है अर्थात्  $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$ , सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) से इस प्रकार से सम्बन्धित

होता है कि MPC जितनी अधिक ऊँची होगी गुणक  $k$  उतना ही अधिक उँचा तथा इसके विपरीत MPC कम होने पर गुणक भी कम होगा।

**गुणक (Multiplier)**

गुणक प्रत्यक्ष रूप से सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) द्वारा निर्धारित होता है। सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति का उच्चोत्तम मूल्य होने पर गुणक का उच्चोत्तम मूल्य को बैज-गणितीय भाषा में निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं—

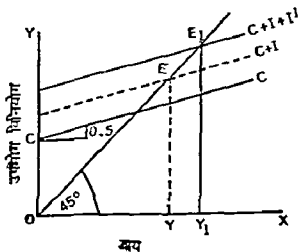
$$k = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} \quad \text{अथवा} \quad \frac{1}{1 - MPC}$$

चूँकि  $\frac{\Delta C}{\Delta Y} \approx MPC$

उपर्युक्त समीकरण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुणक का उच्चोत्तम मूल्य एक से अधिक MPC के उच्चोत्तम मूल्य घटाने के बाद प्राप्त शेषक का उल्टा होता है उदाहरणार्थ यदि

MPC 0.8 है तो गुणक का उच्चोत्तम मूल्य  $\frac{1}{1-0.8}$  अथवा  $\frac{1}{2} = 5$  होगा।

गुणक का आकार सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) द्वारा परिवर्तित होता रहता है। जितनी सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति उँची होगी गुणक उतना ही अधिक होगा। इसके गुणक का हम निम्न ग्राफिक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं—



इसके विपरीत MPC जितनी नीची होगी गुणक उतना ही कम होगा। निश्चय ही एक से अधिक (Infinite) कम हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि में गुणक का





उपभोग अधःपतन ग हम हम निष्पत्ति पर पहुँचने है कि गुणक का अक्षीय मूल्य

$1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}$  का अक्षीय मूल्य का उल्टा होता है। निम्नलिखित समीकरणों द्वारा यह सिद्ध

किया जा सकता है कि कुल वास्तविक आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल निवेश व्यय का योग होती है।

$$Y = C + I \quad \dots(1)$$

उपभोग तथा भीमान्त उपभोग प्रवृत्ति बताती है कि कुल उपभोग तथा कुल आय के मध्य स्थिर सम्बन्ध होता है विशेषतः पर अल्पकालिक स्थितियों में। यह सम्बन्ध धनात्मक होता है अर्थात् आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है परन्तु यह इकाई से कम होता है अर्थात् जितनी मात्रा में आय बढ़ती है उतनी मात्रा में उपभोग नहीं बढ़ता उदाहरणार्थ यदि आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय 100 रुपये से कम होगा। MPC का C द्वारा व्यक्त करने पर कुल उपभोग तथा कुल आय द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

$$C = CY \quad \dots (2)$$

समीकरण (1) में C के स्थान पर CY स्थान पर एक नया समीकरण बतला है जो समीकरण नम्बर 3 कहलाता है—

$$Y = CY + I \quad (3)$$

$$Y - CY = I$$

$$Y(1 - C) = I$$

$$Y = \frac{I}{1 - C}$$

इसमें C का अक्षीय मूल्य एक ग कम तथा शून्य से अधिक है।

अब हम यह मान लें कि कुल निवेश में  $\Delta I$  की वृद्धि होती है तो इसके फलस्वरूप कुल आय में समान मात्रा में वृद्धि हो जायेगी क्योंकि कुल निवेश आय के दो अर्थों में से एक है। इस नई कुल आय को हम  $Y_1$  द्वारा व्यक्त कर सकते हैं इसके लिए निम्न-लिखित समीकरण होगा—

$$Y_1 = CY_1 + I + \Delta I \quad \dots(4)$$

$$= \frac{I + \Delta I}{1 - C} \quad \dots(5)$$

यह ज्ञात करने के लिए कि कुल निवेश में  $\Delta I$  राशि की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अव्यवस्था में कुल आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है हमको नई (अधिक) आय में से पुरानी (कम) आय को घटाना होगा। इसके लिए हम निम्न समीकरण द्वारा दिखाना सकते हैं—

$$Y_1 - Y = \Delta Y = \frac{I + \Delta I}{1 - C} - \frac{I}{1 - C} \quad \dots(6)$$

$$\Delta Y = \frac{I + \Delta I - I}{1 - C} \quad (7)$$

$$= \frac{\Delta I}{1 - C} = \Delta I \cdot \frac{1}{1 - C} \quad (8)$$

उपर्युक्त समीकरणों में यह मिद्द होता है कि कुल आय में हुई कुल वृद्धि ( $\Delta Y$ )

कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि ( $\Delta I$ ) का  $\frac{1}{1 - C}$  गुना होती है परन्तु  $\frac{1}{1 - C}$

गुणक ( $k$ ) है। इस प्रकार कुल आय में हुई वृद्धि कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि का गुणक गुना होती है अर्थात्  $\Delta Y = \Delta I k$

$$= \frac{\Delta Y}{\Delta I} = k$$

उपर्युक्त निष्कर्षों के सम्बन्ध में केवल एक ही मान्यता है और वह यह कि उपभोग ( $C$ ) अथवा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का अन्वेष मूल्य घनात्मक तथा इकाई में कम (एक से कम) होता है।

### गुणक क्रिया (Multiplier Function)

कुल आय में वृद्धि जो कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि का गुणक गुना होती है हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके लिए हम गुणक को दो प्रकार में व्यक्त करते हैं।

(1) एककालिक गुणक (Simultaneous Multiplier)

(2) अवधि गुणक (Period Multiplier)

(1) एककालिक गुणक (Simultaneous Multiplier)—एककालिक गुणक की व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि कुल निवेश, कुल उपभोग तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल आय तथा कुल निवेश में एक ही काल में परिवर्तन होते हैं। कुल आय = कुल उपभोग + कुल निवेश होता है अर्थात्

$$Y = C + I$$

वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश बराबर होते हैं और इस कारण कुल निवेश में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कुल वास्तविक बचत में भी वृद्धि होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में कुल बचत राशि कुल आय राशि तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS) द्वारा निर्धारित होती है। इस कारण अधिक वास्तविक बचत राशि को प्राप्त करने के लिए कुल वास्तविक आय में इतनी वृद्धि होना अनिवार्य है कि सीमान्त बचत प्रवृत्ति के स्थिर रहते हुए कुल बचत में कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि ( $\Delta I$ ) के समान मात्रा में वृद्धि हो सके। इसी बात को एक उदाहरण देकर समझाया जा सकता है माना कि सीमान्त बचत प्रवृत्ति 0.25 है अर्थात् सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.75 है। यदि कुल निवेश में एक करोड़ रुपये की वृद्धि होती है तो समस्त आय में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी क्योंकि

$$k = \frac{1}{1 - MPC} \text{ or } \frac{1}{MPS} \quad k = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ गुना अर्थात् 4 करोड़ (MPS द्वारा)}$$

$$\text{अवधि } k = \frac{1}{1 - MPC} = \frac{1}{1 - 75} = \frac{1}{25} = 4 \text{ गुना अर्थात् 4 करोड़ रुपय।}$$

आय इससे कम वृद्धि होने पर समस्त बचत मात्रा में एक करोड़ रुपय की वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार यदि MPC अथवा MPS किसी एक अवधि में ज्ञात है तो सन्तुलन आय का ज्ञात किया जा सकता है जो कुल निवेश में किसी दी हुई राशि की वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त होगी।

### एककालिक गुणक सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticism of Simultaneous Multiplier Principle)

एककालिक गुणक सिद्धान्त की व्याख्या भी अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांतों की तरह आलोचनाओं में मुक्त नहीं है। इस विश्लेषण की आलोचनाएँ निम्न तथ्यों के आधार पर की जाती हैं—

(1) आलोचना का कहना है कि कुल निवेश तथा कुल उपभोग में एक साथ परिवर्तन नहीं होता। धारणाबद्धता यह है कि जब कुल निवेश में वृद्धि होती है तो इससे लोगों की कुल आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने में थोड़ा समयान्तर देखा जा मिलता है। यदि हम यह मान भी लें कि दानों में अर्थात् निवेश तथा उपभोग में समान्तर नहीं है तो भी उपभोग वस्तु उद्योग का विकास एक साथ सम्भव नहीं होता अर्थात् आय में साथ वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि में थोड़ा समय लगता है।

(2) एककालिक विश्लेषण स्थिर विश्लेषण है क्योंकि यह उस भण के अध्ययन नहीं करता जिससे एक से तुलन आय दूसरी सन्तुलन आय को प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में प्रो० हबर्नर (Prof Haberler) का कहना है कि प्रो० कीन्स का गुणक सिद्धान्त सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का दूसरा नाम मात्र है और कुछ नहीं। इसी प्रकार प्रो० हाट (Prof Hoot) ने कीन्स के गुणक के विचार को गाड़ी के पाँचवें पहिए की संज्ञा दी है अर्थात् इसे अनावश्यक बताया है।

II अवधि गुणक (Period Multiplier)—अवधि गुणक का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि कुल निवेश में वृद्धि द्वारा कुल आय तथा कुल उपभोग वृद्धि होनी तो अवश्य है परन्तु इसमें कुछ समय लगता है। इसी बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी दी हुई समयावधि (t) में होने वाला उपभोग व्यय (Ct) अन्य बातें समान रहने पर पूर्ववर्ती समयावधि (t-1) में प्राप्त आय Y<sub>t-1</sub> द्वारा निर्धारित होता है अर्थात्

$$C_t = f(Y_{t-1})$$

किसी प्रथम समयावधि की कुल आय दूसरी समयावधि में कुल उपभोग को निर्धारित करती है। अवधि गुणक निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है जैसे—

- (1) कुल निवेश में वेश्य एक बार वृद्धि होती है।
- (2) कुल निवेश में जो आरम्भिक वृद्धि होती है वह आन वारों (पश्चात्वर्ती) समयावधियों में निरन्तर होती रहती है।
- (3) कुल निवेश में जो वृद्धि होती है वह कुल निवेश के उस भाग से सम्बन्धित है जिसे स्वाभाविक निवेश कहते हैं।

प्रथम स्थिति जिसमें कुल निवेश में केवल एक बार अथवा एक समयावधि में वृद्धि होती है। यह वृद्धि आरम्भिक समयावधि 1 के लेनर अर्द्धिम समयावधि 1 तक अनन्त

समयावधियों में होगी। कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि तथा गुणक के गुणनफल के बराबर होगी। दूसरी स्थिति का आशय यह है कि समयावधि  $t$  में सन्तुलन आय निवेश में वृद्धि होने के पूर्व समयावधि में आय के स्तर का प्राप्त हो जायेगी। इसी बात को हम एक उदाहरण एवं तालिका द्वारा दिखा सकते हैं। माना कि किसी समय सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.75 है और आरम्भिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो गुणक 4 होने पर  $t$  समयावधि बाद कुल आय में 400 रुपए की राशि की वृद्धि हो जायेगी।

### तालिका

आरम्भिक निवेश वृद्धि का उपभोग तथा आय पर प्रभाव

(करोड़ रुपए में)

| समयावधि | कुल निवेश में हुई आरम्भिक वृद्धि | कुल उपभोग में हुई वृद्धि<br>$\Delta C = 0.75 \Delta Y$ | प्रत्येक अवधि में कुल आय ( $\Delta Y$ ) में वृद्धि | कुल आय में हुई मधीय वृद्धि |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 100 करोड़ रुपए                   | 0                                                      | 100                                                | 100                        |
| 2       | , ,                              | 75                                                     | 75                                                 | 175                        |
| 3       | , ,                              | 56.25                                                  | 56.25                                              | 231.25                     |
| 4       | , ,                              | 42.19                                                  | 42.19                                              | 273.44                     |
| 5       | , ,                              | 31.65                                                  | 31.65                                              | 305.09                     |
| 6       | , ,                              | 23.73                                                  | 23.73                                              | 328.82                     |
| 7       | , ,                              | 17.79                                                  | 17.19                                              | 346.61                     |

उपरोक्त तालिका वर्णित स्थिति में यह मान्यता मानी गई है कि कुल निवेश में आरम्भिक वृद्धि केवल एक बार आरम्भिक अवधि में होती है तथा उसको पश्चात्तों अवधियों में दुहराया नहीं जाता। परन्तु यदि स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) समयावधि  $t$   $\Delta I$  राशि की वृद्धि जारी रखी जाए तो अन्त में  $t$  समयावधि में समस्त आय में निवेश में हुई वृद्धि के गुणक  $(k)$  गुना वृद्धि होगी। विभिन्न अवधियों में आय वृद्धि की प्रक्रिया उस समय तक विद्यमान रहेगी जब तक  $t$  समयावधि के अन्त में कुल वृद्धि होती है वह निवेश वृद्धि गुणक के समान ( $100 \times 4 = 400$  करोड़ रुपए) होगी।

एकत्रासिक तथा अवधि गुणक में अवधि गुणक महत्वपूर्ण विचारा जाता है क्योंकि यह हमारा ध्यान निवेश तथा उपभोग के मध्य उपस्थित उस परस्पर सम्बन्ध की ओर केन्द्रित करता है जो अर्थव्यवस्था में अनेक व्यक्तियों के व्यवहार तथा निर्णयों का परिणाम होता है। यह हम उन शक्तियों के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्रदान कराता है जो निवेश ध्यय में वृद्धि होने के समय अर्थव्यवस्था में मध्यम रूप में उपस्थित रहती है।

गुणक में सामयिक परिवर्तन—गुणक में होने वाले परिवर्तन सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) में परिवर्तनों से सम्बन्धित होते हैं। दीर्घकाल में उपभोग तथा आय के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है जबकि अल्पकाल में ऐसा नहीं होता है। व्यापार चक्र काल में कुल आय में वृद्धि तथा गिरावट के माध्य उपभोग में समानुपात में वृद्धि तथा गिरावट न होने के कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) में भी परिवर्तन होते रहते हैं। व्यापार चक्र की चेतना तथा अभिवृद्धि की अवस्थाओं में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति में गिरावट होने के कारण गुणक में भी गिरावट आ जाती है। सन्तुलन की अवस्था में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती

हुई होने व कारण गुणक में भी वृद्धि हो जाती है तथा आरम्भिक मदी प्रचण्ड मन्ने का सा कारण बर लेती है।

**गुणक के प्रभाव में क्षति (Leakages in Multiplier Effect)**

अभी तक हमने देखा कि जब समुदाय को नई आय प्राप्त होता है वह सारा की मारी उपभोग काय के लिए व्यय नहीं की जाती है। उसका एक भाग बचा लिया जाता है अर्थात् उपभोग नहीं किया जाता है इसी को क्षति (Leakage) की संज्ञा दी जाती है। इस क्षति का प्रभाव यह होता है कि यह राष्ट्रीय आय में हानि बानी वृद्धि का सम्भित करता है। यदि सम्पूर्ण आय जो अर्जित की जाती है उसका उपभोग बर लिया जाय अथवा सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) इकाई के बराबर है तो निवेश में थोड़ी मात्रा में वृद्धि पूरा रोजगार तान में संपन्न हो जाती है और जगक बाद स्तैतित स्थितियाँ उत्पन्न हो जायेंगी। व्ययहारक रूप में यह देखा जाता है कि समस्त आय उपभोग नहीं की जाती अर्थात् MPC इकाई से कम होता है जिन्हे परिणामस्वरूप प्रारम्भिक निवेश से हानि बाना आय व वृद्धि लगातार गिरती जाती है और अंत में कुल आय में वृद्धि की दर सीमित हो रहती है। गुणक का क्षति निम्न रूप में देखा जा सकता है

(i) आयात तथा निर्यात (Import and Export)—आयात अधिक करने से गुणक में कमी आता है जब कि निर्यात अधिक होने से गुणक में वृद्धि होती है। ऐसा प्रायः अल्पकाल में होता है। दाखकाल में ऐसा होता है कि आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातक देश की आय बढ जाती है और उस बढी हुई आय का उपयोग धारे घीरे आयात करने वाले देश का वस्तुओं की माँग बढाता है और जिसका आयात करने वाले देश की आय पर अनुकूल प्रभाव पडता है। परन्तु इसका प्रभाव तब सीमित हो जाएगा जबकि निर्यातक देश अपने यहाँ विदेश से होने वाले आयात को सीमित कर दे या उस पर सखत लगा दे।

(ii) कीमत स्फीति (Price Inflation)—जब समय तक देश में उत्पादक साधन बेरजगार रहेंगे उस समय तक निम्नगोम जो भी वृद्धि होगी उससे अथव्यवस्था का विस्तार होगा और यह प्रवृत्ति उस समय तक लागू रहेगी जब तक पूरा रोजगार का बिन्दु प्राप्त नहीं कर लिया जाता। जैसे ही पूरा रोजगार का बिन्दु या उसके निकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बैंग हो नये निवेशों की कीमत बढेगा साथ ही उत्पादक साधनों का लागू भी बढ जायेगा क्योंकि उत्पादक के साधनों का कमी आ जाएगा अथवा उपलब्ध नए हाथ और उपभोक्ता तथा विनियोग उद्योग दोनों में ही इन साधनों की माँग बढेगी और उनका कीमत बढेगी। इस प्रकार बढी हुई आय का एक भाग उपभोग आय तथा रोजगार बन्धन व स्थान पर कीमती को बढाने में व्यय हो जायगा। इस प्रकार कीमत स्फीति का प्रभाव बढा रहेगा। एसी स्थिति में गुणक गिरावट क्योंकि कीमती में वृद्धि वास्तविक कुल उपभोग को बढाने नहीं दा।

(iii) पुराने ऋणों की अदाएगी (Payment of Old Loans)—कभी-कभी एसा देखा जाता है कि उपभोक्ता का नई आय प्राप्त होता है उसका एक हिस्सा वह बैंग या व्यक्तित्व परमों से लिए गए पुराने ऋणों का चुकाने में चला जाता है और उपभोग की स्थिति में गिरावट आने से गुणक में भी गिरावट आता है।

(iv) सीमांत बचत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Saving)—सामान्य बचत प्रवृत्ति ऊँची हानि पर गुणक में गिरावट आती है। ऐसा प्रायः उस समय दम्नत का मिलता है जब लागू में लगनना पसन्दगी ऊँचा होती है और लोग नवद बाया का अपन पाग रखना अधिक अच्छा समझना दा।

(v) वित्तीय विनियोग (Financial Investment)—जब नई आय का उपभोग उपभोक्ता वस्तुओं पर न करके प्रतिभूतियों तथा वाण्डों (Securities and Bonds) पर अपवा पुराने स्टॉक को खरीदने में व्यय किया जाता है तो इससे उपभोग के स्तर में गिरावट आती है और गुणक भी गिरता है।

### गुणक की आलोचना (Criticism of Multiplier)

गुणक सिद्धान्त की विशेष तौर पर प्रो० कीन्स के गुणक विचार की विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। प्रो० हैबरलर (Prof. Haberler) ने अपने एक लेख 'Mr Keynes Theory of Multiplier : A Methodological Criticism' (1936 में प्रकाशित) कीन्स के गुणक सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पूर्ण घोषित मृत्यु की परिभाषा करना है। यह (गुणक) एक सन्तुलन में दूसरे सन्तुलन अथवा इन दोनों के बीच सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) की व्याख्या नहीं करता यह तोप हले कही हुई बातों का कथन मात्र है। यदि गुणक के विचार को एक विशेष समय में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाय तो यह सम्भव होना चाहिए कि विभिन्न समयों में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति या सीमान्त बचत प्रवृत्ति के स्वभाव से सम्बन्धित उचित परिकल्पनाएँ मानी जाएँ, यदि ऐसा नहीं है तो गुणक का कोई महत्व नहीं होगा। गुणक कोई स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। गुणक के मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यह देखना होगा कि कुल कितनी आय गुणक द्वारा सृजित की गई है तब हमें इस विविध से भाग देना होगा। प्रो० हैबरलर कहते हैं कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि विनियोग में वृद्धि ( $\Delta I$ ) इतनी गुना गुणक है जो कुल आय में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि

$$\Delta I \times \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \Delta Y$$

कीन्स के गुणक विचार को पूर्ववर्ती कथन की आलोचना से यदि

हमें मुक्त करना है तो हम अल्पकाल में सीमान्त उपभोग तथा सीमान्त बचत प्रवृत्तियों के सामान्य व्यवहार की व्याख्या करनी होगी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रो० ए० जी० हार्ट (Prof. A. G. Hart) ने कीन्स के गुणक विचार को गड़ों के पाँचवे पहिये की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त प्रो० हेनरी हैजलिट (Prof. Henry Hazlitt) का कहना है कि यह कीन्सवादी प्रणाली का ऐसा विचित्र विचार है जिसकी कीन्स समर्थकों द्वारा बहुत घटा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है जो एक कोरी कल्पना है। ऐसा कोई कारण नहीं है जो यह सोचने पर मजबूर करे कि गुणक नाम की भी कोई चीज है। वे कहते हैं कि सामाजिक आय, उपभोग, विनियोग तथा रोजगार की मात्रा के बीच न तो कोई संक्षिप्त, पूर्व निर्धारित और स्वचालिक सम्बन्ध होता है। वे आगे बढ़ते हैं कि गुणक का विचार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होने की कल्पना करता है। वे कहते हैं कि कीन्स का यह सोचना कि बेरोजगारी एक सामान्य घटना है और पूर्ण रोजगार एक विशेष घटना है, भ्रामक विचार है। कीन्स की गुणक सम्बन्धी यह भी मान्यता श्रुतिपूर्ण है कि समुदाय की आय को एक भाग का उपभोग नहीं किया जाता और उसका संचित कर लिया जाता है और इसके किसी भाग का विनियोग नहीं किया जाता। परन्तु उनका यह विचार पहले बड़े हुए बचत के इस विचार से भिन्न नहीं था कि बचत एवं विनियोग बराबर ही नहीं होते बल्कि समरूप (Identical) होते हैं। बचत एवं विनियोग तभी समान हो सकते हैं जबकि उपभोग पर न खर्च किया हुआ धन विनियोजित कर दिया जाए। वे कहते हैं कि गुणक का विचार बचत तथा विनियोग की असमानता सम्बन्धी समस्या की ओर संकेत करता है।

किया जा रहा। गुणव अर्नेच्छित्त बेराजगारी की मान्यता मानकर वतत है अर्थात् मजदूरा या वायगान जनसंख्या का प्रचलित मजदूरा की दरा पर काय उपबन्ध नहीं हाता। अर्नेच्छित्त बेराजगारी न हान पर विनियोग ने वृद्धि करन से राजगार उत्पादन तथा आय बढन की सम्भावनाए जाती रहती ह। यदि अर्नेच्छित्त बेराजगारी व्याप्त है ता थोडी-सी धनगणि का विनियोग करन से वस्तुआ तथा सेवाअ या माँग बढती ह पतम्बरूप राजगार का स्तर भी बढना है।

एक अर्द्ध विकसित दश म अर्नेच्छित्त बेराजगारी बहुत धाढा मात्रा म पायी जाती है। जा भी बेराजगारी पायी जाती है वह छिपी हुई बेराजगारी (Disguised Unemployment) होती है। अधिकतर गाँव या तो लेती व काय म या फिर घरनू उद्यागा या कार्या म लग रहते हैं आर इनकी गन्या इन कार्यों म इनकी माँग से अर्जित है। उह इन काया म जो कुछ बतन या मजदूरी व रूप म गन हाती है वह उर गनी ह। गन्तुष्टि प्रदाय करता है जितना भि उह प्रचलित मजदूरी प्राप्त होती। अधिक मजदूरी का प्रयोभन ही उह बतमा काय म निमुक्त कर गवता है दूसर शब्दा म हम कह सक्त ह कि प्रचलित मजदूरी पर अनिश्चित श्रम की पूर्ति हा हाता है। इस प्रकार अर्द्ध विकसित दश म अर्थ हारिक स्थिति यह है कि अर्नेच्छित्त बेराजगारी की उपस्थि न हान व कारण गुणव अधिक गभावी नहीं हाता। भारत जैसे दश म मधुक्त परिवार प्रणा की तथा अल्प बेराजगारी तथा मौसमी बेराजगार आदि व कारण भी गुणव हा महत्व अर्जित हा है। दूसर अर्थात् गुणव मिद्वान्त ता एक अर्थ मान्यता है कि उता वन अच्छा मात्रा म तातपूण हाता है। अर्द्ध विकसित दश म विकसित दशा का अपन्था उत्पादन म तावता रहा पायी जाती। अर्द्ध विकसित दशा म कुन उत्पादन का एक उडा भाग कृषि क्षेत्र म प्राप्त हाता है और कृषि क्षेत्र म उत्पादन तुनात्मक दुष्टि म बतनाददा हाता है। दाना हा नी आद्याभित क्षेत्र म कुञ्जत मादूरा पूजा मय प्रा ता ता अर्थ पूरक कारण र द्वारा उत्पादन म बतनावता दिग्गार्ई दी है। अर्द्ध विकसित दशा म धमशक्ति की बहुवता का उपयोग उत्पादन ता बढान म उपयुक्त कारण व द्वारा सीमित हाता है और गुणव का प्रभाव सीद्रिय अर्थ व क्षेत्र म दिग्गार्ई हाता है वास्तवतः जाय और राजगार र अर्थ नहीं। दाना तुना म एक विकसित दश म उत्पादा तातपूण हाता है। म दीवान म श्रम क्षय म बेराजगार ही नहा दिग्गार्ई दना परत जाय पूरक माधता की भी अभी रहता है। एमी दाना म माँग म थोडी वृद्धि हान म (अनिश्चित विनियोग व कारण) उत्पादा की मागा बढना है जाय आय म वृद्धि वास्तविक आय म वृद्धि करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पूण राजगार की आर उन्मुक्त हाता है वास्तवतः आय और मा दक जाय म अन्तर रहता जाता है जैसे हा पूण राजगार का मिडु का प्राप्ति हा जाती है गुणव प्रभाव की विवति विकसित दशा म भी अर्द्ध-विकसित दश की तरह हा जाती है।

निष्कर्ष - गुणव मिद्वान्त महत्वपूण ह। विश्वव्यापी तागा की मन्दा र समय सावजनिक निमाण कार्यों व पक्ष म प्रस्तुत ता गुणव पर आधारित थ। मा 1934 ई० म अमरीका म राष्ट्रीय रूजवन्त नन्दुीत याजा की घोषणा थी थी वह ती गुणव पर आधारित थी। उग समय 300 मिनिटो डातर राशि व प्रति माह व्यय करन म गुणव राष्ट्रीय आय म चार गुना वृद्धि गुणव प्रभाव व कारण हा दखन ता मिती थी।

गुणव का व्यवहारक मन्दा भा हाता है। गुणव हमारा ध्यात म्य जाय आवर्गित करता है कि विवश म हा हुई आरम्भिक वृद्धि कुन आय र कुन निवश की तुना म अर्पक हाती है। गुणव व प्रभाव र कारण अर्थव्यवस्था म आर्थिक नीतिया व निमाणाआ का कार्यों महत्त्वता मित्रती है। गुणव उन्तर त्रिण मागदणर र रूप म काय करता है। मदी व समय अर्थव्यवस्था का उन्नत उत्पादन म मदद मित्रती है। म दी म निवश गणि म वृद्धि करता अर्थव्यवस्था व त्रिण लाभदायक हाता है।



गुणक सिद्धान्त का प्रमुख दाव यह है कि यह स्थिर सामान्य उपभोग प्रवृत्ति का माप्यता पर आधारित है। इसका अर्थात् गुणक प्रेरित निवेश का ओर ध्यान नहीं देता। गुणक सिद्धान्त स्यासत निवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप केवल उपभोग व्यय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तविकता यह है कि उपभोग व्यय में वृद्धि का परिणामस्वरूप प्रेरित निवेश में जो वृद्धि होता है उसकी उपेक्षा करता है। गुण माप्यता गुणक सिद्धान्त का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व होता है। अर्थ सिद्धान्त की भाँति यह विचार भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है।

### परीक्षा प्रश्न

1. गुणक से आप क्या समझते हैं? इसकी आलोचनाओं का बतलाए।  
(What do you understand by Multiplier / Discuss its criticisms)
2. आर्थिक विश्लेषण तथा आर्थिक नीति में गुणक का महत्व को स्पष्ट कीजिए।  
(Explain the importance of Multiplier in economic analysis and economic policy)
3. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कीन्त गुणक एक अर्द्ध विकसित अथ व्यवस्था का देश में लागू नहीं होता।  
(Do you agree with this view that Keynes's Multiplier does not operate in an under developed economy?)

### 4. टिप्पणी लिखिए—

- (i) एकाधिक तथा अवधि गुणक
- (ii) गुणक के प्रभाव में क्षति

Write notes on

- (i) Simultaneous and Period Multiplier
- (ii) Leakages in Multiplier Effect

### 5. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही और कौन गलत है।

- (i) गुणक वह अनुपात है जो विनियोग में परिवर्तन द्वारा आय में परिवर्तन का बताता है।
- (ii) गुणक का अवधीय मूल्य एक में से MPC का अन्वय मूल्य घटाने से प्राप्त होता है।
- (iii) गुणक का MPC तथा MPS दोनों का द्वारा मान किया जा सकता है।
- (iv) गुणक अर्द्ध विकसित देश में पूर्णरूप से लागू होता है।

### वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) गलत है। (iii) गलत है। (iv) गलत है।

any increase in final demand will give rise to an additional demand for capital goods several times larger than that new final demand

—F A Von Hayek

The acceleration principle serves as useful tool for business cycle analysis and as a helpful guide to business cycle policy

—Kishara

## अध्याय 11

### त्वरक

(ACCELERATOR)

त्वरक का विषय मत्त चर्चा हाना कि कीम स पहन तथा वाढ म काफा हा गइ है परन्तु की म न अपना पुस्तक General Theory म त्वरक सिद्धान्त का यदाकदा चर्चा की है। सबसे पहल त्वरक सिद्धांत की व्याख्या का सम्बन्ध प्रो० ज० एम० क्लार्क (Prof J M Clark)<sup>1</sup> से जाड़ा जाता है प्रो० क्लार्क ने ही त्वरक विचार का महत्व दिया। अथवा स्त्रिया की रचि इस सिद्धांत म आर तब जागृत हुई जब उह यह ज्ञात हुआ कि त्वरक सिद्धान्त का कीम व उपभाग श्रिया के माथ अध्ययन करन पर यह सिद्धांत एक स्व जनित चत्रीय प्रक्रिया के घटित हान का व्याख्या कर सकता है। प्रो० क्लार्क के बाद त्वरक सिद्धांत को विकसित और परिष्कृत करन म कुछ अध्यापिका व नाम विशेष रूप से उल्लेखनाय है जैसे हेराल्ड हिम्स ह्यक हैसन हेबरनर गुडविन कुजनटम किन्का कालडार फिश फननर मेथ्यूज रावटमन तथा संम्युसन आदि।

#### त्वरक का अर्थ (Meaning of Accelerator)

गुणक स्वायत्त निवेश म हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभाग व्यय म वृद्धि के माध्यम द्वारा समस्त आय म हुई वृद्धि का तर्जन करता है जबकि त्वरक सिद्धांत कुन उप भाग म वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल निवेश म हान वाता वृद्धि की व्याख्या करता है। इससे यह स्पष्ट हाता है कि स्वायत्त निवेश म आरम्भिक वृद्धि हान म समस्त आय म हुई कुन वृद्धि का ज्ञात करन के लिए गुणक तथा त्वरक के सम्मिलित प्रभाव का ज्ञात करन आवश्यक है क्यकि आय म हुई वृद्धि गुणक व त्वरक का सम्मिलित परिणाम हाता है।

- 1 जोन मैरिस क्लार्क ने सन् 1917 म Journal of Political Economy नामक पत्रिका म अपन तर्ज द्वारा व्यापार चक्र का सम्बन्धिता के रूप म त्वरक सिद्धान्त का विश्लेषण किया था। सन् 1934 म प्रो० फननर फिश ने अपन एक तर्ज म त्वरक का सम्भावना पर प्रकाश डाला। प्रो० हिम्स ने व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की मयुक्त प्रामाणा का ज्ञान बनाने के लिये सिद्धान्त के विषय म महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस दोता के अध्ययन को एक साथ करने का सारभ यह है कि हम यह मानूँ माना है कि स्वायत्त निवेश म हुई आरम्भिक वृद्धि अथवा कमी हान व प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दाना प्रभाव होने हैं ।

स्वरक सिद्धान्त निवेश पर कुल उपभोग व्यय म इस परिवर्तना के प्रभाव को व्याख्या करता है। स्वरक प्रेरित तथा उपभोग निवेश की व्याख्या करता है तथा बताता है कि वह निवेश जिनके परिणामस्वरूप गुणक क्रियाशील होता है स्वायत्त अथवा उपभोग निर्धारक निवेश होता है । स्वरक तथा गुणक की सम्मिलित क्रियाओं का हम निम्न रूप म समझा सकते हैं—

स्वायत्त निवेश म → कुल आय म → कुल उपभोग म → प्रेरित निवेश म  
 वृद्धि  $\Delta I_a$       वृद्धि  $\Delta Y$       वृद्धि  $\Delta C$       वृद्धि  $\Delta I_p$

स्वरक सिद्धान्त बताता है कि अर्थव्यवस्था म कुल निवेश का वह भाग व्ययित प्रेरित निवेश उपभोग वस्तुओं की माँग में होने वाले परिवर्तन का बताता है । प्रो० वान हेयक ने स्वरक की व्याख्या इस प्रकार की है साधारणतया किसी दी हुई अन्तर्वर्धि में उपभोग वस्तुओं की किसी दी हुई मात्रा का उत्पादन करने के लिए कई गुना अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ने के कारण उपभोग वस्तुओं की माँग में किसी दी हुई मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूँजी वस्तुओं की माँग में कई उपभोग माँग की तुलना म कई गुना वृद्धि होगी ।<sup>1</sup>

स्वरक तथा गुणक में अन्तर

जैसा कि हम जानते हैं गुणक विनियोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आय तथा रोजगार की मात्रा म होने वाले परिवर्तन को बताता है जबकि स्वरक उपभोग में परिवर्तन द्वारा विनियोग पर पड़ने वाले प्रभाव को व्याख्या करता है । गुणक मौलिक उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है जबकि स्वरक मशीनों तथा औजारों के विकास पर निर्भर करता है । हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणक मनीषणनिक तत्व पर तथा स्वरक तकनीकी तत्वों पर निर्भर करता है । वास्तव में देखा जाय तो यह अन्तर कबन मौलिक प्रतीत होता है । स्वरक भी अपने मौलिक और आन्तरिक रूप में मनीषणनिक है परन्तु इस क्रियाशीलता का पक्ष इसे अधिक तकनीकी स्वरूप प्रदान कर देता है । स्वरक के द्वारा हम निवेश पर उपभोग के विकास की गति को दिखाते हैं जबकि गुणक बड़े हुए निवेश के प्रति उपभोग की प्रतिक्रिया को बताता है । इन प्रकार गुणक और स्वरक दाना ही विचार धाराओं में अन्तर है ।

स्वरक की क्रियाशीलता (Working of Accelerator)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है स्वरक सिद्धान्त मशीनों तथा औजारों के विकास पर तथा पूँजीगत माधन पर निर्भर करता है । एक उदाहरण और तालिका द्वारा स्वरक सिद्धान्त की क्रियाशीलता को स्पष्ट किया जा सकता है । हम यह मानकर चलते हैं कि 200 करोड़ की अन्तिम वस्तुओं के लिए हम 100 करोड़ पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और पूँजीगत वस्तु का जीवन काल 10 वर्ष है और इनमें से 10 प्रतिशत को प्रतिवर्ष पुनर्स्थापित करना पड़ता है ।

## त्वरक तालिका

(करोड़ रुपये में)

| समयावधि | अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन | पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता | नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता | पुनर्स्थापित | कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता |
|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1       | 1 000                     | 500                         | 0                              | 50           | 50                                 |
| 2       | 1 200                     | 600                         | 100                            | 50           | 150                                |
| 3       | 1 3 00                    | 650                         | 50                             | 60           | 110                                |
| 4       | 13 00                     | 650                         | 0                              | 65           | 65                                 |
| 5       | 12 00                     | 600                         | —50                            | 65           | 15                                 |
| 6       | 11 00                     | 550                         | —50                            | 60           | 10                                 |
| 7       | 1 000                     | 500                         | —50                            | 55           | 5                                  |
| 8       | 900                       | 450                         | —50                            | 50           | 0                                  |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम समयावधि में 1000 करोड़ रुपये की निमित्त वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए 500 करोड़ रुपये का पूँजीगत माल की आवश्यकता होती है चूंकि हम यह पहले ही मान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत पूँजीगत माल को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है इसलिए 500 करोड़ रुपये के पूँजीगत माल में से 50 करोड़ के पूँजीगत माल अथवा मशीनों की आवश्यकता होगी। दूसरी समयावधि में हम देखते हैं कि अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन की माँग में वृद्धि 1000 से 1200 करोड़ रुपये यानि 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपये की मशीनों तथा औजारों (पूँजीगत माल) की आवश्यकता होती है। अर्थात् कुल पूँजीगत वस्तुओं की माँग 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 600 करोड़ रुपये हो जाती है और कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की माँग 50 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो जाती है इसका अर्थ यह है कि दूसरी समयावधि में 20 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 प्रतिशत पूँजीगत माल की आवश्यकता होती है। तीसरी समयावधि में स्थिति भिन्न हो जाती है अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन 100 करोड़ रुपये में बढ़ना है अर्थात् समयावधि नम्बर दो की अपेक्षा इसमें केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है (1200 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ रुपये) जबकि कुल नई पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता में 26.67 प्रतिशत की कमी आ जाती है (150 करोड़ से गिरकर 110 करोड़ हो रहा जाता है) इसका कारण यह है कि अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में पहले जो 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की कुल मात्रा थी वह आगे आने वाली अवधि में जागे नहीं रखी गई। चौथी समयावधि में अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में तीसरी समयावधि के बराबर 1300 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया है केवल पुनर्स्थापन के अलावा अन्य पूँजीगत माल की आवश्यकता नहीं होगी। इस समयावधि में कुल नयी पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता 110 करोड़ रुपये से बढ़कर केवल 65 करोड़ रुपये ही रह जाती है अर्थात् पूँजीगत वस्तु उद्योग में उत्पादन में 40 प्रतिशत में कुछ अधिक की गिरावट आती है। इसी प्रकार अन्य आने वाली समयावधियों में अर्थात् 5, 6, 7 व 8 में समयावधि 4 की अपेक्षा गिरावट आती जाती है और अन्तिम समयावधि अर्थात् समयावधि 8 में समयावधि प्रथम की अपेक्षा 100 करोड़ की अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आ जाती है और पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग का पतन प्रारम्भ हो जाता है।

उत्पन्न वस्तुओं में एक महत्त्वपूर्ण सामान्य बात यह सामने आती है कि जैसे-जैसे अन्तिम वस्तुओं में उत्पादन में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे पूँजीगत वस्तु उद्योग में भी प्रगति होती जाती है। जैसे ही अन्तिम वस्तुओं में उत्पादन में गिरावट आती है वैसे ही पूँजीगत वस्तु उद्योग में गिरावट आती है और गिरावट की दर इसी प्रकार बनी रहती है। फिर पूँजीगत वस्तु उद्योग पतन के क्षण पर पहुँच जाता है। इस प्रकार मदी का युग प्रारम्भ हो जाता है अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि से पूँजीगत वस्तु उद्योग के विस्तार की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यही विस्तार प्रभाव (Magnifying Effect) आर्थिक उतार-चढ़ाव के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार स्वरक सिद्धान्त व्यापार क्षण के समय अर्थव्यवस्था में व्याप्त कारणों की शक्तिशाली व्याख्या करता है। स्वरक सिद्धान्त से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाना है तो हम धीमी गति की अपेक्षा तेजी से अर्थव्यवस्था का कार्य संचालन करना चाहिए। मदी की स्थिति में निपटने के लिए हम तेजी से अपनी प्रतिविधियाँ का बचाना होगा। प्रो० सेम्युएलसन (Prof. Samuelson) का हम सम्बन्ध में कहना है कि यदि व्यापारिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव होने है तो स्वरक सिद्धान्त इसमें और तेजी से व्यापार क्षणों की प्रिया-शीलता बढ़ा देना है। यदि दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति का कारण अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है तो स्वरक सिद्धान्त की भूमिका उल्टा-ढुंकी होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूँजी का व्यापक उपयोग होता है जिनसे निवेश मार्ग में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का दूर किया जा सकता है।

स्वरक सिद्धान्त की शक्ति दो तत्वों पर प्रमुखतः निर्भर करती है (1) पूँजी उत्पादन अनुपात अथवा पूँजी गुणांक (Capital Output Ratio or Capital Coefficient) (2) पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन (Durability of the Capital Equipment)। पूँजी-उत्पादन का अनुपात जितना अधिक होगा निवेश की वृद्धि भी उतनी अधिक होगी। उपभोग में वृद्धि होने पर निवेश में कम वृद्धि होगी। इस प्रकार पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन या जीवन-काल अधिक होगा स्वरक का मूल्य भी उतना अधिक होगा तथा स्वरक के प्रभाव भी उतने ही अधिक दिखाई देंगे। यदि मशीनों या पूँजीगत साधनों का टिकाऊपन कम है तो स्वरक का मूल्य कम होगा और स्वरक के प्रभाव भी कम होंगे।

### स्वरक सिद्धान्त की सीमाएँ (Limitations of Acceleration Principle)

अन्य आर्थिक सिद्धान्तों की भाँति स्वरक सिद्धान्त में भी कुछ सीमाएँ हैं जो निम्न प्रकार से बनाई जा सकती हैं—

(1) उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का अभाव—स्वरक सिद्धान्त उस समय हमारा माथ नहीं देता जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ने पर प्रेरित निवेश को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्योंकि इस बढ़ी हुई माँग की पूर्ति उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से पूरा किया जा सकेगा। अतिरिक्त समय तथा अतिरिक्त काम की पारियों (Shifts) द्वारा बढ़ी हुई माँग की पूर्ति की जा सकेगी। ऐसा प्रायः व्यापार चक्र की उदरना अवस्था (Recovery or Revival Phase of Trade Cycle) में दिखाई देता है। उन उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता दिखाई देती है अथवा माहुरी ऐसी उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता बनाए रखते हैं जिन उद्योगों की वस्तुओं की माँग में उच्चावचन अथवा उतने उत्पाद की माँग में परिवर्तन होते रहते हैं। स्वरक सिद्धान्त की प्रियाशीलता का सम्बन्ध में हम यह मानकर चलते हैं कि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है और सभी पूँजीगत साधनों का उपयोग पूरा रूप में हो रहा है तथा अतिरिक्त कार्य (Overtime) तथा अतिरिक्त पारियों (Additional Shifts) में कार्य

करने की सम्भावना नहीं है। इसका आशय यह है कि अतिरिक्त क्षमता के अभाव में ही त्वरक सिद्धान्त कार्य करता है।

(2) निवेश वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता—एक अन्य सिद्धान्त भी यह है कि निवेश वस्तु उद्योग अथवा पूंजीगत वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है यदि यह अतिरिक्त क्षमता पूंजीगत मान उद्योग में नहीं हो तो पूंजीगत माधनों (मशीनों) की व्युत्पन्न मांग (Derived Demand) में वृद्धि होने पर उनको पूर्ति बढ़ाना सम्भव नहीं होगी। यदि यह अतिरिक्त क्षमता पूंजीगत वस्तु उद्योगों में उपलब्ध नहीं होगी तो इनकी मांग बढ़ने पर इनकी उत्पादन सम्भव नहीं होगा और इनकी मांग को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच अर्थात् मांग में वृद्धि हेतु पूर्ति में वृद्धि के बीच के समय में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे और त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

(3) मांग का स्वभाव—त्वरक सिद्धान्त लागू होने की एक शर्त यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में होने वाली वृद्धि स्वभाव से स्थायी प्रवृत्ति की हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा। यदि मांग में होने वाली वृद्धि अस्थायी है तो पूंजी विनियोजक उपभोक्ता वस्तु में होने वाली इस प्रकार की अस्थायी वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत माल का बढ़ाने में रुचि नहीं लेंगे। चूंकि पूंजीगत माल में टिकाऊपन का गुण होता है साथ ही इसके लिए अच्छी धनराशि की आवश्यकता होती है इसलिए वस्तु का निर्माता तब तक इसकी खरीदने में रुचि नहीं लेगा जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अल्पकालिक नहीं है। यदि निर्माता यह समझता है कि मांग लगातार बनी रहेगी तभी वह पूंजीगत माल अथवा मशीनों में पूंजी लगाएगा। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्वरक सिद्धान्त की प्रियामोक्षता तर्जनीकी तन्त्रा पर ही केवल आधारित नहीं होती बरन् भविष्य में होत वाली मांग की दर पर भी निर्भर करती है।

(4) पूंजी उत्पादन का स्थिर अनुपात—त्वरक सिद्धान्त की एक अन्य मान्यता यह है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन तथा उन्हें उत्पादित करने वाले पूंजीगत माधनों के बीच अनुपात स्थिर रहता है। वास्तविकता यह है कि यह अनुपात स्थिर नहीं रहता। हमारे गणितीय मसाले में उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकी प्रगति एक आविष्कार के कारण पूंजीगत माधनों अधिष्ठान्त रूप से कार्य करते हैं जिससे कि प्रत्येक पूंजीगत माधनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। इसका अर्थात् भविष्य में व्यापारियों को मजदूरी, ब्याज तथा मांग की सम्भावनाओं के कारण पूंजी—उत्पादन अनुपात में परिवर्तन होना रहने है। पूंजी-उत्पादन अनुपात जितना अधिष्ठान्त होगा त्वरक सिद्धान्त भी उतना अधिष्ठान्त प्रभाव डालेगा।

(5) साधनों की पूर्ति सोचता—त्वरक की एक अन्य मान्यता यह है कि साधनों की पूर्ति सोचपूर्ण होना चाहिए। पूंजीगत माल अथवा मशीनों को उत्पादित करने वाले उद्योगों की क्षमताएँ ऐसी हैं कि जिनमें इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और इनकी आवश्यकता के समय अधिष्ठान्त मशीनों की पूर्ति हो सके। निवेश उद्योगों में प्रसार की क्षमता बनी रहनी चाहिए अर्थात् निवेश उद्योगों में पूर्ण रोजगार की स्थिति न पाई जाए। एक बार जब पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त कर लिया जाए तो फिर ऐसे उद्योगों में किसी भी प्रकार का प्रसार नहीं होना चाहिए। ऐसे उद्योगों में पूर्ण रोजगार का सिन्दु प्राप्त करने के बाद त्वरक सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

(6) माल की सोचपूर्ण पूर्ति—मांग और मुद्रा की सोचपूर्ण पूर्ति त्वरक सिद्धान्त के लागू होने के लिए आवश्यक शर्त है। जब कभी भी प्रेरित निवेश की स्थिति हो तो मुद्रा तथा मांग की पूर्ति निवेश उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। मांग

और गुण की तर्फी होगी तो इमग र्चना की दर में वृद्धि होगी जिससे निवेश की लागत बढ़ेगी जो आम चरकर निवेशों को निम्नमाहिन करेगा। स्वरक के स्वतन्त्र और निर्वाण रूप से कार्य करने के लिए यह जरूरी है कि विनियोग के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होना चाहिए। यदि निवेश हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तो स्वरक सिद्धान्त मफलता-पूर्वक कार्य नहीं करेगा।

(7) उत्पादन के टिकाऊ सारधनों की उपस्थिति—स्वरक सिद्धान्त की एक अन्य मान्यता यह है कि उत्पादन के टिकाऊ साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। निवेश वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण पाए जाने पर ही स्वरक सिद्धान्त लागू होगा।

**स्वरक सिद्धान्त का महत्व (Importance of the Principle of Acceleration)**

स्वरक सिद्धान्त इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है। स्वरक सिद्धान्त के महत्व को निम्न सभ्यो से अर्थात् जा सकता है—

(1) आम संरचना को समझने में सहायक—स्वरक सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सिद्धान्त आय संरचना की प्रतिया को समझने में हमारी सहायता करता है। गुणक सिद्धान्त हमको बताता है कि जैसे-जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे-वैसे लोभा की आय और रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है परन्तु हम गुणक सिद्धान्त के परिणामों में ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम आय पर निवेश की वृद्धि के कुल परिणाम या प्रभाव को जानना चाहते हैं तो हमें स्वरक के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है जो अन्ततः भावी निवेश को प्रेरणा देती है और इस प्रकार गुणक प्रिया के प्रारम्भ होने में कुल आय में वृद्धि होने के बाद आय संरचना की प्रतिया का दूसरा चक्र स्वरक सिद्धान्त की प्रिया-शीलता के कारण प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार स्वरक आय संरचना की वास्तविकता को समझने में बड़ा सहायक होता है।

(2) व्यापार चक्रों की प्रकृति समझने में सहायक—स्वरक की एक विशेषता यह है कि यह व्यापार चक्र की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। व्यापार चक्रों के घटित होने पर उपभोग वस्तु उद्योग की अपेक्षा निवेश वस्तु उद्योग में उतार-चढ़ाव की गति तेज होती है। यदि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में जरा सा भी परिवर्तन होगा तो इसमें निवेश वस्तुओं के उद्योगों में भारी परिवर्तन होंगे। इसलिए व्यापार चक्रों की स्थिति में निवेश उद्योगों में भारी परिवर्तन होने से बचाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

(3) स्वरक सिद्धान्त हमें बताता है कि पूँजीगत वस्तुओं की माँग को एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए उपभोग को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना जरूरी होता है।

(4) स्वरक सिद्धान्त हमें बताता है कि मदी के घटित होने का प्रमुख कारण उपभोग में गिरावट का आना होता है। मदी के समय उपभोग का स्तर बाधे गिर जाता है, इसलिए अध्ययनसे मदी उबारने के लिए उपभोग का स्तर को ऊँचा उठाने में मधो प्रयास करना चाहिए।

(5) स्वरक सिद्धान्त व्यापार चक्र के विश्लेषणार्थक अध्ययन में अपना महत्व रखता है।

स्वरक सिद्धान्त यद्यपि महत्वपूर्ण है परन्तु इसकी मान्यताएँ हम सिद्धान्त का किसी घटक साधनों में व्यक्त करने में बाधा उपस्थित करती हैं। स्वरक सिद्धान्त की कुछ मान्यताएँ जैसे अनिश्चित क्षमता का अभाव, माँग में अस्थायी वृद्धि पूँजीगत वस्तुओं के प्रति इच्छा वस्तुओं का निश्चय अनुपात, निरंतर बदलाव की माँग आदि हमारे वास्तविक व्यवहार से विचलित करती हैं। यदि हम वास्तविक मान्यताओं के आधार पर

है जो निवेश वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली आय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है जबकि खरक सिद्धान्त बताता है कि उपभोग में परिवर्तन किम प्रकार विनियोगों में परिवर्तन लाते हैं। यदि हमें आय संरचना प्रक्रिया का पूरा चित्र देना है तो हमें गुणक तथा खरक दोनों ही के प्रभावों को देना होगा।

गुणक तथा खरक की परस्पर क्रिया के प्रभावों का अध्ययन उपयोगी ही नहीं बल्कि रोचक भी है। प्रारम्भिक निवेश के राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने एवं उनको नापने के लिए हमें गुणक तथा खरक दोनों सिद्धान्तों को मिला देना चाहिए। निवेश में होने वाला परिवर्तन राष्ट्रीय आय को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है जिससे उपभोग का स्तर भी परिवर्तित हो जाता है। उपभोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निवेश परिवर्तित होता है इस प्रकार कारण तथा परिणाम के सम्बन्धों का एक चक्र पूरा हो जाता है। निवेश आय तथा आय पुनः निवेश को प्रभावित करती है और जिससे गुणक तथा खरक क्रिया प्रति क्रिया द्वारा आय में उच्चावचन जो होते हैं उसे निम्न तालिका द्वारा दिया जा सके है

तालिका

(करोड़ रुपये में)

| समयावधि (Period) | स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) | उपभोग में वृद्धि (Increase in consumption) $\Delta c/\Delta y = 0.5$ | प्रेरित निवेश (Induced Investment) $\Delta k/\Delta y = \alpha = 2$ | आय में कुल वृद्धि $2+3+4$ |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                | 2                                      | 3                                                                    | 4                                                                   | 5                         |
| 0                | 0                                      | 0                                                                    | 0                                                                   | 0                         |
| 1                | 100                                    | 0                                                                    | 0                                                                   | 100                       |
| 2                | 100                                    | 50                                                                   | 100                                                                 | 150                       |
| 3                | 100                                    | 125                                                                  | 150                                                                 | 375                       |
| 4                | 100                                    | 187.5                                                                | 125                                                                 | 412.5                     |

नोट—अवधि नम्बर तीन के प्रेरित निवेश जानने के लिए तो अवधि नम्बर 2 की उपभोग प्रवृत्ति को अवधि नम्बर 3 की उपभोग प्रवृत्ति में से घटा देना चाहिए।  $(125 - 50 = 75)$  जो कुछ आवेगा उसे 2 से गुणा करने पर अवधि नम्बर 3 का प्रेरित निवेश मालूम किया जा सकता है  $(75 \times 2 = 150)$  इसी प्रकार से अन्य समयावधियों के प्रेरित निवेश को ज्ञात किया जा सकता है। आय में कुल वृद्धि की Column नम्बर  $2+3+4$  के योग द्वारा मालूम किया जा सकता है। यदि रहे स्वायत्त निवेश अतिरिक्त रहेगा। उपरोक्त सारणी में  $MPC = \frac{1}{2} = 0.5$  तथा खरक सह-गुणांक (Coefficient)  $= 2$  माना है।

उपरोक्त सारणी में 100 करोड़ रुपये का स्वायत्त निवेश आने वाले समय में जुड़ जाता है जो आगे के समयावधियों में निरन्तर बना रहता है। प्रथम समयावधि में 100 करोड़ रुपये का स्वायत्त निवेश 100 करोड़ रुपये द्वारा बढ़ जाता है और इस काल में उपभोग में वृद्धि शून्य दिखाई गई है। इस निवेश वृद्धि का परिणाम दूसरी समयावधि में उपभोग में वृद्धि 50 करोड़ रुपये की लाता है क्योंकि  $MPC = 0.5$  अथवा  $1/2$  है। खरक का मूल्य 2 होने के कारण दूसरी समयावधि में प्रेरित निवेश 100 करोड़ हो जाएगा और कुल आय में वृद्धि 150 करोड़ रुपये होगी। इसी प्रकार तीसरी समयावधि में 150 करोड़ प्रेरित निवेश कुल आय में 375 करोड़ रुपये की वृद्धि करता है। आगे आने वाली समयावधियों में भी इसी प्रकार आय में होने वाले परिवर्तन निर्धारित किए जाते हैं।



## परस्पर प्रिया का महत्व (Importance of the Interaction)

गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया का विचार भी काफी महत्वपूर्ण है। गुणक तथा त्वरक सिद्धान्त की परस्पर प्रियाओं द्वारा व्यापार चक्र का निश्चयनात्मक अध्ययन सम्भव हुआ है। गुणक तथा त्वरक के परस्पर प्रभाव की अनुपस्थिति में व्यापार चक्र का आकार साधारण हुआ होता और इनका नियन्त्रण करना भी सरल होता। प्रा० कुरी द्वारा न कहा है कि यह गुणक विश्लेषण के साथ साथ जा कि सामान्य उपभाग प्रवृत्ति के विचार पर आधारित है त्वरक सिद्धान्त व्यापार चक्र विश्लेषण और व्यापार चक्र की नीति के लिए एक महयोगी मार्ग दर्शक तथा एक उपयोगी अस्त्र है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए।<sup>1</sup>

## परीक्षा-प्रश्न

1. त्वरक सिद्धान्त को परिभाषित कीजिए। इसकी कार्य विधि भी समझें तथा महत्व बताइए।  
(Define the Principle of acceleration Give its working limitations and Significance)
2. त्वरक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मान्यताओं बताइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह सिद्धान्त कम विकसित देशों में कार्य नहीं करता ?  
(Explain the principle of acceleration and pointout its assumptions Do you agree with the view that it does not operate in less developed countries ?)
3. टिप्पणी लिखिए—  
(1) गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया।  
(ii) त्वरक सिद्धान्त की आलोचनाएँ।  
Write notes on —  
(1) Interaction of Multiplier and Accelerator  
(ii) Criticism of the Principle of Acceleration

## वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

4. निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही तथा कौन गलत है।  
(1) त्वरक सिद्धान्त मुल उपभाग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि निवर्णन में हानि वाली वृद्धि की व्याख्या करता है।  
(ii) यह कहना गलत है कि व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की परस्पर प्रिया द्वारा घटित होते हैं।  
(iii) त्वरक प्रमुखतः दो स्तर पर निर्भर करता है। (i) पूर्वी गुणक तथा (ii) पूर्वी गुणक का टिकाऊपन।

## वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है (ii) गलत है। (iii) सही है।

*"It is in conjunction with the multiplier analysis based on the concept of the marginal propensity to consume that acceleration principle serves as a useful tool for business cycle analysis and as a helpful guide to business cycle policy"*

Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of settling debts) and that at the same time acts as a measure and as a store of value' — *G Crother*

Money is any thing that passes freely from hand to hand as medium of exchange and is generally received in final discharge of debts — *Ely*

अध्याय 12

## मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

(DEFINITION AND FUNCTIONS OF MONEY)

### मुद्रा क्या है ? (What is Money ?)

प्रो० वाउवर १ मुद्रा को मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार का सजा दी है। प्रो० थ उधर का कहना है कि मुद्रा मानव आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। प्रत्येक ज्ञान की शाखा में कोई न कोई मौलिक खोज होती है। जिस प्रकार यंत्रशास्त्र में पहिया विज्ञान में अग्नि तथा राजनीतिशास्त्र में मत आविष्कारों के सूचक हैं ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व के सम्पूर्ण व्यापारिक क्षमता में मुद्रा वह महान आविष्कार है जिस पर अन्य सभी आविष्कार आधारित हैं।

मानव सभ्यता १ विकास के साथ मुद्रा का इतिहास जुड़ा है। प्रारम्भ में चक्रवर्तमान समय पर मुद्रा का स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होते आये हैं। मुद्रा की यणना उन वस्तुओं में से की जाती है जिनको किसी एक परिभाषा द्वारा व्यक्त करना एक दुष्कर काम है।

### मुद्रा की परिभाषा (Definition of Money)

मुद्रा जहाँ मानव जीवन के लिए अति आवश्यक एवं अद्वितीय है वहाँ दूसरी ओर इसकी परिभाषा में सम्बन्ध में काफी बड़ा विवाद रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के विभिन्न गुणों को ध्यान में रखकर मुद्रा की पृथक् पृथक् परिभाषायें दी गई हैं। वास्तविकता यह है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोणों एवं अपना मुद्रागत त्रुटि मुद्रा की परिभाषा देने का प्रयास किया है। मुद्रा की इतना अलग परिभाषायें दी गई हैं कि अर्थशास्त्र १ विशेषज्ञों के समक्ष यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि कौन-सी

ऐसी मुद्रा की परिभाषा है जो अपने आप में पूर्ण एवं उपयुक्त हो। मुद्रा की परिभाषाओं के विभिन्न वर्गीकरणों से हम मुद्रा की एक उपयुक्त परिभाषा ढूँढ़ने में सफल हो सकते हैं।

हम इन परिभाषाओं को, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार दी गई हैं, अध्ययन की सुविधा के लिये निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

### वर्णनात्मक अथवा कार्यवाहक परिभाषाएँ (Descriptive or Functional Definitions)

जिन परिभाषाओं में मुद्रा के वायों या वर्णन किया गया है उनका वर्णनात्मक परिभाषाएँ कहते हैं। इनमें मुख्य निम्न हैं —

(क) 'मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे।'<sup>2</sup> — फ्रान्सिस वाकर

(ख) 'मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम (अर्थात् ऋणों के निपटाने के साधन) के रूप में सामान्यतः स्वीकार्य होती है तथा माप की मूल्य के मापक और संचय के आधार का कार्य करती है।'<sup>2</sup> — फ्राउडर

(ग) 'वर्तमान में मुद्रा, प्रत्येक व्यवहार में, केवल शर्तों को निर्धारित नहीं करती बल्कि विनिमय में माध्यम का कार्य भी करती है..... यह एक माप या मूल्य का प्रमाण के रूप में कार्य करती है जिमकी महायत्ना से अन्य वस्तुओं की तुलना की जा सकती है।'<sup>3</sup> — फ्राउडर

(घ) 'यदि कोई वस्तु-विशेष मूल्य निर्धारित करे, वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान-प्रदान करने तथा अन्य आर्थिक कार्य करने के लिये सामान्य रूप में काम में लाने वाली है तब वह मुद्रा है चाहे उसकी वैधानिक और भौतिक विशेषताएँ कुछ भी हों।'<sup>4</sup> — ह्विटलसी

(ङ) 'मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है।'<sup>5</sup> — कॉलबोर्न

1. "Money is that money does."  
Money in Relation to Trade & Industry. — Francis A. Walker
2. "Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange (i.e. as a means of settling debts) and that at the same time acts as measure and as a store of value."  
An Outline of Money. — G. Crowther
3. "In every transaction money, now not only fixes the term. But mediates in the exchange..... It acts as a yard-stick or standard measure of value to which all other things can be compared."  
An Outline of Money. — G. Crowther
4. 'If a particular unit is commonly employed to state values, exchange goods and services or perform other money functions, then it is money whatever its legal or physical characteristics.'  
— Whittlesey.
5. "Money may be defined as the means of valuation and of payment  
— Coulton

प्रो० नैप जीर हाट्टे सिगरेट व सीपियो आदि तो क्या, ये तो गार पत्रा और चैंको को भी मुद्रा के अन्तर्गत गणना करने को तैयार नहीं थे क्योंकि, सामरिकी शक्ति के अभाव में, इनको लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

### आलोचना

यह परिभाषा अत्यन्त सन्तुष्ट है। कॉलवोर्न (Coulborn) के अनुसार यह परिभाषाएँ 'मुद्रा से सम्बन्धित दृष्टियों के दृष्टिकोण' (Lawyer's View of Money) हैं। वास्तविकता यह है कि विनिमय एवं ऐच्छित कार्य हैं, और यदि यह किया केवल सामरिकी दबाव के अन्तर्गत ही जाय तो सच्चे अर्थों में इस विनिमय कहा जाता है। प्रो० नैप ने देश जर्मनी में सन् 1920 के बाद प्रथम महायुद्ध के दुष्परिणामों के कारण, 'गंगा हुआ रि मार्क' की जन स्वीकृति समाप्त हो गई और वह विनिमय का व्यावहारिक माध्यम न रहा। 1944 में हुंगरी में उमबी मुद्रा पेन्गोस (Pengos) के साथ भी यही हुआ और लोगों ने उसको विनिमय में लेने से अस्वीकार कर दिया, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् चीन में भी वहाँ की मुद्रा बानूनी मान्यता होते हुए भी प्रचलन से हट गयी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा के लिए राज्यशक्ति नहीं बनना सर्वग्राह्य का गुण होना जरूरी है। यदि जनता का विश्वास किसी मुद्रा में से हट जाए तो राज्य कितने ही बड़े नियम बना न बना ले, उसे मर्भी के द्वारा स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकता।

### सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ (Definitions based on General Acceptability)

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि सर्वग्राह्यता या सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशेष गुण है। इसी तथ्य पर चल देने के लिये अनेक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा किया है जिनमें से कुछ निम्न हैं—

(क) 'मुद्रा म के सब वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना सन्देह या विशेष जाँच-पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और व्यय चुकाने के माधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं।'<sup>1</sup>

(ख) "मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण और भूय-सम्बन्धी अनुबन्धा को पूर्ण किया जाता है, और जिनमें सामान्य प्रय-शक्ति संचित की जाती है।"<sup>2</sup> —बीन्स

(ग) "मुद्रा वह वस्तु है जिस सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।"<sup>3</sup> —संक्षिप्त

(घ) 'मुद्रा वह वस्तु है जिमें मान के सुगमता, अथवा व्यापारिक दायित्वा के

1 "Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses"  
—Prof. Marshall

2 "Money itself is that by delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held"  
—Keynes

3 "Money is one thing that possesses general acceptability"  
—Saligmen

भुगतान के रूप में विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है।<sup>1</sup>

— रॉबर्टसन

(च) मुद्रा कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मापक के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है।<sup>2</sup>

— केंट

(छ) मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में, स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है, और जो ऋणों के अन्तिम भुगतान के लिए सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है।<sup>3</sup>

— एली

(ज) मुद्रा कहलाने के लिए किसी भी वस्तु को विस्तृत धेन म, विनिमय माध्यम के रूप में, स्वीकार्यता हनी आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि भारी संख्या में लोग उसे वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों।<sup>4</sup>

— पीगू

आलोचना

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह परिभाषाएँ इस तथ्य पर बल देती हैं कि नित्य प्रति के लेन-देन प्रय-विप्रय तथा ऋणा के भुगतान के लिए निस्संकोच रूप से स्वीकार की जाने वाली वस्तुओं को मुद्रा कहते हैं। 'परन्तु इन परिभाषाओं में भी एक कमी' है। य केवल वर्तमान पर ही बल देती हैं जबकि मुद्रा को तीनो काल—भूत, वर्तमान तथा भविष्य—में स्वीकार्य व ग्राह्य होना चाहिए। क्योंकि कौन्स व रोबर्टसन जैसे अनेक अर्थशास्त्री मुद्रा को 'ऋण सम्बन्धी सौदे (Debt Contract) व व्यापारिक दायित्व (Business Contracts) माना है। इन परिभाषाओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि ये मुद्रा के मूल्य की आवश्यक कार्यों पर (जिन पर सामान्य स्वीकृति आधारित या जिनसे प्रभावित होती है) समान रूप से दबाव नहीं डालता गया है। मुद्रा की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जिसमें मुद्रा के समस्त कार्यों और उसके स्वरूप का वर्णन किया गया हो। सम्भवतः मुद्रा की यह परिभाषा हो सकती है—

“मुद्रा वह पदार्थ है जिसको जनता मूल्य वर्तमान तथा भविष्य के भुगतानों के लिए मुक्त-रूप से स्वीकार करती है और शासकीय मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ वह मूल्य मापक व मूल्य-संचक भी होता है।”

### मुद्रा की परिभाषा से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण (Different Views Regarding Definition of Money)

मुद्रा की जो परिभाषाएँ सशरीत की गई हैं उनके अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुछ परिभाषाएँ बहुत व्यापक हैं तथा अन्य कुछ परिभाषाएँ बहुत सन्कुचित हैं।

1. 'D H Robertson defines money as "Anything which is widely accepted in payment for goods, or in discharge of other kinds of business obligations" —Robertson
2. 'Money is anything that is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value —Kent
3. Money is anything that passes freely from hand to hand as medium of exchange and is generally received in final discharge of debts" —Ely
4. "In order of anything to be classed as money, it must be accepted fairly widely as an instrument of exchange, which means that a good number of people are ready to accept it in payment for goods and services provided by them." —Pigou

साधनों के उत्पादन के लिए होती खरीदना, लाभ अर्जित करने की दृष्टि में शून्य-मूल्य अथवा प्रतिभ्रमियों को खरीदना इत्यादि। वह लोग जो इन परिणामप्रतियों में धन नहीं लगाते और भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण अपने धन को मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह इस धन का उपयोग आसानी से तथा इच्छानुसार कर सके। भावी प्रत्याशाओं का हमारे वर्तमान निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग परिणामप्रतियों की अनिश्चित प्रवृत्ति के कारण मुद्रा में अपने धन को संचित रखते हैं।

(ब) भावी भुगतानों का आधार (Standard of Deferred Payments)—मुद्रा की सामान्य स्वीकृति और जनता के विश्वास के कारण मुद्रा में भविष्य के भुगतानों की सुविधा प्रदान की है। अब कुछ स्थितियों में सौदे वर्तमान में किए जाते हैं और उनका भुगतान भविष्य में किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में साथ ही सुविधा प्रदान करके इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम मुद्रा को वर्तमान आर्थिक प्रगति की आधारशिला कहे तो अनुचित न होगा। मुद्रा समाज में वर्तमान भुगतानों को ही सम्पन्न करती है साथ में भावी भुगतानों का आधार भी है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसमें भविष्य में होने वाले भुगतानों का हिमायत करता गया जाता है। जिससे कि शून्य तथा शून्यता दोनों में से किसी की ह्रासि न हो। आधुनिक युग में अधिकांश लेन-देन व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति भुगतानों के रूप में होता है जिसमें मुद्रा के इस कार्य का महत्व और भी अधिक हो गया है।

(ग) मूल्य शक्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—मुद्रा में मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की सुविधा प्रदान की है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को यह हस्तान्तरण कार्य मुद्रा में ही सम्भव बनाया है। इस कार्य को सम्पन्न करने मुद्रा में विनिमय को ध्यापक बनाया है। यदि मुद्रा में मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की सुविधा न होती तो समाज की आर्थिक प्रगति का पत्र भी रुक गया होता। वर्तमान समय में साथ मुद्रा तथा वैकिंग सुविधाएँ, उद्योग, तथा व्यापार और यातायात के साधन उपलब्ध न हुए होते तो समाज प्रगति नहीं कर सकता था।

मुद्रा तथा साथ मुद्रा में मूल्य अंतरण को एक स्थान से दूसरे स्थान करके तथा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करके मनुष्य को बहुत बड़ी अनुविधाया से बना दिया है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति कुछ धनराशि का अंतरण कानपुर से बम्बई करना चाहता है तो वह व्यक्ति कानपुर की किसी बैंक में यह धनराशि जमा करके बैंक ड्राफ्ट बनवा कर अथवा बैंक द्वारा भेज सकता है और बम्बई में प्राप्तकर्ता व्यक्ति को वह धनराशि मिल जाएगी। ड्राफ्ट बनवाने में उसे बहुत थोड़ा-सा शुल्क ही देना पड़ता है। यदि भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है तो बैंक भुगतान में थोड़ी सी धनराशि ही व्यय करती पाएगी। इसी प्रकार एक व्यक्ति नकद धनराशि के लेन-देन की अनुविधा से बचने के लिए बैंक द्वारा भुगतान सेते और देते रहते हैं। इस प्रकार मूल्य शक्ति के हस्तान्तरण की यह सुविधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागे धनराशि को ले जाने के जोरिण से सुविधा प्रदान करती है। व्यापारिक क्षेत्र और विविधित देशों में ऐसी भुगतान करन की एक परिणाम-मयी बन गई है। यह कार्य मुद्रा में ही सम्भव बनाया है।

(3) मुद्रा के आर्थिक कार्य—मुद्रा के आर्थिक कार्य निम्न प्रकार में वर्णित किए जाते हैं

(अ) साथ का आधार (Basis of Credit)—मुद्रा में साथ का आधार बनकर देश की वैकिंग, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अक्षतपूर्वकता की है। अतः हम मुद्रा में अधिक साथ मुद्रा को मूल्य देने लगे हैं। विविधित देशों में तो साथ-मुद्रा का प्रचलन

बहुत अधिक बट गया है। आज के युग में बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं से कहीं अधिक धनराशि की मांग मुद्रा निर्गमित करके व्यापारिक तथा औद्योगिक श्रियाओं के विस्तार और उन्हें सुविधापूर्वक सम्पन्न करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। आज स्थिति यह है कि यदि मांग मुद्रा के सृजन से निर्गम प्रसार का व्यवधान उपस्थित हो जाता है तो इसमें अर्थव्यवस्था तारतम्यिक रूप में प्रभावित होती है। आज विभिन्न देशों में राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रगतिशील और कर्मशासकीय योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि जुटाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जो मांग-मुद्रा हमारे लिए आज इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है उस मांग-मुद्रा का आन्तरिक वैधानिक मुद्रा ही है।

(ब) सामाजिक आय का वितरण (Distribution of Social Income)—वर्तमान पैचीदा अर्थव्यवस्था में मुद्रा सामाजिक आय की उत्पात के विभिन्न साधनों के मध्य वेटवारा करने का सर्वोत्तम पैमाना है। उत्पात के प्रत्येक साधन का उसी योग्यता और श्रम के आधार पर मुद्रा के रूप में मूल्यंकन करके भुगतान किया जा सकता है। वर्तमान समय में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता जिसमें बहुत से मनुष्य सहयोगी उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार जो भी उत्पादन होता है उसमें असंख्य लोगों का योगदान होता है और उमका वितरण भी सभी साधनों के मध्य होना चाहिए। सभी उत्पात के साधनों की योग्यता और कुशलता एक-सी नहीं होती और न ही उनका उत्पादन स्तर एक-सा होता है। मुद्रा के उत्पात के साधनों के मध्य उत्पादन के वेटवारे की इस जटिल समस्या का समाधान कुशलपूर्वक किया है। सामूहिक रूप से उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर एक उत्पादक द्वारा उत्पात के विभिन्न साधनों के मध्य बाँट दिया जाता है और सामूहिक उत्पादन में प्राप्त आय का वेटवारा आभासी से हो जाता है। मुद्रा ने सहयोगी साधनों के मध्य सामाजिक आय के वितरण को करने बनाकर समाज में बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

(स) सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादकता में समानता का आधार—(Basis of Equalising Marginal Utility and Marginal Productivity)—मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं और उनके पास साधन सीमित होते हैं। एक उपनोक्ता की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के सामने सीमित साधनों के कुशलतम प्रयोग में इन आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाय जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकतम सन्तुष्टि के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। यह उग समय सम्भव हो सकता है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई से सीमान्त उपयोगिता समान हो जाए। मुद्रा ने उपनोक्ता को द्रव्य रूपी इकाईयों द्वारा सीमान्त उपयोगिता की समानता का माप सम्भव बनाया है और उपनोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि का लक्ष्य अपने सीमित साधनों द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित करके तथा उत्तरी मात्रा के उपयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार एक उत्पादक के लिए भी उत्पात के विभिन्न साधनों के साधनोत्तम अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने में मुद्रा सहायता प्रदान करती है। एक उत्पादक उत्पात के साधनों पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई से उत्पात के साधनों की सीमान्त उत्पादकता में समानता स्थापित करके न्यूनतम लागत का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

(द) पूँजी की सामान्य रूप प्रदान करने का आधार (Basis of Providing General form of Capital)—मुद्रा ने सभी प्रकार की पूँजी तथा सम्पत्ति को सामान्य रूप प्रदान किया है। अब मांग मुद्रा के रूप में बचत करके अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मुद्रा में गतिशीलता तथा नकदी प्रवृत्ति के कारण मुद्रा को निर्गम भी

पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। जिन् प्रकार हम पानी को हरे या गाल बर्तन में रखें, पानी उसी रंग का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार मुद्रा भी उस वस्तु का रूप धारण कर लेती है जिसमें हम उसे बदलना चाहते हैं अर्थात् मुद्रा द्वारा हम अपनी इच्छा-मुताबक वस्तु को ध्यय कर सकते हैं। मुद्रा से संचित धन तथा पूँजी को किसी भी कार्य के उपयोग में लाया जा सकता है।

(4) मुद्रा के अन्य कार्य—बुद्ध अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के वर्णित उपयोगित कार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य भी बतलाए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

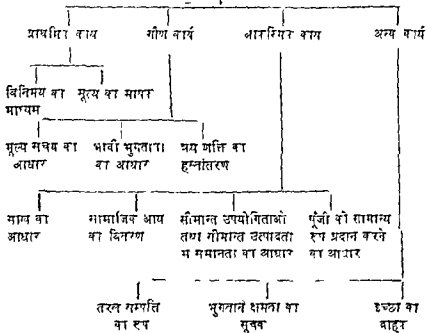
(अ) तरल सम्पत्ति का रूप (Form of Liquid Wealth)—प्रो० जे० एम० कीन्स (Prof J M Keynes) ने मुद्रा के इन कार्य को विशेष महत्व दिया है। प्रो० कीन्स का कहना है कि मुद्रा मनुष्य के पास उपलब्ध सम्पत्ति का सबसे तरल रूप है। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म की अपनी कुछ परिष्कृतियाँ होती हैं जिनसे मुद्रा सर्वोत्तम परिष्कृत सम्पत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की समय-समय पर पूर्ति के लिए अन्य परिष्कृतियों के बजाय मुद्रा में संचित करना उचित समझता है। भविष्य अनिश्चित होता है और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति में दूरदर्शिता का गुण होता है। भविष्य की अनिश्चितता तथा दूरदर्शिता की मात्रा को देखते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय के कुछ भाग को नकद मुद्रा के रूप में रखता है। इस प्रकार वह इस नकदी से अर्थात् मुद्रा रूपी तरल परिष्कृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। तरल मुद्रा के बजाय वह अपनी आय को किसी अन्य परिष्कृत में रखे तो आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य परिष्कृत को बेचकर मुद्रा में परिवर्तित करके ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। ऐसा करने में उसे तात्कालिक रूप से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए मुद्रा रूपी इनाइया द्वारा वह अपनी जीवनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।

(ब) भुगतान क्षमता का सूचक (Guarantor of Solvency)—मुद्रा के इस कार्य का उत्कृष्ट विशेष रूप से प्रो० आर० पी० केंट (Prof R P Kent) ने किया है। वह कहते हैं कि मुद्रा समाज में व्यक्तियों को प्रण भुगतान करने की शक्ति प्रदान करती है। एक व्यक्ति उसी समय तक श्रेष्ठ चुकान में समर्थ हो सकता है जब तक उसके पास मुद्रा है। जब वही भी मुद्रा रूपी परिष्कृति व्यक्ति या फर्म से प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति या फर्म का दिवालिया निवृत्त जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति या फर्म अपनी भुगतान करने की क्षमता बनाए रखने के लिए अपने आय अर्थात् मालिकाना वा एक भाग नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं।



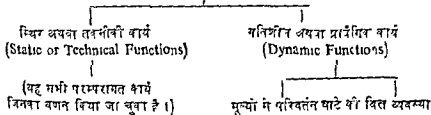
नती हा गव ति त्पारि मुद्रा ती विगी वस्तु म विगी गमय परिबित्त रिवा जा गवता हे जबकि अन्य तिसी वस्तु म आगानी से वदन पाता कटिन काय हे । मुद्रा न मनुष्य को इग प्रकार अपन गवो तिणया वा त्रिधाविन वरन म इहाःपूर्ण भूमिका प्रदान को हे । मुद्रा के उपरुक्त कार्यो को हम निम्न चट द्वारा प्रस्तुत कर गवते हे—

### मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण (I)



मुद्रा के कार्यो का एक अन्य वर्गीकरण अथवा पॉल इजिंग, (Paul Einzig) का वर्गीकरण

### मुद्रा के कार्य का वर्गीकरण (II)



मुद्रा के स्थिर तथा गतिशील कार्यो का वर्गीकरण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल इजिंग (Paul Einzig) ने किया हे । उन्होंने मुद्रा के स्थिर कार्यो का अर्थ उन सभी कार्यो मे रिया हे जो अव्यवस्था का संचालन ता करने हे परन्तु उनको गति प्रदान नहीं करते । इन कार्यो मे मूल्य रूप मे के विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, स्थिति भुगतानो का मान मूल्य मन्वय के कार्यो बाते हे । इमो अतिरिक्त वे सभी कार्यो मे शामिल किए जा गवते हे जिन्हें मुद्रा पढ़ने से करती वा नहीं हे ।

मुद्रा के प्रारंभिक या गतिशील कार्यों में ऐसे कार्यों को स्थिर रिया जाता है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से मूल्य स्तर को प्रभावित करना एवं घाटे की वित्त व्यवस्था रूपी कार्य आते हैं।

(1) मूल्यों में परिवर्तन (Changes in the Value)—वर्तमान गतिशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूल्य स्तर को प्रभावित करना है। अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव अर्थात् मुद्रा एवं स्फीति मान में मुद्रा अर्थव्यवस्था को समुचित गति प्रदान करती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का वातावरण उत्पन्न होता है तो सरकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके पूंजी विनियोजन को बढ़ाती है तथा बैंको द्वारा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सस्ती साख्त उपलब्ध कराती है। इसका मिला-जुला परिणाम यह होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बढ़ता है परिणामस्वरूप समाज की सम्पूर्ण आय बढ़ती है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग समाज में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाती है जिससे मूल्य स्तर बढ़ता है। मूल्यों में घटोतरी साहसियों को पूंजी विनियोजन बढ़ाने में सहायक होती है। इसके विपरीत मुद्रा स्फीतिक काल में मुद्रा की मात्रा तथा ऋण प्रदान प्रवृत्ति को समुचित करके मूल्यों में थोड़ी गिरावट वस्तुओं की मांग बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में गतिमान करते हैं।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मूल्यों में स्थायित्व अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है परन्तु मूल्यों में परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक ही होने देना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सर्वदा सचेत रहना चाहिए कि मूल्य न तो इतने घटने पाएँ और न ही कम हों जिससे कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति न आने पाए।

(2) घाटे की वित्त व्यवस्था—पॉन इजिग ने मुद्रा के गतिशील कार्य में घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा घाटे के वज्र को भी महत्वपूर्ण माना है। वर्तमान समय में सरकार के दायित्व एवं कार्य इतने बढ़ गये हैं कि वह अपनी आय स्रोतों से इनको पूरा करने में समर्थ नहीं होतीं। सरकार या तो देश के केन्द्रीय बैंक से रकम उधार लेकर या फिर घाटे के वज्र बनाने के अतिरिक्त मुद्रा की निकासी का कार्य करती है। सरकार को योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करनी है। इस दिशा में देश का केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा अन्य ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कार्यों के उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मुद्रा के बिना आधुनिक युग में मनुष्य के लिए सम्भव जीवन बिताना सम्भव नहीं है। मुद्रा का उपयोग मानव सभ्यता के विकास के लिए निरान्त आवश्यक है।

### परीक्षा-प्रश्न

1. मुद्रा के स्थैतिक एवं प्रारंभिक कार्यों की व्याख्या कीजिए और एक दिनामर्मीन अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक कार्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

(Discuss the static and dynamic functions of money and indicate the importance of the latter in a developing economy.)

2. मुद्रा के कार्य बताइए। कागजी मुद्रा यह कार्य क्यों नहीं कर पाती है ?

Define the functions of money How far does paper money perform them well.)

3 मुद्रा व मुरय गीण तथा आनस्मिभ नार्यों का वणन वाजिण ।  
(Discuss the main secondary and contingent functions of money)

4 मुद्रा वही है जो मुद्रा वा वाय करती है । ध्याख्या वाजिण ।  
( Money is what money does Discuss )

[सकेत—सरकारी तथा बैंक सारा मुद्रा वा ध्याख्या वाजिण । मुद्रा व नार्यों का सक्षिप्त विवरण दीजिए ।]

5 मुद्रा वे वाय बताइए । वागजी मुद्रा यह वाय वहाँ तक वन जाती है ?  
(Define the functions of money How far does the paper money perform them well ?)

[सकेत—सबस पहले मुद्रा वे नार्यों का सक्षिप्त विवरण दीजिए तत्पश्चात् बताइए कि वतमान समय व ससार वे प्राय सभी देश व वागजी मुद्रा ही अपनाई गई है । यह मुद्रा भनी प्रकार ससार वा सदा वर रही है । परंतु ऐसी मुद्रा वे पीछे बहुमूल्य धातुआ वे वाय व अभाव व मुद्रा वा पूर्ति व तजी से वृद्धि हुई है तथा मुद्रा व मूल्य व तजी से गिरावट आई है जिससे तीसरी दुनिया वे देशो व साधन बिहीन या अल्प साधन वा न्यक्तिया व लिए वाफी आर्थिक बठिनाइयां बनी हैं ।]

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

- 6 निम्नलिखित प्रश्नो व गीन सही तथा गीन गलत है
- मुद्रा मानव आधिष्णारो व एव महत्वपूर्ण आधिष्णार है ।
  - मुद्रा विनिमय वा माध्यम तथा मूल्य मापन वा वाय गदीव एव वाय सम्पन्न करती है ।
  - मुद्रा न सभी प्रकार वा पूजी तथा सम्पत्ति वा एव सामान्य रूप प्रदान किया है ।
  - मुद्रा व स्थान पर अल्प नोई वस्तु ब्यक्ति वा च्छा वा वाटक नहीं हो सकती ।
  - मुद्रा वा निमी वस्तु व निम्न समय परिवर्तित किया जा सकता है ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नो के उत्तर

- (i) गही है । (ii) गलत है । (iii) गही है । (iv) सही है । (v) सही है ।

"Money is the pivot around which the whole economic science clusters."

—Prof. Marshall

अध्याय 13

## मुद्रा का चक्राकार प्रवाह एवं महत्व

(CIRCULAR FLOW AND IMPORTANCE OF MONEY)

### मुद्रा का चक्राकार प्रवाह (Circular Flow of Money)

मुद्रा की चक्राकार प्रवाह की विशेषता के कारण एक अर्थव्यवस्था में द्राव्यिक भुगतानों का प्रभु निरन्तर बना रहता है। जब उपभोक्ता बाजार में उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रयत्न करते हैं तो उनका भुगतान वह मुद्रा के रूप में करते हैं और यह मुद्रा फुटकर वस्तु विनिर्माताओं तथा सेवामालिकों के पास पहुँचती है। फुटकर विनिर्माता इस मुद्रा को थोक व्यापारियों अथवा विनिर्माताओं को देते हैं जिनसे कि वह यह वस्तुएँ प्रयत्न करके लाए थे और थोक विनिर्माता इन उपभोग्य वस्तुओं के निर्माताओं अथवा उत्पादकों को देते हैं। निर्माता अथवा उत्पादकों को जो इस प्रकार से मुद्रा इकाइयाँ प्राप्त होती हैं वे पुनः इनको उत्पत्ति के साधनों के पारिश्रमिक के रूप में जैसे मजदूरी, सगान अथवा किराया, ध्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में बाँट देते हैं। उत्पादकों को जो आय प्राप्त होती है उसका कुछ हिस्सा सरकार के पास करों के रूप में चला जाता है और चक्राकार गति में से बाहर आ जाता है शेष भाग को उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होता है वही चक्राकार गति का हिस्सा बनकर समाज में आर्थिक क्रियाओं के रूप में निरन्तर गतिमान रहता है।

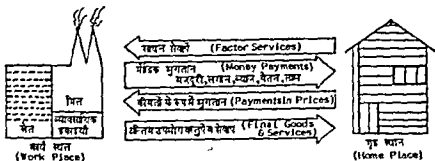
सरकार को जो आय होती है वह उसने द्वारा विभिन्न सेवाओं तथा सुविधाओं के रूप में जैसे प्रशासनिक व्यय, प्रतिरक्षा व्यय, सामाजिक कल्याण सेवाओं और सुविधाओं पर व्यय तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कर दिया जाता है और पुनः चक्राकार गति में शामिल हो जाता है। इसके अलावा जब सरकार की आय से उगड़ व्यय की पूर्ति नहीं होती तो यह नई मुद्रा की निर्यातों तथा बचतों को बढ़ाती है और नये विनियोगों को करती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण तथा नई मुद्रा फिर से चक्राकार गति में शामिल हो जाती है। मुद्रा की इस चक्राकार गति में उच्चावचन अर्थव्यवस्था को अस्थिरता प्रदान करते हैं इसलिए इस चक्राकार गति को सन्तुलन (Equilibrium) में रहना जरूरी होता है जय-जय इस गति में असन्तुलन उत्पन्न हुआ है तब-तब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता एवं अर्थव्यवस्था का वातावरण दिखाई दिया है। विश्व-व्यापी सीमा की मन्दी इस प्रकार की अस्थिरता का उल्लेख उदाहरण है। सीमा की मन्दी में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा पूँजी बाजार को अस्त-व्यस्त कर दिया था। चारों ओर बेरोजगारी, अति उत्पादन,

बाजारों में स्टॉकों में वृद्धि, उपभोग में गिरावट तथा निर्रतता का वातावरण छा गया था। दुनियाँ के अधिकांश देश मन्दी में प्रभावित थे। प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी में मुद्रा की चक्राकार गति में तेजी हो जाने से वहाँ अति स्फीति (Hyper Inflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुद्रा की चक्राकार गति में बिना कोई परिवर्तन हुए अर्थव्यवस्था अस्तन्तुलन की स्थिति में पहुँच जाती है। ऐसा प्रायः प्राकृतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के समय दिखाई देता है।

द्रव्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्राकार गति से हमारे जीवन की प्रगति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम यह मानूँ हाना चाहिए एक व्यक्ति की सोदरी भूमिका होती है। एक उपभोक्ता के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग करता है और उगका दूगका रूप उत्पत्ति के साधन के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं की निरन्तर पूर्ति बनाए रखना होगा है। हम यह भली-भाँति जानते हैं कि हम सभी उपभोक्ता भी हैं साथ ही साथ उत्पत्ति के साधन भी। उपभोक्ता की दृष्टि से हम भोजन, वस्त्र तथा मनान की भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुओं व अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करत हैं। एक कार्यरत व्यक्ति की भाँति हम सभी उत्पत्ति के साधन भी हैं और सरकारी कार्यालयों कारखानों, विद्यालयों, निजी क्षेत्र व अन्य किसी न किसी व्यवसायों में विभिन्न रूप में सेवाएँ प्रदान करते हैं और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति बनी रहती है। हमें अपनी सेवाओं व बदने में सेवाओंजवा से द्रव्य आय प्राप्त होती है जिसका हम विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाने हैं और अपनी आय के शेष भाग को द्रव्य के रूप में संचित करके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोड़ देने हैं।

जिस समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आगमन होता है तो हमें फनम्बल्य एक लेन-देन कार्य दूगरे लेन-देन कार्य की जन्म देता है। उत्पादन सेवाओं की गति का प्रम गृहस्थान (Home Place) से कार्य स्थान (Work Place) जैसे कारखाने, सेन अ्य माविक दनाइयो आदि की ओर होता है।



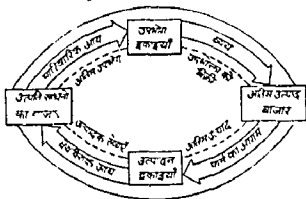
चित्र—(A)

उपर्युक्त चित्र में दिखाया गया है कि हम, अपनी साधन सेवाएँ सेतो, कारखानों अथवा मिलों व्यवसायिक इकाइयों आदि में प्रदान करते हैं और इन इकाइयों की आय उत्पत्ति के साधनों को मजदूरी, लगान, व्याज, वेतन तथा लाभ के रूप में मौद्रिक भुगतानों

के रूप में दे दी जाती है। जिनको पुनः वायंस्थलों के उत्पाद की कीमतों के रूप में दे दिया जाता है और अन्तिम उपभोक्ता वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की गति वायंस्थल से घर की ओर होती है जबकि मुद्रा की गति का प्रथम घर से वायंस्थल की ओर होता है। एक उत्पादन उत्पत्ति साधनों की सेवाओं की घर से सीधे प्राप्त न करने साधन बाजार (Factor Market) जहाँ यह साधन अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता उपभोग्य वस्तुओं (Consumer Goods) को वायं स्थल से सीधे प्राप्त न करने वस्तु बाजार (Commodity Market) से जहाँ वस्तुएँ बिची हेतु प्रस्तुत की जाती हैं प्राप्त करते हैं।

मुद्रा का चक्राकार प्रवाह की स्थिति को निम्नलिखित रेखाचित्र B द्वारा दिखाया जा सकता है।

### मुद्रा का चक्राकार प्रवाह



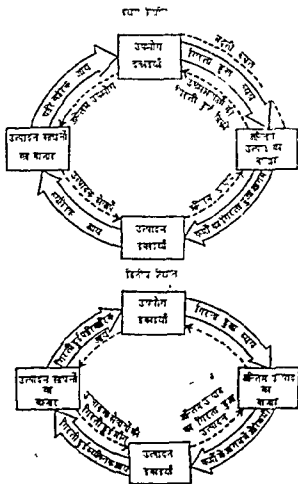
### चित्र—(B)

मुद्रा अर्थव्यवस्था में दो विपरीत दिशाओं में बहती रहती है। इसमें से एक धारा ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं की होती है जो अर्थव्यवस्था में आस्तियों की उत्पादन क्रियाओं का परिणाम है और दूसरी धारा का सम्बन्ध उन मोद्रिक भुगतानों से होता है जिनका उद्योग उस समय होता है जबकि आती सेवाओं के बदले में उत्पादों के साधनों को मोद्रिक पारिधमिक मिलता है। स्पष्ट है कि उत्पादों के साधनों को जो आय प्राप्त होती है उसका उपयोग के साधन बढ़ा तथा अन्य उपभोग्य वस्तुएँ (Consumer Goods) बाजार से खरीदने में व्यय करता है। बाजार के दुबानदार (पूटकर तथा भोज व्यापारी) कारखाना या उत्पादन केन्द्रों से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उपभोक्तियों तथा पँकड़ी के बीच एक मध्यक (Mediator) के रूप में कार्य करते हैं।

मुद्रा अर्थव्यवस्था में जब इस प्रकार की दोनों विपरीत धाराओं में परस्पर समानता रहती है तभी अर्थव्यवस्था में स्थिरता का वातावरण पाया जाता है। जिनसे भाव तथा उत्पादन दोनों ही में स्थिरता पाई जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह (Circulation of Money) में वृद्धि हो जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि क्रिस अनुपात में मुद्रा

प्रवाह में वृद्धि हुई है उभी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो जाए। ऐसी स्थिति को स्फीतिक स्थिति (Inflationary Stage) कहते हैं क्योंकि दम का कीमती-मूल्य उंचा उठने लगता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा प्रवाह में घटो हो जाए तो यह जखी नहीं है कि उभी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में हो जाए। ऐसी अवस्था मुद्रा संकुचन अथवा अस्फीति (Deflation) की होती है इसमें कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी और न्यून उद्योग की स्थिति दिखाई देती है। अर्थव्यवस्था मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा संकुचन उभी देना सुगइयों से तभी बची रह सकती है जबकि मुद्रा तथा वस्तुओं की विपरीत दायों की गति मनुजन में रह। इसके लिए यह आवश्यक है कि आवश्यकता की आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा चयन में उपयुक्त रह।

अर्थव्यवस्था में त्रिग समय तक मनुजन बना रहता है उस समय तक जादित प्रियाओं, जैसे उत्पादन तथा उद्योग का प्रम भी सुचारु रूप में बना रहता है। परन्तु जैन



चित्र (C)

मुद्रा के चक्रांतर प्रवाह की स्थितियां

ही मुद्रा की चक्राकार गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है ममस्त अर्थव्यवस्था लडखडा जाती है। मुद्रा की गति में बाधा के लिए प्रमुख रूप से दो कारण उत्तरदायी होते हैं। प्रथम तो यह बाधा आवश्यक रूप से मुद्रा में कमी तथा दूसरे आवश्यक रूप से मुद्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप दिखाई देती है। जब बैंक साधन निर्माण कम करने लगते हैं, पूर्वी विनियोजन उत्साहवर्द्धक नहीं होता तथा लोगों की बचतें बढ़ने तथा उपभोग घटन की प्रवृत्ति दिखलाता है तो अर्थव्यवस्था मन्दी के चक्र में फँस जाती है अर्थात् मुद्रा की चक्राकार गति में अधिक कमी आ जाती है। मन्दी के समय समय माँग (Effective Demand) में कमी आ जाती है। लोग द्वारा अधिक बचत की जाने लगती है। इससे उत्पादकों को आय में गिरावट होती है और मुद्रा की चक्राकार गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है जैसा कि उपरोक्त चित्र की प्रथम अवस्था से स्पष्ट होता है।

अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग द्वारा अपने व्यय में कटौती करने के कारण कुल समर्थ माँग (Effective Demand) में कमी आ जाती है। समर्थ माँग में गिरावट का असर रोजगार के स्तर तथा व्यक्तिगत आय पर पड़ता है। इससे कारण अर्थव्यवस्था में अवस्थिति स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस बात को उपर्युक्त चित्र में द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत दिखाया गया है। जब लोग अपनी वर्तमान आय की तुलना में व्यय अधिक करते लगते हैं तब अर्थव्यवस्था में स्फीतिक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रा की गति के आकार में वृद्धि हो जाती है जिससे कीमती रोजगार तथा व्यक्तिगत आय के आकार में वृद्धि हो जाती है और कुछ समय बाद अर्थव्यवस्था में सचयी स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

### सन्तुलन की समस्या (The Problem of Equilibrium)

जैसा कि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की दो धाराएँ विपरीत दिशाओं में निरन्तर बहती रहती हैं। इन दोनों धाराओं के प्रवाह को सन्तुलन में रखना एक कठिन कार्य होता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के आकार तथा प्रकार में लगातार परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं उदाहरण के तौर पर ममस्त ऊनी वस्त्र जिसका उत्पादन साल भर होता रहता है उसकी ऊन भेड़ों से लगभग एक ही समय प्राप्त की जाती है। हालाँकि ऊनी कपड़े का निर्माण ऊनी वस्त्र उद्योग में साल भर होता रहता है परन्तु ऊनी वस्त्रों की माँग केवल जाड़ों में ही होती है। उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में मौसमी परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं वे मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की धाराओं के प्रवाह में अनुन्तन उत्पन्न करते रहते हैं। उपभोक्ताओं की मनोवृत्तियों तथा तकनीकी विनास एवं प्रगति के कारण कुछ वस्तुओं की माँग जो पहले शून्य थी आज काफी अधिक दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन तथा आटोमोबाइल उद्योग के उत्पादों की माँग में निरन्तर वृद्धि होनी जा रही है। निम्नी आर्थिक सकट या प्राकृतिक प्रकोपों के कारण बहुत ही उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है क्योंकि उपभोक्ता की ऐसी स्थिति में यह मनोवृत्ति हा जाती है कि शायद भविष्य में इन वस्तुओं की उपलब्धि हो या न हो। नदीधाराएँ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, में उपभोक्ता की उपलब्धि बनी रहती है जिसके कारण उत्पादन उन्ही वस्तुओं को बनाते हैं जिनकी माँग उपभोक्ता करे या फिर अपने उत्पादकों के आन्तरिक तथा बाह्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उपभोक्ता भी अपने व्यय को स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं उनसे इस व्यवहार से अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं की माँग बढ़ती है तो कुछ की माँग बिन्दु ही समाप्त हो जाती है।



इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृतिक तथा मनुष्यवृत्त उपभोक्ता के व्यवहार आंदोलनिक विवादा आदि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को मनुष्यत्व में रखने के लिए यह जरूरी है कि मुद्रा के लिए मुद्रा के चक्राकार प्रवाह में परिवर्तन तथा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में होने वाले परिवर्तन में समन्वय बना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के मुद्रा अधिकारी को मुद्रा की पूर्ति में समय समय पर इन प्रकार परिवर्तन बनने चाहिए जिससे कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन उपभोग तथा वितरण में परिवर्तन होने पर उस दिशा में मुद्रा की पूर्ति भी परिवर्तित रहे। उदाहरणार्थ उत्पादन में वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़े और कमी होने पर मुद्रा की पूर्ति में भी कमी हो। ऐसा उम्मीद स्थिति में सम्भव होगा जबकि मुद्रा के प्रवाह या आवागमन सरकारी नियन्त्रण में हो। मुद्रा के प्रवाह या आवागमन दो बातों पर निर्भर करता है प्रथम मुद्रा की पूर्ति पर दूसरे मुद्रा के वेग पर। मुद्रा की पूर्ति पर सरकार का नियन्त्रण होता है और सरकार को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसमें समय समय पर परिवर्तन करने चाहिए। जबकि मुद्रा का वेग या प्रचलन वेग कभी स्थिर नहीं रहता और इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के प्रचलन वेग को मुद्रा की मात्रा उपभोग प्रवृत्ति नकद सौदों की प्रवृत्ति तरलता पसदगी साम्य सुविधाएँ आय की भुगतान की अवधि तथा भावी कीमत अनुमान आदि जैसे तत्त्व प्रभावित करते रहते हैं। मुद्रा की पूर्ति किसी समय 10 000 करोड़ रुपये है और उमवा आगत प्रचलन वेग 5 है अर्थात् एक रुपया प्रति दिन पाँच रुपये की वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान में प्रयोग में लाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में  $10\,000 \times 5 = 50,000$  करोड़ रुपये का वर्ष भर में वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। यदि अगले वर्ष मुद्रा की पूर्ति दस हजार करोड़ रुपये से बढ़कर बीस हजार करोड़ रुपये हो जाती है और इसके प्रचलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक लाख करोड़ रुपये का व्यय कीमती के दुगुने हान पर ही सम्भव होगा। यदि हम कीमती का स्थिर रहना है तो हम मुद्रा की पूर्ति तथा इसके प्रचलन वेग पर नियन्त्रण रखना होगा।

**सरकार तथा गति का आकार—**उपर्युक्त मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की गतियों के आकार में हमने सरकारी हस्तक्षेप की उपस्था की है। वास्तविकता यह है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा उत्पादन के स्तर को प्रभावित करती रहती है जिससे रोजगार तथा आय के स्तर भी प्रभावित होते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा धारित उसकी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं की गतियों के आकार तथा उमके प्रवाह पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

सरकार का विभिन्न प्रकार की सवाएँ, सुविधाएँ, कर्याणवागं योजनाएँ तथा अन्य कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं जिनमें मुद्रा की गति प्रभावित होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए जनता में विभिन्न प्रकार के कर तथा शुल्क आदि वसूल करती है। जब सरकार विभिन्न कार्यों को करने के लिए जनता से कर वसूल करती है तो मुद्रा की मात्रा की गति तथा भुगतान के रूप में जनता की ओर से हटकर सरकार कोप की ओर होती है। जब सरकार करों की आय को विभिन्न प्रकार की मावजनिक सेवाओं जैसे सड़क, पुल, विद्यालयों के निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अन्य विवादायी योजनाओं पर व्यय करती है उस स्थिति में मुद्रा की गति सरकार की ओर से हटकर जनता की ओर श्रमिका की मजदूरी, वसंचारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, ऋणदाताओं को व्याज, मजदूरी तथा विभिन्न सावजनिक योजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों के भुगतान तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के रखरखाव आदि पर व्यय कर दी जाती है। जब सरकारी व्यय

उमकी आय से अधिक हो जाता है तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की गति के आकार में वृद्धि हो जाती है। इससे विपरीत जब सरकार अपने व्यय में कमी करती है तो मुद्रा की गति में भी कमी जाती है। सरकार अपनी आय-व्यय को प्रतिवर्ष बजट के रूप में सगद में पेश करती है और इसका उद्देश्य जरूरी व्ययों को समायोजित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना होता है। उदाहरणार्थ वेजी ब्रूल में सरकार को अतिरिक्त बजट (Surplus Budget) बनाकर अपने व्यय में कटौती करना चाहिए और मन्दीकाल में घाटे के बजट (Deficit Budgets) बनाकर अपने व्यय बढ़ाने चाहिए जिससे रोजगार तथा आय का स्तर ऊँचा हो सके और मंदी काल में जो कीमत-स्तर में गिरावट आयी है वह मर्याद माँग (Effective Demand) बढ़ने के कारण ऊँचा हो सके। इस प्रकार सरकार अपने बजटों के माध्यम से अर्थव्यवस्था मुद्रा की गति को वांछित दिशा में लाती रहती है।

**मुद्रा का महत्व (Importance of Money)**

हम सब भलीभाँति परिचित हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में मुद्रा एक अद्वितीय वस्तु है जिसने उपभोग, उत्पादन, विनिमय विवरण तथा राजस्व के क्षेत्र को सुगम एवं विवक्षित बनाया है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा एक पहलू नहीं है जो मुद्रा के प्रभाव से अछूता रहा हो। आर्थिक विकास एवं प्रगति की कल्पना मुद्रा विहीन व्यवस्था में करना सम्भव नहीं है। काल्मावस्य तथा उनके समर्थकों ने समाज में आर्थिक दोषों के लिए मुद्रा को उत्तरदायी मानना इतने समाप्त करने की सिफारिश की थी और इसी के आधार पर रूस जैसे साम्यवादी देश में मुद्रा चलाने बोलशेविकों के 1917 की रूसी प्रान्ति के बाद सत्ता में आने पर लिया गया था परन्तु मुद्रा की समाप्ति से बहुत-सी आर्थिक गणनाओं तथा विकास के माँग में बाधाएँ उत्पन्न हो गई थी और पुनः मुद्रा व्यवस्था को अपनाया गया था। हम याद रखना चाहिए कि मुद्रा के यह दोष मनुष्य निर्मित हैं और इनमें समाज को बचाया जा सकता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ तथा उनके समर्थक विद्वानों से लेकर आधुनिक विचारकों तक मुद्रा से सम्बन्धित दृष्टिकोण मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालने में समर्थ हैं।

### पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in a Capitalist Economy)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व अद्वितीय है। पूँजीवादी व्यवस्था में इसे निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है --

(1) आर्थिक स्वतन्त्रता—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति चाहें वह उपभोक्ता हो, उत्पादन अथवा साहसी सभी अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं। अपने हितों की सुरक्षा के लिए स्वतन्त्र रूप से निणय लेकर वे अपनी गति की दिशा को निर्धारित करते हैं। यह कार्य मुद्रा द्वारा सुचारु रूप में किया जा सकता है।

(2) कीमत प्रणाली का आधार—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्रणाली पर आधारित होती है। कीमत प्रणाली स्वयं मुद्रा द्वारा निर्दिष्ट होती है।

मुद्रा वर्तमान समय में कीमत प्रणाली का आधार है। मुद्रा समाज में उपभोक्ता को दुर्लभ सामानों का निरर्थकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। कीमत-प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरोटों व्यक्तियों के भिन्न निर्णयों के मध्य समन्वय स्थापित होता है। इसके द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन व विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होते हैं तथा वैश्वीय प्राथिवागी के नियन्त्रण के बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, कीमत

प्रणाली के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रियाओं का योग या उपभोग-गणियों, प्रीयोगिता तथा माधनों की प्रति में होने वाले परिवर्तनों के साथ सम्बन्ध होता है।

पूर्वजावारी समाज में आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सभी परिवर्तनों का प्रथम प्रेरणा स्रोत बीमत्त प्रणाली होता है। समाज में किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होने से परिणाम-स्वरूप उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसने उत्पादन में वृद्धि पाती है। कीमत-प्रणाली अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों की कीमत परिवर्तनों का रूप देकर उत्पादन में पर्याप्त परिवर्तनों को सम्भव बनाती है। उदाहरणार्थ यदि उभाक्ताओं की गणियों में परिश्रम हो जाने के कारण किसी वस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत में अन्य वस्तुओं की कीमतों की तुलना में वृद्धि हो जावेगी। इससे उत्पादन उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कमी करेगा। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन में माधनों का उपभोग-गणियों की गणियों के अनुसार पुनर्वितरण सम्भव हो सकेगा। अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के माध्यम द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में मध्य उत्पादन माधनों का वितरण तथा पुनर्वितरण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'मुद्रा मूल्य गणियों का आधार है जिसमें सम्पूर्ण अर्थतन्त्र निर्देशित होता है।'

(3) आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक—सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ मुद्रा द्वारा ही निर्देशित होती हैं। उत्पादन उपभोग एवं वितरण के क्षेत्र में यह इस प्रकार काम करती है किम प्रकार की मशीन का तेल किसकी विलनाई (Lubricant) की आवश्यकता होती है। उत्पादन में वर्तमान बड़े पैमाने पर जटिलताओं को मुद्रा में सुचारु रूप में वित्त प्रदान की है। धन-विभाजन विशिष्टीकरण एवं त्वरणीय ज्ञान में उत्पादन के क्षेत्र का बहुत अधिक गुणवत्ता बनाया है जिसका पूरा अर्थ मुद्रा व्यवस्था को ही जाता है।

मुद्रा द्वारा वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के सभी माधनों का बँटवारा करन में सहायता मिलती है। प्रत्येक उत्पादन के माधनों का सेवाओं का मूल्यांकन करने उन्हें उचित वितरित करना सम्भव हो पाया है।

(4) सातल का आधार—पूर्वजावारी अर्थव्यवस्था सातल पर आधारित होती है। उत्पादन एवं व्ययगणियों के बीच में घन उधार लेकर पक्का माल करीबन है। मान बनाकर के जोर व्यापारियों को उधार पर देकर है। थोड़ा व्यापारी गुटार व्यापारों के लिए उधार देता है और गुटार व्यापारी अपने प्रायों के लिए उधार देता है। उधार लेन-देन का यह क्रम मुद्रा द्वारा गति प्राप्त करता है। उधार की एवं की गई रकम पर व्याज भा मुद्रा ही द्वारा तय होता है। इस प्रकार वर्तमान में एक व्यापारी वित्तना मात्र देकर भविष्य में वित्तना मुक्तान प्राप्त करता है, इसका आधार मुद्रा ही है। इस प्रकार मुद्रा-वित्तना तथा आर्थिक-वित्तना के बीच में एक-दूसरे के बीच में भी-सम्बन्ध-रखता है।

(5) पूर्ण निर्माण का साधन—पूर्वजावारी व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा वचनों को अधिनतम सामग्री योजनाओं में वित्तियोजित करने उत्पादन के स्तर का आवश्यकतानुसार आदर्श विन्दु तक ले जाया जा सकता है। समाज की छोटी-छोटी वषटों एवं वित्त होकर एक विनात रूप धारण कर लेती है जिनको छोटी-छोटी पूर्ण वित्तियोजन करने वाली पत्नी तथा वेशों एवं अन्य उधार देन वाली सरथाओं द्वारा वित्तियोजित करने-वित्तियोजन की गति को बढ़ाया जा सकता है। वषटों पूर्ण निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है जोर में वचनों माल माल की जाती है। इस प्रकार मुद्रा पूर्ण निर्माण करने

पूँजी की आवश्यकता का प्रति मरती है। प्रा० ट्रेसकाट (Prof Trescott) ने कहा कि मुद्रा हमारे अर्थतन्त्र का हृदय नहीं तो रक्त तो अवश्य ही है।

(6) आर्थिक प्रणाली की रीढ़ के रूप में—पूँजीवादी व्यवस्था में हाँ नहीं बरन् सभी प्रकार का व्यवस्थापन म मुद्रा न आर्थिक व्यवस्था का सभी महत्वपूर्ण धाना अंत उत्पादन, उपभोग विनिमय वितरण एवं राजस्व आदि का महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया है। आज राज्य का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का आधार ही मुद्रा है। अर्थशास्त्र का विभिन्न विभाग म मुद्रा का योगदान किसी ग छिपा नहीं है।

इतना ही नहीं मुद्रा न मनुष्य का आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ ही सम्पूर्ण अर्थतन्त्र का प्रभावित किया है।

### समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in a Socialist Economy)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व कम नहीं है। कुछ साम्यवादवादी विद्वानों ने मुद्रा का दावा को दूरते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व का प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण एवं सन्तुलन सरकार द्वारा होता है। जिसका उत्पादन किया किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाय मजदूरी का दर क्या हानी चाहिए उपभोग तथा वितरण व्यवस्था तथा वस्तुओं की कीमता का निर्धारण सरकार द्वारा होता है। सरकार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता बरन् अधिकतम सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का इन विशेषताओं का कारण दत्त व्यवस्था के समय का न मुद्रा का अनावश्यक वस्तु समझा था। निम्नलिखित कारणों से समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा की भूमिका नगण्य मानी जाना रही है—

(1) मुद्रा समाज में शोषण तथा आर्थिक शक्ति में बन्दोबस्त का साधन होता है इसलिए मुद्रा विहीन व्यवस्था अपनाकर इस दोष से बचा जा सकता है।

(2) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा संचालित एक नियन्त्रित होती है। समाजवादी व्यवस्था में निजी सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता जैसी चीजें व्यवस्था नहीं होती इसलिए मुद्रा अनावश्यक होती है।

(3) मौद्रिक व्यवस्था पूँजी निर्माण तथा निजी सम्पत्ति का बढ़ावा देता है जबकि समाजवादी व्यवस्था में ऐसी प्रणाली का कोई स्थान नहीं होता। सारी सम्पत्ति राष्ट्र की होती है जिसे पर एक मात्र अधिकार राज्य का होता है।

(4) समाजवादी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का द्विपक्षीय समन्वय का आधार पर चलने का पक्ष में होती है न कि स्वतन्त्र व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार का आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मुद्रा प्रणाली द्वारा किया गया विदेशी व्यापार मोपन को बढ़ावा देता है।

प्रमुख साम्यवादवादी प्रा० कार्ल मार्क्स ने मुद्रा का सभी बुराईयाँ का जड़ माना था और कहा था कि मुद्रा समाज में शोषण को बढ़ावा देती है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (The Theory of Surplus Value) उनका मुद्रा विरोधी अभियान का उत्कृष्ट उदाहरण है। मार्क्स ने इस सिद्धान्त का द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि धर्मियों का उनके धर्म का बराबर का हिस्सा नहीं मिलता और पूँजीपति मजदूरों का मुद्रा रूप में इजाजत का भाग नहीं लेते और यह जानी घटाता बढ़ावा कम होता है। धर्मियों का योगदान मुद्रा

व्यवस्था में हाता है। वह कहते थे कि धर्मिता व धर्म को अंकन में मुद्रा दापपूर्ण है। साम्यवादी व्यवस्था में मुद्रा का अन्त ही जायगा और वस्तुआ वा वस्तुआ में आदान प्रदान किया जाएगा। पाल माक्स व थिचारा में प्रभावित होकर मन् 1917 में वा-त्रोविक पार्टी कम में सत्तारूढ़ हुद् गौर उनमें कम में मुद्राविहीन अव्यवस्था का अगनात का सवल किया। धार्जेरिक पार्टी व सत्ता में आन व वाद सरकारी व्यय की पूर्ति व तिग रूगी सर-वार न अधिक मुद्रा का निकाली थी। मन् 1918 में मुद्रा स्फोटिक स्थितियाँ उभयानक रूप धारण कर लिया। मुद्रा स्फोटिक स्थितियाँ पर वार् पान की दृष्टि में सरगार न मुद्रा समाप्ति की धारणा थी परन्तु कुछ ही महीना बाद रूगी सरवार व सामन बहुत मी गणना सम्बन्धी कठिनाइयाँ आन लगी। आर्थिक याजनाआ व मू-याकन विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति तथा अन्य गणनाएँ बिना मुद्रा व सम्भव नहीं थी। सरगार के सामन मुद्रा व अभाव में बहुत सी कठिनाइयाँ आइ। मन् 1921 में महान शान्तिकारी तनिन न रूगी सरवार का मुद्राविहान अव्यवस्था अपनाव का आदेशना करत हुण कहा था वा-त्रोविका का यह विचार उनक जीवन की महान भूत थी कि समाजवादा गणना तथा नियन्त्रण की अवधि व बिना साम्यवाद आ सकता है। अक्टूबर 1921 में साम्यवादी विचारक ट्राटस्की न (Trotsky) यह ध पणा का थी मुद्रा व बिना आर्थिक याजनाआ का प्रगति का मही मूल्या-पन करना सम्भव नहीं है। प्रा० ट्राटस्का व शब्दा में सरकारी कार्यालयों में बनायी गयी याजनाआ की आर्थिक मायत्ता वाणिज्य गणनाआ के आधार पर आँकी जानी चाहिए। बिना एक सुदृढ मौद्रिक इगई व व्यापारिय उलावन एग गडबडी ही पैदा करमा।<sup>1</sup> लनिन तथा ट्राटस्का जैम महान साम्यवादी विचारक भी मुद्रा का समाजवादी व्यवस्था व तिए आवश्यक मानत थे। ट्राटस्की न ता यहाँ तक कहा है कि एक समाजवादी व्यवस्था में शक्तिशाली मुद्रा का हाना नितान्त आवश्यक है।

एक प्रसिद्ध विचारक प्रा० ए० पी० लनर का कहना है कि समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा अनावश्यक नहीं है। वे कहते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में कीमत प्रक्रिया (Price Mechanism) का विशेष महत्व है परन्तु समाजवादी व्यवस्था में भी यह आवश्यक है। उनका वे शब्दा में विमी भी प्रवार की कठिनाइयाँ ग भरी अव्यवस्था का बिना कीमत-प्रक्रिया व कुशलतापूर्वक करण सम्भव होता है।<sup>2</sup> एग अन्य मौद्रिक अवशास्त्री जार्ज एन० हॉम (George N. Halm) का कहना है कि समाजवादी अव्यवस्था में मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। व कहत हैं कि यद्यपि उत्पादन व वक्ष्य एग मानाजाह ठाग ही

1 The blue prints produced by offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculations. Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos."

—L. D. Trotsky

2 It is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency without a price—mechanism."

—A. P. Lerner

क्यों न निर्धारित किए जाएँ तो भी इन लक्ष्यों के अनुसार साधना का गृही प्रारंभ से बंट-बारा कीमत-प्रणिया के पलस्वरूप ही सम्भव होगा क्योंकि इसी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के उपलब्ध साधनों की उपयोगिता की तुलना की जा सकती है।<sup>1</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मुद्रा को अपनाए हुए हम अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चला नहीं सकते। वर्तमान समय में रूस चीन तथा अन्य कई समाजवादी देशों का उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ कि एक शक्तिशाली मुद्रा इकाई अपनायी जा रही है और वहाँ आर्थिक शोषण तथा आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण का अभाव पाया जाता है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था राज्य के अधीन है और वहाँ फिर भी विनिमय का माध्यम तथा हिसाब-किताब की इकाई के रूप में मुद्रा कार्य कर रही है। उत्पत्ति के साधना का पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में आना जाता है आर्थिक स्वतन्त्रता जो भी है वह राज्य के नियमों के अधीन है। राष्ट्रीय धेतन नीति के अनुसार तथा अधिकम वेतनों की दरें निश्चित है। रंग तथा चीन जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक साधनों का बंटवारा कीमत-प्रणाली (Price-Mechanism) द्वारा नहीं होता फिर भी मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व किसी भी प्रकार में कम नहीं है। इससे कुछ अपवाद समाजवादी व्यवस्था में हो सकते हैं जिनसे यह अर्थ बढ़ाए नहीं सगना चाहिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मुझार मुद्रा को अपनाए बिना काम कर सकती है। प्रसिद्ध मौद्रिक अर्थशास्त्री जॉर्ज एन० हॉम (George N. Halm) ने ठीक ही लिखा है कि "सामाजिक अर्थव्यवस्था सर्वेक एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था ही है और सम्भवतः ऐसी ही रहेगी।"

प्रायःकित एक परिवर्तित विश्व प्रणाली इन बात का उदाहरण है कि भले ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था साम्यवादी हो या पूँजीवादी या फिर एक नियोजित मुद्रा के अभाव में अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना सम्भव नहीं है। यह सही है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उतना महत्व नहीं है जितना कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है परन्तु फिर भी समाजवादी व्यवस्था मुद्राबिहीन अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। एक अन्व स्थान पर प्रो० आस्कर लॉंगे (Prof. Oscar Lange) कहते हैं कि "समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य पद्धति आर्थिक कार्य एवं ध्यापारों के युक्त माध्यम निर्देशन का कार्य करती है किन्तु जब तक मूल्य मुद्रा के अभाव में प्रवृत्त न किए जाएँ तब तक मूल्य पद्धति निरर्थक रहेगी।"

### एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व (Importance of Money in a Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका संचालन पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था रूस की तरह समाजवादी, भारत की तरह मिश्रित या फिर किसी प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था हो सकती है। नियोजित

1. "Even if the aims of production should be determined by a dictator the allocation of resources according to these aims would have to be the result of the working of a pricing process by means of which it is possible to compare the usefulness of the available resources in different fields of employment"

—George N. Halm

अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दी जाती हैं और फिर उनही के अनुगमन कार्य होता है चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, या उपभोग या अन्य आर्थिक विभाग का हो, केन्द्र एव राज्य सरकारों के वित्तीय सहायता की प्राप्ति एवं उनके वितरण का कार्य तथा सरकार की विभिन्न नीतियाँ नियोजित कार्यक्रम में आधार पर लागू होती हैं। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से भाँपा जा सकता है—

(1) मुद्रा का निर्देशित उपयोग—नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को निर्देशित एवं वांछित दिशा में करने का प्रयोग किया जाता है। देश के केन्द्रीय बैंक एवं अन्य ऋण प्रदान एवं सृजित करने वाली संस्थाओं का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन जल्दी-जल्दी न हो सके और राज्य की नीतियों में जनता का विश्वास बना रहे। प्राथमिकताओं को निश्चित करने उन्हीं के आधार पर कार्य किया जाता है जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास समुचित हो सके।

(2) धन के संकेन्द्रण पर रोक—ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों की आय तथा धन के संप्रहण पर भी उचित नियन्त्रण रखने का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि देश की सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित न हो सके। पूर्वी विनियोजन एवं आय सम्बन्धी नीतियाँ इस प्रकार निर्मित की जाती हैं जिससे शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिल सके तथा वितरण योजना देश के अधिन में अधिन नागरिकों को रहित पहुँचा सके।

(3) विकासा में सहायक—नियोजित अर्थव्यवस्था में विकास कार्यों की पूर्ति पाट के बजट बनाकर की जाती है। इस प्रकार नई मुद्रा विकास कार्यों को बढ़ावा देती है।

### मुद्रा के दोष (Evils of Money)

हम देख चुके हैं कि वर्तमान समय में चाहे अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो बिना मुद्रा के उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की गति प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा इस प्रकार से काम करती है जैसे कि मशीन को चलाने के लिए चिबनाई या तेल डालने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा भी आर्थिक क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए चिबनाई का कार्य करती है। यहाँ एक ओर मुद्रा ने हमारे लिए विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचाये हैं वहीं दूसरी ओर दूसरे कुछ दोष भी हैं। मुद्रा के यह दोष मुद्रा के स्वयं के न होकर मनुष्य निर्मित हैं। मुद्रा के बहुत से दोषों से बचा जा सकता है यदि व्यक्ति या समाज मुद्रा का उपयोग एक माधन के रूप में करे न कि साध्य के रूप में। मुद्रा तो हम एक सेवा ही मानें इसे स्वामी कभी न बनने दे। जब कभी भी हम अनापस्यक रूप से मुद्रा को महत्व देने लगते हैं या हमारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक जीवन की क्रियावृत्तियों का मूल्यांकन जब मुद्रा द्वारा ही किया जाने लगता है तो निश्चित रूप से मुद्रा में दोष हमारे सामने प्रकट होना है। मुद्रा के दोषों को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

(1) मुद्रा ने समाज को दो वर्गों अर्थात् हजूर-मजूर, धनी-निर्धन (Haves and Have-nots) में बाँट कर एक-दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न की है। धनी वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण अपनी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के कारण करता है। दूरी के बीच कटुता का वातावरण उत्पन्न हुआ है।

(2) मुद्रा ने आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जिससे नई-नई बुगारवादी समाज में उत्पन्न हो रही हैं।

(3) मुद्रा के चाल से उधार लेना देना सम्भव हुआ है जीव मीम अपनी आय से उपादा व्यय करने लगे हैं।

(4) मुद्रा ने समाज में स्पर्तित्व सिद्धियों को जन्म दिया है जिससे कीमती वस्तुओं की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है और निधन वर्ग जो पहले पेट भर भोजन करता था उसे कम भोजन से ही गुजारा करना पड़ता है। महेश्वर के अनुपात से मजदूरी या वेतन वृद्धि न होने से लोगो पर इसका बुरा असर पड़ा है।

(5) मुद्रा ने लोभ लालच भ्रष्टाचार तथा अन्य नैतिक दोष उत्पन्न किए हैं। आज समाज में चोरी, दकैती, भ्रष्टाचार, गिलाबट वगैरह नाम लौ लाल आदि बुराईयाँ अधिक मुद्रा को एवजित करने की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाई देती हैं।

(6) सामाजिक स्तर तथा व्यक्ति के सम्मान का आधार ध्यति के गुणों के स्थान पर मुद्रा ने ले लिया है।

मुद्रा के प्रति लोगो के बढ़ते हुए शुकव से यह महसूस किया जाने लगा है कि आज समाज में जहाँ मुद्रा ने विकास और प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है वही दुःखी और मुद्रा के प्रति लोगो का रझान बहुत अधिक बढ़ गया है। आज सामाजिक और नैतिक मूल्यो का पतन होता जा रहा है मुद्रा के कारण भाईचारे आपसी सौहार्द का वातावरण सम्भल होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ के आगे किसी का भी सबे से बड़ा नुकसान करने में नहीं हिचकिचाते हैं। मुद्रा जो अर्थो सेवक के रूप में मनुष्य को दोगा किए गए आविष्कारो में एक महत्वपूर्ण आविष्कार मानी जाती है मनुष्य जाति की बड़ी सेवा की है परन्तु आज के भौतिकवादी युग में मुद्रा के प्रति लोगो के बढ़ते व रझान और मुद्रा को आवश्यकता से अधिक महत्व देने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि मुद्रा हमारी रझामिनी बन गई है। मुद्रा के दोष मुद्रा की स्वामिनी रूप का ज्वलत उदाहरण है।

मुद्रा का नियन्त्रण - मुद्रा के बतारे गए उपर्युक्त दोष मुद्रा के स्वयं के नहीं हैं परन्तु यह दोष तो मुद्रा को आवश्यकता से अधिक महत्व देने तथा इमने दुरयोग के कारण उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य जाति के लिए मुद्रा को एक धरदान के रूप में स्वीकार करते हुए तथा इसके अनियन्त्रित होने पर मनुष्य के लिए अभिशाप बतारते हुए प्रो० राबर्टसन (Prof. Robertson) का कथन उपर्युक्त ही प्रतीत होता है। वे कहते हैं मुद्रा जो मानव समाज के लिए अनेक धरदानो का स्रोत है, यदि इस पर नियन्त्रण न रझा जाए तो यह सकट और अरुणस्थिति का कारण भी बन सकती है।<sup>1</sup>

प्रो० राबर्टसन के उपर्युक्त कथन का अर्थ यह है कि यदि हम मुद्रा को मनुष्य जाति का धरदान ही बने रहने देना है तो हमें इसको नियन्त्रित करना चाहिए। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक प्रो० वाल्टर बेजहाट (Prof. Walter Bagehot) ने भी मुद्रा पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका कहना था कि मुद्रा स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर सकती इसलिए मुद्रा अधिकारी को समय-समय पर देना की आवश्यकता-मुसार इसकी प्रती रखनी चाहिए। जिस समय दुनियाँ के विभिन्न देसो में रझमान तथा रझतमान अपना रझा था उस समय मुद्रा की प्रती में परिवर्तन देस में व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होते थे वरन् स्वयं तथा रझत धातुओं की उपलब्धि के अनुसार इनके परिवर्तन हुआ करते थे। इन धातुओं की मात्रों मिणने पर इनकी प्रती बढ जाती थी परिणाम-

1 'Money which is a source of so many blessings to mankind becomes also unless we can control it a source of peril and confusion'



स्वल्प इनका वनन या ती मुद्राओं की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती थी। वर्तमान समय में मुद्रा अधिवाहत १९-मुद्रा है जिसका स्वरूप तथा रजत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। आज के विकासवादी व प्रगतिशील युग में मुद्रा का उपयोग बहुत बढ़ गया है। मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन (Fluctuations) को रोकने का दायित्व देश के मुद्रा अधिकारी और वहाँ के केन्द्रीय बैंक पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके मूल्य में गिरावट (मुद्रा-स्फीति) तथा इसके मूल्य का बढ़ना (अनस्फीति) दोनों ही स्थितियाँ समाज के लिए घातक हैं और इनसे तभी बचा जा सकता है जबकि मुद्रा की पूर्ति इसके मूल्य में स्थिरता बनाय रहे। बढ़ते हुए भीतरवादी युग में जहाँ मुद्रा ने मनुष्य जाति के लिए अनन्त सुविधाएँ जुटाई हैं वही हमारी ओर इसके अनियन्त्रित प्रयोग से नैतिक और सामाजिक नुकसान में गिरावट आई है। मुद्रा के दोषों में बचने का सही तरीका यही है कि हम इन नियन्त्रण में रहें और इनको उतना ही महत्व दें जितनी कि आवश्यकता है।

### परीक्षा-प्रश्न

1. एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चक्राकार प्रवाह से आग क्या समझते हैं? रेखा चित्र द्वारा चक्राकार प्रवाह की स्थितियों को समझाएँ।

(What do you understand by the circular flow of money in an economy? Explain the stages of circular flow of money through diagrams)

2. अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाहों तथा मौद्रिक प्रवाहों में विभेद कीजिए। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के सुचारु रूप में संचारण के लिए मौद्रिक प्रवाह क्या आवश्यक हैं?

(Distinguish between Real Flows and Money Flows' in an economy Why are the money flows considered essential for the smooth working of modern Economics?)

[संकेत—अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाहों तथा मौद्रिक प्रवाहों को चर्चा कीजिए। प्रवाहों की स्थितियों को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अतः मौद्रिक प्रवाहों की बढ़ती हुई आवश्यकता को बताएँ।]

3. एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। पूँजीवाद अर्थव्यवस्था से यह किस प्रकार भिन्न है?

(What is the role of money in a Socialist economy? How is it different from that in a Capitalist economy?)

4. 'मुद्रा एक अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी है।' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(“Money is a good servant but a bad master” Explain this statement)

[संकेत—मुद्रा के लाभ एवं दोषों को बताएँ।]

एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को बताएँ।

(Discuss the importance of money in a planned economy?)

स्तुतिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

6 निम्नलिखित प्रश्नों में सही और ग़लत गनत है—

- (i) द्रव्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्राकार गति से हमारी प्रकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है।
- (ii) मुद्रा की चक्राकार प्रवाह की गति में बाधा उत्पन्न होना से समस्त अर्थव्यवस्था सडकराई जाती है।
- (iii) मदी के समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चक्राकार गति बढ़ती है।
- (iv) मुद्रा सिहीन अर्थव्यवस्था वर्तमान युग में सम्भव है।
- (v) मुद्रा का दोष स्पष्ट के न होकर अनुप्य निर्मित है।

स्तुतिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) सही है। (iii) ग़लत है। (iv) ग़लत है। (v) सही है।

' When we say that the value of a thing depends on supply and demand, we do not or at any rate ought not to mean more than that we think it will be convenient to arrange the causes of changes in value under those two heads  
— Cannon

अध्याय 14

## मुद्रा की पूर्ति तथा माँग

(THE SUPPLY AND DEMAND FOR MONEY)

अर्थशास्त्र में माँग और पूर्ति एक सामान्य सिद्धान्त है जिसका मूल्य निर्धारण सिद्धान्त में विशेष महत्व है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी माँग से बढ़ जाती है तो उस वस्तु का मूल्य गिरता है और जब वस्तु की माँग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है। माँग और पूर्ति का यह सामान्य सिद्धान्त जब मुद्रा पर लागू किया जाए तो इसको मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त कहा जाता है। हम मुद्रा की माँग और पूर्ति मुद्रा मूल्य निर्धारण अथवा मुद्रा परिमाण सिद्धान्त, से पहले अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) की व्याख्या मुद्रा की माँग और पूर्ति पर निर्भर करती है।

### मुद्रा की माँग (Demand for Money)

मुद्रा की माँग मुद्रा को प्राप्त करने के लिए नहीं बरन् इसलिए की जाती है कि यह मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अथवा इसकी माँग मुद्रा द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होती है। मुद्रा तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है, साध्य नहीं। मुद्रा की माँग बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान अथवा प्रय-विप्रय से सम्बन्धित होती है। मुद्रा की माँग निम्नलिखित कारणों से भी जाती है—

(1) विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा की माँग—परम्परावादी अर्थशास्त्रियों (Classical Economist) के दृष्टिकोण से मुद्रा की माँग केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए ही होती है। मुद्रा की माँग केवल इसलिए की जाती है कि उसमें प्रय-शक्ति की क्षमता होती है जिसके द्वारा बाजार से वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। मुद्रा की माँग प्रत्यक्ष न होकर व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) होती है। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की माँग उसमें निहित वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रय करने की क्षमता है। इस प्रकार मुद्रा की माँग का निर्धारण वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति द्वारा होता है। यदि किसी समय समाज के अन्दर लेन-देन अथवा विनिमय के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति बढ़ जाती है तो इसके आदान-प्रदान के लिए मुद्रा की माँग भी बढ़ जाएगी इसके विपरीत यदि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति गिर जाती है तो मुद्रा की माँग भी कम

हो जायगी। यदि हम ऐसा मान लें तो हमें पता चलता है कि किसी देश में एक निश्चित समयवाचि में विनिमय के हेतु उपर्युक्त वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा मुद्रा की माँग का निर्धारण करती है। इस प्रकार मुद्रा की माँग तीन बातों पर निर्भर करती है (i) वर्तमान समय में उत्पादन से प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य (ii) अन्तिम वस्तुओं का उत्पादन मूल्य (iii) उन वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जो भूतकाल में उत्पादित की गई थी अथवा जो वर्तमान में भी उपलब्ध हैं।

एक समयवाचि में विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति अनेक बातों से प्रभावित होती है जैसे उत्पत्ति के साधनों की स्थिति उत्पत्ति के साधनों के रोज-गार की मात्रा उत्पत्ति के साधनों की कार्य-क्षमता अथवा दक्षता तथा तकनीकी ज्ञान उत्पत्ति का पैमाना (Scale of Production) उत्पादन तथा उपभोग में अन्तर, वस्तुओं के हस्तान्तरण की गति तथा बाजार की स्थिति आदि। इनके अतिरिक्त जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, मुद्रा की पूर्ति तथा लोगों की आय आदि भी मुद्रा की माँग को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की माँग अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं संरचना द्वारा भी तय होती है। एक अर्द्ध-विकसित देश में मुद्रा की माँग विकसित देश की अपेक्षा कम होगी। मुद्रा की माँग से सम्बन्धित उपर्युक्त कारण अल्पकाल में स्थिर रहते हैं इसलिए अल्पकाल में मुद्रा की माँग भी स्थिर रहती है। इस प्रकार अल्पकाल में विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा की माँग स्थिर प्रवृत्ति की ओर सकेत करती है। प्रो० इरविंग फिशर (Prof. Irving Fisher) ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की ध्याय्या मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य से प्रभावित होकर की है। प्रो० फिशर भी प्रतिष्ठित अथवा परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के विचार से प्रभावित होकर ही मुद्रा माँग से सम्बन्धित मान्यता अर्थात् मुद्रा की माँग वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। परन्तु प्रतिष्ठित विद्वानों तथा प्रो० फिशर की यह मान्यता एक पक्षीय है क्योंकि मुद्रा की माँग भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तथा सट्टे से लाभ अर्जित करने के लिए भी की जाती है।

नकदों के लिए मुद्रा की माँग<sup>1</sup>—प्रो० फिशर की मुद्रा की माँग सम्बन्धित आलोचना को पढ़ते हुए कौन्सिल अर्थशास्त्रियों तथा कुछ आधुनिक विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की माँग मुद्रा के विनिमय के माध्यम कार्य को सम्पन्न करने के लिए ही केवल नहीं की जाती बल्कि मुद्रा की माँग उनके एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मूल्य संचक (Store of Value) के लिए भी की जाती है। इन विद्वानों की मान्यता है कि मुद्रा की माँग एक निश्चित समयवाचि में लोगों द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय में से नकदों रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की माँग का अर्थ नकद शेष (Cash Balances) से लगाया जाता है। हम यह याद रखना चाहिए कि जब कभी मुद्रा की माँग विनिमय माध्यम कार्य के लिए की जाती है तो इसका सम्बन्ध मुद्रा के चलन वेग (Velocity) तथा सभी प्रकार के लेन-देन से होता है जबकि नकद शेष के रूप में मुद्रा की माँग तथा उसके चलन-वेग का सम्बन्ध केवल उन वस्तुओं के विनिमय से होता है जो एक देश की कुल वास्तविक आय में शामिल होती है। इस प्रकार चलन वेग की आय-चलन वेग (Income Velocity of Circulation) की सजा दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि आय चलन वेग का आकार लेन देन चलन वेग की अपेक्षा छोटा होता है।

उपर्युक्त दोनों स्थितियों में मुद्रा की माँग की ध्याय्या हमें यह बताने में सहायता प्रदान करती है कि मुद्रा की माँग समाज में लोग द्वारा बिमलिये की जाती है। परन्तु इन दोनों उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की माँग किस उद्देश्य के लिए कितनी है अर्थात् मुद्रा की कितनी माँग लेन-देन के उद्देश्य (प्रतिष्ठित तथा प्रो० फिशर के दृष्टिकोण से)

1 तरलता परमदगी आवा मुद्रा की माँग की ध्याय्या अध्याय 9 में देंगे।

तथा मुद्रा की रितनी माँग उनके मूल्य सचय कार्यों (प्रो० रॉम्ब्रिज तथा आधुनिक सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से) के लिए की जाती है।

मुद्रा की माँग को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं—

$$M = M_1 + M_2$$

$M$  = मुद्रा की कुल माँग

$M_1$  = मुद्रा की माँग जो कि लेन-देन तथा मतभ्रंता उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है।

$M_2$  - मुद्रा की माँग जो, पट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है।

मुद्रा की माँग से सम्बन्धित मिल्टन फ्रीडमैन की व्याख्या—अर्थव्यवस्था में नोवेन पुरस्कार विजेता शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की माँग का आशय जनता के पास संचयित मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के विदेशी कोष एवं उनके चलन-योग से किया है। उनका कहना है कि मुद्रा की माँग और मूल्य-स्तर का विपरीत सम्बन्ध होता है। अर्थात् जब मूल्य-स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा की माँग (नगदी प्रवृत्ति) भी बढ़ जाती है वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा रखता एवं आवश्यक प्रिया समझता है। अन्य परिसम्पत्तियों को आगमदायक तथा विलासता सम्बन्धी आवश्यकताओं की भाँति समझता है। आय में वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिन अनुपात में परिसम्पत्तियाँ न बढ़ती हैं। परन्तु आय मुद्रा तथा परिसम्पत्तियों की मात्रा आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित होती है। प्रो० फ्रीडमैन की मुद्रा की माँग के विचार को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं—

$$M = f\left(P, Y \frac{1}{p} \frac{dp}{dt} - rb \text{ re } w, u\right)$$

$M$  = मुद्रा की कुल माँग

$f$  = फलन है

$P$  = मूल्य स्तर (Price Level)

$Y$  = कुल राष्ट्रीय आय (Total National Income)

$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt}$  = मुद्रा की एक इकाई के बदले में उपलब्ध भौतिक माल की मात्रा (Quantity

of Material Units Available Against one Unit of Money)

$rb$  = बाण्ड्स पर मिलने वाली ब्याज की दर (Rate of Interest Available on Bonds)

$re$  = अंशों पर लाभांश (Yields on Equities)

$w$  = सम्पत्तियों का मानवीय सम्पत्ति से अनुपात (Wealth and its Ratio with Human Wealth)

$u$  = उपयोगिता निर्धारित करने वाले वे तत्व जो अभिरचियों तथा प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। (Utility Determining Variables which tend to Influence Preferences)

प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि मुद्रा की माँग अर्थव्यवस्था में विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित होती है जैसे ब्याज की दर, आय, सम्पत्ति, मूल्य स्तर इत्यादि।

वास्तविक आय  $M$  जो परिवर्तन हाते है उसका विनिमय का स्तर प्रभावित होता है जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है। मुद्रा की मांग की लोच आय की मांग की साथ स अधिक होती है।

$$\text{अर्थात् } \frac{\Delta M}{\Delta Y} > 1$$

$\Delta M$  = मुद्रा की मांग में परिवर्तन

$\Delta Y$  = वास्तविक आय में परिवर्तन

प्रो० फ्रीडमैन व मुद्रा की मांग के समीकरण से स्पष्ट होता है कि मुद्रा नकदी की मात्रा जिस व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है उसकी आय में परिवर्तन व अनुपात से अधिक होता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

**मुद्रा की पूर्ति (Supply) of Money)**

मुद्रा की पूर्ति में वैधानिक मुद्रा अथवा साधारण मुद्रा तथा साख मुद्रा अथवा ऐच्छिक मुद्रा दोनों ही जाती है। एक देश की सरकार की जो मुद्रा होती है उसे सामान्य तथा उस देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार व आदेश पर निकाला जाता है। सरकार द्वारा निकाली जाने वाली मुद्रा को विधिप्राप्त मुद्रा (Legal Tender Money) कहते हैं। ऐसी मुद्रा को स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इस मुद्रा में कागजी मुद्रा तथा उसकी सहायक मुद्रा (Token Money) को शामिल किया जाता है। कानूनी मुद्रा व अतिरिक्त साख मुद्रा का भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। यह साख मुद्रा व्यापारिक बैंको द्वारा नियमित की जाती है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा की सजा भी दी जाती है न्यायिक साख मुद्रा की स्वीकृति अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होती है। साख मुद्रा का उपयोग साख मुद्रा सृजित करने वाली बैंकिंग तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। ऐसी मुद्रा प्रायः साख नियमित करने वाली संस्थाओं में निहित विश्वास पर आधारित होती है। साख मुद्रा एक प्रकार का ऐसा अधिकार अथवा दावा होता है जिसके आधार पर बैंक से साधारण अथवा कानूनी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार व अधिकार एक दावा को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे साख मुद्रा बैंक मुद्रा, जमा मुद्रा, बैंक बुक मुद्रा अथवा प्रतिस्थापित मुद्रा (Credit Money Bank Money Deposit Money, Cheque Book Money or Money Substitutes)। बैंकिंग साख-मुद्रा का प्रयोग भी विनिमय के माध्यम तथा अन्य मुद्रा के कार्यों के रूप में होता है इसलिए इसे भी मुद्रा की सजा दी जाती है। एक विकसित देश में विरामशील दल का अंश साख मुद्रा व चलन की परम्परा अधिक एवं सुविधाजनक समझा जाती है।

बैंक व पास जितनी जमा मुद्रा होती है वह भी विभिन्न प्रकार व जमा खाता में रहती है। चालू जमा खाते (Current Accounts) में मुद्रा जमा हानी है उन खातों को जमाकर्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व निवाला जा सकता है अथवा उन बैंक पर बैंक काउंटर निवाला जा सकता है इन्हें मांग जमा (Demand Deposits) कहते हैं। इनके अलावा सेविंग्स बैंक खाते (Savings Bank Accounts) में जमा राशि का भी नियमानुसार एक सप्ताह में धनराशि निकालने की सुविधा होती है इन्हें भी मांग जमा राशि में रखा जाता है अर्थात् मुद्रा की मांग जमाकर्ता द्वारा निकालने की सुविधा दी जाता है। एक जमाखाता निश्चितकालीन जमाखाता (Fixed Deposits) होता है जिसमें जमा का जान वाली राशि जमाकर्ता को एक निश्चित समयावधि अथवा एगो जमाअर्थ को परिपक्वता भवति पर ही दी जाती है। ऐसी जमाअर्थ को टाइम जमा (Time Deposits) भी कहते हैं।

यदि किसी जमाकर्ता को काल जमा से अपनी धनराशि निकालनी पड़ जाए या उसे परिपक्वता अवधि से पहले ही धनराशि की आयव्ययता पड़ जाए तो बैंक ऐसी धनराशि के निकालने पर ब्याज की दर थोड़ा अधिक लेकर जमाकर्ता को धनराशि दे गवता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहते हैं कि जमाकर्ता को ब्याज की सम्पूर्ण राशि के स्थान पर कम ब्याज देकर बैंक यह धनराशि वापस कर सकता है अथवा बैंक ने यदि इस सम्बन्ध में जो भी नियम बना रखे हैं उन्हीं के अनुसार इस प्रकार की जमा राशि परिपक्वता अवधि (Maturity Period) से पहले दी जा सकती है। काल जमा राशि में तरलता उतनी नहीं होती इसलिए इन्हें मुद्रा न कहकर अर्द्धजमा अथवा निरट मुद्रा (Quasi Money or Near Money) ही समा दी जाती है। बैंक मुद्रा की मात्रा निर्धारित करते समय देदान माँग जमाआ (Demand Deposits) को ही लिया जाता है। क्योंकि ऐसी जमाआ को हम बैंक पर चेक लिख कर बाट सकते हैं।

मुद्रा की मात्रा निर्धारित करते समय हमें कुल मुद्रा में तीन प्रकार की मुद्रा शामिल करनी चाहिए (1) देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित कागजी नोटों की मात्रा, (2) सरकार द्वारा निक्को की मात्रा (3) बैंकों में माँग जमा धनराशि। इस प्रकार किसी समयावधि में हमें मुद्रा की कुल मात्रा ज्ञात करने में उपर्युक्त तीन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।

### मुद्रा की प्रभावी पूर्ति (Effective Supply of Money)

सरकार या देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जो भी मुद्रा की मात्रा निकाली जाती है वह समस्त मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं की जाती। इसमें केवल प्रभावी मुद्रा की पूर्ति को ही लेना चाहिए। प्रभावी मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय उस मुद्रा की मात्रा में होता है जो कि चलन (Circulation) में होती है। मुद्रा की कुल पूर्ति का भी सामान्यतया हम दो भागों में बाँटते हैं। प्रथम वह भाग जो केन्द्रीय बैंक सरकारी खजाने तथा व्यापारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा (Reserve Money) के रूप में रखा रहता है। ऐसी मुद्रा कोष या पण्ड के रूप (Basic or Reserve Money) में रहती है चलन (Circulation) में नहीं। इसलिए मुद्रा की पूर्ति गणना में इनके केवल उसी भाग को लिया जाता है जो चलन में आ जाता है। दूसरे भाग में मुद्रा जिसका प्रचलन जनता के मध्य होता है जिसमें व्यक्ति, फर्म, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा निगम आदि आते हैं। मुद्रा की प्रभावी पूर्ति में कुल मुद्रा की मात्रा में हम दूसरे भाग यानि उस मुद्रा को शामिल करते हैं जो व्यय योग्य जनता के हाथों में पहुँचती है। इस प्रकार प्रभावी मुद्रा जानने के लिए हम मुद्रा की कुल पूर्ति में से उस भाग का निवान देना चाहिए जो कि केन्द्र सरकार, बैंक आदि के पास आरक्षित मुद्रा (Reserve Money) के रूप में रहती है। मुद्रा मूल्य निर्धारण में मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को ही मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त औसत रूप से मुद्रा की एक इकाई दिन में एक एक सम्प्राप्ति में कितनी मुद्रा का उपयोग करती है इसे मुद्रा का चलन-वेग कहते हैं और मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को उसके चलन-वेग से गुणा करने के बाद ही प्रभावी पूर्ति का पता लिया जा सकता है। प्रो० इरविंग फिशर ने अपन मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में कानूनी मुद्रा तथा मास्य मुद्रा के प्रचलन वेग को मुद्रा की पूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

### मुद्रा का चलन वेग (Velocity of Money)

मुद्रा के चलन वेग में आशय एक समयावधि में औसत रूप में मुद्रा की एक इकाई द्वारा कितनी इकाइयों का कार्य किया जाता है, से होता है। उदाहरणार्थ यदि एक समयावधि में औसत रूप में एक पाँचों में गुरुत्व है तो सामान्य में वह पाँच गुणा है परन्तु

चूँकि वह पाँच लोगों के हाथों से गुजरता है तो वह एक रुपये का पाय न करने पाँच रुपये का कार्य करता है इसलिए मुद्रा की प्रभावी पूर्ति  $1 \text{ रुपया} \times 5 = 5 \text{ रुपये}$  मानी जानी चाहिए।

मुद्रा विभिन्न प्रकार की होती है और उनका चलन-वेग भी अलग-अलग होता है। वानूनी मुद्रा तथा साख मुद्रा का प्रचलन में भी अन्तर पाया जाता है। इसी प्रकार माकेतिक अथवा सिक्कों के प्रचलन-वेग में अन्तर होता है। हम सभी प्रकार की वानूनी मुद्रा तथा साख मुद्रा का चलन-वेग औसत रूप से निकाल लेते हैं।

मुद्रा के चलन-वेग को हम राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित भी कर सकते हैं। जय हम मुद्रा के चलन वेग को राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित करते हैं तो हम एक निश्चित समयावधि (सामान्यतया एक वर्ष) में केवल उन्ही वस्तुओं तथा सेवाओं को लेन-दान में शामिल करते हैं जो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income) का प्रतिनिधित्व करती है। इसे मुद्रा आय प्रचलन-वेग (Income Velocity of Money) कहते हैं। मुद्रा के आय प्रचलन वेग की विचारधारा को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में अपनाया था जबकि प्रो० फिशर ने मुद्रा के नगद भुगतान-वेग (Transactions Velocity of Money) को मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में अपनाया है।

कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि वास्तविक आय में शामिल वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मुद्रा के प्रयोग की स्थिति उसी समय मानी जायेगी जबकि वह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के रूप में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार मुद्रा के आय प्रचलन वेग में मुद्रा के उस औसत को व्यक्त किया जाता है जो कि मुद्रा की एक इकाई के एक निश्चित समयावधि में अंतिम आय प्राप्तकर्ताओं के नगद शेषों में शामिल होता है या उससे बाहर निकलती रहती है। राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित मुद्रा के प्रचलन-वेग को हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं

$$V = \frac{NNP}{M} \text{ अथवा } \frac{PQ}{M}$$

$V =$  Velocity of Money (मुद्रा का प्रचलन-वेग)

$NNP =$  Net National Product at Current Prices (चालू मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय)

$P =$  Price-Level (कीमत स्तर)

$Q =$  Total Quantity of Goods Relating to National Income (कुल वस्तुओं की मात्रा जो राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित होती है।)

$M =$  Money Supply (मुद्रा की पूर्ति)

मुद्रा के प्रचलन वेग को निर्धारित करने वाले कारण (Factors Determining Velocity of Money)

मुद्रा के प्रचलन-वेग में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा का प्रचलन वेग निम्न तथ्यों द्वारा प्रभावित होता है—

(1) मुद्रा की उपलब्ध मात्रा—किसी समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन वेग पर मुद्रा की मात्रा अपना प्रभाव डालती है उदाहरणार्थ यदि उपलब्ध मुद्रा की मात्रा अथवा पूर्ति उगरी मांग की प्रेरणा अधिक होगी तो मुद्रा की एक इकाई का औसत चलन-वेग



कम होगा और मुद्रा की पूंति उसकी माँग से कम होगी तो मुद्रा का चलन-वेग भी अधिक होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में मुद्रा की एक द्वाई औसत रूप से अधिक बार वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन-देन में प्रयोग में लाई जाएगी।

(2) भुगतान की विधि—यदि लोग उधार लेन-देन की अपेक्षा नकद रूप से भुगतान करेंगे अथवा लोगों द्वारा भुगतान नकद मुद्रा के रूप में होगा तो मुद्रा का चलन-वेग औसत रूप से अधिक होगा।

(3) उपभोग प्रवृत्ति—लोगों में अधिक उपभोग प्रवृत्ति पाई जाएगी और वचत कम होगी तो मुद्रा का प्रचलन-वेग बढ़ेगा जबकि इनके विपरीत की स्थिति में होने पर यह कम होगा।

(4) उधार सौदों के भुगतान की अवधि—मुद्रा का चलन वेग इस बात पर भी निर्भर करता है कि अव्यवस्था में जिन सौदों का उधार लेन-देन होता है उनके भुगतान की अवधि कैसी है। उदाहरणार्थ यदि उधार लेन-देन की औसतन भुगतान अवधि कम है तो मुद्रा का चलन-वेग अधिक होगा और इसके विपरीत यदि उधार सौदों के भुगतान की अवधि अधिक है तो चलन वेग भी औसतन कम होगा।

(5) तरलता एसदगी—जब लोग नकदी अपने पास रखना अधिक पसन्द करेंगे तो मुद्रा का चलन-वेग औसतन कम होगा। इसके विपरीत लोग में तरलता एसदगी कम होने पर चलन वेग अधिक होगा।

(6) मजदूरी भुगतान का तरीका—सामान्यतया यदि अव्यवस्था में उत्पादक या साहसी अपने सन्धान में कायरत मजदूरों या देवतन भोगों कमचागिया को भुगतान लम्बे समय के बाद करते हैं तो चलन-वेग कम होगा क्योंकि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग नकदी अपने पास रखना अधिक पसन्द करेंगे। इसके विपरीत यदि भुगतान की विधि दैनिक या प्रति सप्ताह होगी तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा।

(7) मातायात तथा मवेशावाहन के साधनों की स्थिति—यदि देश में मातायात तथा मवेशावाहन के साधन उपरतिशाल ह तो इसमें वाजार तथा विनिमय का क्षेत्र व्यापक होगा और मुद्रा का चलन-वेग भी अधिक होगा।

(8) देश के सीमांत स्तर की प्रवृत्ति—यदि लोग को महवाभास हो जाय कि आने वाले समय पर वस्तुओं की कीमते बढ़ेंगी तो लोग वस्तुओं को अधिक से अधिक सग्रह करके अपने पास रखेंगे जिससे मुद्रा की इकाइयाँ को जन्दा-जन्दी विनिमय कार्य के लिए उपभोग में लाया जाएगा और उन्का चलन वेग बढ़ेगा।

(9) आर्थिक विकास की स्थिति—यदि देश की आर्थिक विकास का स्तर ऊँचा होगा तो इसमें विनिमय का स्तर भी ऊँचा होगा और मुद्रा का चलन-वेग बढ़ेगा इसके विपरीत स्थिति में मुद्रा का चलन वेग गिरगा।

(10) आर्थिक सम्पन्नता तथा बैंकिंग प्रणाली—जब देश में आर्थिक सम्पन्नता अधिक होगी और बैंकिंग प्रणाली का विकास होगा तो मातृ मुद्रा का प्रचलन-वेग भी बढ़ेगा इसके विपरीत स्थिति में होने पर प्रचलन-वेग गिरगा।

(11) राजनैतिक स्थिति—जिा देश में राजनैतिक स्थान्ति का वातावरण रहता है वही लोग स्वतन्त्रतापूर्वक उधार विनिमय क्रियाओं में भाग लेते हैं, परिणामस्वरूप मुद्रा का चलन वेग में वृद्धि होती है। वहीं राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है वही

लोगों में अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और यहाँ तक कि भयानक जन-दान अधिन करके ही परिणामस्वरूप मुद्रा का प्रचलन बेग में वृद्धि होता है।

### मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन (Changes in the Money Supply)

मुद्रा की पूर्ति का प्रायः तीन स्रोत ही प्रमुख हैं (1) सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति, (2) दण के केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति (3) बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति अथवा राजस्व मुद्रा। यह तीनों ही मुद्रा पूर्ति के सात विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ (Assets) का प्राप्त करत हैं और इन्हीं के आधार पर मुद्रा की पूर्ति का प्रभावित करत हैं और यहाँ इन सत्थाओं का दायित्व (Liabilities) हाते हैं जिनके भुगतान की जिम्मेदारी इनका ऊपर होती है। चूँकि यह दायित्व माँगने पर सामान्यतया देय (Payable on Demand) हान है इसलिए इन्हें ऋण तथा अन्य भुगतानों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। सरकार केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक द्वारा कुल मुद्रा की पूर्ति में समय-समय पर परिवर्तन इन सत्थाओं की मौद्रिक नीति द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। किसी समय एक देश में मुद्रा की पूर्ति में नया परिवर्तन हो जाते हैं। इसके लिए हम उपर्युक्त वर्णित तीन स्रोतों की मुद्रा निर्माण या पूर्ति प्रक्रिया को समझना होगा।

सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का पूर्ति में परिवर्तन दण की बानून मुद्रा की पूर्ति उस दण की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा की जाती है। इन दोनों का कार्यविधि तथा मौद्रिक नीति का देश की मुद्रा पूर्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सरकार तथा केन्द्रीय बैंक को नोट नियमन तथा सहायक मुद्रा निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य सात मुद्रा का नियंत्रण करना भी है इस कारण दण का केन्द्रीय बैंक अपने पास उपर्युक्त सात नियंत्रण विधियों (Methods of Credit Control) द्वारा दण का व्यापारिक बैंक की सात निर्माण शक्ति का वांछित दिशा में जान का लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। वह मौद्रिक तथा राजकाय नीतियों का माध्यम से अव्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकता है। दण का केन्द्रीय बैंक सरकार के एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है परन्तु फिर भी कुछ मामलों में वह स्वायत्त रूप भी बनाए हुए है।

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया दण का केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और 2, 5 10 20 50 100 तथा 500 रूपय के नोट रिजर्व बैंक द्वारा उभार भवन के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। इसके साथ ही एक रूपय का नोट गिरफ्त तथा 50, 25 20 10 5 3 2 तथा 1 पैसे के सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। किसी भी देश का केन्द्रीय बैंक चूँकि सरकार का नियंत्रण में होता है इसलिए वह नाटों की उत्पत्ति ही मात्रा जारी करता है जिनके लिए सरकार से उक्त आदेश प्राप्त होता है। अतः सामान्यतया में वह पुराने नाटों को प्रचलन से हटाकर नए नोटों का नियमन कर सकता है। सरकार का बड़त हुए दायित्व को दखते हुए अथवा सरकार की राजकाय नीतियों का प्रभावित होकर मुद्रा का पूर्ति में निरन्तर परिवर्तन होत रहत है। जब सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है तो इसका पूर्ति के लिए होनाय प्रबंध (Deficit Financing) की नीति अपनाती है। होनाय प्रबंध सरकार केन्द्रीय बैंक में जितने मुद्रा का निर्माण तथा आन्तरिक ऋणों (व्यक्तियों तथा बैंकों) द्वारा अथवा विदेश बाजारों द्वारा कर सकता है। जब यह ऋण व्यक्तियों अथवा बैंकों से लिए जाते हैं तो सरकार इन ऋणों का बदल में प्रस्तुतियाँ (Securities) बनती है जिनका प्रभाव यह होता है कि बैंकों का पान बाप में पड़ते हैं निश्चय मुद्रा का एक भाग सक्रिय मुद्रा का रूप धारण कर लता है। सरकार बना से जो

ऋण प्राप्त करती है उसे घाटे की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है जिनमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की इस पूर्ति का एक भाग सरकार द्वारा व्यय करने पर पुन बँकों के पास जमा राशि के रूप में पहुँच जाता है जो कि बैंकों की प्रारम्भिक जमाओं को बढ़ाता है परिणामस्वरूप बैंक की साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। यह स्थिति एक विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देश में पाई जाती है। अर्द्ध विकसित अथवा विकासशील देशों में माधनों की स्वल्पता सांख्यिक ऋणों पर सरकार की निर्भरता को सीमित करती है। इसलिए अर्द्ध-विकसित देशों में हीनाथ प्रवन्धन का मुख्य स्रोत सरकार द्वारा दश के केन्द्रीय बैंक से अधिक नोट निर्गमित कराने पर ऋण प्राप्त करना होता है। ऐसे ऋण की जमानत के रूप में केन्द्रीय बैंक को सरकार द्वारा वापसागार विपन्न अथवा प्रतिभूतियाँ (Treasury Bills or Securities) दी जाती हैं जिनके आधार पर नोट छापता है। इस प्रकार सरकार अपने बड़े हुए व्यय को पूरा करती है। इस प्रकार नोटों के प्रचलन से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और बैंकों की जमा पूँजी तथा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा भी प्रभावित होती है। चूँकि सरकार के पास मचित कोषों की मात्रा कम होती है और बाध्य ऋणों के लेन की मात्रा भी सीमित होती है इसलिए नोट निर्गमन बढ़ता है और कुल मिलाकर मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है।

दश में मुद्रा की पूर्ति बहुत कुछ उम देश की मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियाँ तथा उनके पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है। सरकार को दश को व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थितियाँ तथा आर्थिक विकास के स्तर द्वारा भी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन सम-यानुसार तथा आवश्यकतानुसार करना पड़ता है। दश की आवश्यकताओं के अनुमान से अधिक अथवा कम मुद्रा की पूर्ति होने पर दश के मूल्य-स्तर (Price-Level) वृद्धि अथवा कमी आती रहती है। जब-जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि देश के उत्पादन तथा राजगार के स्तर को बढ़ाती है तो इससे अव्यवस्था की प्रगति तथा लाभदायकता का संकेत मिलता है।

बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा—मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा भी शामिल होती है जिसे प्रायः बैंकों द्वारा निकाला जाता है। बैंकों की जमाएँ दो प्रकार की होती हैं (i) प्राथमिक जमाएँ (Primary Deposits) (ii) व्युत्पन्न जमाएँ (Derivative Deposits)। जब कभी भी लोग बैंक के पास अपनी नकदी को जमा कराते हैं तो इन्हे बैंक की प्राथमिक जमा राशि कहा जाता है। बैंक बैंकि बरूण्ड एकादश म जमा राशि को छोड़कर अन्य प्रकार की जमा राशियाँ पर अपने ग्राहकों को व्याज का भुगतान करता है और यह व्याज वह जमा धनराशियों पर तभी दे सकता है जबकि वह इन्ट्र ऋण माँगने वाले व्यक्तियों को उधार दे दे और ऐसे ऋणों पर व्याज की समूली बैंक ऋणियों से कर। बैंक ऋण माँगने वालों को नकद भुगतान न करके उनके नाम का खाता खोल देता है और उन्हें चेक बुक देकर चेकों द्वारा भुगतान देने की सुविधा प्रदान कर देता है। बैंक अपने नियमानुसार इस ऋण की कुल राशि का एक प्रतिशत नकद रखकर शेष धनराशि को पुन अन्य ऋणों को ऋण के रूप में देकर उसका खाता खोलकर उसके एक भाग को नकद रखकर शेष राशि को पुन ऋण के रूप में वितरित कर देता है। प्राथमिक जमा के आधार पर ऋण जो दिए जाते हैं वह बैंक की व्युत्पन्न जमा या साख जमा (Derivative or Credit Deposits) कहलाती है। बैंक साख जमा या साख मुद्रा वितरित निकालेगा यह बात बैंक की प्रारम्भिक जमा राशि की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। बैंकों को प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक जमा का एक अनुपात नकद कोष में रखकर शेष को अग्रिम (Advance) अथवा ऋण (Loan) के रूप में दे दिया जाता है। बैंकों की व्युत्पन्न जमा फिर बैंक मुद्रा का रूप धारण कर लेती है किन्तु ऋणों का निर्गमन या बैंक के नाम गटलर निगम लेता है। इसी के आधार पर

कहा जाता है कि ऋण जमा की सृष्टि करते हैं और जमा पुनः ऋण की सृष्टि करती है। व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposits) का निर्माण साख निर्माण कहलाता है। बैंकों के पास जितनी प्रारम्भिक जमा राशि होती है वही उससे 4-5 गुनी सारा मुद्रा का सृजन कर लेते हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि बैंक के पास कोई व्यक्ति 1000 रुपये जमा कराता है तो यह बैंक की प्रारम्भिक जमा कहलाएगी। बैंक इस प्रारम्भिक जमा का एक प्रतिशत यानि 10 प्रतिशत अपन पास रखकर अर्थात् 100 रुपये रखकर शेष 900 रुपये ऋण के रूप में उठा देगा। अब बैंक के पास यह 900 रुपये की धनराशि जमा हो जायेगी जो व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposit) कहलाएगी। बैंक फिर इस 900 रुपये में से 10 प्रतिशत यानि 90 रुपये रखकर शेष 810 रुपये अन्य किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा और यह उसका उस समय तक चलेगा जब तक कि उसने पास और ऋण पर उठाने के लिए धनराशि उपलब्ध ही नहीं रहेगी।

बैंकों की साख निर्माण शक्ति कुछ बातों पर निर्भर रहती है जैसे—(1) बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की माँग नकद रूप में न करके चेकों द्वारा निकालन की सुविधा होती है। (2) कुल जमाओं के एक निश्चित अनुपात से अधिक बैंकों को अपन पास नकद कोष नहीं रखने पड़ते हैं। (3) बैंकों से जनता द्वारा ऋण या अधिमो की माँग लगातार बनी रहे। (4) बैंक अपनी अधिकतम क्षमता तक ऋण देन को तैयार हों। बैंकों की साख निर्माण शक्ति भी असीमित नहीं होती। यह भी नकद कोषा द्वारा निर्धारित होती है। साख निर्माण दश में मुद्रा की मात्रा जनता की बैंकिंग आदतों, कुल देयताओं (Liabilities) का नकद कोष में प्रतिशत व्यापारिक बैंकों का केन्द्रीय बैंक के पास जमा धनराशि या कोष, केन्द्रीय बैंक की साख सम्बन्धी नीति, जमाकर्ताओं की बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्थिति, प्रतिभूतियों के स्वभाव तथा वानुसी तरल कोषानुपात पर निर्भर करती है। फिर भी हम यह सरते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में बैंक अधिक साख मुद्रा का निर्माण कर लेते हैं।

भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप—भारत में मुद्रा की पूर्ति क्या है इसमें सम्बन्धित हम रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक स्टॉको की व्याख्या करेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए मुद्रा को चार भागों में बाँटा है जैसे  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  तथा  $M_4$  आदि।

$M_1$  = जनता के पास उपलब्ध चलन की मात्रा + बैंकों के पास माँग जमाएँ (अन्तर बैंक जमाओं को छोड़कर) + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ (अर्द्ध सरकारी सस्थाओं की माँग जमाएँ + विदेशी सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व-बैंक की माँग जमाएँ)

$M_2$  =  $M_1$  + पोस्ट ऑफिस बचत खातों में चलन जमाएँ

$M_3$  =  $M_2$  + बैंकों के पास काल जमाएँ (शुद्ध अन्तर बैंक जमाएँ)

$M_4$  =  $M_3$  + पोस्ट ऑफिस में कुल जमाएँ (न कि केवल चलन जमाएँ)

भारत में  $M_1$  की जो परिभाषा दी गई है उसका सङ्कुचित अर्थ है। मुद्रा की परिभाषा अत्येक दश के स्थापित कार्यक्रमों के आधार पर दी जाती है। ब्रिटेन में  $M_1$  की गणना करते समय बैंकों के तुलन-पत्र (Balance Sheet) में 60 प्रतिशत चलन-मुद्रा (Transit Items) को घटा देते हैं। इसी प्रकार  $M_3$  में  $M_1$  + निजी क्षेत्र की काल जमाओं (Time Deposits) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी जमाओं (विदेशियों की जमाओं को छोड़कर) की गणना की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A) में  $M_3$  को दर्शाया जाता है जिसमें चलन मुद्रा, व्यापारिक बैंक की जमाएँ तथा बैंकों की आपसी जमाएँ (Mutual Deposits) तथा ऋण संघ (Loan Associations) तथा बन्ने जमाओं के समस्त पत्रा आदि का शामिल किया जाता है।

मुद्रा की पूर्ति ( $M_1$ ) को परम्परागत विचारधारा के अनुसार हम सबल चलन मुद्रा तथा माँग जमाआ का ही शामिल किया जाता है क्योंकि यही विनिमय व माध्यम तथा मूल्य संचय काय को भरोसा मिलाने सम्पन्न करती है। आज की जाधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत सी ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ (Assets) हैं जो विनिमय के माध्यम तथा मूल्य संचय काय को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करती हैं। इन्हींमें शिवायो सम्प्रदाय (जिसमें प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन तथा वाय शामिल हैं) के अनुसार चलन मुद्रा तथा माँग जमाआ व माधवात्त जमाआ (Time Deposits) को भी मुद्रा की पूर्ति  $M_1$  में जानना चाहिए। प्रो० गुर्ले तथा प्रो० शा (Prof Gurley and Prof Shaw) का कहना है कि चलन मुद्रा तथा माँग जमाआ वित्तीय माध्यमों के परिवार के दो बड़े सदस्य हैं जो तरल व साथ ही मूल्य संचय का भी काय करते हैं। इन दो व अतिरिक्त बचत खातों में जमाएँ काय जमाएँ यूनिट्स (Units) अथवा (Shares) तथा ऋण पत्र (Debentures) आदि कुछ अन्य मद भी हैं जो तरल मुद्रा तथा मूल्य संचय काय को भरोसा मिलाने सम्पन्न करती हैं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अध्यापिका का सुझाव है कि विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के मौद्रिक औसत (Monetary Aggregates) का प्रयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रो० सुखमय चन्द्रवर्ती समिति ने सुझाव दिया है कि  $M_1$  का उपयोग मौद्रिक नीति के निर्धारण में मौद्रिक चर (Monetary Variable) के रूप में करना चाहिए।

### शक्तिशाली अथवा उच्च शक्ति युक्त या प्रारक्षित मुद्रा (High Powered or Reserve Money)

भारत में उच्च शक्ति युक्त अथवा शक्तिशाली मुद्रा अथवा प्रारक्षित मुद्रा की व्याख्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा इन प्रकार की गई है।

उच्च शक्ति युक्त मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें निम्नलिखित मद शामिल की जाती हैं—

- (1) जनता के पास चलन मुद्रा।
- (2) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के शेष (Balances)।
- (3) व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के पास नकदी।
- (4) रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ।

शक्तिशाली अथवा उच्च शक्ति युक्त मुद्रा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा की पूर्ति से होता है। किसी भी प्रकार शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा बढ़ाते मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होगी। 1970 के दशक में यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों चरों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। प्रो० सुखमय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि भारत में शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को प्रदान की जाने वाली मात्रा के कारण हुई है। इसलिए यदि सरकार वास्तव में मुद्रा की पूर्ति पर काबू पाना चाहते हैं तो उस शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना होगा।

भारत में 1980 के दशक में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा भारत सरकार को साध्य (Credit) अधिक प्रदान करने के कारण शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। सरकार को ऋण प्रदान करने या सरकार द्वारा अपना बकाया चुकाया जाये, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक में ऋणों का माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। मन्, 1970 से भारत में

प्रारक्षित अधवा शक्तिशाली मुद्रा की माँग के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति में तर्जो स वृद्धि हुई है। सन् 1970 के दशक में बाजार बँकों की शाखा विचार योजना का ध्यान में रखते हुए प्रारक्षित मुद्रा की माँग की इस वृद्धि का परिणाम यह हुआ है कि चलन-जमा-अनुपात में गिरावट आई है। रूबि रिजर्व बैंक का इस प्रारक्षित मुद्रा की माँग पर जोई नियन्त्रण नहीं है इसलिए उस मुद्रा गुणव जैस नकद-बाच-अनुपात (Cash Reserve Ratio—CRR) को मुद्रा की पूर्ति के नियन्त्रण हेतु चुनना पना है।

### परीक्षा-प्रश्न

1. मुद्रा की माँग से आपे क्या समझते हैं? यह किन उद्देश्यों के लिए की जाती है? (What do you understand by the demand for money? For what objectives the demand for money is made?)
2. मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न अंगों का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि उनमें परिवर्तन किन कारणों से होता है? (Analyse the various components of the supply of money and explain the factors responsible for variation in them)
3. मुद्रा की माँग और पूर्ति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। (Discuss the factors determining the demand and supply of money.)
4. शक्तिशाली मुद्रा की परिभाषा कीजिए। इसमें परिवर्तन के बौत-बौत से सोत हैं? (Define High Powered Money. What are the sources of its changes?)

[सकेत— उच्च शक्ति युक्त मुद्रा का अर्थ बताने के बाद हमने विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए तथा अन्त में बताइए कि मुद्रा की पूर्ति का शक्तिशाली मुद्रा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसमें परिवर्तन सरकारी इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। सरकार रिजर्व बैंक में वन कल्प ने तो उचित होगा।]

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

5. निम्न कथनों में कौन सही तथा कौन गलत है—
  - (i) मुद्रा की माँग व्युत्पन्न होती है।
  - (ii) मुद्रा की माँग केवल विविध माध्यम के बायें हेतु होती है।
  - (iii) मुद्रा की पूर्ति में बंधनिक तथा साख मुद्रा शामिल होती है।
  - (iv) भारत में एक रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होने हैं।
  - (v) शक्तिशाली मुद्रा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा की पूर्ति से होता है।

सम्पुनिक प्रश्नों के उत्तर

- (i) गही है। (ii) गलत है। (iii) गही है। (iv) गलत है। (v) गही है।

"There cannot, in short, be intrinsically a more insignificant thing in the economy of society than money, except in character of a contrivance of sparing time and labour"

—J S Mill

अध्याय 15

## मुद्रा परिमाण सिद्धान्त

(QUANTITY THEORY OF MONEY)

पुराने अथवा परम्परावादी अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने मुद्रा को अधिक महत्व नहीं दिया था उनकी दृष्टि से मुद्रा से अधिक महत्वहीन कोई वस्तु नहीं होती है। एडम स्मिथ जैसे विद्वान न मुद्रा की तुलना उम पक्की सड़क से की है जिस पर स्वयं एक घास की पत्ती भी नहीं उगती। मुद्रा को अनुत्पादक एवं महत्वहीन बताते हुए इन विद्वानों ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि मुद्रा किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव नहीं डालती। यह विद्वान फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रो० जे० बी० से (Prof J B Say) व बाजार नियम जिसके अनुसार 'पूति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न कर लेती है।' (Supply Creates its own Demand) से प्रभावित थे। इन विद्वानों की ऐसी धारणा थी कि मुद्रा की आवश्यकता केवल वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रयत्न-विश्रय करने के लिए होती है अर्थात् मुद्रा विनिमय मौदो को निपटाने का एक साधन मात्र है। उनकी दृष्टि से एक मौद्रिक व्यवस्था में नून रोजगार की मात्रा, कुल उत्पादन की मात्रा, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रकार और उनके अनुपात जिनका उत्पादन तथा उपभोग होता है, बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, समाज में सम्पत्ति और आय का वितरण आदि एक विकसित अर्थव्यवस्था में समाज के लोगों के बीच ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि एक कुशल वस्तु-विनिमय अर्थव्यवस्था में होता है। इन विद्वानों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से देन-देन हो या फिर वस्तुओं तथा सेवाओं का देन-देन वस्तुओं तथा सेवाओं द्वारा हो, इसमें कोई फास अन्तर नहीं पड़ता।

प्रतिष्ठित विद्वान यह तो समझत थे कि मुद्रा ने विनिमय को सुविधाजनक एवं सरल बना दिया है परन्तु इस अतिरिक्त मुद्रा स्वयं कोई उपयोगिता प्रदान नहीं करती, मुद्रा एक अनुत्पादक (Unproductive) वस्तु है। प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक प्रो० जे० एम० मिल (Prof J S Mill) ने मुद्रा के महत्वहीन स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहा है कि "सधोप म, मुद्रा में महत्वहीन वस्तु सामाजिक अर्थव्यवस्था के अन्दर कोई ही नहीं सबती, यह समय और श्रम की बचत करने का कार्य करती है। यह उम मर्गीन की भाँति है जो कि कार्य को जल्दी और सुविधापूर्वक करती है और इसकी अनुपस्थिति में यह कार्य कम शीघ्र और सुविधापूर्वक सम्पन्न होगा, अन्य बहुत सी मर्गीनगियों की भाँति,

दस्तावेज अलग और अलग स्वतन्त्र प्रभाव होता है उरार्थ यह तर्क तर्कन योग्य न रहे।<sup>1</sup>

मुद्रा तब नै अस्तित्व में आती है इसमें स्थिरता का अभाव पाया गया है। मुद्रा ने अपने बायों को हमलिय भरती प्रहार में नहीं निभा पाया है क्योंकि इसके मूयों में उष्वा-यचनों को समय-समय पर अनुभव किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मोषने से कि मुद्रा के मूयों में परिवर्तन धागित या अन्य समय के लिए तो हो सकते हैं परन्तु दीर्घकाल में स्वयं अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियाँ नियोजित हो जावेगी जो इसके मूय में स्थिरता नै आयेगी। प्रतिष्ठित विद्वान् कहते से कि मुद्रा अपने बायों को सुधाररूप में करती है अर्थात् विनिमय का माध्यम और मूय मापन का कार्य मुद्रा भतीभती गम्भादिन करती रहती है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि प्रतिष्ठित विद्वानों का यह धारणा मानने योग्य नहीं है। आधुनिक विद्वान् कहते हैं कि मुद्रा हमेशा एक प्रहार में बायें नहीं कर पाती इसकी शक्ति और मूय में निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं जिनसे रोजगार तथा उत्पादन की कुल मात्रा, स्थानिय वस्तुओं की कीमते जिनका त्रय-विषय होता है तथा समाज के लोगों के मध्य वास्तविक सम्पत्ति तथा आय का वितरण प्रभावित होता रहता है। अन्ततः मुद्रा के यह प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होने हैं और जो कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक व्यवहार को प्रभावित करने हैं क्योंकि दीर्घकालिक व्यवस्था छोटी-छोटी या अन्ततःकालिक व्यवस्था की ही एक अनुमान मात्र ही बहो जा सकती है। मुद्रा के मूय में परिवर्तन ही इन सारी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। यदि मुद्रा को अधिक वस्तुओं तथा स्थानिय भूतानों का एक महत्वपूर्ण कारक बनना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि मुद्रा के मूयों में स्थिरता बनी रहे। परन्तु अनुभव इस बात का सार्थक है कि हममें स्थिरता नहीं रहती।

प्रो० जे० एम० बीन्स ने परम्परावादी विद्वानों के इस विचार को शक्यत किया कि मुद्रा एक आवरण मात्र है। प्रो० बीन्स कहते हैं कि मुद्रा हमन भी महत्वपूर्ण है गतिशास्त्री और विविध वस्तु है जो कि विनिमय का माध्यम मूय मापन, स्थानिय भूतानों का मान तथा वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक बहो है और यह आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीन्स कहते हैं कि मौद्रिक क्षेत्र सामान्य आर्थिक व्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। बीन्स की उत्तरत ध्योरी (The General Theory of Employment Interest and Money—1936) मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था के विज्ञान के रूप में जानी जाती है अर्थात् त्रिमेहन उत्पादन का मौद्रिक विज्ञान कहते हैं जिनमें ध्योरी को दर्श, जो कि मुद्रा की माँग और पूर्ति द्वारा निम्नित होती है, एक

1. "There cannot in short, be intrinsically a more significant thing, in the economy of society, than money, except in the character of contrivance of sparing time and labour. It is a machine for doing quickly and commodiously, what would be done though less quickly and commodiously, without it, and like many other types of machinery, it only exerts a distinct and independent influence of its own when it gets out of order"

—J. S. Mill



महत्वपूर्ण भूमिका जरा जरा से। नीम्न के अनुसार मुद्रा व्याज की दर को प्रभावित करती है जिसके द्वारा निम्नियोग प्रभावित होता है और जो सामान्य आर्थिक क्रिया उत्पादन तथा रोजगार पर अपना प्रभाव डालती है।

एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में एक साहसी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। एक साहसी द्वारा अधिक उत्पादन उसी समय किया जाएगा जबकि उस लाभ मिलने की सम्भावना हो। मुद्रा के मूल्य में उल्थावचन साहसी या उत्पादन की आशंकाओं को प्रभावित करते हैं जो कि उनकी व्यापारिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। जब कीमतें घटती हैं तो साहसियों ने लाभ बढ़ते हैं क्योंकि घड़ी हुई लागत से अधिक कीमतें बट जाती हैं और साहसी इस बड़े हुए लाभ से प्रभावित एवं उत्साहित होकर अधिक उत्पादन और पूँजी निर्यात करने लगते हैं। जब कीमतें गिरती हैं तो उदात्त यह उल्थाहक समाप्त होना लगता है और उन्हें हानि उठाने पड़ती है।

ऐसी स्थिति में हम यह जानना जरूरी होता है कि मुद्रा के मूल्य को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री समझते थे कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति महत्वपूर्ण होती है जिसको उन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के द्वारा बताया है। वे कहते हैं कि किसी देश का सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति द्वारा ही तय होता है यदि अन्य बातें समान रहें (Other Things being Equal)। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या से सम्बन्धित हम निम्नान्त विद्वानों के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे।

**मुद्रा परिमाण सिद्धान्त—लेन-देन दृष्टिकोण (Quantity Theory of Money—Transaction Approach)**

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Prof Irving Fisher) के नाम से विख्यात है। परन्तु प्रो० फिशर से पहले भी इस सिद्धान्त की व्याख्या के चिह्न मिलते हैं। इनके प्रतिपादक सोन्डो गेताञ्जी में इटली के लेराय देवनज्जो (Devanzatti) थे। बॉटिन (Bodin) कैंटिलोन (Cantillon) तथा डेविड ह्यूम (David Hume) के लेखन कार्यों में भी इसका उल्लेख है। बाद में प्रो० जे० एम० मिल तथा प्रो० एफ० एन्ड्रू० टॉसिंग (Prof J S Mill and Prof F W Taussing) ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या अपना-अपने ढंग से की है।

**प्रो० जे० एम० मिल के शब्दों में**

‘अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का मूल्य अपनी मात्रा के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसने मूल्य में कमी तथा मात्रा में प्रत्येक कमी में उसने मूल्य में आनुपातिक वृद्धि होती है।’

**प्रो० टॉसिंग के शब्दों में**

‘अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो वस्तुओं का मूल्य पहले से दुगुना और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो वस्तुओं का मूल्य पहले से आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जाएगा।’

प्रो० जे० एम० मिल तथा प्रो० टॉसिंग भी मुद्रा मूल्य की परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि इन विद्वानों ने मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध उसकी मात्रा से जोड़ा है, जिसमें मुद्रा की माँग को कोई महत्व न देकर मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है इसलिए इसे मुद्रा परिमाण की बजाय भी कहें।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के चार प्रमुख निष्कर्ष हैं—

(1) मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के मूल्य में उल्टा या विपरीत सम्बन्ध होता है।

(2) मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तु के मूल्य में सीधा सम्बन्ध होता है।

(3) मुद्रा की पूर्ति तथा उसके मूल्य में जो सम्बन्ध होता है वह आनुपातिक होता है।

(4) मुद्रा की पूर्ति तथा उसके मूल्य का आनुपातिक सम्बन्ध उभी स्थिति में आनुपातिक होगा जबकि अन्य बातें समान रहे।

अन्य बातें जो समान रहनी चाहिए—इसका आशय यह है कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त तभी लागू होगा जबकि निम्नलिखित स्थितियाँ बनी रहें अर्थात् कुछ दशाओं में ही मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के निष्कर्ष लागू होंगे जैसे—

(1) मुद्रा की माँग स्थिर रहनी चाहिए अर्थात् व्यापारिक औद्योगिक तथा घनिष्ठत उपभोग के लिए मुद्रा की माँग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(2) मुद्रा द्वारा ही समाज में सम्पूर्ण लेन-देन (Transactions) होना चाहिए। यदि वही वस्तु-विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत लेन देन हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करके उसे मुद्रा मूल्य में परिवर्तित करके उसकी गणना करनी जानी चाहिए।

(3) साल तथा मुद्रा का निश्चित अनुपात बना रहता है। इसका आशय यह है कि बैंक में कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग नकद मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार जमा रकम तथा नकद कोष और जमा रकम तथा उधार में एक निश्चित अनुपात बना रहता है। इसी अनुपात पर किसी देश में साल की मात्रा निर्भर करती है।

(4) मुद्रा का चलन-वेग (Velocity) मुद्रा की कुल मात्रा को प्रभावित करता है। यदि इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहे तो इसका प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर भी पड़ता है। इसलिए मुद्रा के चलन-वेग को स्थिर मान लिया गया है।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त से सम्बन्धित फिशर की धारणा

अथवा

लेन-देन अथवा सौदा दृष्टिकोण

Prof Fisher's Approach Regarding Quantity Theory of Money

Or

Transactions Approach

अमरीकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Prof Irving Fisher) ने सन् 1911 में अपनी पुस्तक 'Purchasing Power of Money' में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को व्याख्या की है। प्रो० फिशर के शब्दों में 'परिमाण सिद्धान्त क्या है कि (यदि चलन वेग और व्यापार की मात्रा अपरिवर्तित रहे) हम डॉलर की मात्रा में वृद्धि करे चाहे वह वृद्धि सिक्कों की जगह नोटों या सिक्कों की वृद्धि द्वारा हो, तब भी उभी अनुपात में बढ़ेगी।' प्रो० फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या में मुद्रा के विनिमय क

1 'The quantity theory asserts that (provided the velocity of circulation and the volume of trade are uncharged) if we increase the number of dollars whether by increasing coins or by increasing coinage prices will be increased in the same proportion'

मध्यम कार्य (Medium of Exchange Function) की प्रमुखता दी गई है। प्रो० पिशर की व्याख्या की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का प्रयोग किया है। प्रो० पिशर अमरीका के गणितीय सम्प्रदाय के प्रमुख अर्थशास्त्री थे।<sup>1</sup> उन्होंने आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण एक निष्कर्षों को जानने के लिए गणित का प्रयोग करके उनमें अधिक निश्चितता लाने का प्रयास किया है। उनके मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या का समीकरण लेन-देन अथवा विनिमय सौदों का समीकरण कहलाता है। उन्होंने बताया कि  $MV = PT$

$MV =$  Supply of Money मुद्रा की पूर्ति

$PT =$  Demand for Money मुद्रा की माँग

$$\text{अथवा } P = \frac{MV}{T}$$

$P =$  कीमत स्तर

$M =$  मुद्रा की मात्रा

$V =$  मुद्रा का चलन वेग

$T =$  कुल सौदों की मात्रा जिनका विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है।

(इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं एक प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं जो व्यापार की भौतिक मात्रा के बराबर होती हैं)

उपर्युक्त समीकरण की आलोचना इस तथ्य की ओर संकेत करने की गई थी कि इसमें साख मुद्रा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में साख-मुद्रा तथा उसके चलन-वेग का स्थान प्रमुख होता है। इसलिए प्रो० पिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या हेतु एक संशोधित समीकरण दिया है जो निम्न प्रकार है—

$$PT = MV + M'V'$$

$$\text{or } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$P =$  कीमत स्तर (Price Level)

$M =$  मुद्रा की मात्रा जो चलन में होती है (Quantity of Money in Circulation)

$V =$  मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Money in Circulation)

$M' =$  साख मुद्रा की मात्रा (Credit Money)

$V' =$  साख मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Credit Money)

$T =$  उन वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा जिनका विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। (Total Number of Goods and Services which are Exchanged Through Money)

1. प्रो० इरविंग पिशर के नाम से अर्थशास्त्र के विद्यार्थी काफी परिचित हैं। उनके मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या का समीकरण नबद व्यवसाय से नाम ले जाना जाता है। प्रो० पिशर ने अर्थशास्त्र में गणितीय रीति का काफी प्रयोग किया। वे आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण गणितीय समीकरणों द्वारा करने में अधिक रचि रखते थे। वह अमरीकी गणितीय सम्प्रदाय के प्रमुख सदस्य थे।

## मुद्रा का चलन-वेग (Velocity of Money)

मुद्रा के चलन वेग से आशय एक समयवधि में मुद्रा की एक इकाई द्वारा सम्पादित या किए गए गोदों के मूल्य से होता है। इसका अर्थ सामान्य मुद्रा के चलन-वेग से न होकर मुद्रा की एक इकाई के औसत चलन-वेग से होता है। मुद्रा का चलन-वेग निम्नलिखित तरीके से प्रभावित होता है—

### मुद्रा के चलन-वेग को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Affecting the Velocity of Money)

(1) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा का चलन वेग विगी समय अवधि में उपलब्ध मुद्रा की पूर्ति या उगनी मात्रा द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ यदि चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो चलन-वेग कम होगा और मुद्रा की मात्रा कम होने पर यह अधिक होगा परन्तु धारणा यह है कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का चलन वेग भी अलग अलग हो सकता है। मुद्रा का चलन-वेग विभिन्न प्रकार की मुद्राओं या अलग चलन-वेग ही कहा जाता है।

(2) जनता द्वारा नकदी रखने की प्रवृत्ति—जितनी लोगों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए (जैसे गोदा उद्देश्य, दूरदशिता उद्देश्य तथा मुद्रा उद्देश्य) नकदी रखी जायगी उतनी ही मुद्रा की चलन गति धीमी होगी। इनके विपरीत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितनी नकदी या नकद शेष कम रखे जायेंगे मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। हम कह सकते हैं कि मुद्रा का चलन वेग लोगों द्वारा रखी जाने वाली नकदी की मात्रा पर निर्भर करेगा। यह प्रवृत्ति अर्थात् नकदी की प्रवृत्ति मुद्रा बाजार के मजदूरी तथा मजदूरी भुगतान की विधियों द्वारा प्रभावित होती है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे।

(3) मजदूरी भुगतान की प्रणाली—यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह है तो लोगों में नकदी रखने की प्रवृत्ति कम होगी और जल्दी-जल्दी उपभोग पर व्यय होगा जिससे मुद्रा का चलन-वेग बढ़ेगा। यदि मजदूरी भुगतान प्रति पन्चमास या प्रतिमाह है तो प्रति सप्ताह या प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले की अपेक्षा अधिक नकदी रखी जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मजदूरी प्राप्ति की अवधि जितनी अधिक होगी तो उतनी ही नकदी अधिक रखी जाएगी और इस प्रकार मुद्रा के चलन-वेग में मजदूरी भुगतान की अवधि महत्वपूर्ण होती है।

(4) संगठित मुद्रा-बाजार—मुद्रा-बाजार जितना संगठित होगा मुद्रा का चलन-वेग उतना ही अधिक होगा। इसका कारण यह है कि संगठित मुद्रा बाजार में ऋण प्रदान करने, ब्याज तथा उधार देने की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण मुद्रा का चलन-वेग प्रभावित होता है।

(5) जनसंख्या, तकनीकी परिवर्तन मौद्रिक नीति तथा राजकोपीय नीति आदि भी मुद्रा के चलन-वेग को प्रभावित करती रहती हैं। इसका कारण यह है कि इन तरिका में उपभोग, बचत तथा विनियोग के स्तर प्रभावित होते हैं जो चलन-वेग को भी प्रभावित करते हैं।

(6) व्यावसायिक परिस्थितियाँ—व्यापार चक्रों अथवा तेजी वाले और मंदी वाले में व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग में परिवर्तन लाते रहते हैं। तेजी वाले में मुद्रा का चलन-वेग में तेजी आती है क्योंकि दस्तुभ की कीमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोग जल्दी-जल्दी दस्तुभों का ब्य करने सहित करने लगते हैं। इनके विपरीत मंदी वाले में कीमत गिरने के कारण उपभोग और कीमता में गिरावट होने

की प्रतीक्षा में उपभोग को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। परिणामस्वरूप व्यापारिक प्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हैं और चलन-व्यय गिर जाता है।

(7) प्रतिफल की सम्भावनाएँ—जब माँगियों को यह पता चल जाए कि वह जो पूँजी लगा रहे हैं उनको प्राप्त होने वाला प्रतिफल अच्छा है अर्थात् पूँजी की सीमान्त क्षमता पूँजी लागत अथवा ब्याज की दर से अधिक है तो वे पूँजी विनियोजन बढ़ावेंगे और मुद्रा का चलन-व्यय अधिक होगा।

(8) राष्ट्रीय आर्थिक विकास की स्थिति—विकसित राष्ट्रों या देशों में औद्योगिक विभाग उच्च तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान कुशलता के उच्च स्तर से युक्त मुद्रा-बाजार आदि के कारण निर्यात क्षेत्रों में होता है और मुद्रा का चलन-व्यय बढ़ जाता है। जबकि अन्य विकसित देशों में जहाँ गार्य तथा वित्तीय सुविधाएँ कुशलता से साथ उपलब्ध नहीं हैं, मुद्रा का चलन-व्यय कम रहता है। वर्तमान समय में ऐसे अल्प-विकसित देशों में मुद्रा के चलन-व्यय में वृद्धि हुई है क्योंकि इन देशों में वित्तीय संस्थाओं के विभाग तथा कुशलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

(9) आय वितरण की स्थिति—यदि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण समानता की ओर है तो चलन-व्यय में वृद्धि होगी अन्यथा मुद्रा के चलन-व्यय में गिरावट आयेगी।

फिशर के सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of Fishers' Theory)

प्रो० फिशर का सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं को उन्होंने अन्य बातों समान रहे' (Other things being Equal) शर्तों द्वारा व्यक्त किया है। यह मान्यताएँ मुद्रा के चलन-व्यय, व्यापार की मात्रा तथा साख्त-मुद्रा आदि में सम्बन्धित हैं। यह मान्यताएँ निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं—

(1) समाज में मुद्रा तथा साख्त-मुद्रा का चलन-व्यय स्थिर रहता है। मुद्रा तथा साख्त-मुद्रा का चलन-व्यय ऐसे सम्बन्धित कारणों पर निर्भर रहता है जिनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होते इसलिए  $V$  तथा  $V'$  स्थिर रहते हैं।

(2) एक अन्य मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा (T) में कोई परिवर्तन नहीं होता। T प्राकृतिक साधनों, उत्पादन विधियों, धर्म की उत्पादनता, यातायात आदि तत्वों पर निर्भर करता है। T के स्थिर रहने की मान्यता इस मान्यता पर आधारित है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। देश में कोई भी उत्पादन साधन बेरोजगार नहीं होता यही कारण है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अपरिवर्तित रहती है।

(3) सीमा-स्तर पर साख्त मुद्रा के पड़ने वाले प्रभावों की सम्भावना को यह मान कर समाप्त कर दिया गया है कि गानूनी मुद्रा (M) तथा साख्त-मुद्रा (M') का अनुपात स्थिर रहता है।

(4) एक अन्य मान्यता यह है कि सीमा-स्तर (P) एक निष्पन्न तत्व है अर्थात् मुद्रा की मात्रा तथा अन्य तत्वों की मात्रा में परिवर्तन P को प्रभावित करते हैं, परन्तु P में परिवर्तनों का प्रभाव मुद्रा तथा अन्य तत्वों की मात्रा पर नहीं पड़ता। प्रो० फिशर के शब्दों में—

'समीकरण में P एक निष्पन्न तत्व है। यह स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों से निर्धारित होता है, परन्तु दूसरे तत्वों पर स्वयं कोई प्रभाव नहीं डालता।'

(5) फिशर की व्याख्या दीर्घकालिक है क्योंकि इनका विचार है कि दीर्घकाल में मुद्रा का चलन-व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है। अतः तब में  $V$  तथा  $T$  में परिवर्तन हो सकते हैं।

## फिशर के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Fisher's Theory)

फिशर के सिद्धान्त की आलोचनाएँ अधिकांशतः वैश्वीय तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न आधारों पर की गई हैं। इसमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार से बताई जा सकती हैं।

(1) प्रो० फिशर ने  $MV = PT$  माना है जो एक ग्राह्य गणना बताया है अर्थात् यह समाकरण के दोनो पक्ष  $MV$  तथा  $PT$  जति अव्ययस्था में होता है दो रूप हैं उनको व्याख्या करता है। इसमें अनुसार वस्तु द्वारा जो मुद्रा वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए दी जाती है ( $MV$ ) = विनिमयों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में प्राप्त धनराशि ( $PT$ ) है। इस प्रकार यह समीकरण ही मुद्रा तथा वामता की कोई नई जानकारी नहीं देता। इस प्रकार इस सिद्धान्त का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है।

(2) अत्यन्त विषम मान्यताओं पर आधारित सिद्धान्त का अधिकांश आलोचनाएँ इस सिद्धान्त द्वारा अपनाई जान वाली अवस्थाएँ में बताई जा ऊपर आधारित हैं जैसे—

(अ) यह सिद्धान्त समाज में उत्पादन तथा कीमती में ही बात सामान्य परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता। इसमें मुद्रा के घनत्व  $V$  को स्थिर माना गया है जो वृद्धिपूर्ण है। तबजा  $M$  व  $V$  बढ़ जाता है तथा कीमती में इसमें कमी आता है।

(ब) सारा मुद्रा के चलन-व्यय ( $V'$ ) को स्थिर मानना वृद्धिपूर्ण है। वहाँ-वहाँ ऐसा भी देखा जाता है कि बिना मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा  $V$  तथा  $V'$  में बहुत वृद्धि हो जाती है और कीमती स्तर बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ 1920 और उगा बाद जर्मनी में अति-स्फीति का नाम मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तो हा रहा भी परन्तु मुद्रा का चलन-व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा था अर्थात् मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुसार वहाँ अपेक्षा अनुसार में कीमती स्तर में वृद्धि इतनी तेज थी और तेज है कि कीमती स्तर को मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से अधिक उसका घनत्व-व्यय प्रभावित करता है।

(ग) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हीन से कीमती स्तर ( $P$ ) सदैव नहीं बढ़ता। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो और उसी अनुपात में  $T$  की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो  $P$  नहीं बढ़ता।  $T$  में स्थिर रहने की संभावना वृद्धिपूर्ण है क्योंकि अव्ययस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। उत्पादन की मात्रा तथा कीमती-स्तर एक-दूसरे में अप्रभावित नहीं रहते।

(द) मुद्रा तथा सारा मुद्रा  $M$  तथा  $M'$  का अनुपात स्थिर मानना भी वृद्धिपूर्ण है।

(ए)  $P$  अर्थात् कीमती-स्तर एक निश्चित तत्व नहीं है  $P$  स्वयं समाकरण के अन्य तत्वों को प्रभावित करता है।

कुछ विद्वानों ने हमें यह सबत है कि  $V$ ,  $V'$ ,  $T$  और  $M$  तथा  $M'$  के सम्बन्ध साधक ही अपरिवर्तित रहते हैं। यह तत्व बीच-बीच में ही है। यह धरन्तु अत्यन्त में ही परिवर्तित होते रहते हैं। जनसंख्या के आधार आधार का मात्रा मुद्रा का चलन-व्यय तथा मुद्रा तथा सारा मुद्रा आदि तत्वों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।

(3) बीच-बीच में व्याख्या—आलोचक कहते हैं कि प्रो० फिशर ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है। इस सम्बन्ध में प्रो० फिशर का कहना है कि 'अधिक में अतिरिक्त मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि साधारण में मुद्रा की उपस्थिति मात्रा का कीमती स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है परन्तु अतीत

मे.... यह कीमतों की गतियों पर अपना प्रभाव डाल भी सकती है और नहीं भी और यह इस बात पर निर्भर रहता है कि क्या मुद्रा की मात्रा परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग में परिवर्तन द्वारा निष्प्रभावित हो जाते हैं अथवा नहीं।<sup>1</sup>

‘ प्रो० फिशर ने प्राउफर द्वारा कहे गए इस शक्य को स्वीकार किया है। प्रो० फिशर कहते हैं कि चलन-वेग तथा व्यापार की मात्रा (V तथा T) अल्पकाल में परिवर्तित हो सकती है परन्तु दीर्घकाल में जब अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में पहुँच जाती है तो यह तत्व स्थिर हो जाते हैं।

प्रो० वीन्म न फिशर की इस दीर्घकालिक मान्यता की आलोचना करते हुए कहा है कि दीर्घकालिक मन्तुलन आने वाले काल की भाँति होता है जो कभी नहीं आता। वर्तमान परिवर्तनशील समार में दीर्घकालिक मन्तुलन (Long-run Equilibrium) जैसी स्थिति नहीं होती। वीन्म कहते हैं कि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। इस प्रकार फिशर की व्याख्या अल्पकालिक स्थिति, जा वास्तविकता के अधिक निकट है, की अनदेगी करती है।

(4) मर्मावस्था का यह मानना कि T तथा V होने कीमत-स्तर तथा मुद्रा की मात्रा (P तथा M) स्तरन्वय है उचित नहीं है—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की यह मान्यता उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि M में परिवर्तन मुद्रा के चलन-वेग (V) का प्रभावित करने कीमत-स्तर (P) का प्रभावित कर सकते हैं। इतिहास में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मुद्रा के चलन-वेग (V) में परिवर्तन न, न कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन (M) में कीमत-स्तर को प्रभावित किया है। 1920 के बाद जर्मनी में अति-स्फीति (Hyper Inflation) के लिए मुद्रा का चलन-वेग अधिक उत्तरदायी था न कि उसकी चलन-मात्रा (इसका कारण यह था कि जर्मनी की मुद्रा मार्क में तेजी से गिरावट के कारण लोग जल्दी-जल्दी वस्तुओं तथा सेवाओं का ख़रीद करने के लिए मार्क का प्रयोग कर रहे थे)।

मन् 1920 में ही जहाँ एक ओर जर्मनी में कीमत-स्तर बढ़ने का प्रमुख कारण जर्मनी की मुद्रा मार्क के चलन-वेग था, वहीं इस समय अमरीका में मनुद्धि दिखाई दे रही थी। वहाँ व्यापार की मात्रा (T) में वृद्धि तो मुद्रा की मात्रा (M) में वृद्धि हो रही थी जबकि कीमत-स्तर (P) में वृद्धि नहीं पाई जा रही थी। हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि मर्मावस्था के सभी चर (Variables) आपस में मनुद्धि पर निर्भर रहते हैं और यह जानना बड़िन होता है कि कौन-सा तत्व किम तत्व को और कौन-सा प्रतिफल किसके कारण है। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त विभिन्न चरों की पारस्परिक निर्भरता को मनुद्धि पर यह कहना है कि M में परिवर्तन के कारण P प्रभावित होता है, वृष्टिपूर्ण ध्याय्य है।

(5) परिमाण सिद्धान्त में पाई जाने वाली असंगतियाँ—यह आलोचना प्रमुखतः प्रो० जार्ज एन० हाल्म (George N. Halme) द्वारा की गई है। प्रो० फिशर के मर्मावस्था के कुछ चरों की तुलना नहीं की जा सकती उदाहरण के लिए M समय क्षण (Point of

1 the most we can say for the quantity theory is that the quantity in existence seems to be dominant influence on the Price-level on the average of long period But in the short period.... it may or may not control the movements of prices. And whether it does or does not depend on whether changes in the quantity of money are offset by changes in velocity of its circulation.” —Crowther

time) तथा V मर्यादाधि (Period of Time) से सम्बन्धित होना है और इस प्रकार MV का अर्थ दो विभिन्न चीजों को गुणा करने रहता है। इसी प्रकार P अर्थात् कीमत-स्तर में भी सभी प्रकार की कीमतें शामिल होती हैं जैसे—घोक मूल्य तथा फुटकर मूल्य, मजदूरी तथा लाभ। कुछ वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं जबकि कुछ की इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। इसी प्रकार T के अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। प्रो० हॉम कहते हैं कि हम परिमाण समीकरण को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए अन्यथा हम बहुत सी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे।

(6) सिद्धान्त स्थिर समाज के लिए तो सही है प्रगतिशील समाज के लिए नहीं—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ स्थिर समाज के लिए तो सही हो सकती हैं, परन्तु प्रारंभिक अथवा प्रगतिशील समाज के लिए यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रो० बॉग्स वा कहना है कि ऐसे सिद्धान्त का सामाजिक पक्ष समस्या की प्राचीनता को जानना उन तत्वों का विश्लेषण इस प्रकार से हो जो कीमत-स्तर निर्धारण को अस्थिर प्रक्रिया तथा विभिन्न माध्यमियों की प्रणाली का अध्ययन करती हो।<sup>1</sup>

(7) कीमत-स्तर तथा मुद्रा की प्रतिक्रिया के बीच सीधा तथा हेतुक सम्बन्ध नहीं होता—यह आलोचना विशेष रूप से Prof. Von Hayek ने अपनी पुस्तक "Prices and Production" में की है। वे कहते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धान्त यह तो बनाता है कि एक समय विशेष में कीमत-स्तर क्या है परन्तु यह उन कारणों की व्याख्या नहीं करता जो कीमत-स्तर में परिवर्तन लाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह मानते हैं कि यह उन छुपे हुए कारणों की व्याख्या नहीं करता जो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार यह सिद्धान्त M तथा P का अवास्तविक हेतुक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है तथा यह बीजनों में होने वाले उन कारणों पर ध्यान देने को जो मौद्रिक कारणों में उत्पन्न होते हैं, की व्याख्या नहीं करता।

(8) व्यापार चक्रों की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि बिना मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हुए कीमत-स्तर में व्यापार चक्रों के कारण परिवर्तन होते हैं किन्तु बारे में यह सिद्धान्त कुछ नहीं कहता। विषयवस्तुओं की मांग की मन्दी इनका ज्वलंत उदाहरण है। यह सिद्धान्त तो यह कहता है कि मन्दीयान में कीमत-स्तर ऊँचा करने की दृष्टि से धन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। असद्योक्षा में मन्दी के समय धन में अधिक अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा डालने पर भी कीमत-स्तर में आभासी वृद्धि नहीं हुई थी।

(9) मुद्रा की मात्रा (M) को कीमत-स्तर के निर्धारण का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं है—प्रो० बॉग्स कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में कीमत-स्तर निर्धारण में मुद्रा की मात्रा को एकमात्र कारण मान लेना उचित प्रतीत नहीं होगा। ऐसा कहना है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से ही कीमत-स्तर परिवर्तित नहीं होता बल्कि इसमें परिवर्तन आय, व्यय, बचत एवं विनियोग जैसे मुख्य कारणों द्वारा भी होते हैं किन्तु बारे में यह सिद्धान्त कुछ नहीं कहता।

(10) सिद्धान्त कुछ मौद्रिक कारणों की ही नहीं बल्कि अमौद्रिक कारणों की भी उपेक्षा करता है—आलोचक कहते हैं कि प्रो० दर्रिंग रिगर ने उन अमौद्रिक कारणों की

1 'The real task of such a theory is to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the casual process by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another.'  
—J. M. Keynes



बर्चा की है जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं परन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या में इन तत्त्वों की उपेक्षा की है। अमौद्रिक कारणों जैसे यातायात सुविधाओं, उद्योगों में विस्तार तथा मानव आदर्शताओं की भिन्नता आदि ऐसे अमौद्रिक तत्व होते हैं जिनसे व्यापारिक प्रियायात में वृद्धि होती है जिससे परिणामस्वरूप कीमत स्तर में गिरावट आती है। इसी प्रकार बहुत से अमौद्रिक कारणों से मुद्रा के चलन-वेग में वृद्धि कीमत-स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है जिसको प्रो० पिशर अपने सिद्धान्त में महत्व नहीं देते जो गृह्य है।

(11) पूर्ण रोजगार को मान्यता प्रद्विपूर्ण है—आलोचक कहते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्तपूर्ण राजगार की स्थिति को मानकर चलता है जबकि व्यापारिक रूप से पूर्ण रोजगार को स्थिति कहीं भी देश में नहीं मिलती। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त केवल उन्नी अवस्था में नहीं हो सकता है जबकि उत्पादन की मुद्रा लोच गून्व होगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मुद्रा लोच घनात्मक है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि लाएगी और मुद्रा परिमाण सिद्धान्त सभू गरी होगी। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त केवल उन्नी अवस्था में लागू होगा जहाँ बेरोजगार साधन नहीं पाए जाते। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगार साधन हैं तो उत्पादन का प्रति वध नाचदार होगा और मुद्रा की प्रति में वृद्धि लोगों की आय तथा उत्पादन में वृद्धि करेगी न कि कीमत-स्तर में।

(12) यह सिद्धान्त व्यापारियों के सीधों का माप करता है न कि मुद्रा को प्रय-शक्ति का—प्रो० वीन्स कहते हैं कि पिशर की व्याख्या में  $T$  कुल व्यापार की व्याख्या करता है जिसे मुद्रा के माध्यम से मया जाता है। वीन्स कहते हैं कि  $T$  वस्तु माँदा की ओर सवेत करता है जबकि मुद्रा का द्वारा वस्तु सीधों में अतिरिक्त बहुत से व्यापारिक औद्योगिक और विनीय माँदा किए जाते हैं जिनके कारण से यह सिद्धान्त कुछ नहीं रहता। वस्तु माँदा कुल माँदा का एक छोटा सा भाग होते हैं।

(13) यह सिद्धान्त अपूर्ण है क्योंकि यह मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य की व्याख्या करता है, मूल्य सचय काय को नहीं—आलोचक कहते हैं कि पुराने अर्थशास्त्रियों की इन मान्यताओं को प्रो० पिशर न स्वीकार किया है कि मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य केवल विनिमय का माध्यम ही है और इसमें सम्पादित करने के लिए ही केवल मुद्रा की माँग की जाती है वरन् मुद्रा एक महत्वहीन वस्तु है। प्रो० वीन्स कहते हैं कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के अलावा भू-सचय (Store of Value) का कार्य भी करता है जिसकी उपेक्षा प्रो० पिशर नहीं करते। मनुष्य मुद्रा की माँग वतमान आवश्यकताओं की प्रति के अलावा भविष्य की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए भी रखता है जिनके लिए मुद्रा सचय की जाती है। मुद्रा ने घन मय काय को भरन घना दिया है। ममाज में मुद्रा का महत्व इन कारणों से है क्योंकि यह वतमान तथा भविष्य के बीच एक बड़ी का कार्य करती है। प्रो० पिशर न मुद्रा के भूय सचय जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा को है।

(14) कीमत-निर्धारण विधि गृह्यपूर्ण है—यह आलोचना प्रमुख रूप से प्रो० डब्लू० सी० मिचल (Prof. W. C. Mitchell) न की है। वे कहते हैं कि कीमत निर्धारण कुल मुद्रा को कुल वस्तुओं में भाग देना होता है अर्थात्  $P = \frac{M}{T}$ । कीमत-निर्धारण की यह

विधि गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि कीमत निर्धारण में माँग के अलावा भविष्य का भी प्रभाव पड़ता है। Prof. Mitchell कहते हैं कि "अधिकतर समय  $P$  तथा  $T$  समीकरण में मरिभय मात्रा में  $M$  का भाग करत है और  $M$  तथा  $V$  में परिवर्तन लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे  $M$  पर भी प्रभाव डालते हैं।"

(15) कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि प्रो० पिशर की व्याख्या कीमत-निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त से अवलुल त्रय है। सत्यता यह है कि सभी वस्तुओं के समान मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति का फलित्व द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व देता है तथा एक पक्षीय है एन अधूरा है।

(16) कीमत-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रभाव—प्रो० पिशर के सिद्धान्त की एक आलोचना यह भी की जाती है कि इन्हीं दश वा कीमत-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का पड़ना एक प्रभाव की उपेक्षा की है। एक देश का मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ना एक स्वाभाविक घटना है।

(17) व्याज की दर की उपेक्षा—आलोचक कहते हैं कि प्रो० पिशर ने व्याज की दर जैसे मौद्रिक तत्व की उपेक्षा की है जोकि मुद्रा की मात्रा (M) तथा कीमत स्तर (P) के मध्य एक कड़ी का काम करता है।

(18) यह सिद्धान्त यह तो बताता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन क्यों होता है परन्तु यह नहीं बताता कि यह परिवर्तन क्यों होते हैं—प्रो० पिशर ने उक्त आलोचना करते हुए कहा है कि यह नहीं बता सकता कि क्योंकि ऐसा होता है कि मुद्रा की मात्रा जानने पर कीमत स्तर बढ़ता है जबकि दूसरे समय उतनी ही मुद्रा की मात्रा जानने पर कीमत स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।<sup>1</sup>

(19) यह सिद्धान्त उन कारणों की व्याख्या करता है जो चलन-वेग को नियन्त्रित करते हैं—आलोचक कहते हैं कि जब कीमती भू-संपत्ति का चिन्तन प्रथम श्रेणी का मुद्रा के चलन-वेग का तीव्रता नीचा तथा कीमती वस्तुओं का घटने का स्थिति में मुद्रा के चलन-वेग की तीव्रता ऊँची होती है। मुद्रा परिमाण सिद्धान्त इन कारणों की व्याख्या नहीं करता जो चलन-वेग को प्रभावित करने नियन्त्रित करने हैं।

(20) प्रो० बेंनेन का कहना है कि अन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा माँग और पूर्ति के प्रभावों के नियम द्वारा नियन्त्रित नहीं होते—प्रो० बेंनेन का इस सम्बन्ध में कहना है कि मुद्रा की माँग व्यापारिक सौदा की मात्रा पर निर्भर न करके लोगों द्वारा तबदा रचना की योग्यता और इच्छा पर ठीक उन्ही प्रकार निर्भर करती है जिन प्रकार माला की माँग मन्वानों में रहने वाला वस्तु द्वारा होता है न कि उन व्यक्तियों के द्वारा जो मराना का प्रयत्न करके अथवा बिना पर उठाते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)—प्रो० इरविंग पिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की इन आलोचनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सिद्धान्त व्यवस्था एक कृत्रिम मन्त्र पडा है और शायद ही इसका कोई उपयोग भवमात्र जैसे विज्ञान का तर्क है, परन्तु ऐसा मोक्षता उचित नहीं है। सिद्धान्त की उपर्युक्त आलोचनाओं का बाद भी मुद्रा परिमाण सिद्धान्त इन बातों को ध्यान में रखकर बताया है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से कीमत-स्तर सामान्य दशाओं में बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कीमत-स्तर में वृद्धि का एक मात्र नहीं तावक संकम एक प्रमुख कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना होता है।

1. It cannot even explain why it is that a creation of money will some times take and start off a rise in prices, while at another an equal creation may have no effect at all " -Cronther

2. Edwin Cannon

यह सिद्धान्त वर्तमान सरकारों के लिए एक स्रोत एव चिंताकी अवश्य प्रस्तुत करता है और वह यह है कि अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को मुद्रा की मात्रा पर समय-समय पर अनुचित लगाना चाहिए अर्थात् देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मुद्रा की पूर्ति करनी चाहिए। सरकार को उन तत्वों पर भी नियन्त्रण रखना चाहिए जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुद्रा स्फीति जाल में चलन में मुद्रा की मात्रा कम तथा अवस्फीति जाल में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ानी चाहिए अथवा स्फीतिजाल में लोगों की श्रम-शक्ति पर नियन्त्रण के उपाय तथा अवस्फीति जाल में लोगों के लिए श्रम शक्ति प्रदान करने के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को मजबूत की स्थिति में रखने के लिए सरकार की मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मौद्रिक नीति के माध्यम-साथ अन्य उपाय भी सरकार को भोजन की मलाई दी जाती है।

सिद्धान्त की ऐतिहासिक पुष्टि—मुद्रा परिमाण सिद्धान्त व्यर्थ नहीं है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब-जब मुद्रा की मात्रा घटने में लगी है तो मूल्य-स्तर में वृद्धि हुई है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में मूल्य-वादी की शक्ति के इन धातुओं की पूर्ति बढ़ी और योरोप में इन धातुओं के निर्यात होने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ी थी जिससे मूल्य-स्तर बढ़ा था। इसी प्रकार प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के समय में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की मात्रा-स्तर में वृद्धि का कारण बना। वर्ष 1923 में जर्मनी में तथा 1917-48 में चीन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का कारण अति स्फीति (Hyper-Inflation) की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के छोटे-छोटे देशों में दुर्भाग्य से स्वर्ण तथा चाँदी के उत्पादन में गिरावट आने से कीमत-स्तर में गिरावट के चिह्न दिखाई दे रहे थे। प्रो० गुस्ताव कैसल (Prof Gustav Cassel) ने मासिक-वर्षीय आंकड़ा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया था। 1914 के बाद नोट चलने में बढ़ रहे थे जिसके कारण कीमत-स्तर भी बढ़ रहा था।

भारत में भी पिछले वर्षों में लगातार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत-स्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की नवद श्रेय श्याय्या अथवा कॅम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण (Cash Balance Approach of Quantity Theory of Money or Cambridge Economists View)

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या नवद श्रेय समीकरण द्वारा भी की जाती है। मुद्रा परिमाण की इस व्याख्या को प्रमुख रूप में कॅम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों जैसे प्रो० एल्फ्रेड मार्शल प्रो० पीगू प्रो० राबर्टसन तथा प्रो० एम० कीन्स (Prof Alfred Marshall, Prof Pigou Prof Robertson and Prof J M Keynes) आदि अर्थशास्त्रियों ने समर्थन दिया जाता है। परन्तु इन अर्थशास्त्रियों में प्रो० एल्फ्रेड मार्शल, विनिमय पैटी, जॉर्ज लॉर तथा रिचर्ड स्ट्रॉलिन आदि विद्वानों के लेखन कार्यों में इनके विचार मिलते हैं। कॅम्ब्रिज विद्वानों ने प्रो० फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आलोचना प्रमुख रूप से मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के विनिमय माध्यम का पर आवश्यकता से अधिक महत्व देने में पायेस्यका करत हुए की है। कॅम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नवद श्रेय श्याय्या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है जो लोग अपने पास कितनी विनिमय-शक्ति रखते हैं न कि एक सम्भाव्यता में रखते हैं। दूसरे शब्दों में इन विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की मात्रा और पूर्ति द्वारा एक समय-क्षण में मुद्रा का मूल्य निर्भर रहता है न कि एक सम्भाव्यता में। इस विश्वासार्थक अनुमान मुद्रा का मूल्य उत्तरी शक्ति और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। इससे पहले कि अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति पक्ष में महत्वपूर्ण मात्रा

धा और मुद्रा को माँग को स्थिर मानकर उस उपरिष्ठ कर दिया पुनः विभिन्न विद्वानों ने मुद्रा की प्रकृति के साथ मुद्रा के माँग पक्ष को अधिक महत्त्व दिया है।

विभिन्न विचारधाराएँ अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की माँग पर निर्भर करता है और मुद्रा की माँग विनिमय के माध्यम अर्थात् व्यापारिक शोधा व सम्पादन हस्त नहीं होती बल्कि मुद्रा के मूल्य संचय काय (Store of Value) अर्थात् नकद रक्ता की प्रवृत्ति पर जो विभिन्न उद्देश्यों द्वारा प्रभावित होती है निर्भर करती है। यह विद्वान कहते हैं कि मुद्रा की दो विशेषताएँ प्रमुख हैं। प्रथम बैठी हुई मुद्रा (Sitting Money) दूसरी उड़ती हुई मुद्रा (Money on Wings) जो मूल्य संचय (Store of Value) तथा विनिमय के माध्यम (Medium of Exchange) भाषों के लिए होता है। विभिन्न विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की वास्तविक माँग उन लोगों के द्वारा की जाती है जोकि मुद्रा का विभिन्न उद्देश्यों की प्रकृति के लिए अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। विभिन्न सम्प्रदाय के सहायक अर्थशास्त्री प्रो० माण्ड ने नकद शोध समीकरण के सार का दस्तावेज निम्नानुसार बतलाया है।

समाज की प्रत्येक अवस्था में लोग अपनी आय के एक भाग को चलन मुद्रा अर्थात् नकद में रखना चाहते हैं यह भाग 1/5 1/10 तथा 1/20 हो सकता है। इस नकद मुद्रा को रक्ता के कारण उनको अपने व्यक्तियों को संचित करने में आसानी तथा सुविधा हो जाती है तथा उचित भाव रखने से हानि या नुकसान से बचाव होता है परन्तु दूसरा ओर यह असहजता के कारणों के रूप में रक्ता हो सकता है जोकि विनिमय करने में आय प्राप्त करना परेशान करने वाला होता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आय के भाग को मुद्रा तथा अन्य किसी रूप में संचित रखने के विषय में समय समय पर विचार करता है तथा उचित साधन का उचित उपयोग करता है। वह उम्र का भी उम्र अपनी आय तथा धन का नकदी में संचय रखने के कारण प्राप्त होती है तुलना अथवा लाभ तथा उम्र हासिल से करता है जो उमरी आय तथा धन को विनियोजित करके नकद के कारण उठानी पड़ती है - हम यह मानकर चलते हैं कि एक देश के निवासी निरन्तर बीगनन धरना सम्पादन के समय भाग को आपत प्राप्त करके नकद रूप में संचय करते हैं तो सम्पूर्ण मुद्रा की चलन मात्रा इन सब धनराशियों के योग के बराबर होगी।<sup>1</sup>

1 In every state of society there is some fraction of their income which people find it worthwhile to keep in the form of currency it may be a fifth or a tenth or a twentieth A large command of resources in the form of currency renders their business easy smooth and puts them at an advantage in bargaining but on the other hand it locks up in a barren form resources that might yield an income or gratification if invested Every man finds the appropriate fraction after balancing one against another, the advantages of a further ready command and the disadvantages of putting more of his resources into a form in which they yield him no income or income or other benefit

Let us suppose that the inhabitants of a country find it just worthwhile to keep by them on the average ready purchasing power to the extent of a tenth part of their property then the aggregate value of the currency will tend to be equal to the sum of these amounts

—Prof Alfred Marshall

कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण निम्न-लिखित रूप में बताए जा सकते हैं—

(1) प्रो० मार्शल का समीकरण—प्रो० मार्शल के कैम्ब्रिज सम्प्रदाय के संस्थापक अर्थशास्त्रियों में। जैसा कि मार्शल की उपर्युक्त व्याख्या से ज्ञात होता है उन्होंने बताया है कि लोग अपनी वार्षिक आय तथा सम्पत्ति का एक भाग नगदी के रूप में रखते हैं। लोगो द्वारा मुद्रा की माँग का सम्बन्ध उनके द्वारा कुल आय तथा सम्पत्ति के नकद रूप अथवा नकद प्रयोज्य शक्ति (नगदी में मुद्रा तथा बैंक जमाएँ शामिल होती हैं) का सम्बन्ध इस सम्पत्ति तथा आय की मात्रा के स्थिर अनुपात से होता है जिससे हम औसत रूप में  $1/5$ ,  $1/10$  या  $1/20$  भाग में व्यक्त कर सकते हैं। मार्शल का समीकरण निम्न रूप से दिया जा सकता है—

$$M = KY + K'A$$

$M$  = मुद्रा की मात्रा ।  $Y$  = कुल आय ।  $K$  = कुल आय का वह भाग जिससे लोग समाज में मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं ।

$K'$  = कुल सम्पत्ति वह भाग जिसमें उसका स्वामी मुद्रा के रूप में रखता है ।

$A$  = कुल सम्पत्ति का द्रव्य मूल्य

मार्शल के उपर्युक्त समीकरण को हम दो रूपों में दखते हैं प्रथम आय भाग, दूसरा सम्पत्ति भाग। प्रो० मार्शल के समझना के सम्पत्ति भाग को अनावश्यक समझते हुए इसे हटा दिया और उनका समीकरण का सामान्य रूप इस प्रकार हो गया—

$$M = KY$$

$M$  = मुद्रा की मात्रा

$K$  = आय का वह भाग जिसमें लोग नकद रूप में रखना चाहते हैं अर्थात् वह का आपसी सम्बन्ध (That Portion of Income which People Want to Hold in the form of Money or Reciprocal of Velocity)

यदि  $Y$  के स्थान पर  $PO$  को रखा जाये अर्थात् कुल वार्षिक आय कुल वास्तविक उत्पादन (Output or  $O$ ) तथा कीमत-स्तर (Price-Level or  $P$ ) का गुणनफल होती है तो समीकरण का रूप इस प्रकार होगा—

$$M = KPO$$

$$\text{अथवा } P = \frac{M}{KO}$$

$M$  = मुद्रा की मात्रा

$P$  = कीमत-स्तर

$O$  = कुल वास्तविक उत्पादन

$K$  = वास्तविक आय का वह भाग जिससे लोग मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं।

(2) प्रो० पोर्ग का समीकरण—प्रो० ए० नी० पोर्ग प्रो० मार्शल के शिष्य के और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद में अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। उनके समीकरण के भी दो रूप हैं जो निम्नलिखित हैं—

$$(a) P = \frac{KR}{M} \quad (\text{मुद्रा की एक इकाई के मूल्य की व्याख्या के रूप में})$$

$$\text{or } P = \frac{M}{KR} \quad (\text{वस्तु की एक इकाई के मूल्य के रूप में})$$

P = मुद्रा का मूल्य अथवा प्रय शक्ति

M = कुल मुद्रा की मात्रा अथवा मुद्रा इकाइयों की कुल मात्रा

K = कुल वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नगदी के रूप में रखते हैं।

R = कुल वास्तविक आय

प्रो० पीगू कहते हैं कि सभी लोग पूर्णरूप से नादी नहीं रखते अर्थात् वानूनी मुद्रा को अपने पास नगद रूप में नहीं रखते। कुछ लोग इन घनराशि वा ण भाग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रो० पीगू को समीकरण का विस्तृत रूप निम्न प्रकार से सामने आता है

$$P = \frac{KR}{M} [C + h(I - C)]$$

अथवा 
$$M = \frac{KR}{P} [C + h(I - C)]$$

समीकरण P, M, K, R का अर्थ पहले वाले समीकरण के समान है। C = विधि-याप्त अथवा वानूनी मुद्रा की वह राशि जिसे लोग नगदी के रूप में रखते हैं। I - C विधि-प्राप्त नगद कोषों का वह भाग जिसे लोग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। h = बैंक जमाओं का वह भाग जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं। प्रो० पीगू ने अपने समीकरण में बैंक जमाओं को अलग स्थान देने के कारण ही समीकरण को विस्तृत कर लिया है। बैंकि परम्परागत रूप से बैंक जमा भी नगदी की भाँति ही तरल होती है इसलिए व्यापहारिक दृष्टि से प्रो० पीगू के प्रथम समीकरण को ही अधिक मान्यता प्राप्त है अर्थात्

$$P = \frac{KR}{M} \quad \text{or} \quad P = \frac{M}{KR}$$

प्रो० पीगू के समीकरण के तत्व P, K, R को स्वतन्त्र परा (Independent Variables) के रूप में नहीं माना जाता है और न ही यह आवश्यक है सभी चर एक ही दिशा में गतिशील हों। M सरकार द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि M में परिवर्तन होने पर P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। इसका कारण यह है कि M में परिवर्तन के साथ-साथ K तथा R तत्वों में भी परिवर्तन हो सकता है। समीकरण में K द्वारा वास्तविक माँग ज्ञात की जा सकती है।

(3) प्रो० राबर्टसन का समीकरण—प्रो० डी० एच० राबर्टसन वैश्विक सम्प्रदाय के सदस्य थे। उनका नगद शेष समीकरण निम्न प्रकार दिया जाता है—

$$M = PKT \quad \text{or} \quad P = \frac{M}{KT} \quad \text{or} \quad P = \frac{KT}{M}$$

प्रो० राबर्टसन का समीकरण प्रो० पीगू के समीकरण से थोड़ा ही भिन्न है। प्रो० राबर्टसन का समीकरण प्रो० पीगू समीकरण से अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रो० रिचर के समीकरण से इसको तुलना करना आसान है। वैश्विक समीकरण में यह सबसे सरल है। प्रो० राबर्टसन ने P, M, T आदि तत्वों को प्रो० रिचर के समीकरण के अनुपात तथा K को माँग के समीकरण के अनुपात मान लिया है।

(4) प्रो० वीन्स का समीकरण—प्रो० जे० एम० वीन्स पहले कैम्ब्रिज सम्प्रदाय के अर्थशास्त्री और प्रो० मार्गट के समर्थक तथा गिण्ट थे। प्रो० वीन्स के समीकरण को कैम्ब्रिज समीकरण में सशोधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इस समीकरण को वास्तविक शेष व्याख्या (Real Balance Approach) के नाम से अपनी पुस्तक "A Tract on Monetary Reform" में अलग से दिया है। उनका कहना था कि उपभोग इकाइयों में सम्बन्धित वास्तविक लेन-देन की एक निश्चित राशि के बराबर व्यक्ति अपने पास वास्तविक शेष (Real Balance) रखते हैं।

प्रो० वीन्स का कहना है कि मुद्रा को रखने वाले व्यक्ति को वास्तविक शेषों की उतनी मात्रा की आवश्यकता होगी जो कि उपभोग इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक लेन-देन की मात्रा जिस पर उन्हें व्यय किया जाता है के आसानी सम्बन्ध क्या है? उन्होंने वास्तविक शेषों को उपभोग इकाइयों द्वारा मापा है और इस निष्पत्ति पर पहुँचे थे कि यदि वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन-देन की मात्राओं का आपसी सम्बन्ध पूर्ववर्ती या पहले जैसा ही रहता है तो नकद शेषों (Cash Balances) की राशि, जिसकी आवश्यकता होगी वह वास्तविक शेषों की उस राशि के बराबर होगी जिसका निर्धारण उपर्युक्त आपसी सम्बन्धों (वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेन-देन) द्वारा होता है। प्रो० वीन्स का यह समीकरण निम्न प्रकार से है—

$$n = p(K + rK')$$

$n$  = नकद मुद्रा की कुल मात्रा

$p$  = उपभोग इकाइयों की कीमत-स्तर

$r$  = बैंक की नकद निधि तथा कुल जमाओं का अनुपात

$K$  = वास्तविक शेषों की राशि जिन्हें नकद रखा जाता है अथवा उपभोग इकाइयों की मात्रा जिनको जनता मुद्रा के रूप में संचित रखती है।

$K'$  = वास्तविक शेष जो बैंक जमा के रूप में रहते हैं अथवा उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जिनको प्राप्त करने के लिए समाज मुद्रा को बैंकों में जमाओं के रूप में रखता है।

प्रो० वीन्स के इस समीकरण को इस प्रकार भी रखा जाता है—

$$P = \frac{n}{K + rK}$$

प्रो० वीन्स के समीकरण में  $K$  तथा  $K'$  के मध्य अनुपात लोगों की बैंकिंग आदतों पर निर्भर करेगा जबकि उनका विशुद्ध मूल्य लोगों की अपनी आदतों पर निर्भर करेगा।  $r$  का मूल्य बैंकिंग व्यवस्था द्वारा नकदी रखने की प्रथा पर निर्भर करेगा। प्रो० वीन्स यह मानकर चलते हैं कि  $K$ ,  $K'$  तथा  $r$  अल्पकाल में लगभग अपरिवर्तित रहते हैं और  $P$  में परिवर्तन  $n$  में परिवर्तनों के आधार पर होते हैं।

प्रो० वीन्स के उपर्युक्त समीकरण को हम कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेणी में लेते हैं

क्योंकि प्रो० वीन्स के समीकरण  $P = \frac{M}{KR}$  तथा  $P = \frac{n}{K + rK'}$  में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

### कैम्ब्रिज समीकरण नकद शेष की आलोचनाएँ (Criticisms of Cambridge Cash Balances Equation)

नकद शेष समीकरण भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इसकी आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं।

(1) अर्थव्यवस्था में मूल्यों की गत्यात्मक प्रवृत्ति के प्रति उदासीनता—आलोचक कहते हैं कि कैम्ब्रिज व्याख्या अर्थव्यवस्था में मूल्यों की गत्यात्मक प्रवृत्ति के बारे में कुछ नहीं कहती। इन प्रकार यह व्याख्या भी अधूरी है।

(2) मुद्रा के सर्वव्यापी रूप की अक्षय्यता—कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचना का एक आधार यह है कि यह समीकरण मुद्रा की माँग निर्धारण में सभी तथ्यों की व्याख्या नहीं करता उदाहरणार्थ मुद्रा की माँग के उस पक्ष की व्याख्या नहीं करता जो सट्टा उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है तथा जिनका मूल्य की कुल माँग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(3) समीकरण के विभिन्न तत्वों की अस्थिरता—कैम्ब्रिज व्याख्या की एक अन्य आलोचना यह है कि समीकरण में  $K$  तथा  $T$  को स्थिर माना गया है। इस कारण नकद शेष समीकरण में ये सभी आलोचनाएँ लागू होती हैं जो विश्व के समीकरण के बारे में कही जाती हैं।

(4) मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अस्पष्ट है—आलोचक कहते हैं कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री यह विस्मरण नहीं कर पाए कि मुद्रा की मात्रा में किसी भी हुई मात्रा की वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यों तथा उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है।

(5) कीमत स्तर को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों की उपेक्षा—कैम्ब्रिज व्याख्या उन सभी शक्तियों की व्याख्या नहीं करती है जो  $P$  को प्रभावित करती हैं—जैसे न्याय की दर मुद्रा की पूर्ति आदि।

(6) बचत जमा राशियों की अस्पष्ट व्याख्या—यह आराग्य भी कैम्ब्रिज व्याख्या पर लगाया जाता है कि यह उन बैंक जमा राशियों के बारे में कुछ नहीं कहती जो व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदान कणों से होती हैं।

प्रो० फ़िशर की व्याख्या (विन-वेन) तथा कैम्ब्रिज व्याख्या (नकद शेष) की तुलना (Comparison of Prof Fisher's (Transactions) and Cambridge's (Cash Balance) Approaches)

प्रो० फ़िशर एवं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि दोनों विचारधाराओं की व्याख्या के लिए जो समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कुछ समानताएँ तथा अगमनताएँ अथवा अन्तर देखने की स्थिति हैं। यद्यपि पहले हम समानताओं और उनके बाद अगमनताओं का अर्थ जोचन करेंगे।

दोनों समीकरणों में समानता—प्रो० फ़िशर तथा कैम्ब्रिज विचारधारा में समानता अर्थात् आधार पर पाई जाती है—



(1) प्रो० फिशर के समीकरण में मुद्रा व चलन-वेग (V) को अधिक्त महत्त्व दिया गया है जबकि कैम्ब्रिज व्याख्या में नकद राशि (K), जो गणितीय दृष्टि में मुद्रा के चलन-वेग का विपरीत है, को अधिक महत्त्व दिया गया है। यदि दोनों समीकरणों को मुद्रा मूल्य निर्धारण में मिलाया जाए तो महत्त्व न देकर उभे भी मुद्रा ही मात्र दिया जाय तो

गणितीय दृष्टि में प्रो० फिशर और कैम्ब्रिज व्याख्या के समान हार्मो जैस  $P = \frac{MV}{T}$

or  $P = \frac{M}{KR}$  का मत न MV तथा M दोनों एक समान हैं। समीकरण के नीचे वाले

भाग अर्थात् T तथा KR ही अलग दिशाएँ देने हैं। T को प्रो० फिशर न समझ सकने के कारण अर्थात् मोटा में दिया है जो नकद मुद्रा द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं जबकि KR का कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने उक्त नकद मुद्रा में व्यक्त किया है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का प्राप्ति करने हेतु व्यक्ति नकद रूप में खर्चते हैं। इस प्रकार  $1/V$  तथा  $V$  के स्थान  $1/K$  द्वारा भी इन दोनों में समानता स्थापित की जा सकती है।

(2) दोनों ही समीकरण एक ही घटना के दो रूप नजर आते हैं, जैसा कि प्रो० टी० एन० गार्डनर करते हैं। नकद व्ययनाय समीकरण मुद्रा व बहाव (Flow) को अधिक्त महत्त्व देता है जबकि नकद-शेष समीकरण T मुद्रा व स्टॉक जैसा मूल्य (Stock) को अधिक्त महत्त्व दिया गया है। नकद शेष समीकरण में प्रो० पीगू के KR तथा प्रो० हॉमर के  $K + rK'$  प्रो० फिशर के T द्वारा एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम्बन्ध नकद-शेष में सम्बन्धित कार्यों में है। इस प्रकार दोनों समीकरण एक ही घटना के दो रूप नजर आते हैं।

(3) दोनों ही मुद्रा की मात्रा का मूल्य-निर्धारण का एक आधारवाक्य तत्त्व मानते हैं।

दोनों समीकरणों में असमानताएँ

प्रो० फिशर तथा कैम्ब्रिज व्याख्या दोनों में जहाँ एक ओर कुछ असमानताएँ दिखाई देती हैं वहीं दूसरी ओर कुछ महत्त्वपूर्ण असमानताएँ भी देगन भी मिलती हैं जो दोनों व्याख्याओं को एक-दूसरे से पृथक् करती हैं। यह असमानताएँ निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जा सकती हैं—

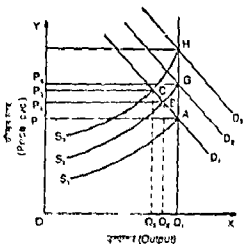
(1) कीमत-स्तर का अर्थ—प्रो० फिशर के समीकरण में कीमत स्तर (P) का अर्थ सामान्य कीमत-स्तर (General Price Level) में है जबकि नकद शेष समीकरण में कीमत-स्तर का अर्थ उपभोग वस्तुओं का कीमतों में है। प्रो० ए० ए० हॉमर (Prof A H Hansen) ने दोनों में अन्तर करते हुए कहा है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की नकद शेष व्याख्या  $M = KY$  मौलिक रूप में मुद्रा तथा कीमतों की पूर्णतया एक नवीन व्याख्या है।

(2) गणितीय दृष्टि से अन्तर—सामान्यतः यह कहा जाता है कि नकद शेष समीकरण नए बीजा-गणितीय परिधान में मुद्रा परिमाण सिद्धांत ही है न कि नहीं है। प्रो० ए० ए० हॉमर कहते हैं कि गणितीय दृष्टि में K नकद व्ययनाय समीकरण  $MV = PO$  में V का उलटा है। वे आगे कहते हैं कि गणितीय समानता की दृष्टि में  $T = 1/K$  में यह निश्चय नहीं हो जाता कि मार्ग-नगरी सिरोपन मानस्य में ह्यूम-फिशर (Hume-Fisher) विरोध-

के रूप में परीच में लाने जाती है तथा परिणामस्वरूप प्रथम वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाने से अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती।

**सागत वृद्धि स्फीति का रेखाचित्र**

निम्न रेखाचित्र सागत वृद्धि स्फीति को बताता है। चित्र में पूर्ण रोजगार उत्पादन सम्बन्धित बिन्दु परां पर प्राप्त होता है जहाँ DI तथा SI एक-दूसरे को काटते हैं अर्थात् A बिन्दु पर। इस बिन्दु A पर उत्पादन  $OQ_1$  है तथा कीमत  $OP_1$  है। जब मुद्रा पूर्ति का



$S_1$  से  $S_3$  पर जाता है तो उत्पादन की मुक्त मात्रा गिरकर  $OQ$  हो जाती है और कीमत-स्तर  $O$  बढ़कर  $OP_3$  हो जाता है। इसी प्रकार जब पूर्ति फलन बढ़कर  $S_3$  हो जाता है तो कीमत-स्तर बढ़कर  $OP_3$  हो जाता है। यह स्थिति उभे समय तक रहेगी जब तक कि पूर्ति फलन बढ़ने की प्रवृत्ति दिसजाएगा।

उदाहरणार्थं जब इस्पात मिन में काम करने वाले श्रमिकों के वेतनों में वृद्धि हो जाने के हेतु इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो परिणामस्वरूप वृद्धि दानों मोटरों ताइरों को आदि वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी। मोटर बसों तथा ट्रकों की कीमत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिवहन तथा यात्रा करने के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। वृद्धि दानों के मूल्यों में वृद्धि होने के हेतु साधान्तर के मूल्य में वृद्धि होगी तथा रहन-सहन की लागत में वृद्धि हो जायेगी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य वेतनों में वृद्धि होगी। इस प्रकार मूल्य-वृद्धि की यह प्रक्रिया सतत रूप धारण कर लेगी। स्फीति के निम्न प्रकार से अगले पृष्ठ पर दिने चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है —

**माँग प्रेरित स्फीति व सामगत वृद्धि स्फीति (Demand Pull Inflation Versus Cost Push Inflation)**

कुछ आर्थशास्त्रियों का विचार है कि स्फीति न केवल माँग वृद्धि अथवा न केवल लागत वृद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि इसमें माँग और लागत दोनों ही अकार की वृद्धि के तत्त्व पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि सागत वृद्धि स्फीति नाम की स्फीति होती ही नहीं है, क्योंकि बिना माँग तथा तद वृद्धि के वृद्धि हुए, सागतों में



केरोजगारी तथा धातु में मंदी लाएगी न कि स्फीति । इसी प्रकार में यह कहा जा सकता है कि माँग वृद्धि स्फीति को नहीं लाती है जब तक लागतों में वृद्धि न आ जाए परन्तु यह स्थिति एक प्रमुख अन्तर की उद्देश्य करती है । जैसे कि क्या सामान वृद्धि पूर्व अधिक माँग के सम्बन्धन अथवा उमड़ो पूरा कर लेती है अथवा क्या यह अमन्तुन की स्थिति में ले जाती है अथवा क्या यह अतिरिक्त पूर्ति (श्रम तथा उत्पादन क्षमता) को सृजित करती है जिसको प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करके रोका या स्थगित किया जा सकता था ।

प्रो० एच० जी० जॉन्सन (Prof H G Johnson) ने दोनों प्रकार की स्फीति के सम्बन्ध में वाद-विवाद को समाप्त करते हुए कहा है कि ' दोनों विद्वान्त स्फीति के स्वतन्त्र एवं अपने आप में पूर्ण विद्वान्त नहीं कहे जा सकते वरन् उन्हें मौद्रिक वातावरण में स्फीति प्रक्रिया (Mechanism) से सम्बन्धित विद्वान्त के रूप में देगना चाहिए ।'<sup>1</sup> यदि व्यावहारिक दृष्टि में देखा जाए तो पता चलता है कि इस बात का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन एवं जटिल कार्य है कि विशेष प्रकार की स्फीति माँग प्रेरित अथवा लागत प्रेरित स्फीति है ।

दोनों प्रकार की स्फीति में अन्तर पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं है परन्तु फिर भी हम जान से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके अन्तर से माँग तथा लागत प्रेरित शक्तियों को अलग करने में गण्यता मित्रती है । इन दोनों का अन्तर नीतिगत दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है ।

### स्फीति अन्तराल <sup>2</sup> (Inflationary Gap)

इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री ने अपने अप्रैल 1941 के बजट भाषण में परिभाषित किया था । उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि ' यह (स्फीति अन्तराल) सरकारी व्यय वह मात्रा है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मातृ-शक्ति अथवा भौतिक सामानिक साधना अथवा समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा साधनों की कोई अनुरूप मात्रा प्राप्त न होती हो ।'<sup>3</sup> स्फीति अन्तराल अर्थव्यवस्था में उम स्थिति को बनाता है जिसमें स्थिर कीमता पर

1 " ... 'The two theories are therefore not independent and self contained theories inflation but rather theories concerning the mechanism of inflation in a monetary environment that permits it ' Essays in Monetary Economics—H G Johnson (London, 1967) P 128

2 स्फीतिक अन्तराल शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन प्रो० जे० एम० कींग ने मई 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "How to Pay for War" में किया था जिसका अर्थ अर्थाधिक सरकारी व्यय में लगाया जाता था, परन्तु स्फीति अन्तराल की घटना उम समय आ सकती है जब पूर्ण रोजगार की अवस्था में कुल निरग माँग में वृद्धि के कुल उपभोग में समान बची नहीं होती हो ।

3 "Inflationary gap is the amount of the government's expenditure against which there is no corresponding release of real resources of manpower or material by some other member of the community " —(Budget Speech of the Chancellor of Exchequer in England, April 1941)

वस्तुओं की कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग अधिक हो जाती है। स्फीति अन्तराल की विचारधारा को वास्तविक आय के स्तर में पूर्ण रोजगार की दिशा में लेना चाहिए। इसको परिभाषित करने के लिए वर्तमान कीमतों पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पर कुल उत्पादन की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है। प्रो० कुरीहार (Prof. Kurihara) ने स्फीति अन्तराल को परिभाषित करते हुए आधार कीमतों पर कुल उत्पादन की तुलना में कुल सम्भावित व्यय की अधिकता माना है। प्रो० क्लैम (Prof. Klein) ने स्फीति अन्तराल का अर्थ उम अन्तर में लिया है जो जनसंख्या अपनी आय में से उपभोग करने की बंटा करनी के मध्य तथा स्फीति से पहले की कीमतों पर जो धनराशि उपभोग के लिए उपलब्ध होगी। यदि यह मान भी लिया जाए कि कुछ साधन बेकार रहते हैं जिनको रोजगार मिल जाने पर वर्तमान आय की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी तो भी पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने से कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे साथ उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मशीनों तथा स्टाफ की क्षमता को घटाने में समय लगता है। कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाने के लिए कृषि और खनिजों का उत्पादन बढ़ाना होगा। श्रमिकों को नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इन सबके लिए अधिा समय की आवश्यकता होगी। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिा समय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जब व्यय बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ेंगी और स्फीति अन्तराल उम समय तक दिखाई देगा जब तक कि वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ाई जाती।

स्फीति अन्तराल को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम एक मुद्रा अर्थव्यवस्था को लेते हैं जिसमें लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय कुल सरकारी तथा निजी व्यय के बराबर होगी जो वित्तियोग तथा उपभोग के रूप में बिया जाता है। माना कि कुल राष्ट्रीय आय 1,200 करोड़ रुपये वर्तमान कीमत-स्तर पर है। अब इस कुल उत्पाद में से सरकार 300 करोड़ की उत्पाति मुद्रा बायों के लिए ले लेती है तो जनता के उपभोग के लिए 900 करोड़ की कुल उत्पाति या राष्ट्रीय आय बचेगी। यह 900 करोड़ रुपये वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए रह जाते हैं। माना कि हम समयावधि में समुदाय की मौद्रिक आय के रूप में 1,200 करोड़ रुपये दिए जाते हैं इसमें से सरकार 100 करोड़ रुपये करो के रूप में ले लेती है। इस प्रकार लोगों के पास 1,100 करोड़ रुपये उपभोग्य आय (Disposable Income) के रूप में बचे रहते हैं। समुदाय के लोग समस्त उपभोग्य आय को व्यय नहीं कर देंगे और इसके कुछ भाग को बचा लेंगे। यदि यह मान लें कि लोग अपनी आय का 10% भाग बचाकर रकने हैं, तो हम 1,100 उपभोग्य आय में 110 करोड़ रुपये बचा लिए जायेंगे और द्राव्यव आय 990 करोड़ रुपये बचेगी जो वस्तुओं के उपभोग पर व्यय की जाएगी (1,100 करोड़ बचत 110 करोड़ = 990 करोड़ रुपये) इस प्रकार वर्तमान कीमत-स्तर पर स्फीति अन्तराल (Inflationary Gap) 90 करोड़ रुपये का होगा (990 करोड़ - 900 करोड़ रुपये)। इस प्रकार जब 900 करोड़ रुपये की वस्तुओं के लिए 990 करोड़ रुपये उपभोग व्यय हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे, तो 90 करोड़ रुपये का स्फीतिक अन्तराल होगा। इसी बात को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है :—

मांग पक्ष (Demand Side) करोड़ रुपये

पूर्ति पक्ष (Supply Side) करोड़ रुपये

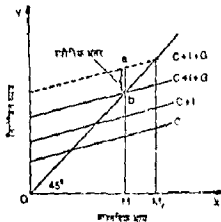
1. मौद्रिक आय जो समुदाय 1,200  
को भुगतान के रूप में दी  
जाती है

1. कुल राष्ट्रीय उत्पादन 1,200  
(GNP) वर्तमान आय  
पर

|                                                     |       |                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 2 दर                                                | 100   | 2 मुद्रा व्यय अभाव मुद्रा                                       | 300 |
| 3 कुल उपभोग आय                                      | 1 100 | राष्ट्रीय आय का मूल्य                                           |     |
| 4 समुदाय द्वारा 10% की दर से बचत कराता              | 110   | जो मुद्रा व्यय का पूर्ण हेतु जाता है।                           |     |
| 5 (मुद्रा उपभोग आय यह राशि जो कुल अनुमानित व्यय है) | 990   | 3 मूल स्पीति की मरदा पर सामान्य सामरिका क निग उपभोग हेतु धाराशि | 900 |

विकास योजना बनाने में भी इस प्रकार का स्ती अन्तरान हो सकता है। मोद्रिय व्यय के रूप में विकास योजनाओं के लिए धाराशि अधिक हो सकती है परन्तु व्यय का साथ उपभोग वस्तुओं का उत्पादन में साथ-साथ वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि विकास योजनाओं के लिए विशेष की जाने वाली धनराशि तथा उत्पन्न विनियोजन के परिणामस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन में समय-विन्ध्य (Time lag) होता है। इसमें एक मोद्रिय तथ्य यह सामने आता है कि जब दर समुदाय के पास उपभोग्य आय की धनराशि तथा उपलब्ध वस्तुओं की धनराशि बराबर होगी तो कीमत-स्तर स्थिर रहेगा किन्तु जैसा उपभोग्य आय उपलब्ध वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो जाएगी ता स्ती अन्तरान दिखाई देगा। इससे विपरीत यदि उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा या मूल्य उपभोग्य आय से अधिक हो जाएँ तो तब इसे अवस्थाती अन्तरान (Deflationary Gap) की संज्ञा दी जाएगी।

राजिती अन्तर के विचार को रेखाचित्र द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।



स्पष्टीकरण—राजिती में  $OY_1$  स्ती पर निरपेक्षित व्यय तथा  $OY_2$  स्ती पर वास्तविक आय की दर्शाया गया है।  $C =$  उपभोग  $I =$  निर्यात तथा  $G =$  सरकारी व्यय।  $OM$  आय के स्तर  $B$  बिन्दु पर निर्यात व सरकारी उपभोग एवं निर्यात का रूप में किया गया कुल व्यय  $(C+I+G)$  प्रयोजित कीमा पर कुल आय  $OM$  का बराबर है। इसी बिन्दु पर प्रयोजित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में पूरा राजकार की स्थिति है तथा स्ती अन्तर शून्य है। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाता है किन्तु  $(C+I+G)$  द्वारा दिखाया गया है ता समान बनाए स्ती के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय और

कुन उत्पादन म भी उमी अनुपात म वृद्धि हानी चाहिए। जैम  $MM^1$  की वृद्धि हाना आवश्यक नहा त। अम-तुन की स्थिति आ जायगी तथा कीमत स्तर बढ़ेगा। रसाचित्र म  $ab$  द्वारा स्फीति अंतर को दिखलाया गया है अर्थात्  $ab = C+I+G$  तथा  $C+I+G$  के अंतर का दिसनाता है। यह अंतर उम समय तक धरा रहता है जब तक अथव्यवस्था म वास्तविक आय म वृद्धि  $MM^1$  व बराबर नहा हा जाती। आय म  $MM^2$  मात्रा म वृद्धि स स्थानिक अन्तर समाप्त हा जायगा तथा कीमता का बढ़ना भी स्थगित हा जायगा।

स्थानि अंतरान का तीन तरीका म कम किया जा सकता ह जैम—

(i) जनता स अ धर बचत करवाना।

(ii) अतिरिक्त प्रय शक्ति को बरा व रूप म घमून कर लेना।

(iii) उपभाग्य आय व बराबर बेशकर उत्पादन की मात्रा का न जाना। एक

अच्छा सरकार स्फीति अंतरान का दूर करन व लिए प्रथम दो तराज अपन ता हे जब कि एन बुरा सरकार नीमता का बढ़न देता है और स्फीति अथव्यवस्था म दिसनाइ देता है।

**स्फीति अंतराल का महत्व (Significance of the Inflationary Gap)**—स्फीति

अंतरान का महत्व दश म बहुत उपयोगी है। यह मोद्रिय तथा राजकाषाय अधिकारिया व निग स्फीति व विरुद्ध गयाप्त बंदम उठान व लिए मागदशन प्रस्तुत करता है और उ ह बताता है कि निम्न ओर किम निगा में स्फीति व विरुद्ध काय करत ह। प्रो० गुरीगाग न स्फीति अन्तरान ७ महत्व को बतात हुए कहा है— स्फीति अन्तरान विनयण जासत व रूप में जैम राष्ट्रीय आय निवेश की मात्रा तथा उपभाग व्यया का साष्ट ध्यम्या करता ह जा कि सरकार की नाति का बरा मात्रजनिन व्यया बचत अभियाना साग नियंत्रण मजदूरी समायाजन व नियारण में सहायता करती हे सक्षम म इग्न अतगत सभी स्थानि विरुद्ध उपाया जोकि उपयाग प्रवृत्ति बचत निवेश आदि का प्रभावित करत ह निम्न कामन-न्तर वा निरारण हाता है सामिन किया जाता है। इन प्रकार यह उा प्रवृत्तिया व प्रत्यक्ष अथवा अत्रत्य रूप म प्रभावित करत हुए मोद्रिय तथा राजकाषाय अधिकारिया व स्थानि अन्तरान का समाप्त करन व लिए एक प्रचारण आगा बंधाना हे निम्न कि जय आन कारी कामता में वृद्धि ना करा जा सा।<sup>1</sup>

1. Analysis of the inflationary gap in terms of such aggregates as national income investment outlays and consumption expenditures savings campaigns credit control wage adjustment—in short all the conceivable anti-inflation measures affecting the propensities to consume to save and to invest which together determine the general price level. It is by influencing those propensities directly or indirectly that the monetary fiscal authorities hope to wipe out the inflationary gap therefore prevent further price increases  
—Kenneth L. Jurell

आर्थिक गतिहीनता के साथ स्फीति अथवा मन्दी स्फीति (Stagflation or Slumpflation)—

वर्तमान युग में आर्थिक दृढ़ता एवं स्फीति दोनों साथ-साथ दिखलाई पड़ते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसको मन्दी स्फीति या आर्थिक गतिहीनता के साथ स्फीति को संज्ञा दी है। यूरोप, अमरीका तथा विकासशील देश (भारत सहित) में जहाँ एक ओर स्फीति के चिह्न बीमारी में वृद्धि बेरोजगारी के साथ उत्पादन में दृढ़ता अर्थात् उत्पादित माल के बिक्राने में कठिनाई की स्थिति दिखलाई देती है। पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति दिखलाई दे रही है। यह नयी स्थिति है।

प्रो० रोम्बुलसन ने मन्दी स्फीति को परिभाषित करते हुए लिखा है "मन्दी-स्फीति एक नई बीमारी का नया नाम है। स्टैगफ्लेशन के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किन्तु साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकता कठिन हो जाता है।"

( 'Stagflation is a new name for a new disease Stagflation involves inflationary rise in prices and wages at the same time that people are unable to find jobs and firms are unable to find customers for what their plants can produce.' )

मन्दी स्फीति में महँगाई, बेरोजगारी तथा वस्तुओं का न बिकना एक ऐसी स्थिति है जो सामान्य स्फीति में भिन्न है। सामान्य स्थिति में महँगाई तो पायी जाती है, परन्तु उसने साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा उत्पादित किया हुआ माल बिक जाता है। उत्पादन को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है तथा व्यापारिक क्षेत्रों में वृद्धि होती है।

मन्दी स्फीति के कारण

- (1) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि।
- (2) धनी देशों के व्यापार में घाटा।
- (3) मजदूरी की दरों में वृद्धि।
- (4) प्राकृतिक प्रकोपों जैसे सूखा, बाढ़ तथा हड़तालों में वृद्धि।
- (5) स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि।

प्रो० रोम्बुलसन ने मन्दी स्फीति के कारणों में एशिया का तथा अफ्रीका के देशों में निरन्तर पड़ने वाले सूखे एवं बाढ़ से उत्पादन में कमी का माना है। वैदोन्वियम पदार्थों एवं बोपेन की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से सामान्य मूल्यों में वृद्धि हुई है।

प्रो० रोम्बुलसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था में मन्दी स्फीति को आवश्यक माना है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उदार मौद्रिक नीति द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के प्रयास एवं आवश्यक वस्तुओं के अच्छे उत्पादन के बाद भी कीमतों में स्थायित्व माने में अग्रगण्य। द्वारा भी कीमतें बढ़ती हुईं नजर आती हैं। भारत तथा अनेक एशियाई देशों में ऐसी स्फीति के चिह्न देखे जा सकते हैं।

आयातित स्फीति—मन्दी स्फीति के लिए अमरीका, जापान तथा जर्मनी जैसे देशों द्वारा उदार आयात नीति भी उत्तरदायी है। इन देशों के विदेशों से आयात के बढ़ने से जो भुगतान किया है उसमें विकासशील देशों के वस्तुओं के बाजारों में वृद्धि के परिणामस्वरूप तथा विकासशील देशों में ऋणों में वृद्धि से भारत निर्माण में वृद्धि हुई है तथा स्फीतिक स्थितियों को बढ़ावा मिला है। इससे रोजगार तथा उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाई।



भारत जैसे विकासशील देश में कपड़ा तथा इन्जीनियरिंग उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की माँग कम होने पर भी इनके मूल्यों में गिरावट नहीं आती है। अर्थशास्त्र की माँग और पूर्ति में सतुलन का सामान्य नियम त्रियाशील नहीं हो पाया है। बड़े-बड़े उत्पादक सरकार की मन्दी का भय दिखाकर तथा तरह-तरह की रियायतें प्राप्त करके मूल्यों में नहीं आने देते। मन्दी तथा स्फोटिक स्थितियाँ साथ-साथ चलती हैं।

### स्फोटि के कारण (Causes of Inflation)

मुद्रा-स्फीति का अर्थ उम अवस्था में लिया जाता है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि तो होती है परन्तु उमने माघ-माघ इनकी पूर्ति में उमी अनुपात में या फिर बिरुधुत वृद्धि नहीं हाती। स्फीति उन कारणों में आती है जो माँग में वृद्धि लाते हैं और माँग में वृद्धि दो प्रकार के कारणों में आती है।

(1) वे कारण जो माँग को बढ़ाते हैं।

(2) वे कारण जिनसे पूर्ति में गिरावट आती है। इन दोनों प्रकार के कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

वे कारण जो माँग को ऊपर की ओर ले जाते हैं (Factors Causing an Upward Shift in Demand) —

यह कारण निम्नलिखित हैं—

(i) हीनार्थ प्रवन्धन (Deficit Financing)—विकासशील देशों में सामान्य रूप से विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रवन्धन नीति का सहारा लिया जाता है इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। लोगों के हाथों में अनिश्चित मुद्रा पहुँचती है और उससे द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

(ii) मुद्रा के चलन-वेग में वृद्धि (Increase in the Velocity of Money)—यह कारण विशेषकर अभिवृद्धि (Boom) के समय अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस काल में पूँजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि अथवा तरलता परसंदगी में गिरावट अथवा उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण मुद्रा का चलन-वेग बढ़ जाता है।

(iii) साख वृद्धि (Credit Expansion)—देश में साख का स्वरूप सरकार तथा व्यापारिक बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर में जब कमी कर देता है अथवा जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है तो साख वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक ऋणों की माँग के कारण जब अपने ग्राहकों को अधिक ऋणों के लिए माघ मुद्रा सृजित की जाती है और इन बैंकों को नकद जमा कम होने लगती है। जब साख में वृद्धि का दौर, चाहे केन्द्रीय सरकार अथवा व्यापारिक बैंकों की पहल पर हो, प्रारम्भ हो जाता है तो वह काफी समय तक चलने का नाम नहीं लेता।

(iv) सार्वजनिक व्यय में तेजी में वृद्धि (Rapid Increase in Public Expenditure)—वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग में सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। चाहे यह वृद्धि सुरक्षा सम्बन्धी व्यय विकास योजनाओं तथा जनता के कल्याणार्थ योजनाओं अथवा अन्य प्रकार के आर्थिक प्रगति सम्बन्धी योजनाओं की पूर्ति हेतु व्यय हो। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग को बढ़ाती है।

(v) निर्यातों में वृद्धि (Increase in Exports)—वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देण्ड अपने भुगतान गन्तुता तथा व्यापार सन्तुलन की बाती का पना में रखन के लिए अग्रिम निर्यात के लिए प्रयत्नशील हैं। अधिक निर्यात की प्रवृत्ति का श्रेय के उद्योगिताओं के लिए उद्योगों हेतु वस्तुओं की कमी महसूस होती है। यदि उन वस्तुओं का माँग पहले जैसी ही बनी रहे जिनका निर्यात प्रारम्भ किया गया है तो भी इनके मूल्य में वृद्धि स्फीतिक स्थिति के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) जनसङ्ख्या में तेजी से वृद्धि (Rapid Growth of Population)—वस्तुओं तथा सेवाओं की अतिरिक्त माँग का एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसङ्ख्या है। विकासशील और अर्द्ध-विकासीय देशों में स्फीति का प्रमुख कारण जनसङ्ख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। उदाहरण के लिये भारत में जनसङ्ख्या वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि के लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी होती है।

(vii) युद्ध व्यय (War Expenditure)—जब कोई देश युद्ध में प्रभावित हुआ जाता है तो सामाजिक-व्यय युद्ध व्ययों को पूरा करने के लिए बढ़ जाता है। युद्ध के समय युद्ध सामग्री के उत्पादन हेतु धन को उपभोक्ता वस्तुओं से हटाया जा कम कर लिया जाता है। सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं का प्रति हेतु देश में साधन युद्ध सामग्री के उत्पादन हेतु हस्तांतरित हो जाते हैं।

(viii) श्रम संघों के काम (Activities of Trade Unions)—वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम संघों के बढ़ते हुए दबाव के कारण भी अग्रिम मजदूरी के माँग का एक कारण तथा अग्रिम छुट्टियों के लिए संधय चेतना रहती है। वर्तमान प्रजातंत्र में युग संघों की सरकार का अपने आप को श्रमिकों के हितों के लिये उत्तरदायी रूप में प्रस्तुत करने के कारण श्रमिक संघों की अनुचित माँगों को मानना पड़ता है। श्रमिकों द्वारा उत्पादकों को घिना घड़ाए हुए जब उनकी मजदूरी बढ़ाना पड़ती है तो इससे सामान्य ब्यय बढ़ाने की माँग में वृद्धि होती है। मजदूरी वृद्धि प्रयत्नशीलता में वृद्धि को लाता है और कामकाज बढ़ने का कारण है।

(ix) उत्पादन तथा बिक्री कर में वृद्धि (Increase in Excise and Sales Taxes)—जब सरकार उत्पादन तथा बिक्री कर बढ़ा देती है तो एक कर का बिवर्तन (Shifting) उत्पादकों द्वारा किया जाता है और इनका अन्तिम भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिससे वस्तुओं की कीमतें भी जोड़ दिया जाता है।

(x) अवमूल्यन (Devaluation)—जब कोई सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है तब एक तो देश के निर्यात बढ़ जाते हैं दूसरा ओर आयातों के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार देश के नागरिकों के लिए ऊँचे कीमतों का सामना करना पड़ता है।

(xi) अन्तर्राष्ट्रीय कारण (International Factors)—एक देश की स्फीति दूसरे देश तक पहुँच जाती है। स्फीतिक देशों की वस्तुओं के आयात करने पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और इसकी भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर देना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य प्रकार के लेन-देन अग्रिम होते हैं। इस प्रकार एक देश की स्फीति अथवा अवस्फूर्ति का प्रभाव दूसरे देशों पर अग्रिम ही पड़ता है।

के कारण जो पूति रो गिराते है। (Factors Causing a Downward Shift in Supply)

यह कारण निम्नलिखित है—

(i) प्राकृतिक प्रयोप (Natural Calamities) — प्राकृतिक प्रयोप, जैसे बाढ सूया धूकूप या पणत, म ध्यापक बीमारी न पंडु जाने आदि कारण म वस्तुआ का उत्पादन पिछड जाता है। वष 1987 म भारत म पडा ध्यापक सूया बीमती म वृद्धि क लिए विणेप तीर पर उत्तरदायी नमडा जाता है।

(ii) उत्पात्ति की स्थिति (Stage of Production) — वस्तुओ की पूति म वसी उम ममय भी होती है जब उत्पादन के क्षेत्र मे नव प्रवर्तन तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण नही अनाया जाता। शीघ्र ही उत्पात्ति ह्याम नियम त्रियाशील हो जाता है। उत्पादन मे वृद्धि लागता म वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है और बीमती बढने लगती है।

(iii) सग्रह की आदत (Habit of Hoarding) — जब स्फीतिक स्थितियाँ होती है तो बीमती स्तर तेजी से बढता है और मुद्रा की नय-शक्ति गिरती है। व्यक्ति भावी बीमती म वृद्धि की आसका म वस्तु का सग्रह आवश्यकता से अधिच बरने लगते है और वस्तुआ की बमी महसूस होती है।

(iv) कुछ उत्पात्ति के साधनो की बमी (Shortage of some Factors of Production) — उत्पात्ति क कुछ महत्वपूण साधना जैसे पूंजीगत साधन, नूमि प्रशिक्षित श्रमिका, बच्चे मात्र आदि की बमी तजी काल म अधिच महसूस की जाती है। बढती हुई माँग को पूरा बरने न लिए उत्पादन का बिम्नतर उननी तेजी म नही होता और वस्तुआ की बमी व्याप्त रहती है।

स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

स्फीति का अध बीमती-स्तर मे होने वाली लगातार वृद्धि से लिया जाता है परन्तु बीमती म यह वृद्धि सभी क्षेत्रो मे एक समान (Uniform) नही होती। यदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो म वस्तुआ तथा सेवाओ की बीमती मे एक समान रूप से वृद्धि हो तो विभिन्न आय अर्जित बरने वाले वर्गों की सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और स्फीति के आधिक प्रभाव तटस्थ होंगे। परन्तु ध्यावहारिक दृष्टि से होता यह है कि स्फीतिक प्रक्रिया म विभिन्न वस्तुआ तथा सेवाओ की बीमती मे परिवर्तन भी विभिन्न दरों से होता है। इस कारण समुदाय के विभिन्न वर्गों की आय के वितरण की स्थिति मे परिवर्तन भी अलग-अलग होता है। किसी वर्ग की स्थिति सुदृढ़, तो किसी की बहुत कमजोर तथा किसी की समान रहती है।

मुद्रा-स्फीति के समुदाय के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव निम्न प्रकार से देखा जा सकता है—

(i) कृषक वर्ग (Farmers) — मुद्रा-स्फीति का कृषक वर्ग पर अच्छा प्रभाव पडता है, क्योंकि उननी अपने द्वारा उत्पादित कृषि पशुओं की बीमती अधिच मिलती है साथ ही कृषक वर्ग ऋणी वर्ग होता है इनलिए स्फीति के समय जब वे अपना ऋण अदा बरते है, तो उन पर ऋणा की अदायगी स्वरूप जो बोझ पडता है उनका वास्तविक भार कम पडता है। किसानों की स्फीति का नाग यह मिलता है एक तो उननी उत्पात्ति की बीमती का मूल्य बढ जाता है दुगर जो बीमती वृद्धि या स्फीति का उ म वस्तु की लागत होंगी है। वह स्फीति की प्रार-

भिन्न-तरंगों में जैसे ब्याज बरो तथा मजदूरी के रूप में जो उनके उत्पाद की लागत में वृद्धि होती है यह बहुत कम होती है विशेष तौर पर उनको मिलने वाली बीमती की वृद्धि की दर की तुलना में।

(ii) उद्यमकर्त्ता (Entrepreneurs)—उद्यमकर्त्ताओं को भी स्फीति में लाभ बहुत कुछ निमाना की भांति होना है। उद्यमकर्त्ता का मिलने वाला लाभ पूंजी निर्माण का बढ़ात एव प्रोत्साहित करत है निष्प्रिय साधना को उत्पादन एव उत्पादित शक्ता बढ़ान के लिए प्रयुक्त करत अथर्व्यवस्था को निवसित किया जा सकता है।

वृषत तथा उद्यमकर्त्ता को मिलने वाले लाभ स्फीति काल में होने ता है, परन्तु यदि स्फीतिक प्रभाव दीर्घकालिक है तो अथर्व्यवस्था को हाति हानी है क्वाकि अमीमिन काल में स्फीति क लाभ अजिन नहीं किए जा सकत। एक मीमा क बाद जो तद्व पूंजी-निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले होते है वे निवेशो के लिए बाधक साबित होने हैं। मन् 1920 क दशक में प्रो० नॉर्से (Prof. Nurkse) ने यूरोप के दशा क अध्ययन क आधार पर यह निष्पन्न निकाला था कि स्फीति की सफलता पूंजी-निर्माण क यन्त्र के रूप में अधिनाम-तथा भावी तथा गैर सम्भावित बीमती में वृद्धि की मात्रा पर निर्भर हाती है <sup>1</sup> जब आगे आन जाने समय में यस्तुआ की बीमती बढ़ने की आशा निश्चित रूप से होती है ता मुद्रा के चलन-वग में वृद्धि होती है बचने नहीं होती है और स्फीति तेजी से निवेशो का प्रोत्साहित नहीं करती। यह स्फीति भी सचयी प्रवृत्ति होगी है।

(iii) विनियोगकर्त्ता बग (Investors)—विनियोगकर्त्ता वग का दा भागा में बाटा जाता है। प्रथम क विनियोगकर्त्ता निजकी आय विनियोग द्वारा लगभग निश्चिन रहनी है अर्थात् क गरकारी प्रतिभूतियों एव बाण्डा में विनियोग करके निश्चिन आय प्राप्त करत रहते है। दूसरी श्रेणी में क विनियोगकर्त्ता आते है जिनका कार्य विभिन्न कम्पनिया क अशा तथा श्रृणयता आदि का खरीदना और बेचना हाता है तथा तजी बाज की स्थिति का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि करत रहत है। प्रथम प्रकार क विनियोगकर्त्ता की स्फीतिकाल में वास्तविक आय घट जाती है क्वाकि उनकी निश्चिन एव अखरिवतनगत आय होंगी है और उनकी इग आय को वास्तविक प्रय शक्ति मुद्रा के मूल्य पटन के माय कम हानी जाता है। दूसरी आर अनिश्चित आय प्राप्त करने वाले विनियोगकर्त्ता के लाभ बढ़ते है क्वाकि उन्हे अपने पाग रगे हुए अशा पर लाभारा की मात्रा बड़ी हुई दर में प्राप्त होंगी है।

(iv) श्रृणी तथा श्रृणदाता बग (Debtors and Creditors)—स्फीति क समय ऋणदाता वग को हाति तथा श्रृणी बग को लाभ होता है। इसका प्रमुग कारण यह है कि ऋणदाता की श्रृण की वापसी जो होंगी है उमका वास्तविक मूल्य स्फीति काल में घट जाता है जबकि श्रृणी स्फीति में जा मूरधन खीटाता है तो उसे कम प्रय शक्ति की अदागी करती पडता है।

(v) मध्यम बग तथा निश्चित आय बग (Middle and Fixed Income Class) स्फीति काल में सबसे ज्यादा नुकसान निश्चिन आय वाले बग के अधियों पर होता है

<sup>1</sup> Success of inflation as an instrument of capital formation depends largely on the degree to which rise in prices is unforeseen and unexpected. —Nurkse

जैसे पेन्शन प्राप्त करने वाले नागरिक या ऐसे असंगठित क्षेत्रों (Unorganised Sectors) काम करने वाले व्यक्ति जिनकी आय प्रायः निश्चित रहती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा के मूल्य में ह्रास के होने पर भी उनको आय नहीं बढ़ती और उनके पास वास्तविक उपभोग्य आय बहुत कम रह जाती है। लोग के जीवन की समस्त वस्तुओं की स्फीति निगल लेती है। साथ ही बूढ़ावस्था का सहारा समाप्त कर देती है। जहाँ तक मध्यम वर्ग का प्रश्न है उस पर भी स्फीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रो० एन्जेल (Prof J W Angell) ने मुद्रा स्फीति के समय जर्मनी में मध्यम वर्ग पर पड़ने वाले स्फीति के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि "स्फीति के कारण उम्र वर्ग को सबसे अधिक बचत सहन करना पड़ा था जो स्वयं अपनी रक्षा सबसे कम कर सकता था। शहर में रहने वालों में मध्यम वर्ग जिसमें अधिकतर छोटी निश्चित आय प्राप्त करने वाले लोग जैसे वेतनभोगी कर्मचारी तथा क्लर्क पेन्शन प्राप्त करने वाले छोटे विनियोजक जो बैंक व्याज तथा लगान पर अपना भुजारा करने वाले थे। संशय में यह लोगों का ऐसा वर्ग था जो मुद्रा के ह्रास की बुराईया से बहुत प्रभावित था। उस वर्ग को स्फीति से नुकान का न तो ज्ञान प्राप्त था और न अवसर प्राप्त था।" प्रो० कैमरर ने मध्यम वर्ग की स्थिति की चर्चा इस प्रकार की है "मध्यम वर्ग जो अपने बड़े परिवार तथा बचत द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कुछ बचन का गन्ध करती है स्फीति के दिना में अपने को गम्भीर स्थिति में पाता है। आय का तुलना में रहने-सहने का व्यय अधिक बढ़ जाता है रागी बचत समाप्त हो जाती है वाठन परिधम, स्वतन्त्रता, बचाव करने या विचार छोड़े देना का समान हो जाने से। इस स्थिति में वर्ग पर निराशा तथा असफलता की भावना अपना अधिकार जमा लेती है।"<sup>2</sup>

स्फीति का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति पर होता है जो कि वतमान प्रजातन्त्र की रीढ़ होते हैं। जर्मनी, आस्ट्रिया, पार्लैण्ड तथा प्राग में अति स्फीति ने प्रथम विश्व-युद्ध के बाद इन देशों में रहने वाले मध्यम वर्ग को विन्तुन नष्ट कर डाला था। प्रो० सी० एन० कैमरर ने स्फीति की तुलना दर्शनी से करते हुए कहा है कि "दोनों ही किसी की कोई वस्तु छानने है अन्तर केवल इतना है एक डारू दिललाई देता है जबकि स्फीति अदृश्य होती है, डारू का निवारण एक समय में एक या कुछ ही व्यक्ति

1. 'The group which suffered most from the inflation, however, was the group which was also least able to defend itself, The middle class among the low-dwellers ..... composed largely of people with small fixed incomes, such as salaried Officials and clerks, recipients of pensions, and little investors living on interest and rent. They were precisely the group most exposed to the evil consequences of currency depreciation, While they lacked both the knowledge and opportunity to combat it.'

J.W Angell

2. E. W. Kemmerer

होते हैं जबकि स्फीति का शिकार पूरा राष्ट्र होता है। जटू को ग्यावाचाय में रण्ट देने के लिए भेजा जा सकता है परन्तु स्फीति कानूनी अग्निार पाक्ष होती है।<sup>1</sup>

### अन्य प्रभाव (Other Effects)

(i) व्यापारिक क्रियाओं पर प्रभाव (Effects on Business Activities)— स्फीति में व्यापारिक क्रियाओं एवं योजनाओं तथा विनियामों को गतता रहता है। स्फीति में हास्य लागत तथा लाभ का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और यह व्यापार की भुगतान क्षमता तथा सुदृढ़ विकास को बड़ा गतता उत्पन्न करती है। इसमें व्याज की दरें बढ़ती हैं और मुद्रा बाजार में एक प्रकार से गतवनी गच जाती है।

(ii) करों में वृद्धि (Increase in Taxation)— स्फीति काग में बढ़ने हुए सामं-जनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार करों की मात्रा बढ़ाती है। सभी प्रकार के कर बढ़ते हैं जिनका बोझ देश के सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है।

(iii) बचतों पर प्रभाव (Effects on Savings)— स्फीति से बचतें बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। मुद्रा के मूल्य में होने वाली गतता गिरावट से लोगो का नकदी अधिमान गिरता है जो बचत निरास्य को ग्तोत्साहित करता है। बचतों में नमी पूंजी निर्माण क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(iv) धनी तथा निर्धन के बीच बुरी का बढ़ता— स्फीति में धनी और निर्धनों के बीच असमानता बढ़ती है। धनी और धनी हो जाते हैं तथा निर्धन और अधिर निर्धनों की श्रेणी में आ जाते हैं। समाज में आर्थिक असमानताओं के बढ़ने से एक वर्ग दूसरे वर्ग से द्वेष और ईर्ष्या करता है। सामाजिक बटुता बढ़ती है।

(v) भुगतान सतुलन (Balance of Payment)— स्फीति के समय एक देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिबलता की ओर जाता है ऐसे देशों के पास विदेशी मुद्राओं के भण्डार भी कम होने लगते हैं।

### नैतिक प्रभाव

स्फीति का एक तराव असर लोगो के नैतिक-स्तर में गिरावट के रूप में सामने आता है। विशेषतः पर व्यापारी वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों का नैतिक-स्तर काफी गिर जाता है। प्रायः वर्ग भौतिक रूप से समृद्धियों बनने की होड़ में स्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। बाला बाजारों रिश्वतगोरी स्रष्टाचार, खोरी, गिलावट आदि आम बाने हो जाती है। जब लोगो की सेहत से की दरें बढ़ने समाप्त हो जाती हैं तो जलता कर विश्वास सरकार से उठने लगता है। प्रो० व्हाइट (Prof. A. D. White) ने काग की श्राति के समय कास में लोगो की हासत जो स्फीतिक प्रभाव से हुई थी उमशी पर्वत बाने

1. "Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or a few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal."  
— C. N. Patel

हूए लिये ? कि फ्रांस के प्रभुय शहरा में विलासिता तथा दुराचार जा लूटो की अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर दोष थे चारा ओर दियाई दे रह थे । वसा में जुग की भावना बढती जा रही थी । यह दुराचार केवल व्यापारिया तथा नताब्रा में भी फैल गया था जा कुछ समय पूर विलासिता बेईमानी तथा लापरवाही के दोषो ग मुक्त ममल जाते थे ।<sup>1</sup>

जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इससे भी अधिक नैतिक सखट उत्पन्न हो गया था । लोगो का इतना अधिक नैतिक पतन हा गया था कि आदमी स्त्रिया के कपडे पहनकर बलिन के नाच घर में पुनिम अधिकाश्या के मामने नाचा करते थे । जर्मनी में अति स्फीति का नया नाच चल रहा था । 'नव युवतियाँ अपन दोषो की घमण्णशानी ढग म व्याख्या करती थी । सालह वर्ष की अवस्था तक पदित्र कुवारी रहना उन दिना बलिन में लज्जाजनक माना जाता था । लडकियाँ अपने दूषित अनुभवो को बतान में गव समझती थी ।'<sup>2</sup>

### राजनैतिक प्रभाव—

मुद्रा-स्फीति का लगातार रहना तथा अतिस्फीति की स्थिति आर्थिक व्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करती बरन यह सामाजिक तथा राजनैतिक गडबडी व त्रिगु भी उत्तरदायी होती है । जर्मनी में अति स्फीति (Hyper inflation) न डॉ० कुनो (D Cuno) की उदार सरकार का पतन किया था और हिटलर को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । कान्स्टान्टीना ब्रेमियानी तुरोनी (Constantino Bresciani Turroni) न जर्मनी में अति स्फीति की स्थिति का वर्णन करते मुद्रा माफ के मूय की घिसाउट योग्यी शताब्दी के इतिहास की एक प्रमुख घटना है । यह इतिहास में अपन प्रकार की एक सखत अधिक भयानक घटना थी और शायद महान युद्ध के बाद हमारी पीढी की अधिराज राजनैतिक तथा आर्थिक बढिनाइया की जिम्मेदारी इसी पर थी । इमने जर्मन समाज के स्थाई वर्गों के धन को बर्बाद कर दिया था और इमने अपन पीछे राजनैतिक तथा आर्थिक असन्तुनन को छोडा था और आने वाले समय में अम्पिरता के लिए पुच्छभूमि छाडी । हिटलर स्फीति की ही गौण उत्पत्ति था । इसी प्रकार महान मन्दी तीमा की (मन्दी)

1 ' In the leading French cities now arose a luxury and licence which was a greater evil than the plundering that ministered to it. In the country the gambling spirit confined to businessmen, it began to break out in official circles, and publicmen who a few years before had been thought above all possibility to taint became luxurious, reckless cynical and finally corrupt'

—Andrew D White

2 ' Young girls bragged proudly of their perversion, to be sixteen and the suspicion of virginity would have been considered a disgrace in any school of Berlin at that time, even girl wanted to be able to tell of her adventures and the more exotic the better' (In the World Yesterday by Sidfan Zweig quoted on Page 10 From Hyper Inflation "

—S K Muranjan

नित्तीय कठिनाइयाँ भी कारी अथ तब अन्तर्राष्ट्रीय उदार प्रणाली या उग्र असाध्यता या परिणाम भी निम्न दम घातक स्थिति को बढावा दिया था। यदि हम यूरोप की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें जर्मनी की अतिस्फीति व अत्यन्त को नहीं भुलाना चाहिए। यदि हम भविष्य में अधिा स्थिरता पाना चाहते हैं तो हमें सीमना चाहिए कि हम उन गत्रनिया को दूर करें जिनके कारण इनको बढावा मिला।<sup>1</sup>

स्फीति को रोकने के उपाय (Measures to Check Inflation)

मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपायों को हम प्रमुख रूप से नीचे श्रेणियों में बाँट सकते हैं—

- (i) मौद्रिक उपाय
- (ii) राजकोषीय उपाय तथा
- (iii) प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा अन्य उपाय।

प्रथम दो प्रकार के उपायों की विस्तृत चर्चा मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति सम्बन्धी अध्यायों में की गई है। यहाँ पर इन उपायों की सशिक्त व्याख्या हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है।

(1) मौद्रिक उपाय (Monetary Measures)—मौद्रिक उपायों का अन्वयण वे उपाय होते हैं जिनका सम्बन्ध मुद्रा निष्कासि तथा उसको नियंत्रित करण धारि बाता स है। जब अति स्फीति की स्थिति होती है तबसि प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति व बाद जर्मनी देश में हुआ था। जर्मनी सरकार ने उस समय पुरानी मात्र मुद्रा को विचुन समाप्त करने गई मात्र मुद्रा घात में आती थी।

दम का वे द्वीय बैंक स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा तथा साग मुद्रा की पूर्ति पर नियन्त्रण तथा सक्ता है। इसके लिए वे-द्वीय बैंक के नाम तान तरीक प्रमुख रूप से है जिनका प्रयोग वन्द्रीय बैंक करता है।

(i) बैंक दर नीति

1 The depreciation of the mark of 1914-23 which is the subject of this work is one of the outstanding episodes in the history of the twentieth century. It was the most colossal thing of its kind in history and next probably to the great war itself. It must bear responsibility for many of the political and economic difficulties of our generation. It destroyed the wealth of the more solid elements in German society and it left behind a moral and economic disequilibrium apt breeding ground for the disasters which have followed. Hitler is the foster-child of the inflation. The financial convulsions of the great depression were in part at least the product of the distortions of the system of international borrowing and lending to which it ravages had given rise. If we are to understand correctly the present position of Europe we must not neglect the study of the great German inflation. If we are to plan for greater stability in the future we must learn to avoid the mistakes from which it sprang.



(ii) खुले बाजार की निवारण तथा

(iii) सदस्य बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास रखी जाने वाली निधि की मात्रा। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक द्वारा अधिक साख सृजन की नीति पर रोक लगाने की दृष्टि से केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर बढ़ा देता है जिससे व्यापारिक बैंकों के लिए केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाता है परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी बैंक दर बढ़ा देने के लिए बाध्य होना महंगा हो जाता है। केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की प्रियाओ (Open Market Operations) द्वारा प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों को मुद्रा बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुद्रा अपने पास रख लेता है और स्फीति पर काबू पाने में सफल हो जाता है। इससे अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक द्वारा न्यूनतम निधि अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है जिससे व्यापारिक बैंकों की नकदी कम हो जाती है और साख-सृजन की उनकी सीमा भी कम हो जाती है।

एक अर्द्ध-विकसित देश चुने हुए साख नियन्त्रण के तरीके सामान्य साख नियन्त्रण के तरीकों में अच्छे समझे जाते हैं। परन्तु साख नियन्त्रण की विभिन्न विधियों को अपनाने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वही नियन्त्रण इतने न हो जाए कि विकास योजनाओं के लिए धन ही उपलब्ध न हो। अर्द्ध-विकसित देशों के अनायास विकसित देशों में भी स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय अधिक फलदायक साबित नहीं हुए हैं। प्रो० हैन्सन का विचार है कि मौद्रिक उपायों को स्फीति के नियन्त्रण के लिए शोण उपायों के रूप में ही देखना चाहिए। वे कहते हैं कि स्फीति रोकने के लिए मुद्रा की प्रीति को नियन्त्रित करना एक उपाय हो सकता है परन्तु यदि स्फीतिक प्रभावों को रोकने के लिए मौद्रिक उपायों को अपनाने से अन्य बहुत सी बुराइयों से बचना चाहिए।

(II) राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures)—मौद्रिक उपाय जब स्फीति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते तो सरकार राजकोषीय उपाय अपनाती है। मौद्रिक उपायों के साथ ही राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। राजकोषीय उपायों में विशेष रूप से करारोपण, सरकारी व्यय तथा सार्वजनिक ऋण आदि आते हैं। इनका मक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

(i) करारोपण (Taxation)—इनके अन्तर्गत सरकार अतिरिक्त अथवा त्रय-शक्ति की जनता से करारोपण में वृद्धि करने प्राप्त करती है। इसके अन्तर्गत पुराने करों की मात्रा में वृद्धि तथा नये करों को लगान सम्मर्पण उपाय आते हैं। करारोपण सम्बन्धी नीति ऐसी होती है जिसमें जनता के पास की अतिरिक्त त्रय-शक्ति को अधिक में अधिक अपने पास की सरकार लेने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार उपभोग्य आय (Disposable Income) में कमी आती है। कुल समर्थ माँग गिरती है तथा स्फीतिक प्रभाव कम होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में करों में चोरी जैसी बुराई दिखाई देती है, इसलिए करारोपण के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में विशेष बल उठाने और सतर्कता बरतनी चाहिए।

(ii) सरकारी व्यय (Government Spending)—स्फीति को रोकने का राजकोषीय उपाय एक यह भी है कि सरकार को अपने बजट हुए व्यय विशेष रूप में अनुत्पादक तथा बेकार के व्ययों पर रोक लगानी चाहिए। वर्तमान समय में कुल व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए सरकार को अपने व्यय में मितव्ययता की नीति अपनाना चाहिए।

में पूँजी विनियोजन किया जाना चाहिए जो शीघ्र उत्पत्ति अथवा प्रतिफल प्रदान करने वाली हो।

(iii) मजदूरी नीति (Wage Policy)—स्फीति के समय सभी दग के कर्मचारी स्फीतिक प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए मजदूरी बढ़ाने पर जोर देते हैं। उत्पादकता पर ध्यान दिए बिना मजदूरी या भत्ते बढ़ाये जाते हैं तो इसका प्रभाव स्फीति को और बढ़ाता है। अति स्फीति का नया तेजी से घटती हुई स्फीतियों में मजदूरी लाभ जामनीति (Wage-Profit Freeze Policy) अपनाया चाहिए और मजदूरी वृद्धि का सम्बन्ध उत्पादकता से कर देना चाहिए। मजदूरी-लाभ बन्धन अथवा जाम-नीति से लोगों के पास उपभोग्य आय में गिरावट आती है और प्रभावपूर्ण माँग का स्तर भी नीचा रहता है।

(iv) विदेशी पूँजी (Foreign Capital)—एक उपाय यह है कि अधिक विदेशी पूँजी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएँ। विदेशी पूँजी द्वारा किए जाने वाले निवेश स्फीति को अधिक नहीं बढ़ाते।

(v) आयात नीति (Import Policy)—स्फीतिक प्रभाव कम करने की दिशा में उदार आयात नीति कारगर साबित हो सकती है यदि यह आयात आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाएँ। साथ ही निर्यातों में कमी करनी चाहिए परन्तु आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी सभी कारगर साबित हो सकती है जबकि देश की भुगतान सन्तुलन की स्थिति अच्छी हो।

अधिकांश विद्वान समझते हैं कि यदि स्फीति अपने प्रारम्भिक चरण में हो तो इस पर काबू पाना आसान है परन्तु यदि यह उग्ररूप धारण कर चुकी है तो इसको नियन्त्रित करना काफी कठिन हो जाता है। अति स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए समस्त पुरानी मुद्रा हटाकर नई मुद्रा चलाने में डालनी होती है जैसाकि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जर्मनी में किया गया था।

स्फीति एक भयानक स्थिति है इसलिए इसे नियन्त्रित करने के लिए किसी एक तरीके से काम नहीं चल सकता बल्कि विभिन्न उपायों को एक साथ अपनाने की आवश्यकता होती है। किसी एक कारण पर निर्भरता निर्णय एक भ्रष्टपूर्ण होती है।

**अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में स्फीति (Inflation in an Under-developed Economy)**

जैसाकि हम जानते हैं प्रो० बीन्स ने स्फीति का सम्बन्ध पूर्ण रोजगार की स्थिति से जोड़ते हुए बताया है कि स्फीति पूर्ण रोजगार के बिन्दु के बाद प्रारम्भ होती है क्योंकि इस बिन्दु में पहले के रोजगार साधन पाये जाते हैं और प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि से उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार बढ़ेंगे और कीमतें अधिक नहीं बढ़ेंगी। वास्तविकता एक व्यवहारिक पक्ष यह है कि पूर्ण रोजगार में बहुत पहले ही कीमतें बढ़ना प्रारम्भ हो जाती हैं, क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति न तो पूर्णतया लोचदार और न ही अन्य साधन जो कि उत्पादन लागत का बढ़ाते हैं। प्रो० बीन्स ने पूर्ण रोजगार से पहले स्फीति स्थिति के लिए निम्न कारण बताये हैं

(1) प्रभावपूर्ण माँग में परिवर्तन उस अनुपात में नहीं होगा जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति होती है।

(2) विभिन्न साधन एक जैसे नहीं होते इसलिए पूर्णतया स्थानापन्न नहीं होते और रोजगार के साधनों में वृद्धि के साथ घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है।

(3) चूंकि विभिन्न साधन एक-दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। कुछ वस्तुओं की पूर्ति की लोच लोचदार स्थिति में पहुँच जाती है जबकि कुछ साधनों में बेरोजगारी अन्य वस्तुओं को उत्पादित करने हेतु बनी रहती है।

(4) मजदूरी-इकाई पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में पहले बढ़ना प्रारम्भ हो जाती है।

(5) वह माध्यम जो सीमान्त माध्यम में प्रवेश कर चुक है उनका परिशोधन उन्नी अनुपात में परिवर्तित नहीं होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में कुछ और बर्तमान प्राप्ति होती है। जिनमें माध्याम रूप में वस्तुओं की पूर्ति में बाधनाई होती है और कीमती म तैजी में वृद्धि पाई जाती है। ये कारण निम्न प्रकार से हैं—

(1) ऐसी अर्थव्यवस्था में बाजार की बहुत सी अपूर्णताएँ देगन को मिनती हैं जैसा बाजार की जानकारी का अभाव साधना की अपूर्ण अविश्वस्यता तथा कुछ विशेष साधनों की गतिशीलता का अभाव आदि। इन तथ्यों के कारण उत्पादन व साधना का आदर्शतम अनुपात अधिक उत्पादन हेतु प्राप्त नहीं होने पाता।

(2) एक विकसित देश में बेरोजगारी हो पर भी प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि व कारण उत्पादन में वृद्धि होती है जबकि एक अर्द्ध विकसित देश में अर्द्ध-बेरोजगारी (Under-employment) तथा छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment) की स्थिति होने पर प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि नहीं होने देती। इस प्रकार मुद्रा प्रसार के कारण उच्च माँग तक पूर्ति नहीं बढ़ेगी जिस माँग तक प्रभावपूर्ण माँग बढ़ेगी और कीमती में वृद्धि बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाएगी।

इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और कारण भी हैं जोकि एक अर्द्ध-विकसित देश में स्फीतिक प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक प्रमुख कारण है वित्तीय साधना की कमी और विकास योजनाओं की पूर्ति हेतु हीनाय प्रयत्न (Deficit financing) का सहारा लेना पड़ता है जिससे स्फीतिक प्रभाव अधिक मालूम पड़ता है। विकास योजनाओं की पूर्ति हेतु पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी दिखाई देती है। इस प्रकार नरद मजदूरी बढ़ने के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुकूल उत्पादन नहीं बढ़ने पाना और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है।

### स्फीति तथा आर्थिक विकास (Inflation and Economic Development)

स्फीति तथा आर्थिक विकास में सम्बन्ध में अर्थशास्त्रों एकमत नहीं हैं। पहले हम उन अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करेंगे जिनका कहना है कि आर्थिक विकास के लिए स्फीति आवश्यक है जबकि दूसरी ओर ऐसे अर्थशास्त्रियों का कहना भी जाता है जिनका मत है कि स्फीति आर्थिक विकास के लिए जरूरी नहीं है बल्कि स्फीति आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है।

प्रो० कोन्स का कहना है कि आर्थिक विकास के लिए स्फीति सहायक होती है। ऐसा माना जाता है कि स्फीति साधनों में गतिशीलता लाती है और मजदूरी प्राप्ति करने साधना से आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण करने लाभ प्राप्त करने वाले साधना तक ले जाती है। चूंकि लाभ प्राप्त करने वाले वर्ग की बचत करने की सीमान्त प्रवृत्ति मजदूरी प्राप्ति करने वाले वर्ग की अपेक्षा उंची होती है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग अपनी बचत को उत्पादन क्षेत्र में लगाकर आर्थिक विकास को दूर कर बढ़ाने है। प्रो० कोन्स आगे कहते हैं कि दोरी-सी स्फीति में कीमती बढ़ती है और उपभोक्ताओं में आशावादना की विरण दिखाई देती है और भविष्य में लाभ की अपेक्षा व कारण के निवेदन को बढ़ाने है। प्रो० मारिन डाव न स्फीति का आर्थिक विकास को दूर करती माना है। प्रो० बालहार का बयान भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है एक छिपी तथा

प्रगतिशील दर में स्फीति या हाहा आर्थिक प्रगति की दर में तेजी लाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली आधार है।<sup>1</sup> प्रो० राबर्टसन ने आर्थिक विकास के लिए हल्की स्फीति को जरूरी माना है। एक अर्द्ध-विकसित देश में ऐसी नीति अधिक कारगर साबित होती है क्योंकि इन देशों में श्रमिका की बहुत बड़ी संख्या स्व रोजगार प्राप्त होती है तथा हल्की स्फीति द्वारा कीमती म प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

बहुत में अर्थशास्त्री हल्की स्फीति (Mild Inflation) को आर्थिक विकास के लिए अनावश्यक नहीं मानते। इन विद्वानों का कहना है कि हमारे वर्तमान संस्थानिक ढाँचे में (Institutional set-up) कीमती म वृद्धि साधना में बेंचवारे की दृष्टि में अर्थव्यवस्था को प्रगतिशीलता की ओर ले जाती है जबकि कीमती म गिरावट से अर्थव्यवस्था में गति-हीनता (Stagnation) की स्थिति आती है। ऐसा कहा जाता है कि सघा तथा फर्मों की एकाधिकारिक शक्ति ऐसी है जिसमें कीमती म वृद्धि आवश्यक है ऐसी स्थिति में अधिकारियों को चाहिए कि वे संबुचनोत्सव नीतियाँ (Deflationary Policies) को न अपनाएँ जिनसे कीमती म गिरावट की अपेक्षा बेरोजगारी अधिक बढ़ती है।

कुछ अर्थशास्त्री स्फीति को आर्थिक वृद्धि की उत्पत्ति मानते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में छोड़ी की स्फीति से बचा नहीं जा सकता। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ उत्पादन में वृद्धि होने में थोड़ा सा समय लगता है और यही कारण है कि कीमती म स्तर में वृद्धि दिखाई देती है। यदि नियोजन निवेश देश में वास्तविक प्रचलना में अधिक हाथों में निश्चित रूप में स्फीति का प्रभाव दिखाई देगा।

अर्थशास्त्रियों का एक अन्य वर्ग है जो कहता है कि स्फीति आर्थिक विकास के स्थान पर आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है। अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० मिल्टन फ्रीडमैन (Prof Milton Friedman) का कहना है कि स्फीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति अपनाना कोई निवृत्तपूर्ण तर्क नहीं है। वह इस बात से भी सहमत नहीं है कि स्फीति आर्थिक विकास में निरपेक्ष अनिवाय तत्व है। वे कहते हैं कि इस स्थिति में भी कोई संकट नहीं है कि स्फीति साधना में पुनर्वितरण द्वारा आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान करती है। उनका मत है कि विगत समय में साधना में पुनर्वितरण के प्रभाव कुछ हद तक आर्थिक विकास के लिए अनुकूल रहे हैं परन्तु इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि यह अनुकूल प्रभाव (Favourable Effects) सभी स्थितियों में दिखाई देगे। प्रो० फ्रीडमैन का विश्वास है कि मुद्रा की पूर्ण जानबूझकर की गई वृद्धि में हमारे अनुकूल प्रभाव प्राप्त नहीं किए जा सकते। जब स्फीति प्रक्रिया जानबूझकर अपनाई जाए तो बहुत में लोगों को उनकी जानकारी हो जाएगी और उनका व्यवहार पुनर्वितरण प्रभाव को रोकने का होगा। प्रो० रैगनर नर्से (Prof Ragnar Nurkse) ने कहा है कि स्फीति की सफलता पूर्ण निर्माण के चरण के रूप में कितनी है, यह अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करेगा कि भावी तथा गैर सम्भावित कीमतों में वृद्धि की मात्रा कितनी है। यदि कीमती म में वृद्धि निश्चित एवं सम्भावित है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ने से बचता है स्थान पर व्यय होने है तथा स्फीति पूर्ण निर्माण को शक्ति कम करती है।

स्फीति मुद्रा में वास्तविक मूल्य का कम करती है इसलिए लोग बचत के स्थान पर पैर जिम्मेदारी व्यय करते हैं। स्फीति पूर्ण निर्माण में बाधा ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि

1. " a slow and steady rate of inflation provides a most powerful aid to the attainment of a steady rate of economic progress " Nicholas Kaldor-Economic Growth and Problem of Inflation, Economica 1959.

दश की पूंजी का बाहर भी ल जाती है। स्फीति में व्यापारिक क्रियाओं का शक्ति एवं दिशा उत्पादक कार्यों व स्थान पर मुद्रा क्षेत्र का क्रिया का आर जाता है। स्फीति कास में कीमता व बड़न में दश व निर्यात व्यापार का घटता गता है। निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ती है तथा आयात बढ़ि हाव है। कुल निर्यात दश की भूतान मनुत्तन को स्थिति प्रतिबून हा जाती है। विदेशी माहाग में स्फीति वान दश की माग को घटता लयता है विदेशी ऋणा का वाग बढ़ जाता है।

### अवस्फीति (Deflation)

#### अवस्फीति की परिभाषा (Definition of Deflation)

अवस्फीति स्फीति व विन्तुन विपरात स्थिति होता है। दश कीमता व उगातार गिरन की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रो० पाउ इन्जिग (Prof Paul Einzig) ने अवस्फीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवस्फीति असन्तुन की वह स्थिति है जिनमें प्रय गति में सन्तुचन कीमत स्तर में गिरावट का कारण अथवा उसका परिणाम होता है।<sup>1</sup> प्रा० बोलबोन ने अनुमात्र अनैच्छिक बेरोजगारी अवस्फीति की बगौरी है।<sup>2</sup> प्रो० पाणू की अवस्फीति की परिभाषा इस प्रकार है— अवस्फीति कीमत-स्तर व गिरन की वह भवस्था है जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय का तुलना में तर्ती में बढ़ता है। प्रा० पीगू ने कीमत-स्तर को प्रत्येक गिरावट को अवस्फीति का ससा नहा दो है उनका अनुमात्र अवस्फीति की स्थिति निम्न बातों व होने पर पाई जाएगी

(1) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़ें परन्तु उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो।

(2) जब उत्पादन की मात्रा बढ़ रही हो और मौद्रिक आय स्थिर हो।

(3) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों कम हो परन्तु मौद्रिक आय तेजी से गिरने की प्रवृत्ति दिशाए।

(4) जब मौद्रिक आय घटता हो तथा उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे।

(5) जब उत्पादन की मात्रा बढ़े तथा मौद्रिक आय घटे।

मुद्रा अवस्फीति की उपर्युक्त परिभाषाओं ने प्रा० पाउ इन्जिग की परिभाषा अजिब उपयुक्त एवं तर्कमूलक मान्य पड़ती है। कीमत-स्तर में हान का प्रत्येक गिरावट का अवस्फीति को ससा नहा दो जा सकती है। कीमत-स्तर में हर्द गिरकर मुद्रा पूति में कमी का ही परिणाम नहीं होती परन्तु कीमत-स्तर में हर्द कमी मुद्रा पूति व सन्तुचन का कारण भी हो सकती है। यदि कीमता में गिरावट उगातार होता है तो अथव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितना कि पढ़न जाती थी। इस प्रकार कीमत स्तर मुद्रा पूति में हर्द कमी का परिणाम भा है और कारण भा।

अवस्फीति उन समय उत्पन्न होता है जब कि मनुदाय द्वारा किया गया कुल व्यय वतमान कामता पर उपलब्ध कुल उत्पादक मूल्य में कम हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तथा कीमता में गिरावट दशक का मिलती है। हम यह पाद रगता

1 Deflation is a state of disequilibrium in which a contraction of purchasing power tends to cause or is the effect of a decline of the price level "  
—Paul Einzig

2 Involuntary unemployment is the hall mark of Deflation "

—Coulborn

चाहिए कि कीमता में प्रत्येक तथा नवीन प्रकार की गिरावट को अवस्फीति नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ जब हम स्फीति के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रभावपूर्ण मोद्रिक तथा राजकोषीय उपायों द्वारा नियन्त्रित करते हैं। उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार बढ़ता है परन्तु कीमतें गिरना प्रारम्भ हो जाती हैं तो इस अवस्फीति नहीं मानना चाहिए।

**मुद्रा-विस्फीति (Disinflation)**—वह प्रक्रिया जिसमें स्फीति को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं तथा जिसमें बेरोजगारी तथा उत्पादन में गिरावट नहीं होती उस अवस्फीति को कहकर मुद्रा-विस्फीति (Disinflation) कहते हैं। अवस्फीति प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण उत्पन्न होती है और सामान्य मन्दी की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाती है जबकि विस्फीति (Disinflation) का उद्देश्य लागतों तथा कीमतों में गिरावट लाना होता है जबकि कीमतों में वृद्धि अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही हो। कीमतों में इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि को विस्फीति द्वारा नीचे लाना वाछनीय होता है, क्योंकि इस प्रकार की कीमतों में गिरावट से उत्पादन तथा रोजगार का स्तर नीचे नहीं गिरता। इसके विपरीत अवस्फीति (Deflation) समुदाय के लिए घातक एवं नाशकारी होती है क्योंकि कीमतों में प्रत्येक गिरावट बेरोजगारी में वृद्धि, उत्पादन तथा नौजा की आय में गिरावट आती है।

**प्रत्यवस्फीति अथवा प्रतिस्फीति (Reflation)**

एक अन्य स्थिति जहाँ मन्दी और स्फीति के बीच पाई जाती है उसे प्रत्यवस्फीति (Reflation) कहते हैं। प्रो० जी० डी० एच० कोल ने प्रत्यवस्फीति का लक्षण बताते हुए कहा है 'प्रत्यवस्फीति उम विशेष प्रकार की स्फीति को कहते हैं जिसमें जानबूझकर मन्दी को छुटकारा पाने के लिए किया जाता है।'<sup>1</sup> जब कीमत-स्तर तर्जों से गिरने लगता है तो अर्थव्यवस्था को मन्दी में मुक्त करने के लिए मुद्रा-विस्तार किया जाता है तो इस प्रतिस्फीति अथवा प्रत्यवस्फीति कहा जाता है। इस अन्तर्गत कीमत-स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठने लगता है और अर्थव्यवस्था को मन्दी की स्थिति से छुटकारा मिलने लगता है। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा प्रतिस्फीति (Reflation) दोनों में ही कीमत-स्तर ऊपर को उठता है, परन्तु दोनों ही स्थितियों में कुछ मौलिक अन्तर (निम्न प्रकार से) बतलाए जा सकते हैं :

(1) मुद्रा स्फीति ऐच्छिक एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है जबकि प्रतिस्फीति ऐच्छिक होती है और सरकार द्वारा इस सोच समझकर उठाया गया कदम कहना गलत नहीं होगा।

(2) कीमतों के अनुसार स्फीति पूर्ण रोजगार बिन्दु तक वाद होती है जबकि प्रतिस्फीति पूर्ण रोजगार बिन्दु से पहले ही होती है।

(3) दोनों में ही कीमतें बढ़ती हैं परन्तु प्रतिस्फीति की तुलना में स्फीति में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं।

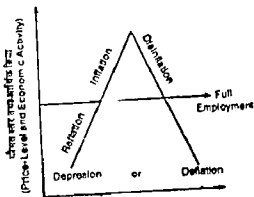
(4) मुद्रा स्फीति को यदि नियन्त्रित न किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देती है जबकि प्रतिस्फीति का नियन्त्रण सरकार के हाथों की बात रहती है।

हम एक रूपाचित्र द्वारा स्फीति, अवस्फीति, प्रतिस्फीति तथा मुद्रा विस्फीति (Inflation, Depression, Reflation and Disinflation) को व्यक्त कर सकते हैं।

1. 'Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve depression.'  
—G. D. H. Cole

मुद्रा अवस्फीति के प्रभाव (Effects of Deflation) .

मुद्रा अवस्फीति मुद्रा स्फीति का तुलना में अधिक हानिकारक एवं भयावह होने है। समाज के विभिन्न वर्गों पर दत्त प्रभाव अधिक दूरगामी एवं पक्का होता है। इसमें



उत्पादन व्यापारिक क्रियाओं तथा रोजगार में स्तर पर बहुत ही प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ता है। इसमें अन्ततः जब कीमतें तजी से गिरती हैं परन्तु उन्नी अनुपात में गिरती हैं गिरावट नहीं होती और उत्पादन को काफी हानि उठानी पड़ती है। साथ ही उत्पादन तथा रोजगार भी गिरते हैं। इसका प्रभाव कुल आय में गिरावट तथा कुल माँग में गिरावट के रूप में दगने को मिलता है। परिणामस्वरूप कीमता में और अगि गिरावट आती है और यह प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। व्यापारिक क्रियाओं में तारा और निराशावादी दृष्टिकोण छा जाता है जो अत में अव्यवस्था को मन्सी में पहुँचा देता है। अवस्फीति में अर्थव्यवस्था माधना के अनुपयोग होने से व्यापिक बर्बादी तो होती ही है साथ ही उनको कुशलता में गिरावट उड़े हलोल्लाहित कर देती है। बरोजगार व्यक्ति का भ्रष्ट बना देती है और बरोजगार व्यक्ति समाज के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। बरोजगार अवस्फीति को भयंकर स्थिति एवं अधिशाप है।

अवस्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव स्थिति के प्रभाव के विन्तुन विपरीत होता है। उदाहरणार्थ यदि मुद्रा स्फीति में निश्चित आय वान तथा मध्यम वर्ग की स्थिति सबसे खराब होती है जबकि अवस्फीति में निश्चित आय वान वर्ग की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ने अथवा कीमत-स्तर में सगता गिरावट के कारण इस वर्ग की वास्तविक उपभोग्य आय (Real Disposable Income) अधिक हो जाती है। वनमान आय से यह वर्ग अगि वस्तुएँ तथा सेवाएँ क्रय कर सकता है। इसी प्रकार यह व्यापारिक तथा उद्यमकर्ता पर प्रतिबन्ध प्रभाव डालता है। उनकी कुल आय गिरती है, टैक्स का रूप में सरकार से भुगतान तथा उत्पाद के अर्थ माधना के पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली पनराशि प्रारिबन्धित रहती है। प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट के कारण उपरान्त उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग तो नही होना साथ ही कुछ प्लाण्ट महीना बेकार पड़े रहने हैं। वित्तीय दृष्टि से कमतरा इरादवा दिशाधिया हातर बन्द हो जाती है। अवस्फीति स्थिति में कृपना का स्थिति भी बारी खराब हो जाती है क्योंकि निमित्त वस्तुओं का अपना कृपि दीन के उत्पादन का कीमतेँ तेजी से गिरना है।

अवस्फीति में निश्चित किराया तथा म्याज अत्रित बन वान माहगिया को लाभ होता है। सभी निश्चित आय वान वर्गों को लाभ तथा परिजनकीन अर्थ वान वान वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे तो अवस्फीति बान में बचता को बढ़ाकर पिनता

है परन्तु माधारणतया आय में निरन्तर गिरावट से बचत करने की योग्यता भी गिर जाती है।

मुद्रा अस्फीति के उपायों में से एक है। अस्फीति में उत्पादन राजस्व आय सभी गिरती है। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है। आज भी दुनिया के देश सन् 1930 की मन्दी का इतना समय बीत जान के बाद भी नहीं भुला पाए हैं। कीमत-स्तर में गिरावट आज भी किसी देश को तीसरे की मन्दी की याद से चौंका देती है।

### अस्फीति को रोकने के उपाय (Measures to Control Deflation)

अस्फीति को रोकने के लिए हम मजबूत रूप से ऐसी नीति अपनाती चाहिए जिससे कुल उत्पादन तथा रोजगार में स्तर में वृद्धि हो। परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाँ प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाएँ। चूँकि अस्फीति का कारण निजी क्षेत्र में व्यापारिक क्रियाओं में सुस्ती आ जाती है और चारा और निराशावादी दृष्टि-काण्ण दृष्टान्त का मिश्रण है इसलिए सरकारी क्षेत्र में आर्थिक शक्तियाँ मोड़नी तथा राजस्व आय शक्तियों का इस प्रकार कार्यान्वित किया जाय जिससे कि कुल उपभोग तथा कुल निवेश माँग में वृद्धि होकर कुल प्रभावपूर्ण माँग बढ़ना चाहिए।

मुद्रा अस्फीति (Deflation) की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक उपाय का अपनायन में हाता है जिससे कि प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं निवेश का बढ़ाना हेतु कदम उठाने चाहिए। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि उपभोग एवं निवेश का बढ़ाने से प्रभावित होता है जिससे कि राजस्व का स्तर बढ़े। कुल मिलाकर हम निम्न उपाय अपनायें जा सकते हैं

(1) करों में छूट (Tax Relief)—अस्फीति में मजबूत प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि हेतु सरकार का ऐसी नीति अपनायें चाहिए जिसमें लोगो का भाग उपभोग्य आय बढ़े। इसके लिए करों में छूट का उपाय प्रयोग करना चाहिए, परन्तु ऐसा करते समय सरकार का यह ध्यान चाहिए कि करों में छूट से लोगो की उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) बढ़े। यदि करदाताओं की सीमान्त व्यय प्रवृत्ति ऊँची है तो कर-छूट नीति सफल होगी। इसके विपरीत यदि करदाताओं की सीमान्त व्यय प्रवृत्ति कम है तो कर-छूट से कुल समर्थ माँग में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होगी।

(2) सरकारी व्यय में वृद्धि (Increase in Government Expenditure)—अस्फीति में निजी क्षेत्र में निरम गिर जाते हैं क्योंकि व्यापारिक क्रियाएँ स्थिर पड़ जाती हैं। इसलिए निवेश में वृद्धि के लिए आवश्यक निरम बढ़ाने के लिए सरकार का नये मावजनिन को अपना हाथ में लेकर व्यय बढ़ाने चाहिए। सरकार का ऐसी योजनाओं को हाथ में लेना चाहिए जिससे कि लोगो को अधिक में अधिक राजस्व प्रदान किया जा सके। सरकार का व्यय बढ़ाने हेतु घाट के बजट (Deficits Budget) बनाना चाहिए ऐसा करके कुल उपभोग माँग में वृद्धि की जा सकती है।

सन् 1930 में अमरीका की न्यू डील नीति (New Deal Policy) तथा फ्रांसीसी ब्लम प्रयोग (Blum Experiment) यह बताते हैं कि इन देशों में मन्दी से उबरने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाकर मजबूतता प्राप्त की थी और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ था। मन्दी में मजबूत सरकार को ऐसी बड़ी योजनाओं का हाथ में लेना चाहिए जो निजी साहसिकता को प्रोत्साहित करें। अर्थात् निरम अर्जित करने वाली न हो। मावजनिन काय नीति प्रभाव-शाली है, यह हम बात पर निर्भर करता है कि इन योजनाओं के लिए वित्तीय साधन कैसे जुटाए जा रहे हैं। वे मावजनिन काय निरम वित्तीय व्यवस्था पराधीनता द्वारा हो



रही है। अवस्फीति से निपटने के लिए उतने कारगर साधित नहीं होते जितने कि मास्रजनिष्ठा तथा पाटे के बजट द्वारा प्राप्त वित्तीय साधनों की प्राप्ति में हो।

(3) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)—अवस्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति का भी महत्त्व लिया जाता है। देश के वित्तीय ढँक द्वारा मास्र नियन्त्रण के उपार्थों में दोन देकर मास्र मुद्राजन शक्ति व्यापारिक ढँकों की बढ़ाई जाती है। ढँक दरों में कमी करने व्यापारिक ढँकों के लवद कोष बढ़ाए जाते हैं। मुले बाजार की गिमाज मुद्राजन वेंध आरक्षित अनुपात तथा अन्य सास्र-नियन्त्रणों का उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति तथा निवेशों में वृद्धि करने प्रभावपूर्ण मास्र में वृद्धि करने रोजगार उत्पादन तथा आय के स्तर में वृद्धि करना होना चाहिए।

मौद्रिक नीति द्वारा निवेशों में वृद्धि सभी सम्भव है जबकि व्यापारों में अधिकत्व में प्रति भाषावान एवं उत्साही प्रतीत हो। यदि साहसी निराशावादी है तो ये वित्तीय ढँक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति उत्साही एवं आशानुबल व्यवहार नहीं करेंगे और निवेशों में वृद्धि नहीं होगी।

(4) पुराने ऋणों का मुगतान (Repayment of Old Loans)—सरकार को पारिष्ठा कि यह पुराने सार्वजनिक ऋणा का मुगतान करके मास्र के पास प्रय शक्ति में वृद्धि करे। ऐसा करके सरकार अवस्फीतिक (Deflationary) स्थिति पर कुछ मास्र तथा मास्र पात्र में सापस गिड हो सकती है।

### स्फीति तथा अवस्फीति के बीच चुनाव (Choice between Inflation and Deflation)

मुद्रा स्फीति तथा अवस्फीति दोनों ही अर्धव्यवस्था के लिए घालक होती हैं, क्योंकि दोनों ही अशानुमन की स्थिति को यताती हैं। दोनों में अवस्फीति मुद्रा-स्फीति की तुलना में अधिक भयानक साधित होती है। निम्न तथ्यों में इसकी पुष्टि होती है—

(1) मानव धम का विनाश—स्फीति में कीमता में वृद्धि होती है और यह वृद्धि शक्ति यह सेते है। स्फीति में रोजगार बढ़ान की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि मास्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अवस्फीति में मूल्यों में गिरावट होने से अर्धव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति बनी रहती है। वस्तुओं के स्टॉकों में वृद्धि के कारण सेवायोजन अपने उत्पादन को घटाने पसत है। बेरोजगारी भीषण रूप धारण कर लेती है। अवस्फीति तर्जन सम्पति (Wealth) के मुद्राजन में बाधा उत्पन्न करके बेरोजगारी बढ़ान के साथ उत्पादन में कटौती के लिए भी उत्तरदायी होता है। बेरोजगारी श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में हानि लाती है और यदि मन्दी अधिक समय तक रहे तो बेरोजगारी उद्दे कार्य करने योग्य भी नहीं रहती। बेरोजगारी के कारण धम दिवसों (Man days) की बहुत बरी हानि होती है। मानव धम विनाश उत्पादन बढ़ा। तथा अन्य विनाश कार्य को पूरा करने में महत्त्वता मिलती है वह व्यर्थ जाता है और राष्ट्र एवं समाज को प्रगति की दृष्टि में घण्टाघर काफी पीछे घटप दिया जाता है।

(2) समाज पर भार के नैतिक पतन—अवस्फीति बेरोजगारी की बहुत बरी पीड बना दाता है जो एक प्रकार में समाज पर एक बोझ साधित होते है। वे अपयोग तथा अनुमान बनाए रह जाते है। समाज में ऐस बेवार मास्र का नैतिक पतन हो जाता है। घुटगाट और आराध बढ़ जाते है। स्फीतिमान में नैतिक पतन, घुटगाट, विमावट, मास्रधरी, रिश्वतगोरी के रूप में सामा आता है। व्यक्ति को मर्दगई के कारण स्फीतिवाल में दोन समय पेटभर भोजन प्राप्त करना एक कठिन समस्या बन जाती है।

(3) ध्वय करने का अधिकार—प्रो० कीन्स कहते हैं कि स्फीति यद्यपि लोगों को ध्वय करने का अधिकार प्रदान करती है परन्तु व्यय उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिफल को छीन लेती है। जब कि अवस्फीति में स्थिति इससे भी भयानक होती है क्योंकि बेरोजगारी व्यक्ति को ध्वय करने के अधिकार से वंचित कर देती है। इस सत्य को नहीं भुलाया जा सकता कि विल्कुल रोटी न मिले वी तुलना में आधी रोटी मिल पाना वही अधिक सतोप-प्रद एवं अच्छा है। स्फीति में श्रमिक को राम प्राप्त होने से आधी रोटी का महारा तो रहता है जबकि अवस्फीति में श्रमिक बेकार रहने से कारण उस आधी रोटी के उपभोग से वंचित रह जाता है।

(4) विनियोजन की गति—मुद्रा स्फीति उत्पादक वग व भाग में वृद्धि रख विदेशों के लिए आभारानुसार वातावरण उत्पन्न करके वृद्धि करती है जिससे निवेशों का स्तर ऊँचा बना रहता है। इससे विपरीत अवस्फीति उद्यमकर्त्ता के लिए विभी प्रवार का प्रोत्साहन नहीं देती। निरन्तर हानि उठाने के कारण उद्यमकर्त्ता भविष्य में प्रति निराशा-वादी हो जाते हैं। अवस्फीति लभान तथा विरामे की आय (Rentier Class) प्राप्त कराने वाले अनुत्पादक वग का उत्साह प्रदान करती है। प्रो० कीन्स के विचारानुसार समाज में बेरोजगारी उत्पन्न करने तथा उत्पादक वग को हतोत्साहित करने का तुलना में विराम की आय पर रहने वाले अनुत्पादक वग को निराश करना अधिक अच्छा है।

अधव्यवस्था के लिये स्फीति तथा अवस्फीति (Inflation and Deflation) दाना ही बुराईयाँ हैं और अधिक प्रणाली की स्थिरता की दृष्टि से दोनों में ही कुछ न कुछ दाप पाए जाते हैं परन्तु जब कभी भी दो बुराईयाँ में से एक को चुनने की बात गमन आती है तो हम निश्चित रूप से अधिक बुराई का अपेक्षा कम बुराई वाली स्थिति का चयन करेंगे। ठीक इसी दृष्टि से स्फीति तथा अवस्फीति दाना ही समाज के लिए बुराईयाँ हैं फिर भी दोनों में अवस्फीति अधिक बुरी है। प्रो० कीन्स के विचारानुसार स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अवस्फीति अनुपयुक्त है। इन दोनों में शायद अवस्फीति अधिक बुरी है।<sup>1</sup> कीन्स ने अवस्फीति का स्फीति की तुलना में अधिक बुरा माना है। थोड़ी सी स्फीति आर्थिक माँगोंरूपी उद्योग में चिक्नाई का कार्य करके उसे गतिशील बनाती है जिससे पुनः उत्पादन में वृद्धि होती है जबकि अवस्फीति कुल उत्पादन को गिराती है।

स्फीति समाज में आय तथा सम्पत्ति के बँटवारे में असमानता लाकर निधना का और निधन तथा धनी का और धनी बनाती है परन्तु यह अवस्फीति की भाँति वास्तविक आय की भूरा मात्रा को कम नहीं करती। स्फीति को रोचना उतना ठठिन नहीं है जितना कि अवस्फीति को रोचना ठठिन होता है। यदि दररा जाय तो वास्तविकता यह है कि भयानक मन्दी के समय लगभग सभी व्यक्ति जिसमें व श्रमदाता भी शामिल होते हैं जिनके पास बहुत से श्रम वसूत्र करने की पडे हैं। उसको भी नुकसान होता है। हालाँकि प्रो० कीन्स ने स्फीति और अवस्फीति के मध्य चुनाव की समस्या उत्पन्न हान पर मुद्रा-स्फीति को चुनने का सुझाव दिया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं गगाना चाहिए कि व स्फीति को अच्छा मानते थे।

स्फीति तथा अवस्फीति दाना ही बुरी हैं और इनके मध्य चुनाव करने जैसी बात हानी ही नहीं चाहिए। हम तो अधव्यवस्था में स्थिरता एवं सन्तुलन बनाए रखने का प्रयास करते हुए दोनों बुराईयाँ से बचना चाहिए।

1 Inflation is unjust and deflation is inexpedient of the two, perhaps deflation is the worse' — J. M. Keynes

### परीक्षा-प्रश्न

- 1 मुद्रा-स्फीति क्या है ? स्फीतिक प्रक्रिया को बताइए और साथ ही स्फीति के प्रमुख प्रकार बताइए ।

(What is inflation ? Give inflationary process along with main types of inflation )

- 2 स्फीति के प्रभाव क्या हैं तथा स्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ?

(What are the effects of inflation and how can inflation be controlled ?)

- 3 स्फीतिक अन्तराल क्या है ? यह कैसे उत्पन्न होता है और अव्यवस्था में इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है ?

(What is inflationary gap ? How does it arise and how can it be removed in the economy ?)

[सकेत लागत प्रेरित तथा माँग प्रेरित स्फीति को विस्तृत व्याख्या दीजिए फिर बताइए कि वास्तविक स्थिति को समझने के लिए दोनों जरूरी हैं।]

- 4 माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्फीति में भेद कीजिए । क्या आप इन दोनों प्रकार की स्फीतियों में किए गए भेद को उपयोगी मानते हैं ?

(Distinguish between demand pull and cost push inflation Do you regard the distinction between these two kinds of inflation as useful ?)

[सकेत—पहले माँग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्फीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए । फिर बताइए कि वास्तविक स्थिति समझने के लिए दोनों की उपयोगिता अपनी-अपनी जगह है।]

- 5 मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । देश के विभिन्न वर्गों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है ?

(Explain clearly the meaning of inflation and deflation How do they effect different sections of society in the country ?)

- 6 मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का अन्तर स्पष्ट कीजिए । उनका देश की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(Distinguish between inflation and deflation How do they affect the economic growth of any country ?)

- 7 "स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अवस्फीति अनुपयुक्त इन दोनों में शायद अवस्फीति अधिक बुरी है ।" क्या आप कीन्स के इस बयान से सहमत हैं ?

( Inflation is unjust Deflation is inexpedient of the two perhaps deflation is the worse ' Do you agree with Keynes s state ment ?)

[सकेत—पहले स्फीति तथा अवस्फीति का अर्थ बताइए उसके बाद इस अध्याय के अन्त में दोनों के बीच चुनाव शीर्षक की सामग्री दीजिए तथा निष्कर्ष बताइए कि दोनों में अवस्फीति अधिक बुरी है।]

निर्माण करने उह लाभप्रद योजनाओं में प्रगत हैं। बैंकी का देश के व्यापारिक विकास में भी योगदान है। बैंक वस्तु बाजार का व्यापक रूप लेकर व्यापारिक प्रियाओं का विस्तार में सहायता देते हैं। व्यापारिक बंध निम्नलिखित रूप में देश का आर्थिक प्रगति में सहायता पहुँचाते हैं।

**बैंक व्यापार तथा उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं**

दुनियाँ के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि 200 वर्षों से अधिक समय में ज्ञान वाली आर्थिक प्रगति में बैंक का काफी मदद की है। व्यापक व्यापारिक प्रियाओं तथा देश में आधुनिकीकरण में बैंक का भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जैसा कि हम देख चुके हैं व्यापारिक बैंक साख निर्माण करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं। जब बैंक कम उधार या अधिक देता है तो साख-मुद्रा की पूर्ति का बढ़ाता है। वर्तमान समय में बैंक जमा या जिनको सामान्यतया बैंकों का माध्यम से निबाना जाता है तथा जिसको वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयत्न के लिए खिया जाता है कुल मुद्रा पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। बैंक न बैंक तथा डाकट जैसी साख मुद्रा को चलाने में डाकट व्यापारिक विनियम सुगम एवं जोखिम रहित बना दिया है। आज कितनी ही बची राशि का भुगतान बैंक चाफटा विनियम हण्डियाँ द्वारा सम्भव हो पाया है। साख मुद्रा का चलाने में स्वदेशी व्यापार के अलावा विदेशी व्यापार के विकास में काफी सहायता दी है। व्यापारिक प्रियाओं तथा बाजार में विस्तृत ज्ञान विशिष्टीकरण औद्योगिक विकास आदि बहुत कुछ कार्य उन्नत बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करत हैं। बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को दल्पकालिक मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक वित्तीय सहायता का प्रदान करत हैं। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सलाहकार तथा पथ प्रदर्शक का कार्य भी करत हैं।

**बैंकों द्वारा देश में उपयुक्त उद्योगों का विकास करना**

बैंक देश में निवेशकताओं का उत्पादक कार्यों के लिए वचनवादी तथा दीर्घकालीन श्रृणा की व्यवस्था करके उह नकद पूंजी उपलब्ध कराने हैं। बैंक की भूमिका आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रहता बरन् उसका प्रोत्साहित करने में बैंक का योगदान भी कम नहीं है। बैंक श्रृणा की सहायता से साहसा अपना इवाई की उत्पादकता बढ़ाकर नई उत्पादन तकनीकों को अपना कर तथा नये नये यंत्रों तथा मशीनों की सहायता से अपने उत्पादन की प्रगत को कम करके बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों के सामने टिक सकता है। बैंक सामान्यतया उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करके देश में उद्योगों का समुचित विकास करके देश का उत्पादकता बढ़ाने में प्रोत्साहित रूप से योगदान करत हैं। परिणामस्वरूप देश में उत्पादन साधना की कार्यक्षमता में वृद्धि ता हाता ही है साथ में राष्ट्रीय आय का स्तर ऊँचा रहता है जिससे उपभोग तथा विनियोग का स्तर भी ऊँचा रहता है। कुल मिला कर, देश, आर्थिक प्रगति, क. निर्णय, क. उपयुक्त, प्रगति, करते हैं।

**देश में पूंजी वितरण असमतलन को दूर करना**

बैंक देश में व्याप्त पूंजी वितरण को असमतलन का दूर करत हैं। व्यापारिक बैंक देश में पूंजी साधना को उन क्षेत्रों में ल जाते हैं जहाँ इनका अभाव पाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक असमतलन को दूर करने में बैंक का योगदान भी किसी प्रकार से नहीं है। देश में विकसित क्षेत्रों से पूंजी का हटाकर अविकसित क्षेत्रों की ओर ले जान में बैंक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास में मदद करत हैं। बैंक न क्षेत्रीय आर्थिक असमतलन को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

### देश में पूंजी संचय तथा पूंजी का निर्माण को प्रोत्साहित करना

बैंक बचतकर्ताओं की बचतों को एकत्रित करके पूंजी संचय तथा पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बैंक बचत सुविधाओं को प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण संस्था है। जहाँ बचतों को एकत्रित करके बैंक पूंजी संचय को सम्भव बनाते हैं वहीं दूसरी ओर बैंक छोटे-छोटे बचतकर्ताओं की पूंजी को एकत्रित करके एक बड़े पूंजी कोष को जन्म देते हैं तथा ऋण माँगने वाले ब्राह्मणों को एक ही स्थान पर ऋण मिल जाते हैं। बचतें पूंजी निर्माण का आधार होती हैं इसलिए बैंक का देश में पूंजी निर्माण करके आर्थिक विकास में सराहनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं बैंक बेकार तथा फालतू पड़ी हुई पूंजी को उत्पादन कार्यों में लगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपनी भागीदारी बनाए रखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की बचतों तथा निवेशों का परिणाम होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में उपभोग का स्तर ऊँचा और बचत का स्तर नीचा होता है जिससे आर्थिक योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन कम पड़ जाते हैं।

### साख निर्माण द्वारा व्यापार को विकसित करना

व्यापारिक बैंक साख-निर्माता होते हैं। साख मुद्रा की पूर्ति में होने वाले उच्चावचनों का देश को आर्थिक प्रगति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। जब अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश की अधिक आवश्यकता हो तो व्यापारिक बैंकों को अधिक साख-निर्माण करने की नीति देश का केन्द्रीय बैंक अपना सकता है। व्यापारी तथा निर्माता वर्ग को अधिक ऋण प्रदान करके निवेशों को बैंक बढ़ा सकता है। जिससे देश में आय तथा रोजगार का स्तर ऊँचा हो जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके बैंक व्यापार तथा उद्योगों को ऋण प्रदान करके पूंजी निवेश बढ़ा सकते हैं जिससे कि देश का विकास तीव्र गति से हो सके।

### बैंक द्वारा ऋणों का मुद्रोकरण करना

व्यापारिक बैंक अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक तुष्टियों के बदले में माँग जमाओं (Demand deposits) को लेकर समुदाय की सेवा करती है। व्यापारिक बैंक उधारकर्ताओं से ऋण, जिनमें द्रव्य के नकदी गुण का अभाव होता है, वय करके उसके बदले में उन उधारकर्ताओं को भाग जमा देती है जो लोगों द्वारा साधारणतया मुद्रा के समान स्वीकार की जाती है। बैंक इस प्रकार की विनियम क्रियाओं को करके ऋण का मुद्रोकरण करती है। बैंक केवल मुद्रा का व्यापार ही नहीं करती वरन् मुद्रा का निर्माण भी करती है। हम बैंकों द्वारा साख निर्माण के अन्तर्गत देख चुके हैं कि बैंक व्यापार तथा उद्योग के लिए वित्तीय महायता देकर साख-निर्माण किस प्रकार करती है। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में व्यापारिक बैंक केवल साख-निर्माण ही नहीं करते वरन् उस साख के उपयोग को सम्भव बनाकर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं।

### बैंकों द्वारा ब्याजदर को प्रभावित करना

व्यापारिक बैंक ब्याज की दर को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश तथा रोजगार के स्तर को प्रभावित करती है। बैंक मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन उत्पन्न करके मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर अपना प्रभाव डालकर उपभोग तथा उत्पादन की क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अर्थव्यवस्था में सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनाकर बैंक ब्याज की दर गिराती है अन्य बातें समान रहते हुए, परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है।

## अर्द्ध विकसित देशों में बैंकों का महत्व (Importance of Banks in Underdeveloped Countries)

बैंक की विकसित देशों में अलावा अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्प विकसित देशों में बैंक विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी बचतों को समाज में एकत्रित करने, पूँजी संचय तथा पूँजी निर्माण को सम्भव प्रदान करता है। अर्द्ध विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या छोटे छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वहाँ बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में सम्पूर्ण आय का उपयोग अनुत्पादक कार्यों तथा उपभोग पर व्यय हो जाता है। ऐसे देशों में रागों की बचतों को आकर्षित करने के लिए प्रामाण्य क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना इनकी दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बैंक का राष्ट्रीयकरण के प्रथम तथा द्वितीय चरण (वर्ष 1969 तथा 1980) के बाद गेस्ट बैंक और इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे कस्बों में अपना शाखाएँ खोला है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रवर्तित (Sponsored) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता तक अथवा घर-घर बैंकिंग प्रणाली की सुविधाएँ पहुँचाने का कार्य किया है जिससे रागों में बैंकिंग आदतें विकसित हुईं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बचतों का देश में विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीयकृत एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयत्नशील है। इस दिशा में हम अभी और आगे बढ़ना है। भारत की विशालता को दसपट हुए बैंकों को पहुँच से अब भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र छूट हुए हैं। जब तक सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली प्रामाण्य क्षेत्रों में शाखाएँ स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्प नहीं लगे तब तक सुलभ भविष्य का आशा करना व्यर्थ है।

अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी बाजार तथा मुद्रा बाजार को विकसित होने के कारण पूँजी का अभाव की स्थिति बनी रहती है और औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय सुविधाएँ नहीं जुटाई जा सकती। देश में पूँजी बाजार को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में स्थित व्यापारिक बैंक उद्योगों तथा अन्य फर्मों के धनो तथा ऋणपत्रों (Shares and Debentures) को खरीदें। ऐसा करना स्वयं बैंक के हित में भी होता है क्योंकि बैंकों का विकास उद्योगों का विकास पर निर्भर करता है। हमारे अलावा निर्यातक इण्डिया का बट्टा करने वाले देशों के निर्यात व्यापार को विकसित करने में भी व्यापारिक बैंक सहायक हो सकते हैं। अर्द्ध विकसित देशों के सामने सदा मुश्किलों का असन्तुलन का समस्या तथा विदेशी विनिमय का अभाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा स्थिति से निपटने के लिए इन देशों में निर्यातक उद्योगों तथा निर्यात सम्बद्ध योजनाओं (Export promotion Programmes) द्वारा पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित करने विदेशों में बहुत ही आवश्यक आयात किए जा सकते हैं।

### बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)

यद्यपि कार्यों का आधार पर बैंकों का वर्गीकरण करना कठिन है क्योंकि सभी देशों में बैंक का कार्य एक समान नहीं होता परन्तु ऐसा होत हुआ भी बैंकों का वर्गीकरण सामान्य तथा उनके कार्यों का आधार पर ही किया जाता है। सामान्यतया कार्यानुसार बैंकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है।

- (1) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)
- (2) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)
- (3) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)

- (4) कृषि बैंक (Agricultural Bank) (महत्वांगी एव भूमि विकास बैंक)
- (5) बचत बैंक (Saving Bank)
- (6) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank)

(1) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)—व्यापारिक बैंक व बैंक होती हैं जो महात्वांगतया व्यापार और उद्योग को अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान करती हैं। ये बैंक जनता से जमाओं के रूप में नकदी प्राप्त करती हैं। जमाकर्ताओं का यह जमा उनके माँगन पर स्वयं उनको अथवा उनके आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को वापस लौटाती है। वर्तमान समय में वाणिज्य बैंक जमाओं का स्वीकार करने तथा व्यापारिकों को ऋण देना के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करती हैं। उदाहरणार्थ भारत में लगभग सभी व्यापारिक बैंक ऋणियों का नया विक्रय करती हैं। इससे अतिरिक्त ये शाहवा के ड्रापट्टा द्वारा द्रव्य का एक स्थान दूसरे से स्थान पर भेजने का कार्य करता है। बड़ी बड़ी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों का ताकर आदि की सुविधा भी प्रदान करती हैं।

(2) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)—औद्योगिक बैंक प्रमुख रूप से उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण सहायता प्रदान करने तथा औद्योगिक विकास में विशेष रूप से योगदान देती हैं। इन बैंकों द्वारा बड़ी बड़ी औद्योगिक फर्मों का अनेक ऋण तथा बॉण्ड्स तथा अग्रा आदि की विधी करवाने में सहायता देते हैं और उनके ऋण पत्रों की हामी (Underwriting) भी करते हैं।

उद्योग का अचन (Fixed) तथा वायशीन (Working) पूँजी की आवश्यकता होती है क्योंकि दीर्घावधि तक इसका वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे विपरीत वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल को खरादने तथा धूमिका का वेतना का भुगतान करना के लिए अल्पावधि के लिए वायशीन पूँजी की आवश्यकता होती है। वायशीन तथा अचन पूँजी की मात्रा उद्योग की प्रकृति तथा इसके आकार द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग तथा अचन पूँजी के बीच अचन तथा कम वायशीन पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्योग विपरीत लोहा तथा इस्पात के समान बड़े आकार के उद्योगों को अधिक वायशीन तथा अचन पूँजी की आवश्यकता होती है। जमनी फाग अग्राका आदि औद्योगिक विनिर्माण दशा में इन बैंकों का काफी विभाग हुआ है।

अधिकांश औद्योगिक बैंक दीर्घावधि ऋण प्रदान करती हैं तथा इन कारण से जमाकर्ताओं से अधिक अथवा दीर्घावधि जमा प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देती हैं। भारत में इन प्रकार के बैंकों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है। यद्यपि कुछ समय पूर्व दश में औद्योगिक विकास बैंक की गति तीव्र करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1964 ई० में औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) की स्थापना की है। यह बैंक देश के औद्योगिक विकास के लिए सहायता दे रहा है।

(3) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)—विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य देश के विदेशी मुद्राओं का परिवर्तित करके आयात विनिमय द्वारा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—आयात तथा निर्यात को अन्तर्देशीय सहायता प्रदान प्रोत्साहित करना होता है। साधनों की उपस्थिति के अनुसार कभी-कभी ये बैंक अन्तर्देशीय व्यापार का भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

विदेशी विनिमय बैंक का मुख्य कार्य विदेशी मुद्राओं का परिवर्तित करके आयात विनिमय में सहायता प्रदान करना होता है। यह बैंक विभिन्न दशा की मुद्राएँ अपने पास

रखत है तथा अन्य देशों में अपने बैंक की शाखाएँ खोलकर विदेशी व्यापार का सुगम बनाने हेतु करते हैं। इन बैंकों की वाय पद्धति इस प्रकार होती है। जब कोई विनिमय बैंक विनिमय बिल गरीदती है तो उस विनिमय बिल की राशि उस उम्मीद की मुद्रा में दनी जाती है। तब वह बैंक उस बिल का विदेश में स्थित अपनी शाखा का भेजता है तथा उसकी वह शाखा आहार्यी (Drawee) में उस बिल में लिखित धनराशि का विदेशी मुद्रा में वसूल कर लेती है। ऐसा करने में विभिन्न देशों की मुद्राओं का स्थानान्तरण बिना ही अन्तर्गोष्ठीय भ्रमण होता रहता है। इसका अन्तर्गत यह बैंक अग्रिम विनिमय प्रतिभूतियाँ का आयात निर्यात आदि विदेशी व्यापारिक क्रियाओं को सम्पन्न करते हैं। यह बैंक विदेशी विनिमय दरों में हानि उठाकर चढ़ावा का रोककर उनमें हानि का जोषिम का काम करते हैं।

(4) कृषि बैंक (Agricultural Bank) कृषि बैंक व बैंक होती है जो कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृषकों को अल्पवर्षीय मध्यावधि तथा दीर्घवर्षीय ऋण सहायता प्रदान करती है। कृषि में सम्बन्धित कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण व्यापारिक बैंक कृषि का ऋण सहायता प्रदान नहीं कर पाते हैं। प्रथम कृषि उत्पादन करने नहीं है तथा यह प्राकृतिक प्रकाश पर अधीन है। अतः पालन में हानि की स्थिति में बैंक के लिए कृषक को ऋण चुकाना काफी कठिन है तथा बैंक को फसल का भय रहता है। भारत में कृषि बिल की समस्या का आज भी समाधान नहीं हो सका है। यद्यपि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1955 ई० में तथा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए की गई थी। अगस्त 1967 ई० में भारत सरकार ने कृषि वित्त का समन्वय का समाधान करने हेतु एक राष्ट्रीय मानक परिषद (National Credit Council) का स्थापना का है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा अव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मानक वितरण पर नियन्त्रण रखेगी। भारत में कृषि के दीर्घवर्षीय तथा अल्पवर्षीय ऋण भूमि विकास बैंक तथा कृषि मानक समितियाँ द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

(क) भूमि विकास बैंक (Land Development Bank) — भूमि विकास बैंक किसानों की आवश्यकताओं के ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह 5 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किसानों का ऋण देता है। इस ऋण का आधार किसानों का भूमि को बंधक के रूप में रखना है। इन ऋणों का भ्रमण आमामान विस्तार तथा एक निश्चित अर्थात् बंधक प्रारम्भ होता है। यह बैंक सहकारी के आधार पर संगठित होते हैं। दुभाग्यवश यह आभासीत सफलता नहीं मिल पाते हैं।

(ख) कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Banks) — यह बैंक किसानों की आवश्यकताओं के ऋणों का पूर्ति करते हैं। भारत में सहकारी बैंक का स्वरूप इस प्रकार है। ग्रामीण स्तर पर सहकारी साक्ष्य समिति (Village Coop Credit Society) जिसमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति मित्राकार इस समिति का गठन करते हैं। इस समिति की पूर्ण प्रवेश शुल्क अर्थात् की बिलों जनता तथा मददों द्वारा जमा किए गए निक्षेपों के अन्तर्गत कोषों के अन्तर्गत तथा राज्य सहकारी बैंक के ऋणों द्वारा प्राप्त होती है। इस समिति द्वारा कृषक सहकारी बैंक से ऋण लेते हैं जो कि जिनमें यह समितियाँ सम्बद्ध होती हैं और इन संधियों के ऋण प्राप्त करती हैं। इन सहकारी बैंकों के अन्तर्गत केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks) होते हैं जो आवश्यकता परन्तु पर सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। इनके अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) होते हैं जो जिले के केंद्रीय सहकारी बैंकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन राज्य सहकारी बैंकों के अन्तर्गत राज्य बैंक और इण्डिया के कृषि साक्ष्य विभाग होता है।



अधिक है वे बैंक रिजर्व ऑफ इण्डिया की दूबारी सूची में सम्मिलित बैंक कहलाती हैं। जिन व्यापारिक बैंकों की चुवता पूंजी व आरक्षण 5 लाख रुपये से कम है वे बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। व्यापारिक बैंक जमाकर्ताओं से जिनमें व्यक्ति, उद्योग, वाणिज्यिक संस्थान तथा अन्य सम्मिलित हैं चालू मियादों तथा बचत जमाएँ स्वीकार करती हैं। ये बैंक व्यापार तथा उद्योग को अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती हैं। कुछ भारतीय बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन भी करती हैं तथा इन बैंकों की विदेशों में शाखाएँ भी हैं। गत कुछ वर्षों में बड़े व्यापारिक बैंकों ने अभिगोपन के रूप में कार्य करके उद्योगों के साधारण अंशों का अभिगोपन भी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने गारन्टी योजना के अधीन लघु उद्योगों को भी ऋण सहायता प्रदान की है।

### व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति

अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की कुल जमा राशियाँ जुलाई 1988 में 1 26 009 करोड़ रुपये थीं। 23 मार्च 1990 को कुल जमा राशि 1 66 005 करोड़ पी जबकि 24 अगस्त 1990 को जो बढकर 1 75 000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई अर्थात् 5 महीनों में बैंक 5.3% प्रतिशत की वृद्धि ही रिकार्ड की गई। वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार विगत वर्षों में बैंकों में जमा की उच्च वृद्धि के सामने अभी तक बैंकों की जमा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। बैंकों में समपावर्धि जमा राशि में वृद्धि की दर भी काफी धीमी है। इस वर्ष यह 6 प्रतिशत की दर से 8 242 करोड़ तक पहुँची जबकि पिछले वर्ष पहले 6 महीने में दूसरी वृद्धि 7.8 प्रतिशत की दर से बढकर 9 146 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। वर्ष 1989-90 की जमा वृद्धि 19.1 प्रतिशत की तुलना में रिजर्व बैंक ने 1990-91 के लिए जमा वृद्धि दर का अनुमान 16.6 प्रतिशत रखा है। जमा वृद्धि दर में लम्बे समय से आ रही गिरावट का अभी बन् रहने की सम्भावना है।

### व्यापारिक बैंकों का कार्य (Functions of Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकों का कार्य निम्नलिखित है—

(1) जनता से जमा पर रुपये प्राप्त करना—बैंक को पूंजी दो प्रकार से प्राप्त होती है। प्रथम अज या हिस्सों को मुद्रा बाजार में बँचकर दूसरे व्यापारिक बैंक जाता जमा स्वीकार करते हैं तथा इन जमा राशियों पर व्याज देते हैं, ये बैंक चार प्रकार में जमा ग्रहण करते हैं—(i) चालू खाता (ii) संचय खाता, (iii) निष्चलनाधीन खाता (iv) बचत खाता।

(i) चालू खाता (Current Account)—यह एक महत्वपूर्ण खाता होता है इसके धारक बितनी ही बार बैंक में लेन-देन इस खाते का माध्यम से करते हैं। इन खातों पर बैंक सामान्यतः कोई व्याज नहीं देते बल्कि उल्टे ही बैंक ऐसे खातेदारों से आकस्मिक शुल्क वसूल कर लेता है। इस खाते की स्वयं का प्रयोग बैंक अपने हितों के लिए न करे बरकरा है क्योंकि इसकी स्वयं व भी भी माँगी जा सकती है। इस खातेदार को एक न्यूनतम धनराशि अपने खाते में रखनी होती है।

(ii) बचत खाता (Savings Bank Account)—यह खाते अधिकतर छोटी बचतों का सामान्य व्यक्ति के द्वारा रखे जाते हैं। इन खातों पर सम्बन्धित बैंक व्याज देता है। ऐसे खातों में कम जमा तो कई बार की जा सकती है परन्तु धन निवानने की सुविधा मन्ताह में दो या तीन बार ही दी जाती है। वर्तमान समय में ऐसे खातों की स्वयं पर 5% से 6% व्याज दिया जाता है।

(iii) निश्चित अवधि व बचत (Fixed Deposit Account) इन खातों में एक निश्चित अवधि के लिए तोग अपनी रकम जमा करवाने हैं। यह समयावधि सामान्यतः 3 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। इस पर व्याज जमा करवाई जाने वाली अरधि के अनुसार दिया जाता है। इसमें धन जमा करने वाले व्यक्ति को बैंक एक रसीद दे देती है।

इस जमा खातदार अपनी रकम निश्चित समयावधि के बाद ही ले सकते हैं परन्तु यदि उन्हें इस अवधि से पहले ही धन की आवश्यकता हो जाय तो बैंक इन खातों पर दिए जाने वाले व्याज से अधिक व्याज देता है। यह खात उन्हीं व्यक्तियों द्वारा खोल जाते हैं जिनको व्याज के पर्याप्त आय की प्राप्ति करनी हो जाती है और जो एक निश्चित अवधि के लिए धन देने की स्थिति में हों। इसी रकम का बैंक विनियोजित करती रहती है।

(iv) घरेलू बचत खाता (Home Safe or Savings Account)— कुछ बैंक घरेलू बचत खात की सुविधाएँ अपने ग्राहकों को देते हैं। सामान्यतः बैंक अपा ग्राहकों के लिए छोटे की छोटी छोटी मुल्यों का गिजोरी देते हैं और उसका साखा लगाकर बचत करवाते अपने पास रख लेता है एक निश्चित समय के बाद बैंक का प्रतिनिधि ऐसे ग्राहक के घर जाता है और तारा खोलकर रकम उस ग्राहक के सामने पिनकर ले जाता है और उसको जमा रसीद देकर उस रकम को ग्राहक के खात में डाल देता है। बैंक इस पर साधारण व्याज देता है। अल्प बचत तथा बच्चे या गृहणियों की सुविधा तथा छोटी छोटी बचतों को आवृत्त करने के लिए ऐसे खाते खोले जाते हैं।

(ii) ऋण प्रदान करना - ये बैंक अतिरिक्त धन को उत्पादक तथा व्ययसाधियों को विभिन्न प्रकार की जमानता पर ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा करने में बैंक को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ये बैंक व्यक्तिगत जमानता पर ऋण नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा करने में बैंक को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भारत में ऐसी संस्थाओं का अभाव है जो बैंक को उनमें ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सही सही सूचना दे सकें। व्यापारिक बैंक अपना अतिरिक्त धन व्यापारियों को ही अल्पकालीन ऋणों में रूप में देते हैं क्योंकि इनमें एक ओर तरलता रहती है तो दूसरी ओर उन्हें ऐसे ऋणों पर अपेक्षाकृत उच्च व्याज दर प्राप्त होती है।

ऋणों के प्रकार—व्यापारिक बैंक द्वारा निम्न प्रकार से ऋण दिए जाते हैं—

(i) नकद साक्ष (Cash Credit) - व्यापारी वर्ग को नियमित रूप से धन की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारी को कितने धन की आवश्यकता होती है इसका अनुमान पहले से लगा जाता है और उतनी ही रकम उत्तर लेने का समझौता बैंक से कर लिया है। यह रकम व्यापारी नकद न खेरेर समय-समय पर बैंक से लेता रहता है। उसे निगली गई रकम पर ही व्याज देना पड़ता है। यह रकम पर्याप्त जमानत पर दी जाती है। व्यापारी वर्ग सामान्यतः भण्डार या सरकारी प्रतभूतियों को धरोहर के रूप में बैंक के पास रखते हैं इस पर साभास तथा व्याज ग्राहक को मिलता है।

(ii) अधिविर्ष (Overdrafts) - यह सुविधा सामान्यतः चलू खातेंदार लेते हैं। यह खातदार बैंक में जमा राशि से अधिक रकम खर्च करने का समझौता कर लेते हैं। यह रकम अधिविर्ष कहलाती है। ग्राहक के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने जिनकी रकम अधिविर्ष के रूप में खर्च करने का समझौता किया है उतनी रकम एक बार में निकाल ले। आवश्यकतानुसार वह अधिविर्ष को रकम लेता रहता है और ग्राहक को वास्तविक निकासी जान वालों राशि पर व्याज देना होता है। अधिविर्ष की रकम पर्याप्त जमानत तथा ग्राहक को साक्ष पर दा जाता है।

(iii) अग्रिम (Advances)—बैंक की अधिकांश रकम ऋण अथवा अग्रिमा के रूप में जाती है। ऋण एक निश्चित रकम के निर्धारित व्याज की दर पर दिए जाते हैं। जब बैंक किसी व्यक्ति का अग्रिम देता है तो यह रकम खातेदार के हिसाब में लिखा दी जाती है। रकम बैंक के खाने में लिख जान के बाद उसी दिन से व्याज ग्राहक पर लगता है। चाहे ग्राहक यह रकम एक मास ले ले अथवा बिस्ता में बैंक से निमाने। इतने विपरीत नकद साथ तथा आधिविकल्प में जितनी रकम ग्राहक लेता है उसी पर व्याज लगता है।

ऋण जमानत पर तथा निश्चित रकम अर्थात् के लिए दिए जाते हैं। यह ऋण पूर्णतः सुरक्षित ही होते हैं।

(iv) व्यापारिक बिलों की कटौती (Discounting of Trade Bills)—बैंक अपना चालू पूंजा का एक भाग व्यापारिक बिलों में लगाता है। बैंक मार्गदर्शिका (Usance bills) की कटौती तुरन्त करता है। बिलों की कटौती करते समय बैंक एक ठग वाद का ध्यान रखता है कि मध्यस्थित बिल व्यापारिक बिल ही हों। विक्रित दशा में बिलों की कटौती करने के लिए कटौती गृह (Discount House) स्थापित किये गये हैं।

व्यापारिक बिलों में धनराशि लगाने पर व्यापारिक बैंक का अल्पकाल के लिए पैसा लगाना पड़ता है दूसरे व्यापारिक बैंक का आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दण्ड के नन्द्रीय बैंक से मुनाया जा सकता है। व्यापारिक बिलों के लन-दन द्वारा ऋणदाता एवं ऋणी दोनों को लाभ रहता है।

(III) एजेंसी अथवा प्रतिनिधि कार्य (Agency or Representative Functions) व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कुछ सवाएँ उमक द्वारा माँगी जान पर उपलब्ध करता है। कुछ सवाएँ सशुल्क तथा कुछ निशुल्क प्रदान की जाती हैं। यह मुनिघाएँ निम्नलिखित हा सकती हैं—

(i) ग्राहकों के चेक, बिलों आदि के भुगतानों को सग्रहीत करना—बैंक ग्राहक के चेक विनिमय बिल टूण्डों आदि का भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में डाल देता है। चालू खातेदारों को यह सुविधा प्रायः निशुल्क दी जाती है अन्य स्थानों के लिए बैंक शुल्क लेता है।

(ii) ग्राहकों के चेक, बिल आदि का भुगतान देना—बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करत है। कर्मो-वर्षों तो ग्राहकों के आदेश पर स्थानार किए गये बिलों का भुगतान कर देने में और इस कार्य के लिए ग्राहकों से शुल्क ले लेत हैं।

(iii) नियमित भुगतान करना और सग्रह करना—ग्राहकों के स्थाई आदेश (Standing Order) पर बैंक ग्राहकों के मकान के विराय, बीमा पॉलिसी की प्रिम तथा अन्य दायित्वा का निगटारा अर्थात् भुगतान प्राप्त करने तथा उन्हें सग्रहीत करने का कार्य करत रहते हैं। बैंक ग्राहकों के इन कार्यों का करने के लिए कुछ शुल्क लेत है।

(iv) विप्रेषण सुविधाएँ (Remittance Facilities)—बैंक अपने ग्राहकों के लिए रकम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का व्यवस्था करता है।

(v) असा तथा प्रतिभूतियों का इय विद्रम—बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार की कम्पनियाँ के असा, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि सरीदत और बचत रहते हैं।

(vi) सन्दर्भ पत्र—बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना विदशा तथा दण्ड के विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों की आवश्यकतानुसार देत है यह सवा प्रायः निशुल्क होती है।

(vii) ट्रस्टी तथा प्रबंधक के रूप में—बक अपने ग्राहकों की सम्पत्ति की व्यवस्था विभाजन तथा प्रबंध का कार्य भी करता है।

(viii) वित्तीय सलाहकार—बक अपने ग्राहकों के लिए पूजा विनियोजन के साथ-साथ धन की जानकारी देकर ग्राहकों को सुदृढ़ धन प्रबंधन की सलाह भी देता है।

(IV) विविध कार्य (Miscellaneous Functions)—उपरोक्त कार्यों के अलावा बैंक कुछ कार्य और करता है जिन्हें सहायक कार्य कहा जाता है जैसे—

(i) सम्पत्ति तथा बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना—बक अपने ग्राहकों का बहुमूल्य वस्तु सम्पत्ति जैसे—सोना चाँदी हथियार-जवाहरात तथा कीमती पत्रों को रखने के लिए नाकस सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इन नाकस का एक चाबो बक के पास तथा दूसरी ग्राहक के पास रहता है। जब तक दोनों चाबियाँ नहीं मिलीं तब तक नाकस नहीं खुलेगा। नाकस सुविधा के लिए बक वार्षिक बिराया लेता है।

(ii) विदेशी विनियम तथा साख पत्रों अथवा भागों की सुविधा—व्यापारिक बक ऐसे ग्राहकों के लिए यह सुविधाएँ देता है जो विदेशी यात्रा पर जाते हैं या विदेशों से धन लेना चाहते हैं। विदेशों पर जाने वाले यात्रों को सुविधा से बच जाता है।

(iii) उपभोक्ता साख देना—बक अपने ग्राहकों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं जैसे—स्टर मोटर साईकिल कार फ्रिज एयर कंडीशनर कूलर आदि की खरीदने की सुविधा देता है। ऐसी सुविधाएँ औद्योगिक विभागों के लिए प्रायः दी जाती हैं।

(iv) अक संप्रह एव शिक्षण—प्रायः सभी बड़े बक बचत वित्त तथा व्यापार आदि सम्बन्धी आँकड़ों संप्रह कर उन्हें समय-समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। इनके प्रकाशन से जनता एवं बक के ग्राहकों के लिए जानकारी मिलता रहती है।

(v) साख का निर्माण—व्यापारिक बक के प्रमुख कार्यों में साख निर्माण का कार्य आता है। बक अपना जमा राशि स कई गुना साख मुद्रा की मात्रा निर्माण करके प्रदान करता है।

### बैंकों द्वारा साख मुद्रा का निर्माण (Credit Creation by Banks)

बैंकों को साख मुद्रा निर्माण का कार्य के कारण वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रो० सेयस न कहा है कि बक केवल मुद्रा का आदान-प्रदान करने वाले नहीं होते परंतु महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा के निर्माता होते हैं (Banks are not merely surveyors of money but also in an important sense manufacturers of money) तथा वे साख निर्माण के कार्य द्वारा बक की कुल जमा पूंजी कई गुना बढ़ाता है। एक बक का साख निर्माण शक्ति सामित होती है। बक का अपना आरम्भिक जमा पूंजी का एक भाग नकद के रूप में रखना पड़ता है जिससे कि वह अन्य बचत कार्यों का सुगमतापूर्वक निपटा सकता है।

वर्तमान समय में साख मुद्रा का एक दश का अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस साख मुद्रा का निर्माण बक द्वारा किया जाता है। बक अपने पास जमा का जमा धनराशि के आधार पर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। साख मुद्रा निर्माण के समय दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती हैं। प्रथम तो यह है कि मर्याद अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तिगत बक (Individual banks) होता है कोई एक बक अपना कुल नकद जमा का केवल कुछ प्रतिशत भाग ऋण के रूप में उधार पर दे सकता है परंतु एक अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण बचत प्रणाली कुल नकद जमा (Total cash)

deposits) का बर्ध गुना राशि उधार देकर मांग मुद्रा का निर्माण कर सकती है। दूसरी जो सांग मुद्रा निर्माण के विषय में है वह यह कि हम प्राथमिक जमाआ (Primary deposits) तथा गौण जमाआ (Secondary or derivative deposits) के बीच अन्तर पाते हैं। प्राथमिक जमाआ का निर्माण अथवा प्रत्यक्ष जमा तथा गौण जमाआ का संश्लेष अथवा अप्रत्यक्ष जमा (Indirect deposits) भी कहते हैं। प्राथमिक जमाआ का निर्माण जमाआ का वास्तविक जमा के आधार पर होता है और वह द्वारा इनका निर्माण नहीं होता जबकि गौण अथवा संश्लेष जमाआ का निर्माण बैंक करत है और इनका आधार प्राथमिक जमा आ होता है। गौण जमा आ का द्वारा व्यापारिक तथा कृषि या अग्रिम तथा ऋण प्रदान करने के फलस्वरूप होता है। गौण जमाआ प्राथमिक जमाआ का परिणाम होती है और गौण जमाआ के निर्माण के कारण अव्यवस्था में मुद्रा का गुणवृद्धि होता है।

यह एक व्यापारिक संस्था के समान होता है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह लाभ बैंक जमाआ का प्राप्त करने के लिए ऋण के रूप में उठाकर व्याज तथा अन्य वैशेषिक जमाआ को प्रदान करता उठाता है। बैंक प्राथमिक जमाआ के आधार पर सांग मुद्रा का निर्माण करता है। ऋण प्रदान करने के लिए और इन ऋणों पर मिलने वाले लाभ में से जमाआ का निर्माण करता है। जमा पूँजी पर व्याज देकर शेष धन व्याज के रूप में प्राप्त करके लाभ करता है। इस प्रकार बैंक निष्क्रिय जमाआ का संश्लेष जमाआ में बदल देता है जिसका उपयोग निवास तथा अन्य संस्थाओं के विस्तार हेतु किया जाता है। एक कुशल बैंक वही होता है जो आवश्यकता तथा नियमानुसार नकदी से ज्यादा नकदी पाने में सक्षम उस उपयुक्त समय पर ऋण तथा अग्रिमों का मांग करने वाला का देकर अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सके।

### सांग निर्माण प्रक्रिया (Process of Credit Creation)

सांग निर्माण प्रक्रिया का आरम्भ बैंक के पास उनके जमा रत्ताओं की धनराशि का प्राथमिक जमाआ के रूप में अपना नकदी को जमा करने के साथ होता है। बैंक अपने सामान्य अनुभव के आधार पर यह जानते हैं कि जो भी जमाकर्ता बैंक के पास अपनी धनराशि जमा करते हैं वह एक साथ एक मुश्त अपना धनराशि का वापस लेना चाहते हैं। बैंक विभिन्न प्रकार की जमा पूँजी प्राप्त करते हैं जैसे सामान्य बचत खाते में, सावधि जमा खाते में आदि। बचत खाते (Savings Bank Account) में जो धनराशि जमा की जाती है उसका वह से नियमानुसार जमाकर्ता निकाल सकता है। सावधि जमा खाते अथवा निश्चित अवधि (Fixed Deposit Account) खाते में जो धनराशि जमा की जाती है उसका बैंक पर निश्चित अवधि तक आगामी से उधार दे सकता है जबकि बचत खाते में प्राप्त जमा पूँजी के एक निश्चित भाग का नकद अपने पास रखकर बैंक शेष धनराशि का उधार दे देता है। इस प्रकार बैंक जमा नकद जमाआ का ऋण चाहने वाला का जमाआ का अर्जन के अनुसार उधार देकर एक ऋण पर व्याज प्राप्त करता है। सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का दृष्टि से सांग मुद्रा निर्माण का प्रवृत्ति बहुगुणक होता है। इस जमा गुण के अर्थ में एक से अधिक परन्तु अनन्त में बढ़ता है। परन्तु एक बैंक का दृष्टि से सांग एक एक प्राथमिक जमा या अथवा कुछ प्रतिशत भाग ही उधार देकर सांग मुद्रा का निर्माण करता है। एक बैंक की अग्रिम सांग मुद्रा निर्माण प्रक्रिया जमा रत्ताओं द्वारा प्राथमिक जमा राशि के ऊपर निर्भर करती है।

सांग मुद्रा निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में देश का मुद्रा अधिकारी अथवा राष्ट्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली अथवा बैंक जमा रत्ता तथा प्रत्याह्वारकर्ता शामिल होते हैं, तथा उधारकर्ता पक्ष के चार पक्ष होते हैं। सांग-मुद्रा निर्माण के सम्बन्ध में उधारकर्ता पक्ष

का यह महत्त्व होता है कि इस धन द्वारा साख-मुद्रा की उस वास्तविक माँग राशि का निर्धारण होता है जिसका सम्पूर्ण बैंकिंग जमाआ निर्माण करती है अन्य तीनों पक्ष बैंकिंग प्रणाली का इष्टतम साख-मुद्रा प्रति धमता अथवा साख मुद्रा की उस इष्टतम राशि का, जिसका निर्माण बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जा सकता है निर्धारित करते हैं।

प्र० रिपोर्टों कहते हैं कि बैंक का साख मुद्रा निर्माण धन का पारस्परिक उग गम्य होता है जब बैंक द्वारा जमावर्त्ताओं के धन का उपयोग करती है। जब तक बैंक अपनी पूँजी को उधार देती है तब तक वह बचत पूँजापति उग का धन भाँटती है। संशोधन हम पर गत है कि बैंक अपने जमावर्त्ताओं की धनराशि का उपयोग करते हैं इस कारण बैंक द्वारा साख मुद्रा निर्माण का सम्बन्ध इसका अपना जमावर्त्ताओं की धनराशि का निवर्त्ताओं का उधार देना ही है। देश के केन्द्रीय बैंक का साख मुद्रा का विस्तार एवं संकुचन में बड़ा महत्त्व होता है। साख मुद्रा का विस्तार एक संकुचन बैंक जमाआ का विस्तार एक संकुचन में सम्बन्ध होता है। केन्द्रीय बैंक के पास साख नियन्त्रण का अधिकार अस्त होने से जिनका उपयोग वह आवश्यकतानुसार करता रहता है।

बैंक जमा का प्रकार से सृजित की जाती है। बैंक जमा का एक रूप उग गम्य हमारे सम्मुख आता है जबकि ग्राहक को नकदी या चा उसका पास जमा होती है। ऐसी जमा प्राथमिक जमा कहलाती है। यह प्राथमिक जमाएँ बैंक की परिसम्पत्ति (Assets) तथा दायता (Liabilities) दोनों में ही वृद्धि करती है। प्राथमिक जमा ही बैंक की जमा माना जा सकता है। प्राथमिक जमाआ से चलन मुद्रा जमा मुद्रा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और समुदाय के लिए उपलब्ध मुद्रा की प्रति अपरिवर्तित रहती है।

बैंक दूसरे प्रकार की जमाओं को प्राप्त करती है जिन्हें गौण जमा (Derivative deposits) या (Secondary deposits) कहते हैं यह जमा ऋणा का देन अथवा प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बैंक की परिसम्पत्ति में वृद्धि हानि से होती है। व्युत्पन्न जमा अथवा गौण जमा (Derivative or Secondary Deposits) की मात्रा बैंक द्वारा ऋण प्रदान नीति तथा बैंक की विनियोग नीति पर निर्भर करती है। जब बैंक एक ग्राहक को ऋण प्रदान करता है अथवा एक विवेता से प्रतिभूति खरीदता है तो सामान्यतया वह इसका व्युत्पन्न नकद न करके ऋणी अथवा प्रतिभूति के विवेता का अपना मही सात रतन देता है और इतनी धनराशि उस सात में शल देता है जितना ऋण दिया है अथवा प्रतिभूति उसने खरीदा है। ऋणी अथवा प्रतिभूति विवेता का यह धनराशि बैंक पर चेक लिखावर अदा करन या उस देन का प्रावधान होता है। बैंक के इस प्रकार के चलन (Custom) के आधार पर यह बहान्त प्रचलित है कि प्रत्येक ऋण एक जमा का निर्माण करता है। (Every loan creates a deposit)।

व्युत्पन्न जमा बैंक द्वारा निर्मित होने से समुदाय की माँग जमाआ पर अधिकार में वृद्धि बिना साक्षात् पास मुद्रा में कमी किए होती है। इस प्रकार व्युत्पन्न जमाएँ समाज में मुद्रा के कुल स्तर में वृद्धि करती हैं। सामान्य रूप से बैंक गौण अथवा व्युत्पन्न जमाआ को प्राथमिक जमा के आधार पर निर्गत करते हैं। प्रत्येक बैंक यह अनुभव करता है कि कुछ प्राथमिक जमाएँ उसमें पास जमा होती हैं और कुछ उग पास में निबलती रहती हैं। सामान्य अनुभव के आधार पर एक नया यह भी माना जाता है कि जितना जमा कर्ता अपनी पूँजी बैंक के पास जमा करता है वह सारी का सारी पूँजी एवं साथ में नकदी अथवा कुछ प्राथमिक जमाओं के एक भाग को ही बैंक में एक समय निशाना जाता है। बैंक नकदी रतन का कार्य करता है जिससे कि वह माँग पर जमा धनराशि का भूषण कर सके इस प्रकार नकदी रतन का Customary cash reserve ratio जो कि

10 प्रतिशत या फिर कुछ और ही सक्ता है। Customary cash reserve ratio भी बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है। बैंक इस नकदी को आंशिक रूप से तरल मुद्रा तथा आंशिक रूप से कन्द्रीय बैंक के पास रखी जाने वाली नकदी का करता है।

ऋण प्रदान करने जो व्युत्पन्न जमा बैंक द्वारा होती है उनका भुगतान को ऋण लेने वाला बैंक पर बैंक नियंत्रण निकाल सकता है परन्तु जिनको यह धनराशि प्राप्त होती है वह दूसरे बैंक में नकदी या बैंक जमा करा सकता है। दूसरे बैंक के पास इस प्रकार नकदी या बैंक जमा होने से उसका व्युत्पन्न जमा बढ़ जाती है और उसका आधार पर वह अधिक मात्रा मुद्रा का निर्माण कर सकता है। यह बैंक किसी अन्य बैंक में पाम चला जाता है और फिर यह उसकी प्राथमिक जमा का रूप धारण कर लेता है और यह प्रक्रिया उग समय तक चलता रहती है जब तक कि मास की कुछ मात्रा अथवा व्युत्पन्न जमाएँ सभा बैंक द्वारा पहली वाली बैंक का प्राथमिक धनराशि से बढ़ गुना बढ़ जाती है।

हम व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली में साक्ष्य निर्माण प्रक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं इस उदाहरण द्वारा हमने यह भी माना है कि बैंक अपना जमा का 10 प्रतिशत नकदी का रूप में रखता है। माना कि एक व्यक्ति बैंक A के पास 10,000 रुपये जमा करता है तो बैंक A का तुलन पत्र (Balance sheet) निम्न प्रकार होगी

#### बैंक 'A' तुलन पत्र-1 (Balance Sheet)

| दयताएँ (Liabilities)  |           | परिसम्पत्तियाँ (Assets) |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| मांग जमाएँ (प्राथमिक) | 10,000 ₹० | नकद जमा                 | 10,000 ₹० |
|                       |           | आवश्यक काप              | 1,000 ₹०  |
|                       |           | अतिरिक्त कोष            | 9,000 ₹०  |

बैंक A के पास 9,000 ₹० का अतिरिक्त राशि है। बैंक 1,000 ₹० नकद काप का रखता है तथा 9,000 ₹० का बराबर का व्युत्पन्न जमा (Derivative deposits) का निर्माण कर सकता है। बैंक का तुलन-पत्र परिवर्तित होकर निम्न प्रकार से होगा—

#### बैंक 'A' तुलन-पत्र 2

| दयताएँ (Liabilities)    |           | परिसम्पत्तियाँ (Assets) |           |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| मांग जमाएँ (प्राथमिक)   | 10,000 ₹० | नकद कोष                 | 10,000 ₹० |
| मांग जमाएँ (व्युत्पन्न) | 9,000 ₹०  | ऋण                      | 9,000 ₹०  |

माना कि बैंक 'A' से उधार लेने वाला X व्यक्ति 9000 रु० का चेक मिस्टर Y के लिए देता है और Y इस चेक को बैंक B में जमा कर देता है तो बैंक B का तुलन-पत्र इस प्रकार होगा -

बैंक 'B' तुलन पत्र-1

| देयताएँ (Liabilities)                       |           | परिसम्पत्तियाँ (Assets)                          |           |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| माँग जमाएँ (प्राथमिक)<br>(Deposits Primary) | 9 000 रु० | नकद काष<br>(Cash Reserve)                        | 9 000 रु० |
|                                             |           | नकदी जिस रखना<br>ज़रूरी है<br>(Required Reserve) | 900 रु०   |
|                                             |           | अतिरिक्त कोष<br>(Excess Reserve)                 | 8 100 रु० |

उपरोक्त तुलन-पत्र दर्शाता है कि बैंक B के पास अतिरिक्त काष 8100 रु० के हैं और B इन 8100 रु० की व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण कर सकता है। जब बैंक B अपने गृहणा का विस्तार करता है तथा अपनी अतिरिक्त कोष का बराबर जमा कर लेता है तो इसका तुलन पत्र निम्न प्रकार में होगा -

बैंक 'B' तुलन पत्र 2

| देयताएँ (Liabilities)   |           | परिसम्पत्तियाँ (Assets) |           |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| माँग जमाएँ (प्राथमिक)   | 9 000 रु० | नकद कोष                 | 9 000 रु० |
| माँग जमाएँ (व्युत्पन्न) | 8 100 रु० | गृहण                    | 8,100 रु० |

बैंक B 8,100 रु० का गृहण जब किसी व्यक्ति का देता है और यह व्यक्ति मिस्टर C इस 8,100 रु० गृहण राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करता है जो बैंक C में अपने खाते में जमा करा देता है तो बैंक C का तुलन पत्र निम्न प्रकार में होगा -

बैंक C तुलन-पत्र

| देयताएँ (Liabilities) |       | परिसम्पत्तियाँ (Assets)    |           |
|-----------------------|-------|----------------------------|-----------|
| माँग जमाएँ (प्राथमिक) | 8 100 | नकद काष                    | 8 100 रु० |
|                       |       | नकदी जिस रखना<br>ज़रूरी है | 810 रु०   |
|                       |       | अतिरिक्त काष               | 7 290 रु० |

उपरोक्त तुलन-पत्र दर्शाता है कि बैंक C के पास अतिरिक्त कोष 7,290 रु० के बराबर हैं अर्थात् बैंक C 7,290 रु० के बराबर व्युत्पन्न जमा का सृजन कर सकता है।



इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक बार बैंक की स्यताओं में वृद्धि होती है परन्तु यह वृद्धि घटता हुआ हो सकती है। मान्य सृजन का प्रक्रिया उस समय तक चालू करता रहता जब तक कि प्रथम बैंक का मौजूद अतिरिक्त बाण्य 1000 रुपय का विभिन्न बैंकों का महा हो जाता और यह बैंक का अतिरिक्त बाण्य (excess reserve) नहीं हो जाते। मान्य सृजन का इस प्रक्रिया में परिणामस्वरूप कुल महा स्यताओं का योग प्राथमिक जमा का 10 गुना होना तक यह प्रक्रिया चालू रहता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मान्य सृजन प्रक्रिया में अनुचित अव्यवस्था में प्रत्येक बैंक प्रणाली का प्रचलित होना पर एक बैंक में प्राथमिक जमा का 10 गुना होना और प्रत्येक मान्य मुद्रा का मात्रा अथवा व्यय न जमा हो जाता है। इस मान्य मुद्रा के अतिरिक्त उदाहरण के आधार पर इस प्रकार समझाया जा सकता है -

#### साख का गुणक विस्तार (Multiple Expansion of Credit)

| 1     | 2                                  | 3                                       | 4                              |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| बैंक  | दयताएं (प्राथमिक जमाएं), रुपया में | नकद बाण्य जो जरूरी होते हैं (रुपया में) | अग्रिम (धृत्यता जमा रुपया में) |
| A     | 10 000                             | 1 000                                   | 9 000                          |
| B     | 9 000                              | 900                                     | 8 100                          |
| C     | 8 100                              | 810                                     | 7 290                          |
| D     | 7 290                              | 729                                     | 6 561                          |
| E     | 6 561                              | 656.10                                  | 5 904.90                       |
| Total | 1 00 000                           | 10 000                                  | 90 000                         |

आजगीतीय रूप में स्तम्भ संख्या (2) = 10 000 रुपय + 10 000 रुपय (9/10) + 10 000 रुपय (9/10)<sup>2</sup> + 10 000 रुपय (9/10)<sup>3</sup> + ... + 10 000 (9/10)<sup>n</sup> यह गुणोत्तर प्रारंभ का योग (sum of Geometric progression) होता है  $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1}$  अथवा  $n \rightarrow \infty$  अथवा अनंत (infinity) अथवा  $a - 1/r$   $r$  हमने उपर्युक्त उदाहरण में  $r = 9/10$  अथवा 90 प्रतिशत तथा  $a = 10,000$ । इन सूत्रों का एक काम नये गणना पर हम यह पाते हैं -

$$10\,000 \left( \frac{1}{1 - 9/10} \right) = 10\,000 \frac{1}{1/10} \\ = 10\,000 \times 10 \\ = 1\,00,000 \text{ रुपय}$$

हम यह देखते हैं कि मान्य सृजन प्रक्रिया का अंत उस समय होता है जब विसा बैंक का बाण्य का अतिरिक्त बाण्य (excess reserve) अन्त में नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मान्य-सृजन अथवा व्युत्पत्ति, जमा प्रक्रिया उस समय तक चलती रहता है जब तक कि उसका अतिरिक्त बाण्य का अंतरण दूसरे बैंक का नकद बाण्य अनुपात (reserve ratio) के आधार पर होता रहता है।

इस जमा गुणक विस्तार प्रक्रिया में प्रमुख रूप में तीन पक्ष बाण्य करते हैं (i) बाण्य जो अंत में बैंक में जमा करते हैं (ii) बैंक जो कि अपना जमा का एक भाग

ही नकदी के रूप में रखता है (iii) उधार लेने वाले (सावजनिक अथवा निजी) व्यक्ति जिनसे बैंको को अपनी परिसम्पत्तियों को अर्जित करने में सहायता मिलती है।

**बैंक की साख निर्माण शक्ति की सीमाएँ (Limitations on Bank's Power of Credit Creation)**

वर्तमान समय में वैश्विक प्रणाली के अंतर्गत साख निर्माण व्यापारिक बैंको द्वारा किया जाता है परंतु बैंक की यह साख निर्माण शक्ति असीमित नहीं होती। प्रत्येक बैंक किसी दी हुई सीमा तक ही साख निर्माण कर सकती है। बैंको की साख निर्माण शक्ति कई बातों पर निर्भर करेगी यह बातें निम्न प्रकार से हैं—

(1) नकदी की मात्रा—बैंको की साख निर्माण की सीमा बैंको के पास उपलब्ध प्राथमिक जमाओं (Primary deposits) की मात्रा पर निर्भर करेगी। प्राथमिक जमाएँ ही बैंको को नकदी प्रदान करके बैंको को साख निर्माण का आधार होती हैं। प्राथमिक जमाओं की मात्रा जितनी अधिक होगी बैंको की साख निर्माण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि उतने ही अधिक अतिरिक्त योग साख निर्माण के लिए उपलब्ध होंगे। प्रो० कोस ने प्राथमिक जमाओं के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस दर तक कोई बैंक ऋण दर बिना कठिनाई के साख मुद्रा का निर्माण कर सकती है वह दर जमाकर्ताओं से नकदी के रूप में प्राप्त प्राथमिक जमाओं की दर पर निर्भर होती है। बैंक के पास नकदी की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है जैसे देश में कुछ ऋण मुद्रा की मात्रा कितनी है लोगों में वैश्विक आदान-प्रदान की दर तथा व्याज की दर कितनी है आदि-आदि।

(2) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति साख मुद्रा का निर्माण की सीमा देश के केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर भी निर्भर करती है। देश के अर्थ-सदस्य बैंको को केन्द्रीय बैंक की नीति तथा आदेशों को मानना पड़ता है। केन्द्रीय बैंक देश में साख नियंत्रण कई तरीकों से कर सकता है जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएँ, आनयन जमा दर, कोषानुपात, भाजित भाँग समझौते बुझाने की कार्यवाही तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि आदि। वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक विभिन्न देशों में साख नियंत्रण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की वैश्विक व्यवस्था केन्द्रीय बैंक नियंत्रण एवं मांग निर्देश पर काम करती है।

(3) नकद कोष अनुपात—जैसा कि हम जानते हैं कि साख निर्माण नकद कोषानुपात की मात्रा पर निर्भर करता है। नकद कोष जितने अधिक रहने का चलन होगा उतने अतिरिक्त कोषों की मात्रा कम रहेगी और इस मांग नियंत्रण भी कम होगा इस विपरीत स्थिति में साख निर्माण अधिक होगा। नकद कोष अनुपात कई बातों पर निर्भर करेगा जैसे देश में वैश्विक वातुन जैसे हैं लोगों की बचत में जमा तथा निष्कर्षों की भादतें जैसा है आवश्यकता के समय बैंको की आपसी देन-देन की व्यवस्था जैसी है आदि-आदि।

(4) अर्थ-सदस्य बैंको का व्यवहार—व्यक्तिगत बैंक की साख निर्माण शक्ति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अर्थ-सदस्य में अर्थ-बैंक किस सीमा तक साख निर्माण कर रही है। यदि कोई बैंक अर्थ-बैंक की परवाह नहीं करे अथवा बैंक की तुलना में अर्थ-साख निर्माण कर रही है तो शीघ्र ही उक्त बैंक की समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी और बैंक दिवालिया हो जाएगी क्योंकि बैंक के ऋणियों द्वारा अर्थ-सदस्यों को दिए गए ऋण अर्थ-बैंक को प्राप्त होंगे और इस कारण बैंक विशेष रूप से उन सभी बैंको का वैश्विक प्रणाली की अर्थ-सदस्य बैंको को नकदी देकर भुगतान करना पड़गा। इस विपरीत यदि

वैब विशेष अन्य साधी वैबा की तुलना में कम मात्रा में साल्व मुद्रा का निर्माण करती है तो शीघ्र ही उसे इस बात का अनुभव हो जाएगा कि उसकी पालतू नबदी में वृद्धि हो रहा है। जिस ऋणियों का ब्याज पर उधार देकर वैब को लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रा. हामब विचार उल्लेखनायक है वह कहते हैं कि यदि एक व्यक्तिगत वैब सामान्य सारा-विस्तार की दर से साथ अपने को नहीं रखा पाता तो यह वैब नबदी अधिक प्राप्त करेगी और इसका फल इस प्रकार अतिरिक्त बाणों का संचय होगा जिसका कि यह ऋण से रूप में देने को तैयार होगा। यदि एक व्यक्तिगत वैब अन्य वैबों की तुलना में अधिक ऋण विस्तार या विनियोग की नीति अपनाता है तो इसकी नबदी कम होगी और यह आवश्यक तोषा का रखा ही शत पू. नहीं कर सकता और इसका ऋण तथा निवर्णों को कम करना होगा।<sup>2</sup>

(5) वैबिंग आदतें तथा वैबिंग प्रणाली प्राणों की वैबिंग आदतों तथा वैबिंग प्रणाली से ही प्राणों का साधा सम्बन्ध साम्य मुद्रा की मात्रा से होता है और प्राणों की मात्रा का निर्धारण में यह तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि योग शीघ्र या निपटाया गया नबदी द्वारा करता कम देकर और प्राण मुद्रा अपना वैबों द्वारा सुगमता नहीं करता तो वैबों के निगुणक प्राण विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। योग में वैबिंग आदतें तभी कारगर होती हैं जहाँ देश में वैबिंग प्रणाली का विस्तार मरुत में स्थित रूप में हो।

(6) रखी जाने वाली जमानत की प्रति वैबों की ऋण प्रदान करने की शक्ति इन ऋणों के लिए रखी जमानतों के स्वरूप पर निर्भर करती है। वैबों जो भी ऋण देता है उगरे गीठ जमानत के रूप में सम्पत्ति जैसे बिला अक्षा तथा स्टॉक आदि (bills shares and stocks) को अपने पास रखता है। इसी आधार पर प्रा. फ्राउडर का कहना है कि वैब मुद्रा का सृजन नहीं करते यह तो अन्य प्रकार की सम्पत्ति को मुद्रा में परिवर्तित करते हैं।<sup>3</sup> जब वैबों प्राणों का सृजन करता है तो वास्तव में यह अंतरत जमानतों के धारकों का तरपता प्रदान करता है। वैबों की प्राण निर्माण शक्ति उधार देने वालों द्वारा ही जाना जाता है परन्तु प्रतिभूतियों तथा जमानतों के द्वारा एक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि जमानत के रूप में अनुमोदित प्रतिभूतियाँ नहीं रखी गई हैं तो वैबों द्वारा प्राण सृजित करने में जोरिम अधिक होगा।

साक्ष्य सृजन सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Theory of Credit Creation)

कुछ अर्थशास्त्रियों की समीक्षा धारणा है कि वैबों प्राणों या मुद्रा का सृजन नहीं करता। इन अर्थशास्त्रियों में प्रमुख रूप में डॉ० चार्ल्स लोकर तथा डॉ० एडविन वनो का नाम आता है। इन सिद्धान्तों का कहना है कि यह सोचना प्रवृत्तिपूर्ण है कि प्राण सृजन का प्रारम्भ वैबों द्वारा होता है जबकि वास्तविकता यह है कि प्राण सृजन का प्रारम्भ जमानतों द्वारा

1 If an individual bank fails to keep up with the general rate of credit expansion it will receive more cash than it loses and it will therefore, accumulate excess reserves which it will tend to loan out. If an individual bank expands loans or investments more rapidly than other banks it will lose cash, may not be able to fulfil the reserve requirements and will tend to reduce its loans or investments. —G N Hahn

2 'The bank does not create money out of thin air, it transmutes other forms of wealth into money. —G Crowther

द्वारा होता है जिनके धन को बैंक ऋण पर उठाते हैं। बैंक उस राशि में अधिक राशि उधार नहीं दे सकते जितनी कि जमाकर्ताओं ने जमा की हुई है। डॉ० घाल्टर लीफ एन व्यावहारिक बैंकर थे और वे कहते थे कि जब बैंक किसी जमा का निर्माण करता है तो वह जमा धन-राशि बैंक से कुछ समय बाद निकाल ली जाती है इस प्रकार बैंक जमा धन-राशि से अधिक उधार नहीं दे सकता। वास्तविकता यह है कि बैंक साख विस्तारण नहीं कर सकता।

डॉ० एडविन केनन (Dr Edwin Cannan) ने अपनी An Economist's Protest में बैंकिंग प्रणाली की तुलना रेलवे स्टेशन व सामान रखने वाले स्थान (Cloak Room) से की है। वे कहते हैं कि एक रात्रिकनव म 100 सदस्य नियमित रूप से आते हैं और एक छाता लाते हैं। जैसे कि वनव व काउंटर पर जमा कर देते हैं। काउंटर क्लर्क अपने अनुभव व आधार पर यह जानता है कि एक घन्टे में दस सदस्य ही छात की मांग करते हैं और 90 छातों को वह रात्रि भर के लिए विराए पर उठा देता है और इससे उसे कुछ मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया चाहिए कि काउंटर पर बैठ व्यक्ति ने 90 छातों का निर्माण कर दिया है? ऐसा कदापि नहीं हुआ है। इस प्रकार बैंक भी यह जानत हुए कि सभी जमाकर्ता एक साथ अपनी जमा धन-राशि को नहीं निकालते व इस जमा राशि का कुछ भाग उधार पर उठा देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंक ने साख का निर्माण कर दिया है। सामान धर का चपरासी उन छातों से अधिक छात उधार पर नहीं दे सकता जितने कि उसने पाम जमा कराये गये थे और एक वापरवाह बैंकर भी अपने पास की धन-राशि तथा दूसरे लोगों की धन-राशि से अधिक नहीं उधार दे सकता है।<sup>1</sup> इस प्रकार साख निर्माण सही तरीके से उस प्रणाली की व्याख्या नहीं है जिसके द्वारा बैंक मुद्रा की उत्पत्ति होती है।

प्रो० क्राउथर व प्रो० केनन के उपयुक्त तक के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दो प्रकार के उत्तर दिए हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बात एक बैंकर की दृष्टि से सही हो सकती है परन्तु यह उम समय सत्य नहीं होती जब कि हम इसे सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली व सदस्य में देखें। जब एक बैंक साख का निर्माण करती है तो यह साख दूसरे बैंक में जाता है तो यह बैंक ऋणों को देकर मुद्रा निर्माण का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित मुद्रा का एक भाग प्रथम बैंक के पाम वापस आ जाएगा जो कि इस प्रकार अपना कुछ नकदी को वापस प्राप्त कर लेगा। परन्तु यदि इसके अतिरिक्त कोष मौलिक रूप से बैंकिंग प्रणाली से कहीं बाहर से आये ह तो इसे दूसरे बैंक में नकद कोष का विस्तार करना चाहिए और जब तक बैंकिंग प्रणाली में नई जमा के गुणक रूप में कहीं इसका निर्माण नहीं होता तो इन बैंकों को नकद जमा अनुपात अत्यंत रूप से इनका सामान्य सख्या से अधिक होगा। घटती हुई जमा तथा नकदी वापसी का क्रम उस समय तक चलना चाहिए जब तक कि अतिरिक्त गुणक धन-राशि का निर्माण नहीं हो जाता।

प्रो० क्राउथर कहते हैं कि इसका व्यावहारिक पक्ष यह है कि बैंक जमा का आकार हम सभी मजल में आया जबकि इनकी तुलना हम चलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक वकों के नकद कोष से करें। उन्होंने उदाहरण के रूप में नवम्बर 1934 में ग्रेट ब्रिटेन के

1 The most abandoned cloak room attendant cannot lend out more umbrellas than have been entrusted to him and the most reckless banker cannot lend out more money than he has of his own plus what he has of other peoples

व्यापारिक बैंक की शुद्ध जमा पूंजी की चर्चा की जो उस समय 6500 मिलियन पाँड थी। जबकि वनन में मुद्रा राशि उस समय 16477 मिलियन पाँड तथा बैंकों के नकद बोधों की राशि 237 मिलि पाँड थी। इस प्रकार यदि बैंक न साख निर्माण नहीं किया तो फिर यह 4615 मिलि पाँड की अतिरिक्त धनराशि यदि साख निर्माण से प्राप्त नहीं हुई तो यह वहाँ से आर्ष। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक कई गुना अनुपात में साख निर्माण करते हैं।

### परीक्षा-प्रश्न

- 1 व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।  
(Discuss the main functions of the Commercial Banks)
- 2 बैंक आधुनिक व्यापार एवं उद्योग की आधारशिला है। व्याख्या कीजिए।  
(Bank is the foundation stone of modern Commerce and Industry Explain)  
[संकेत—बैंक का महत्व बैंक तथा आर्थिक विकास, बैंक व्यापार तथा उद्योग के लिए आवश्यक होता है तथा औद्योगिक विकास में बैंक की भूमिका देखिए। अतः से बताइए कि बिना क्या व्यापार एवं उद्योग बिना बैंक की सहायता से चल नहीं सकते। अतः में कहिए कि उपर्युक्त वर्णन मूल्य ही प्रतीत होता है।]
- 3 एक व्यापारिक बैंक द्वारा साख-निर्माण काय की व्याख्या कीजिए।  
(Discuss the credit creation function of a Commercial Bank)
- 4 साख निर्माण में क्या आशय है? व्यापारिक बैंक की साख निर्माण शक्ति की सीमाएँ क्या हैं?  
(What is Credit creation? What are the limitations on Bank's Power of Credit creation?)

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत बताइए—

- (i) आर्थिक विकास तथा बैंक एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर हैं।
- (ii) व्यापारिक बैंक साख-निर्माता होते हैं।
- (iii) बैंक की साख निर्माण शक्ति प्रसीमित होती है।
- (iv) व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
- (v) व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।

### वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) गलत है। (ii) गलत है। (iii) सत्य है। (iv) सत्य है। (v) गलत है।

A central bank is a bank that the government sets up to handle its transactions to co-ordinate and control the commercial banks and most important to help and control the nation's money and credit conditions

~ Danielson

अध्याय 18

## केन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य

(CENTRAL BANK AND ITS FUNCTIONS)

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

केन्द्रीय बैंकिंग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से पश्चिमी बणिज्य प्रणाली के विकास में काफी सहायता मिली है। विश्व का सबसे पुराना केन्द्रीय बैंक स्थापना का रिक्त बैंक था जिसकी स्थापना सन् 1656 में निजी पूंजी द्वारा की गई थी। टी। 12 वीं याद अर्थात् सन् 1668 में इसकी समस्त पूंजी केन्द्रीय नियंत्रण में चली गई। इसे प्रारम्भ में नोट नियंत्रण का अधिकार मिला। सन् 1897 में कानूनी रूप से इसे नोट निर्मित करने का अधिकार मिल गया था। समय की दृष्टि से हम स्वीडन के रिक्त बैंक को सबसे पहला केन्द्रीय बैंक मानते हैं परन्तु एक आदर्श केन्द्रीय बैंक के रूप में बंक ऑफ इंग्लैंड ने सबसे पहले तय किया जिसकी स्थापना सन् 1694 में हुई थी। इसे केन्द्रीय बैंक की माता (Mother of the Central Banks) कहा जाता है। ऐसा कहने का मुख्य कारण यह है कि बंक ऑफ इंग्लैंड विश्व के अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का मार्ग दर्शा रहा है और उन्हीं जो परम्पराओं की नींव डाली उनका दुनिया के अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के पालन किया। सन् 1826 में बंक ऑफ इंग्लैंड को देश के अन्य भागों में अपनी शाखाएँ खोलने का अधिकार प्राप्त हो गया। सन् 1833 में इसने द्वारा नियमित नोटों को कानूनी मुद्रा (Legal Tender Money) घोषित कर दिया गया था। बंक ऑफ इंग्लैंड का साथ साथ वहाँ समुक्त पूंजी बैंकों का भी नोट नियंत्रण का अधिकार मिला हुआ था यदि वे सदन के चारों ओर 6 मीटर दूर से बाहर बसे हों। नोट नियंत्रण का अधिकार एकाधिकार एवं सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उसका बढाते हुए वार्षिक से उरी वहाँ एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया। उन्हीं इन वार्षिक से प्रभावित होकर इंग्लैंड के अन्य समुक्त पूंजी या बैंकों ने बंक ऑफ इंग्लैंड में अपने समाने खोलने प्रारम्भ कर दिए। सन् 1847, 1857 तथा 1866 के संकटों का सामना इस बैंक ने सफलतापूर्वक किया जिससे प्रभावित होकर विश्व के अन्य भागों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की बन गिया।

सन् 1800 में बंक ऑफ फ्रांस 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड्स 1817 में बंक ऑफ आस्ट्रिया तथा बंक ऑफ नार्वे 1818 में नेशनल बैंक ऑफ डेन्मार्क 1850 में नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम 1856 में बंक ऑफ स्पेन 1860 में बैंक ऑफ एशिया में 1875 में रिश बैंक ऑफ जर्मनी 1882 में बंक ऑफ जापान आदि ने केन्द्रीय बैंक के रूप में काम प्रारम्भ कर दिया।

### केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition of a Central Bank)

केन्द्रीय बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। केन्द्रीय बैंक की प्रथि-  
काश परिभाषाएँ केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर आधारित हैं। समय-समय पर केन्द्रीय बैंक के  
कार्यों तथा उसके अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है इसी को ध्यान में रखकर विभिन्न  
विद्वानों ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषाएँ दी हैं। प्रो० किश तथा एल्किन ने केन्द्रीय बैंक की  
परिभाषा देते हुए कहा है कि 'केन्द्रीय बैंक वह बैंक होती है जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा  
मान की स्थिरता को बनाए रखना होता है।'<sup>1</sup>

प्रो० थोरस स्मिथ के अनुसार केन्द्रीय बैंकिंग का अभिप्राय उस बैंकिंग प्रणाली से  
है जिसके अन्तर्गत किसी एक बैंक का नोट जारी करने का पूर्ण एवं अवशिष्ट अधिकार  
प्राप्त होता है।<sup>2</sup> प्रो० आर० पी० कैंडल ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा कुछ इस प्रकार की  
है "केन्द्रीय बैंक वह संस्था होती है जिसका उद्देश्य जनता के सामान्य कल्याण के हित में  
मुद्रा की मात्रा का विस्तार एवं संकुचन करना होता है।"<sup>3</sup> प्रो० आर० जी० हार्ट्ज के अनु-  
सार, 'केन्द्रीय बैंक, बैंकों की बैंक होती है तथा इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि बैंक  
के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है।'<sup>4</sup> प्रो० शॉ के अनुसार केन्द्रीय बैंक यह  
बैंक होती है जो देश में माँग पर नियंत्रण रखती है।'<sup>5</sup>

नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सेम्युलसन के शब्दों में 'केन्द्रीय बैंक एक ऐसा  
बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लक्ष्य-क्षेत्रों में कार्य करने व्यापारिक बैंकों का नियन्त्रण  
करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं माँग व्यवस्था के नियन्त्रण में सहयोग देने के लिए  
स्थापित की जाती है।'<sup>6</sup>

प्रो० डी० कॉक (Prof M H De Kock) के मतानुसार केन्द्रीय बैंक उस बैंक  
को कहते हैं जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली का शिखर होती है तथा जो सम्पूर्ण  
देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। केन्द्रीय बैंक का जनता से  
प्रत्यक्ष रूप में संबंध इस प्रकार के सम्बन्ध रखने चाहिए जो इसकी मौद्रिक तथा बैंकिंग  
नीति की सफलता के लिए आवश्यक हो। इसकी जनता से जमाबांध के रूप में नकदी को  
स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा न ही जनता को प्रत्यक्ष रूप में ऋण इत्यादि प्रदान करने  
चाहिए। यह सब कार्य केन्द्रीय बैंक को देश की व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली के द्वारा  
सम्पन्न करना चाहिए।'<sup>6</sup>

1 "A central bank is that bank the essential duty of which is the  
maintenance of stability of the monetary standard"

—Kisch & Flinn

2 'The primary definition of central banking is a banking system in  
which a single bank has either a complete or residuary monopoly of  
note issue'

—Veera Smith

3 The central bank is an institution charged with the responsibility of  
managing the expansion and contraction of the volume of money in  
the interest of the general public welfare"

—R P Lutt

4 R G Howtrey

5 'A Central bank is a bank that the government sets up to handle its  
transactions to co-ordinate and control the commercial bank and  
most important to, help and control the nation's money and credit  
conditions"

—P. A Samuelson

6 M H De Kock :

केन्द्रीय बैंक की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन कर। से हमें केन्द्रीय बैंक के स्वभाव एवं स्वरूप के बारे में जानकारी हो जाती है। आधुनिक अधशास्त्री केन्द्रीय बैंक द्वारा सम्पादित कार्यों को आधार मानकर केन्द्रीय बैंक की परिभाषा करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 'केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का शिरोधार है। इसका देश के सभी व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण होता है यह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है नोटों व प्रचलन का एक भाग अतिरिक्त रूप से दण्ड को मौद्रिक आवश्यकताओं व अनुसार साल मुद्रा का नियंत्रण एवं नियंत्रण करती है।

### केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of a Central Bank)

प्रो० डी० फाक के अनुसार केन्द्रीय बैंक का कार्य निम्नलिखित हैं—

- (1) नोट निगमन का एकाधिकार
- (2) सरकारी बैंकर एजेंट तथा सलाहकार
- (3) सदस्य बैंकों की नकदी धनराशि का संरक्षण
- (4) राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षक
- (5) अर्थात् ऋणदाता
- (6) सदस्य बैंकों का समाशोधन गृह
- (7) व्यापारिक तथा मौद्रिक नीति की आवश्यकतानुसार साल मुद्रा का नियंत्रण

करना।

प्रो० डी० फाक ने केन्द्रीय बैंक के कार्यों को 10 श्रेणियों में प्रस्तुत की थी उसी के आधार पर यहाँ में केन्द्रीय बैंक के कार्य बताए जाते हैं। इन कार्यों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(i) नोट निगमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue)—केन्द्रीय बैंक की स्थापना से ही देश में नोटों का प्रचलन अथवा नोटों को नियमित करने का एक मात्र अधिकार (monopoly) उस देश के केन्द्रीय बैंक को मिला हुआ है। प्रो० डी० फाक (Prof De Kock) कहते हैं कि केन्द्रीय बैंक के नोट निगमन का अधिकार के कारण केन्द्रीय बैंकों को 20 वीं शताब्दी में नोट निगमन बैंक (Bank of Note Issue) कहा जाता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा निगमन का कोई काम तथा विशेषताएँ हैं

(i) एकरूपता—जब केन्द्रीय बैंक नोट छापता है तो उनमें एकरूपता का गुण पाया जाता है। जिससे धोरा धडी को सम्भाव्यताएँ कम हो जाती हैं।

(ii) जनता का विश्वास—कृति केन्द्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है और नोट निगमन वह किसी न किसी विदेशी विदेशी एवं देश की आवश्यकता पड़ने पर ही इन्हें छापता है इसलिए जनता का विश्वास नोट निगमन में निहित रहता है।

(iii) साल निर्माण पर नियंत्रण—कृति केन्द्रीय बैंक मुद्रा निगमन का एक भाग अधिकारी होता है तो साल मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण करने का काम स्वयं ही ही है। नोट मुद्रा में वृद्धि या कमी स्वयं सरकार द्वारा मुद्रा निर्माण पर नियंत्रण करता है और साल मुद्रा का आधार स्वयं का मुद्रा होता है।

(iv) मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता—केन्द्रीय बैंक मुद्रा का अन्तःकरण एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाए रखती है। यदि मुद्रा निगमन का काम व्यापारिक बैंक का होना तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखना सम्भव नहीं था।

(v) स्थिति सापेक्षता—केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निगमन का एकाधिकार से देश का मुद्रा प्रणाली स्थिति में सापेक्षता का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि



कन्द्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा में दण की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करता में मदद करता है।

(vi) सरकार को लाभ प्राप्त कराने की एकाधिकारी सम्पत्ति राष्ट्रीय बैंक होता है जो लाभ प्राप्त करता है उसका सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

2. सरकारी बैंकर एजेंट एवं सलाहकार (Government's Banker Agent and Advisor) कन्द्रीय बैंक का दूसरा मुख्य कार्य यह है कि यह सरकार के लिए बैंकर का कार्य करता है। अभिवृत्तियों तथा बैंकरों के रूप में राष्ट्रीय बैंक सरकारों तकदी रखने का संरक्षण करता है तथा विभिन्न सरकारों को सलाह देता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार का अधिकांशतः कार्य भी देती है। यह सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों में सरकार का सलाह देती है। कन्द्रीय बैंक सरकार को आर्थिक विपत्तियों मुद्राओं का प्रत्यक्ष विषय भी करता है तथा सरकार के द्वारा बैंक का माध्यम से हाँ जाता है तथा प्रणाली भी देती है। स्मरण रहे कि यह सभी कार्यों में राष्ट्रीय बैंक सरकार का विशेष प्रदान करता है।

3. बैंक का बैंक (Banker's Bank) — वर्तमान समय में कन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह बैंक का कार्य करता है। राष्ट्रीय बैंक का अन्य बैंकों का साथ में ही सम्बन्ध होता है जो अन्य बैंकों का अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। यह उनकी नकदों का संरक्षण करती है उनका प्रणाली प्रदान करती है तथा समय-समय पर आर्थिक व्यवस्था पर उनकी विनीय तथा आर्थिक मामलों में सलाह देता है तथा राष्ट्रीय बैंक अन्य बैंकों के बीच समाशोधन गृह (Clearing House) का कार्य भी करती है जिसमें नकद मुद्रा का उपयोग में वृत्त होता है। व्यापारिक तथा अन्य बैंकों को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत न्यूनतम बैंक आरक्षण अनुपात के रूप में राष्ट्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है जिसके कारण नकदों का कन्द्रीयकरण हो जाता है इससे यह लाभ होता है कि दण का कार्य मुद्रा प्रणाली आचरित हो जाती है तथा साथ मुद्रा नियंत्रण की समस्या भी हल हो जाती है। इससे अतिरिक्त नकद आरक्षण कन्द्रीय बैंक के पास हो जाना से किसी भी दण की सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली शक्तिशाली बन जाती है तथा नकद आरक्षण का संरक्षण में इष्टतम उपयोग किया जा सकता है।

4. राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षक (Custodian of the Nations Reserve of Foreign Currency) वर्तमान समय में कन्द्रीय बैंक राष्ट्र की सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के संचय का संरक्षण करती है। यह कन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि दण की मुद्रा इतनी ही बाल्य मूल्य की स्थिर रखना कन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए कन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं का आरक्षण संचित करती है। उदाहरणार्थ यदि किसी दण की मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है तो बैंक उस दण की मुद्रा का वृद्धि लगता है परन्तु उग दण की मुद्रा की कीमत गिर जाता है। इसी प्रकार यदि किसी दण की मुद्रा की कीमत गिर जाती है तो उस मुद्रा की कीमत प्रारम्भ कर देती है परन्तु उग कीमत बढ़ने लगती है। इस प्रकार कन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की कीमतों में स्थिरता बनाय रखता है।

5. सदस्य बैंकों का समाशोधन गृह (Clearing House of Member Banks) — वर्तमान समय में सम्बन्धित बैंकों को समाशोधन गृह अथवा निवासी गृह (Clearing house) की सुविधा प्रदान करना भी कन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य बन चुका है। यह कार्य बैंक बैंक द्वारा 1854 में सम्पन्न किया गया था। कुछ समय पश्चात् अन्य कन्द्रीय बैंक भी इस कार्य का काम ले लीं। शा (Shaw) विलिस (Willis) तथा जांसी (Jauncy) के विचारों में सदस्य बैंकों के मध्य समाशोधन गृह द्वारा सदस्य बैंकों के बीच परस्पर व्यवसाय सम्बन्धी मुद्दों को सम्भव बनाना कन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। इसमें कन्द्रीय बैंक के पास सम्बन्धित बैंकों के खाते होते हैं। कन्द्रीय बैंक के इस

कार्य के द्वारा प्रत्येक बैंक को अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग ढंग से व्यवहार करने को मजबूती के द्वारा नियंत्रित करने की समस्या समाप्त हो जाती है और इस प्रकार देश की समुचित बैंकिंग प्रणाली को काफी सुनिश्चित होती है।

6 अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort)—वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक अथवा बैंकों को सहायता प्रदान करने के अन्तिम ऋणदाता का कार्य भी करती है। जब किसी बैंक को सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तब केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में उस बैंक को ऋण देकर दिवालिया होने से बचाती है। इस प्रकार से अन्तिम ऋणदाता के रूप में केन्द्रीय बैंक संकटकाल में देश की सहायता करने की आवश्यकता के लिए व्यवस्था उत्पन्न करती है। बंजहार्ट (Bagehot) ने 1873 ई. में प्रकाशित अपनी Lombard Street शीघ्रक नामक पुस्तक में केन्द्रीय बैंक का इस कार्य के महत्त्व का वर्णन किया था तथा बैंक आफ इंग्लैंड का ध्यान संकटकाल में देश में अन्य बैंकों को ऋण देकर इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आकर्षित किया था। बंजहार्ट की पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात् बैंक आफ इंग्लैंड ने अन्तिम ऋणदाता का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्तमान समय में प्रत्येक केन्द्रीय बैंक इस कार्य को करती है भारत में 1960 ई० में पालाई सेन्ट्रल बैंक के दिवालिया हो जाने पर देश का अन्य व्यापारिक बैंकों से जब जमाकर्त्ताओं ने भारी मात्रा में अपनी जमाओं को वापस लेना आरम्भ कर दिया था तब व्यापारिक बैंकों को जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अन्तिम ऋणदाता के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

7 साल का नियन्त्रण (Controller of Credit)—केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था में साल मुद्रा पर नियन्त्रण करने अथवा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाये रखना है। इस कार्य का महत्त्व वर्तमान समय में इतना अधिक हो गया है कि साल मुद्रा नियन्त्रण के कार्य को ठीक प्रकार से सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय बैंक को देश की समुचित बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने के लिए शक्ति तथा अधिकार दिए जाते हैं। साल मुद्रा नियन्त्रण से कोमल स्तर में स्थिरता विदेशी विनियम दर में स्थायित्व बनाय रखा जा सकता है। व्यापार तथा को नियंत्रित करने देश की स्वयं निधि का बचाने तथा उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। अतएव साल नियन्त्रण अति आवश्यक है और यह केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य बन चुका है।

### साल नियन्त्रण (Credit Control)

साल नियन्त्रण की आवश्यकता (Need for Credit Control)

साल मुद्रा को हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा वर्तमान सम्पूर्ण वित्तीय ढांचा साल मुद्रा प्रणाली पर आधारित है इसलिए साल हमारी अर्थव्यवस्था का अतिरिक्त अंग बन गई है। इस कारण हम अपना वर्तमान व्यापारिक व्यवस्था का जीवन रक्षक नहीं तो अतिरिक्त नहीं हूँगे। साल एक ऐसा अतिरिक्त अथवा नाजुक अंग है कि इसका दुरुपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए साल मुद्रा को नियंत्रित एवं नियमित करने की आवश्यकता होती है। प्रो० डी० फोर्क साहब साल की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं कि 'बहुत वर्षों से सभी ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि साल का सृजन तथा वितरण बहुत से दशों में विद्यमान जटिल आर्थिक समझन की दृष्टि से किसी एक प्रकार से निर्मित होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह था कि साल सभी प्रकार के मौद्रिक तथा अर्थव्यवस्थात्मक निपटारों में एक मुख्य

भूमिका निभाती है और इस प्रकार यह अच्छाई या बुराई का एा शक्तियाली तत्व का रूप में प्रतिनिधित्व करता है।<sup>1</sup>

बैंकीय बैंक द्वारा नियंत्रण का प्रकार में करता है—

(I) मात्र नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ

(II) मात्र नियंत्रण का गुणात्मक विधियाँ।

मात्र नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ का अर्थ उन मापना में है जो बैंक द्वारा तथा का प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें विपरीत मात्र नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ का अर्थ उन मापना में है जिनके द्वारा बैंक का मात्र प्रकार का विना नकद बोधा का प्रभावित किए हुए नियंत्रण किया जाता है। मात्र नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ द्वारा देश का आवश्यकतानुसार सात वितरण आयाग एवं दिशा का निर्धारित किया जाता है।

जब हम मात्र नियंत्रण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अर्थात् परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियाँ का पृथक् पृथक् अध्ययन करेंगे—

### I परिमाणात्मक विधियाँ (Quantitative Methods)

- (1) बैंक दर अथवा कटौती दर (Bank Rate or Discount Rate)
- (2) खुले बाजार का क्रियाएँ (Open Market Operations)
- (3) न्यूनतम बैंड आरक्षित अनुपात (Minimum Legal Reserve Ratio)
- (4) तरलता अनुपात (Liquidity Ratio)

### II गुणात्मक विधियाँ (Qualitative Methods)

- (1) मात्र मुद्रा की रशनिग (Rationing of Credit)
- (2) प्रत्यक्ष बाणवाही (Direct Action)
- (3) नैतिक अनुसय या समझाना (Moral Suasion)
- (4) चयनात्मक सात नियंत्रण (Selective Credit Controls)
- (5) विज्ञापन तथा प्रचार (Publicity)।

#### I परिमाणात्मक विधियाँ

(1) बैंक दर अथवा कटौती दर (Bank Rate or Discount Rate)—संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र द्वारा 1939 में इसका प्रयोग किया यह मात्र बैंकीय बैंक के अन्तिम प्रणाली का साथ का कारण है। बैंक दर व्याज की वह दर है जिसे पर बैंकीय बैंक मदस्य बैंक को प्रथम श्रेणी तथा उत्तम ऋणपत्रों का बढा करके अथवा इनका महासक आह का रूप में बैंक दर ऋण प्रदान करता है। प्रो० पीटर फोर्सेर अनुसार कटौती दर नीचे वह है जिसका अंतगत्त का बैंक अपने द्वारा चयन को कुछ अन्यत्रा नान सम्पर्क को पुनः कटौती का गठने का प्रतिबन्धित कर सकता है। अर्थात् सुरक्षित मात्र इतर है।

1. For many years it has been almost universally accepted that the creation and distribution of credit under the intricate economic organisation existing in most of the countries should be subjected to some form of control. The main reason was that credit comes to play a predominant part in the settlement of monetary and business transactions of all kinds and thus represent a powerful force for good or evil'

( 'Discount Policy may conveniently be defined as the varying of the terms, and of the conditions in the broadest sense under which the market may have temporary access to Central Bank Credit through discounts of selected short term assets or through secured advances )

वाणिज्य बैंक ब्याज का जिहा दर पर व्यापारियों का ऋण देती है उस दर में तथा बैंक दर में इस विधि प्रकार का सम्बन्ध है कि जब बैंक की दर में वृद्धि हो जाती है तो वाणिज्य बैंक भी अपना ब्याज की दर में समान जथा अधिका वृद्धि कर देती है। इसके विपरीत बैंक दर में कमी होने पर वाणिज्य बैंक भी अपनी ब्याज की दर में कम कर देता है। बैंक दर में परिवर्तनों के द्वारा केन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में सास मुद्रा को मात्रा पर नियंत्रण रखती है। यदि केन्द्रीय बैंक को यह ज्ञात होता है कि देश में स्फीति उत्पन्न हो गई है तो केन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में स्फीति को समाप्त करने के उद्देश्य से बैंक दर में उपयुक्त वृद्धि कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि वाणिज्य बैंक भी अपनी ब्याज की दर में वृद्धि कर देती है। जब वाणिज्य बैंक व्यापारियों से अपने ऋण पर पहले की तुलना में अधिक ब्याज लेने लगती है तो वस्तुओं की उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि ब्याज की दर उत्पादन लागत का भाग है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहते हुए उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर व्यापारी बैंकों से उधार लेना कम कर देते हैं। परिणामस्वरूप अव्यवस्था में संपूर्ण निवेश की मात्रा कम हो जाती है। निवेश की राशि में कमी हो जाने से उत्पादन साधनों की माँग में कमी हो जाने के कारण वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनकी आयें कम हो जाती हैं। उत्पादन साधनों की आयों में कमी हो जाने के कारण कुल उपभोग में कमी हो जाती है क्योंकि उपभोग व्यय आय द्वारा निर्धारित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में कमी हो जाती है तथा इनकी कीमतों में भी कमी हो जाती है।

इसके विपरीत देश में अवस्फीति तथा बेरोजगारी उत्पन्न हो जाने पर केन्द्रीय बैंक द्वारा दर में कमी कर दी जाती है। बैंक दर में कमी हो जाने पर वाणिज्य बैंक भी अपनी उधार दान दरों में कमी कर देती है। इससे उद्यमकर्त्ता को पहले से अधिक निवेश करने का उत्साह प्रदान होता है। अधिक निवेश होने पर अव्यवस्था में उत्पादन साधनों को अधिक रोजगार प्राप्त होने लगता है जिसके कारण उनकी आयों में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग माँग में वृद्धि हो जाती है माँग में वृद्धि हो जाने के कारण कीमतों में गिरावट समाप्त हो जाती है। अव्यवस्था में बैंक दर में होने वाले परिवर्तन आर्थिक स्थिति के सूचक का कार्य करते हैं। बैंक दर में वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चेतावनी देती है परन्तु बैंक दर में कमी इस बात को सूचित करती है कि देश की अव्यवस्था अभिवृद्धि से दूर है तथा देश में अधिक निवेश किया जा सकता है।

**बैंक दर के प्रभाव—**बैंक दर में परिवर्तन के दो प्रभाव होते हैं—(1) आन्तरिक प्रभाव (ii) बाह्य प्रभाव।

(1) आन्तरिक प्रभाव—इसका आशय उन प्रभावों से है जिनका दश में अन्दर अनुभव किया जाता है जैसे—

(i) साख की मात्रा पर प्रभाव—जब केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर बढ़ा देता है तो इससे बाजार की ब्याज दर बढ़ जाती है तथा गृहणें हो जाते हैं तथा उनकी माँग में गिरावट आती है तथा साख संकुचन होता है। इसके विपरीत बैंक दर घटने से बाजार की ब्याज दर भी घटती है। इसका प्रभाव से ऋण लेना सस्ता हो जाता है ऋणों का माँग बढ़ता है और साख का विस्तार हाता है।

(ii) आन्तरिक मूल्य स्तर तथा मजदूरी पर प्रभाव—बैंक दर में वृद्धि के कारण ऋण महंगे हो जाते हैं जिससे व्यापार तथा उद्योग रुकता जाता है राजस्व गिरता है। प्राण का क्रय शक्ति में गिरावट आता है और वस्तुओं की मांग गिरती है। पत्र-स्वरूप उदाहरण म भी बना आता है। प्राण वस्तुओं का मांग सचय हनु नहीं बरत, इस कारण वस्तुओं की मांग में और भी गिरावट आता है बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि मांग में कमी से उत्पादन का स्तर गिरता है उत्पादन इवाइयाँ उत्पादन बन्द करन लगता है लागत की आय गिरता है। इससे विपरीत अर्थात् बैंक दर में कमी के कारण इससे अव्यक्त विपरीत परिणाम हात है।

(ii) बाह्य प्रभाव—इसका सम्बन्ध देश का बाह्य अर्थव्यवस्था में हाता है।

(i) विदेशी-विनिमय दर पर प्रभाव—जब विदेशी देश का अन्तर्गत बैंक अपनी बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो विदेशी पूँजी प्राण देश में आयातित होती है देश का निर्यात में वृद्धि हाता है आयात घट जाते हैं क्योंकि अनता की प्रयोजन में गिरावट आती है। इन सबका प्रभाव यह हाता है कि उदाहरण का मुद्रा का विदेशी विनिमय दर अनुभूत हो जाता है। मुद्रागत सन्तुलन तथा व्यापार सन्तुलन भी अनुभूत होना व प्रवृत्ति दिखता है। इससे विपरीत बैंक दर में गिरावट होने से अव्यक्त विपरीत परिणाम होने लगे हैं।

(ii) विदेशी पूँजी आवागमन पर प्रभाव—बैंक दर में परिवर्तन से विदेशी पूँजी का आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। जब बैंक दर बढ़ना है तो विदेशी पूँजी विनिमय दर इस देश में अपनी पूँजी लगाकर उदाहरण बैंक दर का लाभ उठाता है। बैंक दर घटने से देश की पूँजी एवं विदेशी पूँजी का आवागमन जान लगनी है।

दर में परिवर्तन किन कारणों से किया जाता है

बैंक दर में वृद्धि निम्न कारणों से की जाती है

- (1) देश का बाह्य पूँजी प्रवाह रोकने के लिए।
- (2) विदेशी विनिमय दर की प्रतिस्पर्धा का रक्षण हेतु।
- (3) देश का बाह्य स्वयं प्रवाह का रक्षण हेतु।
- (4) देश में बढ़ती हुई मृदा प्रवृत्ति पर अनुभव लगाने हेतु।
- (5) मुद्रा गजार में मुद्रा प्रवृत्ति का अतिक्रमण से मूल्य स्तर वृद्धि रोकने हेतु।

बैंक दर में कमी निम्न कारणों से की जाती है—

- (1) देश में विनिमय में वृद्धि के लिए।

(2) पूँजी की मांग में गिरावट होना पर उच्च वृद्धि के लिए जिससे कि बैंक का कोष शेष में न पड़े रहे।

- (3) विदेशी पूँजी का अन्धाधुन्ध आयात का स्थिति पर बाध पाने के लिए।

(1) बैंक दर नीति की सीमाएँ (Limitations of the Bank Rate Policy)

मात्र मुद्रा का मात्रा पर नियन्त्रण करके केन्द्रिय बैंक का बैंक दर नीति सीमित रूप में ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का बनाय रख सकती है। बैंक दर का सीमाएँ कई बातों पर निर्भर होती है।

(1) केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक का मध्य सम्बन्ध—यह देश की बात पर निर्भर हाता है कि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक का मध्य सम्बन्ध प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध है। यदि यह सम्बन्ध अति निकट तथा गहरा है तो व्यापारिक बैंक बैंक दर में परिवर्तन का अनुसार अपना व्याज का दर में उपयुक्त परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक की नीति का सफल बनाने में सहयोग देगा। इससे विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक का दूर का सम्बन्ध है और व्यापारिक बैंक केन्द्रिय बैंक से विनाय मात्रा में उधार नहीं

लेती है तो केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं होगी। अन्वित्ति-देश में जहाँ केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों का गणनी तथा कण-दत्ता के रूप में विशेष सम्बन्ध नहीं होता है बैंक दर नीति को अपने उद्देश्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। एक दर नीति को सफलता के लिए देश में केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंकों के मध्य गहरा सम्बन्ध एवं सम्बन्ध होना आवश्यक है।

(2) निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति— बैंक दर नीति को सफलता निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति पर भी निर्भर होती है। स्थिति में जब कीमतों में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है व्यापारी भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्रीय बैंक कीमत स्तर को स्थिर रखने के उद्देश्य से अपनी बैंक दर में वृद्धि करती है और देश में वाणिज्य बैंक भी केन्द्रीय बैंक के साथ अपनी व्याज की दर में वृद्धि करके सहयोग देता है तो भी केन्द्रीय बैंक को अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। व्याज की दर में वृद्धि होने पर भी यदि देश में निवेशकर्ता भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की आशा करते हैं तो वे बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त करने के बजाय ऊँची व्याज की दर पर ऋण लेकर भी उनके लाभ प्राप्त होने की आशा होती है। इस का एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। यदि भविष्य में निवेशकर्ता यह आशा करते हैं कि कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी तो व्याज की दर में यदि 19 प्रतिशत की वृद्धि भी हो जाती है तो भी वे बैंकों से ऋण लेने से नहीं रूकेगे। अन्वित्ति के कारण माला मुद्रा की माँग पूर्णतया व्याज निरपेक्ष हो जाती है और बैंक दर में वृद्धि होने का इस माँग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे अतिरिक्त व्याज की दर में वृद्धि होने का प्रभाव कुल उत्पादन लागत पर बहुत कम पड़ता है क्योंकि व्याज का उत्पादन लागत का एक बहुत कम भाग होता है। इससे अतिरिक्त बहुत से व्ययसामग्री में पूँजी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है और इस कारण ऐसे व्ययसामग्री पर व्याज की दर में परिवर्तनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि दीर्घकाल में बैंक दर का निवेश पर अपेक्ष प्रभाव पड़ता है परन्तु अल्पकाल में यह प्रभाव अतिरिक्त तथा कम होता है और जीवन में अल्पकाल का महत्व दीर्घकाल की तुलना में अधिक होता है।

मर्दी में बैंक दर का मध्य अभिवृद्धि (boom) का काम की तुलना में अधिक असफल सिद्ध होता है। मन्दी काल में जब निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति निराशावादी तथा धारण कर लेती है तथा भविष्य में वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर गिरावट होने की आशा होने के हेतु भविष्य अनिश्चित हो जाता है तब बैंक दर में कटौती भी आसानी से नहीं की जाये निवेशकर्ता कम व्याज की दर पर भी बैंकों से ऋण प्राप्त करके निवेश करना ही चाहते हैं। यदि निवेशकर्ता यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में 10 प्रतिशत का कमो-कमो तो 9 प्रतिशत ऋणात्मक व्याज का दर (जो सम्भव नहीं है) क्योंकि वाणिज्य बैंकों का उद्देश्य ऋण लेकर लाभ प्राप्त करना है) पर ऋण लेकर भी उनका हानि होगी। मर्दी में बैंक दर नीति को मोटा की क्राउडर ने एक सुन्दर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। अर्ध-शर-स्थिति में निवेशकर्ता वर्ष की तुलना छोड़े से तथा वर्षों में प्राप्त होने वाली ऋण सहायता की तुलना पानी से करते हुए क्राउडर ने लिखा है कि केन्द्रीय बैंक छोड़—निवेशकर्ता वर्ष—ने सामने पीने के लिए पानी (ऋण) रखा करता है, परन्तु वह पाइ को पाना पीने पर बाध्य नहीं कर सकता है। यदि पाइ को पाना नहीं है तो अधिक पानी सामने होते हुए भी वह पानी नहीं पीयेगा। मर्दी में दर पड़े की व्यास बिन्दु, समाप्त हो जाती है और यदि उसके मुषण भी पाया गिरता है तो भी वह नहीं पीता है।

## (2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

खुले बाजार की क्रियाएँ केन्द्रीय बैंक की साहाय्य द्वारा नियंत्रण की द्वारा प्रमुख रीति है। इस रीति का प्रयोग केन्द्रीय बैंक बहुधा बैंक दर के पूरक के रूप में करती है। इस

रीति के अन्तर्गत वन्द्रीय बैंक द्वारा बाजार में सर्वाधिकार तथा उत्तम ऋण प्रदाता तथा प्रतिभूतियाँ का प्रयोजन करके अर्थव्यवस्था के संचालन में मुद्रा की मात्रा में उपयुक्त रणनीति अथवा वृद्धि करके साख-मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखती है। स्थिति—अभिवृद्धि—में वन्द्रीय बैंक ऋणपत्रों का कम कीमत पर बचकर अर्थव्यवस्था में सस्ती मुद्रा की आपूर्ति करके कीमत स्तर में कमी करने का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था में जब प्रस्तावित ऋणपत्रों का खरीदते हैं तो वाणिज्य बैंकों के पास नकदी कम हो जाती है और उनके अपनी साख-मुद्रा निर्माण की मात्रा में कमी करने पड़ती है। ऐसा करने पर ऋणपत्रों को ऋण में बदलने तथा पुराने ऋणपत्रों से अपने ऋणों का भुगतान करके लेती है। साख-मुद्रा की मात्रा में कमी होने का कारण निवेश की मात्रा में कमी आती है और कीमत स्तर भी कम हो जाता है।

इसके विपरीत मन्दी में वन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ तथा ऋणपत्रों को अधिक कीमत पर खरीद कर अर्थव्यवस्था के संचालन में वृद्धि करके मन्दी को समाप्त करने की चपटा करती है। नकदी बढ़ जाने पर वाणिज्य बैंकों की नकदी में वृद्धि हो जाती है और वे अधिक नकदी के आधार पर अधिक साख-मुद्रा का निर्माण करती है। जिसके कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था को मन्दी से मुक्ति मिलती है।

खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए आवश्यक बातें—(1) बाजार में हुण्डियाँ का प्रयोजन साख-मुद्रा नियन्त्रण का अप्रत्यक्ष रीति है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वाणिज्य बैंक अपने नकदी कापा में कमी अथवा वृद्धि करती है अथवा नहीं। खुले बाजार में हुण्डियाँ को खरीदने तथा बेचने की रीति इन मान्यताओं पर आधारित है कि साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा कमी बैंकों की नकदी में वृद्धि तथा कमी पर निर्भर होता है। परन्तु ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं है। अभिवृद्धि में बैंकों के पास कम नकदी होने से भी साख-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत मन्दी में यद्यपि वाणिज्य बैंकों की कुल नकदी में वृद्धि हो जाती है परन्तु फिर भी वे अधिक साख-मुद्रा का निर्माण नहीं करती हैं।

(2) वन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वन्द्रीय बैंक के पास उपयुक्त ऋणपत्रों की कितनी मात्रा है और कितनी मात्रा में वह ऋणपत्रों को मन्दी के पास में अधिक मूल्य पर खरीदने का तैयार है। यदि वन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से हानि सहन करने के लिए तैयार भी होता है तो भी यह सम्भव है कि इसका अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त हो। यह सम्भव है कि स्थिति के समय वन्द्रीय बैंक के पास बेचने योग्य ऋणपत्रों की मात्रा इतनी कम हो कि सार ऋणपत्रों को बचकर भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं हो सके। वन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाओं की व्याख्या करते हुए बेंगलूर ने लिखा है कि वन्द्रीय बैंक अभिवृद्धि का रोकने के लिए केवल उतनी ही बारूद का प्रयोग कर सकती है जितनी कि उसको मन्दी से लड़ने के समय प्राप्त हुई है और बारूद की यह मात्रा अभिवृद्धि पर काबू पाने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।

(3) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दण्ड का मुद्रा बाजार में गठित एवं विकसित हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वन्द्रीय बैंक के लिए प्रतिभूतियाँ का प्रयोजन द्वारा वांछित परिणाम मिलने की आशा नहीं होगी।

(4) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता नहीं हो सकती है जब कि व्यापारिक बैंकों प्रतिभूतियों में धन विनियोजित करने के लिए एक प्रकार से आदी हो गई है।

(5) व द्रीय बैंक का अधिकार नि अनुमोदित या सरकारी प्रतिभूतियां जिनका वि-  
नय विषय व द्रीय बैंक करता है उनमें मूल्या म शीघ्र परिवर्तन न होना व यदि मूल्य म  
शीघ्र परिवर्तन हान ता विनियामरता इनम पूजा विनियोजन स कतरावण और नियार्ण  
सफन एा हा सत्ता ।

**खुले बाजार की क्रियाओं को लोकप्रियता क कारण**

वर्षान्त समय म राज्य निय प्रण व उपाय क रूप म खुल बाजार का प्रियाशा की  
सीताप्रमता निम्नान्वित कारणता स अधिक हा गई है—

(1) खुल बाजार का प्रियाए तुरन्त बैंका व नकद काया का बाछित दिशा म त  
जान म सहायक हाती है ।

(2) यह विधि प्रथम विश्व युद्ध क बाद राज्य नियन्त्रण क लिए अधिक उपयोगी  
निद्व हुई है ।

(3) मुद्रा बाजार म सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां व न्य विषय का  
बचत बढ़ता जा रहा है इसनिए वन्द्रीय बैंक को खुले बाजार की प्रियाए सपादित करने  
म काफी सुविधा मिली है ।

(4) बैंक दर नीति क बाछित परिणाम न निवचन तथा इसकी सीमाआ एवं अय  
धोषा म सवदनशासता को दानते हुए खुल बाजार की प्रियाए बैंक दर नीति क अच्छे  
विनरूप क रूप म साबित हुई है ।

**बच दर नीति तथा खुल बाजार की क्रियाओं म अन्तर भयवा दोनो मे कौन धंष्ट है ?**

साख नियन्त्रण की परिमाणात्मक अथवा प्रत्यक्ष रीतिया म बच दर एवं खुल  
बाजार का प्रियाए दाना ही महत्वपूर्ण है परन्तु बैंक दर नीति की अपेक्षा खुल बाजार  
का प्रियाए अधिक धंष्ट है । यह बात दाना म निम्नान्वित अन्तर द्वारा स्पष्ट हो जाती है

(1) नकद कोषा पर प्रभाव—बैंक दर नीति की अपेक्षा खुल बाजार की प्रियाए  
व्यापारिक बैंक क नकद काया को तुरन्त एवं प्रत्यक्ष रूप स प्रभावित करती है । जब  
वेन्द्रीय बैंक खुल बाजार की प्रियाआ द्वारा प्रतिभूतियां खरीदता है तो व्यापारिक बैंक  
इस प्रतिभूतिया को बचते है तो तुरन्त ही इन बैंका की नकद काय प्रभावित अर्थात् बढ़  
जात है । यदि वन्द्रीय बैंक प्रतिभूतिया को मुद्रा बाजार म बचता है ता बैंका व नकद  
कोष तुरन्त ही कम हा जाते है । बैंक दर नीति इतना शाप्रता स प्रत्यक्ष रूप स बैंका व  
नकद कोष का प्रभावित नहा करती ।

(2) बारम्बारता—बैंक दर म बार बार परिवर्तन करना सम्भव नहीं हाता ।  
कदाचि बैंक दर नीति द्वारा स्वदशा बैंका व नकद काय ही प्रभावित नहा हात वरन्  
दिशा बैंका एवं पूजा क आवागमन पर भी प्रभाव पडता है । इसक साथ व्यापारिक  
बैंका व कोषा म होने वाल परिवर्तना का पूर्वानुमान लगाना कठिन हाता है इसर विपरीत  
खुल बाजार की प्रियाआ की क्विन ही बार वेन्द्रीय बैंक अपना सक्ता है और निश्चित  
तथा बाछित दिशा म साख परिवर्तन करना सम्भव हो सक्ता है ।

(3) ऐच्छिक—खुल बाजार की प्रियाए ऐच्छिक हाती है अर्थात् यह व्यापारिक  
बैंका पर अनुचित दबाव नहा हाती है । व्याज क दर म परिवर्तन द्वारा व्यापारिक बैंक  
लाभ वमान की दृष्टि स प्रतिभूतिया का न्य विषय करत है । इसक विपरीत बैंक दर  
नीति म जब परिवर्तन हाते है ता प्रण प्रदान करने वाले बैंक एवं सस्याआ का अपनी  
व्याज दर म इसी परिवर्तनानुसार परिवर्तन लान क लिए बाध्य होना पडता है ।



वैर्घवासीन दरों पर प्रभाव—वैर्घ नीति व्याज की अल्पवासीन दरों को प्रभावित करती है। क्योंकि व्यापारिक बैंक अल्पवासीन ऋण प्रदान करते हैं। इससे विपरीत रूपले व्यापार की प्रियावा में सरकारों प्रतिभूतियों दीघवासीन समय के लिए भी बेची जाती है इसलिए इनके द्वारा व्याज की दीघवासीन दरें तथा मांग नीति को भी प्रभावित किया जा सकता है।

सार नियन्त्रण की दोनों रीतियाँ एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे की पूरक व रूप में ही समायोजनीय होती चाहिए। अव्यवस्था की आवश्यकतानुसार ही दोनों का समय समय पर प्रयोग वांछित होगा। यदि आवश्यकता है तो दोनों को एक साथ भी उपभाग में लाना चाहिए। दोनों विधियाँ न बॉन रौन माँ विधि श्रेष्ठ है इसका उत्तर इन के लिए हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैर्घ नीति की अपक्षा खुले बाजार की प्रियाएँ अधिक श्रेष्ठ एक उत्तम है।

### (3) न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात अथवा परिवर्तनशील तरतु कोषानुपात (Minimum Legal Reserve Ratio or Variable Reserve Ratio)

अव्यवस्था में वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात में जो प्रत्येक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का निर्धारित प्रतिशत दर पर आरक्षण के रूप में रखना पड़ता है उपर्युक्त परिवर्तन करना भी केंद्रीय बैंक अव्यवस्था में बैंकों को मांग-मुद्रा निर्माण प्रियाओं पर नियन्त्रण कर सकता है। प्रत्येक देश में जहाँ केंद्रीय बैंक होती है वाणिज्य बैंकों को अपना कुल जमाओं का विधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात के रूप में जमा रखना पड़ता है। इस अनुपात में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के पास नकदी की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करके अव्यवस्था के संचालन में कुल मांग-मुद्रा की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि कर सकता है।

अमेरिका में इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त 1906 ई० में न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि के रूप में अत्यधिक मांग-मुद्रा निर्माण की हानियों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से किया था। इस अनुपात में वृद्धि हो जाने पर सदस्य बैंकों की नकदी 3,100 मिलियन डॉलर गति से घट कर अब 1,800 मिलियन डॉलर रह गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 1937 ई० में इस अनुपात में पुनः वृद्धि की गई थी। यह कुछ वर्षों में न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात रीति का प्रयोग 1951 ई० में कोरिया युद्ध (Korean War) के कारण उत्पन्न र्णोति को रोकने के उद्देश्य से किया गया था।

मांग-मुद्रा नियन्त्रण की अन्य रीतियाँ न समान रूप रीति की भाँगीमाएँ हैं। प्रथम जब वाणिज्य बैंकों के पास अधिक नकदी होता है तो वे केंद्रीय बैंक की न्यूनतम वैध आरक्षित अनुपात रीति को अनादर कर सकते हैं। दूसरे वाणिज्य बैंक अपना जमाओं के ढाँचे में लचकतें करके अपने केंद्रीय बैंक की रीति का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि चाँू तथा मियादी जमाओं पर केंद्रीय बैंक के पास इन जमाओं का 2 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत भाग न्यूनतम वैध निधि के रूप में जमा करना पड़ता है तो म्यादी निर्माण वाणिज्य बैंक अपना मांग-मुद्रा में मियादी जमाओं में कमी तथा चाँू जमाओं में वृद्धि दिलानेकर केंद्रीय बैंक को कम नकदी भेजने में सफल हो सकता है।

मांग की मात्रा मांगे का पूर्ण पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि मांग पर भी निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों की मांग-तृप्तन की क्षमता में परिवर्तन द्वारा

वांछित उद्देश्या की पूर्ति सफलता में केन्द्रीय बैंक को उम समय नहीं मिली यदि माँग में परिवर्तन उम दिशा में नही होता जिसमें केन्द्रीय बैंक चाहता है। उदाहरणार्थ मन्दी के समय प्रारंभित निर्धि अनुपात में कमी होना पर भी लागू में विस्तार नही होना पाता।

जन्दी उत्तरी निर्धि माँग में परिवर्तन करना उचित नही होता। इसको धरमात्र मद्रा की पूर्ति हेतु मात्र-मात्र प्रयोग में नही लाना चाहिए। यह एक प्रकार से और-नचना (Inflexible) अस्त्र होता है। प्रो० डी० कार इस सम्बन्ध में कहते हैं 'जबकि यह बैंक नन्द माँग उपलब्ध पूर्ति तथा वांछित परिवर्तन का बहुत कुछ गत्व प्रभावशा की तरफा है इसकी कुछ तकनामा तथा मनावैज्ञानिक भीमार्ण है जो बताता है कि इसका मोच ममम-कर और कच्छानुमात्र करन असाधारण परिस्थितिया में ही प्रयोग करना चाहिए।'<sup>1</sup>

**आलोचनाएँ** --(1) विभिन्न बैंकों के पास विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त निधियाँ होती हैं इनमें विमो प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न बैंकों पर एक सा नहीं पड़ता। कुछ बैंकों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा तथा कुछ पर बहुत अधिन होकर पड़ता है। इस पर एक आगेप यह भी बताया जाता है कि बैंक वैश्विक विदेशीय मध्यस्था जैसे वामा कम्पनिया विद्याम बैंक जावाम समितिया आदि पर जो कि व्यापारिक बैंकों की प्रतिस्पर्धी होती हैं बोट प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) निर्धि माँगों में परिवर्तन कुछ व्यापारिक बैंकों के लिए अनिश्चितता लाना है। कभी-कभी इसमें नियम तथा परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही कष्णपूर्ण होता है इसलिए इस वडे मोच-अमममकर अपनाता चाहिए। ऐसा कहते हैं कि निर्धि माँगों में परिवर्तन घोषणा माना में महा जोड़ पश्य के बाद नियम जा चाहिए।

(3) यह माँग की लागत में वृद्धि करता है। चूँकि केन्द्रिय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा न्यूनतम बैंध आरक्षित निर्धि पर कोई ब्याज नहीं देता इसलिए व्यापारिक बैंक न्यूनतम निर्धि की माँग बढ़ने से अपने ब्याज की अतिवृत्ति अपने ऋणियों से अधिक ब्याज की बसूरी द्वारा करते हैं।

(4) इसका आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसका प्रतिभूतिया के बाजार पर प्रतिभूत प्रभाव पड़ता है। जब केन्द्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम बैंध आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों की नन्दी का एक भाग केन्द्रीय बैंक को हस्तांतरित होना पड़ता है और वे अपने पास रखी हुई प्रतिभूतिया (Securities) को बचन लगते हैं। इस प्रकार के प्रभाव का रोक्कन के लिए अति प्रतिभूतिया के मूल्या में गिरावट न आना देना के लिए यह मुजाव दिया जाता है कि केन्द्रीय बैंक का लूने बाजार की त्रियाआ द्वारा प्रतिभूतिया का श्रय कर लेना चाहिए जिससे कि इसकी मुद्रा बाजार में पूर्ति अतिव न बढ़ने पाए और उनकी कीमतें स्थिर रहें।

न्यूनतम बैंध आरक्षित अनुपात की उपयुक्त सीमाआ तथा आनाचनाआ के बारे में सामान्य नियंत्रण एवं उपयोगी एवं शक्तिशाली अस्त्र है। प्रो० सयस कहते हैं कि

1 While it is a very prompt and effective method of bringing about the desired changes in the available supply of bank cash it has some technical and psychological limitations which prescribe that it should be used with moderation and discretion and only under obviously abnormal conditions"

यह एक ऐसा अस्त्र है जिसे केन्द्रीय बैंक के हाथ में रहना चाहिए।  
केन्द्रीय बैंक को सभी शक्ति देना केन्द्रीय बैंक उपयोगी तरीके से कार्य कर सकता है  
जिसका वि व्यापारिक बैंक से करने की आशा नहीं की जा सकती है।<sup>1</sup>

#### (4) तरल कोषानुपात (Liquidity Ratio)

दशक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल पूंजा का एक भाग तरल रूप में रखना  
पड़ता है। इस तरल मुद्रा का एक भाग नकद राशि और एक भाग अनुमानित प्रतिभूतियां  
रूप में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक निश्चित मामा के अन्तर्गत मुद्रा तरल  
तथा प्रतिभूतियां के रूप में रखा जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि बैंक का अपने माधन का एक अंश  
आवश्यक रूप से सरकारी प्रतिभूतियां में रखा जाना पड़ता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक द्वारा  
नियंत्रण किया जाता है।

यहां उद्देश्य व्यापारिक बैंक को उच्च शक्ति पर अकुशल रखा जाता है ताकि  
वैयक्तिक परिसम्पत्तियां (Assets) का नुकसान न हो सके और उचित मात्रा में  
म विस्तार की क्षमता में वृद्धि न हो पाए।

मुद्रा स्थातिक स्थितियों पर काबू पाने के लिए सामान्य नियंत्रण का यह तरीका  
महत्वपूर्ण होता है। कुछ स्थितियों में इनका पूर्ण भिन्न-भिन्न प्रकार के हाना-पह  
प्रबंधन नीति से सम्बंधित होता है। जब कानून द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक का  
अपना पूंजा का एक भाग सरकारी प्रतिभूतियां में रखा जाना अनिवार्य कर देता है तो सरकार  
के लिए हाना-पह प्रबंध (Deficit financing) को अपनाता आता है।  
वित्तीय प्रबंधन का यह नीति स्थातिक विरुद्ध होता है क्योंकि जितना धन ग्राहकों  
सरकार को दे जाता है व्यापारिक बैंक उस राशि को सामान्य व्यवसाय के लिए ग्राहकों-संयुक्त  
में नहीं वापस पाते। यदि आर्थिक विकास तथा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण एक  
स्थातिक दबाव बढ़ रहा हो तो मौद्रिक नीति के सरकारी नीति के लिए सामान्य नियंत्रण  
की यह नीति लाभकारी होती है।

### II गुणात्मक विधियां

#### (1) साख मुद्रा रक्षण (Credit Rationing or Rationing of Credit)

यही नीति कि अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकताओं  
का ध्यान में रखकर साख मुद्रा निर्माण की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है तथा  
विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग-अलग (quota) निर्धारित कर दिया जाता है। निश्चित मात्रा  
को उसका निर्धारित अलग-अलग अधिक मात्रा मुद्रा उत्पादन करता है। अर्थात्  
यह नीति सामान्य मुद्रा नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तरीका है परन्तु इस नीति में कुछ व्यापारिक  
स्थातिक बाधाएँ हैं।

(1) केन्द्रीय बैंक का एक मात्र धन का निर्माण आवश्यकताओं तथा अन्य  
सम्बंधित सामान्य मुद्रा निर्माण का मापदण्ड का मापदण्ड रखा जाता है और यह दबाव  
कठिन कार्य है।

1 It is a weapon which should always be placed in the hands of a central bank whose freedom is circumscribed by the conditions under which the effective utilisation of open market operations. Given such power the central bank can perform useful functions which commercial banks cannot be expected to perform.

(2) केन्द्रीय बैंक को प्रत्येक बैंक के अभ्यर्षो की मात्रा को निर्धारित करना होता है।

(3) इस रीति में व्यापार का विकास साख मुद्रा की मात्रा से सीमित हो जाता है। जर्मनी में रिचम बैंक जो यहाँ की केन्द्रीय बैंक थी ने इस रीति का प्रयोग 1924 ई० 1629 ई० तथा 1931 ई० में किया था।

(4) जर्मनी के अतिरिक्त रूस तथा मैक्सिको आदि देशों में भी इस रीति का प्रयोग उपलब्ध साख मुद्रा का भिन्न व्यवसायो में न्यायपूर्ण वितरण करा व उददेश्य से किया गया है। साख मुद्रा तथा पूँजी का राशनिंग तानाशाही दशा में महान तथा विस्तृत योजनाओं को सफलता के लिए अतिआवश्यक होता है। तानाशाही राश्या व अतिरिक्त अधिकसित दशों में भी साख मुद्रा अभ्यर्षो की राशि को विभिन्न व्यवसाया व लिए निर्धारित करना देश के आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ मैक्सिको में साख मुद्रा राशनिंग की रीति को उस दश में साख मुद्रा पर नियन्त्रण करने व लिए उपयोग किया गया है।

### (2) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

प्रत्यक्ष क्रिया का अभिप्राय प्रतिरोधी क्रियाओं से होता है। जब कोई बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन नहीं करती है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक व विरुद्ध अनेक प्रकार की सीधा कार्यवाहियाँ — उस बैंक को हुण्डियों को न भुनाना तथा उसको ऋण देने से इनकार करना इत्यादि करके उस बैंक को अपने आदेश मानने पर बाध्य कर सकती है। प्रवरात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) की रीति के द्वारा केन्द्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का अच्छे प्रकार से नियन्त्रण कर सकती है। अमरीका में फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) ने 1928 1929 ई० में इसके आदेश का उल्लंघन करने वाली बैंकों को हुण्डिया को भुनान से इनकार करके प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्रयोग किया था। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 1956 ई० में प्रवरात्मक साख मुद्रा नियन्त्रण की रीति का सफल प्रयोग कर रही है।

केन्द्र नियोजित देशों में केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के साख नियन्त्रण का पूरा एवं प्रत्यक्ष अधिकार होता है। साख निर्माण संस्थाएँ अर्थात् बैंक केन्द्रीय बैंक द्वारा आदेशों तथा निबन्धों के लिए निर्धारित नीति का अनुसरण करते हैं। केन्द्रीय बैंक द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि अधिमो की राशि उद्देश्य तथा ब्याज की दर क्या होगी केन्द्रीय बैंक स्वयं सरकार के अधीन कार्य करने वाला बैंक होता है। इस सम्बन्ध में इन सरकारी निर्देशों का पालन भी व्यापारिक बैंकों से कराना होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का अधिकार गुद तथा अन्य असाधारण परिस्थितियों में सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है।

प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) उन देशों में साख नियन्त्रण की एक अन्ती विधि मानित हो सकती है जहाँ मुद्रा बाजार में बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं तथा उनकी

- 1 Rationing of credit and capital is a logical concomitant of the intensive and extensive planning adopted in regimented economies. Not only is this method resorted to in authoritarian economies but as Wagemann rightly claims even in more primitive economic conditions the setting of credit quotas is the only decisive method which the central bank has in order to prevent excessive credit demands on the part of business " — E Wagemann

शाखाएँ बहुत अधिक मात्रा में पायी जाँ। इमक अतिरिक्त व्यापारिक बैंका के लिए कन्द्रीय बैंक पर काफी ब नियंत्रण रहना पता है। पुनर्जाती सुविधाया ब नियंत्रण व्यापारिक बैंक ब द्रीय बैंक क पास जात हा आदि आदि।

प्रत्यः कायवाही रीति में बहुत सी कांठनाइयाँ पाई जाती है। कन्द्रीय बैंक क पास व्यापारिक बैंका का गारा निस्तार करवा ती पूरा जानकारी होनी चाहिए। कन्द्रीय बैंक को यह भी मानूँ हाना चाहिए कि उचित एवं अनुचित में इस भेद किया जाय साथ ही साख क उपयोग का दूसरी-तीसरी तथा चौथी पार्टी द्वारा जितना किया जा रहा है। सभी बातें एक साथ पाई नहीं जाती इमंत्रण क समय तक द्वारा प्रत्यक्ष कायवाही क प्रयोग क अभी-कभी वाचित परिणाम प्राप्त हात है। इमंत्रण प्रत्यक्ष कायवाही करत समय कन्द्रीय बैंक का काफी स्वयंश में काम नता चाहिए।

### (3) नैतिक अनुयय या समझाना (Moral Persuasion)

कन्द्रीय बैंक अव्यवस्था में वाणिज्य बैंका का सम्भाल की रीति क द्वारा सुझाव क रूप में प्रार्थना करव अपन साखमुद्रा नियन्त्रण क काय में बका का सहयोग प्राप्त करता है। दश में स्फीति उत्पन्न हा जान पर कन्द्रीय बैंक दश में सभी वाणिज्य बैंका का उनर कृणा का मात्रा में उपयुक्त कमा करवा का सुझाव देती है। इमके विपरीत यदि दश में मदी विद्यमान है ता कन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंका को उदार उधारदान नाति का अपना कर उमक कृणा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करन का सुझाव देती है। वाणिज्य बैंक साधारणतया कन्द्रीय बैंक क सुझावा का पालन करती है। इमंत्रण प्राम स्वार्थ हानेण क्त्वादि दशा में जहाँ वाणिज्य बैंक कन्द्रीय बैंक का अपना नता मानती ह इम रीति का काफी सफलता प्राप्त हुई है। उमक अतिरिक्त भारत आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड आदि दशा में भा जहाँ कन्द्रीय बैंका का स्थापित हुए अधिक समय नहीं हुआ है यह रीति काफी सफल सिद्ध हुई है।

भारत में सबप्रथम रिजर्व बैंक आप दृष्टिया में इम रीति का प्रयोग 1949 ई० में एषय क अवसूच्यन क समय किया था। 1949 ई० में रिजर्व बैंक क गवर्नर न वही वाणिज्य बैंका क प्रतिनिधिया का बमर्द में एक अधिवेशन आयोजित किया था जिसका गवर्नर न बैंका का गटटवाजी क लिए श्रेण न लन का सुझाव दिया। कन्द्रीय बैंक का इम सुझाव का काफी अच्छा प्रभाव पडा तथा वाणिज्य बैंका न गटटवाजी क लिए दिा जान बात अग्रिमा में पर्याप्त कमी करव रिजर्व बैंक का अपन सहयोग का परिचय दिया। तब में रिजर्व बैंक द्वारा इस रीति का प्रयोग किया जा रहा है तथा वाणिज्य बैंका न रिजर्व बैंक का इच्छाया का आदर किया है।

### (4) चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control)

चयनात्मक साख नियन्त्रण की विधियाँ कन्द्रीय बैंक द्वारा मोद्रिक व्यवस्था की वनमान नीतियाँ हैं। इन विधिया की विशेषता इमंत्रण भी और अधिक है क्वाकि इतना उद्देश्य किमी विशेष काय क लिए साख की दिशा निर्धारित करना हाता है और साख की कुल मात्रा का प्रभावित करना इनका उद्देश्य नहीं हाता। कर्मा-रभा मामान्य मात्र पर नियन्त्रण करना अव्यवस्था क लिए हानिकारक सिद्ध हा सकता है और साथ का उपयोग उन कामा में अधिक मात्रा में हा जाता है जिनकी आवश्यकता अव्यवस्था क लिए नहा हाती। साथ को करव उन्ही क्षत्रा तथा कार्या तक सीमित रखना चाहिए जिनका प्रयोग अव्यवस्था क लिए उपयोग तथा लाभप्रद हा। इमक लिए बहुत स दशा में कन्द्रीय बैंक चयनात्मक साख नियन्त्रण का अपनाता है जो स्वतन्त्र होत है। साख नियन्त्रण क यह तराये साख का स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रयोग डालत हुए अच्छ परिणाम सामन लात हैं जबकि

इन्हें सही समय तथा सही दिशा में अपनाया जाय। इनकी उपयोगिता उस समय और भी बढ़ जाती है जबकि सामान्य साख रीतियों के साथ इन्हें अपनाया जाता है।

**चयनात्मक साख नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Selective Credit Control)**

चयनात्मक साख नियन्त्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) बैंक साख के जरूरी तथा गैर जरूरी उपयोगों में मध्य भेद करना तथा अर्थ-व्यवस्था में गैर-जरूरी क्षेत्रों के लिए बैंक अप्रिमों के सम्बन्ध में प्रथम नीति अपनाना।

(2) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्थान पर अर्थव्यवस्था के केवल कुछ क्षेत्रों अथवा विन्धुओं को प्रभावित करना जिनकी अधिक आवश्यकता महसूस की जाती हो।

(3) किस्तों अथवा किराये पर खरीद योजनाओं (Instalment and Higher Purchase Schemes) के अन्तर्गत खरीदी जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर रोक लगाना; स्फीतिक स्थितियों से निपटने के लिए सामान्यतया बैंक द्वारा आसान किस्तों तथा किराये पर खरीद योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं पर खरीद के लिए साख पर रोक लगाई जाती है।

(4) दशक भुगतान सन्तुलन की स्थिति को प्रभावित करना। इसके अन्तर्गत निर्यात उद्योगों के विनिमय बिलों की पुनर्वटोती सुविधा देना। भुगतान सन्तुलन की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक आयात हेतु विनिमय बिलों को हतोत्साहित करने के लिए पुनर्वटोती दर (Re-discount rate) उंची कर देता है तथा निर्यात बिलों के लिए यह दर भीची रखता है।

(5) इसका उद्देश्य सभी प्रकार की साख को नियन्त्रित करना होता है इसमें व्यापारिक तथा वित्तीय साख भी शामिल की जा सकती है।

साख-मुद्रा नियन्त्रण की इस रीति का निर्माण सबसे प्रथम अमरीका में राष्ट्रपति के आदेश अनुसार अगस्त 1941 ई. में हुआ था। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उपभोक्ताओं को ऋण देने का आदेश देती है। अमरीका तथा यूरोप के देशों में जहाँ उपभोक्ता बैंकों से ऋण प्राप्त करके वस्तुओं को खरीदते हैं साख-मुद्रा की इस रीति का विशेष महत्व है। इस रीति का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जा सकता है—

(क) विभिन्न कटौती दर— इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विनिमय बिलों के लिए भिन्न प्रकार की कटौती दरें निर्धारित कर देता है। इसका उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता को सरल तथा कुछ क्षेत्रों में बढ़ा करना होता है। यदि सरकार कृषि के लिए ऋण सुविधाओं को बढ़ाना चाहती है तो कृषि विनिमय बिलों की कटौती दर कम कर दी जाती है। इससे कृषि कार्यों तथा व्यापार हेतु विनिमय बिल बढ़ेंगे।

(ख) उपभोक्ता किस्त साख का नियमन— इसका अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के खय के लिए दिये जाने वाले ऋण को संभूत अथवा ऋण बन्धन अपनाता है। कभी कभी उपभोक्ता वस्तुओं को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा निश्चित कर दी जाती है अथवा किस्त की न्यूनतम धनराशि तथा ऋण अदायगी की सीमा तथा समय निश्चित कर दिया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यूरोप के सभी देशों में ऐसी रीति अपनाई गई थी। इस रीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं के वस्तुओं की खरीद पर खरीदने, विप्रेताओं द्वारा उधार पर शत बंधन तथा बैंकों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर ऋण बन्धन लगाना होता है जिससे कि साख-प्रसार न हो।

(ग) अन्तर निर्धारण—व्यापारिक बैंक जो भी ऋण देते हैं वह किसी न किसी जमानत या सम्पत्ति की धरोहर पर दिये जाते हैं। जमानत की धनराशि का प्रायः ऋण का मूल्य का अन्तर 20 से 50 प्रतिशत रखा जाता है। परन्तु कभी-कभी कन्द्रीय बैंक इस प्रकार निश्चित अन्तरों में हस्तक्षेप करके इस अन्तर निर्धारण की सीमा को बढ़ा देता है। उदाहरणार्थ, यदि व्यापारियाँ ने मोदामा में गहूँ अधिक मात्रा में भर दिया है और बाजार में टुन्निम कमी कर दी है। मान लीजिए कि बैंक ने गहूँ पर ऋण दान का 25% माँजिन रखा है, तो केंद्रीय बैंक इसकी सीमा 25% से 40% कर देता है तो व्यापारियाँ 11 15% अतिरिक्त जमानत के रूप में या तो धनराशि या फिर उतने मूल्य का गहूँ रखा जा सकता है। इस प्रकार बाजार में गहूँ की पूर्ति बढ़ाते उसका मूल्य में गिरावट आती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अन्य उपभोक्ता अथवा अन्य कमी वाली वस्तुओं का सम्बन्ध में गहरी नीति अपना सकती है।

(घ) आयात पूर्व जमा केंद्रीय बैंक आयातों का प्राथमिकता देने का माध्यम ही आयात राशि का एक भाग जमा करता है। इस प्रकार इस धनराशि पर मिलने वाली व्याज की हानि होती है। इस नीति का उद्देश्य आयातों का निरन्तराहित करना होता है।

(ङ) नकद ऋणों का सघनात्मक प्रयोग—इस निधि का अंतर्गत केंद्रीय बैंक ने पाप व्यापारिक बैंक अन्विष्ट रूप में जो तरह कोष रखा है उसमें भी पुष्कल मात्रा में अपाई जाती है केंद्रीय बैंक कुछ विशेष क्षेत्रों में वित्तियोजना धाराओं का अपाई प्राप्त नकद जमा के रूप में करता है। इसका आणव्य विभिन्न क्षेत्रों में पुँजी निवेश बढ़ाना होता है।

(च) ऋणों की जाँच तथा नियन्त्रण केंद्रीय बैंक एक निश्चित धाराओं से अधिक ऋण दान पर उम प्रकार की पाबन्दी लगा सकता है। इस नीति का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में ऋणों का प्रोत्साहित करना तथा कुछ क्षेत्रों में निरन्तराहित करना होता है। प्रथम विश्व-युद्ध के पहलू में तीव्रता से जाड़ा न्यूनीकरण तथा स्वीडन में इस नीति का प्रयोग हुआ था।

### विज्ञापन प्रचार (Publicity)

वर्तमान युग में केंद्रीय बैंक अपनी नाव मुद्रा नियन्त्रण नीति का सफल बनाना का उद्देश्य से विज्ञापन के द्वारा जनता तथा निवेशकर्तारों का ध्यान अपनी नीति में आरंभ करती है। उन देशों में जहाँ नागरिक शिक्षित होते हैं विज्ञापन प्रकार की नीति केंद्रीय बैंक की नाव-मुद्रा नियन्त्रण नीति का एक मुख्य अंग हो जाती है। इस नीति का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में ऋणों का प्रोत्साहित करना तथा कुछ क्षेत्रों में निरन्तराहित करना होता है। प्रथम विश्व युद्ध के पहलू में तीव्रता से जाड़ा न्यूनीकरण तथा स्वीडन में इस नीति का प्रयोग हुआ था।

### सारांश

यद्यपि केंद्रीय बैंक का अर्थव्यवस्था के संचालन में नाव मुद्रा की पूर्ति पर नियन्त्रण करना एक अत्यन्त महत्त्व प्राप्त होता है परन्तु अनुभव से पता चलता है कि यह आर्थिक स्थिरता पर पूर्ण नियन्त्रण करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाती है। केंद्रीय बैंक की नाव-मुद्रा नियन्त्रण नीति की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि स्फीति तथा अवस्फीति अब भी समय-समय पर देश की अर्थव्यवस्था के सन्तुलन को भंग करती रहती है। केंद्रीय बैंक का अधिकांश काम विस्तार हानि के साथ-साथ स्फीति की समस्या पहलू की अपेक्षा अधिन गम्भीर होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्फीति तथा अवस्फीति उत्पन्न होना के अनेक मौद्रिक तथा अमौद्रिक कारण होते हैं। केंद्रीय बैंक केवल मौद्रिक कारणों पर अपनी नाव मुद्रा नियन्त्रण नीति के द्वारा प्रभाव डाल सकती है। अतः अर्थव्यवस्था तथा मन्दी पर विजय पाने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक अपने मन्दा का आर-

म्बिक अवस्था में ही पूरी शक्ति के साथ प्रयोग करे। परन्तु दुभाग्यवश राजनातिक कारणों से केन्द्रीय बैंक ऐसा करने में असमर्थ रहती है। वास्तव में अभिवृद्धि तथा भन्दी को कभी भी आरम्भिक अवस्था में रोक्ने का प्रयत्न नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक निवेशकर्ताओं की मनावृत्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। यही कारण है कि केन्द्रीय बैंक अपना मौद्रिक तथा मांग मुद्रा नियन्त्रण नीतियों के द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का बनाय रख सकती है। परन्तु यह हाते हुए भी केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक तथा मांग मुद्रा नियन्त्रण नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता स्थापित करने में एक बड़े अंश तक सरकार की सहायता करने समाज की सेवा करती है।

### अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय बैंक

अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में जहाँ बैंकिंग प्रणाली का विकास नहीं हुआ होता है जहाँ वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का अभाव तथा मुद्रा बाजार अविनियमित होता है, केन्द्रीय बैंक का कार्य अर्थव्यवस्था में केवल मांग मुद्रा का नियन्त्रण करना नहीं है। इसका अधिक महत्वपूर्ण कार्य देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली का सन्तुलित विकास को सम्भव बनाने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान देना है। यदि देश में बैंकिंग का विकास नहीं हुआ है तो केन्द्रीय बैंक का वाणिज्य बैंक का भी कार्य करना देश में साधारण बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी उदार नीति तथा सरकार पर अपना उदार प्रभाव डाल कर केन्द्रीय बैंक का दण्ड में वाणिज्य बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

केन्द्रीय बैंक को दण्ड में संगठित मुद्रा बाजार की भी स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में संगठित मुद्रा बाजार का होना अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मुद्रा बाजार के माध्यम द्वारा ही अर्थव्यवस्था में पूँजी उपलब्ध होती है। मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था की औद्योगिक प्रगति का आधार होता है इससे माध्यम द्वारा उद्योग तथा वाणिज्य का वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। केन्द्रीय बैंक का अर्थव्यवस्था में संगठित वित्त बाजार का विकसित करने पर विचार करना चाहिए। अर्ध विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक को भूमिका कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए साख्त को प्रोत्साहित करना होता चाहिए। दण्ड में सहकारिता के आधार पर सहकारी तथा भूमि विकास बैंक की स्थापना एवं उसमें संगठन में केन्द्रीय बैंक की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक का काम व्याज की दर पर इस बैंक के लिए मध्य-कालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक का दण्ड में पूँजी बाजार की भी विकसित एवं संगठित करना चाहिए जिससे दण्ड में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त बेल मिल सके। पूँजी बाजार में द्वारा औद्योगिक निगमों तथा संस्थाओं के ऋण पत्रों तथा अंशों (Debentures and Shares) का प्रयत्न-श्रम होता है और उद्योगों के लिए तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए पूँजी प्राप्त हो जाती है।

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (केन्द्रीय बैंक का रूप में) अर्थव्यवस्था के नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य तथा सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रही है। भारत में रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) का वैश्विक विकास की स्थापना सन् 1950 में की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे बसों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना है, यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में वचता को प्रोत्साहित करता है। कृषि साख्त सम्बन्धी नीति निर्माण हेतु रिजर्व बैंक में कृषि साख्त विभाग की स्थापना की है। आवश्यकता पड़ने पर यह विभाग भारत सरकार 'राज्य सरकार' तथा सहकारी संस्थाओं के लिए कृषि साख्त सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करता है। सन् 1947 में



भारत सरकार ने विदेशी विनिमय नियंत्रण एकट पास किया। रिजर्व बैंक के इस विभाग द्वारा गणस्त विदेशी विनिमय का प्रय विषय दिया जाता है।

भारत में बिन बाजार की निमित्त बचन की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी 1952 को बिन बाजार योजना प्रारम्भ की जिसमें अन्तगत अनुसूचित बैंकों को गृही प्रतिभा पत्रा (Usance Promissory Notes) के आधार पर माँग श्रृण प्राप्त करवा का गविधा की गई थी। सन् 1970 से नई बिन पुनःटौती योजना (Bill Re-discounting Scheme 1970) प्रारम्भ की गई। इस अन्तगत रिजर्व बैंक उत बिना की पुनःटौती करवा। निम्न महत्त्व हो गया था जो सन्वारी विभागा का मात का वृत्ति करवा से उ पत हात थे। 1976 में रिजर्व बैंक ने अपनी माग सञ्चत नीति (Credit Squeeze Policy) का अन्तगत अनुसूचित बैंकों को मूत पत बट्टा राटा (Basic Re-discount Quota) तय कर दिया था। सन् 1978 में रिजर्व बैंक ने नवीन रिक शागा सञ्चत नीति (New Branch Licensing Policy) की घोषणा की जिसमें मात बाता पर मात दिया गया था।

- (i) उत मात में बैंक को शागाण जहाँ जहाँ पहल रिक नता था।
- (ii) सञ्चत वगैरे का अधिख बैंक माग प्रदात की जात।
- (iii) मात की विभाग योजनाओं में बैंकों की भागीदारी बढ।

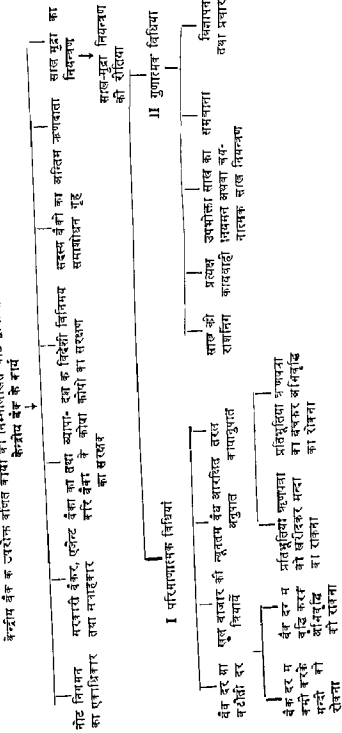
भा नीय अन्तगत मात प्रधान है उन्निग हुगरा विभाग तर तर सम्भार रही है तत ता वि र्ण ता श्वाक हाहा हाता। रिजर्व बैंक ने वृत्ति विभाग हेतु मात माग विभाग का विगत दिया। विगत मुख्य वाम वृत्ति विगत में सम्भारित समस्याओं का अध्ययन मात अनुसंधान करता है। वृत्ति विभाग हेतु रिजर्व बैंक ने दो बाता की स्थापना की थी—

(i) राष्ट्रीय वृत्ति माग (दीघकालीन क्रियाओं) कोष [National Agricultural Credit (Long Term) Operation Fund] जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1956 में की गयी।

(ii) राष्ट्रीय वृत्ति माग (स्थानीयकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] जिसकी स्थापना 30 जून 1956 को की गई। वृत्ति माग (दीघकालीन क्रियाओं) कोष की स्थापना का प्रयुग उद्देश्य राज्य सरकारों की विभिन्न उद्देश्या के लिए श्रृण प्रदात करना था जैसे—(अ) महसारी बैंक एवं प्राग्भिन वृत्ति माग समितियाँ की शबर पूंजी में हिस्सा पता (ब) वृत्ति उद्देश्या के निम्न राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन श्रृण प्रदात करना (स) अ श्रीय मूमि बन्ना बैंकों के श्रृण पत्रा को सरादना तथा उत दीघकालीन श्रृण प्रदात करता। इसी प्रकार राष्ट्रीय वृत्ति माग (स्थानीयकरण) कोष की स्थापना का उद्देश्य राज्य महसारी बैंकों को मध्यकालीन प्रय विभिन्न उद्देश्या के लिए देता था जैसे (अ) मूत बाढ आदि प्रावृत्तिक सिद्धांतों के समय विगत। ब दीघकालीन श्रृणा को मध्यकालीन श्रृणा में परिवर्तित करना (ब) वृत्ति माग हेतु बिन घोषण करना।

उपर्युक्त बाता कोषों को 12 जुलाई 1982 को नव-स्थापित वृत्ति माग प्रामीण विभाग के राष्ट्रीय बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) में मिला दिया गया है। इस अन्तगत 1963 में स्थापित वृत्ति पुनःरित एव विगत निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation) का भी NABARD में मिला दिया गया है। NABARD ने वृत्ति पुनःरित एव विगत निगम के मात माग प्राप्त कर दिया है। इतना ही नहीं राजकीय महसारी बैंकों तथा क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों (State Co-operative Banks and Regional Rural Banks) में सम्भारित मात माग NABARD को मात दिए गए हैं। वृत्ति माग के क्षेत्र में NABARD राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था के रूप में सामने आई है।

केन्द्रीय बैंक के उपरोक्त वर्णित कार्यों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है—



औद्योगिक वित्त व विकास हेतु रिजर्व बैंक ने पृथक् रूप में औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य दीपकान्तर औद्योगिक वित्त व्यवस्था में सहायता देना है। इस अतिरिक्त हमने विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगम (State Financial Corporations) की अणपूर्वी में भी भाग लिया है। रिजर्व बैंक इन निगमों का अल्प-कालीन, मध्यकालीन तथा दीपकान्तर ऋण प्रदान करता है। इनके अलावा औद्योगिक साग एव निवेश निगम तथा पुनर्वित्त निगम (Industrial Credit and Investment Corporation and Refinance Corporation) की स्थापना की गई थी। मन् 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India IDBI) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास में सहायता देना है। इस प्रकार भारत में रिजर्व बैंक आरू इण्डिया कन्द्रीय बैंक व रूप में गणतन्त्रापूर्वक कार्य कर रहा है। देश में मुद्रा बाजार एव पूर्वी राजाग र पर्याप्त विकास र अभाव में रिजर्व बैंक का आशान्तर गणतन्त्रा नहीं मित पाई है। आन पाल समय में रिजर्व बैंक की निर्णायक एव अौर अधिक प्रभावी भूमिका होगी ऐसी आशा हमें करनी चाहिए। रिजर्व बैंक ट्राप तथा औद्योगिक विकास हेतु दिशा निर्देश राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों का देता रहता है।

### परीक्षा-प्रश्न

- 1 कन्द्रीय बैंक क्या है? कन्द्रीय बैंक व कार्यों का विवचन कीजिए।  
(What is a Central Bank? Discuss the functions of a Central Bank)
- 2 कन्द्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? कन्द्रीय बैंक व रूप में रिजर्व बैंक आरू इण्डिया व कार्य बताइए।  
(What do you mean by a Central Bank? Give functions of the Reserve Bank of India as a Central Bank)  
[संकेत—रिजर्व बैंक भारत का कन्द्रीय बैंक है तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों में जा यह कन्द्रीय बैंक र रूप में करता है, व्याख्या कीजिए। रिजर्व बैंक व कार्यों का अध्याय 19 में दें। इसमें पहले इसी अध्याय में अर्द्ध-निरुक्ति अर्थव्यवस्था में कन्द्रीय बैंक नामक शोधक का matter भी दें।]
- 3 “साग नियन्त्रण की दृष्टि से खुल बाजार की प्रियाएँ बैंक दर नीति का पूरक हैं।” विवचना कीजिए।  
(From the standpoint of credit control open market operations are complementary to bank rate policy” Discuss)  
[संकेत—सागप्रथम बताइए कि बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की प्रियाएँ, कन्द्रीय बैंक की परिमाणान्तर विधि व अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण विधियाँ हैं। दोनों की आवश्यकता साग नियन्त्रण व लिए हाती है। दोनों में अन्तर बताइए तथा अन्त में निष्पत्ति दीजिए कि दोनों एक दूसरे का पूरक हैं प्रति-स्पर्धी नहीं।]
- 4 कन्द्रीय बैंक की परिमाणान्तरक एव गुणात्मक विधियाँ में अन्तर कीजिए तथा उनका अनुनात्मक महत्त्व का बताइए।  
(Distinguish between quantitative and qualitative methods of credit control and examine their relative importance)

[सकेत—दोना विधियों की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए अन्त में बताइए कि साल नियन्त्रण के लिए कभी-कभी केन्द्रीय बैंक का दोनों प्रकार की विधियों को आंशिक रूप में प्रयोग करना पड सकता है।]

5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही तथा कौन गलत है

- (i) जब बैंक दर बढा दी जाती है तो साल सकुचन होता है।
- (ii) बैंक दर में कमी साल विस्तार हेतु की जाती है।
- (iii) खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक दर नीति से थोड होती है।
- (iv) खुल बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए मुद्रा बाजार विकसित एवं संगठित होना चाहिए।
- (v) कन्द्रीय बैंक आर्थिक अस्थिरता को नियन्त्रित करने में पूरा रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सका है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) सही है। (iii) सही है। (iv) सही है। (v) सही है।

बैंक का मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थित है। केन्द्रीय कार्यालय में बैंक के प्रधान सामाजिक वा कार्यालय सचिव वा कार्यालय वैधानिक विभाग कृषि साग विभाग बैंकिंग विकास विभाग विनिमय नियन्त्रण विभाग तथा अनुसन्धान शास्त्र व सस्या शास्त्र विभाग स्थित है।

दश में केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का सफलतापूर्वक करन में उद्देश्य से रिजर्व बैंक में दश व विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय प्रधान कार्यालय तथा शाखाएँ स्थापित की हैं। नई दिल्ली काबुल बम्बई तथा मद्रास में स्थानीय प्रधान कार्यालय तथा कापुर बगलौर पटना हदराबाद, नागपुर इत्यादि स्थानों पर बैंक में अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं। इसमें अतिरिक्त जयपुर जयपुर तथा अन्य स्थानों पर भी रिजर्व बैंक में सायजनिक ऋण कार्यालय स्थित है। जिन स्थानों में रिजर्व बैंक का शाखा नहीं है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रिजर्व बैंक के कार्यों का सम्पादन किया जाता है। बैंक का एक कार्यालय लंदन में भी है जिसका कार्य अभिकर्ता व कार्यों का करन में अतिरिक्त भारत के उच्च आयुक्त (High Commissioner for India) का हिसाब रचना भी है।

### रिजर्व बैंक के विभाग

#### (Departments of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक आप इण्डिया के वर्तमान समय में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करन में लिए 20 विभाग हैं जो निम्नलिखित हैं —

(1) छपन वा निगमन विभाग (Issue Department)—रिजर्व बैंक का यह प्रमुख विभाग है जिसका मुख्य कार्य नाटा का निगमन करना होता है। नाट छापन का कार्य नागिव में स्थिति प्रग में होता है। यह नाटा का दश व विभिन्न सरकारी गजाना में उनकी माँग व अनुसार भजता है। निगमन विभाग की शाखाएँ बम्बई बनारस कागपुर वानपुर बगलौर हैदराबाद पटना तथा नई दिल्ली में स्थित हैं।

(2) बैंकिंग विभाग (Banking Department)—इस विभाग की स्थापना 1 जुलाई 1950 को हुई थी। इस विभाग का प्रमुख कार्य अनुसूचित बैंकों का पुनर्जमा पूँजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा करवाना होता है। यह विभाग अनुसूचित बैंकों के लिए समझौता गृह (Clearing House) का भी कार्य करता है। इसमें अनावा सरकार के लिए ऋण व्यवस्था तथा अन्य प्रकार के उन दश का कार्य भी यह विभाग करता है।

(3) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—यह विभाग कृषि साय तथा कृषि सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए कार्य करता है।

(4) बैंकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development)—दश में बैंकिंग सुविधाओं व विवास का कार्य इसी विभाग का सौंपा गया है। ग्रामीण बचत का प्रोत्साहित करन का दायित्व भी इस विभाग का है।

(5) बैंकिंग संचालन का विभाग (Department of Banking Operations)—इस विभाग का मुख्य कार्य अनुसूचित बैंकों का निरोक्षण एवं परामर्श देना है। नये बैंकों का स्थापन के लिए यह विभाग सहायता देता है तथा पुराने बैंकों की नई शाखाओं का स्थापन की अनुमति भी इसी विभाग में दी जाती है। अनुसूचित बैंक अपनी पूँजी में वृद्धि इस विभाग का पूरा अनुमति के बिना कर सकते हैं।

(6) विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)—विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों की समस्त दल रख इस विभाग के गुणुद होती है। भारत सरकार ने 1947 में विनिमय नियन्त्रण एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का

विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कानून एवं मांग निर्देशन के लिए व्यापक अधिकार प्रदान किए थे। विदेशी विनिमय एवं विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसकी महत्ता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी विभाग की स्थापना की है जिसका कार्य विनिमय नियन्त्रण के बारे में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना एवं सरकार की ओर से विदेशी विनिमय का दाय विनियम करना होता है।

(7) औद्योगिक वित्त विभाग (Industrial Finance Department)—इस विभाग का मुख्य कार्य औद्योगिक वित्त सम्बन्धी मामलों में राज्य वित्त विभागों को परामर्श देना तथा छोटे पैमाने और मध्यम श्रेणी के उद्योगों का वित्तीय सहायता देना होता है।

(8) कानून विभाग (Legal Department)—इस विभाग में कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो रिजर्व बैंक को विभिन्न क्षत्रों पर कानूनी सहायता देते हैं। इस विभाग द्वारा समय समय आदेशों एवं विज्ञप्तियों को जारी किया जाता है और उनमें कानूनी पहलू पर भी विचार किया जाता है।

(9) गैर बैंकिंग कम्पनीज विभाग (Non Banking Companies Department) इस विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में हुई और इसका मुख्य कार्यालय कटकता में स्थित है। जैसा कि इससे नाम से ही विदित है यह विभाग गैर बैंकिंग कम्पनीज एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए परामर्शदाता एवं उनके कार्यों पर निगरानी रखता है।

(10) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Research and Statistics) इस विभाग का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित आंकड़ों का संकलन कर उन्हें प्रकाशित करना होता है। रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रकाशकों में माध्यम से यह विभाग रिजर्व बैंक की मौद्रिक वित्तीय एवं उत्पादन सम्बन्धी नीतियों का प्रचार करना होता है। इससे सरकार को अपनी आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों में निर्माण में काफी सहायता मिलती है।

### रिजर्व बैंक के कार्य

#### (Functions of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य सरकार का आर्थिक नीति में अनुसार भारतीय मुद्रा प्रणाली का इस प्रकार नियमन करना है कि आर्थिक स्थिरता के साथ देश का अर्थव्यवस्था का मनुवित्त आर्थिक विकास सम्भव हो सके। संक्षेप में बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं —

#### (1) कागजी मुद्रा का निर्यमन (Issue of Paper Currency)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को देश में नोट प्रचलन का पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। नोट प्रचलन कार्य बैंक का नोट प्रचलन विभाग करता है पहले स्वर्ण तथा विदेशी ऋणपत्रों के आरक्षणों के आधार पर नोटों का प्रचलन करता था।

आरम्भ में अधिनियम के अनुसार नोटों का प्रचलन अनुपाती आरक्षित प्रणाली (Proportional Reserve System) के अनुसार किया जाता था। अधिनियम के अनुसार कुल नोट प्रचलन राशि का 40% स्वर्ण धातु स्वर्ण सिक्का तथा विदेशी ऋणपत्रों के रूप में तथा शेष 60% भारत सरकार के रुपया ऋणपत्रों, सरकारों के रूप में तथा रुपयों के रूप में रक्षित कोष में रखना आवश्यक था। नोट प्रचलन की अनुपाती आरक्षित प्रणाली देश में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय तक विद्यमान रही।

सन् 1957 में योजना को सफल बनाने के कारण अनुपाती आरक्षित प्रणाली को विद्यमान रखना कठिन हो गया। अनुपाती आरक्षित प्रणाली के अन्तर्गत अधिक मुद्रा का

प्रचालन जो याजना की पूर्ति के लिए आवश्यक था आरक्षण म स्वण अथवा विदेशी ऋण-पत्रा को बढाय बिना सम्भव नही था । वास्तव म विदेशी आयाता म वृद्धि होने क कारण रिजर्व बैंक क विदेशी विनियम आरक्षण म कमी होती जा रहा थी । अत अक्टूबर 1956 म रिजर्व बैंक आफ इण्डिया म पर्याप्त सशोधन करन के उपरान्त अनुपाती आरक्षित प्रणाली का परिष्कार करके न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपना लिया गया । जिसके अनुसार रक्षित बाप म 115 करोड रु० की राशि का स्वण तथा 400 करोड रुपय की विदेशी प्रतिभूतिया की मात्रा न्यूनतम आरक्षण निर्धारित की गयी । परन्तु दुर्भाग्यवश विदेशी ऋणपत्रा की मात्रा कुछ हा समय पश्चात् 400 करोड रुपय की न्यूनतम राशि स भी कम हो गयी । एसी चिन्ताजनक स्थिति म रिजर्व बैंक अधिनियम म पुन सशोधन करना आवश्यक हो गया अत कुछ समय पश्चात् रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (द्वितीय संशोधन) अधिनियम बना जिसके अनुसार रिजर्व बैंक के प्रचालन विभाग आरक्षित बापा म स्वण का राशि जोर विदेशी ऋणपत्रा की न्यूनतम राशि 400 करोड स घटाकर 200 करोड कर दी गया जिसम 115 करोड रुपय का सोना अथवा गोन क सिक्क तथा 85 करोड रुपय का विदेशी प्रतिभूतिया होना आवश्यक था ।

### चलन तिजोरियाँ (Currency Chests)

रिजर्व बैंक का चलन तिजोरिया स आशय उन तिजोरिया स है जा मुद्रा का पूर्ति हेतु हाती है और उनम नाट हात है । दश भर म ऐसा 3506 चलन तिजोरियाँ है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का शाखाए सभा स्थाना पर नही है इसलिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया उसकी गहायन बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रमुख शाखाया म इस प्रकार की तिजोरियाँ रहता ह इन चलन तिजोरिया क अन्तर्गत 487 स्थाना पर 34 तिजोरियाँ (Sub chests) रहती है जा मुद्रा डिपो भी वहनाती है । रिजर्व बैंक शाखाएँ जहाँ नहा है वहाँ स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक रिजर्व बैंक क प्रतिनिधि म रूप म कार्य करत है । जब कभी व्यापारिक बैंक का साख का आवश्यकता होती है ता शर्की पूर्ति क लिए व उस बैंक स सम्पर्क करके जिसके पास चलन तिजोरी है । रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि सम्बन्धित व्यापारिक बैंक म इस मासता की जमानत क रूप म अनुमादित प्रतिभूतियाँ तथा विनियम बिना की (Bills of exchange) रखवा लता है तथा चलन तिजोरा म स मुद्रा निवानकर व्यापारिक बैंक का द दता है ।

चलन तिजोरिया म स कितना धनराशि निरानी गइ है उतका त्साव चलन तिजोरी रखन वाद बैंक का रखना पडता है । जब बाड बैंक चलन तिजोरा म जा भा पैसा तथा उम रिजर्व बैंक क नाम निम्न दिया जाएगा और धाराशिक्ष बापता क समय भा एसी धनराशि रिजर्व बैंक का जमा क रूप म अर्पित कर दा जाएगा । कितना धनराशि इस चलन तिजोरी स निराना जाती है उम ही मुद्रा की पूर्ति म शामिल किया जाता है । जा भी धनराशि चलन तिजोरा म रहगी वह मुद्रा की पूर्ति नहा माना जाएगा । सम्प्रति प्रतिनिधि बैंक म चलन तिजोरा का हिसाब रखा है तथा इसका सूचना रिजर्व बैंक कायालय म सप्ताह म एक बार या फिर जैस भी निर्देश रिजर्व बैंक द उगा क अनुसार भजता रहता ह चलन तिजोरिया का हिसाब लगात समय तिजोरिया म जमा धनराशि रिजर्व बैंक क वैकिंग विभाग म जमा गमनी जाती है ।

चलन समय म भारत क रिजर्व बैंक द्वारा 2 5 10 20 50, 100 500 रुपय क नाट नियमित किय जाते है । जबकि उम 1 000 5 000 तथा 10 000 रुपय क नोट निवानन का अधिना निराना है । नू 1977 म अवल्य स्वा म स चलन की गमाप्ति क लिए अभियान चलाया गया था । उम समय घट समजा जान लगा कि चलन का अधिना राशि 1 000, 5,000 तथा 10,000 रुपय क नाटा म छिपाकर रखी

अतः रिजर्व बैंक व सामान साग नियन्त्रण की एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी। इस समस्या को हल करने के लिए 15 नवम्बर 1951 का बैंक ने बैंक दर में ½% (अर्थात् 3 प्रतिशत में बढ़ाकर 3½%) की वृद्धि की साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी घोषणा की कि वह इस तिथि से सरकारी प्रतिभूतियाँ की जमानत पर ऋण देगा परन्तु उन्हें गरीबदगा नहीं। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने सामान नियन्त्रण करने के उद्देश्य से बैंक दर में पहली बार वृद्धि की। इस वृद्धि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि मुद्रा बाजार में सामान मुद्रा महँगी हो गई तथा बैंक ने अपनी उधारदान में वृद्धि कर दी। इस अतिरिक्त बैंक ने व्यापारियों को निमन्त्रण पाय के लिए अग्रिम देने बन्द कर दिया।

16 मई 1957 का रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर 3½% से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया और बाद में 2 जनवरी 1963 का इस 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4½ प्रतिशत कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय प्रचलित मुद्रा स्फीति का नियन्त्रित एवं नियमित करना था। बढती हुई मुद्रा स्फीति का अधिक्त प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए 26 सितम्बर 1964 तथा 17 फरवरी 1965 को बैंक दर बढ़ाकर क्रमशः 5% और 6% कर दी। मई 2 माघ 1968 का रिजर्व बैंक ने बैंक दर घटाकर 6% से 5% कर दिया। 8 जनवरी 1971 को पुनः बढ़ाकर 5% से 6% कर दी गयी। 30 मई 1973 का बढ़ाकर 7% कर दी गई तत्पश्चात् 23 जुलाई 1974 का बैंक दर में पुनः वृद्धि कर 9% कर दी गयी। बैंक दर में अतः अपेक्षा से अधिक वृद्धि अथवा कमी को नहीं उभरता है हम तार्किक ढंग आसानी से समझ सकते हैं।

### भारत में बैंक दर

| परिवर्तन की तिथि | बैंक दर |
|------------------|---------|
| 15 नवम्बर 1951   | 3.5%    |
| 16 मई 1957       | 4.0%    |
| 2 जनवरी 1963     | 4.5%    |
| 26 सितम्बर 1964  | 5%      |
| 17 फरवरी 1965    | 6%      |
| 4 माघ 1968       | 5%      |
| 8 जनवरी 1971     | 6%      |
| 30 मई 1973       | 7%      |
| 23 जुलाई 1974    | 9%      |
| 11 जुलाई 1981    | 10%     |

27 फरवरी 1982 का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने घोषणा की कि अनुसूचित बैंक का ऋण जमा भन्तव्य पर 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत व्याज की छनराशि। माघ 1982 में दब गयी।

रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 23-7-74 का 9 प्रतिशत घातित की थी उसका बढा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने आशा की है कि वर्ष 1981-82 में अन्ततः व्यावसायिक क्षेत्र में मांग विभाग की वृद्धि 19 प्रतिशत रहगी जो देश के उत्पादन क्षेत्र के लिए उसकी सामान सम्बन्धी अर्थान्तरिक माँग का पूरा कर सकेगी। वर्ष 1981-82 में बैंक औसत मांग का 36% (Aggregate Bank Credit) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाएगा जबकि 1979 में इन क्षेत्रों को औसत बैंक मांग का 33% ही मिलता था। छोटी व नगरीय योजना के अन्तर्गत यह बढ़कर 40% करवा के निश्चित था। 1 माघ 1982 में बैंक ने अतिरिक्त वित्तीय बचत गता पर षोडी भी वृद्धि कर दी है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक ने यह वृद्धि 5% से 1.5% तक की है। यह वृद्धि दर नये बचत गता



एव पुराने बचत खाते की परिष्कृता पर लागू होगी। निम्न तालिका द्वारा निश्चित राशियों वचत खाते पर ब्याज की दरों का दिललाया जा सकता है —

| निश्चित बारीक बचत                    | 2 मार्च 1981 से लागू | 1 मार्च 1982 से लागू |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 15 दिन से 45 दिन तक                  | 2.5%                 | 3%                   |
| 46 दिन से 90 दिन तक                  | 3.0%                 | 4%                   |
| 91 दिन से 6 महीने तक                 | 4.0%                 | 5%                   |
| 6 महीने से अधिक तथा 9 माह से कम      | 4.5%                 | 6%                   |
| 9 महीने से अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम  | 5.5%                 | 7%                   |
| 1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम  | 7.5%                 | 8%                   |
| 2 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम | 8.5%                 | 9%                   |

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ—देश में साधन नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रिय बैंक खुले बाजार की क्रियाएँ भी अपनाते हैं। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है कि देश का केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों प्रथम श्रेणी के विलो एव प्रतिपा पत्रों का क्रय विव्य करता है। रिजर्व बैंक साल नियन्त्रण करने के लिए भारतीय मुद्रा बाजार में समय-समय पर सरकारी ऋणपत्रों को क्रय विव्य करता है। दूसरे छद्म से पूर्व रिजर्व बैंक की खून बाजार की क्रियाएँ केवल सीमित मात्रा में ही हुआ करती थी। उस समय इन क्रियाओं का उद्देश्य मुद्रा बाजार में होने वाली मौसमी कमी को दूर करना था। मुद्रा बाजार में भी खुले बाजार की क्रियाओं में विशेष वृद्धि नहीं हुई। मुद्रा के परभाव केन्द्रिय बैंक द्वारा देश में भाव्य मुद्रा का नियन्त्रण करने हेतु बड़े पैमाने पर खुले बाजार की क्रियाएँ अपनायी गयीं। अब भी मुद्रा बाजार की परिस्थिति को देखते हुए केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) समय-समय पर खुले बाजार की क्रियाएँ अपनाता है।

(iii) परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात (Variable Reserve Ratio)—आरम्भ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम के अनुसार सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाआ तथा भिपादी जमाआ का 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात के रूप में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास नकदी के रूप में जमा कराना पन्ता था। सन 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में सभी बैंकों पर अधिक नियन्त्रण करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन क्रिया गया।

इस संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को यह अधिकार दिया गया कि यह अनुसूचित बैंकों की माँग तथा भिपादी जमाआ सम्बंधी न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात में श्रमश 5% से 20% और 2% से 8% तक वृद्धि कर सकता है। एका अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम प्रतिशत के अन्दावा उच्च और भी नकद कोष जमा करने के लिए आन्ध दे सकता है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में 1962 में एक और संशोधन हुआ जिसके अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास न्यूनतम वैधानिक आरक्षित अनुपात में सभी प्रकार की जमाआ पर 3 प्रतिशत जमा कराना होगा परन्तु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का यह भी अधिकार दिया कि वह चाह तो इसे बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। वर्तमान समय में यह 15% है।

सर्व निम्नलिखित उद्देश्यों से उच्च कोषों में परिवर्तन करने की नीति का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने समय-समय पर अपनाया है। 29 जून 1973 को अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली न्यूनतम राशि का अनुपात 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया। तत्पश्चात् 8 सितम्बर 1973 को यह अनुपात 6% तथा 22 सितम्बर 1973 से यह प्रतिशत 7% कर दिया था। वर्ष 1982-83 के लिए यह अनुपात 8% था। वर्तमान समय में यह 10% है।

(iv) तरलता अनुपात अथवा वैधानिक तरलता अनुपात (Liquidity Ratio or Statutory Liquidity Ratio SLR) एक अन्तर्गत समस्त अनुसूचित बैंका को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित भाग तरल मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश के केंद्रीय बैंक की भूमिती मांग नियमन के लिए वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके सावधानी का नियंत्रण करता है। 28 नवम्बर 1978 का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया न अनुसूचित बैंका का यह आदेश दिया था कि वे अपने वैधानिक तरलता अनुपात का 33% से बढ़ाकर 34% कर दें। जिस व्यापारिक बैंका ने मान लिया। वर्ष 1989 में इसे बढ़ाकर 3% कर लिया गया है जो वर्तमान समय तक लागू है। मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इसका प्रयोग करता है।

(v) चयनात्मक साधन नियंत्रण (Selective Credit Control) — चयनात्मक साधन नियंत्रण का अर्थप्रार्थ उक्त नियंत्रण से है जिसमें अन्तर्गत केंद्रीय बैंक कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ही न केवल बैंका का साधन प्रदान करता है। वास्तव में एक नियोजित एवं विवक्षित साधन अथवा व्यवस्था में चयनात्मक साधन नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है क्योंकि नियोजित में कुछ उद्देश्यों का प्राथमिकता दी जाती है।

रिजर्व बैंक भी कुछ वर्षों में साधन नियंत्रण के लिए चयनात्मक साधन नियंत्रण का प्रयोग कर रहा है। उदाहरणार्थ मई 1970 में भारत में मृदा बाजार का अत्यधिक प्राप्ति इन मित्तों जिनमें उच्च व कामल स्तर में उत्पादन वृद्धि हुई। इन दिनों का समय के लिए रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंका का यह आदेश दिया था कि वह मृदा बाजार के लिए साधन प्रदान न करें। इस प्रकार भारतीय व्यापारिकों में साधन पदाथों के संग्रह करने का प्रवृत्ति का रोकेने के लिए अनुसूचित बैंका का यह आदेश दे रहा है कि वे साधन पदाथों का आह पर व्यापारिकों का काम से काम मात्रा में ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार समय समय पर अन्य वस्तुओं के संग्रह का रोकेने के लिए अनुसूचित बैंका का उच्च आह पर कम ऋण देने के आदेश लिये गए। 7 अप्रैल 1982 रिजर्व बैंक ने मण्डला उद्योग में अधिक स्टाक जमा हान तथा कम रिक्वायर्ड हान के कारण घराहृ पर ऋण देने के मूल्यतर (Margin) में 10% छूट देने की घोषणा की थी जिसमें इस उद्योग में मंदी का वातावरण न पनप सके।

इसके अलावा भी रिजर्व बैंक चयनात्मक साधन नियंत्रण विधि के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में ऋण देने पर प्रतिबंध लगा तथा अनुसूचित बैंका को यह साधन उमन समय समय पर दिया है कि अल्पकालीन अथवा कोई भी बैंक ऋण देता है तो उगर्धी पूरा अनुमति उस रिजर्व बैंक से लेना होगा।

(vi) नैतिक प्रभाव की नीति — उपरोक्त नीतियों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अपने मन्स्य बैंका का समय वृत्तों अपना निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर मन्स्य बैंका के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता है और समय-समय पर मन्स्य बैंका का परिपत्र भेजकर भी उन्हें साधन का मात्रा का निर्धारण करने का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए मिनम्बर 1949 में भारतीय रुपय का अवन्यूनता के कारण रिजर्व बैंक के यत्न में तथा के सभी प्रमुख बैंका के प्रतिनिधियों का मासिक बुगार्ट थी और उनमें अनुरोध किया था कि वे मृदा के कार्यों के लिए व्यापारिकों को साधन प्रदान न करें।

(3) सरकारी बैंकर प्रतिनिधि एवं सहायकार (Government Banker Agent and Adviser)

देश में मुद्रा प्रचरण का एकाधिकार प्राप्त होने तथा साधन मुद्रा का नियमन करने की शक्तियाँ प्राप्त हान के अतिरिक्त रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश में केंद्रीय तथा राज्य

सरकारों के प्रति बैंक का बाय भी करती है। यह सरकार वा आर्थिक मौद्रिक सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देती है। सरकारी बैंक होन क नशते रिजर्व बैंक का बाय सरकारी ऋणपत्र बाजार में सरकार की उधार तथा भुगतान नीतियों को सफल बनाना होता है। यह केन्द्रीय व राज्य सरकारों की ओर से बर्जों का चालू करती है तथा उनको बर्जों की राशि तथा बर्जों को चालू करने के समय सम्बन्धी परामर्श भी देती है। यह सांख्यिक ऋण का प्रवर्धन भी करती है। रिजर्व बैंक का बायता पढने पर केन्द्रीय सरकार की ओर से टण्डर द्वारा साप्ताहिक नीलाम में राजकोष पत्रों का भी बेचती है। रिजर्व बैंक केन्द्रीय व राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण भी देती है जिनका भुगतान ऋण देने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाता है। सरकार वहुधा नए बर्जों को चालू करने के लिए निवेश ऋण साख औद्योगिक वित्त तथा नियोजन एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी वित्तीय समस्याओं आदि विषयों पर रिजर्व बैंक से परामर्श प्राप्त करती है।

#### (4) विदेशी विनिमय की व्यवस्था (Regulation of Foreign Exchange)

रिजर्व बैंक मुद्रा के विनिमय मूल्य को स्थिर रखता है। स्पष्ट व विनिमय मूल्य को निर्धारित दर पर स्थिर बनाए रखना व उद्देश्य से रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी विनिमय दर का प्रयोजन करती है। रिजर्व बैंक भारत के विदेशी विनिमय एवं मुद्राओं तथा स्वण एवं अन्य वहुमूल्य धातुओं का संरक्षण भी होता है।

#### (5) बैंकों को बैंक (Banker's Bank)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश में अन्य बैंकों के प्रति बैंक का बाय करती है। बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के प्रति वे सब बाय करती है जो कोई बैंक अपने आह्वानों के प्रति करती है। अन्य शब्दों में यह बैंक से जमा स्वीकार करती है उनको वाज देती है उनका प्रति शोधन गृह का बाय करती है तथा अन्तिम ऋणदाता के रूप में वाजनाई के समय उनका वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह बैंकों को कठिनाई के समय परामर्श भी देती है।

#### (6) अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के बाद उसने अन्य अनुसूचित बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता की भूमिका निभायी है। जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग जमाओं तथा मियादा जमाओं (Demand Liabilities and Time Liabilities) का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना होता है अर्थात् न्यूनतम आरक्षित अनुपात (VRR) तथा कानूनी तरल कोषानुपात (SLR) जो कि वर्तमान समय में 15% तथा 38% है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों के अल्पकालीन ऋणदाता रहता है और इन्हीं में से वह आवश्यकता पढने पर अनुसूचित बैंकों को ऋण प्रदान करता रहता है। सेंट्रल बैंकिंग परिस्थितियों में अनुसूचित बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ही अन्तिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है।

#### (3) समाशोधन गृह कार्य (Clearing House Functions)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया देश का केन्द्रीय बैंक है इसलिए यह विभिन्न बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है वहाँ स्टेट बैंक आफ इण्डिया रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में समाशोधन गृह को सुविधाएँ प्रदान करता है।

औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इण्डिया (Industrial Development Bank of India) जिसे भी स्थापना 1 जुलाई 1964 का है भी पूर्णतया रिजर्व बैंक का सहायक है। इस बैंक का उद्देश्य राजस्व तथा निष्पत्तियों की औद्योगिक दबाइयाँ का वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दाघा-रिजर्व बैंक) काप (National Industrial Credit Longterm Operation Fund) 1 जुलाई 1964 का स्थापित किया था जो काप का उपयोग रिजर्व बैंक औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किया गया था और रिजर्व बैंक का तरादा तथा औद्योगिक विकास बैंक का अन्य वित्तीय संस्थाओं को अज्ञात तथा रिजर्व बैंक का सुरीदन का विधि प्रणाली का नियंत्रण कर सकती है।

उद्योगों का सहायता प्रदान करने के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 1 सरकार का आर्थिक मन्त्रालय के माध्यम से योजना आयोग के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक आधुनिक विनिर्देशित बैंक के रूप में कार्य करता है। यह योजना 1960 में शुरू की गयी थी। जिसे भी साख गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) कहा जाता है। यह योजना एपेक्स गैरकारी बैंकों (Apex Co-operative Banks) द्वारा उद्योगों को दिया गया प्रसारण अत्रिमा पर लागू होती है। यह अतिरिक्त 1964 का आरम्भ में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया का स्थापन करने का रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। उद्योगों का विधि एवं उद्योगों के विभाग के विधि 100 करोड़ रुपये की पूंजी से उद्योग विकास बैंक का स्थापना हुई जिसका IDBI से भी सहायता मिली।

### रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त

(Reserve Bank and Agricultural Finance)

देश में कृषि विकास के लिये सभा सम्भव सहायता देने के उद्देश्य से 1935 में आरम्भ से ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में एक नयी माला विभाग का स्थापित किया गया। कृषि का वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों का कृषि इण्डिया का जमानत पर 15 महान के लिए बैंक दर से भी कम व्याज दर पर कृषि देता है। मौसमी कृषि विभागात् राज विनीय सहायता प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को बैंक दर से 2% नारा दिया दर पर 1967-68 में 314.16 करोड़ रुपये का राजि का स्वीकृति प्रदान का था।

सक्षम में रिजर्व बैंक कृषि वित्त सम्बन्धी निम्न कार्य करता है—

- (1) यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों का स्वीकृत प्रतिभूतियाँ एवं ऋणपत्रों के आधार पर अज्ञात माला प्रदान करता है।
- (2) यह बैंक नारसैम प्राप्त माला में रबी गेड कृषि उपज के आधार पर ऋण देता है।
- (3) कृषि उपज के आधार पर कृषि का ऋण पर व्याज में 2% का छूट दी जाता है।
- (4) भूमि विकास योजना के ऋण का उद्देश्य के लिये बैंक की पूंजी को बढ़ाने में योगदान देता है।
- (5) बैंक राज्य सहकारी बैंकों का प्रतिफल देता है कि यह सहकारी माला सम्बन्धी अज्ञात माला सक्षम है।
- (6) बैंक राज्य सहकारी बैंकों के कृषि विभाग का पुनर्बन्धन करता है तथा उनके आधार पर ऋण माला प्रदान करता है। परन्तु इन प्रकार के वित्त 15 माह का अवधि में परिपक्व हो जाना चाहिये।

फरवरी 1956 में कृषि को और अधिक सहायता देने के नये नये कोषों की स्थापना की गई थी—

- (1) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit Long-Term Fund)
- (2) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) कोष (National Agricultural Credit Stabilisation Fund)

इन कोषों की सहायता से राज्य सहकारी बैंकों 7 सालों में काफी वृद्धि हुई है। 30 जून 1977 तक राष्ट्रीय कृषि साख कोष में कुल धनराशि 334 करोड़ रुपये थी। सन् 1975-76 में रासायनिक खाद की खरीद एवं उसकी वितरण के लिए भी रिजर्व बैंक ने 28 20 करोड़ रुपये स्वीकार किये थे।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी रिजर्व बैंक ने कृषि विकासार्थ मध्यमकालीन ऋण प्रदान किये हैं, जिनकी राशि 1977-78 में 81 32 करोड़ रुपये थी। विगत कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक ने भूमि विकास बैंकों को भी मध्यमकालीन ऋण प्रदान किये हैं।

सन् 1963 में रिजर्व बैंक ने एक कृषि पुनर्वित्त निगम स्थापित किया था जिसे अब पुनर्वित्त एवं विकास निगम कहा जाता है। इस निगम का उद्देश्य कृषि तथा सिंचाई, मुर्गीपालन एवं मछली पालन आदि है। इस निगम को केन्द्रीय बैंक ने सन् 1974-75 में 40 करोड़ रुपये के एवं 1979-80 में 85 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये हैं।

12 जुलाई, 1982 को कृषि एवं ग्रामीण विकास का दायित्व कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (NABARD) को मिल गया है। अब केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण साख प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। अब दोनों कोषों, राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन काय) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) कोष का विलय NABARD में हो चुका है। अब कृषि एवं ग्रामीण विकास की साख हेतु रिजर्व बैंक के स्थान पर NABARD अपना दायित्व निभा रहा है। नाबाड (NABARD) की स्थापना से ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए एक शीघ्र संस्था की स्थापना हुई है। अब नाबाड ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए बहुत से ऋणों के पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। भारत जैरे कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बाहुल्य अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए इस प्रकार की शीघ्र संस्था की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी।

### रिजर्व बैंक की सफलताएँ

#### (Achievements of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की सफलता का मूल्यांकन निम्न तथ्यों से लगाया जा सकता है —

(1) सरकार के बैंकर के रूप में— रिजर्व बैंक न सरकारी बैंकर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सरकारी आय व्यय का सम्पूर्ण लेने-दने का व्योरा यह रखता है। सरकार के लिए पर्याप्त आय जुटाने की दृष्टि से यह उसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। समय समय पर केन्द्रीय सरकार के लिए ऋण लेने एवं उनके भुगतान तथा व्याज आदि की अदाएँ की R B I हिसाब रखता है।

(2) सरकार का परामर्शदाता— रिजर्व बैंक व पाम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का दल होता है जो अपनी विशेषज्ञ सेवाएँ समय-समय पर प्रदान करते हैं। केन्द्र सरकार के आदेश पर यह विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, IBRD, तथा अन्य देशों की सरकारों का तथा दश में जीवन बीमा निगम, यूनिट

ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, टृपि पूनवित निगम औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक तथा क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंको आदि न काय कर रहे ह ।

(3) औद्योगिक वित्त दश १ औद्योगिक विकास का सुचारु रूप तथा सतुलित रूपन को दृष्टि से उद्योगों के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्त निगमों को सहायता प्रदान की है ।

(4) कृषि वित्त रिजर्व बैंक की स्थापना न तन्त्र वाद ही इसने कृषि व विभाग के लिए कृषि साध विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की । साथ ही दश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की स्थापना द्वारा भी कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए काफी प्रयत्न किए हैं ।

(5) समाशोधन गृहों की व्यवस्था—रिजर्व बैंक न विभिन्न बैंक द्वारा आपसी लेन-देन के निपटारे के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना की है । वर्तमान समय में लगभग 100 अधिक समाशोधन गृह स्थापित किए गए हैं । जहाँ R B I के कार्यालय नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सुविधा प्रदान करता है । इस गृह में एक निश्चित तिथि पर सभी बैंकों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं और आपसी लेन-देन को नकद न करके चेकों के माध्यम में देनदारों एवं लनदारों निपटाते हैं ।

(6) अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आँकड़ों का प्रकाशन—रिजर्व बैंक अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मुद्रा एवं साख बैंकिंग सहकारिता विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन कर उन्हें प्रकाशित करता है । इससे अर्थव्यवस्था की आधुनिक एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलती रहती है तथा सरकार का इन क्षेत्रों में अपना नीतियाँ न निर्माण में इन आँकड़ों से काफी सहायता मिलती है ।

(7) विदेशी विनिमय के सरक्षक का कार्य—रिजर्व बैंक न विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया । सम्पूर्ण विदेशी विनिमय का प्रयत्न तथा विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी सभी कार्य इसी का दायर्य में सम्पन्न होते हैं । देश की बहुमूल्य धातुओं के सरक्षक के अलावा यह विदेशी विनिमय बाजार का सरक्षक होता है । यह विनिमय दरों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य पर भी नजर रखता है । यह सरकार का समय समय पर विदेशी विनिमय बाजार में स्थिति की जानकारी भी देता है । आयात एवं निर्यात सम्बन्धी कार्यों के लिए भी रिजर्व बैंक में ताल्लूम प्राप्त करना जरूरी है ।

(8) देश के बैंकिंग विकास में सहायता—रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार इनके विभिन्न बैंकों के कार्यों के विस्तार तथा बैंकिंग प्रियाओं द्वारा बैंकिंग विकास किया है ।

उपरोक्त कार्यों के अलावा इनके स्वतन्त्रता सम्बन्धी सुविधाएँ साख नियन्त्रण तथा बैंकिंग विकास आदि के लिए भी रिजर्व बैंक का योगदान महत्वपूर्ण है । देश के शीप बैंक के नाते भी रिजर्व बैंक का सवाएँ सहायता रहा है ।

### रिजर्व बैंक की असफलताएँ (Failures of the Reserve Bank)

इनकी असफलताओं का निम्नलिखित तथ्यों में आना जा सकता है —

(1) मुद्रा बाजार में समायोजन का अभाव—भारतीय मुद्रा बाजार में विभिन्न अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत एवं अंतर्गत मुद्रा बाजारों के बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है । अधिकांश मुद्रा बाजार का क्षेत्र असंगठित है और उस पर रिजर्व बैंक का कोई प्रभाव नहीं

1. अधिनियम के लिए रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त शीपक दिये ।

रहता। रिजर्व बैंक की अपनी नीतियों के विर्यान्वयन में इस कारण भी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है।

(2) साख नियन्त्रण में कठिनाई—रिजर्व बैंक को साख मुद्रा व नियन्त्रण में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कि रिजर्व बैंक ने समय-समय पर विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न गतियों का अपनाया है। इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक का असफलता की जर्बा हमने इस अध्याय में का है।

(3) व्याज की दरों में असमानताएँ—रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा बाजार व ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण एवं सम्बन्ध व अभाव में यहाँ व मुद्रा बाजार में व्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है। जब तक कि रिजर्व बैंक का दशो दक्ष एवं असंगठित मुद्रा बाजार पर अपना प्रभाव नहीं होता तब तक व्याज की दरों की यह असमानताएँ बना रहगी।

(4) बैंकिंग सुविधाओं का असतुलित विकास—रिजर्व बैंक की स्थापना व 47 वर्षों के बाद भी देश में बैंकिंग सुविधाओं का सन्तुलित विकास नहीं हो पाया है। स्टेट बैंक तथा 20 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में इनकी शाखाओं का विस्तार काफी हुआ है परन्तु बहुत कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सुविधाएँ जनता व बहुसंख्यक वर्ग तक नहीं पहुँच सकी हैं। इस ओर अभी प्रयास करना शेष है।

(5) मुद्रा स्फीति को रोकने में असमर्थ—रिजर्व बैंक अपना नीतियों का माध्यम से मुद्रा स्फीति जैसा घातक बुराई पर अकुशल प्रणतया नहीं लाया गया है। आज्ञा है कि रिजर्व बैंक अपनी साख एवं मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्थाओं द्वारा मुद्रा-स्फीति जैसी बुराई पर काबू पा लेगा। अग्रे, 1982 तक सरकार का दावा है जसने मुद्रा-स्फीति की दर शून्य तक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करली थी परन्तु यदि यह सही भी मान लिया जाय तो कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति जो अब भी बनी हुई है उस क्या कहा जायेगा। रुपये का आन्तरिक मूल्य बराबर गिरता जा रहा है। कीमत वृद्धि पर अकुशल यह नहीं लगा पाया है।

(6) बिल बाजार के विकास में असफलता—अपनी स्थापना के 37 वर्षों के बाद भी रिजर्व बैंक एक अच्छे बिल बाजार के विकास में सफल नहीं हो पाया है। बिल बाजार योजना व अन्तर्गत और अधिख उदारतापूर्ण व्यवहार अपना कर रिजर्व बैंक व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी ला सकता है।

### परीक्षा-प्रश्न

1. रिजर्व बैंक के कार्यों पर प्रवाग डालिए।

(Discuss the functions of the Reserve Bank)

अथवा

रिजर्व बैंक के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण काजिए।

(Examine critically the functions of the Reserve Bank)

अथवा

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्यशालता का मूल्यांकन काजिए।

(Evaluate the working of the Reserve Bank of India)

2. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की साख नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

(Write a short essay on Reserve Bank of India's credit control policy)

## अथवा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए मुद्रा एवं साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों को बताइए।

(Describe various methods of monetary and credit control adopted by the Reserve Bank of India)

[संकेत—साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों को बताइए। भारत में प्रयुक्त विभिन्न विधियों का वर्णन करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की नियंत्रण करने के विभिन्न तरीकों का मूल्यांकन करते हुए इसकी प्रभावशालीता का भी चर्चा कीजिए।]

- 3 रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। यह कहाँ तक प्रभावशाली रही है ?

(Explain the chief characteristics of credit control policy of the Reserve Bank. How far they have been effected ?)

[संकेत—रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। उसका मूल्यांकन करते हुए साख नियंत्रण की उचित नीति अधिक प्रभावशाली नहीं है। इस ओर उसकी प्रभावशालीता का चर्चा कीजिए।]

- 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत बताइए।

- (i) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भारत का केंद्रीय बैंक है।
- (ii) रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था।
- (iii) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को साख नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति मिली है।
- (iv) रिजर्व बैंक साख नियंत्रण हेतु परिमाणों को तथा गुणात्मक नियंत्रणों का उपयोग करता है।
- (v) रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार को समायोजित करने पर भी नियंत्रण करता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

- (i) सही है। (ii) सही है। (iii) गलत है। (iv) सही है। (v) गलत है।



A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages

—J M Keynes

Business cycle is nothing more than rhythmic fluctuations in the overall level of employment income and output

—D Dillard

the business cycle is peculiarly a manifestation of the industrial segment of the economy from which prosperity or depression is redistributed to other groups in the highly interrelated modern society

—I H Hunt

अध्याय 20

व्यापार चक्र

(TRADE CYCLE)

व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की गतिशीलता जिनका सम्बन्ध रोजगार उत्पादन आय कीमतों तथा सभ्यता होता है से सम्बन्धित होता है। परन्तु प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं की गतिशीलता को हम व्यापार चक्र (Trade or Business Cycle) की संज्ञा नहीं दे सकते। हम केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के उतार-चढ़ाव को व्यापार चक्र की संज्ञा देते हैं जिनको हम एक निश्चित समय अंतराल के बाद महसूस करते हैं। यदि हम संसार की आर्थिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो हम जात होंगे कि दुनियाँ का विभिन्न अर्थव्यवस्था विशेषरूप से युजी वादी अर्थव्यवस्थाएँ दमन विधि और अल्पवधि तथा आकार का दृष्टि से कम या अधिक उच्चावचन के रूप में जीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य घटनाएँ साबित हुई हैं।

आर्थिक क्रियाओं में उच्चावचन अर्थव्यवस्था में विभिन्न रूप में हो सकते हैं। सामान्यतया यह दीर्घकाल अथवा अपकाल में होता है। इसी प्रकार से कुछ उच्चावचन का आकार तथा अवधि अधिक तथा कुछ का आकार कम होता है कुछ उच्चावचनों की अवधि केवल कुछ महीनों की होती है और इनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी सीमित तथा हल्का होता है जबकि कुछ-कुछ उच्चावचन कई वर्षों की गणनाविधि वाले होते हैं जो अर्थव्यवस्था पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दुनियाँ के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इन उच्चावचनों का अध्ययन करके इनकी प्रकृति प्रभाव तथा विशेषताओं का ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

व्यापार चक्र की परिभाषा (Definition of Business Cycle)

अमरीका के अर्थशास्त्री प्रो० डब्ल्यू० सी० मंचेल (Prof W C Mitchell) के शब्दों में व्यापार चक्र को अग्र प्रकार से परिभाषित किया गया है

' - व्यापार चक्र उच्चावचना का यह रूप हाते है जो उन राट्टा की जो अपना बाय प्रमूस रूप स व्यवसायिक प्रतिष्ठाना स गभठित करत ह की गम्पूण आर्थिक प्रियाआ स पाए जात है। व्यापार चक्र स सामान्य विस्तार की स्थिति स लगभग एक हा गमय स बहुत सी आर्थिक प्रियाओ स विस्तार हाता है। एकाक बाद सामान्य सुस्ती गिरावट मदी विमुक्ति की अवस्थाएँ पाइ जाती ह जो अउल व्यापार चक्र की विस्तार अवस्था स मिन जाती है। पणिवतना का यह प्रम आरतीय होता है।<sup>1</sup>

प्रा० मिचिन की व्यापार चक्र का उन परिभाषा द्वारा उन्हांस यह बतान का त्याग किया है कि व उच्चावचन जिन स भाग स गम्पूण अर्थव्यवस्था स हाता है। व्यापार चक्र कहनात ह। उन स अनुसार व्यापार चक्र उन चक्र उच्चावचना स अलग होत है जो अर्थव्यवस्था क किमी भाग स पाए जात ह। वैन यहाँ यह कहना उचित है कि हम उन उच्च उच्चावचना तथा एस चर्त्रीय उच्चावचना स भेद करना चाहिए जो गम्पूण अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था क किमी भाग स विद्यमान हाते है। ऐसा करना समाज भा आवश्यक है कयाकि गम्पूण अर्थव्यवस्था का समस्यार्थ अर्थव्यवस्था क छोटे छोट भागा स मिन हाती है। प्रा मिचिन स अपनी परिभाषा स स्पष्ट किया है कि व्यापार चक्र का तात्पर्य उन उच्चावचना स हाता है जो व्यापारिक क्षेत्र स जात है तथा नियमत रूप स आदर्तीय हान का प्रवृत्ति रखा ह।

प्रा० ज० एम० का स अपना दान पुस्तका (A Treatise on Money (1930) तथा The General Theory of Employment Interest and Money (1936) स व्यापार चक्र की परिभाषा इस प्रकार दा है। अपना पुस्तक A Treatise of Money स व कहत है 'व्यापार चक्र उत्तम व्यापार अवधि जिसम मूल्य स वृद्धि तथा बगेजगारा क आकार स गिरावट हाती है तथा खराब व्यापार अवधि जिसम मूल्य स गिरावट तथा बगेजगारा स वृद्धि होती है का भाग होना है।'<sup>2</sup>

General Theory स किना व्यापार चक्र का परिभाषित करत हुए लिउने ह चक्रवत गति स हमारा जाणय उम स्थिति स हाता है जिसम अर्थव्यवस्था प्रगति करती है अर्थात् ऊपरी दिशा स गतिमान हाती है ता उन शक्तिया का जा दन अर्थव्यवस्था का ठपर की ओर ढकवता है अधिक शक्ति प्राप्त हा जाती है और यह क दूसर पर सचयी रूप स प्रभाव डालती है किन्तु उनकी शक्ति प्रमस घटती जाता है और कुछ गमय क बाद एक बिन्दु पर आकर इनका स्थान विरार्धी दिशा स गतिमान शक्तिया का प्राप्त हा जाता है। यद्यपि यह शक्तियाँ भी अपन पूवजा (विरार्धी शक्तिया) क समान आरम्भ स कुछ गमय तक अधिक शक्ति प्राप्त करती है परन्तु अपन अधिकतम विकास का प्राप्त करत

1 business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that organise their work mainly in business enterprises. A cycle consist of expansions occurring at about the same time in many economic activities followed by similar general recessions, contractions and revivals which merge with the expansion phase of the next cycle, this sequence of changes in recurrent but not periodic'

—W C Midell

2. 'A trade cycle is composed of priods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentage alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages'

—J M Keynes

यह भी कम हो जाती है तथा अन्त में अपनी निरोधी शक्तियों को रथा दे देती है। इससे अतिरिक्त व्यापार चक्र की एक अन्य विशेषता सबट की घटना है अर्थात् उपरी प्रवृत्ति के स्थापन पर नीचे की ओर प्रवृत्ति का स्थानापन्न आकस्मिक रूप से प्रयुक्त के माध्य होता है किन्तु जब नीचे की ओर की प्रवृत्ति का जगह ऊपरी प्रवृत्ति का स्थानापन्न होता है तो इस प्रकार तौक्षण निर्माण अवस्था निश्चयमान नहीं होती है।<sup>1</sup>

जे० एम० कीन्स द्वारा प्रस्तुत व्यापार चक्र की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम व्यापार चक्र की निम्नलिखित विशेषताएँ प्राप्त करते हैं -

(1) व्यापार चक्रों में प्रसार तथा संकुचन (expansion and contraction) की सर्वाधिक वैकल्पिक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। चक्रीय उत्पन्न चक्रों की प्रवृत्ति तब ही होती है।

(2) व्यापार चक्र की ऊपरी एवं नीचे की ओर की गतिशा की अवधि में तथा गमय के अनुक्रम में एक प्रकार की नियमितता पाई जाती है।

(3) व्यापार चक्र में सबट की घटना उपरिष्ठत होती है इसका अर्थ यह है कि ऊपर बिन्दु (Peak) तथा अधोबिन्दु (trough) यथाक्रमण नहीं होते दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि ऊपरी दिशा की गति में जब परिवर्तन होता है तब यह परिवर्तन एकाएक होता है तथा नीचे की ओर की दिशा की गति में होने वाला परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक श्रद्धा होता है। इसके वस्तुस्थिति व्यापार चक्र की चोटी नीचे की ओर तथा तब ही चपटी होती है।

एक अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री प्रो० बेनहम ने व्यापार चक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है 'व्यापार चक्र वैभव तथा सम्पन्नता की वह अवधि है जिसके बाद अवसाद और मन्दो की स्थिति आती है।'<sup>2</sup>

प्रो० रेगनर फ्रिश् (Prof Ragnar Frisch) द्वारा दी गई व्यापार चक्र की परिभाषा निम्न प्रकार है -

'बाह्य प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालकर इसे तब ही तरह उसी प्रकार गतिमान करती हैं जिस प्रकार कोई बाहरी धक्का घड़ी लहर को झुका देता है। लेकिन लहरवत गति की सम्बन्धी झूलती हुई अर्थव्यवस्था में आन्तरिक दबाव द्वारा निर्धारित होती है अर्थव्यवस्था का हल गोलों में ऊँचे दर्जे की नियमितता हो सकती है चाहे इन हलकोरा (oscillation) को जन्म देने वाली प्रवृत्तियाँ बिल्कुल अव्यवस्थित हों।'<sup>3</sup>

व्यापार चक्र की उक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम व्यापार चक्रों की प्रवृत्ति के बारे में कह सकते हैं कि इसका आशय आर्थिक विशाला के उन उन्नाचलन (Fluctuations) में होता है जो निश्चित अरधि के बाद बार-बार उत्पन्न होते हैं। इससे की विभिन्न पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विचार के लगभग 200 वर्षों का इतिहास बताता

1 J M Keynes

2 Benham

3. 'Impulses from outside operate upon the economy, causing it to move in a wave-like manner just as an external shock will set a pendulum swinging. But it is the inner structure of the swinging system which determines the length of the wave movement. The oscillation of the system may have a high degree of regularity, even though the impulses which set it going are quite irregular in their behaviour.'

—Quoted by A H Hansen

है कि यह देश व्यापार चक्रों से पीड़ित रहे ह। बोर्ड भी दो चक्र एन से नहीं हो सकते । इस सम्बन्ध में प्रो० सैमुएलसन (Prof Samuelson) ने व्यापार चक्रों के उल्लेखनीय हैं । वह कहते हैं कि यद्यपि वे एक जैसे बच्चे नहीं होते परन्तु उन्हें एक ही परिवार का सदस्य होने का रूप में पहचाना जा सकता है । व्यापार चक्र में सामयिकता (Periodicity) तथा समन्वयिता (Synchronism) जैसी दो प्रमुख विशेषताएँ पाई जाती हैं । सामयिकता से आशय व्यापार के उतार चढ़ाव अर्थात् विस्तार (Expansion) तथा संकुचन (Contraction) एन दूसरे के ऊपर निर्धारित रूप में प्रतिष्ठित होने से है । जबकि समन्वयिता से आशय उम स्थिति से होता है जबकि व्यापार चक्र के समान देश की सभी फर्मों पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है अर्थात् समृद्धि का या गरीबी का लाभ तथा मंदी का या गरीबी का हानि उठानी पड़ती है ।

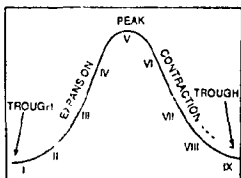
### व्यापार चक्र के रूप अथवा आर्थिक उतार-चढ़ाव के रूप (Types of Trade Cycle or Types of Economic Fluctuations)

आर्थिक उतार-चढ़ाव अथवा व्यापार चक्रों का नापने के लिए विभिन्न अवशास्त्रियों ने इसको नापने की व्यवहारिक कठिनाई का ध्यान में रखते हुए इन विभिन्न रूपों तथा आवृत्तियों की चर्चा की है । इतिहास हमें ज्ञात करा कि एक रूप तथा एक शक्तिवाने चक्रों की गति असम्भव है परन्तु फिर भी आर्थिक उतार-चढ़ाव इतने अनियमित नहीं हुए हैं कि उनको अनुपयुक्त मान लिया जाए । पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ आज भी किसी न किसी रूप में इनसे पीड़ित रहती हैं परन्तु इन आर्थिक उतार-चढ़ावों की तीव्रता में अन्तर हो सकता है जो अनियमितताएँ उपस्थित रहती हैं वे मुख्य रूप से इस स्थिति का परिणाम होती हैं कि एक साथ विभिन्न प्रकार के चक्र संचलित होते रहते हैं ।

संसार के आर्थिक इतिहास के अध्ययन में ज्ञात होता है कि व्यापार चक्रों की न्यूनतम अवधि 4 वर्षों तथा अधिकतम अवधि 12 वर्षों तक की रहती है । अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० एल्विन एच हैन्सन (Prof Alvin H Hansen) ने अपने अध्ययन के आधार पर व्यापार चक्रों को छोटे तथा बड़े व्यापार चक्रों में बाँटा है । उनके अनुसार बड़े व्यापार चक्रों की औसत अवधि 8 वर्षों तथा छोटे व्यापार चक्रों की औसत अवधि लगभग 3½ वर्षों की होती है । प्रो० हैन्सन ने अमरीका का अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की घटनाक्रम का नापने के लिए 142 वर्षों अर्थात् 1795 से 1937 तक की अवधि का अध्ययन किया और इन निष्कर्षों पर पहुँचे कि इस अवधि में 17 बड़े व्यापार चक्र उपस्थित हुए जिनकी औसत अवधि 8.35 वर्षों की थी । 1807 से 1937 तक की 130 वर्षों की अवधि में अमरीका में 37 छोटे व्यापार चक्र विद्यमान रहे जिनकी औसत अवधि 3.1 वर्षों की थी । प्रो० हैन्सन बड़े व्यापार चक्रों की अवधि 8 वर्षों से थोड़ी अधिक मानते हैं । यद्यपि बड़े व्यापार चक्र 6 वर्षों की न्यूनतम अवधि में लेकर 12 वर्षों की अधिकतम अवधि के हात में परन्तु सामान्यतया न्यूनतम तथा अधिकतम अवधियाँ 7 म लेकर 10 वर्षों तक की होती हैं ।

छोटे व्यापार चक्रों की समयावधि सामान्यतया 3 वर्षों से लेकर 6 वर्षों तक की होती है । प्रो० हैन्सन (Prof A H Hansen) ने 130 वर्षों की समयावधि अर्थात् सन् 1807 से 1937 तक अमरीका के आर्थिक इतिहास के विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया कि 37 छोटे व्यापार चक्रों के घटित होने की पुष्टि की है । इस समयावधि के विश्लेषण में एक निष्कर्ष यह भी सामने आया कि छोटे व्यापार चक्रों एक ही समयावधि में चलते हैं । प्रो० हैन्सन ने यह भी सोई आशा करने विशेषज्ञों ने व्यापार चक्रों की नियमितता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । अमरीकी अर्थशास्त्री क्लेमेंट जेम्स (Prof Clement

बिन्दुओं या I तथा IX द्वारा दिनाया गया है। प्रो० मिचिल तथा बर्नेस द्वारा वर्णित इन



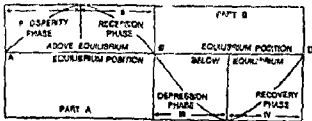
चित्र 1

स्थितियों को निम्नलिखित षाट द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है जो चित्र 1 की पुष्टि करता है।

| अवस्थाएँ              | उप-अवस्थाएँ     | व्यापार चक्र में स्थिति                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ऊर्ध्वबिन्दु (trough) | I तथा IX        | ऊर्ध्वबिन्दु (Trough)                                |
| प्रसारण (Expansion)   | II III तथा IV   | ऊर्ध्वबिन्दु से अधोबिन्दु के प्रारम्भ की स्थिति।     |
| अधोबिन्दु (Peak)      | V               | अधोबिन्दु (Peak)                                     |
| संकुचन (Contraction)  | VI VII तथा VIII | अधोबिन्दु की समाप्ति से ऊर्ध्वबिन्दु के प्रारम्भ तक। |

प्रो० शुम्पीटर (Prof. J. A. Schumpeter) प्रो० मिचिल तथा प्रो० बर्नेस के उक्त वर्णन में सन्तुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि व्यापार चक्र को एक मन्तुवन की अवस्था से दूसरे मन्तुवन की अवस्था तक विभाजित करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने दो अवस्था यात्रे व्यापार चक्र को व्यक्त किया है जैसे भाग A तथा B जिनका निरूपण अध्याय की चित्र 2 द्वारा व्यक्त किया गया है। चित्र में A भाग ऐसी दो अवस्था वाले व्यापार चक्र की व्याख्या करता है जिसमें सम्पूर्ण अवधि में आर्थिक प्रियाओं का स्तर मन्तुवन की अवस्था से ऊपर होता है तथा भाग B में दो अवस्था यात्रे ऐसी व्यापार चक्र का दिनाया गया है जिसमें सम्पूर्ण व्यापार चक्र की अवधि में आर्थिक प्रियाओं का स्तर मन्तुवन की अवस्था में नाब रहता है। प्रस्तुत चित्र 2 में चार मन्तुवन बिन्दु हैं। भाग A में मन्तुवन अवस्था A में B बिन्दु तक तथा भाग B में मन्तुवन अवस्था C में D तक उदगारित गई है। भाग A में एक मन्तुवन बिन्दु A में और दूसरे मन्तुवन बिन्दु B तक व्यापार चक्र की समाप्ति अर्थात् नहीं जाती है। इन वर्षों को समृद्धि की अवस्था

गता जाता है। तृती प्रकार भाग B में भी दो अवस्थाओं को व्यापार चक्रों में दिखाया गया है कि अवधि में अर्थव्यवस्था संतुलन से नीचे स्तर पर रहती है।



चित्र 2

प्रो० शुम्पीटर (Prof J A Schumpeter) ने व्यापार चक्र की जिन चार अवस्थाओं का वर्णन किया है सामान्यतः उन्हें ही व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है।

1 समृद्धि अवस्था अथवा प्रसारण [Prosperity (Boom) or Expansion Phase]

2 सुस्ती अवस्था अथवा मंदी से मन्दी की ओर (Recession phase the Turn from prosperity to Depression)

3 मन्दी अवस्था अथवा संकुचन का स्थिति (Depression Phase or State of Contraction)

4 चेतना अवस्था अथवा मन्दी से समृद्धि की ओर (Revival Phase or the turn from Depression to Prosperity)

1 समृद्धि अवस्था (Prosperity Boom or Expansion Phase)-- व्यापार चक्र की समृद्धि अवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है। प्रो० हेबरलर ने समृद्धि अवस्था या अर्थव्यवस्था से लिया है जिससे वास्तविक आय का उपभोग वास्तविक अर्थ का उत्पादन तथा रोजगार का स्तर ऊँचा होता है और इसमें बेकार साधन या बेरोजगार श्रमिक या तो होते ही नहीं हैं या फिर इनकी संख्या कम होती है।<sup>1</sup>

समृद्धि अवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं— (1) उत्पादन तथा व्यापार का मात्रा में वृद्धि तथा विस्तार (2) रोजगार के स्तर में बहुमुखी वृद्धि (3) बढ़ता हुआ कामगार दर, (4) व्याज का दर में वृद्धि तथा सट्टे बाजार की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी (5) सारा तथा लेन-देन कार्यों में वृद्धि (6) वास्तविक विनियोग में वृद्धि (7) मजदूरी तथा लाभ में वृद्धि आदि तथा समाज की आय में वृद्धि (8) व्यापार के क्षेत्र में आशावादिता (9) अर्थव्यवस्था का अपनी पूर्ण कार्यक्षमतानुसार कार्य करना आदि।

समृद्धि अवस्था में चारों ओर आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और इसमें ऐसे प्रावणिक तंत्र स्वरूप सामर्थ्य हो उठते हैं जिन्हें व्यापारिक क्रियाओं को नई स्फूर्ति मिलता है। बीमते बढ़ने से लाभ बढ़त हैं जिससे साहसियों द्वारा विनियोग के लिए सदैव

1 Prosperity is a state of affairs in which the real income consumed and the level of employment are high or rising, and there are no idle resources or unemployed workers or very few of either  
—G Huberler

प्रा माहा प्रभा रहता है। नये विनियोग व निर प्रतिक्रिया का बाजार गर्म रहता है। प्रत्येक उत्पादक अपनी व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाकर नये सन्तान रहता है। नये विनियोग नये राजगार अवसरों में वृद्धि जिसे उत्पादन तथा आय में भी वृद्धि होती है। प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है जिनके राजगार का स्तर पुनः बढ़ता है। इस प्रकार ममृद्धि का नये प्रमाण का जो अन्तःस्था रहती है वह नये सृजित तथा मचयो हाती है।

ममृद्धि अवस्था का अन्त उम समय होता है जब कि प्रसारण की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। ममृद्धि के अन्त में ही उम पतन व चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जब विनियोग वृद्धि की गति रुकती है तथा अर्थिक विनियोग हेतु वित्तीय माधन में कमी दिखाई देने लगती है परिणामस्वरूप बैंक द्वारा व्याज की दर ऊँची कर दी जाती है। कमी व भाव श्रम तथा अन्य उत्पादन माधन की कमी महसूस होने लगती है और इनके पारिष्कारिक (prices) बढ़ने लगते हैं। इन सबका मित्रा जुना परिणाम यह होता है। मागत व्यय बढ़ जाता है जिससे उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों ही प्रभावित होते हैं। अन्त में दुःख लागत व्यय का पूरा करने के लिए उत्पादन अपने उत्पाद का कीमतें बढ़ाता है उपभोक्ता में गिरावट विधी में गिरावट पार्यों के माधन में गिरावट जाती है। प्रत्येक पद अपने उत्पाद को शीघ्र बचन का प्रयास करता है। कर्मचारी कुछ पदों में इमी हाड में अपनी वस्तुओं की कीमतें गिरा देती हैं और कुछ पदों को हानि उठाना पड़ती है। कुछ मित्रा व ममृद्धि का नये अधिक आशावादिता अतः में निराशावादिता (Pessimism) का जन्म देती है। इमीलिए यह भी कहा जाता है कि ममृद्धि अवस्था नये अपना जन्म गौदेती है।

2 मुस्ती अवस्था (Recession Phase) जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ममृद्धि स्वयं मुस्ती अवस्था का नये व निर उतरदायी हानी है। मुस्ती को एक अवस्था कहने की अपेक्षा एक माड की सजा देना चाहिए जो ममृद्धि का मदी अवस्था में ले जाती है। मुस्ती अवस्था थोड़े समय ही दिखाई देती है। इस अवस्था में साहसिकता (entrepreneurs) को अपनी वृद्धि का आभाम हानि लगता है और वह यह अनुभव करने लगते हैं कि उनके द्वारा ममृद्धिनाल में प्रारम्भ किए गए कार्य लाभप्रद नहीं रहें। उममें व्याप्त निराशावादी दृष्टि काण उनका मनाबन का घटाला है परिणामस्वरूप बहुत सी पदों में एक एक करके बन्द होना प्रारम्भ हो जाती है। उन सबका मित्रा जुना परिणाम यह होता है कि राजगार का स्तर में गिरावट आती है विनियोग गिरते हैं क्योंकि उत्पादन करना लाभप्रद नहीं आता, बैंक अग्रिम बैंक द्वारा व्याज की दर नीची करने पर भी नहीं बढ़ते। प्रभावपूर्ण माँग में गिरावट आती है जिसे कमी और लाभ दोनों का ही स्तर गिरता है। ममृद्धि बाजार में नये का वातावरण छा जाता है और उमकी गतिविधियाँ में गिरावट आ जाती है। प्रा० एम० डब्लू ली० (Prof M W Lee) ने मुस्ती अवस्था की सजा उम जगल से दी है जो एक बार लगने में अपने माग में अन्त घात सभी माग का घटने कर देती है।<sup>1</sup>

3 मदी अवस्था (Depression Phase)—मदी या ममृद्धि अवस्था का वित्तीय विपरात कहा जाए तो अतिशक्ति नहीं होगी। व्यापार उम की मदी अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा राजगार का स्तर में काफी गिरावट आता है। बाजार और निराशावादिता ही दिखाई देती है। प्रा० हवरर ने मदी की अवस्था का बड़ मुन्दर शब्दों में उम प्रकार व्यक्त किया है 'मदी का अन्त उम अवस्था में होता है जिसे प्रति व्यक्ति आय के उप-

1 'A recession once started tends to build upon itself much as forest fire once underway tends to create its own draft and given impetus to its destructive ability.' —M. W. Lee Economic Fluctuation

योग एवं उत्पादन तथा रोजगार के स्तर गिरते हैं और यह एक प्रकार से एक ऐसी असाधारण स्थिति होती है जिसमें बेकार साधन विशेषरूप से धर्म का उपयोग नहीं होने पाता।<sup>1</sup>

मंदी अवस्था में अर्थव्यवस्था के चारों ओर गिरावट के चिह्न अवश्य दिखाई देते हैं परंतु यह एक समान प्रभाव चान नहीं होते। उदाहरणार्थ फुटकर व्यापार पर उतना प्रभाव पड़ता जितना कि थोक व्यापार पर पड़ता है इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मौसमी दशाओं तथा कृषि में और व्यापारिक क्षेत्र की बहुलता के कारण यह क्षेत्र अधिक प्रभावित नहीं आता। जब कि दूसरी ओर मंदी का अधिक प्रभाव निर्मित उद्योगों, खनन निर्माण परिवहन विशेष तौर पर पूंजीगत वस्तुओं, भवनों, मशीनों आदि पर दिखाई देता है।

मंदी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे ही मुद्रा का उपयोग भी घटता है। मंदी में केवल मुद्रा ही ऐसी निधि होती है जिसका माँग बढ़ता है। समान या अधिक क्रिया में गिरावट व्यापार के क्षेत्र पर एक प्रकार से काले बादलों की भाँति देख जाते हैं जिससे बैंक जमाओं में (banks deposits) गिरावट आती है नये ऋणों का माँग गिर जाती है। कोई भी साहसी किसी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता। स्टॉक बाजार (Stock exchanges) में विभिन्न फार्मों के अगो तथा प्रतिभूतियों के मूल्य गिरते हैं।

मंदी अवस्था में राष्ट्रीय आय के वितरण में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। साहसी के पास गिरते हैं और कभी कभी यह ऋणात्मक भी होत है। केवल उन लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है जो कि मंदी के बाद भी रोजगार पर लगे हुए होते हैं इसका कारण यह है कि कीमतों में गिरावट होने से उनके पास उपलब्ध आय (Disposable income) बढ़ जात है।

एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति भी हमेशा नहीं बनी रह सकती इसका कारण यह है कि वे तब जो मंदी के लिए उत्तरदायी होत है स्वयं ही कमजोर पड़ने लगत है। साहसियों द्वारा अपनी प्लांट तथा मशीनों को बदलने की कार्यवाही एक जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा कुछ समय के लिए टिकाऊ वस्तुओं की माँग कम हो जाती है। धीरे धीरे टिकाऊ वस्तुओं की माँग उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ने लगती है (सावजनिक विनियोगों में कुछ प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाती है) परिणामस्वरूप कुछ समय पश्चात् उत्पादकों द्वारा प्लांट तथा मशीनों को बदलने का कार्य शक्ति प्राप्त करता है उत्पादन को बढ़ाया मितता है रोजगार के अंतर, घटत है जिससे आय तथा प्रभावपूर्ण माँग में और वृद्धि होती है। बैंक भी सध बढ़ाने के लिए तयार रहने है। निराशावांशिता से ही आशावादिता के चिह्न दृष्टि गोचर होने लगते है और आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाया मितता है। यहाँ से ही चेतना अवस्था अथवा मंदी से समृद्धि की ओर अर्थव्यवस्था बढ़ती है।

4 चेतना अवस्था (Revival or Recovery phase) अर्थव्यवस्था कुछ समय मंदी की अवस्था में रहने के पश्चात् चेतना अवस्था का अनुभव करने लगती है। इसने अंतगत मंदी से समृद्धि की ओर अर्थव्यवस्था गतिमान होता है। चेतना अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की माँग बढ़ाने लगती है कर्त्तव्य पूंजी उद्योगों में विनियोग तथा रोज

1 Depression means a state of affairs in which real income consumed or volume of Production per head and the rate of employments are falling or are subnormal in the sense that there are idle resources and unused capacity especially unused labour



वार बढ़ता है और आय बढ़ती है। आय में वृद्धि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाती है। कीमतें, लाभ विनियोग, रोजगार तथा आय सभी में दृष्टि के लक्ष्य दिखाई देते हैं। एक बार प्रसारण अवस्था के प्रारम्भ होने से रोजगार उत्पादन तथा आय धीरे धीरे बढ़ती है। इसी चेतना अवस्था में सट्टा बाजार (stock exchange) अधिक सक्रिय हो जाते हैं।

चेतना अवस्था में साहसियों में आशावादिता (Optimism) व्यापार में आशावाद को जन्म देकर विनियोग के लिए माँग प्रवृत्त करती है। साध की माँग तथा बैंक ऋणा की माँग बढ़ने लगती है। व्यापारिक क्रियाओं में तथा साधना की कीमतें बढ़ने से व्यय बढ़ते हैं। जिससे पुनः समाज में साधना की आय बढ़ती है जिससे पुनः व्यय बढ़ते हैं। इस प्रकार चेतना अवस्था के एक बार प्रारम्भ होने का अव्यवस्था का पुनः एक नई शक्ति मिनती है और चेतना की अवस्था शीघ्र ही समृद्धि की धारा में मिल जाती है और चक्र की पुनरावृत्ति होती है।

चेतना की अवस्था शक्ति और समयावधि की दृष्टि अलग-अलग होती है अथवा यह कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस शक्तियों द्वारा इस का जन्म हुआ है। उदाहरणार्थ चेतना अवस्था का प्रारम्भ नव प्रवृत्त अथवा नये क्षेत्रों में, नये उत्पादों अथवा मरदा के समय की पूजा जो व्यय थी उसे कार्यशील बनाकर अथवा सरकार द्वारा नये कार्य आरम्भ करके आदि आदि कारणों से चेतना अवस्था का प्रारम्भ हो सकता है और यही कारण है कि चेतना अवस्था का रूढ़ शक्ति और प्रभाव कैसा होगा इसे जानने के लिए हम इस अवस्था को प्रारम्भ करने वाले कारणों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

जो h अर्थात् गुणव और v अर्थात् त्वरक व विभिन्न मूल्या पर निर्भर करती है। यह स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं—

- (i) आय में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर घटती दर से परिवर्तन होता है। और आय नये सन्तुलन प्राप्त कर लेती है।
- (ii) आय होने वाले उच्चावचन समय चक्र का आधार पर हात है।
- (iii) आय में बढ़ती हुई समय सारणी के अनुसार परिवर्तन होत है।
- (iv) आय में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर बढ़ती हुई दर से परिवर्तन होता है।

(v) स्थिर आयात के समय चक्र का अनुसार आय में परिवर्तन होता है।

व्यापार चक्र नियंत्रण सबन्धी नीति (Policy to control Trade cycle)

व्यापार चक्र एक जटिल प्रक्रिया है इनके घटित होने के लिए एक नहीं बरन् अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने हेतु कौन सी नीति अपनानी चाहिए इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। अधिकांश विद्वानों व्यापार चक्र की घटना को एक आवश्यक और स्वयं घटित होने वाली प्रक्रिया मानते हैं परन्तु इन बातों से सभी एकरम प्रतीत होता है कि व्यापार चक्रों की तीव्रता को कम तथा इनके घटित होने में विलम्ब आवश्यक किया जा सकता है। इस मन्त्र में लिए जाने वाली प्रयत्नों की प्रकृति अबरोधात्मक एवं उपचारार्थक हो सकती है।

व्यापार चक्र के रूप में उत्पन्न सबट के रोबन अथवा उसको समाप्त करने की बात सबट उत्पन्न करने वाले कारणों पर निर्भर करती है। सामान्यतः व्यापार चक्र का रोबन के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया जा सकता है अर्थात् निम्न नीतियों को अपनाने से व्यापार चक्रों के सबट या उसका तीव्रता को कम तथा किसी हद तक समाप्त किया जा सकता है।

(1) **मौद्रिक नीति (Monetary Policy)**—व्यापार चक्रों को रोकने एक उचित मौद्रिक नीति अपनाने की सलाह दी जाती है। एक उचित मौद्रिक नीति का अनुसरण करके तेजी तथा मन्दी की स्थिति को रोक जा सकता है। यदि किसी कारणवश इन्हे रोकना सम्भव न भी हो तो भी उचित मौद्रिक नीति द्वारा व्यापार वृद्धि तथा मन्दी के परिणामों को घटाता तथा आर्थिक स्थिरता को यथासम्भव प्राप्त किया जा सकता है।

मौद्रिक नीति में ऋण तथा ब्याज से सम्बन्धित बैंकिंग तथा साख नीति, मौद्रिक मानक (monetary standard) तथा इनके प्रबन्ध को शामिल किया जाता है। मुद्रा की मात्रा को प्रभावित बैंक साख तथा उसके द्वारा कीमतों तथा आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर को प्रभावित किया जा सकता है। इसके सहस्रपूर्ण साधनों में बैंक दर निर्धारण तथा स्वतन्त्र बाजार कार्य आते हैं। जब व्यापारिक क्रियाएँ विस्तार की प्रवृत्ति दिखा रही हों तो बैंक दर बढ़ जाती है व्यापारिक क्रियाओं के अनुचित विस्तार के कारण साख की मात्रा कम हो जाती है। बैंक साख पर रोक लगाकर विस्तारशील प्रवृत्ति पर गैर सहायता है। मन्दी के समय अर्थव्यवस्था में निराशावादिता को लहर दौड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनाना चाहिए जिससे कि व्यापारिक क्षेत्र में निवेश की मात्रा बढ़ाई जा सके।

बैंक साखनीति द्वारा दो प्रकार से नियन्त्रण होता है गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। परिमाणात्मक नियन्त्रण का सम्बन्ध सामान्य साख व्यवस्था से है। इसके द्वारा बैंक की प्रतिभूतियाँ प्रभावित होती हैं। साख नीति द्वारा व्यापारिक क्रियाओं को बाधित किया जाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

वर्ष 1930 से पहले व्यापार चक्र विरोधी नीति के रूप में मौद्रिक नीति एक उपयुक्त तथा प्रभावशाली नीति मानी जाती थी। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि देश के केन्द्रीय बैंक के नेतृत्व को व्यापारिक बैंक कितना महत्व देते हैं? बैंक अपने ऋणियों को दी जाने वाली साख का प्रयोग करने के लिए कितना तैयार होते हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें साख प्रदान की गई है तथा क्या व्यापारी वर्ष बदलती हुई बैंक दरों के अनुरूप अपने आप को समायोजित कर लेगा या नहीं।

मौद्रिक नीति सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ आशिक रूप से सत्य होती हैं इसलिए मौद्रिक नीति की उपयोगिता सीमित होती है। मन्दी के समय मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध रहती है जैसा कि तीसरा वी विश्वव्यापी मन्दी से विदित है। मन्दी की अवस्था में व्यापारिक क्षेत्र में निराशावादिता की लहर दौड़ जाती है और सस्ती मुद्रा नीति तथा ब्याज की दर में समुचित बदोती करों पर भी निवेशों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। नीची ब्याज की दर केवल मुद्रा की तरलता बढ़ाता है। मन्दी के समय पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की दर ब्याज की दर से निवेशों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। केवल सरकारी प्रयासों द्वारा प्रभावपूर्ण माँग बढ़ाकर पूँजी निवेश का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाते हैं।

(ii) **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)**—राजकोषीय नीति का प्रयोग मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में हुआ या जब मौद्रिक नीति अक्षमानी और अनुपयुक्त हो जाती है तो राजकोषीय नीति व्यापार चक्रों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इससे दो साधन प्रमुख हैं। (i) सरकारी राजस्व तथा (ii) सरकारी व्यय। इसमें अन्तर्गत बजट नीति, बचत को प्रोत्साहन ऋण सम्बन्धी नीति आदि द्वारा राजकोषीय नीति अपनाई अतः सामान्यतः बहुधा यह देखा जाता है कि राष्ट्रभाष्य का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी व्यय के रूप में होता है। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व व राजकोषीय

तथा सरकारी व्यय का महत्वपूर्ण योगदान है जैसा कि हमने देखा प्रो० वीन्स का विचार है कि व्यापार चक्रों के लिए बचत एवं निवेश के मध्य असन्तुलन की स्थिति का आना होता है। ऐसी स्थिति में सरकार तथा उसने निर्यातों के पूंजीगत व्ययों को गैर सरकारी निवेशों के साथ सहायोजन किया जा सके तो असन्तुलन की स्थिति को रोका जा सकता है तो आर्थिक स्थिरता का वातावरण बनाया जा सकता है। यदि फिर भी इन दोनों अर्थात् बचत एवं निवेश के मध्य असमानता बनी रहे तो उस सरकारी व्यय द्वारा समायोजित करने के प्रयास हो सकते हैं। सेजीवाल में जब सरकारी व्यय अधिक हो रहा है, राष्ट्र की मात्रा अधिक हो तो सरकार को सन्तुलित बजट नीति का सहारा लेना चाहिए।

जब अर्थव्यवस्था मन्दी की चपेट में हो तो सरकार को घाटे के बजट (Deficit Budget) बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। विभिन्न करों को हटाने का काम कराने में छूट उदार शर्तों पर ऋण आंशिकता आदि करना चाहिए जिससे कि प्रमादपूर्ण मांग बढ़े रोजगार के साधनों को अधिनाधिक रोजगार मिले और आपातवादिता के दृष्टिकोण को सावर अर्थव्यवस्था को मन्दी से उबारना जा सके।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय (International Measures)—व्यापार चक्र एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना है इसलिए इसे रोकने में एक देश द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय उपायों को अपनाने की सलाह दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादनों नियन्त्रण अर्थात् प्राथमिक उत्पादनों की कीमतों तथा उत्पादन सम्बन्धी उपाय अपनाने से सहाह दी जाती है। इस प्रकार के नियन्त्रण की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जैह कई देशों में कृषि छोटे स्तर पर होते हुए भी जीविका का प्रमुख साधन है। परन्तु यह लाभदायक न होते हुए भी चालू रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियन्त्रण मांग और पूर्ति में होने वाले आवस्मिक परिवर्तनों को समुक्त करने उनकी कीमतों में होने वाला वृद्धि और नियन्त्रण रखकर अर्थव्यवस्था को उच्चावचनों (Fluctuations) से रोकता है

इसी प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशों को नियन्त्रित करने अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय निवेश नियन्त्रण प्रायः विकासशील अर्थव्यवस्था में लागू किया जाता है।

(iv) नियमित विकास (Steady growth)—ऐसा कहा जाता है व्यापारिक उतार चढ़ाव आधुनिक औद्योगिक जीवन की तीन मूलभूत विशेषताओं के अभाव में नहीं पाए जायेंगे। जैसे अनेक वस्तुओं का टिकाऊपन, उत्पादन की जटिल तथा समय लगने वाली संरचना तथा मुद्रा का प्रयोग। यदि वस्तुओं में टिकाऊपन की कमी है तो जो चीजें अन्तिम रूप से उत्पादित होंगी वे उपभोक्ताओं की माँग के ठीक बराबर रहेगी। यदि माँग में परिवर्तन होगा तो आनुपातिक रूप से पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा।

यह तीनों पहलू एक औद्योगिक समाज की व्यापक तथा केन्द्रीय विशेषताएँ हैं। यह एक नियन्त्रित एवं नियोजित समाजवादी व्यवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ऐसा समाज में भी यह विचार करना पड़ता है कि नव-प्रवर्तन को वहाँ जल्दी लाया जाए या धीरे-धीरे। व्यापारिक उतार-चढ़ाव आज के औद्योगिक पूँजीवादी समाज के आवश्यक अंग हैं। हमें नियमित विकास के विचार के साथ अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ हमें व्यापार चक्र के मोड़ों (turning points) तथा व्यापार चक्र की गिरावट तथा प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखना चाहिए।

व्यापार चक्र एक जटिल एवं महत्वपूर्ण घटना है और इसके लिए एक नही करने अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। इनके निवारण हेतु हम विभिन्न उपाय अपनाने पड़ते हैं। यह समझना कठिन नहीं है कि व्यापार चक्र दीर्घकालीन विकास पथ को और दीर्घकालीन विकास पथ व्यापार चक्र को मर्यादित बना देता है।

**निष्कर्ष**—व्यापार चक्र जैसी पेचीली घटना के समाधान के लिए कोई एक सरल एवं निश्चित उपाय नहीं है। बाल भावर्स ने व्यापार चक्र को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक बीमारी की सजा दी है उनका कहना था कि यदि अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र की बुराइयों से दूर करना है तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके ऐसा किया जा सकता है। प्रो० हैन्सन के विचार इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं वे कहते हैं कि 'व्यापार चक्र आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी विचित्र विशेषता है कि इस पर नियन्त्रण करना सरल कार्य नहीं है। व्यापार चक्र यतिशील समाज की एक ऐसी निहित विशेषता है जिसकी उपस्थिति का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में निवेश के आकार में होने वाले निरन्तर परिवर्तन हैं। यह परिवर्तन उस समय भी विद्यमान रहेंगे जब अर्थव्यवस्था की स्वस्थ अवस्था हो जायेगी। व्यापार चक्रों को नियन्त्रित करने के लिए समय-समय पर मौद्रिक तथा राजनीतीय नीतियों का समान्यतः प्रयोग किया गया है।

### परीक्षा प्रश्न

- 1 व्यापार चक्र क्या है ? इसके सक्षण विशेषताओं तथा निवारण को बताइए।  
(What is trade cycle ? Give its characteristics phases and remedies)
- 2 व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं ? व्यापार चक्र के विभिन्न रूप क्या हैं ?  
(What do you understand by trade cycle ? What are the types of trade cycle ?)

### वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा ग़लत सा गलत है।

- 1 (i) व्यापार चक्र पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सामान्य घटना है।
- (ii) व्यापार चक्रों को मापना एक कठिन कार्य है।
- (iii) व्यापार चक्र एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी लागू होते हैं।
- (iv) व्यापार चक्रों को नियन्त्रित करना आसान है।
- (v) व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है।

### वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

(i) सही है। (ii) सही है। (iii) गलत है। (iv) सही है। (v) गलत है।

1 A H Hansen